

प्रचार पुस्तकमाला—१४

हिन्दी वालो, सावधान !

रविशंकर शुक्ल

139



हिन्दी वालो, सावधान !

रविशंकर शुक्ल

840

451

HINDUSTANI ACADEMY
Hindi Section

Library No. ५५२३

Date of Receipt ७/१२/७९

प्रकाशक : काशी नागरी प्रचारणी सभा

मुद्रक : साहित्य मन्दिर प्रेस, लिमिटेड, लखनऊ

प्रथम बार : संवत् २००४ वि० : मूल्य ३।।

निवेदन

प्रस्तुत पुस्तक के शीर्षक की प्रेरणा मुझे श्री संपूर्णानन्द जी की पुस्तक 'ब्राह्मण, सावधान' से मिली। पुस्तक का विषय, जैसा कि इसके शीर्षक से प्रकट है, हिन्दी प्रेमियों को हिन्दी पर आये हुए और आने वाले खतरे से सावधान करना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरा अपना ख्याल है कि हिन्दी-प्रेमी हिन्दी पर आने वाले खतरे से या तो पूर्णतया परिचित नहीं हैं या उन्होंने उसके भयंकर परिणाम की भली भाँति कल्पना नहीं की है। हिन्दी-प्रेमी हिन्दी की संकटपूर्ण स्थिति का कुछ कुछ अनुभव तो करते हैं, परन्तु वे कुछ तन्त्रा वश, कुछ मांह वश और कुछ देश के आजकल के राजनीतिक वातावरण के कारण इस स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर गहराई के साथ विचार करने में असमर्थ हैं। हिन्दी के संकट को पूर्णतया न पहचान सकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह संकट उन्हीं राजनीतिक नेताओं की ओर से आया है जिन्हें हम काफी समय से अत्यन्त श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते आये हैं। इस संकट को उत्पन्न करने वालों में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका अब तक हिन्दी की उन्नति, प्रचार और प्रसार में बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन सब कारणों से यकायक यह विश्वास करने को हर किसी का जी नहीं चाहता कि ये व्यक्ति हिन्दी पर इतना भयंकर और घातक प्रहार कर सकते हैं। संभव है, कुछ हद तक निश्चित है, कि इन व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो स्वयम् नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी सरगमियों का फल क्या होगा। आजकल के राजनीतिक वातावरण ने हमारे चारों ओर एक ऐसा जाल सा बुन दिया है कि क्या नेता और क्या साधारण व्यक्ति, सबको प्रत्येक वस्तु धुँधली नो देख पड़ती है। श्रुति मुंशी के शब्दों में, आजकल प्रत्येक वस्तु राजनीतिक

भँवरों में पड़ कर गँदली हो गई है। फलस्वरूप हिन्दी-प्रेमी हिन्दी प आने वाले संकट को भी स्पष्टतया नहीं देख पा रहे हैं। राजनीति के मैदान में जो धूल उड़ रही है उसमें इस संकट का आकार-प्रकार छिप सा गया है। पर वह संकट तो विद्यमान है ही। युद्ध की गर्मी में राजनीतिज्ञों कोर इसकी पर्वाह नहीं रह गई है कि उनकी चालों का देश के दूर भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हिन्दी के दुर्भाग्य से हिन्दी के अधिकांश प्रेमी और समर्थक भी राजनीतिज्ञ ही हैं, और इस कारण वे भी हिन्दी-संसार का वैसा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं जैसे नेतृत्व की उसे इस समय आवश्यकता है। वे स्वयम् राजनीति के शिकज्जे में जकड़े हुये हैं। उनके हाथ पैर राजनीति के उलझट्टे में उलझे हुये हैं और उनके मुँह पर राजनीति का ताला पड़ा हुआ है। शायद उनके दिमाग में भी राजनीति का घटाटोप छाया हुआ है। उनके पास हिन्दी को देने के लिये समय भी नहीं। उनसे अधिक आशा करना व्यर्थ है।

ऐसी स्थिति में राजनीति के कोलाहल से दूर बैठे हुये एक हिन्दी-प्रेमी का जो कर्तव्य हो जाता है, उसी को सामने रखकर मैंने इस पुस्तक को लिखा है। मेरा दृष्टिकोण शुद्ध हिन्दी के हित का दृष्टिकोण है। मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, राजनीतिक नेताओं में मेरी अन्ध-भक्ति नहीं। राजनीतिक नेता व्यक्तिगत रूप से कितनी ही ऊँची श्रेणी के व्यक्ति क्यों न हों, मैं उन्हें भाषा के विषय में खोलने का अधिकारी मानने को तैयार नहीं। भाषा के विषय में मैं किसी राजनीतिक संस्था, भले ही वह वयस्क मताधिकार के आधार पर बनी हो, का फैसला मानने को भी तैयार नहीं। इतिहास साक्षी है कि किसी देश का उद्धार केवल राजनीतिज्ञों द्वारा नहीं हुआ है। विशेष रूप से इस देश में देश का साहित्यिक और सांस्कृतिक नेतृत्व राजनीतिज्ञों के हाथ में कभी नहीं रहा। भाषा और साहित्य की परंपरायें हमें व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और तुलसी से मिली हैं, अशो,

समुद्रगुप्त, अकबर और बाजोराव से नहीं। आज गांधीजी हिन्दी के भाग्य का निर्णय नहीं कर सकते। आज कांग्रेस नहीं कह सकती कि इस लिपि में लिखो और ऐसी भाषा में बोलो। भूँटी एकता के नाम पर देश की प्राचीन भाषा और संस्कृति को, जिसे हमने हजारों वर्ष से सुरक्षित रखा है, हम छोड़ नहीं सकते। इस समय राजनीतिज्ञों की आवाज़ के सामने साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक नेताओं की आवाज़ घीमी पड़ गई है, यह बात दूसरी है। संभव है मेरी आवाज़ राजनीति के कोलाहल में हिन्दी-प्रेमियों को न सुनाई पड़े, परन्तु इस कारण मैं हिन्दी के एक सेवक के नाते अपने पवित्र कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकता। मैं तो इस आशा से प्रेरणा पाता हूँ कि शीघ्र ही राजनीति का घटाटोप हटेगा और राजनीतिज्ञों का उससे अधिक महत्त्व न रह जायगा जितना समाज ने इस प्राचीन देश के हजारों वर्ष पुराने इतिहास में उन्हें देना उचित समझा है।

पुस्तक स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में हिन्दी और हिन्दी वालों को अपनी कमज़ोरियों का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है। दूसरों की कमज़ोरियाँ देखने की अपेक्षा अपनी कमज़ोरियाँ देखना सदैव एक अधिक कठिन कार्य रहा है। परन्तु सफलता प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम अपनी कमज़ोरियों को दूर करना अत्यावश्यक है। सच तो यह है कि जिस दिन से मनुष्य को अपनी कमज़ोरियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं और जिस दिन से वह अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की चेष्टा करता है, उसी दिन से वह सफलता की ओर अग्रसर होने लगता है। हिन्दी की अपनी कमज़ोरियों को दूर किये बिना सफलता मिल नहीं सकती। इसलिये मैं पहले भाग को अधिक महत्त्व देता हूँ।

मेरा संस्कृत का ज्ञान नहीं के बराबर है, और यद्यपि मैं थोड़ी बहुत उर्दू जानता हूँ, मुझे अरबी और फारसी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इसलिये कसम्भव है पहले भाग में मैंने जिन शब्दों को उदाहरण-स्वरूप पेश किया है,

उनमें से कुछ के मूल स्रोतों के विषय में मुझसे भूल हो गई हो। आशा है बिना पाठक इन भूलों को क्षमा करेंगे। मैंने कोषों से शब्दों के उदाहरण ढूँढ़ने की बिलकुल चेष्टा नहीं की है। जो शब्द नित्य सुनने और पढ़ने में आते हैं, उन्हीं को उदाहरण-स्वरूप पेश कर दिया है। एक बात और। हिन्दी की शुद्ध और स्टैण्डर्ड शैली के विषय में मैंने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, उनके अनुसार अपनी भाषा सुधारने का मैंने बिलकुल प्रयत्न नहीं किया है। पाठक मेरी भाषा को इन सिद्धान्तों की कसौटी पर न कमें। मैंने अपनी स्वाभाविक शैली में ही लिखा है, जिससे पाठकों को आज कल की औसत दर्जे की हिन्दी अर्थात् आजकल के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के हिन्दी लेखकों की हिन्दी, जिसमें सुधार की आवश्यकता मैंने बताई है, का नमूना ढूँढ़ने के लिये पुस्तक के बाहर न जाना पड़े। मैंने शुद्ध हिन्दी के विषय में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है उनके विपरीत बातें पाठकों को पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर मिल जायँगी। उनसे पाठकों को पता चलेगा कि हिन्दी की बीमारी की जड़ कितनी गहरी है और उसे उखाड़ कर रेंकने के लिये कितनी शक्ति और प्रयास की आवश्यकता है। प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार शुद्ध और अच्छी हिन्दी का आदर्श तो चोटी के लेखक और साहित्यिक हो उपस्थित कर सकते हैं। मैं उन पर चल कर केवल अपनी शैली को अस्वाभाविक और अपने को उपहासास्पद बनाता। इन सिद्धान्तों का मेरी शैली पर अनजाने में जो प्रभाव पड़ गया हो, उसकी बात दूसरी है।

पुस्तक के दूसरे भाग में हिन्दुस्तानी की बला का निरूपण किया गया है। उसके विषय में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मैंने 'हिन्दुस्तानी' के समर्थकों के तर्कों का उत्तर देने का अथवा राष्ट्र-भाषा की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न नहीं किया है। यहाँ मैंने केवल यह बतलाने की चेष्टा की है कि 'हिन्दुस्तानी' से हिन्दी को क्या खतरा है

और उसका निवारण किस प्रकार करना चाहिये। जो पाठक राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी-वाद पर मेरे विचार जानना चाहें, उन्हें निवेदन है कि वे मेरी पुस्तकें 'राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन' तथा 'मौलाना गांधी ?' * (जो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री श्री श्रीमन्नारायण के 'मौलाना गांधी' शीर्षक लेख के उत्तर में लिखी गई है) पढ़ लें।

परिशिष्ट में कुछ ऐसी सामग्री एकत्र की गई है जिसका पुस्तक के विषय से सम्बन्ध है, अथवा जिससे विषय के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। परिशिष्टों का परिचय यथास्थान दे दिया गया है। परिशिष्ट १५ पं० रामचन्द्र शुक्ल की पुस्तिका 'हिन्दुस्तानी का उद्गम' का मुख्यांश है। इसे यहाँ पं० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द्र जैसे युक्त-प्रान्त और बिहार के हिन्दुस्तानी वालों के लाभार्थ दिया गया है जो उर्दू को ही वास्तविक हिन्दुस्तानी समझते हैं, उर्दू को हिन्दी से प्राचीन, हिन्दुओं और मुसलमानों की 'मुश्तरका ज़बान' और न जाने क्या क्या समझते हैं, और जिन्होंने बचपन में मौलवी से उर्दू सीखने के बाद शायद कभी उर्दू के इतिहास पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा और जो शायद आज भी उससे अनभिज्ञ हैं। आशा है इसमें उन राजनीतिक नेताओं को भी विचार करने की सामग्री मिलेगी जिनका 'हिन्दुस्तानी'-प्रेम राजनीति पर निर्भर है और जिन्होंने अभी तक 'हिन्दुस्तानी' को किसी दूसरी दृष्टि से देखना, जाँचना-पड़तालना आवश्यक नहीं समझा है। हमें विश्वास है, इससे गांधी जी, श्री राजगोपालाचार्य और श्रीयुक्ती जी. खेर जैसे अहिन्दियों को भी लाभ होगा जिन्हें हिन्दी-उर्दू सम्बन्धों वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं और जिनकी बहक का कारण बहुत कुछ यही है। हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी के

* दोनों पुस्तकें गंगा पुस्तकमाला, लाट्रूश रोड, लखनऊ से मिल सकती हैं।

निकोने भगड़े में जिन्हें सत्य की चिन्ता हो और जो वास्तविकता का अधिक विस्तार से जानना चाहते हों, उनसे निवेदन है कि वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित श्री चन्द्रबली पाँडे की खोजपूर्ण पुस्तकें 'उर्दू का उद्गम', 'उर्दू का रहस्य', 'भाषा का प्रश्न' 'कचहरी की भाषा और लिपि', 'सुलत बादशाहों की हिन्दी', 'विहार में हिन्दुस्तानी', आदि और सबके अन्त में बिष्टामंदिर-प्रकाशन, मुरार (ग्वालियर) द्वारा प्रकाशित उनकी नवीन कृति 'नागरी का अभिशाप' अवश्य पढ़ें। हमें विश्वास है, इन पुस्तकों से उर्दू और 'हिन्दुस्तानी' के ईमानदार समर्थकों की आँखें खुल जायँगी।

यह पुस्तक गत वर्ष सितम्बर में पूर्ण हो गई थी, परन्तु कागज़, आदि की कठिनता के कारण अब तक न छप सकी। इस बीच में देश में ऐसी अनेक घटनायें घटी हैं जिनका भाषा के प्रश्न पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कुछ और बातें ऐसी हुई हैं जिनसे भाषा की समस्या पर तीव्र प्रकाश पड़ता है। परन्तु इस कारण मूल पुस्तक में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। मूल पुस्तक में जो दो-एक बातें ऐसी आई हैं जो अब तक सुलभ चुकी हैं, पुस्तक में उनकी चर्चा इतिहास का काम देगी, और भविष्य के लिये पथ-प्रदर्शन करेगी। गत वर्ष सितम्बर से अब तक जो नई बातें हुई हैं उनका समावेश परिशिष्ट १७ और उत्तर-परिशिष्ट १, २ और ३ में कर दिया गया है, और मूल पुस्तक से उनका सम्बन्ध पुस्तक में यथास्थान पाद-टिप्पणों देकर जोड़ दिया गया है। कहना न होगा, इस बीच की सबसे बड़ी घटना भारत का विभाजन है। परिशिष्ट १७ तथा उत्तर-परिशिष्ट १, २ और ३ पर इसकी छाप प्रत्यक्ष है। इसका राष्ट्र-भाषा की समस्या पर जो गहरा और एक अर्थ में निर्णयात्मक प्रभाव पड़ता है उसका उत्तर-परिशिष्ट ३ में विशेष रूप से विवेचन किया गया है।

ऐसी धारणा थी कि राष्ट्र-भाषा का प्रश्न भारतीय विधान-परिषद के

१४ जुलाई, १९४७ से आरंभ होने वाले अधिवेशन में तय हो जायगा। पुस्तक की छपाई जुलाई में ही आरंभ हुई थी, अतः १४ जुलाई तक पूरी पुस्तक का छपना संभव न था। मैंने सोचा कि यदि राष्ट्र-भाषा के प्रश्न का अन्तिम निर्णय होने से पूर्व विधान-परिषद के सदस्यों के पास पूरी पुस्तक न सही, पुस्तक की ऐसी सामग्री ही पहुँच सके जिसका भारत के विभाजन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से विशेष सम्बन्ध है, तो अच्छा होगा। इस उद्देश्य से उत्तर-परिशिष्ट १, २ और ३ को पहले छपा लिया गया और यह सामग्री पुस्तकाकार विधान-परिषद के सदस्यों के पास भेज दी गई। पुस्तक में इसका नामकरण 'उत्तर-परिशिष्ट' होने और उसमें पृष्ठ-संख्या फिर से आरंभ होने का यही कारण है।

अब स्थिति यह है कि राष्ट्र-भाषा का प्रश्न विधान-परिषद के आगामी अधिवेशन में तय होगा। हिन्दी के भाषाकाश में आशा की जो एक किरण दिखाई देती है वह यह है कि विधान-परिषद के कांग्रेसी सदस्यों ने बहुमत से हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि के पद पर प्रतिष्ठित करने का निर्णय किया है। परन्तु कांग्रेसी नेतागण अब भी विरोध कर रहे हैं। हिन्दुस्तानी की बला आसानी से नहीं टलेगी। हिन्दी वालों को अपनी समस्त शक्ति से जोर लगाना होगा। राष्ट्र-भाषा के पद और हिन्दी प्रांतों में राज-भाषा के पद पर हिन्दी की प्रतिष्ठा होने के बाद हमें जिस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा वह है शिक्षा के माध्यम की समस्या जिस पर परिशिष्ट १७ में विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में हिन्दी के कुछ समर्थकों तक में यह भ्रम फैला हुआ है कि हिन्दी प्रांतों में उर्दू को भी शिक्षा का माध्यम होना चाहिये। अभी हाल में इलाहाबाद में हुये प्रगतिशील हिन्दी लेखक सम्मेलन में इस विषय पर घोर वाद-विवाद होना और उसका किसी निर्णय पर न पहुँचना इसका उदाहरण है। परन्तु सत्य यह है कि यदि हिन्दी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम अकेली और केवल हिन्दी

न होगी, तो हिन्दी प्रान्तों में भाषा की समस्या तो ज्यों की त्यों रहेगी ही, राष्ट्र-भाषा के पद और हिन्दी प्रान्तों में राज-भाषा के पद पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का निर्णय भी बहुत हद तक निरर्थक और अवास्तविक सिद्ध होगा। दूसरी बात जिस पर ध्यान देना होगा वह है कि रेडियो में 'हिन्दुस्तानी' का पूर्ण बहिष्कार करके हिन्दी की उचित प्रतिष्ठा की जाय और अन्य सब सरकारी विभागों में, हिन्दी प्रान्तों में और केन्द्र में, केवल लिपि ही देवनागरी न हो बरन् भाषा भी यथार्थ में हिन्दी हो, और इस हेतु शासन सम्बन्धी और अदालती पारिभाषिक शब्दों का एक स्टैंडर्ड हिन्दी कोष बनाया जाय।

यदि इस पुस्तक से हिन्दी-प्रेमियों को हिन्दी पर आये हुये 'हिन्दुस्तानी' रूपी संकट को पहचानने में सहायता मिली, और उन्होंने समय रहते सावधान हो कर उसका सामना करने के लिये उचित कदम उठाये तो मैं अपना प्रयत्न सफल समझूँगा।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी,

७ सितम्बर, १९४७

रविशंकर शुक्ल

प्रकरण-सूची

प्रकरण	पृष्ठ
१. हिन्दी की अपनी समस्या	१
१. हिन्दी का द्वैतवाद	१
२. द्वैतवादियों के कुछ तर्क	१०
३. क्या करें ?	१८
४. कुछ आक्षेपों के उत्तर	८१
५. क्या हिन्दी कृत्रिम है ?	८७
२. हिन्दुस्तानी की बला	१०५
१. हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप	१०६
२. हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी	१२०
३. हिन्दुस्तानी वालों के हथकण्डे	१२५
४. क्या करें ?	१५५

परिशिष्ट

परिशिष्ट १ (हिन्दी की कृतियों में मुसलमान पात्रों का उद्गार में कथोपकथन)	१६७
परिशिष्ट २ (The Vernacular of United Provinces)	२०४
परिशिष्ट ३ (हम हिन्दी वाले !)	२१५
परिशिष्ट ४ (वर्धा की हिन्दुस्तानी)	२२१
परिशिष्ट ४ पर टिप्पणी	२२६

प्रकरण	पृष्ठ
परिशिष्ट ५ (हिन्दुस्तानी)	२३५
परिशिष्ट ६ (“हिन्दुस्तानी का प्रचार क्यों” पर एक दृष्टि)	२३६
परिशिष्ट ७ (दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किधर ?)	२४५
परिशिष्ट ८ (महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष क्यों ?)	२४६
परिशिष्ट ९ (महाराष्ट्र में राष्ट्र-भाषा का प्रचार)	२५२
परिशिष्ट १० (महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा समस्या)	२५७
परिशिष्ट ११ (महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा समस्या)	२६०
परिशिष्ट १२ (भारत की राष्ट्र-भाषा की समस्या)	२६३
परिशिष्ट १३ (हिन्दुस्तानी का वेदान्त)	२६६
परिशिष्ट १४ (‘हरिजनसेवक’)	२७४
परिशिष्ट १५ (हिन्दुस्तानी का उद्गम)	२८१
परिशिष्ट १६ (युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा)	२८७
परिशिष्ट १७ (हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम)	३०२

उत्तर-परिशिष्ट (पृष्ठ ३२४)

उत्तर-परिशिष्ट १ (रोमन लिपि का जयजयकार)	१
उत्तर-परिशिष्ट २ (‘राष्ट्रीय’ सरकार की रेडियो की भाषा विषयक नीति)	१५
उत्तर-परिशिष्ट ३ (‘हिन्दुस्तानी’ का रहस्य — एक हिन्दी के मुख से)	३६

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४६	६	सान्निद्वय	सान्निध्य
५६	२	इङ्गलिस्तानी	इङ्गलिस्तानी
६२	२०	अनाधिकारी	अनधिकारी
६६	२४	एका-कारता	एकाकारता
७६	१६	करेगा,	करेगा)
८३	२२	Renaissane	Renaissance
८८	४	प्रदश	प्रदेश
८८	२२	में वे	में
१०१	२५	ज़ले	ज़िले
१३६	१६	कौसल्यापन	कौसल्यायन
१४७	१५	हुआ	हुआ,
१४७	१६	भ्रष्ट,	भ्रष्ट
१६२	१	को	की
१७४	२०	प्रयत्न	प्रयत्न
१७६	२३	बनाये	बनावें
१७८	२	जनना	जनता
१८१	५	की	को
१८१	५	समक्ष	समक्ष
१८४	७	अहिन्दियों	अहिन्दियों
१८६	११	—, द्वेष नह	, द्वेष नहीं—

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२१६	८	चन	चैन
२१६	२५	र्णतः	पूर्णतः
२१८	१४	का	की
२१८	१८	अतनी	अपनी
२२३	१०	उदारण	उदाहरण
२२६	१५	मथिली	मैथिली
२५०	२४	नने	नेने
२८७	२५	श्रुकी ति-रुचि	की श्रुति-रुचि

उत्तर-परिशिष्ट (पृष्ठ ३२४)

१२	२५	'इङ्गलिस्तनी'	'इङ्गलिस्तानी'
२३	२५	समाचा	समाचार
४१	फुटनोट	'पुनर्लेख'	'पुनश्च'
४६	६	हिन्दी	हिन्दी तो
५३	२५	Persani	Persian
५४	५	or	of

निवेदन

४	१	प	पर
४	४	कोर	को
४	२५	अशो	अशोक
५	२१	सफलना	सफलता
५	२५	कसम्भव	सम्भव
१०	११	-स्तानी	-स्तानी

हिन्दी की अपनी समस्या

मरु-भूमि में एक जानवर होता है जो बालू की आँधी चलने पर अपना सिर भूमि में गड़ा लेता है। हिन्दी संसार में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। वे स्वयम् तो सो ही रहे हैं, औरों को भी चादर ओढ़े सोये रहने का उपदेश दे रहे हैं। यदि कोई उठने का उपक्रम करे भी है तो उसे थपकी देकर सुला देना चाहते हैं। ऐसे पलायनवादियों को छोड़कर शेष को मालूम है कि हिन्दी पर एक महान् संकट आया हुआ है। इस संकट का नाम है 'हिन्दुस्तानी'। ब्रिटिश सरकार तो उर्दू या हिन्दुस्तानी नामधारी उर्दू के नाम पर हिन्दी को मिटा डालने के लिये बहुत समय से प्रयत्नशील है ही, परन्तु हम समझते थे कि अपनी सरकार आने पर शायद यह अनानाचार बन्द हो जाय। अब वह आशा भी नष्ट होगई, बल्कि यह नया संकट उसी की ओर से आया है या आना चाहता है। यह हिन्दी को भीतर ही भीतर समाप्त करना चाहता है अथवा उसे केवल कविता की भाषा बनाना चाहता है। जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले अपने घर की स्थिति देखी जाती है। देखें, आज हिन्दी की क्या हालत है।

१. हिन्दी का द्वैतवाद

हिन्दी के एक प्रसिद्ध नासिक पत्र का एक अंक सामने है। इसके प्रथम ५० पृष्ठों में आये हुये अरबी फारसी अर्थात् उर्दू के शब्द ये हैं—

मकसद, मुक़रर, सूदा, ख़त, दोस्त, सुबह, फ़र्ज़, वारिश, नफ़रत, सदास्त,

तरजुमा, मरीज़, सज़ा, बेवकूफ़, नुमायन्दा, हुक़्म, अहम, वज़ीर, एतराज़, सरहद, सदी, साहिर, तहज़ीब, महदूद, सब्र, शुक्रिया, रक़्बा, इफ़रात, नज़़ारा, दुश्मन, शाम, ज़रूम, मेहमान, किताब, मुलाक़ात, इन्तज़ाम, मुश्किल, आसमान, इन्सान, दिमाग़, वक्त, मशहूर, तादाद, तनख़्वाह, ख़्वाब, मिसाल, ज़िन्दगी, नज़र, फैसला, तकलीफ़, मौजूद, ख़त्म, रोज़, ताज्जुब, काश्त, ज़ायका, इस्त-हान, मदद, फ़ायदा, जगह, फर्क, सिर्फ़, एलान, ख़ास, मुनासिब, मुताबिक़, मज़ा, वाकई, फ़स्ल, ईमानदारी, सतर, ख़िलाफ़, कोशिश, हमला, मुख़ालफ़त, सब्ज़ी, रोज़ाना, रिश्ता, कायदा, मुफ्त, आवाज़, रोशनी, मुल्क, रूह, बेरहम, जुल्म, फ़ौरन, शहंशाह, बग़ैरह, कमज़ोर, ज़िम्मेदार, अलावा, बादशाह, सलाह, मशविरा, तारीफ़, पैशाम, बहस मुवाहिदा, तब्ज़ा, कामयाब, मातहत, यक़ीन, ख़्वाहिश, मिज़ाज़, ख़िदमत, तमन्ना, इरूफ़, शराफ़त, आमदनी ।

लगभग इन सब शब्दों के हिन्दी पर्याय भी इन्हीं ५० पृष्ठों में आये हैं और बिलकुल उन्हीं अर्थों में प्रयुक्त हुये हैं जिनमें उर्दू शब्द । प्रायः एक ही लेख में, बल्कि एक ही वाक्य में, हिन्दी और उर्दू के पर्यायवाची शब्द मौजूद हैं, और एक ही भाव या वस्तु के लिये एक बार हिन्दी का शब्द आया है और दूसरी बार उर्दू का शब्द । क्या आप बता सकते हैं कि संसार की किस भाषा में, हिन्दी को छोड़कर, ऐसा देखने में आता है ? उर्दू में तो अवश्य ही नहीं ।

अँग्रेज़ी में ऊपर से पर्यायवाची जान पड़ने वाले कई कई शब्द होते हैं, परन्तु उनमें ध्वनि और अर्थ का सूक्ष्म अन्तर होता है, और अच्छी अँग्रेज़ी जानने वाला एक के स्थान में दूसरा शब्द प्रयुक्त करने की भूल नहीं करेगा । 'Letter' के स्थान में 'Despatch', 'Able' के स्थान में 'Competent', 'Speech' के स्थान में 'Discourse', 'Hate' के स्थान में 'Contempt' आदि, आदि कोई नहीं लिखेगा । फिर ऐसे सूक्ष्म अर्थ-भेद वाले कई कई शब्द प्रायः गम्भीर भावों को प्रकट करने के लिये होते हैं । नित्य

काम में आनेवाले शब्द प्रायः अकेले होते हैं। अँग्रेजी में 'Morning', 'Evening', 'Duty', 'Province', 'Letter', 'Minister', 'Sky', 'Rain', 'Word' आदि, आदि के लिये दूसरे शब्द नहीं हैं या प्रयुक्त नहीं होते। परन्तु हिन्दी में तो (उर्दू में नहीं) 'प्रातः काल', 'सन्ध्या', 'कर्त्तव्य', 'प्रान्त', 'पत्र', 'मन्त्री', 'आकाश', 'बर्षा', 'शब्द' आदि, आदि के साथ साथ 'सुबह', 'शाम', 'फर्ज', 'सूबा', 'खत', 'बर्ज़ार', 'आसमान', 'बारिश', 'लफ्ज़' आदि, आदि भी प्रत्येक पृष्ठ पर विराजमान हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके दो या दो से अधिक शत प्रतिशत अर्थ-साम्य वाले पर्याय होते हैं, परन्तु हिन्दी में तो ऐसे शब्दों की संख्या की मर्यादा ही नहीं है। उर्दू कोष केवल हिन्दी-शब्द-सागर में ही नहीं समाया हुआ है, वह व्यवहार में भी बहुत हद तक हिन्दी पत्रों और पुस्तकों के पत्रों पर विद्यमान है, और हिन्दी के बड़े से बड़े साहित्यिकों की बोलचाल में भी विद्यमान है, बल्कि यों कहिये, बोलचाल में और भी अधिक प्रबल रूप में विद्यमान है।

हिन्दी की इस स्थिति के अनिवार्य परिणाम पर भी विचार कर लीजिये। बार बार कहा जाता है कि जो शब्द हिन्दी और उर्दू दोनों में आते हैं, उनके आधार पर कामन भाषा, राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' बनाई जाय। बात तो ठीक है। ऐसा क्यों न किया जाय ? ऐसी हिन्दुस्तानी कम से कम हिन्दी-उर्दू प्रदेश की कामन भाषा या राजभाषा तो हो ही सकती है। श्रीसम्पूर्णानन्द कहते हैं कि हिन्दी-शब्द-सागर में सम्पूर्ण उर्दू कोष इसलिये मौजूद है कि उर्दू भी हिन्दी की एक शैली है, और हिन्दी-शब्द सागर में वे सब शब्द हैं जो दोनों शैलियों के लेखक प्रयुक्त करते हैं (वह केवल एक ही शैली की लिपि में शायद इसलिये छपा कि दूसरी शैली के लेखकों को उसकी जरूरत नहीं है !)। अच्छा, मान ली यह बात। परन्तु उन उर्दू के शब्दों के लिये क्या कहा जाय जो हिन्दी शैली के लेखक नित्य लिखते हैं ? कोषों को दीजिये छोड़, जो

शब्द हिन्दी लेखक और उर्दू लेखक दोनों प्रयुक्त करते हैं उनके आवाज पर 'हिन्दुस्तानी' क्यों न बनाई जाय ? हिन्दी वाले कहेंगे (जैसा श्रीसम्पूर्ण-नन्द ने ही कहा है), बात तो ठीक है, परन्तु उन हिन्दी पर्यायों को कैसे छोड़ा जा सकता है जिनको भी हिन्दी लेखक प्रयुक्त करते हैं ? इस तर्क में बिल्कुल जान नहीं। हिन्दी वाले इन शब्दों को प्रयुक्त करते होंगे, परन्तु उर्दू वाले तो नहीं करते। हिन्दी पढ़ने वाले इन शब्दों को जानते होंगे, परन्तु उर्दू पढ़ने वाले तो नहीं जानते। फिर कामन भाषा में ये शब्द 'आम-फहम', कामन पर्यायवाची शब्दों के मौजूद होते हुये कैसे लिये जा सकते हैं ? हिन्दी वालों को हजारों शब्दों के दो दो पर्यायों को घोटने की, लिखने की और कोष-बद्ध करने की फुरसत होगी, परन्तु कामन, आमफहम भाषा में यह शब्दाडंबर नहीं चल सकता। है हिन्दी वालों के पास इसका कोई उत्तर ?

बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। भाषा एक सिद्धान्त नहीं, जो तर्क से सिद्ध किया जा सके। भाषा एक व्यवहार की, नित्य के काम की चीज़ है। भाषा में वे ही शब्द जीवित रहेंगे जो नित्य बोलचाल में आते हैं, और उन्हीं में भाषा के जीवन और शक्ति की अभिव्यक्ति होगी। और बोलचाल में वे ही शब्द अपने आप आवेंगे जिन्हें सब समझते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसी भाषा और उसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिसे दोनों समझते हैं। इस नियम में कोई तर्क व्यापार नहीं डाल सकता। अब हिन्दी की परिस्थिति पर शौर कांजिये। समस्त हिन्दी प्रदेश में हिन्दी के साथ साथ उर्दू चलती है और सब जगह हिन्दी पढ़ने वाले और उर्दू पढ़ने वाले बूले मिले रहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि हिन्दी वाले अपने हिन्दी शब्द जानते हैं और हिन्दी में प्रचलित उनके उर्दू पर्याय भी जानते हैं, परन्तु उर्दू वाले केवल उर्दू पर्याय जानते हैं, तो हिन्दी प्रदेश की बोलचाल

में केवल उर्दू शब्द ही आँवेंगे—इसे कोई तर्क या भाषा-प्रेम रोक नहीं सकता। यह बात प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। उदाहरण के लिये, ऊपर जिन उर्दू शब्दों को एकत्र किया गया है उनके हिन्दी पर्याय उर्दू वाले भूलकर भी नहीं लिखते और परिणामस्वरूप हिन्दी प्रवेश की शिष्ट बोलचाल में इन हिन्दी शब्दों में से अधिकांश प्रायः नहीं चलते, जब कि उर्दू पर्याय बाज़ारों में, गलियों में, रेल के डिब्बों में, आदि सब जगह सुनने को मिल जायेंगे। यदि कहीं पर हिन्दी पर्याय चलने भी हैं तो उनका प्रयोग करने वाले उर्दू पर्याय अज्ञान्य जानते हैं, परन्तु उर्दू शब्दों का प्रयोग करने वालों में से अधिकांश हिन्दी पर्यायों को जानते ही नहीं, अर्थात् बोलचाल की कामन भाषा में ये ही उर्दू शब्द हैं, हिन्दी पर्याय नहीं हैं। इन हिन्दी पर्यायों को हिन्दी वाले आनस में बैठ कर या समा सोसाइटियों में भले ही प्रयुक्त कर लें, परन्तु ये आन जनता में नहीं चलते, और जब तक लिखित हिन्दी में शब्दों का यह द्वैतवाद ऐसा ही रहेगा तब तक कभी नहीं चलेंगे। यह केवल हिन्दुस्तानी को कृत्रिम रूप से गढ़ने की बात नहीं है कि हिन्दी उर्दू दोनों में जो शब्द आते हैं उन्हें ले लो। वास्तव में ऐसे ही शब्द बोलचाल में प्रचलित हैं, और ऐसे ही शब्द आगे चलकर भी बोलचाल में प्रचलित होंगे*। विद्वानों के साहित्य में हिन्दी उर्दू अलग अलग रहेंगी पर बोलचाल की हिन्दुस्तानी बन कर रहेगी, उसे बनाने का प्रयत्न कोई करे चाहे न करे। किसी भी स्थान की बोलचाल की

* ऐसा होने में रेडियो और सिनेमा बहुत बड़ी सहायता पहुँचा रहे हैं और पहुँचायेंगे। आज हमें रेडियो से शिकायत है और शिकायत का पूरा मौका है। उसे जाने दीजिये। सिनेमा को लीजिये। सिनेमा तो शुद्ध व्यापारिक सिद्धान्तों पर चलता है; वह तो साम्प्रदायिकता से आत प्रीत अफसरों के हाथ में नहीं है, उसे तो जनता से काम है और इस कारण सिनेमा तो बता सकता है कि अधिकाधिक संख्या में जनता किन शब्दों को समझती है। आज हमें सिनेमा से क्यों शिकायत है? यदि सिनेमा 'अन्तर' के बजाय 'कर्म', 'सहाय-

भाषा सदैव एक रही है और एक रहेगी, और उसमें हजारों शब्दों के दो दो पर्याय न कभी चले हैं और न कभी चल सकते हैं। यदि एक 'भूति' के बजाय 'हमदर्शी', 'मनुष्यता' के बजाय 'इन्सानियत', अर्थात् वे सभी उर्दू शब्द जो हिन्दी उर्दू दोनों में आते हैं और इस कारण जिन्हें उत्तरी भारत की (अर्थात् हिन्दी उर्दू प्रदेश की) सब जनता समझती है, प्रयुक्त करता है और उनके हिन्दी पर्यायों को कभी प्रयुक्त नहीं करता, तो वह क्या बुरा करता है ? सिनेमा भाषा का प्रेमी नहीं, रुपये का प्रेमी है। उसे हमारे शब्दों से प्रेम क्यों हो, जब हमें ही उनसे प्रेम नहीं, हम ही उनके उर्दू पर्यायों को धड़ल्ले से लिखते हैं (और बोलते तो केवल उर्दू शब्द ही हैं) ? सिनेमा के पात्र उन शब्दों को क्यों बोलें जिन्हें हम ही नहीं बोलते, और उन शब्दों को क्यों न बोलें जिन्हें सब बोलते हैं ? जब कोई चित्र-निर्माता विशेष कारणों से, विशेष कर धार्मिक चित्रों में, ऊपर वाले उर्दू शब्दों के बजाय हिन्दी शब्दों का प्रयोग करता है, तब हम उसकी प्रशंसा के पुल बाँध देते हैं और 'हिन्दी-प्रेम' के लिये उसे बधाई देते हैं। परन्तु यह सोचकर शर्म नहीं आती कि इसकी प्रशंसा करने की नौबत ही क्यों आई। यह एक ऐसी साधारण बात क्यों नहीं है जिसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता ही न हो और जिसे प्रत्येक चित्र-निर्माता स्वयम् अपने लाभ के लिये करना आवश्यक समझे ? वास्तव में हम अपनी कमज़ोरी की तरफ़ देखना नहीं चाहते। यह सोचने नहीं बैठते कि ऐसे चित्र कितने हैं जिनमें इन हिन्दी शब्दों का प्रयोग हुआ है (और क्यों हुआ है) और ऐसे चित्र कितने हैं जिनमें इनके उर्दू पर्यायों का प्रयोग हुआ है, और इस व्यापारिक युग में ऐसे, हिन्दी शब्दों वाले, दो चार चित्र भी कब तक बन सकेंगे। ऐसा क्यों है कि कलकत्ता (अर्थात् बंगला प्रदेश) और बम्बई (अर्थात् मराठी-गुजराती प्रदेश) में जो 'हिन्दुस्तानी' के चित्र बनते हैं उनमें भी यही उर्दू शब्द आते हैं। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि यह बात कि हमारे हिन्दी शब्द अन्य भाषाओं के अधिक निकट हैं बिल्कुल बेकार है। वास्तव में हिन्दी प्रदेश में प्रचलित हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही मुख्य है ?

सारांश यह है कि सिनेमा का नामज़ा एक ऐसा मामला नहीं है जिसे हम आन्दोलन चलाकर या केन्द्रीय धारा-सभा में उठा कर ठिकाने पर ला सकें।

प्रदेश में दो साहित्यिक भाषायें चलती हैं तो ज्यों ज्यों उस प्रदेश की बौद्धिक उन्नति होगी, वहाँ की जनता के सामाजिक जीवन का स्तर ऊँचा होगा और समाग्रों, दफ्तरों कचहरियों, धारा-समाग्रों आदि में आपस में बैठकर वाद-विवाद करने और विचारों का आदान-प्रदान करने के अवसर आयेंगे, त्यों त्यों उस प्रदेश की बोलचाल में आवश्यक शब्द उन दोनों साहित्यिक भाषाओं में से छुँट छुँटाकर आयेंगे, और सबसे पहले वे शब्द आयेंगे जो दोनों साहित्यिक भाषाओं में कामन हैं, अर्थात् दोनों में चलते हैं और इसलिये दोनों के पढ़ने वालों को मालूम हैं, और इन्हीं शब्दों को सिनेमा, रेडियो, आदि ग्रहण करते जायेंगे। उदाहरण के लिये, यदि हिन्दी साहित्य में 'तक़रीर', 'मक़सद', 'स्यासी' और 'बज़ारत', 'सदर' और 'सदारत' का प्रवेश हो गया तो हिन्दी प्रदेश की बोलचाल में 'भाषण', 'उद्देश्य', 'राजनीतिक', 'मंत्रि-मंडल', 'सभापति', और 'सभापतित्व' कभी नहीं आयेंगे, क्योंकि उर्दू साहित्य में इनका प्रयोग भूलकर भी नहीं होता, और न उर्दू वाले भूलकर भी इन्हें बोलते हैं, और जिस प्रकार आज हम भीकते हैं कि ".....हम सजा और शुरु को तो सहज समझते हैं और दण्ड तथा आरम्भ को कठिन। मुश्किल तो हमारे लिये सहज होता है पर कठिन कठिन ही रह जाता है।

वह तो अपनी कमज़ोरी दूर करने से डीक होगा। जब तक अपनी कमज़ोरी दूर न की जायगी तब तक लाख गला फाड़िये, सिनेमा जो अब कर रहा है, वही करता रहेगा। रेडियो में भी यही बात होगी, क्योंकि सभी प्रगतिशील देशों में (जैसे अमरीका) रेडियो एक व्यापारिक संस्था बना दिया गया है और व्यापारिक सिद्धांतों पर चलता है। बाद को चल कर भारत का रेडियो भी एक व्यापारिक संस्था हो जायगा और तब उसे कोई राजनीतिक चाल या दबाव सिनेमा की नक़ल करने से न रोक सकेगा। दूसरे शब्दों में एक ओर तो सिनेमा और रेडियो केवल बोलचाल में प्रचलित शब्दों का प्रयोग करेंगे और दूसरी ओर इन शब्दों का इस प्रकार प्रचार कर उन्हें बोलचाल में से कभी निकलने न देंगे।

हमें पृथ्वी की जगह जमीन, आकाश की जगह आसमान और अन्यास की जगह आदत कहने की आदत पड़ गई है....." ('अच्छी हिन्दी', पृष्ठ १८५), उसी प्रकार तीस वर्ष बाद दूसरी पीढ़ी 'तकरीर', 'मकसद', 'त्यासी', 'बज़ारत', 'सदर', 'सदारत'.....को सरल और 'भाषण', उद्देश्य', 'राजनीतिक', 'मंत्रि-मंडल', 'समापति', 'समापन'.....को कठिन समझेगी, और फिर धीरे धीरे लिखित हिन्दी ने भी इन हिन्दी शब्दों का बहिष्कार हो जायगा, और इस सबके लिये वे हिन्दी लेखक ही उत्तरदायी होंगे जो आज उर्दू-कोष से छुट्ट छुट्ट कर उर्दू शब्दों को हिन्दी में घुसेड़ने में ही अपना पाँडित्य समझते हैं । कोई जीवित साहित्यिक भाषा, यदि उसे जीवित रहना है, बोलचाल की उपेक्षा नहीं कर सकती । यदि हिन्दी में साधारण बोलचाल में सब जगह प्रचलित उर्दू शब्दों के स्थान में हिन्दी शब्दों का ज़बर्दस्ती प्रयोग किया गया, तो वह संस्कृत के समान मृत-भाषा हो जायगी, और यदि हिन्दी में बिना मर्यादा के और अनावश्यक उर्दू शब्द घुसेड़ने की यही प्रवृत्ति रही और हिन्दी जीवन के साथ भी चली, तो कालान्तर में साहित्यिक हिन्दी भी उर्दू में परिणत हो जायगी, और जो हिन्दी शब्द आज अपने उर्दू पर्यायों के साथ साथ हिन्दी में दिखाई देते हैं वे एक एक करके विलकुल लुप्त हो जायेंगे । बोलचाल की वास्तविक कामन भाषा तो उर्दू होगी ही, और उसी में सरकारी काम होगा, रेडियो बोलेगा और सिनेमा चित्र बनायेगा ।

इसका परिणाम भी समझ लेना चाहिये । अपने प्राचीन शब्दों के छूट जाने से अपना प्राचीन साहित्य भी हमसे दूर हो जायगा और हमारी संस्कृति तथा सभ्यता को एक ज़बर्दस्त धक्का लगेगा । भाषा संस्कृति और सभ्यता का जीता जागता प्रतीक होती है । भाषा का स्वाभाविक विकास या परिवर्तन होना और बात है, उसका चिह्न और दूषित होना और बात । मध्यदेश की भाषा संस्कृत बुद्ध के समय में बोलचाल में पाली का रूप धारण कर चुकी

थी, परन्तु पाली उसी समयता और संस्कृति का वाहन थी और उसमें संस्कृत साहित्य स्वाभाविक रूप से उतरता चला आता था। पाली भी बदली, परन्तु स्वाभाविक रूप से। भारत पर यूनानियों के आक्रमण के फलस्वरूप ग्रीक के प्रभाव के कारण भारतीय भाषा के विकृत होने का भय उत्पन्न हुआ। परन्तु भारतीय समाज उस समय सजग था। उसने भाषा को विकृत होने से बचाने का पूरा प्रयत्न किया। समाज के नेताओं ने आदेश दिया, 'कण्ठेऽपि प्राणो यावन्ती न वदेत्'। क्यों? उन्हें शुद्ध संस्कृत या पाली लिखने में तो कोई रोकता न था। परन्तु नहीं, उन्होंने समझा कि यदि बोलचाल में ग्रीक शब्द भारतीय शब्दों को निकालकर घुस गये तो कालान्तर में उनका साहित्य में भी घुस जाना अनिवार्य है, और इससे संस्कृति की अवश्य हानि होगी। संस्कृत की इस अग्रगण्य पीढ़ी में आज हिन्दी है। आज हिन्दी को वही काम करना है जो संस्कृत ने, पाली ने और अपभ्रंश ने किया है। हिन्दी के संस्कृत शब्द हमें अपने अतीत से, अपने प्राचीन साहित्य से जोड़ते हैं। उनमें जाति का जीवन है, जाति को मर मिटने की प्रेरणा देने की शक्ति है। हिन्दी जानने वाले के लिये संस्कृत अपेक्षाकृत सुगम है। हिन्दी के संस्कृत शब्दों के कारण हिन्दी में संस्कृत साहित्य उतारना, उसका अनुवाद करना सरल है। अगर हम आज अपनी मूर्खता के कारण हिन्दी में अपने शब्दों के होते हुये अरबी फ़ारसी के शब्द भरते चलेंगे तो परिस्थिति ऐसी है कि हमारे अपने शब्द हमसे सदा के लिये छूट जायेंगे और हम अपनी सारी पौरुष सम्पत्ति से हाथ धो बैठेंगे। आजकल के हजारों हिन्दी कवियों और लेखकों से भी हाथ धो बैठेंगे। हिन्दी में अनावश्यक अरबी फ़ारसी शब्द भरने की जो प्रवृत्ति आज हम देख रहे हैं, उससे हमें यही खतरा है। जो हिन्दी लेखक एक प्रचलित हिन्दी शब्द के स्थान में उर्दू शब्द का प्रयोग करता है, वह साउदे के शब्दों में अपनी मातृ-भाषा के प्रति अनुम्य असाध ता करता ही है, परिस्थिति ऐसी है कि वह एक प्रकार से हिन्दी शब्द की कन्न तैयार करता है।

२. द्वैतवादियों के कुछ तर्क

हिन्दी की इस द्वैत की बीमारी को स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिये कुछ तर्क भी उपस्थित किये जाते हैं। उन पर भी विचार कर लेना चाहिये।

(१) प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को कैसे छोड़ा जा सकता है।

अवश्य नहीं छोड़ा जा सकता। इतना ही नहीं, प्रचलित शब्द छोड़ने से भी नहीं छूट सकते। वास्तव में इसीलिये हिन्दी वालों को सावधान करने की ज़रूरत है। परन्तु 'प्रचलित' से तात्पर्य क्या है? संसार की जीवित भाषाओं का ऐसा कौनसा शब्द है जो कहीं न कहीं प्रचलित नहीं है? जिस प्रदेश को हम 'हिन्दी प्रदेश' कहते हैं (अर्थात्, युक्त-प्रान्त, बिहार, मध्य-प्रान्त और राजस्थान) उसमें प्रचलित अर्थात् उसकी विभिन्न बोलियों में प्रचलित सभी शब्द क्या हिन्दी में हैं अथवा लिये जा सकते हैं? यदि केवल खड़ीबोली (लिखित खड़ीबोली वा बोली जाने वाली खड़ीबोली?) में प्रचलित शब्दों को 'प्रचलित' की उपाधि दी जा सकती है, तो उर्दू का ऐसा कौनसा शब्द है जो 'प्रचलित' नहीं है—और वह भी इसी हिन्दी प्रदेश में? फिर हिन्दी में केवल इतने ही उर्दू शब्दों को घुसेड़ कर क़नात क्यों कर ली जाती है? हिन्दी को उर्दू से भिन्न रखने की ही क्या ज़रूरत है? चूँकि मुसलमान उर्दू छोड़ नहीं सकते और न उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, हिन्दी वाले ही हिन्दी को उर्दू बना दें—कामन भाषा भी बन जाय और हिन्दी उर्दू का भगड़ा भी खतम हो जाय। सब उर्दू शब्द 'प्रचलित' ही होंगे। फिर, इंगलिस्तानी वा वायू हिन्दुस्तानी भी तो खड़ी बोली है। उसके 'प्रचलित' अंगरेज़ी शब्द क्यों छोड़ दिये जाते हैं? 'ख़त', 'तक़रीर', 'स्वासी', 'वज़ारत'.....आदि, आदि ही क्यों? 'लेटर', 'स्वीच', 'पोलीटिकल', 'मिनिस्ट्री' आदि, आदि भी क्यों नहीं?

[मज़ा इस बात का है कि केवल हिन्दी वालों को 'प्रचलित' अरबी फारसी शब्दों की चिन्ता है, उर्दू वालों को 'प्रचलित' हिन्दी शब्दों की चिन्ता नहीं। हिन्दी वाले आप उर्दू शब्दों को 'प्रचलित' करते जाते हैं और फिर कहते हैं, 'प्रचलित' उर्दू शब्दों को कैसे छोड़ा जा सकता है !]

यदि केवल साधारण, नित्यप्रति की बोलचाल में प्रचलित शब्द ही 'प्रचलित' कहे जा सकते हैं, और 'साधारण', 'नित्यप्रति' की परिभाषा ऐसी है कि उसमें 'स्पीच', 'पोलिटिकल', 'मिनिस्टरी' के लिये गुन्जाइश नहीं, तो 'तक़रीर', 'स्यासी' और 'बज़ारत' के लिये भी गुन्जाइश नहीं हो सकती। (और फिर 'प्रचलित' का कांटूर कैसे खींचा जाय ?) यदि ऐसा है कि उसमें सदैव 'आसमान', 'ज़रूरत' और 'किनारा' आते हैं, 'आकाश', 'आवश्यकता' और 'तट' कभी नहीं, तो हिन्दी में 'आकाश', 'आवश्यकता' और 'तट' कभी आना ही नहीं चाहिये, सदैव 'आसमान', 'ज़रूरत' और 'किनारा' ही आना चाहिये। तात्पर्य यह कि इस 'साधारण', 'नित्यप्रति' की परिभाषा की जानी चाहिये, 'प्रचलित' की कोई मर्यादा निश्चित होनी चाहिये और वास्तव में 'प्रचलित' और उनके अप्रचलित पर्यायों का जो द्वैत हिन्दी को व्याप्त किये हुये है, उसे दूर करना चाहिये।

(२) हमें अपना हाज़मा बढ़ा लेना चाहिये।

ठीक है, परन्तु अंट शंट, बिना सोचे समझे, असमय कुसमय और बिना ज़रूरत खाने से हाज़मा बढ़ता नहीं, विगड़ता है। अपना स्वस्थ अंग काट काटकर फेंकते जायँ और माँग माँग कर उसकी जगह चपेकते जायँ, तो यह कोई बुद्धिमानी की बात न होगी। अपने घर का माल छोड़कर अन्यत्र भील माँगने जाना हाज़मा बढ़ाना नहीं है। जो भोजन खाया जाय—अधिक मात्रा में या कम मात्रा में, वह आवश्यक होना चाहिये। हिन्दी में सम्पूर्ण उर्दू कोष और सम्पूर्ण अँगरेज़ी-कोष (इंगलिस्तानी को 'हज़म' करने के लिए) हज़म करने की शक्ति नहीं है—चूरन खाकर भी नहीं। और न प्रत्येक शब्द

के दो दो (यत्कि तीन तीन) पर्याय होना बड़े हुये हाजमे की निशानी है। यह तो घादी है। इसे छौटना है, बढ़ाना नहीं है।

यह तो हाजमा बढ़ाने के विषय की बात हुई जो सदैव लागू है। परन्तु हिन्दी को तो परिस्थिति ही दूसरी है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, एक भी अनावश्यक उर्दू शब्द हजम करने का अर्थ है उसके हिन्दी पर्याय से सदैव के लिये हाथ धो बैठना। यदि हम इसी प्रकार उर्दू शब्द 'हजम' करते चलेंगे तो हिन्दी उर्दू को नहीं बरन् उर्दू हिन्दी को हजम कर जायगी, अर्थात् हिन्दी लुप्त हो जायगी और केवल उर्दू, अपने इसी रूप में, रहेगी। उर्दू ने जमाने से हिन्दी शब्दों को सफलता के साथ मतरुक कर रक्खा है और यह काम अब भी जारी है। यह नहीं हो सकता कि उर्दू वाले तो हजम किया हुआ उगलते जायँ और हिन्दी वाले स्वदेशी माल छोड़कर विदेशी माल निगलते जायँ। यदि हिन्दी को समाप्त करना ही अभीष्ट हो तो बात दूसरी है, परन्तु यदि हिन्दी की रक्षा करना ही है तो बहुत सोच समझ कर खाना होगा।

(३) सभी भाषाएँ अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करती हैं।

अवश्य ग्रहण करती हैं। परन्तु वे ही शब्द ग्रहण किये जाते हैं जो भाषा की अभिव्यंजना शक्ति के पूरक होते हैं और अपने भाण्डार में नहीं होते। आखिर उर्दू भी तो एक भाषा है जो हिन्दी के साथ साथ उसी प्रदेश में प्रचलित है। परन्तु उर्दू में तो हिन्दी जैसी धाँधली देखने में नहीं आती। उर्दू भी हिन्दी से शब्द ग्रहण करती है, परन्तु आँख मीच कर, अनावश्यक शब्द नहीं। हिन्दी को ही 'समापति' या 'अभ्यक्ष' होते हुए 'सदर' की क्या आवश्यकता पड़ गई? अँगरेजी ने भी हजारों शब्द विदेशी भाषाओं से ग्रहण किये हैं परन्तु अपने शब्दों के होते हुये नहीं। 'Friend' होते हुये अँगरेजी 'मित्र' या 'दोस्त' कभी ग्रहण नहीं कर सकती। हिन्दी ने भी बंगला, अँगरेजी, आदि भाषाओं से शब्द ग्रहण किये हैं और आगे भी करेगी, परन्तु केवल आवश्यक शब्द ही। 'मित्र' होते हुये हिन्दी 'Friend' ग्रहण नहीं

कर सकती (यद्यपि वह ईंगलिस्तानी में चलता भी है) । यही बात उर्दू शब्दों के साथ लागू होनी चाहिये । उर्दू हिन्दी की एक शैली है, इस कारण उर्दू शब्दों के साथ रियायत नहीं की जा सकती । यदि उर्दू के हिन्दी की एक 'शैली' होने के कारण हिन्दी में आने वाले अनावश्यक उर्दू शब्दों पर आपत्ति नहीं की जा सकती, तो उस 'शैली' की लिपि में हिन्दी लिखे जाने पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, अर्थात् आवश्यकता न होने पर भी एक अतिरिक्त लिपि, उर्दू लिपि, हिन्दी के लिये स्वीकृत हो जाना चाहिए । वर्धा से भी एक कदम आगे !

फिर ईंगलिस्तानी भी हिन्दी की एक 'शैली' है, इसलिये हिन्दी में अनावश्यक, ईंगलिस्तानी के अँगरेज़ी शब्दों पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, और रोमन लिपि स्वीकृत होने पर भी नहीं !

वास्तव में 'उर्दू हिन्दी की एक शैली है', इसी कारण हिन्दी को उर्दू से सबसे अधिक खतरा है, और इसी कारण उर्दू हिन्दी का मैदान मार सकती है और मार रही है । यह शैलीवाद हिन्दी को बहुत हानि पहुँचा चुका । अब इसका अन्त होना चाहिये । जिस प्रकार हम उर्दू लिपि से द्वेष नहीं करते, परन्तु उसमें हिन्दी लिखने के लिये तैयार नहीं, उसी प्रकार हम उर्दू शब्दों से द्वेष नहीं करते, परन्तु अपने शब्द होते हुये हम उन्हें हिन्दी में स्थान देने के लिए तैयार नहीं । फिर, यह शैलीवाद एकतरफा नहीं चल सकता । उर्दू भी हिन्दी को अपनी एक 'शैली' मान कर हिन्दी शब्दों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का तैयार है जैसा व्यवहार उर्दू शब्दों के साथ करने की सलाह हमें दी जाती है ?

यदि हिन्दी और उर्दू दोनों के लिखने वाले (और पढ़ने वाले) एक ही होते और दोनों में (और दोनों लिपियों में) हिन्दी उर्दू के शब्द एक समान आते होते तो भी विशेष हानि न थी, क्योंकि अन्त में स्वाभाविक रूप से छूट छूटाकर वे ही शब्द रहते जिन में जीवित

रहने की नैसर्गिक शक्ति होती और जो समाज को भा जाते । यदि उर्दू न होती और मैदान में एकमात्र हिन्दी होती तब तो हिन्दी में अनावश्यक और आवश्यक अरबी फारसी शब्द आने से बिलकुल हानि न होती । जो शब्द अनावश्यक सिद्ध होते वे पुराने, जमे हुये शब्दों के मुकाबले में अपने आप मर जाते और आवश्यक शब्द भाषा में स्वयं जाते— किसी दल को यह आग्रह न होता कि नहीं, हमारी भाषा में तो केवल यहो अरबी फारसी शब्द आँवेंगे, और न किसी दल को एक भिन्न लिपि में लिख कर एक भिन्न शैली और एक भिन्न साहित्य की सृष्टि करने का आग्रह होता । यदि आज अँगरेज़ी में सौ दो सौ अँगरेज़ी शब्दों के अरबी फारसी पर्याय जोड़ भी दिये जायँ, तो चूँकि किसी अँग्रेज़ी लेखक को इन अरबी फारसी शब्दों के प्रति कोई आग्रह न होगा, वे चलेंगे ही नहीं—अधिक से अधिक कोष में पड़े रहेंगे । स्पष्ट है कि हिन्दी क अँगरेज़ी या किसी अन्य प्रदेश की एक लिपि में, एक संस्कृति वाले लेखकों द्वारा लिखी जाने वाली एकमात्र भाषा से तुलना नहीं की जा सकती । हिन्दी की विशेष परिस्थिति है । हिन्दी का पाला उर्दू से पड़ा है जिससे उसका पग पग पर मुकाबला है । और उर्दू ने प्रण कर रखा है कि वह हिन्दी का शब्द चारों तरफ से निराश और लाचार होकर ही लेगी और वह अपना प्रण पूर्ण रूप से निभा रही है । (उर्दू लिपि की अपूर्णता के कारण इस प्रण के निभाने में और भी सहायता मिल रही है ।) उर्दू वाले हिन्दी शब्दों का बहिष्कार करने पर तुल हुये हैं । फिर हिन्दी किस प्रकार सब कुछ भूल कर 'उदार' बन जाय ? यह 'उदारता' तो मौत का फन्दा प्रमाणित होगी ।

(४) हिन्दी में हिन्दी शब्दों के उर्दू पर्यायों को ध्वनि का अन्तर करके लिया जा सकता है ।

परन्तु कितने शब्दों को लिया जा सकता है ? 'आशायी' और

‘दशमलव’, ‘आकाश’ और ‘आसमान’ में ध्वनि का अन्तर किस प्रकार किया जाय ? और फिर ध्वनि का अन्तर इसलिये ज़बर्दस्ती करें कि उन शब्दों को किसी प्रकार खपाना ज़रूरी है अथवा आवश्यकता के अनुसार करें ?

अँगरेज़ी में तीन शब्द हैं, ‘Confer’, ‘Advise’ और ‘Consult’ । तीनों में भेद है । हमारे सामने भी तीन शब्द हैं, ‘परामर्श’, ‘सलाह’ और ‘मशविरा’, जिनमें से दो—‘सलाह’ और ‘मशविरा’—उर्दू में चलते हैं, तीसरा ‘परामर्श’ नहीं चलता । यदि हम इन्हें अँगरेज़ी के तीन शब्दों के अर्थ में रूढ़ कर लेते हैं, तो क्या ‘परामर्श’ उर्दू में भी चलने लगेगा ? कदापि नहीं । उर्दू वाले या तो ‘सलाह’ और ‘मशविरा’ को ही तीनों अर्थों में रूढ़ कर लेंगे या एक तीसरा शब्द अरबी फारसी से और गढ़ लेंगे । फल यह होगा कि बोलचाल में केवल दो—‘सलाह’ और ‘मशविरा’—ही चलेंगे, और इसलिये ‘परामर्श’ धीरे धीरे हिन्दी साहित्य से भी लुप्त हो जायगा । हिन्दी में ‘दृष्टि’, ‘नज़र’ और ‘निगाह’ तीनों चलते हैं, और कितने ही प्रयोग ऐसे हैं जहाँ पर एक के बजाय दूसरा शब्द नहीं रक्खा जा सकता । परन्तु उर्दू में ऐसे सब प्रयोग केवल नज़र और ‘निगाह’ से हो जाते हैं । उर्दू में ‘दृष्टि’ का प्रवेश नहीं है और न होगा । फलतः साधारण बोलचाल में ‘नज़र’ और ‘निगाह’ ही चलते हैं, ‘दृष्टि’ नहीं चलता । हम हिन्दी वाले ‘Weather’ के लिये ‘मौसम’ और ‘Season’ के लिये ‘ऋतु’ का प्रयोग करते हैं, परन्तु उर्दू वालों ने ‘मौसम’ को दोनों अर्थों में रूढ़ कर लिया है—वे यह भी कहते हैं ‘आज का मौसम अच्छा है’ और यह भी कहते हैं ‘जाड़े के मौसम में ।’ फलतः बोलचाल से ‘ऋतु’ शब्द उठता चला जा रहा है और उसकी जगह भी ‘मौसम’ ले रहा है । श्री राजगोपालाचारी ने फर्माया है कि अँगरेज़ी में कोई कहता है ‘I know it’, कोई ‘I perceive it’,

कोई 'I am sensible of it', कोई 'I have an understanding of it', कोई 'I have a knowledge of it', इसी प्रकार 'हिन्दुस्तानी' में हिन्दी उर्दू के सभी शब्दों के लिये गुन्जाइश हो सकती है और इस प्रकार भाषा 'समृद्ध' हो जायगी (शायद राजा जी तामिल वालों को इस प्रकार तामिल को 'समृद्ध' बनाने की सलाह न देंगे)। प्रथम तो हिन्दी और उर्दू में क्रियाओं, विभक्तियों और थोड़े से देशज शब्दों को छोड़कर और सब शब्द भिन्न भिन्न हैं। आज भी भिन्न शब्दों की संख्या २० हजार से अधिक है, और दिन पर दिन बढ़ती जाती है। जिस भाषा की कुल शब्द-संख्या लगभग ५० हजार हो, उसमें २० हजार शब्दों के—और वह भी ज्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्दों के—२० हजार और पर्याय जोड़ देना भाषा को उस बच्चे के समान बना देना होगा जिसकी टांगें तो दो हों परन्तु दो सिर हों और जुड़े हुये दो पेट हों। वह भाषा काम की चीज़ नहीं रहेगी। वह नुमाइश में रखने की चीज़ हो जायगी। अंगरेज़ी में 'Friend', 'Difference', 'Sky' जैसे हजारों शब्दों के दर्जनों या दो दो पर्याय नहीं हैं और न इस प्रकार के हजारों शब्दों के दो दो पर्यायों में ध्वनि का अन्तर करना संभव है। अंगरेज़ी में सब पारिभाषिक शब्द भी एक ही एक हैं और उनके अर्थ निश्चित हैं, परन्तु हिन्दी और उर्दू के पारिभाषिक शब्द सर्वथा भिन्न हैं। पारिभाषिक शब्दों में ध्वनि का अंतर करना किसी भी प्रकार संभव नहीं, और न हजारों (शीघ्र ही लाखों) पारिभाषिक शब्दों के जोड़े रखकर भाषा से एक दिन भी काम चल सकता है, और न उन्हें प्रत्येक को सिखाया जा सकता है। दूसरे, उर्दू लिपि में हिन्दी के हजारों शब्द लिखे ही नहीं जा सकते। तीसरे, यदि अंगरेज़ी में एक एक शब्द के दर्जनों पर्याय हैं तो एक एक शब्द के दर्जनों अर्थ भी हैं, और हमें अपनी भाषा को 'समृद्ध' बनाने के लिये अंगरेज़ी के सभी पर्यायवाची शब्दों के उतने ही पर्याय ढूँढ़ने की ज़रूरत नहीं—हम भी अपना एक

ही शब्द कई अर्थों में रूढ़ कर सकते हैं जैसे कितने ही शब्द इस समय भी कई कई अर्थों में रूढ़ हैं, हिन्दी में भी और उर्दू में भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि अँगरेज़ी में एक एक शब्द के कई कई पर्याय हैं तो उनका प्रयोग, ध्वनि का अन्तर करके या ध्वनि का अन्तर किये बिना, अँगरेज़ी के सभी लेखक करते हैं और उन्हें एक ही लिपि में लिखते हैं—न अँगरेज़ी के लेखक हिन्दी उर्दू के लेखकों की भाँति दो दलों में बँटे हुये हैं और न अँगरेज़ी हिन्दी उर्दू की भाँति दो लिपियों में लिखी जाती है। स्पष्ट है, अँगरेज़ी की तुलना हिन्दी या हिन्दुस्तानी से नहीं की जा सकती, और न अँगरेज़ी कोष की तुलना 'हिन्दी कोष + उर्दू कोष' से की जा सकती है। यदि हम आज अपने शब्दों के साथ उर्दू पर्याय जोड़ भी लें, तो उर्दू लेखक हिन्दी पर्यायों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। हम यदि 'speech', 'discourse', 'lecture', 'talk', 'address', आदि की ध्वनि को स्पष्ट करने के लिये 'भाषण', 'वक्तृता', 'व्याख्यान', 'प्रवचन', 'अभिभाषण', आदि के साथ 'तकरीर' को और जोड़ भी लें, तो भी उर्दू वालों को सिवा 'तकरीर' के और कोई शब्द स्वीकार न होगा (और होगा भी तो 'lecture', 'speech', 'talk', आदि, हिन्दी का शब्द नहीं), और फलतः सब अर्थ 'तकरीर' में ही रूढ़ हो जायेंगे, केवल 'तकरीर' बोलचाल में चलेगा और शेष सब मर जायेंगे।

हमसे प्रायः कहा जाता है, अरे, एक एक शब्द के अनेक हिन्दी पर्याय याद करते हो या नहीं (कितने शब्दों के?), एक उर्दू पर्याय (क्या वह सदैव एक ही होगा?) और याद कर लो। उत्तर में इतना कहना काफी है—क्या उर्दू वाले भी उर्दू पर्यायों के साथ एक एक हिन्दी पर्याय याद करने को तैयार हैं?

सारांश यह कि ध्वनि में अन्तर करके उर्दू शब्द ग्रहण करने वाला खेल एक हद तक ही—बहुत कम शब्दों के विषय में—खेलना संभव है, और

उस हद तक भी अपने शब्दों के मृत हो जाने का पूरा भय है क्योंकि दूसरी पार्टी यह खेल हमारे साथ खेलने के लिये तैयार नहीं।

(५) उर्दू लेखक भाषा के मामले में सजग और जागरूक (language conscious) हैं, हिन्दी लेखक नहीं हैं।

इसी का तो रोना है। मुसलमानों ने ज़माने से उर्दू के विषय में प्यूरिटन (विशुद्धतावादी) रुख ग्रहण कर रक्खा है। वे अपनी भाषा और संस्कृति के मामले में जागरूक और सावधान रहे हैं, और हैं। वे जान-बूझकर हिन्दी शब्दों का वहिष्कार करते हैं। उनकी देखा देखी उर्दू के हिन्दू लेखकों ने भी वैसा ही किया (और कर रहे हैं), परन्तु हिन्दी वालों ने भाषा का महत्व नहीं समझा, उन्होंने उसकी शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया और बिना संकोच और सोच-विचार के अपनी भाषा में अनावश्यक अरबी-फारसी शब्दों को घुसने दिया। इसी प्रवृत्ति को अब बदलना है। यदि इस प्रवृत्ति को नहीं बदला गया तो हिन्दी उर्दू में बदल जायगी। सदैव से इतिहास में दो भाषाओं (या दो शब्दों) की प्रतिद्वन्द्विता में उसी की भाषा (या शब्द) की विजय होती आई है जो उसका अपेक्षाकृत अधिक ध्यान रखता है और उससे अधिक दृढ़ता के साथ चिपका रहता है।

३. क्या करें ?

अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी के इस द्वैतवाद को किस प्रकार दूर किया जाय, और इससे हिन्दी को जो खतरा पैदा हो गया है, उससे हिन्दी की रक्षा किस प्रकार की जाय। यह हिन्दी के विद्वानों, हिन्दी-प्रेमियों, हिन्दी-हितैषियों और हिन्दी की संस्थाओं के लिये अत्यन्त विचारणीय और चिन्तनीय विषय होना चाहिये। इस सम्बंध में शीघ्र ही कदम उठाना चाहिये। विद्वानों के विचारार्थ कुछ सुझाव नीचे दिये जाते हैं।

(१) हिन्दी का स्वरूप निश्चित हो जाना चाहिये। हिन्दी में इस समय जो घाँवली चल रही है, उसे समाप्त कर हिन्दी का एक निश्चित,

सर्वमान्य और सर्वसुलभ स्वरूप उपस्थित किया जाय । हिन्दी के चोटी के विद्वान् भाषा का आदर्श सामने रखें और हिन्दी के जो लेखक मनमानी करने पर तुले हुये हैं उन पर अंकुश लगायें । हिन्दो-प्रदेश बहुत विशाल है, और दिन पर दिन हिन्दी का क्षेत्र और बढ़ता जा रहा है । यदि हिन्दी के स्वरूप को निश्चित करने का और उसे परिमार्जित और परिष्कृत करने का प्रयत्न न किया गया तो 'हिन्दी' नाम की कोई एक ऐसी भाषा न रहेगी जिसका हिन्दी-क्षेत्र के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक ही रूप हो और जिसे एक लेखक जिस रूप में लिखे उसी में दूसरा लेखक लिखे । भाषा अपना काम तभी कर सकती है जब वह जैसी यहाँ लिखी जाती है वैसी ही हजार मील की दूरी पर लिखी जाय । हिन्दी के स्वरूप को निश्चित करने के विषय में व्याकरण (मुख्यतः लिंग और वचन), स्पेलिंग (उदाहरणार्थ, संबंध या सम्बन्ध), शब्दों के रूप (उदाहरणार्थ, कोठरी हो या कोठड़ी, बौछार या बौछाड़, अमरीकी या अमरीकन, जादगा, जावेगा, जायेगा या जाएगा (या जाओगा), मौसम या मौसिम, पहले या पहिले, वापस या वापिस, सिर या सर, डिब्बा या डब्बा, घबरा या घबड़ा, खेती बारी या खेती बाड़ी, तबियत या तबीअत, फल्ल या फसल, बूटेन या बरतानिया, बूटिश या बर्तानवी, सोवियत या सोवियट, अतलांतिक या अटलांटिक, अमेरिका या अमरीका, स्याम (देश) या श्याम (देश), बर्मा या ब्रह्मा, दक्खिन, दक्खन या दक्षिण, पूर्व या पूरब, पच्चीस या पच्चिस, चवालीस, चवालिस या चौवालीस, आदि, आदि), आदि सम्बंधी कितनी ही बातें हैं जिन्हें निश्चित करने की आवश्यकता है*,

* श्रीयुत रामचंद्र वर्मा ने अपनी बहुमुख्य पुस्तक 'अच्छी हिन्दी' में ऐसी बहुत सी बातों की ओर ध्यान खींचा है । उन्होंने भाषा और लिपि की अनेक आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान दिखाया है । हर्ष का विषय है कि काशी में एक भाषा-संस्कार-समिति बनी है जिसका उद्देश्य भाषा का संस्कार करना है । यह समिति उस संगठन का बीज-रूप हो सकती है जिसकी हिन्दी के स्वरूप को निश्चित करने के लिये आवश्यकता है ।

परन्तु यहाँ केवल अरबी फारसी शब्दों के विषय में हिन्दी के स्वरूप के निश्चयीकरण पर थोड़ा सा विचार किया जायगा । !

जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है, अरबी फारसी शब्दों के संबंध में हमें प्रचलित-वाद से सहायता नहीं मिलती । हिन्दी-प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ के कुछ लोग 'जुमा', 'जुमेरात' और 'पीर' न बोलते हों, परन्तु इस कारण वे हिन्दी में 'शुक्र', 'बृहस्पत' और 'सोमवार' के साथ साथ नहीं लिये जा सकते । और हिन्दी-प्रदेश में शिक्षित समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 'फ्राइडे', 'थर्सडे', 'मंडे', 'संडे', आदि न बोलता हो (खड़ी बोली में ही), परन्तु इस कारण वे भी हिन्दी में नहीं लिये जा सकते । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सब अरबी फारसी शब्दों को हिन्दी में से निकाल देना चाहिये । हमें बहुत से अँगरेजी शब्दों को रखना है और आगे भी बहुत से अँगरेजी शब्दों को लेना है । इसी प्रकार हमें बहुत से अरबी फारसी शब्दों को रखना है और आगे भी बहुत से अरबी फारसी शब्दों को लेना है । क्या अँगरेजी और क्या अरबी फारसी, दोनों के विषय में हमारे सिद्धान्त एक से होने चाहिये । अन्तर केवल इस बात से पड़ता है कि खड़ी बोली लिखने वालों में, कम से कम अभी तक, ऐसा कोई दल नहीं जिसका अँगरेजी शब्दों अर्थात् 'इङ्गलिस्तानी' के प्रति आग्रह हो । फलतः अनावश्यक अँगरेजी शब्द साहित्य में प्रवेश नहीं करने पाते । सब खड़ी बोली लिखनेवाले—हिन्दीवाले और उर्दूवाले—लिखते समय अँगरेजी शब्दों से सतर्क रहते हैं, उन्हें बोलचाल में प्रचलित होते हुए भी नहीं लिखते यदि उनके अपने अपने पर्याय मौजूद हैं या बनाये जा सकते हैं, और प्रत्येक अँगरेजी शब्द को ठोंक बजा कर और नितान्त आवश्यक समझ कर ही लिखते हैं । उर्दू वाले इसी प्रकार हिन्दी शब्दों से भी सतर्क रहते हैं, परन्तु हिन्दी वाले अरबी फारसी शब्दों को अपना ही माल समझते हैं और इच्छा-नुसार चाहे जिस अरबी फारसी शब्द को ला बैठालते हैं—कभी यह सोचने

का कष्ट नहीं करते कि उधार मांगने की आवश्यकता भी है या नहीं, और न यह सोचते हैं कि ऐसा करने का क्या परिणाम हो रहा है और अपने घर की दाँल पर क्या गुज़र रही है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि अरबी फारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित होनी चाहिये, और जो अरबी फारसी शब्द आवश्यक हैं अथवा जिन्हें परिस्थिति देखते हुये रखना अभीष्ट है उन्हें छोड़ कर शेष का वहिष्कार कर देना चाहिये और भविष्य के लिये भी बिना सोचे समझे अनावश्यक उर्दू शब्दों को हिन्दी में घुसेड़ने की बढती हुई प्रवृत्ति का दमन कर उन सिद्धान्तों को स्थिर कर देना चाहिये जिनके अनुसार अरबी फारसी शब्द ग्रहण किये जा सकते हैं । हिन्दी के एक स्टैंडर्ड कोष का निर्माण किया जाय जिसमें शब्द निश्चित किये हुये रूप, निश्चित की हुई स्पेलिंग में, निश्चित की हुई लिंग के संकेत, आदि के साथ तो छुपें ही, उसमें केवल उन्हीं अरबी फारसी (या अँगरेज़ी) शब्दों का समावेश किया जाय जो हिन्दी में ग्रहीत माने जायँ । जिन उर्दू शब्दों का हिन्दी से वहिष्कार होना चाहिये उनको एक तालिका अलग से भी सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

स्पष्ट है, यह स्टैंडर्ड कोष हिन्दी-शब्द-सागर से बहुत भिन्न होगा । हिन्दी-शब्द-सागर में से वे सब अरबी फारसी शब्द निकालना पड़ेंगे जिनको हिन्दी में स्थान नहीं दिया जा सकता । यदि नागरी प्रचारिणी सभा को उर्दू शब्दों और 'उर्दू शैली' से विशेष प्रेम है, तो वह उस 'शैली' के शब्दों को अलग कोष-बद्ध करके उसी 'शैली' की लिपि में छाप दे, और उसे अप-हु-डेट रखने के लिये अपने कोष-फंड का आधा रकबा इयरमार्क कर दे * ।

* जब रूस, चीन, आदि विदेश 'हिन्दी' के स्टैंडर्ड कोष की मांग करें, तो नागरी प्रचारिणी सभा चाहे तो केवल 'हिन्दी' शैली का स्टैंडर्ड कोष भेज दें और चाहे तो उसके साथ उर्दू 'शैली' का उर्दू लिपि में छपा हुआ उर्दू-कोष भी भेज दे । नागरी हिन्दी-कोष में अनुमन-तरकी-उर्दू के पास से

बेचारे हिन्दी के कोष-प्रकाशकों का कागज़ और रुपया और हिन्दी के कोष-पाठकों का समय नष्ट नहीं होना चाहिये ।

ज्यों ज्यों हिन्दी का शब्द-भांडार बड़े त्यों त्यों हिन्दी के स्टैंडर्ड कोष का आकार भी बड़े, परन्तु उसमें सदैव वे ही अरबी फ़ारसी शब्द समाविष्ट किये जायँ जो स्टैंडर्ड हिन्दी में ग्रहीत समझे जायँ। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिस किसी लेखक ने हिन्दी में जिस किसी उर्दू शब्द का प्रयोग कर दिया, उसे हिन्दी कोष में उठा कर धर दिया ।

अरबी फ़ारसी शब्दों की मर्यादा जिन सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित होनी चाहिये, यहाँ उनका आभास देना अनुचित न होगा । इस समय हिन्दी में प्रचलित अरबी फ़ारसी शब्द निम्नलिखित वर्गों में बाँटे जा सकते हैं । ऊपर जो अरबी फ़ारसी शब्द इकट्ठे किये गये हैं वे सब के सब इन वर्गों में विभक्त हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त हिन्दी में प्रचलित कुछ अन्य अरबी फ़ारसी शब्द भी प्रत्येक वर्ग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप पेश किये गये हैं—

(अ) वे अरबी फ़ारसी शब्द जिनके देशज (या संस्कृत तद्भव) पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं और इसलिये जिन्हें हिन्दी में से तुरंत निकाल देना चाहिये । उदाहरण—

तलाश (खोज), सुराख (छेद), सुख (लाल), बज़नी (भारी, गरु), बज़न (बोझ), बर्दाश्त करना (सहना), शोरगुल (हल्ला, दुन्द), तमशा (विल्ला), सहन (आँगन), वेशुमार (अनगिनती), स्वाह (काला), ज़र्द (पीला), आबपाशी (सिंचाई), काश्त (खेती), पैदावार (उपज), जरखेज (उपजाऊ), काश्तकार (किसान), ज़वेर (गहना), आये हुये सम्पूर्ण उर्दू-कोष को समाया हुआ देख कर विदेशों को हैरानी तो न हो और हमें लज्जा और हानि तो न उठाना पड़े । जो भाषा अपने को एक अलग स्वतंत्र भाषा कहती है, अपना अलग नाम रखती है और अपने को अलग लिपि में लिखती है, उसका अपना अलग कोष भी होना चाहिये जो केवल उसी का हो और उसे छोड़ कर और किसी का न हो ।

ज़िक्र (चर्चा), दाग (धब्बा), फतह (जीत), दर्द (पीड़ा, पीर),
 इफरात (बहुतायत), गुम होना (खो जाना), तलाश करना (खोजना,
 ढूँढ़ना), गुफ्तगू (बातचीत), इजाफा (बढ़ोतरी, बढ़ती), क़तरा (बूँद),
 नुक़ता (बिन्दी), रोशनी (उजाला), आवादी (बस्ती), इज़म करना
 (पचाना), ख़त (चिट्ठी), गुज़ारना (बिताना), गुज़रना (निकलना),
 दरियाफ्त (पूछना), जंग (लड़ाई), तरक़ी (बढ़ती), मुदाक़बाद
 (बघाई), ज़ख़म (घाब), ज़ख़मी (घायल), तक्सीम करना (बाँटना),
 दरम्यान (बीच), सख़्त (कड़ा), नज़दीक (पास), मेहमान (पाहुन),
 बग़ैर (बिना), दायरा (घेरा), सलूक (बर्तावा), फर्ज करो (मान लो),
 तारीफ (बड़ाई), हमला (चढ़ाई), तफ़रीह (मन बहलाव), बलबा
 (दंगा), गर्द (धूल), बारिश (मेह), इन्तज़ार (बाट), इस्तमाल करना
 (बर्तना), बू (महक), तरीक़ा (ढंग), ज़िन्न करना (सीखना), साथ
 (छाँई), बुजुर्ग (बड़े बूढ़े), अज़ीज़ (बड़े बूढ़े), अज़ीज़ (सगे संबंधी),
 सबज़ी (तरकारो, भाजी) ताल्लुक (लगाव), तादाद (गिनती), कमरबंद
 (नाला), सैलाब (बाढ़, बहिया), सुबह (सबेरा), दिल (जी), तख़्ती
 (पट्टी), किताब (पोथी), अन्दरूनी (भीतरी), अन्दर (भीतर), दरख़्त
 (पेड़), आहिस्ता (धीरे), ताज़ुब (अचरज), पेशगी (अगाऊ, वयाना),
 मर्तवा (बार), तरफ (ओर), मुलाज़िम (नौकर), मुलाज़मत (नौकरी),
 इन्कार करना (मना करना), सुमानियत (मनाही), राहत (चैन),
 हिफाज़त से (सँभालकर), आमदरफ्त (आना जाना, आवाजाही), ख़रीदना
 (मोल लेना), बुनियाद (नींव), खातिर तबाज़ो (आब भगत), बाक़िफ
 (जानकार), बाक़ियत (जानकारी), ग़ल्ला (अनाज), बीबी (बहू),
 आवाज़ देना (पुकारना, गुहराना), ज़रा (तनिक), ख़ौफ (डर), खून
 (लोहू), चिराग (दिया), काबू (बस), क़ै (उल्टी), क़ै करना (उल्टी
 करना, ओकना), शिकन (सिकुड़न), बुज़दिल (डरपोक), शरीफ (भला)

वह भूलना न चाहिये कि अरबी फारसी और उर्दू का प्रभाव जनता—गाँवों में बसने वाली जनता जो सम्पूर्ण जन-संख्या का ६० प्रतिशत है और शहरों में भी निम्नवर्ग की जनता—की भाषा पर बहुत कम पड़ा है। शहरों में स्त्रियों की भाषा अर्थात् घर के भीतर बोली जाने वाली भाषा—वास्तविक मातृ-भाषा—पर भी विदेशी प्रभाव बहुत कम पड़ा है। अरबी फारसी शब्दों का बाहुल्य तो अदालतों, कचहरियों, दफ्तरों, पुलिस की चौकियों, म्यूनि-सिपैलिटियों, आदि के चारों तरफ मँडराने वाले लोगों की बोलचाल में मिलता है क्योंकि इन सब जगहों में विदेशी शासन ने पहले फारसी को और फिर उर्दू को बैठा रक्खा है। हमारी मानसिक गुलामी ने इन्हीं लोगों की भाषा को प्रधानता दे दी है। (जिस प्रकार आज इंगलिस्तानी की नकल करना शिष्टता का टूट-भार्क बन गया है ; कांग्रेस के नेता आपस में और बोलचाल में उस उर्दू उर्फ हिन्दुस्तानी का प्रयोग नहीं करते जिसे वे जनता के सामने जनता की भाषा कहकर मंच से बोलते हैं, वरन् शुद्ध इंगलिस्तानी बोलते हैं)। अपने को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले, विदेशी शासन और विदेशियत के पीछे नोन सचू बाँधकर चलने वाले, गाँधीवादी, राष्ट्र-वादी, घोर राष्ट्रीयता और शुद्ध स्वदेशी के पुजारी कांग्रेसजनों को भी यही भाषा प्रिय है। उन्हें भाषा छोड़कर शेष सब स्वदेशी और जनता का प्रिय है। भाषा के मामले में अदालतों की भाषा ही उनका आदर्श है। (चाहे जब युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जाकर 'हिन्दुस्तानी' मुन लीजिये ; उदाहरणार्थ, सबके मुँह से 'मुल्क' मुन पड़ेगा—बेचारा देश अपने ही देश में देशियों द्वारा देश से निर्वासित मिलेगा)।, सारांश यह कि 'आमफहम', 'बोलचाल', 'प्रचलित' का माप-दंड शहरों (और वह भी मुख्यतः दिल्ली और लखनऊ के बीच के शहरों) के इसी कलमजीबी, अर्थ-राजनीतिक अत्यल्पसंख्यक वर्ग की बोलचाल (और वह भी घर के बाहर की बोलचाल—मुंशीजी घर में 'जौजे' नहीं, 'हमार मेहरारू' ही कहते

सुन पड़ते हैं) हो गया है। चूँकि इस समय राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी हलचलों में शहरवालों के हाथ में प्रभुत्व है, प्रत्येक बात शहरों के मापदंड से नापी जाती है। विदेशी शासन ने शहरों को गाँवों से और बुद्धिजीवी वर्ग को वास्तविक जनता से इतना दूर कर दिया है कि शहरवाले हर एक बात को अपने दृष्टिकोण से देखने के आदी हो गये हैं। भाषा के मामले में भी यही बात है। लखनऊ में हिन्दुस्तानीवादी बड़े तपाक से पूछेंगे, म्याँ, यहाँ 'अतिथि' कौन बोलता है (विलकुल ठीक), और 'मेहमान' को ('गेस्ट' को नहीं) 'हिन्दुस्तानी' की उपाधि दे देंगे, मानो लखनऊ से तीन कोस पर चारों ओर बसने वाले विशाल जन समुदाय में, जिनसे अवघ आवाद है, चलने वाले 'पाहुन' शब्द का कोई महत्व ही न हो। हिन्दी वाले जब लिखने बैठेंगे तो या तो 'मेहमान' रहने देंगे या उसके स्थान पर 'अतिथि' घर देंगे जिसे कोई नहीं बोलता। 'पाहुन' उन्हें भी नहीं सूझेगा या रुचेगा।

तात्पर्य यह कि हिन्दी वाले, जो अपनी भाषा के लिये जनता की भाषा होने का दावा करते हैं, या तो एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को 'हज़म' कर लेंगे जो दाल में नमक के बराबर भी नहीं है या उनके स्थान में अमर-कोष से शब्द चुन लायेंगे जिन्हें कोई नहीं बोलता—कथा कहते समय पंडितजी भी नहीं बोलते। अपने घर की दौलत—वास्तविक हिन्दी शब्द जो अधिकांश जनता और वास्तविक मातृ-भाषा में प्रचलित हैं—नहीं रखती। यह सत्य है कि हिन्दी में यह प्रवृत्ति उर्दू से आई है (उर्दू का फसाहतवाद), प्राचीन हिन्दी साहित्य में ऐसा नहीं है, उसमें देशज और तद्भव शब्द निसंकोच भाव से और घड़ल्ले से आते हैं और वाद ही को हम उर्दू के प्रवाह में बह गये। परन्तु यदि आज हिन्दी को उर्दू

※ऐसे ही शब्दों के कारण 'हिन्दी' पर 'कृत्रिम' होने का लालछन लगाया जाता है। आगे देखिये।

से लोहा लेना है, बोलचाल की भाषा बनना है तो उसे इस प्रवृत्ति का तुरन्त त्याग कर वास्तव में जनता की भाषा बनना पड़ेगा। 'अनुनय विनय' का मोह त्याग कर 'चिरौरी' को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो शिष्ट बोलचाल में 'आरजू मिन्नत' ही चलता रहेगा। लाख 'प्रतीक्षा' लिखिये, शिष्ट बोलचाल में 'इन्तज़ार' ही चलेगा, परन्तु यदि साहित्यिक हिन्दी 'वाट' अपना लेगी तो शिष्ट बोलचाल में भी 'वाट' चल जायगा और यदि ऐसा नहीं करेगी तो जो जनता आज 'वाट' बोलती है वह भी 'इन्तज़ार' बोलेगी, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक आदमी अपनी से ऊँची श्रेणी के आदमी की बोलचाल को अपनाता है। जब तक साहित्यिक हिन्दी 'चिरौरी', 'वाट' जैसे ठेठ हिन्दी शब्दों को शिष्ट साहित्य में स्थान देगी नहीं, तब तक उच्च श्रेणियों और शहरवालों की इन शब्दों के प्रति किम्भक्त दूर होगी नहीं, और जब तक ये शब्द ऊँची श्रेणियों और शहरवालों की बोलचाल में स्थान पायेंगे नहीं, तब तक इन शब्दों को बोलने वाली जनता भी इन शब्दों को गँचारू समझेगी और इन्हें छोड़कर शिष्ट बोलचाल में प्रचलित अरबी फारसी शब्द अपनाती जायगी। इस प्रकार इन शब्दों को न अपना कर उनके स्थान में विदेशी शब्दों को प्रयुक्त करके एक ओर तो हिन्दी वाले साउदे के शब्दों में * अपनी मातृ-भाषा के प्रति अक्षम अपराध करेंगे और दूसरी ओर अपने इन शब्दों की मौत का कारण बनेंगे।

यदि तनिष्ठ ध्यान से देखा जाय तो हिन्दी में प्रचलित सैकड़ों अरबी फारसी शब्दों के बोलचाल में प्रचलित ऐसे देशज और तद्भव पर्याय मिल

* "Ours is a noble language, a beautiful language. I can tolerate a Germanism for family sake; but he who uses a Latin or a French phrase where a pure old English word does as well, ought to be hung, drawn and quartered for high treason against his mother tongue."

(Southey in 'Essay on Style')

जायेंगे जो या तो उनके अर्थ को शत प्रतिशत व्यक्त करते हैं या उनके भाव को भली भाँति प्रकट करने में समर्थ हैं। हम दफ्तरों की भाषा सुनने और लिखने के इतने आदी हो गए हैं कि ये शब्द कभी कभी ध्यान में नहीं आते। जब लेखक अति साधारण भाव या वस्तु के लिये किसी अरबी फारसी शब्द को सुनता है तो सोचने लगता है कि क्या मुसलमानों के आने से पूर्व हमारी बोलचाल में इसके लिये भी कोई शब्द नहीं था, और कल्पना करता है कि अगर यही बात उसकी माता, दादी या नानी ने कही होती तो किस प्रकार कही होती, और उसे तुरन्त उसका देशज या तद्भव पर्याय सूझ जाता है। ऊपर अरबी, फारसी शब्दों के साथ कोष्ठकों में जितने देशज और तद्भव शब्दों के उदाहरण दिये गये हैं उनमें से एक शब्द भी ऐसा नहीं जिसे लेखक बचपन में अपनी माता के मुख से नित्य न सुनता हो (और जिसका अरबी फारसी पर्याय उनके मुख से एक बार भी सुना हो) और जिसे वह अब भी घर में सदैव न बोलता हो और इसलिये जो उसकी वास्तविक मातृ-भाषा का, माँ के दूध के साथ मिला हुआ अपना प्रिय शब्द न हो। वास्तव में भाषा को तो हम क्लमबालों ने बिगाड़ा है और हम ही उसे अपनी मातृ-भाषा से दूर लिये जा रहे हैं। जिन्होंने किसी स्कूल में शिक्षा नहीं पाई, वे ही मातृ-भाषा को विशुद्ध रूप में बोल रहे हैं, और किसी अँगरेजी या अरबी फारसी शब्द को प्रयुक्त किये बिना ऐसी धारा प्रवाह और सीधी चोट करने वाली बोलते हैं कि बाबू लोग सम्पूर्ण अँगरेजी और अरबी फारसी साहित्य चाट कर भी क्या बोलेंगे। बाबू साहब साधारण से बात भी अपनी अपठ नौकरानी को नहीं समझा पाते, परन्तु नौकरानी को अपनी बात बाबू साहब को समझाने के लिये शब्दों की कमी महसूस नहीं होती। कारण यही है कि अँगरेजी और उर्दू पढ़ने वाले बाबू साहब का अपनी मातृ-भाषा से कोई नाता रह नहीं गया, और नौकरानी को अपनी मातृ-भाषा के सिवा और कुछ आता नहीं। अगर हमारी हिन्दी भी ऐसी हो जिसे पढ़ कर बाबू साहब की

अवस्था न सुधरे तो बेकार है उसका होना आर झूठ बात है उसे मातृ-भाषा बताना ।

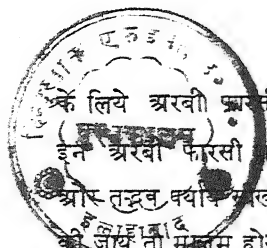
आज हिन्दी एक विशाल प्रदेश की साहित्यिक भाषा है । समझ में नहीं आता कि उसे 'आमफहम' बनाने के लिये एक छोटे से वर्ग में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को घुसेड़ना ही क्यों आवश्यक है । इस भाषा का आधार खड़ी बोली है, खड़ी बोली के प्रत्येक देशज शब्द को, किसी भी अरबी फारसी शब्द के मुकाबले में, हिन्दी में होने का जन्मसिद्ध अधिकार तो है ही, हिन्दी-प्रदेश की किसी भी जनपदीय बोली के किसी देशज शब्द को भी अरबी फारसी शब्द के मुकाबले में हिन्दी में होने का कहीं अधिक अधिकार है । दूसरे शब्दों में, हमें हिन्दी से उन सभी अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार कर देना चाहिये जिनके देशज पर्याय हिन्दी-प्रदेश की किसी भी बोली में मौजूद हैं, और हिन्दी प्रदेश के किसी भी जनपद की बोलचाल में प्रचलित हैं । ये देशज शब्द अरबी फारसी शब्दों की अपेक्षा हमारे कहीं अधिक निकट हैं, और ये शब्द जीवित हैं जब कि इन अरबी फारसी शब्दों के संस्कृत पर्याय बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, इसलिये ये शब्द भाषा में जान फूंक देंगे और उसे वास्तव में आमफहम बना देंगे । इन शब्दों का कोई हिन्दुस्तानी मुकाबला न कर सकेगा । हिन्दुस्तानी का कोई समर्थक इन शब्दों का विरोध न कर सकेगा । जब बोलचाल ही भाषा के आमफहम होने का माप-दंड है तो हम एक अरबी फारसी शब्द के बजाय हिन्दी-प्रदेश के किसी भी भाग की जनता की बोलचाल में प्रचलित उसका देशज पर्याय क्यों न लें, भले ही वह अरबी फारसी शब्द भी कहीं बोलचाल में चलता हो । हम हिन्दी जनता के किसी विशेष वर्ग या हिन्दी प्रदेश के किसी विशेष भाग को प्रधानता क्यों दें ? आज खड़ी बोली हिन्दी केवल खड़ी बोली जनपद में नहीं बोली जाती । वह सम्पूर्ण हिन्दी-प्रदेश में बोली जाती है, क्योंकि उसके बोलने वाले सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश में पैले हुये हैं । हिन्दी-प्रदेश के प्रत्येक

भाग में उस भाग विशेष के देशज शब्द खड़ी बोली में प्रयुक्त होते हैं। मान लीजिये कहीं अरबी फारसी शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। हम प्रत्येक शब्द के दर्जनों पर्याय तो ले नहीं सकते। हमें भाषा को सार्वदेशिक रूप देने के लिए सबसे अधिक निकट पर्याय छाँट लेना है। क्यों न हम अरबी फारसी शब्द के बजाय उसका कोई देशज पर्याय छाँटें ? हिन्दी सम्पूर्ण हिन्दी-प्रदेश की साहित्यिक भाषा इसीलिये है कि उसमें हिन्दी प्रदेश की सभी बोलियाँ अन्तर्निहित हैं। जब हिन्दी ब्रज, अवधी, बुन्देली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, आदि बोलियों से अपना घरेलू नाता जोड़ती है तो उसे इन बोलियों को अरबी फारसी की अपेक्षा प्राथमिक महत्व भी देना पड़ेगा, और विदेशी भाण्डार की ओर ताकने से पहले इन बोलियों के शब्द-भाण्डार से शब्द चयन करना होगा। इन हिन्दी बोलियों के बाद राजस्थानी और विहारी बोलियों की बारी आयगी जिनके बोलने वालों ने हिन्दी को अपनी साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। इतना बड़ा देशी खज़ाना सामने होते हुये विदेशी शब्दों को अपनाना बोर मूर्खता और पागलपन है। (हाँ, अगर हिन्दी को केवल शहरों के थोड़े से लोगों की और उनमें से भी केवल पुरुषों की भाषा बनाना अमीश है, तो बात दूसरी है।) यही देशज-शब्द-प्रधान हिन्दी वास्तविक हिन्दुस्तानी या जनता की भाषा होगी जो सब प्रकार से स्वदेशी, बोलचाल की, जीवित भाषा होगी। यदि कोई हिन्दुस्तानी वाला कहेगा कि अरबी फारसी शब्द बोलचाल में प्रचलित है इसे क्यों नहीं लेते, तो हम कह सकेंगे कि इसका यह देशज या तद्भव पर्याय भी बोलचाल में प्रचलित है इसलिये इसे ही क्यों न रहने दें ? बोलचाल में प्रचलित एक एक शब्द के डेढ़ दर्जन पर्यायों को रखना है तो वे अपनी हिन्दुस्तानी में रक्खें, हमें इस गड़बड़-घोटाले की आवश्यकता नहीं (और उर्दू को तो नहीं है ही—वह छोटे से वर्ग में प्रचलित केवल अरबी फारसी शब्दों को ही लेकर संतुष्ट है)।

यहाँ दो आक्षेपों का उत्तर देना असंगत न होगा। पहला आक्षेप यह

हो सकता है कि इस प्रकार हिन्दी में स्थानिकता का दोष आ जायगा। उत्तर में इतना कहना यथेष्ट है कि छोटे से बर्ग में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को लेना भी स्थानिकता के दोष से खाली नहीं है (और उनके अप्रचलित संस्कृत पर्यायों को रखना तो नितान्त दोषपूर्ण है, कृत्रिम है और, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, व्यर्थ प्रयास है)। यह बात दूसरी है कि राजनीतिक कारणों से अदालतों और कचहरियों में बैठकर ये अरबी फारसी शब्द हिन्दी-प्रदेश के शिक्षित समाज के विशिष्ट वर्गों से परिचित हो गये हैं (इस प्रकार अँगरेज़ी शब्द भी शिक्षित समाज से परिचित हैं)। हमारे देशज और तद्भव शब्द भी, जिन्हें हम छाँटेंगे, साहित्यिक हिन्दी के द्वारा सब जगह एक समान परिचित हो जायँगे। इतना अवश्य है कि प्रत्येक लेखक को चाहे जिस देशज शब्द को प्रयुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से तो खड़ी बोली हिन्दी के इतने ही रूप हो जायँगे जितनी हिन्दी प्रदेश में बोलियाँ हैं, और सम्पूर्ण प्रदेश को एक साहित्यिक भाषा के सूत्र में बाँधने के लिये सब जगह एक समान रूप वाली कोई भाषा न रहेगी। हमें हिन्दी की बोलियों से शब्द सावधानी और सोच-विचार के साथ ग्रहण करने होंगे, और तब उन्हें हिन्दी में, साहित्यिक हिन्दी में, स्थान मिलेगा। परन्तु यह बात इससे सम्बंध रखती है कि भाषा का स्वरूप किस प्रकार, किस ढंग से स्थिर किया जाय और कौन स्थिर करे, न कि इस सिद्धान्त से कि अरबी फारसी शब्दों के स्थान में उनके देशज पर्याय लेने चाहिए अथवा नहीं। भाषा का स्वरूप किस ढंग से स्थिर किया जाय और कौन करे, इस पर आगे विचार किया जायगा।

दूसरा आक्षेप यह हो सकता है कि इस प्रकार हिन्दी राष्ट्र-भाषा होने के इतने उपयुक्त न रहेगी। परन्तु क्या इस समय अरबी फारसी शब्दों के कारण वह राष्ट्र-भाषा होने के उससे अधिक उपयुक्त है? जिन प्रान्तीय भाषाओं से हिन्दी अपना सामीप्य जताती है उन भाषाओं के बोलने वालों



के लिये अरबी फारसी शब्द भी अपरिचित हैं। आज जिस प्रकार उन्हें इन अरबी फारसी शब्दों को सीखना पड़ता है उसी प्रकार वे उनके देशज और तद्वत् पर्याय शब्द लेंगे। फिर, यदि हिन्दी की सब बोलियों की तुलना की जाय तो मालूम होगा कि संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द सब बोलियों में वही हैं, केवल एक ही वस्तु या भाव के लिये भिन्न भिन्न देशज पर्याय भिन्न भिन्न बोलियों में प्रचलित हैं, अर्थात् जिन वस्तुओं या भावों के लिए खड़ी बोली में देशज शब्द हैं, लगभग उन्हीं वस्तुओं या भावों के लिये अन्य बोलियों में देशज शब्द हैं। दूसरे शब्दों में, जितने अरबी फारसी शब्दों के देशज पर्याय हमें समष्टि रूप में हिन्दी बोलियों से मिल सकते हैं, उनमें से अधिकांश के देशज पर्याय हमें खड़ी बोली से ही मिल जायेंगे, और शायद राष्ट्र-भाषा हिन्दी का धीरे से धीरे समर्थक भी यह सलाह न देगा कि खड़ी बोली हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के उपयुक्त बनाने के लिये खड़ी बोली की क्रियाओं और विभक्तियों को छोड़कर शेष सब देशज शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द धरे दिये जायें। राष्ट्र-भाषा होने से पहले हिन्दी एक जीवित, एक जाति की बोलचाल की और एक प्रदेश की मातृ-भाषा है। राष्ट्र-भाषा एक कृत्रिम-भाषा नहीं हो सकती, और न एक कृत्रिम भाषा व्यंजना-शील और प्रगतिशील भाषा हो सकती है और राष्ट्र का कार्य सम्पादन कर सकती है। अँगरेज़ी पहले एक जाति की मातृ-भाषा है और फिर एक विशाल साम्राज्य की राष्ट्र-भाषा। अँगरेज़ी को इस साम्राज्य की राष्ट्र-भाषा होने के उपयुक्त बनाने के लिये मातृ-भाषा अँगरेज़ी में से शब्द निकाल निकाल कर उनके स्थान में साम्राज्य की अन्य भाषाओं के शब्द धरने की सलाह कोई न देगा और न ऐसा हो सकता है। अँगरेज़ी भाषा का मूल आधार अँगरेज़ जाति और इंग्लैंड की बोलचाल की भाषा ही हो सकती है। यह बात दूसरी है कि अँगरेज़ी आवश्यक शब्द साम्राज्य की अन्य भाषाओं से ग्रहण करे। इसी प्रकार राष्ट्र-भाषा हिन्दी का मूल आधार

हिन्दियों और हिन्दो प्रदेश की मातृ-भाषा या बोलचाल की भाषा हो हो सकती है। इसमें कोई काट छाँट नहीं की जा सकती। हाँ, हिन्दी को यदि नये शब्दों की आवश्यकता पड़े और वे हिन्दी की प्रकृति के अनुसार हिन्दी के देशज श्रोतों और हिन्दी की स्वाभाविक उपजीव्य भाषा संस्कृत से न मिल सकें तो उन्हें इधर उधर न जा कर राष्ट्र की अन्य भाषाओं से ग्रहण करना चाहिये। 'राष्ट्र-भाषा' का यही अर्थ हो सकता है। राष्ट्र-भाषा बनाने के लिये किसी भाषा की प्रकृति नहीं बदली जा सकती और न उसकी निजी शब्दावली में परिवर्तन किया जा सकता है। सारांश यह कि पहले हिन्दी को अपनी बोलचाल की भाषा, अपने प्रदेश की मातृ-भाषा बनाना चाहिये। किसी भाषा का प्रचार अन्य भाषाओं के समीप होने के कारण नहीं होता, इससे प्रचार में आसानी भले ही हो जाय। किसी भाषा का प्रचार तो उस भाषा के बोलने वालों की शक्ति पर निर्भर है। जब वे ही उस भाषा को उसके लिखित रूप में नहीं बोलेंगे तो उसे दूसरे कैसे बोल सकेंगे? जब हिन्दी वाले जैसी हिन्दी लिखेंगे वैसी बोलेंगे, और जैसी बोलेंगे वैसी लिखेंगे, अपना सारा काम काज उसमें करेंगे और उसमें उत्तम साहित्य की रचना करेंगे तब हिन्दी में शक्ति आयेगी, उसके उदाहरण, सुहावरो आदि का आदर्श स्थिर होगा और वह चारों ओर फैल कर राष्ट्र-भाषा का पद प्राप्त करेगी। हिन्दी को हिन्दी-प्रदेश की जनता की बोलचाल के निकट लाने के लिये हिन्दी के देशज शब्दों और धातुओं को पहला स्थान देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हिन्दी आमफहम, जनता की भाषा, वास्तविक हिन्दु-स्तानी बनेगी।

(आ) वे अरबी फारसी शब्द जिनके संस्कृत तत्सम या तद्भव पर्याय जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं और इसलिये जिनका हिन्दी से बहिष्कार कर देना चाहिये।

हिन्दी में प्रचलित जिन अरबी फारसी शब्दों के देशज पर्याय प्रचलित

हैं उनके विषय में ऊपर जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उन्हीं के अनुसार हिन्दी में से उन अरबी फ़ारसी शब्दों को भी निकाल डालना चाहिये जिनके संस्कृत तत्सम और तद्भव पर्याय जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं, भले ही वे अरबी फ़ारसी शब्द भी विशिष्ट वर्गों की अथवा जनता की ही बोलचाल में प्रचलित हों। ऐसे अरबी फ़ारसी शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

हक़ (अधिकार), बेरहम (निर्दयी), बेशर्म (निर्लज्ज), संजीदा (गम्भीर), रूह (आत्मा), गुनाह (पाप), सबाब (पुण्य), बदनसीब (अभाग्य), हुक्म (आज्ञा), कब्ज़ा (अधिकार), रोज़ाना (नित्य), रोज़ (दिन), क़िला (गढ़), ज़हर (विष), ज़हरीला (विषैला), मज़ (रोग), मरीज़ (रोगी), दरिया (नदी), दलशम (कफ़), मुलाक़ात (भेंट), यकीन (विश्वास), सज़ा (डंड), जुर्म (अपराध), सुजरिम (अपराधी), क़सूर (दोष), ख़िदमत (सेवा), बेबक़ूफ़ (मूर्ख), इन्ताज़ (न्याय), इन्साज़-पसन्द (न्यायी), ख़ैरियत (कुशल), ख़ैर सल्ला (कुशल मंगल), बेबा (विधवा), ख्वाहिश (इच्छा, अभिलाषा), रंज (दुःख), तकलीफ़ (कष्ट), बारिश (वर्षा, बरखा), तफ़रीह (आनन्द), फौरन (तुरन्त), बदहज़मी (अपच, औगुन), शाम (संझा, सँझ), ज़िरम (शरीर, देह), रोज़गार (व्यापार), ज़मीन (धरती, भूमि, चू), शादी (विवाह, ब्याह), मुल्क (देश), शिश्तेदार (सम्बन्धी), शिश्ता (सम्बन्ध), मुआद (इच्छा), औलाद (सन्तान), क़दम (पग), क़तार (पंक्ति, पौंती), ख्वाय (स्वप्न, सपना), ज़ायका (स्वाद), बज़ीर (मन्त्री), हिस्सा (भाग), तज़ुरवा (अनुभव), तज़ुरवेकार (अनुभवी), एतवार (विश्वास), पनाह (शरण), दौलत (धन), बजह (कारण, कारन), उम्मीद (आशा, आस), बेफ़िक़ (निश्चिन्त, निचिन्त), फ़िक़ (चिन्ता), दादशाह (राजा), मिज़ाज़ (स्वभाव), खुश (प्रसन्न), हुक्ूमत (राज), सल्तनत (राज्य,

राज), नेहरवानी (कृपा), मोहब्बत (प्रेम), कमज़ोर (दुर्बल), इन्तज़ाम (प्रबन्ध), मुश्किल (कठिन), बच्चा (बालक), मदद (सहायता), माफ़ (क्षमा), ज़वान (जीभ), इस्तहान (परीक्षा), खुशबू (सुगन्ध), बदबू (दुर्गन्ध), बू देना (गंधाना), शक (सन्देह), तालीम (शिक्षा, पढ़ाई), अक़लमन्द (बुद्धिमान), फायदा (लाभ), नुक़सान (हानि), तक्दीर (भाग्य), जगह (स्थान), बतन (देश), इत्तिफ़ाक़ (संयोग), इत्तिफ़ाक़न (संयोग से), कर्ज (ऋण), पैशाम (सन्देश), तरकीब (उपाय), काबिल (योग्य, जोग), तसल्ली (धीरज, संतोष), खूबसूरत (सुन्दर), दौलतमन्द (धनी), मदद या इमदाद (सहायता) ।

(इ) हिन्दी प्रदेश की जनता की बोलचाल में प्रचलित अरबी फ़ारसी शब्द जिनके देशज, तद्भव या संस्कृत तत्सम पर्याय जनता की बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं । ऐसे शब्दों को हिन्दी में निःसंकोच ले लेना चाहिये ।

यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि हिन्दी प्रदेश की बोलचाल का माप-दंड हिन्दी प्रदेश के गाँवों, क़स्बों और शहरों में बसने वाली ६५ प्रतिशत जनता की बोलचाल है, शहरों में रहने वाले विशिष्ट वर्गों की बोलचाल नहीं । वास्तव में इन विशिष्ट वर्गों की कोई बोलचाल है ही नहीं । वह राजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदलती चलती है । कभी वह हिन्दी थी, फिर उर्दू हुई, आज वह इङ्गलिस्ताना है । कल वह हिन्दी के राजभाषा होने पर फिर हिन्दी हो जायगी । हम इन विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित विदेशी—अरबी फ़ारसी या अँगरेज़ी—शब्दों को हिन्दी में लेने के लिये बिलकुल बाध्य नहीं । परन्तु जो विदेशी—अरबी फ़ारसी या अँगरेज़ी—शब्द अपने स्वदेशी पर्यायों के साहित्यिक अस्तित्व के बावजूद हमारे दुर्भाग्य से, हमारी राजनीतिक परतन्त्रता के कारण जनता की बोलचाल में प्रचलित हो गये हैं, उन्हें हमें जनता की भाषा के नाते ले लेना चाहिये । हमारे सौभाग्य से ऐसे शब्दों की संख्या अधिक नहीं है । सिद्धान्ततः हमें इन शब्दों

का भी बहिष्कार करने का और उनके स्थान में स्वदेशी पर्यायों को प्रचलित करने का अधिकार है। संसार के वे सभी स्वतन्त्र देश जो कुछ समय पहले तक परतन्त्र थे (जैसे तुर्की) ऐसा कर रहे हैं (भारत की सब भाषाएँ भी बोलचाल में प्रचलित अँगरेज़ी शब्दों का बहिष्कार करने पर कटिबद्ध हैं)। प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों में वे विदेशी शब्द जनता की बोलचाल में मिल गये, अनुकूल परिस्थिति होने पर हमारे स्वदेशी शब्द फिर प्रचलित हो सकते हैं। परन्तु इस समय परिस्थिति देखते हुये जनता की बोलचाल में प्रचलित ऐसे सभी अरबी फारसी शब्दों को हिन्दी में रखना उचित है जिनके स्वदेशी पर्याय जनता की बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं। इन शब्दों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—

(1) वे शब्द जिनके स्वदेशी पर्याय कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं।

उदाहरण—

आसमान, किनारा, लेकिन, रिहाई, बानी, बाद, गरमी, गरम, रेगिस्तान, मुकदमा, खर्च, क्लम, दवात, सलाह, रोशनाई या स्वाही, सफ़ेद, जिम्मेदार, अख़बार, नुमाइश, मज़बूत, अलावा, फुरसत।

इन शब्दों के हिन्दी पर्याय हिन्दी कोष में रहें अर्थात् उनका बिल्कुल बहिष्कार न हो, परन्तु वे विशेष अवसरों पर, विशेष कारणों से ही प्रयुक्त किये जायें। साधारणतया हिन्दी में इन अरबी फारसी शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिये। उदाहरणार्थ सदैव 'आसमान' का प्रयोग होना चाहिये, 'आकाश' का प्रयोग किसी विशेष कारण के उपस्थित होने पर ही क्षम्य समझा जाय।

(ii) वे शब्द जिनके संस्कृत पर्याय शिष्ट समुदाय या शिक्षित समाज की बोलचाल में आते हैं परन्तु साधारण, अपढ़ जनता की बोलचाल में साधारणतया नहीं आते। उदाहरण—

नतीजा, हमेशा, गरीब, अमीर, सबूत, ताक़त, कायदा, दोस्त, दुश्मन,

उमर, रोजी, दबा, अन्दाजा, आसान, आदमी या इंसान, खुशी, सूबा, मुकर्रर, फर्ज, नफरत, आवहवा, बायदा, जुल्म, मौका, असल में, कमजोरी, मज़बूती, सवाल, बदनामी, नामवरी, मुमीयत, आजादी, ज़रूरत, सिर्फ, फरक, भिसाल, रफतार, मंजूर, ऐलान, तबदीली, खजाना, बक्त, हद, ज़िन्दगी, दरखास्त, तनखाह, मशहूर, कोशिश, दिमाग, फौज, मेहनत, जवाब, हिम्मत, शहर, शुरू, खतम, मौजूद, मर्द, कैद, कैदी, तसवीर, फैसला, रास्ता, नज़र, याद, हिसाब, लायक, बरवाद, शामिल, आमदनी, खुद, पैदा, इस्तीफा, जाहिर, इत्तिला, बुखार, शुरूआद, मुनासिब, कीमत, कीमती, अक्सर, तन्दुरुस्ती, आखिरी, खबर, इशारा, खास, सब, आमदनी ।

इन अरबी फारसी शब्दों के हिन्दी पर्यायों को सर्वत्र बोलचाल में प्रचलित करने का हमें अधिकार है क्योंकि वे कृत्रिम नहीं कहे जा सकते । अर्थात् ये अरबी फारसी शब्द हिन्दी और हिन्दी-कोष में रहें, परन्तु इनका प्रयोग विशेष अवसरों पर विशेष कारणों से ही किया जाय । साधारणतया अपने हिन्दी पर्यायों का ही प्रयोग होना चाहिए क्योंकि वे सर्वत्र बोलचाल में तभी प्रचलित हो सकते हैं ।

(ई) वे अरबी फारसी शब्द जिनके हिन्दी पर्याय हमारे पास हैं ही नहीं या जिनके हिन्दी पर्याय अत्यन्त कठिन, दुरूह और भारी भरकम हैं । इन्हें ले लेना चाहिए और इनके हिन्दी पर्यायों को गढ़-गढ़ा कर प्रचलित करने का प्रयत्न करके हास्यास्पद नहीं बनना चाहिये ।

उदाहरण—

कागज़, इज़्जत, ज़बर्दस्ती, ज़्यादती, ज़ोर, ज़माना, शिकायत, सिफ़ारिश, खुशामद, मज़ा, तबियत, नवाब, कब्र, कमी, ग़लती, शर्त, मौसम, रियायत, मामला, तख़्त, फसल, मसलहत, कार्रवाई, मेज़, तलाक़, दिलचस्पी, अरमान, फर्श, सफ़ाई, ज़मानत, तगादा, तख़मीना, उम्मीदवार, हिज्जे, क़ानून, मुहाबरा, मसबिदा, ग़लत, बकील, क़रार, माकूल, नागवार, मुखातिब,

ईमानदारो, ईमान, मुफ्त, परेशान, ताज़ा, मंसूख, मुअत्तल, तफ़तोश, शिनाख्त, मुआवज़ा ।

हमें कुछ अरबी फारसी शब्द ऐसे भी लेने पड़ेंगे जिनके हिन्दी पर्याय हैं तो, पर वे अरबी फारसी शब्दों के सब प्रयोगों और अर्थों में रूढ़ नहीं हैं । उदाहरणार्थ, 'यह दिलचस्प कहानी है' के बजाय यह तो कह सकते हैं 'यह मनोरंजक कहानी है,' परन्तु 'इस मामले से मुझे दिलचस्पी है' में 'दिलचस्पी' को नहीं बदला जा सकता । 'इधर उधर से पूँजी जमा की' की जगह 'इधर उधर से पूँजी इकट्ठी की' हो सकता है, परन्तु 'डाकघर में रुपया जमा कर दो' के बजाय 'डाकघर में रुपया इकट्ठा कर दो' नहीं हो सकता । 'हिसाब सीखो' में 'हिसाब' की जगह 'गणित' हो सकता है, परन्तु 'खर्च का हिसाब यों है' में 'हिसाब' की जगह 'गणित' भद्दा और मुहावरे के विरुद्ध होगा ('हिसाब' 'Mathematics' और 'Account' दोनों के अर्थ में रूढ़ है, 'गणित' नहीं है) । 'पत्र को प्रतिलिपि' हो सकता है, परन्तु 'अँगरेज़ों की नक़ल' कहना पड़ेगा । परन्तु ऐसे अरबी फारसी शब्दों को हमें तभी प्रयुक्त करना चाहिये जब उनके स्थान में अपने शब्द प्रयुक्त करना सम्भव न हो, अर्थात् जब मुहावरे, दोलचाल या रोज़मर्रा का तफ़ाज़ा हो । इन शब्दों से यही प्रकट होता है कि ज्यों ज्यों कोई शब्द अधिकाधिक व्यवहार में आता है त्यों त्यों वह अनेक अर्थों में रूढ़ होता चला जाता है । ('मौसम' का उदाहरण पहले दिया जा चुका है ।) हमने अपने स्वदेशी शब्दों की ओर से नज़र फेर ली, इसलिये उनके अर्थ संकुचित होते चले गये । हमें अब अपने शब्दों का अर्थ विस्तृत करना चाहिये और उन्हें विभिन्न ध्वनियों और अर्थों में रूढ़ करना चाहिये (उदाहरणार्थ, 'यात्रा' को केवल धार्मिक यात्रा के लिये रिज़र्व करने की आवश्यकता नहीं, रेल के 'सफ़र' को भी 'यात्रा' कहना चाहिये) । मुहावरों में जो अरबी फारसी शब्द पैठ गये हैं उन्हें भी केवल मुहावरों के साथ लेना होगा, परन्तु भविष्य में अपने ही शब्दों से मुहावरे बनाने चाहिये ।

हमें कुछ ऐसे अरबी फारसी शब्द भी लेना पड़ेंगे जिनके अर्थ में और जिनके हिन्दी पर्यायों के अर्थ में ध्वनि का अन्तर है। उदाहरणार्थ, 'अनुभव' में वह ध्वनि नहीं है जो 'महसूस' में है। 'भाग्य' और 'किस्मत', 'लज्जा' और 'शर्म' में ध्वनि और अर्थ का अन्तर है। परन्तु ऐसे शब्दों की संख्या अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। इस मामले में अत्यन्त सतर्कता से काम लेना पड़ेगा। कारणों का निर्देश पहले किया जा चुका है (देखिये पृष्ठ १५-१७)। हमें अपने शब्दों में ही सब ध्वनियाँ और अर्थ रूढ़ करने चाहिये। इन्हीं तीन शब्दों को लें, तो व्यवहार करने से 'अनुभव' में 'महसूस' की ध्वनि बड़ी सरलता से आ सकती है, क्योंकि शब्द में विभिन्न ध्वनियाँ शब्द का प्रयोग करने से ही आया करती हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो चूँकि उर्दू वाले 'अनुभव' नहीं अपनायेंगे और 'महसूस' में ही 'अनुभव' की ध्वनि भी रूढ़ कर लेंगे, बोलचाल में केवल 'महसूस' रह जायगा और इस अर्थ में 'अनुभव' का व्यवहार बिल्कुल वन्द हो जायगा। 'भाग्य' के बारे में, यदि अब तक भारत जैसे भाग्यवादी देश का 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' से काम चल गया, तो अब 'Luck,' 'Fate,' 'Fortune' और 'Destiny' के अर्थों और ध्वनियों को स्पष्ट करने के लिये 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' के अतिरिक्त 'किस्मत,' 'तक्दीर,' 'नसीबा' और 'मुकद्दर' में से दो शब्द छुँटने की आवश्यकता नहीं—सब काम 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' से अब भी चल सकता है और चलना चाहिये, नहीं तो चूँकि उर्दू वाले 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' लेंगे नहीं, चारों ध्वनियाँ उन्हीं दो उर्दू शब्दों में रूढ़ हो जायँगी जिन्हें हम ग्रहण करेंगे (क्योंकि बोलचाल में वे ही दो शब्द हिन्दी उर्दू में कामन होने के कारण चलेंगे), और 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' हमसे विदा हो जायँगे। 'शर्म' और 'लज्जा' के विषय में, उर्दू वालों को 'लज्जा' की आवश्यकता नहीं। उन्होंने पहले से ही 'शर्म' को 'Shame' और 'Shyness' दोनों अर्थों में रूढ़ कर लिया है—वे यह भी कहते हैं, 'शर्मिन्दा होना पड़ा,'

और यह भी कहते हैं, 'लड़की शर्मा रही है'। हम 'लड़की लजा रही है' तो कहते ही हैं, 'शर्मिन्दा होना पड़ा' के बजाय विलकुल उसी अर्थ में 'लजित होना पड़ा' भी कह सकते हैं और कहना चाहिये ।

हमें सभी आवश्यक शब्द जो हिंदी और संस्कृत के खजाने से न मिल सकें अरबी फ़ारसी से लेने की आवश्यकता नहीं । अन्य भारतीय भाषाओं का निजी शब्द-भांडार तो हमारे सामने है ही, हमें अँगरेज़ी, जो हमारे बहुत काशी निकट आ गई है और जिसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व और स्थान है, से भी पूरी सहायता लेनी चाहिये । यदि अरबी फ़ारसी को अधिक महत्त्व इसलिये दिया जाना चाहिये कि अरबी फ़ारसी शब्द उर्दू में होंगे और इसलिये वे हिन्दी प्रदेश में ही प्रचलित होंगे, तो यह नहीं भूलना चाहिये कि हिन्दी प्रदेश में अँगरेज़ी शब्द भी प्रचलित हैं । एक अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित अँगरेज़ी शब्द को छोड़ कर अरबी फ़ारसी शब्द को ग्रहण करना मूलतः, और उर्दू की गुलामानी की निशानी होगी, स्वाभाविकता के विरुद्ध होगा और भाषा को बोलचाल से दूर लेजाने में सहायक होगा । उर्दू वालों ने 'Editor,' 'Leader,' 'Character,' 'Public,' 'Jubilee,' 'Secretary,' 'Art,' 'Member,' 'Policy,' 'Scheme,' 'Science,' 'Grammar,' आदि, आदि शब्दों को अपनाया, उनके सरल, प्रचलित हिन्दी पर्यायों को नहीं लिया । वे कहते हैं कि अँगरेज़ी शब्द भी तो प्रचलित हैं और इनके हिन्दी पर्यायों को जानने वालों की अपेक्षा अधिक उर्दू पाठकों को पहले से ही मालूम हैं, फिर इन्हें ही क्यों न लें ? उनका तर्क सोलहों आने ठीक है । हम हिन्दी वाले ही जब अरबी फ़ारसी शब्द का सामना होता है तब अपना प्रचलितवाद भूल जाते हैं । हम एक अरबी फ़ारसी शब्द को उसके हिन्दी पर्याय से अधिक प्रचलित बताने के लिये और उसे 'हज़म' करने के लिये सदैव तैयार रहते हैं, परन्तु जब एक अँगरेज़ी शब्द उनके अरबी फ़ारसी पर्याय से अधिक प्रचलित होता है, और उस शब्द की हमें

आवश्यकता होती है तो अँगरेजी शब्द को अपनाते हुए सकुचाते हैं, बगलें भाँकने लगते हैं और अन्त में अरबी फारसी को ही गले से लगाते हैं। उदाहरण के लिये, हिन्दी पत्रों में 'मुअत्तल' चलता है। कितने हिन्दी पाठक ऐसे हैं जो 'सर्वेड' नहीं समझते या पहले से नहीं जानते, परन्तु 'मुअत्तल' समझते और जानते हैं? दोनों में से किसी शब्द को न जानने वालों और अशिक्षितों के लिये दोनों शब्द एक समान अपरिचित हैं, फिर इस 'मुअत्तल' को 'सर्वेड' से प्रीफर (या 'तरजीह'!) क्यों किया जाय? 'मुहय्या' के बजाय 'स्प्लाई' क्यों न कहा जाय? यही बात उन शब्दों के लिये कही जा सकती है जिन्हें ऊपर मोटे अक्षरों में छापा गया है।

(उ) वे अरबी फारसी शब्द जो ऊपर के किसी वर्ग में नहीं आते। इनका हिन्दी से बहिष्कार होना चाहिये। उदाहरण—

मक़सद, सदर, सदारत, तरजुमा, ज़बान (भाषा के अर्थ में), वाकई, तलफ़्फ़ुस, वाशिन्दा, महदूद, मुख़्तलिफ़, मुख़ालिफ़, मुख़ालिफ़त, मुताबिक़, मुल्तवी, नुमायन्दा, तक्ररीर, रहनुमाई, सतर, अहम, अमूमन, ग़ालबन, मुकम्मल, तब्ख़ा, उसूल, महलूम, फ़ख़, इलज़ाम, ताक्कीद, इन्तानियत, हुक्मत, ज़वानी, याददाश्त, मौज़ू, बहस, मुबाहसा, मातहत, दरअसल, हासिल, निज़दार, वज़ीफ़ा, बग़ैर, ईजाद, एतराज़, तोहमत, नाज़, आयन्दा, अफ़साना, फ़साना, राज़, मुदई, मुदालह, वालिग़, नामज़द, सेहनतक़श, तबाह, ज़ालिम, ज़ुर्रत, ग़ैर-वाजिब, जमात, वानज़ूद, दाख़िल, बागी, बगावत, लाज़मी, कुर्बानी, कुर्बान, बफ़ादारी, एलची, रुख़सत, शुक्रगुज़ार, नज़ज़ारा, ऐशोआराम, ग़ुरबत, मुफ़ीद, निस्वत, रद्दोवदल, यानी, बेजा, गुमराह, सुलह, क़ौमो, ग़ैर-मुनासिब, उल्क़त, माली हालत, ग़द्दार, अहलकार, अमला, शराफ़त, तहज़ीब, माहिर, ख़ाबिन्द, मानो, रक़बा, हामी, हिमायत, ख़िलाफ़, दरियादिल, मामू या मामू जान, चचा या चचा जान, भाई जान, सिपहसालार, बादशाह

सलामत, मलका, उस्ताद, मंगार, मर्दुमशुमारी, ओहदा, अजोबो गरीब, मुतफर्रिक, कुदरती, कुदरत, हमददी, जरव, तरमीम, शहंशाह, वाजिव, तकरीबन, सेहत, करोव, अखितयार, नाराज, नाखुश, खरीद-फरोखत, अन्न, दरिन्दा, निजाम, शुक्रिया, सरहद, हैरतअंगेज, वरखिलाफ, वेशकीमत, मुतल्लिक, हसीन, सदी, मुस्तकिल, लफज, साजिश, वाकया, वारदात, फेहरिस्त, तनहा, तनहाई, नुकताचीनी, जायज, इजहार, शराफत, तमन्ना, नुस्ख, हलफ ।

हिन्दी प्रदेश की अधिकांश साधारण जनता को अभी तक साधारण बोलचाल के लिए इन शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । वे अरबी फारसी शब्द 'जनता' की बोलचाल में प्रचलित नहीं, और इसलिए इन्हें हिन्दी में प्रयुक्त करना अस्वाभाविक है । इनमें से कुछ शब्द वा सभ्य शब्द विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित माने जा सकते हैं, परन्तु ऐसे विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में इनके हिन्दी पर्याय भी प्रचलित हैं, और इसलिए हम इन विदेशी शब्दों को नहीं ले सकते (इङ्गलिस्तानी के अँगरेजी शब्दों की भाँति) । यदि विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित कुछ अरबी फारसी शब्द ऐसे भी हैं जिनके हिन्दी पर्याय विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में भी प्रचलित नहीं, तो भी हम उन विदेशी शब्दों को नहीं ले सकते (इङ्गलिस्तानी में प्रचलित, कितने ही हिन्दी के अप्रचलित शब्दों के अँगरेजी पर्यायों की भाँति) । जैसा पहले कहा जा चुका है, हमें उनके हिन्दी पर्याय प्रचलित करने का पूर्ण अधिकार है और हमें उन्हें अवश्य प्रचलित करना चाहिए । इस वर्ग के शब्दों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, उनमें से कितने शब्दों को हिन्दी में खुलेआम लेखक की राय में महापाप है, उन्हें मोटे अक्षरों में छाप दिया गया है । वास्तव में हिन्दी के जो लेखक असावधानी से या जान बूझकर (या 'हिंदुस्तानी' के आग्रह से ?) इन शब्दों को और इस प्रकार के अन्य शब्दों को हिन्दी में प्रयुक्त कर रहे हैं वे हिन्दी को हत्या कर रहे हैं,

और इस समय जब कि हिन्दी अपने जीवन के सबसे नाजुक दौर में से गुज़र रही है और उस पर चारों ओर से प्रहार हो रहे हैं, ऐसे लेखकों को साहित्यिक दंड देना अनुचित न होगा।

ऊपर प्रत्येक वर्ग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप जो शब्द पेश किये गये हैं, उनके विषय में विद्वानों में मतभेद हो सकता है। कुछ विद्वान् एक शब्द को निकालने की सलाह देंगे, कुछ उसको रखने की सलाह देंगे। कुछ विद्वान् एक शब्द को किसी वर्ग में रखेंगे, कुछ विद्वान् किसी दूसरे वर्ग में। ऊपर अरबी फ़ारसी शब्दों के जिन वर्गों को बहिष्कार-योग्य बतलाया गया है, उनमें से प्रत्येक वर्ग के कुछ शब्दों को शायद सिद्धान्त के अपवाद-स्वरूप लेना भी आवश्यक होगा। इन सब बातों के विषय में लेखक को अपनी ओर से बिल्कुल आग्रह नहीं है। उसका उद्देश्य तो केवल विद्वानों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना है कि हिन्दी में प्रचलित अरबी फ़ारसी शब्दों की सयाँदा निश्चित होनी चाहिये, और हिन्दी में नये नये अनावश्यक अरबी फ़ारसी शब्दों की जो बाढ़ आ रही है, उसे रोकने का प्रयत्न होना चाहिए। कौन सा शब्द रखना चाहिये और कौन सा शब्द निकालना चाहिये (और किन सिद्धान्तों के अनुसार), इसका अन्तिम निर्णय तो हिन्दी के विद्वानों को एक सभा ही कर सकती है। परन्तु इतना फिर कहना पड़ेगा कि जिन शब्दों का बहिष्कार करना है, उनका प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। यदि हिन्दी पर्याय के साथ बहिष्कृत अरबी फ़ारसी शब्द का भी प्रयोग होगा तो हिन्दी पर्याय बोलचाल में कदापि प्रचलित न हो सकेगा, और यदि पहले से प्रचलित होगा तो अप्रचलित हो जायगा। कारण पहले बतलाये जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में, हिन्दी को एक दृढ़ नीति पर दृढ़ता के साथ चलाना होगा। उसमें भूँठी 'उदारता', घातक 'हज़म'-वाद या शब्दों के द्वैतवाद के लिये कोई गुंजाइश नहीं रखी जा सकती। या तो सदैव हिन्दी शब्द, वह बोलचाल में चाहे अप्रचलित

ही क्यों न हो, प्रयुक्त होना चाहिये या फिर उर्दू शब्द को ही ग्रहण कर लेना चाहिये और उसी को प्रयुक्त करना चाहिये। दोनों के प्रयोग से, यदि हिन्दी शब्द बोलचाल में अप्रचलित है तो वह कभी प्रचलित न होगा, हाँ, भाषा उसके कारण अवश्य कृत्रिम कही जायगी और वास्तव में होगी भी, और अन्त में हिन्दी का वह अप्रचलित शब्द साहित्य से भी अवश्य निकल जायगा। यदि हिन्दी का शब्द भी बोलचाल में प्रचलित है, तो हिन्दी में दोनों के प्रयोग से केवल उर्दू का शब्द ही कामन शब्द माना जायगा क्योंकि वह हिन्दी पढ़ने वालों और उर्दू पढ़ने वालों दोनों को एक समान मालूम होगा और अन्त में हिन्दी का शब्द बोलचाल से निकल जायगा और फिर साहित्य में से भी निकल जायगा और केवल उर्दू का शब्द रहैगा। उदाहरण के लिए 'तक़रीर' को लीजिये जो हिन्दी में कुछ लेखकों को कृपा से दर्शन देने लगा है। 'भाषण' उर्दू में नहीं चलता, और न कभी चले। जहाँ तक हिन्दी से सम्बन्ध है, 'तक़रीर' के साथ दो ही बातें हो सकती हैं— (१) बोलचाल में 'तक़रीर' प्रचलित है, 'भाषण' अप्रचलित है। यदि ऐसा है तो या तो सदा 'तक़रीर' लिखा जाय और उसे हिन्दी में 'हज़म' कर लिया जाय। परन्तु यदि 'भाषण' को बोलचाल में प्रचलित करना अभीष्ट है तो ऐसा हिन्दी में 'तक़रीर' और 'भाषण' दोनों का प्रयोग करने से कभी नहीं होगा; वह तो सदैव 'भाषण' लिखने से और 'तक़रीर' का पूर्ण बहिष्कार करने से ही हो सकता है। (२) बोलचाल में 'भाषण' भी प्रचलित है। ('तक़रीर' तो 'प्रचलित' है ही)। यदि ऐसा है तो 'तक़रीर' को हिन्दी में प्रयुक्त करने का कारण ? यदि कोई शब्द हिन्दी में केवल इस कारण लिया जा सकता है कि उसे खड़ी बोली में कोई न कोई बोलता है— उसका हिन्दी पर्याय मौजूद या प्रचलित हो अथवा न हो, तो जैसा पहले कहा जा चुका है, हिन्दी में सम्पूर्ण उर्दू-कोष और आधा अँगरेज़ी-कोष उठा कर धर देना पड़ेगा। कि ऐसा केवल हिन्दी वाले करेंगे (उर्दू वालों)

को खड़ी बोली में बोले जाने वाले हिन्दी संस्कृत शब्दों से कोई सरोकार नहीं), अन्त में खड़ी बोली में केवल उर्दू-कोष ही लक्षित होगा, और फिर लिखित हिन्दी में भी केवल वही दिखाई देगा। सिनेमा, रेडियो, आदि में भी वही दिखाई देगा—कोई जाकर यह देखने का कष्ट नहीं करेगा कि हिन्दी-कोष में उन उर्दू शब्दों के, जो उर्दू-कोष में हैं और सब जगह चल रहे हैं और जिन्हें सब समझ रहे हैं, और कौन कौन से पर्याय भी सँजोये हुये हैं *। 'तक़रीर' को ही लें। चूँकि उर्दू वाले 'तक़रीर' छोड़कर 'भाषण' स्वप्न में भी नहीं लिखेंगे, हिन्दी में 'भाषण' के साथ साथ 'तक़रीर' घुसेड़ने का केवल यही परिणाम होगा कि हिन्दी वाले 'तक़रीर' भी सीख जायेंगे और फिर बोल-

* पं० रामनरेश त्रिपाठी एक जगह लिखते हैं : "हिन्दी के कितने ही शब्द, जो उर्दू में लिखे नहीं जा सकते, हमेशा के लिए हमसे छूट जायेंगे—जैसे भाग्य, संदिग्ध, आवश्यक, प्रमाण, साहित्य और विद्वान के स्थान पर हमें क्रिस्मत, मशकूक, ज़रूरी, सवूत, अदब और आलिम लेना पड़ेगा। लेने के हम विरोधी नहीं, क्योंकि नए शब्दों से हमारा शब्द-कोष बढ़ता ही है, घटता नहीं....."। स्पष्ट है, इस प्रकार शब्द लेने से हिन्दी शब्द-कोष का बढ़ना तो अलग रहा, 'हिन्दी शब्द-कोष' नाम की कोई चीज़ ही न रह जायगी। उर्दू वाले स्वप्न में भी क्रिस्मत, मशकूक, ज़रूरी, सवूत, अदब और आलिम के रहते भाग्य, संदिग्ध, आवश्यक, प्रमाण, साहित्य और विद्वान नहीं लिखेंगे—उनकी लिपि में लिखना संभव हो तो भी नहीं (वे लिखें भी क्यों ? एक एक शब्द के दो दो पर्यायों की ज़रूरत ?)। हिन्दी में क्रिस्मत, मशकूक..... आलिम घुसेड़ने से आज हिन्दी बालकों को दूना बॉम्ब, कोप-प्रकाशकों को दूना कागज़ और छुपाई का सूर्चा, आदि तो उठाना ही पड़ेगा, कल तक भाग्य, संदिग्ध.....विद्वान का हिन्दी से टिकट ही कट जायगा। क्रिस्मत, मशकूक..... आलिम ही कामन भाषा, राष्ट्र-भाषा के शब्द कहे जायेंगे, और वास्तव में होंगे भी। भाग्य, संदिग्ध.....विद्वान उर्दू लिपि की अपूर्णता और अवैज्ञानिकता के कारण नहीं, अपने ही कमों (या 'उदारता', 'हज़मवाद'!) के कारण हमसे सदैव के लिये छूट जायेंगे।

चाल में 'तक़रीर' ही चलेगा, 'भाषण' पीछे पड़ता जायगा। किसी बक्ता या सिनेमावाले को भी 'भाषण' की ज़रूरत न रह जायगी। लिखित हिन्दी में भी फिर अधिकाधिक 'तक़रीर' का ही प्रयोग होगा और एक पीढ़ी बाद डा० ताराचन्द्र और पं० सुन्दरलाल के वंशज पूछेंगे, अमों, यह 'भाषण' क्या चीज़ है ? यह हिन्दुस्तानी तो मालूम नहीं देता। वास्तव में वह एक अजीब चीज़ होगी, और उसका उपयुक्त स्थान मुदा अजायबघर या अमर-कोष होगा। 'समबन्ध' (एक तरफ़ ?), 'उदारता' (वा आत्म-समर्पण ?), 'राष्ट्रीयता' (वा अराष्ट्रीय मूलमानों की चापलूसी ?), 'प्रचलितवाद' (वा उर्दू की गुलामी ?) आदि, आदि का नारा लगा कर आज जो हिन्दी लेखक 'तक़रीर' और ऐसे ही अन्य अनावश्यक उर्दू शब्दों को हिन्दी में घुसेड़ रहे हैं, वे हिन्दी को जड़ से खोद रहे हैं।

साधारण श्रेणी के हिन्दी लेखकों को संक्षेप में यह सलाह निःसंकोच दी जा सकती है कि वे किसी भी अरबी फारसी शब्द का प्रयोग करने से पहले यह सोच लें कि उसका हिन्दी पर्याय है वा नहीं, और यदि है तो उससे काम चल सकता है वा नहीं। यदि इस प्रकार वे एक बार हिन्दी में ग्रहीत या ग्रहण करने योग्य अरबी फारसी शब्द के वजाय भी अपना हिन्दी शब्द लिख जायँ, तो वह शलती हिन्दी में अनावश्यक अरबी फारसी शब्द घुसेड़ने की शलती से कहीं अधिक ज़्यादा होगी। प्रथम श्रेणी के हिन्दी लेखकों से निवेदन है कि वे हिन्दी में किसी नवीन अरबी फारसी शब्द को प्रयुक्त करने से पहले यह सोच लें कि हिन्दी के अपने खोत उस शब्द का स्वदेशी पर्याय देने में समर्थ हैं वा नहीं, और उस शब्द के कारण हिन्दी के किसी प्राचीन वा प्रचलित शब्द का जीवन तो खतरे में नहीं पड़ता। प्रत्येक अवस्था में, किसी भी अरबी फारसी शब्द को प्रयुक्त करने से पहले यह याद कर लेना लाभदायक सिद्ध होगा कि उसका हिन्दी पर्याय, यदि वह वर्तमान है, उर्दू में भूल कर भी प्रयुक्त नहीं होगा।

एक बात और। अरबी फारसी का जो भी प्रचलित शब्द हिन्दी में लिया जाय, उसे तद्भव रूप में ही लिया जाय। जब एक ऐसे शब्द को ग्रहण करने का कारण यही है कि वह प्रचलित है, तो जिस रूप में वह प्रचलित है उसी रूप में उसे न लेने का कारण? हम एक ऐसे शब्द को इस लिये नहीं लेते कि वह अरबी फारसी का शब्द है, बरन् इसलिये लेते हैं कि हिन्दी भाषी जनता ने उसे अपना लिया है, हिन्दी ने उसे अपने में खपा लिया है और अपने साँचे में ढाल लिया है, वह चाहे जहाँ से आया हो। जब ऐसी बात है, तो उसे उसके हिन्दी रूप में ही लेना चाहिए और उसे उसका पुराना अरबी फारसी जामा पहनाने का प्रयत्न करके अपनी भाषा की हीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए। सभी उन्नत भाषायें परकीय शब्दों के साथ ऐसा करती हैं। उर्दू वाले भी जब किसी प्रचलित हिन्दी शब्द को ग्रहण करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो उसे उसके चलते रूप में ही ग्रहण करते हैं (उदाहरण—‘वैपार’, ‘गाइक’, ‘समन्दर’, ‘देस’), परन्तु हिन्दी के लेखक या तो उर्दू की पुरानी गुलामी के कारण या अपना पांडित्य दिखाने के लिये ‘ज्वादह’, ‘वेजह’, ‘दर्जह’, ‘तबीअत’, ‘मुआमला’, ‘मुआफी’, आदि भी लिखते देखे जाते हैं, ‘शुरूआद’, ‘कसूर’, ‘तगदीर’, ‘तगादा’, ‘जवाब’ आदि, आदि के बजाय ‘शुरूआत’, ‘तकदीर’, ‘कुसूर’, ‘तकाजा’, ‘जवाब’, आदि की तो कोई बात ही नहीं। शायद कोई हिन्दी लेखक हिन्दी में ‘टिकट’, ‘लालटैन’, या ‘अस्पताल’ छोड़ कर ‘टिकेट’, ‘लैन्टन’ या ‘हॉस्पिटल’ लिखने की धृष्टता न करेगा, परन्तु हिन्दी के बहुतेरे लेखक ढूँढ़ ढूँढ़ कर, कोष देख देख कर उर्दू शब्दों को उनके तत्सम अरबी फारसी रूप में लिखने का प्रयत्न करते देखे जाते हैं। यह प्रवृत्ति बोर हीनता और दीनता की द्योतक है। ऊपर ग्रहण करने योग्य अरबी फारसी शब्दों के जो उदाहरण दिये गये हैं, (बर्ग (इ) और (ई) के शब्द) उन्हें उसी रूप में लिखा गया है जिस रूप में उन्हें लेना चाहिये।

(२) हिन्दी को अपने आदर्शों और सिद्धान्तों की रक्षा करते हुये सरल से सरल और बोलने में मधुर तथा सुगम बनाना चाहिये । इस संदेश की कुछ बातें ये हैं—

(अ) जहाँ तक संभव हो, संस्कृत शब्दों के बजाय देशज, और तत्सम के बजाय तद्भव शब्दों का प्रयोग होना चाहिये ।

ऊपर १. (अ) में जिन अरबी फारसी शब्दों के उदाहरण दिये गये हैं उनमें से लगभग सब के संस्कृत पर्याय भी हिन्दी में प्रचलित हैं, जबकि उनके केवल देशज पर्यायों को प्रचलित होना चाहिये था । ऐसे सब शब्द पहले प्रकार के शब्दों के उदाहरण हैं । कुछ और उदाहरण—

प्रथम (पहला), सर्वप्रथम (सबसे पहला), समस्त (सारा), कथन (कहना), इच्छुक हैं (चाहते हैं), आगमन (आना), पूर्ति के लिये (पूरा करने के लिये), वार्तालाप (बातचीत), संलग्नता (लगन), नवीन (नया), कार्य (काम), प्राचीन (पुराना), कृप (कुआँ), अन्य (दूसरा), एकत्र (इकट्ठा), नेत्र (आँख), शीतल (ठंडा), आवृत्त (ढका हुआ), व्यतीत किया (बिताया), पश्चात्ताप (पछतावा), संकीर्ण (सँकरा), आच्छादित (छाया हुआ), कण्टक (काँटा), कंटकाकोर्ण (कँटीला), पर्वतीय (पहाड़ी), पर्वत (पहाड़) ।

कुछ तत्सम शब्दों के उदाहरण जिनके बजाय तद्भव शब्दों का प्रयोग होना चाहिये—

निद्रा (नींद), लक्ष (लाख), स्वर्ण (सोना), स्वर्णकार (सुनार), लौह (लोहा), लौहकार (लुहार), चर्मकार (चमार), आर्ध (आधा), विवाह (व्याह), रात्रि (रात), छिद्र (छेद), पंक्ति (पाँती), जिह्वा (जीभ), हस्ति (हाथी), कुम्भकार (कुम्हार), ग्राम (गाँव), वाष्प (भाप) ।

यह नहीं भूलना चाहिये कि एक देशज शब्द के होते हुये संस्कृत पर्याय

का प्रयोग करना लगभग उतना ही बुरा है जितना एक स्वदेशी शब्द के होते हुये एक विदेशी शब्द का प्रयोग करना। ऐसा करने से भाषा कठिन और जनसाधारण के लिये अपरिचित सी भी बनती है। देशज शब्दों के विषय में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है। उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। सोचने की बात है कि ऊपर जिन शब्दों को मोटे अक्षरों में छपा गया है, उनको क्या आवश्यकता थी? उनसे भाषा को क्या लाभ हुआ? संस्कृत हिन्दी की माता है, हिन्दी को संस्कृत से उधार लेने का अधिकार है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दी को संस्कृत बना दिया जाय। हमें नये शब्द गढ़ते समय भी सबसे पहले देशज शब्दों और धातुओं पर नज़र डालनी चाहिये। यदि उनसे काम न चले, तभी संस्कृत या अन्य स्वदेशी और विदेशी भाषाओं को टटोलना चाहिये। तद्भव शब्द होते हुये तत्सम शब्द का प्रयोग भी अवांछनीय है और भाषा को कठिन बनाता है। अशक्तियों द्वारा बिगाड़े हुये शब्दों जैसे 'देस', 'लछ्मीनरायन', 'लच्छमी', 'गनेस', 'गाहक', 'वैपार', 'वैपारी', 'सकत' (शक्ति), 'रामन्दर', आदि को सुधारना और बात है, और सर्वमान्य 'नींद', 'लाख', 'जीम', 'रात', आदि के बजाय 'निद्रा', 'लक्ष', 'जिह्वा', 'रात्रि', आदि का लिखना और बात है। वास्तव में देशज और तद्भव शब्द ही हिन्दी के निजी, असली हिन्दी शब्द हैं, शेष तो उधार लिये हुये ही कहे जायेंगे। हिन्दी अपनी निजी सम्पत्ति की उपेक्षा करके एक धनी और स्वतंत्र भाषा नहीं बन सकती। एक बात और है। संस्कृत के शब्द प्रायः नुकीले और बोलने में कठिन होते हैं, परन्तु देशज और तद्भव शब्द हिन्दी की ध्वनि प्रणाली में ढले हुये, बोलने में सरल, मधुर, छोटे और गोलमटोल होते हैं, क्योंकि असंख्य प्राणियों के मुख में बलते बलते उनके कोने झड़ चुके होते हैं। भाषा पर ये शब्द भार स्वरूप नहीं मालूम देते। वास्तव में यही भाषा को गति और प्रवाह प्रदान करते हैं।

(आ) संस्कृत के शब्द लेते समय या संस्कृत से शब्द गढ़ते समय इस बात का पूरा खयाल रखना चाहिये कि वह शब्द हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली पर भार न हो। हमें उस शब्द को हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली के अनुसार ढालकर ग्रहण करना चाहिये। बँगला वाले ऐसा ही करते हैं। बँगला में संस्कृत शब्द हिन्दी से भी अधिक हैं, परन्तु वे सब शब्द बँगला की ध्वनि-प्रणाली में ढाल लिये गये हैं। इसीलिये बँगला इतनी मधुर भाषा है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हिन्दी की कर्कशता दूर न होगी। 'सान्निध्य', 'नैक्य', 'दौर्बल्य', 'गम्भीर्य', 'स्वातन्त्र्य', आदि 'सन्निद्धता', 'निकटता', 'दुर्बलता', 'गम्भीरता', 'स्वतन्त्रता', आदि के सुकावले में लिखने में ही नहीं, बोलने में भी कठिन हैं। ऐसे शब्दों को बोलते समय बक्ता को ऐसे शब्दों के प्रति स्वाभाविकतया अरुचि उत्पन्न होती है, और वह उनके सरल पर्याय ढूँढ़ता है। ऐसे समय प्रायः अरबी-फारसी शब्द आड़े आते हैं और बक्ता भाषा-प्रेम को तिलांजलि देकर सीधी राह पकड़ता है। यह प्राकृतिक नियम है कि यदि एक शब्द बोलने में कठिन हो और उसका कोई पर्याय बोलने में सरल, तो सरल पर्याय ही चलेगा। अपने अपने प्रदेश में एकाधिपत्य और अखंड राज राजने वाली भाषाओं की बात दूसरी है (उदाहरणार्थ तामिल प्रदेश में तामिल के कठिन से कठिन और लम्बे से लम्बे शब्द चल जायेंगे), परन्तु हिन्दी प्रदेश में हिन्दी शब्दों का उर्दू शब्दों से सुकावला है। 'आज़ादी' के सुकावले में 'स्वतन्त्रता' कहाँ चला ? हाँ, 'सुर्ख फौज़' या 'आज़ाद हिन्द फौज़' के बजाय 'लाल सेना' या 'आज़ाद हिन्द सेना' (यदि हिन्दी वालों को इसकी चिन्ता हो तो) चल सकता है। 'जंग-ए-आज़ादी' के सुकावले में 'स्वातन्त्र्य-युद्ध' नहीं चल सकता, हाँ, 'स्वाधीनता-संग्राम' चल सकता है। भाषा की ध्वनि-प्रणाली सदैव एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज़ है, हिन्दी वालों को तो हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली का ध्यान रखना अन्य कारणों से और भी आवश्यक है। जो शब्द हिन्दी की ध्वनि-

प्रणाली में नहीं खपेंगे वे या तो बिल्कुल नहीं चलेंगे या, यदि उनके मुकाबले पर दूसरे शब्द न हुए तो, हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली में स्वतः ढल जायेंगे और लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में भारी अन्तर पड़ जायगा। हिन्दी में 'टिकेट' नहीं खप सकता था, इसलिये वह 'टिकट' हो गया, 'लैन्टर्न' 'लाल-टैन' हो गया। अँगरेज़ी में 'बम्बई' नहीं खपता था, इसलिये वह 'बाम्बे' हो गया, 'कलकत्ता' 'कैलकटा' हो गया, 'मथुरा' 'मटरा' हो गया, इत्यादि। हिन्दीवालों को अपनी भाषा की ध्वनि-प्रणाली पहचानना चाहिये और उसके अनुसार चलना चाहिये। तुलसी और हिन्दी के अन्य प्राचीन कवियों की रचनाओं में संस्कृत शब्दों को हिन्दी के साँचे में ढालकर ही लिया गया है। उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यही है। गाँववाले आनन्द के साथ कवीर की साखियाँ गाते हैं और गा पाते हैं। 'प्रसाद', पन्त या 'निराला' की कविता का प्रवाह भी क्या उनके कण्ठ से इसी स्वच्छन्दता के साथ निकल सकता है? संस्कृत शब्दों की व्यर्थ की तोड़-मरोड़ अच्छी नहीं (इस मामले में प्राचीन हिन्दी कवि भी निर्दोष नहीं कहे जा सकते), परन्तु संस्कृत शब्दों को सदैव अपने मूल तत्सम रूप में लेने का मोह भी अच्छा नहीं।

(इ) हिन्दी में यौगिक और समास-युक्त शब्दों का कम से कम प्रयोग होना चाहिये। जहाँ तक हो सके, शब्द लम्बे न हों।

(ई) विषय चाहे गम्भीर हो चाहे हल्का, भाषा सरल से सरल होनी चाहिये। जो बात कम शब्दों में, सरल शब्दों में, और सीधी तरह कही जा सकती है, उसे शब्दाडम्बर के साथ, कठिन शब्दों में, घुमा फिरोकर कहने की प्रवृत्ति कभी अच्छी नहीं कही जा सकती। आधुनिक हिन्दी को 'ग्रामफहम' बनाने के लिये उसे कांग्रेस की या वर्धा की हिन्दुस्तानी बनाने की ज़रूरत नहीं और न वह इस प्रकार ग्रामफहम हो सकती है परन्तु उसे अभी और सरल अवश्य बनाया जा सकता है। सदैव सरल से सरल शैली का प्रयोग होना चाहिये।

(उ) हिन्दी कविता को भाषा को बहुत सरल करने की ज़रूरत है । यहाँ भाव से नहीं, भाषा से अभिप्राय है । हिन्दी कविता का कुछ हाल ही समझ में नहीं आता । एक ओर तो उसमें तुक बैठाने के लिये चाहे किसी अरबी फारसी शब्द को घुसेड़ दिया जाता है (उदाहरणार्थ 'वेढव' बनारसी के दोहे) और दूसरी ओर उसमें चाहे किसी, कठिन से कठिन, नितान्त अपरिचित और अनावश्यक संस्कृत शब्द को धर दिया जाता है । कवि-गण यह सोचने का कष्ट नहीं करते कि यह शब्द 'हिन्दी' का है भी या नहीं । वे अपने आप को अक्षरशः सब नियमों से मुक्त समझते हैं । ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो उन्हें यह समझा सके कि कवित्व-शक्ति अपनी भाषा के शब्दों, सरल से सरल शब्दों, में भाव प्रकट करने में है, दुनिया भर की भाषाओं—चाहे अरबी फारसी चाहे संस्कृत—के शब्दों का जमघट करके तुक मिलाने में नहीं । ऐसा मालूम होता है कि अधिकांश आधुनिक हिन्दी कवियों को सुबोधता, प्रवाह और रचानगी से शब्दाडम्बर अधिक प्रिय है । परिणाम यह है कि इन कवियों को लोकप्रियता तो नहीं मिलती ही, हिन्दी की भी गहरी हानि हो रही है । हिन्दी के वर्तमान कवियों को कितनी कवितायें ऐसी हैं जो जनता को ज़बान पर चढ़ गई हैं ? परन्तु सड़े हुये, अर्थहीन, वे सिर पैर के फिलमो गात चारों ओर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हँसते रोते सुनने को मिल जायेंगे । जब तक कवि-गण अपनी कोठरी में बैठकर शब्द-जाल रचने और कविताओं में दुरुह शब्दों और उनसे भी दुरुह भावों (जिन्हें शायद वे स्वयं नहीं समझते) को भरने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, तब तक जनता इन्हीं गन्दे फिलमी गीतों से अपना मनोरंजन करती रहेगी । ऐसी बात नहीं कि उत्तम साहित्य जन-मुलभ नहीं हो सकता या लोक-मुलभ भाषा में नहीं रचा जा सकता । वास्तव में उत्तम साहित्य की पहचान यही है कि वह लोक-मुलभ हो । तुलसी का उच्च प्रकाश-स्तंभ अभी हजारों वर्ष तक हिन्दी के ही नहीं, अन्य भाषाओं के कवियों

का भी मार्ग-प्रदर्शन कर सकता है। वास्तव में हिन्दी के कवियों को अत्यन्त प्रशस्त और प्राचीन परंपरायें विरासत में मिली हैं। यदि वे उससे लाभ न उठायें, तो यह हिन्दी का दुर्भाग्य है। आधुनिक युग में बंगाल में रवीन्द्र ने जनता को जन-कविता दी, फलस्वरूप बंगाल के एक एक वक्ते की ज़बान पर टैगोर के गीत विराजमान हैं। इस प्रकार कवीन्द्र रवीन्द्र ने साहित्य और जनता के बीच की खाई को पाटा, परन्तु हिन्दी के कवि साहित्य और जनता के बीच की खाई को और चौड़ा कर रहे हैं। हिन्दी के कवियों को तुरन्त अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिये। उन्हें राष्ट्र की कविता का निर्माण करना है। यदि हिन्दी कवि अपनी भाषा को सरल कर लें, तो कवि-सम्मेलनों द्वारा हिन्दी-प्रचार में भी बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। कवि-सम्मेलनों की लोकप्रियता भी बढ़ेगी और उनसे जनता के सांस्कृतिक जीवन का स्तर भी ऊँचा होगा और जनता की रुचि परिमार्जित होगी।

(३) उच्च विषयों के लिये पारिभाषिक शब्द बनाये जायँ और उन्हें निश्चित (standardise) किया जाय। इन शब्दों की अन्य भारतीय भाषाओं को भी आवश्यकता है। अच्छा हो यदि सभी भारतीय भाषाओं के विद्वान् मिलकर पारिभाषिक शब्दों के एक स्टैंडर्ड कोष का निर्माण करें। उर्दू के प्रतिनिधि न बुलाये जायँ, क्योंकि उर्दू वाले अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाने पर तुले हुये हैं। उन्हें बुलाने से केवल व्यर्थ का विवाद होगा, और जो काम हो सकता है वह भी न होगा *।

* पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्दावली गढ़ने के विषय में डा० रघुवीर के आधीन इंटरनेशनल एकाडेमी आफ इंडियन कल्चर, लाहौर, का प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय है। डा० रघुवीर देश और विदेश के विद्वानों की सहायता और सहयोग से आधुनिक ज्ञान और विज्ञान को लगभग ६०० विशिष्ट शाखाओं के लगभग २० लाख अँगरेजी तथा अन्य पारिभाषिक भाषाओं के पारिभाषिक शब्दों के स्वदेशी पर्याय गढ़ने में संलग्न हैं। ये सब पर्याय संस्कृत

हिन्दी को अदालतों, दफ्तरों और सरकारी काम काज एवं शासन (administration) में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की भी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि पिछली कई शताब्दियों से इन स्थानों में या अरबी फारसी के शब्द चले हैं या अँगरेज़ी के। हिन्दी का एक स्टैंडर्ड अदालती और शासन-शब्द-संग्रह प्रकाशित किया जाय जिसमें उन अरबी फारसी या अँगरेज़ी शब्दों को रक्खा जाय जिन्हें हिन्दी में रखना मंज़ूर है और शेष के हिन्दी पर्याय देशी धातुओं से बना कर या प्राचीन ग्रन्थों को शोध कर कोष-वद्ध किये जायँ।

वैज्ञानिक, अदालती या शासन सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों के विषय में धाँधली और गड़बड़ की बिलकुल गुन्जाइश नहीं रहनी चाहिये। विद्वान् मिल कर पारिभाषिक शब्दों को अन्तिम रूप से तय करें, और फिर स्टैंडर्ड कोष छपें। इस समय इस मामले में बड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। कोई 'त्रिकोण' लिखता है, कोई 'त्रिभुज', कोई 'धारा-सभा' लिखता है, कोई 'व्यवस्थापिका-सभा' (कोई 'असेम्बली' भी); कोई 'अदालत' लिखता है, कोई 'कोर्ट'; कोई 'मुद्दई मुद्दालह' लिखता है, कोई 'बादी प्रतिवादी'; कोई 'जज' लिखता है, कोई 'न्यायाधीश', इत्यादि, इत्यादि। हिन्दी के समाचार-पत्रों का तो बुरा हाल है। मालूम होता है उनके सामने कोई आदर्श है ही नहीं। खूब मनमानी चल रही है। चाहे कोई संस्कृत का,

शब्दों और धातुओं से बनाये जा रहे हैं जिससे सब भारतीय, आर्य तथा द्रविड़, भाषाओं की पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्दावली एक ही हो। इस अँगरेज़ी-हिन्दी (भारतीय) पारिभाषिक कोष का प्रत्येक शब्द देवनागरी, बँगला, तामिल तथा कन्नड़ लिपियों में छपा जा रहा है। हिन्दी की साहित्यिक संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे डा० रघुवीर से सम्पर्क स्थापित करें, उनके कार्य में सब प्रकार से पूर्ण सहयोग दें और इस महाकोष से पूरा लाभ उठायें तथा अदालती, शासन संबंधी, आदि शब्दावली को अलग से छाप कर हिन्दी संसार के सामने रखें और उन शब्दों को प्रचलित करें।

अँगरेज़ी का या अरबी फ़ारसी का शब्द उठा कर धर दिया जाता है और फिर भी एक अर्थ में सदैव एक ही शब्द का प्रयोग नहीं होता। साधारण से साधारण शब्द के मामले में वही हाल है (उदाहरण के लिये 'Dead-lock' के लिये 'ज़िच', 'अड़ंगा', 'गति-अवरोध' आदि, आदि चलते हैं जिनमें से कोई भी ठीक अर्थ को व्यक्त नहीं करता)। इसमें समाचार-पत्रों का अधिक दोष नहीं। उनके सामने कोई स्टैंडर्ड और पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है ही नहीं। कारण जो भी हों, 'भाषा' की संज्ञा का दावा करने वाली किसी भाषा के लिये यह अत्यन्त लज्जा की बात है।

(४) एक हिन्दी एकाडेमी की स्थापना होनी चाहिये जो भाषा-विषयक सब विवादों का फैसला करे, ऊपर भाषा संबन्धी जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है उनके अनुसार भाषा में परिवर्तन, संशोधन करके भाषा का स्वरूप निश्चित करे और उसका आदर्श सामने रखे। यही हिन्दी हमारी 'आदर्श हिन्दी' या 'किंग्स हिन्दी' होगी। अब तक जो कार्य हिन्दी के कुछ लेखकों ने व्यक्तिगत रूप से किया है, वह अब एक हिन्दी एकाडेमी ही कर सकती है। अब एक हिन्दी एकाडेमी ही हिन्दी पर उचित नियंत्रण रख सकती है और हिन्दी लेखकों पर यथेष्ट और व्यापक प्रभाव डाल सकती है। यही एकाडेमी अरबी फ़ारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित करे और हिन्दी का स्टैंडर्ड कोष प्रकाशित करे जिसमें केवल वे ही अरबी फ़ारसी शब्द हों जिन्हें हिन्दी में रखना है। इस कोष में सब शब्द अपने निश्चित रूपों में हों। इस स्टैंडर्ड कोष को अपडेट रखना अर्थात् समय समय पर उसके परिवर्धित संस्करण प्रकाशित करना भी इसी एकाडेमी का काम होगा। इस एकाडेमी को एक स्टैंडर्ड और परिपूर्ण अँगरेज़ी-हिन्दी कोष भी प्रकाशित करना चाहिये। यह एकाडेमी उन अरबी फ़ारसी शब्दों की एक अलग तालिका भी प्रकाशित करे जिनका हिन्दी से बहिष्कार होना चाहिये, और आगे के लिये भी उचित कार्रवाई करे जिससे हिन्दी अरबी-

फारसी, अँगरेजी और उर्दू के सम्पर्क से अवांछनीय रूप से कलुषित न होने पावे। भाषा और लिपि की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसी एकाडेमी के तत्वावधान में होनी चाहिये। जनपदीय बोलियों के साहित्य का अध्ययन और संकलन किया जाय, वज्रियों, बड़इयों, लुहारों, सुनारों, राज सज्जद्वारों, आदि के नित्य काम में आने वाले शब्दों को इकट्ठा करके स्टैंडर्डइज़ किया जाय, उनका हिन्दी कोष में समावेश किया जाय और जिन शब्दों की हमें जरूरत है उन्हें अधिकाधिक संख्या में इन स्रोतों से लिया जाय तथा बढ़ा जाय। स्टैंडर्ड हिन्दी पारिभाषिक शब्द कोष, जिसकी हिन्दी में उच्च विषयों को पढ़ाने के लिये बहुत शीघ्र आवश्यकता पड़ेगी, का निर्माण भी इस एकाडेमी का एक महत्त्वपूर्ण कार्य होगा। यह एकाडेमी अपना एक अलग पत्र भी प्रकाशित करे, जिसके द्वारा भाषा संबंधी सभी बातों पर अधिकृत रूप से प्रकाश डाला जाय। श्रीयुत रामचन्द्र वर्मा की 'अच्छी हिन्दी' जैसी पुस्तकें एकाडेमी तैयार करा के प्रकाशित करे। इन पुस्तकों में हिन्दी जनता और हिन्दी लेखकों को 'हिन्दुस्तानी' की ओर से सावधान करते हुये यह भी साफ़ तौर से बतलाया जाय कि अच्छी हिन्दी का 'हिन्दुस्तानी' से कोई सरोकार नहीं, अच्छी हिन्दी में व्याकरण, मुहावरों, स्पेलिंग, आदि के साथ साथ शब्दावली का नामला भी शामिल है और अच्छी हिन्दी को शब्दावली की दृष्टि से भी अच्छी और शुद्ध होना चाहिये। ऐसी पुस्तकें स्कूलों, कालेजों, और विश्वविद्यालयों में हिन्दी विषय के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य पाठ्य-पुस्तकें स्वीकृत कराई जायँ। सारांश में, यह एकाडेमी भाषा को शुद्ध, परिमार्जित, सरल, सुबोध, समृद्ध, व्यापक और समुद्र बनाने का प्रमुख, केन्द्रीय एवं सर्वमान्य साधन होगी जिनका निर्णय भाषा संबंधी सब बातों में अंतिम होगा। इस एकाडेमी की स्थापना के लिये सबसे पहले कदम उठाना चाहिये नागरी प्रचारिणी सभा, काशी को। अपनी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को हिन्दी प्रचार और हिन्दी के राजनीतिक पहलू से निवटने के लिये ऐसे सुदृढ कार्यों के भार से मुक्त कर देना चाहिये।

(५) एक हिन्दी समाचार एजेन्सी की स्थापना की जाय जो हिन्दी पत्रों को शुद्ध, आदर्श, स्टैंडर्ड हिन्दी अर्थात् 'किंग्स हिन्दी' में समाचार सप्ताई करे। इससे भाषा का स्वरूप निश्चित करने में सहायता मिलेगी, भाषा विषयक धाँधलीवाज़ी दूर होगी, पत्रों का स्तर और स्टैंडर्ड ऊँचा होगा, पत्रों के अनुवाद-सम्पादकों की कठिनाइयाँ दूर होंगी और हिन्दी पत्र अँगरेज़ी पत्रों का स्थान ले सकेंगे। पढ़ने में आया है कि कोई सज्जन देवनागरी का टेलीप्रिन्टर बना रहे हैं जिससे हिन्दी में समाचार अँगरेज़ी में समाचारों की भाँति भेजे जा सकेंगे, परन्तु जब तक वह नहीं बनता तब तक हिन्दी समाचार एजेन्सी को डाक और तार से ही काम निकालना चाहिये। यह एजेन्सी कांग्रेस नेताओं के 'हिन्दुस्तानी' भाषण और वक्तव्य भी स्टैंडर्ड हिन्दी में भेजे जिससे हिन्दी पत्रों द्वारा भाषा कलुषित न होने पावे। (आज-कल कितने ही पत्र कांग्रेस नेताओं के हिन्दुस्तानी उर्फ उर्दू के भाषण ज्यों के त्यों छाप देते हैं ; नेताओं को उपस्थित जनता के ६५ प्रतिशत के वजाय मुसलमानों को अपनी बात समझाने की ज़्यादा चिन्ता होती है, पर हिन्दी पत्र तो हिन्दी का न सही, कम से कम हिन्दी पाठकों का ख्याल रखें ।) जब आल इन्डिया रेडियो हमारी न्यायोचित माँग पूरी करने के लिये विवश होगा, तो जिस प्रकार बी. बी. सी. अँगरेज़ी भाषा का और उसके शुद्ध उच्चारण का आदर्श संसार के सामने रखता है, उसी प्रकार हिन्दी समाचारों के प्रसार द्वारा अच्छी हिन्दी का आदर्श सामने रखा जा सकेगा।

(६) हिन्दी और देवनागरी के माध्यम से उर्दू प्रचार विलकुल बन्द हो जाना चाहिये। कुछ विशेष बातें जिनकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है, निम्नलिखित हैं—

(अ) पहला कर्तव्य हिन्दी पत्रों के सम्पादकों का है। उन्हें सब समाचार, वक्तव्य, आदि शुद्ध और अच्छी हिन्दी में छापना चाहिये। कांग्रेस नेताओं की 'हिन्दुस्तानी' को ज्यों का त्यों छापने का मोह

त्यागना होगा। कांग्रेस नेता जब अँगरेजी बोलते या लिखते हैं तब शुद्ध और अच्छी अँगरेजी बोलने या लिखने का शक्ति भर प्रयत्न करते हैं। ईश्वर की कृपा से उन्हें अच्छी अँगरेजी आती भी है, इसलिये अँगरेजी पत्रों को उनके भाषण, वक्तव्य, लेख, आदि ज्यों के त्यों छापने में कोई उज़्र नहीं होता। परन्तु जब वे 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं तो हिन्दी या उर्दू की साहित्यिक परंपरा और शुद्धता का ध्यान नहीं रखते (कुछ नेताओं को छोड़ कर किसी प्रकार की 'हिन्दुस्तानी', जिसके वे गुण गाते फिरते हैं, अच्छी तरह उन्हें आती ही नहीं और न वे अच्छी तरह सीखने की आवश्यकता समझते हैं : कोई सा हिन्दी शब्द किसी भी उर्दू शब्द के साथ बैठाल दिया, होगई कांग्रेस मार्का 'हिन्दुस्तानी')। वे भाषा को जान बूझकर विकृत करने का प्रयत्न करते हैं। हिन्दी पत्र उनकी अनर्गल और अटपटी 'हिन्दुस्तानी' छाप कर अपनी भाषा की मट्टी पत्तीद नहीं कर सकते।

(आ) हिन्दी में विदेशियों या मुसलमानों का कथोपकथन उर्दू में नहीं होना चाहिये। यह एक अत्यन्त अस्वाभाविक और आपत्तिजनक बात है, इसलिये और भी कि बड़े बड़े साहित्यिक इस भ्रम में फँसे हुये मालूम पड़ते हैं कि विदेशियों और मुसलमानों से उर्दू में ही बातचीत कराना उचित है। इस विषय में कुछ समय पहले हिन्दी पत्रों में प्रकाशित 'हिन्दी कृतियों में मुसलमान पात्रों का उर्दू में कथोपकथन' शीर्षक लेख में (देखिये परिशिष्ट १) विद्वान लेखक ने जो कहा है, उसके बाद कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

(इ) हिन्दी गद्य या पद्य में इस प्रकार के वाक्यांश लिखना अत्यन्त मूर्खतापूर्ण और अनुचित है—'हिन्दी का विद्वान्, उर्दू का माहिर,' 'हिंदुओं की देशभक्ति, मुसलमानों की हुवुलतबतनी,' 'हिन्दुओं का धर्म और मुसलमानों का मज़हब,' 'श्री.....ने कविता सुनाई, जनाब.....ने अपनी नज़्म सुनाई' आदि, आदि। ये सब उदाहरण हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रों से लिये गये हैं।

भाषा के इस पाकिस्तान और वर्ण-भेद के विषय में कुछ कहना अनावश्यक है। यह दोष बहुत हद तक ऊपरवाले दोष (आ) के अन्तर्गत है। यह उर्दू की गुलामी के सिवा और कुछ नहीं। अँगरेज़ी में इस प्रकार लिख कर कोई नाम पैदा करना नहीं चाहेगा:—‘Patriotism of Christians, desh-bhakti of Hindus, hubbulvatni of Muslims’, ‘Christian religion, Hindu dharma and Muslim mazhab’, ‘English poems, Hindi kavitas, Urdu nazms’, आदि।

दूसरे शब्दों में, हिन्दी की एक निश्चित संस्कृति होनी चाहिये। प्रत्येक भाषा की एक संस्कृति होती है, अर्थात् प्रत्येक भाषा एक विशिष्ट संस्कृति का प्रतीक होती है, और उसमें उसी संस्कृति का वातावरण लक्षित होता है तथा उसी की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। अँगरेज़ी की संस्कृति ईसाई अँगरेज़ों की संस्कृति है। उसमें प्रत्येक धर्म का पात्र अँगरेज़ी में वात करता है, सब को ‘मिस्टर’ कहा जाता है (किसी को ‘श्री’ या ‘जनाब’ नहीं), सबके धर्म को ‘रिलीजन’, सब के पिता को ‘फादर’, सबकी माता को ‘मदर’, इत्यादि कहा जाता है। हिन्दी की संस्कृति क्या हो? उर्दू की संस्कृति मुसलमानी संस्कृति है। तथाकथित ‘हिन्दुस्तानी’ की संस्कृति भी वही है। डा० ताराचन्द्र और पं० सुन्दरलाल की प्रयागवाली ‘हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी’ की ‘हिन्दुस्तानी कलचर’ की परिभाषा है शिक्षित समाज के आदाबअर्ज़ और पैजामा वाले वर्ग की संस्कृति। उनके लिये वही हिन्दू-मुस्लिम सम्मिश्रित संस्कृति का आदर्श है, और उसी वर्ग की भाषा आदर्श ‘हिन्दुस्तानी’ है। उनकी नज़र में न नमस्ते और धोती वाले वर्ग की संस्कृति का कोई महत्व है, और न शहरों और गाँवों में बसनेवाली करोड़ों हिन्दू और मुसलमान जनता की संस्कृति का—जिस प्रकार उनकी नज़र में इनकी ‘हिन्दुस्तानी’ का कोई महत्व नहीं। परन्तु हम तो आदाबअर्ज़ और पैजामा वाले वर्ग की संस्कृति को गुड मॉर्निंग और पतलून वाले वर्ग की संस्कृति से

अधिक महत्व नहीं दे सकते, और जिस प्रकार शहरों के शिक्षित, अल्प-संख्यक वर्ग की उर्दू या इङ्गलिस्तानी जनता पर लादना अनुचित समझते हैं, उसी प्रकार जनता पर आदाबअर्ज़ और पैजामावाले वर्ग की संस्कृति लादना अनुचित समझते हैं। हिन्दी की संस्कृति परम्परागत भारतीय संस्कृति है जिसका आधार हिन्दू संस्कृति है। हिन्दी में सब धर्मों के साथ हिन्दी में बोलेंगे, कोई उर्दू में नहीं बोलेंगा; सबके धर्म को 'धर्म' कहा जायगा, किसी के धर्म को 'मज़हब' नहीं; सब धर्मों के अनुयायियों को 'श्री' से सम्बोधित किया जायगा, किसी को 'जनाब' या 'हुज़ूर' या 'साहब' से नहीं; सबके पिता को 'पिता' कहा जायगा, किसी के पिता को 'अव्वा जान' नहीं; सबकी माता को 'माता' कहा जायगा, किसी की माता को 'अम्मी जान' नहीं; सब धर्मों के अनुयायी 'नमस्ते' करेंगे और 'धन्यवाद' देंगे, कोई 'आदाब अर्ज़' या 'गुड मॉर्निंग' नहीं करेगा और न कोई 'शुक्रिया' अदा करेगा या 'थैंक यू' कहेगा, इत्यादि, इत्यादि। अधिकांश हिन्दी लेखक अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ तो इन नियमों का पालन करते हैं, परन्तु मुसलमानों के साथ नहीं करते। वे ईसाई और अँगरेज़ पात्रों से अँगरेज़ी में, चीनी पात्रों से चीनी में, रूसी पात्रों से रूसी में न बोलवाकर सब से हिन्दी में ही बोलवाते हैं, परन्तु मुसलमानों से उर्दू में बोलवाते हैं। वे 'ईसाई धर्म', 'शिन्तो धर्म', आदि तो कहते हैं, परन्तु मुसलमानों का 'मज़हब' ही रहता है। एक ईसाई, चीनी या जापानी से तो 'नमस्ते', 'धन्यवाद', 'पिता' कहलवायेंगे परन्तु मुसलमान से 'आदाब अर्ज़', 'शुक्रिया' और 'अव्वा जान' ही कहलवायेंगे। कुछ और हिन्दी लेखकों की अवस्था इनसे भी अधिक दिगड़ी हुई है। उन्होंने हिन्दी और हिन्दी संस्कृति को केवल भारतवासी हिन्दुओं के लिये रिजर्व कर दिया है और शेष सब धर्मों और देशों के लोगों पर उर्दू और मुसलमानी संस्कृति थोप दी है (उदाहरणार्थ, श्रीगुरुदेवविहारी मिश्र कृत 'पुण्यमित्र')। भाषा का यह स्वनिर्मित पाकिस्तान हिन्दी और देवनागरी द्वारा

उर्दू प्रचार में सहायक तो है ही, हिंदीवालों की मूर्खता और होनता और हिन्दी की अपमानजनक स्थिति का द्योतक भी है। इस पाकिस्तान को तुरन्त दूर करना चाहिये।

(ई) हिंदी में उर्दू के अवतरण, शेरें, इत्यादि प्रायः इस प्रकार उद्धृत की जाती हैं मानो वे हिंदी की ही हों। कुछ और हिंदी लेखक हिंदी और देवनागरी द्वारा उर्दू प्रचार के पुण्य कार्य को पूर्ण करने के लिये उर्दू शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके हिंदी पर्याय लिख देते हैं जिससे हिंदी पाठकों को उर्दू सीखने में किसी प्रकार की असुविधा न हो ! यह एक अत्यन्त शोचनीय अवस्था है जिसे तुरन्त दूर होना चाहिये। उर्दूवाले उर्दू में हिंदी के अवतरण देवनागरी से उल्था करके उर्दू लिपि में ज्यों के त्यों धरने की मूर्खता करके उर्दू पाठकों के कोम-भाजन नहीं बनते और न अपनी मूर्खता को छिपाने के लिये (या उसे पूर्णतया सिद्ध करने के लिये !) फिर हिन्दी शब्दों के आगे कोष्ठकों में उर्दू शब्द लिखते हैं। यदि वे ऐसी मूर्खता करने की सोचें भी, तो उनकी लिपि उन्हें तुरन्त ठीक रास्ता दिखा देगी। अँगरेज़ी में जब किसी दूसरी भाषा का अवतरण उद्धृत किया जाता है तो उसका मूल न देकर उसका अँगरेज़ी अनुबाद दिया जाता है। यदि मूल देना आवश्यक ही होता है, तो उसके साथ उसका अँगरेज़ी अनुबाद अवश्य दिया जाता है। ऐसा ही हिन्दी में होना चाहिये। उर्दू से हिंदी में अनुबाद करना तो फिर अपेक्षाकृत सरल है। जिस हिन्दी लेखक को उर्दू का अवतरण उद्धृत करना हो वह यदि मूल को उर्दू लिपि से ज्यों का त्यों देवनागरी में रखने के बजाय देवनागरी में उसका हिंदी अनुबाद लिखता चले, तो उसे तों कोई विशेष कष्ट नहीं होगा, परन्तु पाठक पर उसकी बड़ी कृपा होगी और हिन्दी की रक्षा भी हो जायगी। यदि मूल देना आवश्यक ही हो तो उसे उर्दू लिपि में दिया जाय। उर्दू हिंदी की एक शैली ही सही, परन्तु उसकी अपनी अलग लिपि भी तो है। जिस प्रकार हिन्दी में आवश्यकता पड़ने पर अँग-

रेज़ी के मूल अवतरण अँगरेज़ी की लिपि अर्थात् रोमन लिपि में दिये जाते हैं और देवनागरी में उनका हिंदी अनुवाद दिया जाता है, उसी प्रकार यदि उर्दू का अवतरण मूल रूप में देना आवश्यक हो तो उसे उर्दू लिपि में दिया जाय और देवनागरी में उसका हिन्दी अनुवाद दिया जाय। जो पाठक उर्दू जानता है और मूल समझ सकता है, वह उर्दू लिपि में पढ़ भी लेगा— देवनागरी द्वारा हिंदी पाठकों को उर्दू क्यों सिखाई जाय ? जब तक उर्दू वाले देवनागरी को स्वीकार नहीं करते अर्थात् जब तक उर्दू देवनागरी में नहीं लिखी जाती, और जब तक उर्दूवाले एक पृथक लिपि में लिखकर उर्दू नामक एक पृथक भाषा या शैली की सृष्टि और विकास करना नहीं छोड़ते, तब तक देवनागरी में सदेव हिंदी ही होनी चाहिये, उर्दू कभी नहीं। हिंदी पत्र पत्रिकाओं को देवनागरी में उर्दू के लेख, कवितायें भी नहीं छापनी चाहिये और न उर्दू पुस्तकों की समालोचना करनी चाहिये।

हिंदी में जब किसी अग्रहीत अरबी फारसी शब्द को किसी विशेष कारण से प्रयुक्त करना पड़े, तो उसे उसी प्रकार उल्टे कामाओं के बीच में और उसके आगे कोष्ठक में उस शब्द को फारसी लिपि में लिखकर प्रयुक्त करना चाहिये जिस प्रकार हिंदी में अग्रहीत और अपरिचित अँगरेज़ी शब्द उल्टे कामाओं के बीच में लिखा जाता है और उसके आगे कोष्ठक में उसे रोमन लिपि में लिखा जाता है। इससे पाठक को मालूम हो जायगा कि यह शब्द विदेशी है, हिंदी का नहीं है और यहाँ किसी विशेष कारण से प्रयुक्त किया गया है। अँगरेज़ी में इस प्रकार के शब्दों को प्रायः इटैलिक्स में लिखा जाता है।

(उ) हिन्दी के कुछ लेखकों और कवियों ने हास-परिहास की परिभाषा अधिकाधिक उर्दू शब्दों का प्रयोग ही मान रखी है। उनकी राय में परिहास की पराकाष्ठा यही है कि हिन्दी शब्दों के स्थान में ढूँढ़ ढूँढ़ कर दूरूह अरबी फारसी शब्द धर दिये जायँ। अपनी ही भाषा में अपने ही शब्दों

द्वारा हँसने हँसाने में उन्हें आनन्द नहीं आता । जब तक वे हास्य के स्तम्भ में 'हमारी न्यायशीला सरकार ने हमें न्याय प्राप्त करने की जो सुविधायें प्रदान की हैं' लिखने के बजाय 'हमारी इन्साफ़रसन्द सरकार ने इन्साफ़ हासिल करने की जो सहूलियतें हमें बखशी हैं' न लिखेंगे, तब तक उनको समझ में इस वाक्य में हास्य का पुट नहीं आ सकता । उदाहरण के लिये, हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'देशदूत' को लीजिये । उसके सबसे पहले पृष्ठ पर ही 'सीधो टेढ़ी खरी मजेदार' शीर्षक हास्य का स्तम्भ रहता है । ऐसा मालूम होता है कि इस स्तम्भ के लेखक की राय में, और सम्पादक की राय में भी, इस स्तम्भ की मुख्य विशेषता और आकर्षण अरबी फ़ारसी शब्दों का प्रयोग ही है । केवल एक ही अंक में इस स्तम्भ के अन्तर्गत चुटकुलों में प्रयुक्त कुछ अरबी फ़ारसी शब्दों के नमूने देखिये—ख़सूसियत, शायी, तनज़ुली, ज़ुरत, मुतफ़्फ़ी, मह-रूम, इलहाम, निजात, फिरकापरस्ती, तरमीम, अख़बारनबोस, बाशिन्दा, हुब्बुलबतनी, राज़, पैग़ाम, मुख्तलिफ़, मौजू, ख़ाबिन्द, महदूद, बाक़ई, शिगूफ़ा, इमदाद, इत्यादि ।

हास्य के कवियों का भी वही हाल है । हास्य-जगत के दो प्रमुख कवियों 'वेधङ्क' और 'वेढव' बनारसी की हास्यपूर्ण कवितायें वा तुकबन्दियाँ प्रायः साप्ताहिक 'संसार' और 'देशदूत' में छपती हैं । इन कविताओं और तुकबन्दियों की एक विशेषता यह है कि इनकी भाषा में किसी अरबी फ़ारसी शब्द के प्रवेश करने पर कोई रोक-टोक नहीं—हिंदी के शब्दों की संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या में अनाधिकारी अरबी फ़ारसी शब्द इन कविताओं और तुकबन्दियों में बिग़ाजमान रहते हैं ।

हास्य की यह परिभाषा हिंदी को छोड़कर संसार की किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलेगी । उर्दू में तो कदापि नहीं ।

(७) कांग्रेस की ओर से देश भर में प्रचार किया जाता है कि युक्त-प्रान्त की भाषा 'हिंदुस्तानी' है जिसका अर्थ हुआ कि 'हिंदी' किसी प्रदेश

की मातृ-भाषा नहीं है, वह तो केवल साहित्य में पाई जाती है। 'हिंदुस्तानी' के समर्थक कांग्रेस नेताओं के विचार में युक्तप्रान्त की जनपदीय बोलियाँ ब्रज, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी, आदि 'हिंदुस्तानी' की—उसी 'हिंदुस्तानी' की जिसे वे सभा सोसाइटियों में मंच से बड़े चाव से बोलते हैं—बोलियाँ हैं, हिंदी की नहीं। देश भर में इस प्रचार से अत्यन्त आति फैल रही है और हिंदी की घोर हानि हो रही है। जब भाषा के आधार पर प्रान्तों की सीमा निर्धारण का प्रश्न आता है, तो युक्तप्रान्त 'हिंदुस्तानी भाषी क्षेत्र' (Hindustani speaking area), कांग्रेस की सहमति और प्रेरणा से, माना जाता है। (इस 'क्षेत्र' में मध्य-प्रान्त और बिहार भी शामिल कर दिये जाते हैं!) यहाँ की भाषा 'हिंदुस्तानी' ठहराई जाती है, हिन्दी नहीं। फलतः कांग्रेस के राज्य में यहाँ की प्रान्त-भाषा या राज-भाषा अपने आप वही दो लिपियों वाली 'हिंदुस्तानी' होगी जिसे भारत के विभिन्न प्रान्तों, जातियों और सम्प्रदायों को खुश करने के लिये आधी हिंदी और आधी उर्दू में थोड़ी सी बँगला, थोड़ी सी तामिल, थोड़ी सी पश्तो, आदि छोड़कर भारत के ४० करोड़ नर-नारियों की राष्ट्र-भाषा के पद को सुशोभित करने के लिये बड़े बड़े भट्टों में पकाया जा रहा है। कितनी आत्तानी से 'हिंदी' की जड़ कट गई और हो गया कांग्रेस और गांधीजी की प्रिय 'हिंदुस्तानी' का दखल ! 'हिंदुस्तानी' भी एक प्रान्तीय भाषा, एक प्रान्त की (या कई प्रान्तों) की मातृ-भाषा होगई ! चूँकि 'हिंदुस्तानी' अभी तक कुछ नहीं और इसलिये सब कुछ है, युक्त-प्रान्त की पुरानी राज-भाषा उर्दू (क्या वह 'हिंदुस्तानी' नहीं है ? ख़ास तौर से बर्धा के पंडितों के अनुसार तो जैसे हिंदी हिंदुस्तानी, वैसे उर्दू हिन्दुस्तानी) को निकालने की बात कैसी ? बस, उर्दू ज़िन्दाबाद ! केवल इतना और आपस में तय कर लिया जाय कि उर्दू को उर्दू नाम से कभी न पुकारा जाय, उसे सदैव 'हिन्दुस्तानी' नाम से पुकारा जाय और लोगों को देवनागरी में भी लिखने की छूट दे दी जाय ! (डा० ताराचन्द और पं०

सुन्दरलाल खुशी के लड्डू बाँटें !) बँगला के आधार पर बंगाल, मराठी के आधार पर महाराष्ट्र, गुजराती के आधार पर गुजरात, तामिल के आधार पर तामिलनाद, तेलगू के आधार पर आन्ध्र और इसी प्रकार अपनी अपनी मातृ-भाषाओं के आधार पर अन्य प्रान्त बन जायेंगे जिनमें उनकी अपनी अपनी मातृ-भाषायें और मातृ-लिपियाँ राजभाषा और राजलिपि बनेंगी और फलेंगी-फूलेंगी (स्कूलों में द्वितीय भाषा के रूप में अँगरेज़ी की भाँति 'हिन्दुस्तानी' या किसी दूसरी भाषा को भले ही पढ़ाया जाय), परन्तु हिन्दी के पल्ले पड़ेगा 'हिन्दुस्तानी भाषी प्रदेश' जहाँ हिन्दी को नहीं, 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित किया जायगा, अर्थात् उर्दू को इसी प्रकार अखण्ड राज्य करने दिया जायगा । 'हिन्दी' का, 'हिन्दी भाषी' कोई प्रदेश या प्रान्त ही नहीं होगा, जिसका अर्थ होगा कि भारत में 'हिन्दी' कहीं बोली ही नहीं जाती । यह है युक्त-प्रान्त की भाषा को 'हिन्दुस्तानी' बताने का रहस्य । कांग्रेस के इस प्रचार का युक्त-प्रान्त के निवासियों पर भी प्रभाव पड़ा है । युक्त-प्रान्त के निवासी किसी शिक्षित व्यक्ति से पूछिये, 'आपकी मातृ-भाषा क्या है ?', उत्तर मिलेगा, 'हिन्दुस्तानी' । अपनी मातृ-बोली गई, जिस भाषा की वह बोली है वह भी गई, रह गई वस 'हिन्दुस्तानी' ! ब्रज-वासी भी 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं, अवध-निवासी भी 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं, काशी-वासी भी 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं ! हिन्दी गई सो गई, 'ब्रज' और 'अवधी' भी उठ गईं जिनके साहित्य का इस 'हिन्दुस्तानी' का साहित्य अभी सैकड़ों साल तक पानी भरे ! जब तक 'हिन्दी' थी तब तक ब्रज और अवधी का भी अस्तित्व था, 'हिन्दुस्तानी' में उन्हें स्थान कहाँ ? कांग्रेस प्रचार के मारे हुये शिक्षित सज्जन कहते हुये सुनाई देंगे, 'अँगरेज़ी में नहीं, हिन्दुस्तानी में बात कीजिये' । अपने मुँह से 'हिन्दी' कहना उन्हें साम्प्रदायिकतापूर्ण और ओछा मालूम पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें यही सिखाया है कि हिन्दी का अर्थ है साम्प्रदायिकता, 'क्योंकि हिन्दी साम्प्रदायिक भाषा है, विशुद्ध राष्ट्रीयता की हुगली तो 'हिन्दुस्तानी'

हैं'। किसी अखिल भारतीय सभा में युक्त-प्रान्त वाले से पूछिये, 'आप कौन हैं, कहाँ के हैं ?' उत्तर मिलेगा, 'हिन्दुस्तानी'। बंगाली अपनी मातृ-भाषा बंगला बतानेगा, 'बंगला' में बोलने का आग्रह करेगा और अपने आप को बंगाली बतानेगा ('हिन्दुस्तानी' तो हिन्दुस्तान के सभी निवासी हैं)। इसी प्रकार बिहारी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, आदि अपनी अपनी मातृ-भाषा और अपना अपना प्रान्तीय नाम लेंगे, किन्तु अपनी मातृ-भाषा 'हिन्दी' और अपने आप को 'हिन्दी' बताने वाले बिरले ही मिलेंगे।

सारांश यह कि इस 'हिन्दुस्तानी' नाम के कारण यह भावना दृढ़ होती जा रही है कि हिन्दी किसी प्रदेश की, किसी की मातृ-भाषा नहीं, उसे कोई नहीं बोलता और उसकी जगह जो कुछ है सो वह 'हिन्दुस्तानी' है। इससे हिन्दी को प्रान्त-भाषा की पदवी से भी हटाने में (जैसे रेडियो में), और उसकी छाती पर उर्दू और उर्दू लिपि को बैठाने में बड़ी सहायता मिल रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये १९४१ की जन-गणना के समय लखनऊ रेडियो से और अन्य उपायों से जन-गणना से सम्बन्धित अससर्गों ने युक्त-प्रान्त की जनता को सलाह दी कि वे अपनी मातृ-भाषा 'हिन्दुस्तानी' लिखें (वे बोलते ब्रज, अवधी, आदि चाहे जो हों !), और जन-गणना के फारम भरने वालों को सरकारी आदेश दिया गया कि वे मातृ-भाषा के स्थान में किसी के हिन्दी या उर्दू बताने पर केवल 'हिन्दुस्तानी' लिखें। ये सब 'हिन्दी' का नाम निशान मिटाने की तैयारियाँ हैं। मज़े की बात यह है कि सन् १९३१ की जन-गणना तक जन-गणना के फारमों और रिपोर्टों में युक्त-प्रान्त की मातृ-भाषा 'हिन्दी' लिखी गई है। दस वर्ष में हिन्दी बदलकर 'हिन्दुस्तानी' हो गई ! यह है गांधी-कांग्रेस-चमत्कार ! गांधी-वादी, राष्ट्र-वादी कहेंगे, हिन्दी उर्दू के साथ समान व्यवहार किया गया, चलो हिन्दी उर्दू का भेद मिट गया (किन्तु आसानी से, जादू का डंडा फिरा कर !), आदि, परन्तु वास्तव में हिन्दी का अस्तित्व मिट गया। उर्दू तो किसी प्रदेश की मातृ-भाषा है ही नहीं, उसका क्या बिगड़ा ?

उल्टे 'हिन्दुस्तानी' के नाते उर्दू और उर्दू लिपि का युक्त-प्रान्त पर उतना ही अधिकार हो गया जितना हिन्दी और देवनागरी का, और यह कहने की गुंजाइश और यह बतलाने का साधन भी न रहा कि युक्त-प्रान्त में इतनों की मातृ-भाषा हिन्दी है और केवल इतने अपनी मातृ-भाषा उर्दू बताते हैं। सब प्रकार से हिन्दी की बोर हानि हुई, और इसी कारण मुसलमान तहेदिल से युक्त-प्रान्त की भाषा को 'हिन्दी' के बजाय 'हिन्दुस्तानी' कहे जाने के साथ हैं।

हिन्दी की रक्षा के निमित्त इन बातों की आवश्यकता है:—

(अ) स्पष्ट घोषणा की जाय और प्रचार किया जाय कि १. युक्त-प्रान्त की प्रादेशिक या देशज भाषा अर्थात् मातृ-भाषा हिन्दी है, 'हिन्दुस्तानी' नहीं, क्योंकि वहाँ की विभिन्न जनपदीय बोलियाँ हिन्दी भाषा की बोलियाँ हैं। हिन्दुस्तानी या खड़ी बोली स्वयं हिन्दी की एक बोली है जो युक्त-प्रान्त के एक डेढ़ ज़िले में बोली जाती है, इसलिये युक्त-प्रान्त की भाषा का नाम 'हिन्दुस्तानी' कदापि नहीं हो सकता। 'लैंगुएज सरवे आफ इण्डिया' में युक्त-प्रान्त की भाषा को 'हिन्दी' ही बताया गया है और यही नाम अब तक बराबर जन-गणना की रिपोर्टों में प्रयुक्त होता आया है; २. युक्त-प्रान्त विशुद्ध हिन्दी प्रान्त है, और यहाँ की जनता की मातृ-भाषा और बोल-चाल की भाषा हिन्दी है, 'हिन्दुस्तानी' नहीं, इसलिये यहाँ हिन्दी का ही एकाधिकार हो सकता है। उर्दू किसी प्रदेश को जन-भाषा या मातृ-भाषा नहीं। वह एक साहित्यिक भाषा है, और युक्त-प्रान्त में उर्दू पढ़ने पढ़ाने और उसमें काम करने की छूट उसी हद तक और उसी प्रकार दी जा सकती है जिस प्रकार किसी अन्य साहित्यिक भाषा जैसे अँगरेज़ी, बँगला, इत्यादि में; ३. साहित्यिक दृष्टि से भी आधुनिक, साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दी ही युक्त प्रान्त की साहित्यिक भाषा हो सकती है, क्योंकि यहाँ की विभिन्न बोलियों के साहित्य की और लोक-साहित्य की आधुनिक हिन्दी साहित्य से एका-कारता और एकरूपता है, उर्दू साहित्य या किसी 'हिन्दुस्तानी' साहित्य से नहीं।

(आ) युक्त-प्रान्त का नाम 'हिन्द-प्रान्त' या केवल 'हिन्द' रक्खा जाय ('युक्त-प्रान्त' कोई नाम में नाम है !) ।

(इ) यहाँ के रहने वालों को बताया जाय कि उनकी मातृ-भाषा हिन्दी है, उन्हें अपनी मातृ-भाषा हिन्दी बताना चाहिये, 'हिन्दुस्तानी' का नाम न लेना चाहिये, और अपने आप को भी 'हिन्दी' बताना चाहिये ।

(ई) 'जय हिन्द' के साथ साथ, जैसा कि श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने सुझाया है, 'जय हिन्दी' हमारा नारा होना चाहिये ।

(उ) सरकार पर ज़ोर डाला जाय कि सरकारी कागज़ों में, जन-गणना की रिपोर्टों, आदि में यहाँ की भाषा के लिये सदैव 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग उसी प्रकार होना चाहिये जिस प्रकार अब तक होता रहा है । यहाँ की भाषा का नाम 'हिन्दुस्तानी' नहीं हो सकता ।

(ऊ) सरकार पर ज़ोर डाला जाय कि इस प्रान्त का नाम 'हिन्द' सरकारी तौर से स्वीकृत किया जाय । सरकारी स्वीकृति की प्रतीक्षा किये बिना राष्ट्रीय पत्रों तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को इस प्रान्त के लिये 'हिन्द' नाम का प्रयोग आरम्भ कर देना चाहिये । *

इन बातों का विशेष रूप से 'हिन्द' नाम का, ज़रूरत मनावैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा । हिंदी कम से कम अपने घर को जालिक समझी और मानी जायगी (पंजाब की भाँति युक्त-प्रान्त में भी उर्दू या अन्य भाषाएँ भले ही टिकी रहें, परन्तु उनका युक्त-प्रान्त पर जन्मजात अधिकार नहीं माना जायगा —

* अभी हाल में युक्त-प्रान्त की सरकार ने 'वर्नाक्युलर' शब्द का त्याग करने का आदेश देते हुये कहा कि इस प्रान्त की भाषा के लिये 'वर्नाक्युलर' के स्थान में 'हिन्दुस्तानी' या 'प्रान्त की भाषा' लिखा जाय, जिसका अर्थ हुआ कि इस प्रान्त की भाषा 'हिन्दुस्तानी' है । जैसा ऊपर बताया गया है, यह गहरी कूटनीति की चाल है जिसके द्वारा इस प्रान्त पर हिन्दी को निकाल कर 'हिन्दुस्तानी' को थोपा जा रहा है । इस विषय में लेखक ने एक लेख लिखा था जो अंगरेज़ी पत्रों में छपा था । उसे परिशिष्ट २ में दिया गया है ।

जिस प्रकार पंजाब में यह कहने का कोई साहस नहीं कर सकता कि पंजाब की मातृ-भाषा उर्दू है, पंजाबी नहीं)। अन्य प्रान्तीय भाषाओं के समान हिंदी की कम से कम एक प्रान्तीय भाषा की सी स्थिति होगी और केंद्रीय प्रकरणां में उसकी उपेक्षा करना संभव न होगा। बंगालियों, गुजरातियों, तमिलों, आदि की भाँति हिन्दियों को भी अनुभव होगा कि उनकी भी एक विशिष्ट भाषा और संस्कृति है, और उनमें भ्रातृ-भाव, एकभाषा-भाव उत्पन्न होगा और उनका अपनी मातृ-भाषा हिन्दी के प्रति प्रेम जाग्रत होगा। जिस प्रकार अन्य प्रांतवाले अपनी अपनी मातृ-भाषा या प्रांत-भाषा से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हिंदी-जन अपनी मातृ-भाषा और प्रांत-भाषा हिंदी से प्रेम करना सीखेंगे और उसकी रक्षा के लिये कटिबद्ध होंगे। आज युक्त-प्रांत में हिंदी के प्रति जनता में जो उपेक्षा भाव पाया जाता है उसका कारण यही है कि उन्हें अपनी मातृ-भाषा का असली नाम ही साफ साफ नहीं बताया जाता जिससे उनमें उसके प्रति प्रेम, उसकी उन्नति करने और उसके स्वरूप को विशुद्ध रखने की इच्छा उत्पन्न हो सके। उल्टे उन्हें 'हिंदुस्तानी' नाम द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह पाठ पढ़ाया जाता है कि उनकी भाषा गन्दी हुगली तो है ही, और यदि नहीं है तो उसे अब दनाया जाय। 'हिन्दुस्तानी' के चक्र में फँस कर हिंदी-जनता हिंदी की उपेक्षा करती है। इस नाम के कारण उसे हिंदी और उर्दू में अन्तर भी दिखाई नहीं देता, हिंदी शब्द और उर्दू शब्द में अन्तर दिखाई नहीं देता और हिंदी उर्दू दोनों एकसी जान पड़ती हैं। फलतः 'हिन्द' में हिंदी की वैसी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती जैसी एक भाषा की अपने निजी प्रदेश में होनी चाहिये। 'हिंदी' नाम के बजाय 'हिंदुस्तानी' नाम से यही अन्तर हो जाता है। 'हिंदी' नाम यदि शुद्धता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है तो 'हिंदुस्तानी' नाम बरबस गन्दगी की ओर धकेलता है। जब तक 'हिंद' नाम और हिंद की भाषा के नाम की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक हिंदी को शुद्ध करने और शुद्ध रखने की स्वाभाविक प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी।

(८) बोलचाल की भाषा का सुधार होना चाहिये।

लिखते समय तो भाषा का कुछ ध्यान रक्खा भी जाता है, परन्तु बोलचाल में शिक्षित समाज भाषा का तनिक भी ध्यान नहीं रखता। परिणाम-स्वरूप शहरों के शिक्षित समाज की बोलचाल में एक और अनावश्यक (भाषा की दृष्टि से) अँगरेजी शब्दों की भरमार है—यहाँ तक कि उसका अलग नाम 'इङ्गलिस्तानी' या 'बाबू हिंदुस्तानी' रख दिया गया है, और दूसरी ओर अनावश्यक अरबी फ़ारसी शब्दों की भरमार है। दोनों बातों के कारण एक ही प्रकार के हैं। पहले 'इङ्गलिस्तानी' को लीजिये जिसका अभी साहित्य में प्रवेश नहीं हुआ है। इसके विषय में डा० रामकुमार वर्मा कहते हैं, "....मैं तो आज देखता हूँ कि भाषा के बोलने के सम्बन्ध में अधिक से अधिक लापरवाही बरती जाती है। मेरे विश्वविद्यालय ही में किन्हीं दो विद्यार्थियों की बातचीत सुन लीजिये। उनके सारे वार्तालाप में सम्भवतः एक भी वाक्य ऐसा न होगा जिसे अच्छी हिंदी कह सकें। उदाहरण के लिये मेरे एक विद्यार्थी ने एक दिन मुझसे कहा—डाक्टर साहब, आप उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। बड़ा इन्टरेस्टिंग डिसकशन हुआ। मैं स्पीकर के प्वाइन्ट अव्व्यू से ऐसी नहीं कर सका और मैंने ऐसी फोर्सफुल स्पीच डेलीवर की कि आडिअंस बाज़ मूव्ड कम्पलीटली एंड दि हाउस बाज़ इन माइ फ़ेवर। मैंने उसे उसी समय रोककर कहा कि मैं नहीं समझा। ज़रा हिंदी में कहिये। वह लजित हुआ और 'एक्सक्यूज मी' कह कर चला गया। उसने 'जमा कीजिये' नहीं कहा।.....यदि अँगरेजी की संज्ञाओं, उसके विशेषणों और क्रिया विशेषणों के मिश्रण की यही प्रवृत्ति भाषा में रही तो आज से सौ वर्ष बाद हिंदी से संघर्ष लेने के लिये आज की हिंदुस्तानी की भाँति कोई इङ्गलिस्तानी भाषा खड़ी होगी और वही राष्ट्र-भाषा होने के लिये हिंदी से युद्ध करेगी। भाषा-सुधार सम्बन्ध में हमारा जो गम्भीर उत्तरदायित्व है, उसे अभी हम आँख खोलकर नहीं देख सकते, यह हमारा नैतिक पतन है।"

(अ. भा. हिंदी साहित्य सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन में साहित्य-परिषद् के सभापति पद से दिये भाषण से) इसके बाद कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती । हमें इस इंगलिस्तानी से पीछा छुड़ाना ही होगा, और इसके लिये शिक्षित समाज में ज़ोरदार आन्दोलन करना चाहिये । अब दूसरी बीमारी—अरबी फ़ारसी शब्दों की भरमार—लीजिये जो अपेक्षाकृत अधिक पुरानी है और जो 'उर्दू' नाम से साहित्य में भी स्थान पा चुकी है और इस कारण जिसे बहुत से लोग अब बीमारी नहीं मानते (इंगलिस्तानी को अभी तक सब—हिंदुस्तानी वाले भी—बीमारी मानते हैं) । यह बीमारी कहीं अधिक भयंकर है क्योंकि यह उर्दू साहित्य से और पुष्ट होती है और एक दल इसको (एक अलग लिपि में) लिख कर और बोल कर फैलाने में यत्नशील है जब कि इंगलिस्तानी को अपने किसी विशेष साहित्य का सहारा नहीं है और कोई दल उसका प्रचार नहीं चाहता । हिंदी वालों ने बोलचाल का महत्व बिलकुल नहीं समझा है । वे समझते हैं, लिखो हिंदी, बोलते रहो चाहे उर्दू । उर्दू के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री रघुपति सहाय 'फिराक़' ने कुछ दिन हुये गोरखपुर में कहा, "उर्दू हिंदीकी अपेक्षा बोलचाल की भाषा के अधिक निकट है । हिन्दी के लेखक और साहित्यिक स्वयं वह भाषा नहीं बोलते जिसे वे लिखते हैं ।" मियाँ बशीर अहमद का कथन है, "युक्त-प्रान्त की लिखी जाने वाली भाषा हिन्दी है और बोली जाने वाली भाषा उर्दू है ।" यदि हम केवल शिक्षित समाज के विशिष्ट वर्गों की बोलचाल को लें, तो दोनों कथनों में बहुत कुछ सच्चाई है । यह बात तो सोलह आने सच है कि हिन्दी के लेखक और साहित्यिक नित्य बोलचाल में वह भाषा नहीं बोलते जिसे वे लिखते हैं । स्टेशन पर, रेल में, बाज़ार में—चाहे जहाँ उनकी बातचीत सुन लीजिये । पर उर्दू के लेखक और साहित्यिक वही भाषा बोलते हैं जिसे वे लिखते हैं । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता—भले ही उर्दू वाले प्रयत्न करके ही ऐसा करते हों या कर

पाते हों। वे कम से कम बोलने के मामले में सजग हैं जब हिन्दी वाले बेखबर हैं। यदि किसी हिन्दी वाले को किसी उर्दू वाले से बातचीत हो तो सौ में सौ विरसे वह उर्दू में होगी ('आदाबअर्ज' से आरम्भ और 'खुदा हाफिज़ है' से अन्त होकर !)। हिन्दी वाला प्रयत्न करके उर्दू में बोलेंगा और इसमें गर्व का अनुभव करेगा (देखो, हमें उर्दू भी आती है, हम कितने उदार और विशाल-हृदय हैं !), और इस प्रकार सिद्ध करेगा कि उर्दू ही कामन भाषा है, साहित्य सम्मेलनों में जाकर वह चाहे जो हाँकता हो। यदि हिन्दी वाले को ज़रा यह मालूम हो जाय कि जिससे वह बात कर रहा है वह मुसलमान है अथवा उपस्थित लोगों में एक दो मुसलमान भी हैं, तो उसे हिन्दी बोलने में शर्म आवेगी, वह हिचकिचायेगा, और अन्त में ढूँढ़ ढूँढ़ कर उर्दू शब्दों का ही प्रयोग करेगा। यदि किसी हिन्दी शब्द का प्रयोग करना ही पड़ा तो उसके चेहरे पर संकोच, भिन्न और क्षमायाचना का भाव लक्षित होगा। प्रत्येक दशा में बोलचाल में साधारण से साधारण हिन्दी शब्द बोलने में हिन्दी वाले हिचकिचाते हैं (वे कांग्रेस के प्रचार से शायद उसे 'साम्प्रदायिक' और 'हिन्दू-मुसलिम एकता' के लिये वातक समझते हैं, और उर्दू को एकता का सिंहद्वार !)। हाँ, लिखते समय वे कठिन से कठिन संस्कृत शब्द को निःसंकोच लिख डालेंगे। यह है हिन्दी वालों का मातृ-भाषा प्रेम और यह है उनकी संस्कृति ! * हिन्दीवालों को दूसरों के सामने अपनी मातृ-भाषा में बोलने में गर्व का अनुभव होना तो अलग रहा,

जैसा पं० अमरनाथ झा ने कहा है, 'हिंदी वाले 'पंडित साहब' तो कह लेंगे परन्तु 'मौलवी जी' कभी नहीं'। हिन्दीवालों को 'मुसम्मात कमला' में या 'महारानी साहबा' में कोई अस्वाभाविकता नहीं मालूम पड़ती, परन्तु 'श्रीमती अशगरी' कभी नहीं कह सकते, वे 'बेगम' ही रहेंगी। हिन्दीवालों को पंडितजी से, अपने इष्ट मित्रों यहाँ तक कि अपने सम्बंधियों से भी 'आदाबअर्ज' करने में शर्म नहीं आती, परन्तु सड़े से सड़े मुसलमान से भी 'नमस्ते' या 'नमस्कार' करना पाप समझते हैं। 'जैरामजी की' तो गँवारों के लिये रिज़र्ब है ही !

उल्टे शर्म आती है और इसलिये उर्दू की शरण लेते हैं। वे अपनी चेष्टाओं से सिद्ध करते हैं कि मुसलमानों की मातृ-भाषा तो उर्दू ही है और वे उर्दू के सिवा और कुछ नहीं बोलते या समझते। उर्दू वाले तिलकधारी पंडितजी से भी शुद्ध उर्दू में बोलेंगे। कोई समझे या न समझे, उनकी बला से। उन्हें जो आता है, जो वे लिखते हैं, वही बोलेंगे, चाहे कोई मौजूद हो। उन्हें अपनी उर्दू में बोलने में कोई अस्वाभाविकता या भिन्नक प्रतीत नहीं होती। वे अपनी स्वाभाविक शैली छोड़कर क्यों इधर उधर ताकें? मौलाना आज़ाद (या पं० नेहरू) किसी अखिल भारतीय सभा के सम्मुख शुद्ध उर्दू में बोलने के लिये किसी की क्षमा-याचना नहीं करते, परन्तु पं० गोविन्द वल्लभ पन्त, डा० राजेन्द्रप्रसाद, यहाँ तक श्री टंडनजी भी या तो शुद्ध हिन्दी में बोलेंगे ही नहीं (बिना आधे पौने उर्दू शब्दों को मिलाये वे अपने आप को विशुद्ध राष्ट्रीयता से च्युत समझेंगे—गांधीजी का भी तो डर है कि कहीं कांग्रेस की 'इन कारउन्सेल्स' में वे 'साम्प्रदायिक,' 'संकुचित हृदय,' 'तंग खयाल,' 'महासभाइट' न घोषित कर दिये जायँ!), और यदि बोलेंगे तो चेहरे से मालूम होगा कि बड़ी बहादुरी तो की है, परन्तु अपराध हुआ, आशा है उपस्थित सज्जन क्षमा करेंगे। यह हिन्दी वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है जो उन्हें पग पग पर नीचा दिखाती है।*

शिक्षित समाज की साधारण बोलचाल का भी वही हाल है। उसके विषय में पहले बतलाया जा चुका है। नेताओं की देखा देखी कांग्रेस के छोटे भाई भी उर्दू में बोलना स्वराज्य-प्राप्ति का सीधा रास्ता समझते हैं।

अब प्रश्न होता है, बोलचाल का सुधार किस प्रकार होना चाहिये? सबसे पहली आवश्यकता है हिन्दी के परिमार्जन और संशोधन की। उसके विषय में सभी आवश्यक बातें पहले कही जा चुकी हैं। जिन सिद्धान्तों के अनुसार हिन्दी का परिमार्जन संशोधन होना है, उनका निर्देशन भी किया जा चुका

*परिशिष्ट ३ भी देखिये।

है। जब तक जैसी हिन्दी बोलना मंजूर है वैसी ही नहीं लिखी जायगी, और जैसी लिखी जाय वैसी ही नहीं बोली जायगी, तब तक हिन्दी का उद्धार नहीं हो सकता। यह विलकुल सोधी सी बात है कि जैसी हिन्दी बोलना मंजूर है वैसी ही लिखो और जैसी लिखते हो वैसी बोलो। और बोलते समय भाषा का उसी प्रकार ध्यान रखो जिस प्रकार लिखते समय रक्वा जाता है। इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो समय कराके छोड़ेंगे और फिर बाद की पछताने से कुछ हाथ न आएगा। लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा का सीधा और अटूट संबंध है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। कृत्रिम उपायों से दोनों में अन्तर अधिक समय तक कभी नहीं रक्वा जा सकता, इसलिये उनको सावधानी से एक दूसरे के निकट लाने में ही बुद्धिमानी है। आज हिन्दी में इतने ज्यादा अनावश्यक अरबी फारसी शब्द (जिनके विरुद्ध यह पुस्तक एक विद्रोह है) क्यों आते हैं ? उर्दू में सैकड़ों उर्दू शब्दों के साथ उनके हिन्दी पर्याय क्यों नहीं आते ? इसका कारण यही है कि आज के हिन्दी लेखक जिस समाज के अंग हैं और जिस समाज में उनका उठना बैठना होता है, उसकी बोलचाल में यही उर्दू शब्द आते हैं, उनके हिन्दी पर्याय नहीं आते। इसलिये जब वे हिन्दी लिखने बैठते हैं तो वे हिन्दी शब्दों को तो प्रयत्न करके, आग्रह करके बैठते हैं, परन्तु नज़र बचते ही, ध्यान बैठते ही उर्दू के शब्द, जिन्हें वे चौबीसो घंटे चारो ओर सुनते हैं और जो उनके दिमाग में चक्कर काटते होते हैं (और जिनमें शायद वे अपनी सोचाई भी करते हैं), अनायास क्लम से निकल पड़ते हैं। इसलिये एक ही वाक्य में, एक ही अर्थ में हिन्दी और उर्दू के पर्यायवाची शब्द दिखाई देते हैं। हिन्दी के द्वैतवाद का कारण बोलचाल की भाषा ही है। यदि बोलचाल का सुधार नहीं होगा और उसमें हिन्दी शब्द नहीं आयेंगे, तो हिन्दी लेखकों के लिये अप्रचलित हिन्दी शब्दों के प्रति आग्रह और प्रचलित उर्दू शब्दों के विरुद्ध चौकसी रखना अधिक समय तक संभव न होगा, और जब तक लिखित हिन्दी की

वही दशा रहेगी तब तक हिन्दी के पाठक हिन्दी उर्दू दोनों के पर्याय सीखते रहेंगे और ऐसी अवस्था में हिन्दी पर्याय बोलचाल में कभी प्रचलित न हो सकेंगे। उर्दू वालों के साथ मामला बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने साहित्य से ही नहीं, अपनी बोलचाल से भी हिन्दी शब्दों को मतरूक कर दिया है, जब कि हिन्दी वाले साहित्य से तो उर्दू शब्दों को मतरूक करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु बोलचाल में वही उर्दू शब्द बोलते रहते हैं। उर्दू वालों को कुत्ते ने थोड़े ही काटा है जो वे उर्दू शब्दों को, जिन्हें वे स्वयम् चौबीसो घण्टे बोलते हैं और दूसरों को बोलते सुनते हैं, छोड़ कर हिन्दी शब्द लिखें। इसलिये उर्दू में शब्दों का द्वैतवाद दिखाई नहीं देता। हिन्दी वाले 'उद्देश्य' लिखते लिखते 'मक़सद,' लिख जायेंगे क्योंकि वे स्वयम् 'मक़सद' बोलते हैं, 'उद्देश्य' नहीं बोलते। उर्दू वाले 'मक़सद' छोड़ कर 'उद्देश्य' क्यों लिखें ? यह सच है कि उर्दू से कितने ही प्रचलित देशज और तद्भव शब्दों को मतरूक कर दिया गया है, परन्तु उर्दू वालों ने उन शब्दों को अपनी बोलचाल से भी मतरूक कर दिया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, हिन्दी वालों ने उन उर्दू शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द धर दिये परन्तु बोलते रहे वही उर्दू शब्द। या वे अपनी बोलचाल से भी उन उर्दू शब्दों को मतरूक करें और अपने संस्कृत शब्द बोलें, या फिर प्रचलित देशज और तद्भव शब्द लिखें और वही बोलें, और जिन उर्दू शब्दों को लेना है उन्हें निश्चित रूप से अपना लें और उनके स्थान में संस्कृत शब्द लिखने या बोलने का प्रयत्न न करें। जिन प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों को उर्दू वालों ने अपने साहित्य या बोलचाल से मतरूक कर दिया है, उन्हें बोलने में तो हिन्दी वालों को अवश्य ही गर्व अनुभव करना चाहिये और उनके उर्दू पर्यायों को भूलकर भी नहीं लिखना या बोलना चाहिये। जैसा पहले कहा जा चुका है, बोलचाल की एक कामन भाषा या हिन्दुस्तानी तो बन कर रहेगी। यदि हिन्दी वाले अपने हिन्दी शब्द बोलेंगे (उर्दू वाले

तो उर्दू शब्द बोलेंगे ही) तो हिन्दी और उर्दू दोनों के शब्द बोलचाल में प्रचलित होंगे, और जहाँ एक और हिन्दी वाले उर्दू शब्द समझेंगे वहाँ दूसरी ओर उर्दू वाले भी हिन्दी शब्द समझेंगे, और ऐसी अवस्था में जो कामन हिन्दी या हिन्दुस्तानी स्वाभाविक रूप से बनेगी उसमें हिन्दी का उतना ही अंश होगा जितना होना चाहिये। ऐसी अवस्था में यदि लिखित हिन्दी में हिन्दी शब्दों के साथ साथ बोलचाल में प्रचलित उनके उर्दू पर्याय घुस ही पड़ेंगे तो लिखित उर्दू में भी उर्दू शब्दों के साथ साथ बोलचाल में प्रचलित उनके हिन्दी पर्यायों को घुसने से कोई न रोक सकेगा, और इस प्रकार साहित्य में भी यदि हिन्दुस्तानी बनी, तो उसमें हिन्दी का उतना ही अंश होगा जितना स्वाभाविक रूप से होना चाहिये। लिखित हिन्दी के किसी संस्कृत शब्द के प्रति कृत्रिमता का आक्षेप भी न किया जा सकेगा, क्योंकि बोलचाल में वह भी तो प्रचलित होगा। सारांश यह कि हिन्दी बोलने से आगे बढ़ेगी, केवल जिनसे नहीं। जो अपनी भाषा और अपनी भाषा का शब्द नहीं छोड़ता और उसे अधिक दृढ़ता के साथ बोलता है, उसी की भाषा को अन्त में जीत होती है और उसी की भाषा का प्रचार होता है। यदि हिन्दी वाले बोलने में कमजोरी दिखलायेंगे तो उर्दू ही कामन भाषा होगी और वही राष्ट्र-भाषा होगी। हिन्दी का अन्य भाषाओं से सामीप्य वाला गुण घरा रह जायगा। उर्दू वाले बोलकर अपनी भाषा भारत के कोने कोने में ले जायेंगे, हिन्दी वाले हिन्दी लिखकर और उर्दू

॥अहिन्दी भाषी भी साहित्य की खड़ी बोली की नहीं, बोलचाल की खड़ी बोली की नकल करेंगे और स्वयम् वैसी ही बोलेंगे। ऐसा होना स्वाभाविक है। एक शिक्षित बंगाली जब लखनऊ में आ बसता है तो उसकी भी खड़ी बोली वैसी ही होती है जैसी लखनऊ के शिक्षित समाज की बोलचाल। न कि हिन्दी यद्यपि वह बँगला के कहीं अधिक निकट है। अपने बंगाली मित्र से वह बँगला में बात करेगा, और बोलेगा 'शेष', 'शरीर', 'सम्बन्ध', 'भाषा', 'कर्त्तव्य', 'मानुष' 'अनुवाद', आदि, परन्तु दूसरी ही सांस में अपने लखनौआ

बोलकर केवल हास्यास्पद बनेंगे। जो भाषा सब लोग बोलेंगे वही कामन भाषा 'हिन्दुस्तानी' कहलायेगी, लिखा चाहे जो कुछ जाय। यदि बोलचाल में हिन्दी

मित्र से (या बाज़ार में) खड़ी बोली में बात करते समय बोलेगा, 'ख़त्म', 'जिस्म', 'रिश्ता', 'ज़वान', 'फ़ज़', 'आदमी या शख्स', 'तरजुमा', क्योंकि अपने चारों ओर की खड़ी बोलचाल में—हिन्दी वालों की अथवा उर्दू वालों की—वह नित्य इन्हीं शब्दों को सुनता है, लिखित हिन्दी में 'शेष', 'शरीर' 'सम्बन्ध', 'भाषा', 'कर्त्तव्य', 'मनुष्य', 'अनुवाद' उसने भले ही देखे हों। (भाषा के साथ संस्कृति का भी वही हाल है। लखनऊ में बसा हुआ एक हिन्दू बंगाली दूसरे हिन्दू बंगाली से सदैव 'नमस्कार' करेगा, परन्तु दूसरी ही सांस में अपने लखनौआ हिन्दू मित्र से 'आदाबअज़' करेगा। कारण वही हैं।) हाँ, यदि लखनऊ की खड़ीबोली बोलचाल में उसे 'ख़त्म' 'जिस्म', 'रिश्ता', 'ज़वान', 'फ़ज़', आदि के साथ साथ 'शेष', 'शरीर', 'सम्बन्ध', 'भाषा', 'कर्त्तव्य', आदि भी—निःसन्देह हिन्दी वालों के मुख से—सुनने को मिलेंगे तो उसके मुँह से भी खड़ी बोली में यही हिन्दी शब्द अधिक सुगम और परिचित होने के कारण निकलेंगे (और जब वह हमें आपस में एक दूसरे को 'नमस्कार' करते देखेगा तब वह हमें भी 'नमस्कार' करेगा, जो भाषा हम स्वयम् नहीं बोलेंगे, बस केवल लिखेंगे, उसके लिये हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि अन्य भाषा भाषी उसे—उस लिखित भाषा को—बोलें? पहले हम स्वयम् अपनी लिखित भाषा को इसी रूप में बोलकर आदर्श उपस्थित करें, फिर अहिन्दी भाषी उसे अपेक्षाकृत अधिक सुगम, परिचित और सरल होने के कारण अपने आप अपनायेंगे। उर्दू या वर्धा की हिन्दुस्तानी अपने आप धरी रह जायेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक प्राणी सबसे सरल मार्ग (line of least resistance) अपनाता है। इस नियम की अवहेलना अधिक समय तक कदापि नहीं हो सकती, चाहे गांधीजी, कांग्रेस और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा एड़ी चोटी का ज़ोर क्यों न लगा दें।

(यही बात लिखित हिन्दी के साथ लागू है। हम सदैव शुद्ध हिन्दी लिखें, सूखी राष्ट्रियता और 'हिन्दुस्तानी' के चकर में आकर उसमें उर्दू शब्द न भरें, फिर देखेंगे अहिन्दी भाषी इस हिन्दी को छोड़कर वर्धा की

$$\frac{\text{हिन्दी} + \text{उर्दू}}{2} =$$

न आई तो लिखित हिन्दी की भी आत्मा मर जायगी। आज चारों ओर जो यह सुनने में आता है कि हिन्दी की प्रकृति मर रही है, उसमें जाति की आत्मा का प्रतिविम्ब नहीं दीख पड़ता, आदि, इसका कारण यही है कि हिन्दी लिखने वाले साधारण बोलचाल में या इङ्गलिस्तानी बोलते हैं या उर्दू (और उसी में सोचते हैं)। फिर हिन्दी की प्रकृति सुरक्षित रहे तो कैसे रहे? भाषा की प्रकृति बोलने से बनती है, बोलने से ही वह पहचानी जाती है, बोलने से ही सुहावरे बनते हैं, शब्दों के अर्थों का विस्तार होता है, उनमें अपेक्षित ध्वनि आती है, आदि। भाषा जब बोलनी जाती है तभी उसमें स्वाभाविकता, प्रौढ़ता, लचक व्यंजना-शीलता और जीवन तथा प्रवाह आता है। यदि बोलचाल में हिन्दी वाले उर्दू शब्द, उर्दू सुहावरे अपनाते चले जायेंगे तो हिन्दी में लिखते समय अपने शब्द और सुहावरे अपने आप अपरिचित से, कृत्रिम और बेजान मालूम पड़ेंगे।

हिन्दी वालों को चाहिये कि वे सदैव—साधारण बोलचाल में, मित्रों की गोष्ठी में या मंच से—शुद्ध और स्टैंडर्ड हिन्दी बोलें और बोलते समय भाषा का उसी प्रकार और उतना ही ध्यान रखें जितना लिखते समय रखते हैं, या रखना आवश्यक है। वे हिन्दी प्रान्तों के निवासियों—हिन्दू, मुसलमान, सिख या ईसाई—से या उनके बीच में बोलते समय उर्दू में बोलने की या उर्दू शब्दों का व्यवहार करने की भयंकर भूल कदापि न करें, क्योंकि ऐसा करके वे यही सिद्ध करेंगे कि हिन्दी प्रान्तों के सब निवासी हिन्दी नहीं समझते, बहुत से निवासी उर्दू ही बोलते और समझते हैं, और उर्दू ही इन प्रान्तों का कानन भाषा है। हमें हिन्दी मुसलमानों से बातचीत करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम हिन्दी

‘हिन्दुस्तानी’ किस प्रकार अपनाते हैं। हिन्दी का भविष्य हिन्दी वालों—हिन्दी के लेखकों, साहित्यिकों और हिन्दी भाषियों—के ही हाथ में है। (आगे दूसरा भाग देखिये।)

में ही बोलें। यदि कोई हिन्दी मुसलमान किसी हिन्दी शब्द को न समझे तो तो वह उसका अर्थ पूछ ले। यदि हिन्दी मुसलमान उर्दू में बोलें (जैसा कि वह बोलता है), तो हमें इस पर आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु हम भी उससे उर्दू में क्यों बोलें? हम अपनी मातृ-भाषा, जो उसकी भी मातृ-भाषा है यद्यपि वह इससे इन्कार करता है, क्यों छोड़ें? जिस प्रकार हम उसकी उर्दू समझने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार वह हमारी हिन्दी समझने का प्रयत्न करे। यदि कोई हिन्दी भाषी उर्दू भी जानता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह किसी हिन्दी मुसलमान से उर्दू में बोलें। वह अपनी उर्दू विशेष अवसरों और उपयोगों के लिये (जैसे सीमा-प्रान्त में भ्रमण करते समय) उठा रखे। गांधीजी कहते हैं कि मैंने अपनी अँगरेजी अँगरेजों और विदेशियों के लिये रिजर्व कर रखी है, सब हिन्दुस्तानियों के लिये मेरे पास 'हिन्दुस्तानी' है। हिन्दो बालों को इससे शिक्षा लेनी चाहिये। वे अपना उर्दू-ज्ञान पाकिस्तान निवासियों के लिये रख छोड़ें, परन्तु सब हिन्दियों से, धर्म का कोई भेद भाव किये बिना, हिन्दी में बोलें, जिस प्रकार एक बंगाली या मराठी या गुजराती किसी भी धर्म के अनुयायी बंगाली या मराठी या गुजराती से क्रमशः बंगाली, मराठी और गुजराती में बात करता है। ऐसा होने पर ही हिन्दी हिन्द-प्रान्त और हिन्दी प्रान्तों की वास्तविक मातृ-भाषा या प्रान्त-भाषा कहलाने की अधिकारिणी होगी। हिन्दी वाले हिन्दी मुसलमानों से उर्दू में बोलकर स्वयम् हिन्दी की इस स्वभाव-सिद्ध व्यापकता में अविश्वास उत्पन्न करते हैं। उन्हें अपने प्रान्तों की सीमा के अन्दर और अपने प्रान्त-निवासियों के साथ या उनके बीच में निसंकोच, बिना फिझक या हिच-किचाहट के हिन्दी में बोलना चाहिये। यदि वे चाहें तो इस मामले में अपने पड़ोसी शिक्षित हिन्दी मुसलमान से ही, जो हिन्दी शब्द जानते हुये भी सदैव उर्दू में बोलता है या बोलने का प्रयत्न करता है, शिक्षा ले सकते हैं*।

* भाषा के साथ संस्कृति का अटूट संबंध है। हिन्दी बोलचाल के साथ

जिस प्रकार प्रत्येक प्रान्त, ज़िले, नगर और स्कूल में हिन्दी साहित्य सम्मेलनों और परिषदों की स्थापना हुई है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रान्त, ज़िले, नगर और स्कूल में 'हिन्दी बोलो क्लब' या 'हिन्दी बोलो गोष्ठी' की स्थापना होनी चाहिये। इन गोष्ठियों का उद्देश्य हिन्दी बोलचाल का प्रचार और हिन्दी जनता का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर खींचना होगा। इन गोष्ठियों में सब बातचीत हिन्दी में हो और इनके तत्वावधान में जन-सभायें की जायँ जिनमें जनता को बोलचाल की भाषा में सुधार करने की आवश्यकता बताई जाय। यह एक बिल्कुल नई बात होगी, परन्तु इसकी परम आवश्यकता है। इसके बिना हिन्दी का उद्धार संभव नहीं। हिन्दी

हिन्दी संस्कृति भी आनी चाहिये। हिन्दी भाषियों को अपनी बोलचाल, अपने आचरण तथा व्यवहार में हिन्दी की संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिये। हिन्दी की संस्कृति क्या है अर्थात् हिन्दी किस संस्कृति का प्रतीक है, यह पहले बतलाया जा चुका है (देखिये पृष्ठ ५६)। हिन्दी बोलचाल के साथ हिन्दी शिष्टाचार को भी सुधारने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ अभिवादन को ही लीजिये जिसकी ओर पहले संकेत किया जा चुका है (पृष्ठ ७१, पाद-टिप्पणी)। हिन्दीवाले (यहाँ तक कि तिलकधारी पंडितजी भी) किसी से भी (वह चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई, सिख या किसी अन्य धर्म या सम्प्रदाय का) 'नमस्ते', 'नमस्कार', 'प्रणाम' या 'जै रामजी की' को छोड़कर 'आदाबअर्ज़', 'सलाम' या 'गुडमॉर्निंग' करके अपनी हीनता क्यों प्रकट करते हैं ? मुसलमान 'आदाबअर्ज़', जिसे स्वयम् हिन्दू मुसलमानों से कहते हैं, छोड़कर कुछ और हिन्दुओं से क्यों कहें ? बस, 'आदाबअर्ज़' कामन अभिवादन अपने आप हो गया—स्वयम् हिन्दीवालों के व्यवहार और स्वीकृति से ! हिन्दीवालों को 'आदाबअर्ज़' की इस बढ़ती हुई बीमारी का उपचार करना चाहिये। उन्हें सबसे—हिन्दू या मुसलमान—'नमस्ते' या 'नमस्कार' कहना चाहिये ! यदि हिन्दी मुसलमान 'आदाबअर्ज़' कहे तो आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु स्वयम् अपना अभिवादन क्यों छोड़ें ? 'नमस्ते' और 'आदाबअर्ज़' दोनों ही प्रचलित हों।

साहित्य का बहुतेरा प्रचार हो चुका, हो रहा है और शिक्षा के प्रसार के साथ अपने आप होगा ; अब हिन्दी बोलचाल के प्रचारकी आवश्यकता है जिसे सरकारी तौर से ही किया जा सकता है । हिन्दी बोलचाल की स्थापना और प्रचार के बिना हिन्दी की दशा एक पहिये के रथ के समान हो जायगी— वह आगे बढ़ ही न सकेगी और अन्त में वह मुर्दा समझ ली जायगी । हिन्दी बोलचाल को अँगरेज़ी और उर्दू दोनों के पंजों से मुक्त करना है । अभी हाल में पत्रों में यह समाचार छपा था कि प्रयाग के वकीलों ने एक 'हिन्दुस्तानी बोलो क्लब' की स्थापना की है, और यह नियम बनाया है कि इन क्लब का जो सदस्य बोलचाल में अनावश्यक अँगरेज़ी शब्द प्रयुक्त करेगा उस पर प्रति अँगरेज़ी शब्द एक पैसा जुर्माना किया जायगा । पता नहीं उस क्लब का क्या हुआ, परन्तु उसकी राय में 'वाइफ', 'पॉलिटिक्स', 'मिनिस्ट्री', 'रिटिन', 'प्लैटिफ', 'कल्पेविल होमीसाइड', 'मूवेविल प्रापर्टी', आदि बोलने पर जुर्माना किया जायगा, क्योंकि ये शब्द अँगरेज़ी के और 'विदेशी' हैं, पर 'बीबी', 'स्वास्त', 'वज़ारत', 'तहरीरी', 'मुद्ई', 'क़त्ल इन्सान मुस्तलिजम सज़ा', 'जायदाद मनकूला', आदि बोलना स्वाभाविक समझा जायगा क्योंकि ये 'हिन्दुस्तानी' हैं ! हिन्दी बोलो क्लब 'वाइफ' और 'बीबी', 'पॉलिटिक्स' और 'स्वास्त', 'मिनिस्ट्री' और 'वज़ारत', 'रिटिन' और 'तहरीरी', 'प्लैटिफ' और 'मुद्ई', 'कल्पेविल होमीसाइड' और 'क़त्ल इन्सान मुस्तलिजम सज़ा', 'मूवेविल प्रापर्टी' और 'जायदाद मनकूला' दोनों को विदेशी और त्याज्य समझेगा । 'हिन्दुस्तानी बोलो क्लब' का शर-संधान शिक्षितों की इंगलिस्तानी के विरुद्ध होगा, 'हिन्दी बोलो क्लब' का शर-संधान शिक्षितों की इंगलिस्तानी और उर्दू-हिन्दुस्तानी दोनों के विरुद्ध ।

जो भाषा सभ्य-समाज बोलता है उसी का अनुकरण और लोग करते हैं । इसलिये हमारे नेताओं, राज-मंत्रियों, शिक्षकों, समाज-व्यवस्थापकों, धारा-सभाओं के सदस्यों, आदि पर इस बात का विशेष उत्तरदायित्व है कि

वे अपनी बोलचाल की भाषा सुधारें, और शुद्ध हिन्दी बोलचाल का आदर्श उपस्थित करें, और मंच से भी शुद्ध हिन्दी बोलें। ग्रामीण जनता की भाषा बिलकुल विकृत नहीं हुई है। जब गाँवों में शिक्षा का प्रसार और प्रचार होगा, और उनका शहरों से सम्पर्क बढ़ेगा, तो ग्रामीण जनता शहरों के शिक्षित समाज की बोलचाल को अपनायेगी। हमें चाहिये कि हम उन्हें शुद्ध हिन्दी बोलचाल दें, नहीं तो वे भी इसी वर्तमान आँगरेज़ी और अरबी फारसी शब्दों से बोझिल बोलचाल को अपनायेंगे, और इस प्रकार जनता की भाषा का नहीं, शहरों के सुदृढ़ी भर आदमियों की विकृत भाषा का प्रसार-प्रचार होगा और वही बोलचाल की व्यापक भाषा होगी। फिर उनका बदलना या सुधार करना असम्भव हो जायगा।

४. कुछ आक्षेपों के उत्तर

ऊपर पेश किये गये सुझावों और उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो आक्षेप आमतौर से किये जाते हैं या किये जायेंगे, उनका उत्तर दिये बिना संभव है कुछ लोगों को ये व्यर्थ और पांच जान पड़ें। इनलिये कुछ आम आक्षेपों (वर्तमान अथवा संभावित) का उत्तर नीचे दिया जाता है।

(१) कोई हिन्दी एकाडेमी भाषा पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती।

प्रश्न भाषा को बाँधने का नहीं, उसको मर्यादा रखने का है। स्टैंडर्ड हिन्दी शब्द-कोष के सम्बन्ध में यह पहले कहा जा चुका है (पृष्ठ २२) कि दिन प्रति दिन अधिकाधिक विदेशी शब्द हिन्दी में गृहीत होते ही रहेंगे और स्टैंडर्ड हिन्दी शब्द-कोष में स्थान पाते जायेंगे; परन्तु किसी भी समय यह कहा जा सकेगा कि अब तक की अर्थात् वर्तमान हिन्दी का यह कोष है। हिन्दी एकाडेमी भाषा संबंधी प्रत्येक बात में समय और आवश्यकतानुसार अपनी नीति बदलेगी, परन्तु हर समय उच्च स्खलता और बाँधली

बाज़ी का दमन कर भाषा की मर्यादा रखेगी। उदाहरण के लिये, व्याकरण सदैव भाषा के बाद आता है और भाषा के पीछे पीछे लँगड़ाता हुआ चलता है, परन्तु प्रत्येक समय पर भाषा की मर्यादा बताने के लिये और भाषा को एक सीमा के भीतर रखने के लिये उस समय के व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हिन्दी एकाडेमी प्रत्येक समय पर स्टैंडर्ड हिन्दी का आदर्श रखेगी, यद्यपि वह आदर्श स्वयम् समय के अनुसार बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, हिन्दी एकाडेमी भाषा पर स्थिर नियंत्रण नहीं, गतिशील नियंत्रण रखेगी।

(२) ये सब बातें प्रतिक्रियावादी हैं।

होंगी। जबर्दस्ती विदेशी अरबी फारसी शब्द मिलाकर 'हिन्दुस्तानी' गढ़ने, देवनागरी की छाती पर विदेशी फारसी लिपि बैठाने और उसे देश पर लादने जैसे प्रतिक्रियावादी कार्यों की प्रतिक्रिया अपने आप होगी। अगर एक ओर भाषा को 'हिन्दुस्तानी' के नाम से अरबी-फारसीमय बनाने का जोरदार और जानबूझ कर प्रयत्न किया जा रहा है, तो देश की भाषा और संस्कृति के अभिमानियों को हिन्दी के नाम से भाषा विशुद्ध रखने और करने का प्रयत्न जानबूझ कर करना ही होगा। अगर 'हिन्दुस्तानी' की सर्व-मन्ही दानवी ने जन्म न लिया होता, अथवा उसके जन्म के लिये वर्षा में यज्ञ न हो रहा होता, तो हिन्दी को क्लेबन्दी करने की ज़रूरत न पड़ती। अगर 'हिन्दुस्तानी' की बाढ़ न आई होती, तो हिन्दी पर मेंढ़ बाँधने की आवश्यकता न होती। ऊपर जितनी बातें कही गई हैं उनके पीछे 'प्रतिक्रिया' और 'सांप्रदायिकता' की भावना नहीं, आत्म-रक्षा की भावना है। अपने का बचाना हमारा धर्म है। भारत के इतिहास में एक समय संस्कृत को भी यावनी भाषा के प्रभाव से बचाने की ज़रूरत पड़ चुकी है। आज मराठी, जिसका अपने प्रदेश में अखण्ड राज्य है, का अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार-कोष छुप चुका है। आज अँगरेज़ी जैसी विकसित और शक्तिशाली

भाषा को विकृत होने से बचाने के लिये आये दिन प्रयत्न होते रहते हैं। फिर कल की हिन्दी को, जो अभी बचपन से जवानी में पदार्पण ही कर रही है, कलुषित और विकृत होने से बचाना किस प्रकार 'प्रतिक्रिया' कहा जा सकता है, विशेषकर तब जब कि उस पर 'हिन्दुस्तानी' छुरा ताने खड़ी हुई है और सर्वशक्तिमान कांग्रेस और गांधीजी उसे शाह दे रहे हैं? प्राकृतिक समन्वय को कोई नहीं रोक सकता, परन्तु अप्राकृतिक समन्वय का, जिसका अर्थ हो मृत्यु, क्या किया जाय? पिछले दस वर्षों में हिन्दी उत्तरोत्तर विकृत की गई है, उसमें अनेक अरबी फारसी शब्द ज़बरदस्ती धुसेड़े गये हैं, परन्तु इन दस वर्षों में उर्दू में क्या अन्तर हुआ है, उसमें कितने हिन्दी शब्द धुसे या धुसेड़े गये? क्या यही 'समन्वय' है? आज हिन्दी को बिगाड़ने वाले चारों ओर सैकड़ों दिखाई दे रहे हैं, परन्तु उर्दू को बिगाड़ कर लिखने वाले या बोलने वाले कितने हैं? आज राष्ट्रीयता का बाना धारण किये हुये सैकड़ों कांग्रेसी हिन्दी के पीछे लट्ट लिये घूम रहे हैं, और हिन्दी की मुन्नत करने के लिये उधार लाये बैठे हैं, परन्तु उर्दू से चूँ करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। यदि ऐसे लोग हमें और हमारे सिद्धान्तों को प्रतिक्रियावादी बताते हैं, तो हमें एक बार नहीं सौ बार प्रतिक्रियावादी कहलाना स्वीकार है।

(३) ये सब बातें पुनरुत्थान (revivalism) की भावना से प्रेरित हैं।

अवश्य प्रेरित हैं। भारत के पिछले ४० वर्षों के इतिहास की सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनायें और आन्दोलन इस भावना का फल हैं। भारतीय पुनर्जागरण (Indian Renaissance) के युग की, जिसका आरम्भ राजा राममोहनराय से हुआ, सबसे महती प्रेरणा वही भावना है। इसी भावना के बशीभूत होकर हम आज स्वदेशी राज्य, स्वदेशी व्यवहार, स्वदेशी आचार-विचार और स्वदेशी भाषा की माँग कर

रहे हैं। हम आज अँगरेज़ियत, अँगरेज़ी भाषा और कोट पतलून का ही विरोध क्यों करते हैं? क्या ये सब बातें समाज में, समाज की चोटी की श्रेणियों के जीवन में नहीं घुस गई हैं, और उर्दू के समान नहीं लद गई हैं? राजभाषा अँगरेज़ी को ही निकालने की बात क्यों की जाती है? क्या अँगरेज़ी पिछले दो सौ वर्षों से राजभाषा नहीं है? क्या शिक्षित समाज के लिये आज अँगरेज़ी मातृ-भाषा से भी बढ़कर नहीं है? फिर उसकी जगह मातृ-भाषा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है? क्या अँगरेज़ी के शब्द शिक्षितों की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों के समान नहीं घुस गये हैं? उन्हीं को मातृ-भाषा से क्यों बहिष्कृत किया जाता है? जब मनुष्य चेतता है और 'स्व' को पहचानने की योग्यता प्राप्त करता है, और अपने पिछले ऐश्वर्य को वाद कर उसे पुनः प्राप्त करना चाहता है, तभी उसमें कुछ करने की शक्ति आती है और तभी वह महानता की ओर अग्रसर होता है। "मैं बड़ा होता हूँ तो अपनी शक्तियों से।" मुझे प्रेरणा मिलती है, जाननी शक्ति मिलती है तो अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, इसलिये मैं अपनी भाषा को शुद्ध करना और रखना चाहता हूँ। आज फारस तो फारसी में से धुले मिले अरबी शब्द निकाल रहा है, और तुर्की अपनी भाषा में से धुले मिले अरबी और फारसी शब्द निकाल रहा है। फिर यदि हम हिन्दी में से उन विदेशी शब्दों को निकालना चाहते हैं जो उसमें ज़बर्दस्ती या अज्ञानतावश घुसेड़े जा रहे या घुस गये हैं, तो हमीं को दोष क्यों दिया जाता है? यह संस्कृति का प्रश्न है, और भाषा संस्कृति को प्रधान पोषक है। यदि हम आज हिन्दी की विशुद्धता की रक्षा नहीं करेंगे तो हिन्दी—वह भाषा जिसका

ॐ श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल लिखते हैं कि जब कोई गांधीजी से 'हिन्दुस्तानी' में बात करते समय किसी अँगरेज़ी शब्द का व्यवहार करता है तो वे उसका मज़ाक उड़ाते हैं। हिन्दू मुसलमानों में समान भाव से प्रचलित अँगरेज़ी शब्दों के प्रति हिन्दुस्तानी वालों का यह रुझ है, परन्तु अरबी फारसी शब्द बढ़ाये बिना 'हिन्दुस्तानी' हिन्दुस्तानी नहीं कहला सकती!

‘हिन्दी’ नाम से बोध होता है—मिट जायगी, और उसके साथ हमारी संस्कृति मिट जायगी, हमारा साहित्य मिट जायगा, हम अर्थात् वह सब कुछ जिसका ‘हम’ और ‘हमारा’ से बोध होता है, मिट जायगा, गहरी धार्मिक हानि होगी और आने वाली पीढ़ियाँ हमें कोसेंगी। हमें आज हिन्दी की रक्षा करनी ही है, उसे चाहे प्रतिक्रिया कहा जाय, चाहे संकुचितहृदयता कहा जाय और चाहे रिवाइवलिज्म कहा जाय।

(४) साधारण जनता भाषा के प्रति जागरूक (language conscious) नहीं है।

नहीं है तो करना होगा। जनता तो भेड़ों के झुन्ड के समान है, उसे नेताओं ने जिधर हाँक दिया उधर चल दी। जनता किन्नी चीज़ से ‘कांशस’ नहीं होती, उसे कांशस’ किया जाता है। जनता को पेट भर खाने और तन भर कपड़े के सिवा किसी और चीज़ की चिन्ता नहीं होती। संस्कृति का निर्माण और उसकी रक्षा जनता नहीं, जननायक किया करते हैं। भाषा के मामले में भी नेतृत्व साहित्यिक और विद्वान् ही करते हैं, जनता केवल उनका अनुसरण करती है। भारतीय जनता भी न ‘लैंग्वेज कांशस’ है और न कभी थी। उसने सैकड़ों साल तक राजभाषा फारसी का पानी भरा फिर भी ‘लैंग्वेज कांशस’ नहीं हुई। परन्तु फारसी से जनता को जो व्यावहारिक और सांस्कृतिक हानि हुई, वह जननायकों को मालूम है। भता हो अँगरेज़ बहादुर का जिसने फारसी को हटाकर प्रान्तीय भाषाओं को प्रतिष्ठित किया, बर्ना न ‘जनता’ ने फारसी को हटाने की माँग की और न उसे (कितने ही जननायकों को भी) फारसी लदे रहने पर कोई उज्र था। आज ‘जनता’ को राजभाषा अँगरेज़ी से भी कोई शिकायत नहीं है—यह शिकायत तो उसमें अब नेता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें, उन्हीं को, मालूम है कि इस अँगरेज़ी से क्या हानि होगी। ‘जनता’ तो अब भी खुशी से पैसे देकर अँगरेज़ी में दरखास्त लिखाने के लिये तैयार है। हाँ, यदि कांग्रेस सरकार उससे उसकी भाषा में ही

लिखी हुई दरखास्त मंजूर कर ले तो उसे खुशी अवश्य होगी, परन्तु 'अँगरेज़ी निकालो' की जो और जैसी भावना गांधीजी या अन्य नेताओं के दिमाग में काम कर रही है, उसकी वृ भी 'जनता' को नहीं छू गई है। उसे तो यह अब बताया जा रहा है कि अँगरेज़ी विदेशी है, उसका बहिष्कार करो, अँगरेज़ी में भाषण मत दो, पत्रव्यवहार मत करो, आदि। यह सब जनता को 'लैंग्वेज कांशस' करना ही तो है। जनता को इंगलिस्तानी से भी कोई चिढ़ नहीं, वह खुशी खुशी अँगरेज़ी शब्द बोलने के लिये भी तैयार है, बल्कि वह उसे बड़प्पन का चिन्ह समझती है। चाहिये तो यह कि जनता से शिक्षित समाज की इंगलिस्तानी की नकल न करने के लिये भी न कहा जाय। अँगरेज़ी शब्दों के मामले में ही उसे 'कांशस' क्यों किया जाय ? यदि 'हिन्दी बोलो क्लब' से साधारण जनता को दिलचस्पी नहीं हो सकती, तो प्रयाग के 'हिन्दुस्तानी बोलो क्लब' से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, ऐसा क्लब भी नहीं स्थापित होना चाहिये। यदि 'हिन्दुस्तानी बोलो' का आन्दोलन हो सकता है, तो 'हिन्दी बोलो' का आन्दोलन भी हो सकता है। यदि हम जनता से अपनी प्राचीन संस्कृति और भाषा के अनुरूप अपनी भाषा सुधारने के लिये कहते हैं, तो इस पर किसी को क्यों आपत्ति होती है ? जनता के लिये क्या अच्छा है, और भाषा की कौन सी प्रवृत्ति त्याज्य है और कौन सी ग्राह्य, इस पर तो जननायकों में मतभेद हो ही सकता है। यदि हम यह समझते हैं कि हिन्दी में 'हिन्दुस्तानी' के नाम से या किसी और नाम या 'वाद' की आड़ में अरबी फारसी शब्द भरने की प्रवृत्ति उतनी ही बुरी है जितनी अँगरेज़ी शब्द भरने की, और भाषा में से अनावश्यक अरबी फारसी शब्द उसी प्रकार निकालना चाहिये जिस प्रकार अनावश्यक अँगरेज़ी शब्द, तो क्या ग़लत समझते हैं ? इस पर तर्क हो सकता है और विरोधियों को हम तर्क के लिये आमंत्रित करते हैं, परन्तु यह बात कि जनता 'लैंग्वेज कांशस' नहीं है फिर क्या महत्व रखती है ?

जो सज्जन यह कहते हैं कि जनता 'लैंगुएज कांशस' नहीं है, वे भी शायद यह पसंद न करेंगे कि उर्दू राजभाषा बनी रहे, परन्तु उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि 'जनता' उर्दू के भी विरुद्ध नहीं है, जनता अदालतों की भाषा से भी 'कांशस' नहीं है, यदि यही भाषा बनी रहे तो भी उसे कोई उज्र नहीं है अर्थात् यदि हिन्दुस्तानीवालों की 'हिन्दुस्तानी' के बजाय विशुद्ध उर्दू का ही दौर दौरा रहे, तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं। वह उसे भी सहन कर लेगी और बिना उज्र के सौ साल से सहन कर ही रही है। 'उर्दू हटा कर हिन्दुस्तानी करो' यह नारा भी जनता का नहीं, केवल थोड़े से जननायकों का है। जनता ने तो अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी और गुलामी भी स्वीकार कर ली हैं। इनके प्रति जनता को 'कांशस' करना और इनसे जनता को मुक्ति दिलाना भी केवल कुछ जननायकों का काम है। उन्होंने ही जनता को बताया कि वह गुलाम है, पराधीन है, और उन्होंने ही उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये उकसाया और स्वदेशी पर जोर दिया। जिन्होंने यह सब कुछ किया, उन्हें ही भाषा के मामले में भी बताया होगा कि विदेशी शब्दों और विदेशी लिपि की पराधीनता भी बुरी है। उन्हें ही भाषा के मामले में भी स्वदेशी पर जोर देना होगा, विदेशी शब्दों के प्रति जनता को कांशस करना होगा और उनसे मुक्त होने की इच्छा को उत्पन्न करना होगा। यदि स्वदेशी आन्दोलन के कुछ नेता स्वदेशी के तर्क को भाषा के मामले में अन्त तक (logical conclusion तक) निभाने के लिये तैयार नहीं, तो यह बात दूसरी है, परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि जनता को 'लैंगुएज कांशस' करना होता है और यह काम थोड़े से लोग ही किया करते हैं।

५. क्या हिन्दी कृत्रिम है ?

कुछ समय हुआ, देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद ने फरमाया कि हिन्दी बहुत हद तक कृत्रिम भाषा है, वह इने गिने लोगों की मातृभाषा है, और

सलाह दी कि हिन्दी बाले जितने ही अधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना ही वे हिन्दी को अच्छा बनायेंगे। जो 'हिन्दुस्तानी' जैसी कृत्रिम भाषा गढ़ने वालों के एक अगुआ हैं, जिन्होंने कृत्रिम रूप से 'हिन्दुस्तानी' गढ़ने के लिये कमेटियाँ बैठाई हैं और जो स्वयम् हिन्दुस्तानी गढ़ा भाषाओं के एक सुलिया हैं, उन्हें हिन्दी पर 'कृत्रिमता' का लांछन लगाना शोभा नहीं देता। हम उनसे यह भी पूछना चाहेंगे कि जिस 'हिन्दुस्तानी' को उन्होंने बिहार पर लदवाया और अब फिर लदवाना चाहते हैं, वह ही कितने बिहारियों की 'मातृ-भाषा' है, और उन महमूद सीरीज़ और राजेन्द्र सीरीज़ को रीडरों की 'हिन्दुस्तानी' जिसने सीता को 'वेगम' और बाल्मीकि को 'मौलवी' बना दिया, कहाँ तक अकृत्रिम और स्वाभाविक है, और फारसी लिपि जिसका सीखना वे सब बिहारियों के लिये अनिवार्य करना चाहते हैं, कहाँ तक किसी 'हिन्दुस्तानी' की, और कितने बिहारियों की स्वाभाविक लिपि है? यदि अधिकाधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ही अकृत्रिमता लाने का सबसे सरल नुस्खा है, तो क्यों नहीं उन्होंने रबीन्द्र को अरबी-फारसीमय बँगला लिखने की सलाह दी, और क्यों नहीं वे गांधी जी से अरबी-फारसीमय गुजराती लिखने के लिये कहते? हिन्दी पर ही उनकी कृपा-दृष्टि क्यों है, उसी को वे अरबी-फारसीमय क्यों बनाना चाहते हैं? अस्तु, डा० राजेन्द्र प्रसाद के विचारों का तो उचित मूल्यांकन फिर होगा, परन्तु क्या हिन्दी वास्तव में कृत्रिम है?

हाँ, हिन्दी कृत्रिम है। वह कृत्रिम इसलिये नहीं है कि उसमें बहुत से अवाङ्मनीय या बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्द हैं—उर्दू में अवाङ्मनीय या बोलचाल में अप्रचलित अरबी फारसी शब्दों की संख्या और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में अवाङ्मनीय या बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्दों की संख्या इससे कम नहीं है, वरन् वह कृत्रिम इसलिये है कि उसमें अनावश्यक, अवाङ्मनीय, या बोलचाल में अप्रचलित, या हिन्दी शब्दों की अपेक्षा

कम प्रचलित अरबी फारसी शब्दों की भरमार है (हिन्दी का द्वैतवाद)। इस भरमार को दूर करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के सफल होने पर हिन्दी आज की हिन्दी से अधिक संस्कृत-निष्ठ ही होगी, और उसमें अरबी फारसी शब्दों की संख्या और कम होगी। जहाँ तक हिन्दी में प्रचलित संस्कृत शब्दों का सम्बन्ध है वहाँ तक हिन्दी पर कृत्रिमता का आरोप केवल उन संस्कृत शब्दों के कारण किया जा सकता है जो हिन्दी प्रदेश की बोलचाल में कहीं—विशिष्ट शिक्षित वर्गों में या साधारण जनता में—प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनमें से कुछ के देशज, कुछ के अरबी फारसी और कुछ के देशज और अरबी फारसी दोनों पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं। यदि, जैसा कि होना चाहिये, बोलचाल का माप-दण्ड विशिष्ट वर्गों की बोलचाल नहीं, बल्कि हिन्दी प्रदेश की साधारण, बहुसंख्यक जनता की बोलचाल माना जाय, और इन संस्कृत शब्दों में से उन शब्दों को निकाल दिया जाय जिनके किसी भी प्रकार के पर्याय केवल विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित हैं, साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं क्योंकि उसे अपने नित्य के काम के लिये अभी तक उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अर्थात् यदि इन संस्कृत शब्दों में से उन संस्कृत शब्दों को छोड़ दिया जाय जिन्हें, ईंगलिस्तानी में प्रचलित आंगरेजी शब्दों की भाँति विशिष्ट वर्गों में उनके अरबी फारसी पर्यायों के प्रचलित होते हुए, प्रचलित करने का हमें अधिकार है, तो शेष संस्कृत शब्दों की संख्या कुछ सौ से अधिक न होगी, क्योंकि दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश साधारण जनता के जीवन का स्तर इतना ऊँचा ही न हुआ कि उसे अपनी नित्य की बोलचाल के लिये एक लम्बी चौड़ी शब्दावली की आवश्यकता पड़ती, और यदि उसे कभी आवश्यकता पड़ी भी, तो वह अपने प्राचीन शब्दों और प्राचीन शब्द-स्त्रोतों को छोड़कर अरबी फारसी की शरण लेने के लिये उस प्रकार मजबूर न हुई जिस प्रकार शहरों का शिक्षित समाज

मजबूर हुआ । ये बचे हुये कुछ सौ संस्कृत शब्द ऐसे हैं जो कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनके देशज या अरबी फारसी पर्याय या दोनों प्रकार के पर्याय साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं । इनमें से कुछ ऊपर के (२) (अ) वर्ग (पृष्ठ ४७) में आजाते हैं और शेष के अरबी फारसी पर्याय ऊपर के (१) (इ) (i) वर्ग (पृष्ठ ३५) में आ जाते हैं । इनके साथ क्या होना चाहिये, यह पहले बतलाया जा चुका है । यदि हिन्दी को कृत्रिमता या अकृत्रिमता की दृष्टि से नहीं, बरन् शुद्ध जनता की सुविधा की दृष्टि से देखा जाय, तो इन कुछ सौ संस्कृत शब्दों में उन संस्कृत शब्दों को और जोड़ना पड़ेगा जो शिक्षित समाज की बोलचाल में तो प्रचलित हैं परन्तु जनता की बोलचाल में जिनके अरबी फारसी पर्याय प्रचलित हैं (इनके अरबी फारसी पर्याय ऊपर के (१) (इ) (ii) वर्ग (पृष्ठ ३५) में आ जाते हैं; इनके साथ क्या होना चाहिये, यह भी वहीं बताया जा चुका है) । इस प्रकार इन शब्दों की संख्या लगभग ५०० हो जायगी । यदि इन शब्दों में उन संस्कृत शब्दों को भी जोड़ ही दिया जाय जिन्हें छोड़ने के लिये ऊपर कहा गया है, अर्थात् उन संस्कृत शब्दों को भी जोड़ दिया जाय जो शिक्षित समाज की बोलचाल में भी प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अरबी फारसी पर्याय केवल शिक्षित समाज की साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं—साधारण जनता को उनकी या उनके अरबी फारसी पर्यायों की अब तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी (और इसलिये जिन्हें, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रचलित करने का और उनके अरबी फारसी पर्यायों का बहिष्कार करने का हमें अधिकार है), अर्थात् यदि, जहाँ तक बोलचाल का संबंध है, हिन्दी के केवल वे ही संस्कृत शब्द सब प्रकार से अकृत्रिम और अधिकारी समझे जायँ जो या तो साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं वा, यदि उनकी या उनके अरबी फारसी पर्यायों की आवश्यकता जनता को नहीं पड़ी—केवल शिक्षित समाज को पड़ी, तो

शिक्षित समाज की बोलचाल में प्रचलित हैं, तो इन शब्दों की संख्या लग-भग एक हजार तक पहुँच जायगी (यदि केवल वे ही संस्कृत शब्द लिये जाते जो हिन्दी प्रदेश की बोलचाल में कहीं भी—जनसाधारण की बोलचाल या शिक्षित समाज की बोलचाल में—प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनके देशज या अरबी फारसी पर्याय हिन्दी प्रदेश की बोलचाल में प्रचलित हैं, तो (१) (इ) (ii) वर्ग के अरबी फारसी शब्दों के संस्कृत पर्यायों को जोड़ने की आवश्यकता न पड़ती, और यह संख्या एक हजार से भी कम होती) । सरांश यह है कि किसी भी प्रकार या किसी भी दृष्टि से देखा जाय, हिन्दी में प्रचलित ऐसे संस्कृत शब्दों की संख्या जिन पर उँगली उठाई जा सकती है, किसी भी प्रकार एक हजार से अधिक नहीं है । अब सोचने की बात है कि क्या वह भाषा जिसकी कुल शब्द संख्या ५० हजार से अधिक हो और दिन प्रति दिन बढ़ती जाती हो, केवल एक हजार शब्दों के कारण कृत्रिम कही जा सकती है ? यह भी न भूलना चाहिये कि इन एक हजार संस्कृत शब्दों के देशज या अरबी फारसी पर्याय भी (जो बोलचाल में प्रचलित हैं) हिन्दी में आते हैं । हिन्दी ने साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित सभी अरबी फारसी शब्दों को ही नहीं अपनाया है, वरन् उसमें विशिष्ट वर्गों की बोलचाल वाले अरबी फारसी शब्द भी आते हैं, अर्थात् यदि हिन्दी से किसी को शिकायत हो सकती है तो केवल इतनी ही कि इन एक हजार बोलचाल में प्रचलित देशज या अरबी फारसी शब्दों के साथ साथ उनके बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत पर्याय क्यों आते हैं । हिन्दी में शब्दों के द्वैतवाद को दूर करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है, और इसे दूर करने के लिये जो सिद्धान्त यहाँ प्रतिपादित किये गये हैं उन पर आक्षेप करने का शायद 'अकृत्रिमता', 'स्वाभाविकता' या 'हिन्दुस्तानी' के बड़े से बड़े समर्थक को भी साहस न होगा । हम डा० राजेन्द्रप्रसाद तथा 'हिन्दुस्तानी' के अन्य पक्षपा-

तियों को विश्वास दिलाते हैं कि इन सिद्धान्तों के अनुसार हिन्दी में से जितने संस्कृत शब्दों को निकालना पड़ेगा, उनसे उन अरबी फारसी शब्दों की संख्या कई गुना अधिक होगी जिन्हें हिन्दी में से इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार निकालना पड़ेगा। यहाँ यह बात देना भी आवश्यक है कि हिन्दी में आने वाले जिन अरबी फारसी शब्दों के विरुद्ध इस पुस्तक में आवाज़ उठाई गई है, उनकी संख्या भी इस समय एक हजार से अधिक नहीं है। इस पुस्तक को पढ़कर कोई यह कहने का साहस न करे कि हिंदी कोई भाषा नहीं, उसमें तो उर्दू के सभी शब्द आते हैं। ये एक हजार अरबी फारसी शब्द वही हैं जिन्हें हिंदी लेखक हिंदी प्रदेश में अपने चारों ओर बोलचाल में सुनते हैं (देशज, संस्कृत तत्सम या तद्भव शब्दों के साथ साथ या अकेले), और असावधानी के कारण हिन्दी में स्थान दे देते हैं अथवा, यों कहिये, लिख जाते हैं। बोलचाल में बहुत अधिक शब्द हैं ही नहीं। एक गुलाम और मिछड़े हुये देश के निवासियों की जिन पर पिछले एक हजार वर्षों से विदेशी शासकों ने सब गम्भीर कार्यों और व्यवहारों के लिये विदेशी भाषाओं को लाद रक्खा हो, बोलचाल की शब्दावली समृद्ध हो ही कैसे सकती है। बोलचाल की शब्दावली से सध ही कितने काम सकते हैं ? यदि हिंदी में आनेवाले बोलचाल में प्रचलित इन एक हजार अरबी फारसी शब्दों को रहने ही दिया जाय, और उनके देशज और बोलचाल में प्रचलित अथवा अप्रचलित संस्कृत पर्यायों का हिंदी से पूर्ण वहिष्कार कर भी दिया जाय, तो कौन सी समस्या हल हो जायगी ? यह प्रश्न तो फिर भी रह जायगा कि उन शब्दों को जिनकी गंभीर कार्यों के लिये आवश्यकता है (और जिनकी संख्या बहुत अधिक है और दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है) परन्तु जो बोलचाल में कहीं नहीं पाये जाते, कहाँ से और किन सिद्धान्तों के अनुसार लाया जाय। ऐसे शब्दों के लिये उर्दू अरबी और फारसी, अरब और फारस की शरण क्यों लेती है ? यदि ऐसे शब्दों के लिये उर्दू को अरबी फारसी का दरवाज़ा खटखटाने का कोई अधिकार

है ही, तो हिंदी को संस्कृत और प्राचीन हिंदी साहित्य के पास जाने का एक हजार गुना अधिक अधिकार है। तथाकथित 'स्वाभाविकता' या 'हिंदुस्तानी' का कोई भक्त इसके विरुद्ध चूँ कर सकता है ? हिन्दी में इस समय भी लगभग १५ हजार संस्कृत शब्द हैं जो उर्दू के अरबी फ़ारसी शब्दों से सर्वथा भिन्न हैं और जिनके साथ साथ उनके उर्दू पर्याय हिंदी में कभी नहीं आते। १५ हजार ऐसे संस्कृत शब्दों के सामने एक हजार हिंदी शब्दों का, जिनके साथ साथ अरबी फ़ारसी पर्याय हिंदी में आते हैं, कोई विरोध महत्त्व नहीं। इन एक हजार शब्दों के विषय में चाहे जो कुछ निर्णय हो—चाहे सब के सब हिंदी शब्द निकाल दिये जायँ और उनके स्थान में केवल अरबी फ़ारसी शब्द रक्खे जायँ, चाहे थोड़े से हिन्दी शब्द निकाले जायँ और चाहे हिंदी शब्द और अरबी फ़ारसी शब्द दोनों रक्खे जायँ—इससे हिंदी के स्वतन्त्र अस्तित्व और उर्दू से पृथक्त्व पर बिलकुल आँच नहीं आती। हमें वाज़ाह बोलचाल की नहीं, एक समृद्ध साहित्यिक भाषा की आवश्यकता है। हिंदी का भाग्य तो ऐसा फूटा है कि हिंदी के लेखक केवल बोलचाल—साधारण बोलचाल अथवा विशिष्ट वर्गों की बोलचाल—में प्रचलित अरबी फ़ारसी शब्दों को (बोलचाल में प्रचलित अथवा अप्रचलित अपने पर्यायों के होते हुए) लेकर ही सन्तुष्ट नहीं हैं वरन् वे उन शब्दों के मामले में भी जो कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, और इसलिये जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों को संस्कृत या अरबी फ़ारसी से उधार लेना है, हिंदी में द्वैतवाद फैला रहे हैं (हिंदुस्तानीवालों और 'हिंदुस्तानी' के प्रताप से ?), अर्थात् हिंदीवाले अप्रचलित और अनावश्यक उर्दू शब्द हिंदी में घुसेड़ रहे हैं, और हिंदुस्तानीवालों की सिखाई हुई राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता की परिभाषा की लपेट में आकर अपने बहुप्रचलित हिंदी शब्द बोलने से भी शर्माते हैं। लेखक को इसकी अधिक आशा नहीं कि हिन्दीवाले इस पुस्तक को पढ़कर हिंदी में घुसे हुये इन एक हजार अरबी फ़ारसी शब्दों को यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार धराने

का प्रयत्न करेंगे। उसे केवल थोड़ी सी आशा यह है कि हिंदीवाले शायद आगे के लिये सावधान हो जायँ और अपने ही हाथों हिंदी की कन्न तैयार करना छोड़ दें। हिंदुस्तानीवाले इस पुस्तक को पढ़कर भड़कें नहीं।

जब हिंदी की कृत्रिमता का सवाल उठा है तब उर्दू की हालत पर भी सरसरी नज़र डालना असंगत न होगा। उर्दू डेढ़ सौ साल से अधिक से हिंदी शब्द मतरूक करती आरही है। उर्दू ने जनता की बोलचाल में प्रचलित सैकड़ों देशज, और संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों को मतरूक कर दिया है और उनके स्थान में अरबी फ़ारसी शब्दों को भर लिया है। इन अरबी फ़ारसी शब्दों में से कुछ जनता की बोलचाल में प्रचलित हो गये हैं, कुछ केवल शिक्षित समाज की बोलचाल में प्रचलित हैं, कुछ विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित हैं, और शेष कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं। हिंदी में बोलचाल में प्रचलित किसी देशज या संस्कृत तत्सम या तद्भव शब्द को मतरूक करने का कभी प्रश्न ही नहीं उठा और न कभी उठ सकता है। इतना ही नहीं, हिंदी में बोलचाल में प्रचलित सभी अरबी फ़ारसी शब्द भी, बोलचाल में प्रचलित हिंदी पर्यायों के होते हुये, आते हैं, परन्तु उर्दू में बोलचाल में प्रचलित हिन्दी शब्द, यदि बोलचाल में उनके उर्दू पर्याय प्रचलित हों तो, कभी नहीं आते। उर्दू के ऐसे अरबी फ़ारसी शब्दों की संख्या भी जो साधारण बोलचाल में कहीं प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके हिन्दी पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं, उन संस्कृत शब्दों की संख्या से कहीं अधिक है जो बोलचाल में कहीं प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अरबी फ़ारसी पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं। हिन्दी में जहाँ ऐसे बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्दों के साथ उनके बोलचाल में प्रचलित अरबी फ़ारसी पर्याय भी आते हैं, वहाँ उर्दू में बोलचाल में अप्रचलित अरबी फ़ारसी शब्दों के साथ उनके बोलचाल में प्रचलित हिन्दी पर्याय कभी नहीं आते। हिन्दी के जितने संस्कृत शब्दों के विरुद्ध हमें यह शिकायत है कि उनके देशज पर्याय प्रचलित होते हुए उन्हें क्यों

प्रयुक्त किया जाता है, उन सबके (वास्तव में उनसे अधिक के) अरबी फारसी पर्याय उर्दू में प्रयुक्त होते हैं; बल्कि जहाँ हिन्दी में संस्कृत शब्दों के साथ साथ देशज पर्याय भी आते हैं वहाँ उर्दू में देशज हिन्दी पर्याय नहीं आते। इन अरबी फारसी शब्दों के सुट्टी भर लोगों की बोलचाल में प्रचलित होने के कारण उर्दू कृत्रिमता के दोष से बरी नहीं हो सकती। ऐसे विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में इन देशज शब्दों के हिन्दी संस्कृत पर्याय भी मिल जायेंगे। फिर, हिन्दी के जितने संस्कृत शब्दों के विरुद्ध हमें यह शिकायत है कि उन्हें बोलचाल में उनके अरबी फारसी पर्यायों के उनसे अधिक प्रचलित होते हुये क्यों प्रयुक्त किया जाता है, उनसे अधिक संख्या में उर्दू के ऐसे अरबी फारसी शब्द हैं जिनके संस्कृत पर्याय बोलचाल में उनसे अधिक प्रचलित हैं; बल्कि जहाँ हिन्दी में ऐसे संस्कृत शब्दों के साथ साथ उनके बोलचाल में उनसे अधिक प्रचलित, अरबी फारसी पर्याय भी आते हैं, वहाँ उर्दू में ऐसे अरबी फारसी शब्दों के साथ उनके बोलचाल में उनसे अधिक प्रचलित संस्कृत पर्याय कभी नहीं आते। हिन्दी के जितने संस्कृत तत्सम शब्दों के विरुद्ध किसी को यह शिकायत हो सकती है कि वे बोलचाल में उसी रूप में नहीं बोले जाते, उनसे उर्दू के ऐसे तत्सम अरबी फारसी शब्दों की संख्या कम नहीं है जो बोलचाल में उसी रूप में नहीं बोले जाते। जो शब्द कहीं की बोलचाल में प्रचलित नहीं है, उनके लिये उर्दू स्वदेश छोड़ कर विदेशों की खाक छानती है, अपने को एक विदेशी लिपि में (जिसके विषय में शंका हो ही नहीं सकती कि वह हिन्दी की स्वाभाविक लिपि नहीं है, हिन्दी लिखने के उपयुक्त नहीं है और देवनागरी की अपेक्षा कहीं कम प्रचलित है) लिखती है, अपने को विदेशी आभूषणों से सजाती है और विदेशी संस्कृति अपनाती है। ये सब बातें अलग हैं। जिस प्रकार हिन्दी में बोलचाल में प्रचलित सभी अरबी फारसी शब्द भी आते हैं उसी प्रकार उर्दू में बोलचाल में प्रचलित सभी

हिन्दी शब्द—देशज, संस्कृत तत्सम या तद्धव—भी आवें, और यदि उर्दू इस द्वैतवाद को नहीं अपना सकती तो ऊपर प्रतिपादित जिन सिद्धान्तों के अनुसार हम अरबी फारसी शब्द हिन्दी में रखना चाहते हैं कम से कम उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार उर्दू में हिन्दी संस्कृत शब्द आवें—यह हमारा उन उर्दू वालों को जवाब है जो हिन्दी से अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार करने के लिये ऊपर प्रतिपादित सिद्धान्तों पर उँगली उठाना चाहें। जिन सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार हिन्दी के संस्कृत शब्दों को साधारण बोलचाल में अप्रचलित, परन्तु उनके अरबी फारसी या देशज पर्यायों को साधारण बोलचाल में प्रचलित बताया जाता है, और जिन सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार हिन्दी के संस्कृत शब्दों को उनके अरबी फारसी या देशज पर्यायों की अपेक्षा साधारण बोलचाल में कम प्रचलित बताया जाता है, उन्हीं सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार उर्दू अपने ऐसे अरबी फारसी शब्दों का त्याग करे जो साधारण बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके संस्कृत या देशज पर्याय साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं, और ऐसे अरबी फारसी शब्दों का त्याग करे जो संस्कृत या देशज पर्यायों की अपेक्षा साधारण बोलचाल में कम प्रचलित हैं, और यदि उर्दू ऐसा नहीं कर सकती तो कम से कम वह अपने आपत्तिजनक अरबी फारसी शब्दों के साथ वैसा व्यवहार करने को तैयार हो जैसा हिन्दी के आपत्तिजनक संस्कृत शब्दों के साथ करने के लिये ऊपर जोर दिया गया है—यह हमारी उन उर्दू वालों को चुनौती है, जो हिन्दी को कृत्रिम बताते हैं।

अब 'हिन्दुस्तानी' की अकृत्रिमता (!) को लीजिये। 'हिन्दुस्तानी' के भक्तों के सामने दो हो रास्ते हैं। वे 'हिन्दुस्तानी' का ढाँचा खड़ी बोली को आधार मान कर या तो बोलचाल की भाषा की दृष्टि से खड़ा कर सकते हैं या लिखित भाषा की दृष्टि से। पहले बोलचाल को लीजिये। हम हिन्दुस्तानी वालों को आमंत्रित करते हैं कि वे इस सिद्धान्त को रक्खें कि

वे हिन्दुस्तानी को जिस प्रदेश की भाषा बनाना चाहते हैं उस सम्पूर्ण प्रदेश की बोलचाल में एक शब्द के प्रचलित विभिन्न पर्यायों में से उस पर्याय को हिन्दुस्तानी में लेंगे जिसे सब से अधिक व्यक्ति बोलते हों, और उन शब्दों के मामले में जिनकी अभी तक नित्य की साधारण बोलचाल में आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अर्थात् जो बोलचाल में हैं ही नहीं, वे हिन्दुस्तानी के लिये हिन्दुस्तान के अपने स्रोतों को शरण लेंगे। बोलचाल में प्रचलित सभी अरबी फ़ारसी शब्द हम लेते हैं (और एक बार को हम बोलचाल में प्रचलित उनके स्वदेशी पर्यायों को, चाहे वे अपेक्षाकृत कम प्रचलित हों अथवा अधिक, बिलकुल छोड़ने को भी तैयार हैं), बोलचाल में अप्रचलित सभी आवश्यक शब्द उर्दूवाले और हिन्दुस्तानीवाले हिन्दुस्तानी स्रोतों से लें। यही सही और सच्ची बात है, और 'बोलचाल की भाषा सबसे पहले', इस सिद्धांत का यही अर्थ हो सकता है। यदि हिन्दुस्तानीवाले इस बात के लिये, अर्थात् बोलचाल में अनुपस्थित शब्दों के लिये हिन्दुस्तान के पुराने 'सुर्दा' स्रोतों को प्राथमिक महत्त्व देने को तैयार नहीं, तो हम कहते हैं कि बोलचाल में अनुपस्थित शब्द वे उस प्रदेश, जिसकी भाषा वे हिन्दुस्तानी बनाना चाहते हैं, में प्रचलित साहित्यिक भाषाओं से लें, और एक शब्द के विभिन्न पर्यायों में से उसको लें जिसे सबसे अधिक व्यक्ति लिखते हों। (उदाहरण के लिये यदि इन्तज़ार, बाट, प्रतीक्षा में से 'बाट' सब से अधिक व्यक्तियों की बोलचाल में आता है तो 'बाट' लें; आसमान, आकाश में से 'आसमान' अधिक चलता है तो 'आसमान' लें, एतराज, आपत्ति में से 'एतराज' बोलचाल में अधिक आता है तो 'एतराज' लें; तहज़ीब, सम्मता में से 'सम्मता' अधिक व्यक्तियों की बोलचाल में आता है तो 'सम्मता' लें; और 'अन्तर्राष्ट्रीय' 'राजनीतिक', 'दशमलब', 'बैतुलअकबामी', 'स्यासी', 'आशायी' में से 'अन्तर्राष्ट्रीय', 'राजनीतिक', 'दशमलब' लें, क्योंकि ये शब्द या उनके उर्दू पर्याय कहीं बोलचाल में नहीं आये, परन्तु साहित्य में इन शब्दों को उर्दू पर्यायों की

अपेक्षा अधिक व्यक्ति लिखते हैं।) यदि वे हिंदुस्तानी को हिंदी प्रदेश की भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धांतों को, जो किसी स्वदेशी-भावना पर नहीं, बरन् शुद्ध प्रजातन्त्र या लोकतंत्र पर अवलम्बित हैं, संपूर्ण हिंदी प्रदेश की बोलचाल और हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषाओं अर्थात् हिंदी और उर्दू पर लागू करके हिंदुस्तानी गढ़ें। यदि वे हिंदुस्तानी को सम्पूर्ण भारत की भाषा अर्थात् राष्ट्र-भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धान्तों को संपूर्ण भारत की बोलचाल और संपूर्ण भारत की साहित्यिक भाषाओं पर लागू करके हिंदुस्तानी गढ़ें। हम दावा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी बनेगी वह दोनों ही प्रकरणां—हिंदी प्रदेश के अथवा समूचे राष्ट्र के—में आधुनिक हिंदी से केवल इतनी भिन्न होगी कि उसमें आधुनिक हिंदी की अपेक्षा अरबी फ़ारसी शब्दों की संख्या और भी कम होगी—वह बिलकुल वही होगी जो ऊपर प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार हिन्दी का परिष्कार करने के बाद हिंदी हो जायगी। यदि हिंदुस्तानीवाले दूसरे रास्ते से अर्थात् लिखित भाषा की दृष्टि से चलना चाहते हैं, तो वे हिंदी प्रदेश के प्रकरण में हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषाओं अर्थात् आधुनिक हिंदी और आधुनिक उर्दू में से उन शब्दों को लें जिन्हें हिंदी प्रदेश में अधिक व्यक्ति लिखते हों, और राष्ट्र-भाषा के प्रकरण में खड़ी बोली को आधार मान कर संपूर्ण भारत की साहित्यिक भाषाओं में से उन शब्दों को लें जिन्हें अधिक व्यक्ति लिखते हों। हम दावा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी बनेगी उसमें हिंदी प्रदेश के प्रकरण में आधुनिक हिंदी की अपेक्षा एक भी अरबी फ़ारसी शब्द अधिक न होगा, और राष्ट्र-भाषा के प्रकरण में वे वह आधुनिक हिंदी से भी अधिक संस्कृत-निष्ठ होगी। परन्तु हिंदुस्तानीवाले कहीं ठहरे, अपने शीमुख से किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करें तब तो। सिद्धांत का तो वह भी तकाज़ा है कि एक भाषा हिंदुस्तानी एक ही लिपि में लिखी जाय*, और वह लिपि ऐसी हो

* पं० राधेश्याम कथावाचक ने एक बार 'उर्दू' हिन्दी से अधिक बोली

जिसमें ऊपरवाले सिद्धान्तों के अनुसार निर्मित हिंदुस्तानी शुद्ध लिखी और पढ़ी जा सके, और जो हिन्दी प्रदेश के प्रकरण में हिंदी प्रदेश में, और राष्ट्र-भाषा के प्रकरण में राष्ट्र में अधिक प्रचलित हो, और जिसे अधिक व्यक्ति जानते हों। मगर सच तो यह है कि हिंदुस्तानीवाले हिंदुस्तानी को किसी सिद्धान्त के अनुसार नहीं, बल्कि सब सिद्धान्तों को ताक पर रखकर हिंदी-उर्दू की खिचड़ी अर्थात् एक प्रकार की उर्दू—आधुनिक उर्दू की अपेक्षा ज़रा कम अरबी-फ़ारसीमय उर्दू—बनाना चाहते हैं। (इस हिंदुस्तानी के नमूने डा० राजेन्द्रप्रसाद के ही प्रान्त में कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित जन-साक्षरता-समिति के पत्र 'रोशनी' और डा० राजेन्द्रप्रसाद की आशीर्वाद-प्राप्त महमूद रीडरों में और राजेन्द्र सीरीज़ की रीडरों में मिल सकते हैं।) वे हिंदुस्तानी को जनता-जनार्दन की सेवा के लिये, सब से अधिक व्यक्तियों की सब से अधिक सुविधा के लिये जनतन्त्रात्मक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं, बल्कि एकता का स्वाँग रचने के हेतु पाकिस्तानियों, मुस्लिम लीगियों को खुश करने के लिये बनाना चाहते हैं। यहाँ यह बताना असंगत न होगा कि जब बिहार की कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित हिंदुस्तानी-गढ़-कमेटी में कमेटी-के एक सदस्य पं० रामनरेश त्रिपाठी ने यह प्रस्ताव रक्खा कि हिंदुस्तानी के लिये शब्द हिंदी उर्दू के कोषों से लुँटने के बजाय हिंदी प्रदेश की जनमतीय बोलियों में से—जनता के वास्तविक शब्द—ले लिये जायँ, तो उन से अन्य सदस्य सहमत न हुये, और त्रिपाठीजी को त्याग-पत्र देना पड़ा। यह है 'अकृत्रिम' हिंदुस्तानी, 'जनता की हिंदुस्तानी' की असलियत, और यह है उस प्राकृतिक, स्वाभाविक हिंदुस्तानी की कहानी जिसे हिंदी पर कृत्रिमता का जाती है—उर्दू बोलने की भाषा है और हिन्दी लिखने की, यह दावा करने वाले एक व्यक्ति को यह उत्तर दिया कि अच्छा, उर्दू वाले लिखने के लिये देवनागरी स्वीकार कर लें हम उर्दू को ही हिन्दी मनवा देंगे। हम हिंदुस्तानी वालों से कहते हैं कि वे हिन्दुस्तानी की एक ही लिपि देवनागरी रखें, हम उर्दू को ही हिन्दुस्तानी मान लेंगे।

आरोप करनेवाले डा० राजेन्द्रप्रसाद ने बिहार पर लादा और अब फिर लादना चाहते हैं। यदि वे वास्तव में हिंदी को कृत्रिम भाषा समझते हैं, और उर्दू को अकृत्रिम भाषा समझते हैं, तो समझ में नहीं आता वे हिंदुस्तानी क्यों गढ़ना चाहते हैं, उर्दू को ही वे वास्तविक हिंदुस्तानी और बिहार की भाषा क्यों नहीं घोषित कर देते? यदि वे उर्दू को भी कृत्रिम समझते हैं, तो समझ में नहीं आता कि वे दो कृत्रिम भाषाओं हिंदी और उर्दू से कृत्रिम उपायों से एक अकृत्रिम हिंदुस्तानी किस प्रकार मथ कर निकाल लेंगे। हाँ, यदि हिंदुस्तानी, श्री आनन्द कौसल्यायन के शब्दों में, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य की नहीं, हिंदू-मुस्लिम पैक्ट की भाषा है, तो बात दूसरी है। और वह पैक्ट भी कैसा जिसकी नींव में पानी भरता है, जो बनावटी और अस्थायी है, और जिस पर एक फरोक तो जान देने को तैयार है, दूसरा दस्तखत करने को भी तैयार नहीं—जिसे मान कर अपनी ईमानदारी दिखाने के लिये एक तो अपनी गर्दन काटने को तैयार है (बल्कि काट रहा है), दूसरा अपनी मूँछें नीची करने को भी तैयार नहीं! यह याद रहे कि बिहार की कांग्रेस सरकार ने हिंदुस्तानी गढ़ कमेटी बैठाई, और बिहार पर हिंदुस्तानी को लादा, परन्तु सीमा-प्रांत की कांग्रेस सरकार ने शुद्ध उर्दू और केवल उर्दू लिपि छोड़ कर किसी दूसरी हिंदुस्तानी या लिपि से नाता नहीं जोड़ा *। यह भी याद रहे कि डा० राजेन्द्रप्रसाद की राय में, मालूम होता है, 'हिंदुस्तानी' केवल बिहार के हिंदुओं की 'स्वाभाविक' भाषा है, क्योंकि राजेन्द्र-प्रसाद-हक समझौते के अनुसार बिहार के मुसलमान छात्र 'हिंदुस्तानी' पढ़ने के लिये बाध्य नहीं किये गये—उन्हें 'हिंदुस्तानी' के बजाय उर्दू पढ़ने का विकल्प दिया गया, परन्तु हिंदू छात्रों को यह विकल्प नहीं दिया गया। यह है डा० राजेन्द्रप्रसाद की 'अकृत्रिम' हिंदुस्तानी, और कांग्रेस की तथा-कथित कामन भाषा, राष्ट्र-भाषा का पोलखाता।

* आगे 'हिंदुस्तानी की बला' शीर्षक प्रकरण भी देखिये।

अब रही मातृ-भाषा की बात । सो खड़ी बोली ही कितने व्यक्तियों की मातृ-भाषा है ? खड़ी बोली केवल डेढ़ ज़िलों की मातृ-भाषा है । वहाँ भी सब लोग एक ही प्रकार की खड़ी बोली नहीं बोलते और एक ही शब्दावली का प्रयोग नहीं करते । कोई 'बोली' एक विशाल प्रदेश की और बहु-संख्यक जनता की मातृ-भाषा नहीं हो सकती । जो खड़ी बोली उत्तरी भारत के शहरों में बोली जाती है, वह उसके बोलने वालों की मातृ-भाषा तो नहीं है ही, उसका स्वरूप भी सब जगह एक सा नहीं है । फिर किस खड़ी बोली को आदर्श मानें, अर्थात् किस खड़ी बोलचाल को साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार मानें ? यह कहना बिल्कुल शलत और बेकार है कि किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल ऐसी है कि वह पेशावर से पटना तक के विशाल प्रदेश में सब जगह एक समान 'आमफहम' है, और इसलिये उसी को साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार बनाया जाय । पेशावर से पटना तक के विस्तृत प्रदेश में स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की खड़ी बोली बोली जाती है, अर्थात् भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है । हाँ, हिन्दी और उर्दू का रूप सब जगह एक सा है, क्योंकि वे साहित्यिक, लिखित भाषाएँ हैं और सब जगह एक ही रूप में पढ़ाई जाती हैं, और उन्हें जो पढ़ते हैं, वे उन्हें समझते हैं—सब अपने आप नहीं समझने लगते । इसी प्रकार जो भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी बनाई जायगी वह भी पटना से पेशावर तक सब जगह सबकी समझ में अपने आप नहीं आयगी । उसे भी हिन्दी उर्दू के समान पढ़ाना पड़ेगा । फिर किसी खास, छोटे से स्थान या वर्ग की हिन्दुस्तानी बोलचाल को उस साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार क्यों बनाया जाय ? यदि हिन्दुस्तानी या खड़ी बोली उत्तरी दोआब की मातृ-भाषा है और इसलिये उत्तरी दोआब का विशेष महत्त्व है, तो भी एक ज़िले की हिन्दुस्तानी बोलचाल को (जो स्वयम् ज़िले में भी सब जगह एक सी नहीं है) इतने विशाल प्रदेश या सम्पूर्ण

भारत की साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार क्यों बनाया जाय ? (एक बार पं० सुन्दरलाल ने फरमाया कि राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी का आदर्श दिल्ली नगर की गलियों में बोली जाने वाली हिन्दुस्तानी है !) यदि आज खड़ी बोली युक्त-प्रान्त, बिहार, मध्य-प्रान्त और राजस्थान की साहित्यिक भाषा, या राष्ट्र-भाषा का आधार मानी जा रही है, तो इसका कारण यह नहीं है कि खड़ी बोली एक या दो जिलों की मातृ-भाषा है, बरन् यह है कि खड़ी बोली दूर दूर तक फैल गई है, दूर दूर तक बोली जा रही है और सैकड़ों वर्षों के दौरान में खड़ी बोली का एक ऐसा स्वरूप तैयार हो चुका है जो हिन्दी प्रान्तों में और सारे देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ है । तात्पर्य यह कि पेशावर से पटना तक के प्रदेश की साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, बरन् खड़ी बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो इस प्रदेश के अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ हो, अर्थात् उसमें हिन्दी प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित शब्द ही रक्खे जा सकते हैं । देश की राष्ट्र-भाषा साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार भी किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, बरन् खड़ी बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो देश के अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ हो, अर्थात् उसमें देश में सबसे अधिक प्रचलित शब्द ही रक्खे जा सकते हैं । जैसा पहले कहा जा चुका है, दोनों ही दृष्टियों से यह आधार आधुनिक खड़ी बोली हिन्दी में अन्तर्निहित है, और यदि खड़ी बोली के इस सर्वाधिक सुलभ स्वरूप के आधार पर सर्वाधिक सुलभता के सिद्धान्त के अनुसार ही एक साहित्यिक हिन्दुस्तानी का निर्माण किया जाय, तो वह आधुनिक साहित्यिक हिन्दी से भिन्न न होगी । दूसरे शब्दों में, आधुनिक हिन्दी ही हिन्दी प्रदेश और सम्पूर्ण देश के लिये सबसे अधिक सुलभ और सबसे अधिक उपयुक्त हिन्दुस्तानी है । यदि हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी उर्दू की खिचड़ी किसी जनतन्त्रात्मक सिद्धान्त के अनुसार

हिन्दुस्तानी गढ़ने के लिये नहीं, बरन् हिन्दू-मुस्लिम पैकट की भाषा तैयार करने के लिये पकाना चाहते हैं, तो वे उसे केवल मातृ-भाषा बनावें— उसे वे किसी प्रान्त की भाषा क्यों बनाते हैं ? जिस प्रकार अन्य प्रान्त अपनी अपनी साहित्यिक भाषाओं को प्रान्त की भाषा बनाने के लिये स्वतन्त्र हैं, उसी प्रकार उक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त को अपने वहाँ उस खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का अधिकार होना चाहिये जो उनके लिये सबसे अधिक सुलभ हो। तब तौर से यदि बिहार किसी प्रकार की खड़ी बोली को अपनाना चाहता है, तो उसके लिये वही खड़ी बोली सबसे अधिक उपयुक्त होगी जो बिहारियों के लिये सबसे अधिक सुलभ हो और बिहार की मातृ-भाषाओं के सबसे अधिक निकट हो। इस प्रकार आधुनिक खड़ी बोली हिन्दी ही बिहार के लिये सबसे अधिक उपयुक्त खड़ी बोली या हिन्दुस्तानी उहरती है*। फिर बिहार में हिन्दी के बजाय हिन्दू-मुस्लिम पैकट वाली हिन्दुस्तानी को प्रान्त-भाषा क्यों बनाया जाता है ? जो कोई हिन्दुस्तानी हिन्दी में उर्दू मिलाकर गढ़ी जायगी, वह उतनों से अधिक की मातृ-भाषा हो ही नहीं सकती जितनों की मातृ-भाषा खड़ी बोली हिन्दी है, हाँ, वह हिन्दी की अपेक्षा अधिक कठिन अवश्य हो जायगी। ऐसी अवस्था में डा० राजेन्द्र-प्रसाद यह बतलाने की कृपा करें कि मातृ-भाषा की तुहाई देकर हिन्दुस्तानी गढ़ने का क्या अर्थ है, और यह भी बतलाने की कृपा करें कि बिहार पर हिन्दी छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी को लादने का क्या कारण है, और देव-नागरी के साथ किसी दूसरी लिपि को लादने का क्या कारण है ? और यदि उनका हिन्दी को ही रखने का विचार है, तो उसे उसके पुराने और प्रचलित नाम 'हिन्दी' के बजाय 'हिन्दुस्तानी' नाम से क्यों पुकारा जाय ?

मातृ-भाषा के सम्बंध में यह भी ध्यान देने की बात है कि कोई भी भाषा केवल बोलचाल में आने वाले शब्दों से काम नहीं चला सकती। भाषा और

बोली में यही अन्तर होता है। किसी प्रदेश की साहित्यिक भाषा वही कहलाती है जिसमें उस प्रदेश की बोलियाँ अन्तर्निहित होती हैं। इस प्रकार आधुनिक हिन्दी हिन्दी प्रदेश की साहित्यिक भाषा है। यदि वह इसी रूप में अधिक मनुष्यों की मातृ-भाषा नहीं है, तो उर्दू भी इसी रूप में अधिक मनुष्यों की मातृ-भाषा नहीं है, बर्मा की हिन्दुस्तानी भी अधिक मनुष्यों की मातृ-भाषा नहीं है, कोई भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी उसी रूप में अधिक मनुष्यों की मातृ-भाषा नहीं हो सकती, आधुनिक साहित्यिक बँगला भी उसी रूप में अधिक बँगालियों की मातृ-भाषा नहीं है, और आधुनिक साहित्यिक गुजराती, मराठी, तामिल या तेलगू भी उन्हीं लिखित रूपों में अधिक व्यक्तियों की मातृ-भाषायें नहीं हैं (और इन भाषाओं में भी हिन्दी की भाँति ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु उनके अन्य पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं, अर्थात् इन भाषाओं के भी लिखित रूपों और बोलचाल के रूपों में वही अन्तर है जो लिखित हिन्दी और बोलचाल की हिन्दी में है, और जो सर्वत्र लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में होता है), परन्तु इस कारण उन्हें कृत्रिम बताने का या उनमें अरबी फारसी का पुट देने का साहस किसी ने नहीं किया।

हिन्दुस्तानी की बला

अब तक हिन्दी के परिष्कार की, अर्थात् अपने घर की बात कही गई। जब किसी बाहरी शत्रु से मुकाबला करना होता है, तो पहले अपने घर की स्थिति ही ठीक करनी होती है। आज हिन्दी को एक नये शत्रु 'हिन्दुस्तानी' का मुकाबला करना है, इसलिये पहले इसी पर विचार किया गया कि हिन्दी को अन्दर से मजबूत बनाने के लिये हिन्दी में क्या-क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अब यह देखना होगा कि इस शत्रु का क्या स्वरूप है, उसकी क्या चाल है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका क्या अभिप्राय है और उसका दमन किस प्रकार करना चाहिये।

जहाँ तक राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी-वाद के सैद्धान्तिक पहलुओं का सम्बन्ध है, वहाँ तक उनका विवेचन लेखक अपनी पुस्तक 'राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन' में कर चुका है। उस पुस्तक में हिन्दुस्तानी वालों के सब तर्कों का समुचित उत्तर दे दिया गया है, और उनके आन्दोलन की पोल भी खोल दी गई है। परन्तु वह शक्ति का युग है, तर्क का नहीं। जिसकी लाठी, उसकी मेंस। इसी युग-धर्म को पहचान कर हिन्दुस्तानी वाले अपने हिन्दुस्तानी-वाद को तर्क-संगत और न्याय-संगत सिद्ध करने की चिन्ता किये बिना एक ओर अपने विरोधियों—हिन्दी, और हिन्दी साहित्य सम्मेलन—को नेस्तनाबूद करने में व्यस्त हैं और दूसरी ओर येन केन प्रकारेण जनता को भौंसा देकर, उसकी राष्ट्रीय भावना, गांधीजी और कांग्रेस के नाम से लाभ उठाकर शक्ति प्राप्त

करने में संलग्न है। हिन्दी वालों को तनिक विस्तार से बताने की ज़रूरत है।

१. हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप

हिन्दुस्तानी आन्दोलन एकतरफा है। कहने के लिये तो हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी और उर्दू के साथ एक समान व्यवहार करना चाहते हैं, परन्तु सत्य कुछ और ही है। हिन्दी का-और केवल हिन्दी का-अस्तित्व ही मिटाया जा रहा है, उसे भारतीय भाषाओं की सूची में से ही निकाल बाहर किया जा रहा है। निम्नलिखित सत्यों पर गौर कीजिये—

१. कांग्रेस वाले अर्थात् सब हिन्दू अपनी राष्ट्रीयता दर्शाने के लिये 'हिन्दुस्तानी' अर्थात् ज़बरदस्ती उर्दू शब्द मिला-मिला कर—कोई कोई सा शब्द, कोई कोई सा शब्द—बोलें, सब मुसलमान—लीगी या कांग्रेसी या नेशनलिस्ट—फिर भी शुद्ध उर्दू बोलें। विभिन्न प्रान्तों वाले अपनी अपनी प्रान्तीय भाषायें बोलें। 'हिन्दी' कोई नहीं बोलें।

२. आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अपनी सारी कार्रवाई तेलगू में करे, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी मराठी में, पंजाब कांग्रेस कमेटी उर्दू में, युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कमेटी और मध्य-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 'हिन्दु-स्तानी' में। 'हिन्दी' में कार्रवाई कहीं नहीं।

३. विभिन्न प्रान्त अपनी अपनी प्रान्त-भाषा को राज-भाषा बनायें, पंजाब और सीमा-प्रान्त (जो कांग्रेस के ही अधिकार में है) जहाँ की मातृ-भाषा उर्दू नहीं है, उर्दू को राज-भाषा बनायें, हिन्दी प्रान्त अर्थात् युक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त 'हिन्दुस्तानी' (और 'दोनों लिपि') को राज-भाषा बनायें। 'हिन्दी' कहीं की, किसी प्रान्त की राज-भाषा नहीं।

४. 'बुनियादी तालीम' (बेसिक एजुकेशन), 'नई तालीम', आदि वर्धा की शिक्षा-योजनाओं का माध्यम विभिन्न प्रांतों में हो विभिन्न प्रांतीय भाषायें, पंजाब में उर्दू, बिहार और मध्य-प्रान्त (बिद्या-मन्दिर योजना) में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'। 'हिन्दी' माध्यम कहीं नहीं।

५. आसाम, बंगाल, मदरास, उड़ीसा की कांग्रेसी सरकारें अपने अपने प्रान्त में 'हिन्दुस्तानी' (या हिन्दी उर्दू दोनों) और दोनों लिपियों का प्रचार करें और सबके लिये 'हिन्दुस्तानी' (या हिन्दी उर्दू दोनों) और दोनों लिपियों की शिक्षा अनिवार्य करें, पंजाब की संयुक्त कांग्रेसी सरकार और सीमा-प्रान्त की विभुद्ध कांग्रेसी सरकार केवल उर्दू और उर्दू लिपि का प्रचार करें। सिन्ध, दलूचिस्तान और बंगाल की लीगी सरकारें तो केवल उर्दू और उर्दू लिपि का प्रचार करें ही (अर्थात् सारे राष्ट्र की भाषा—वास्तविक राष्ट्र-भाषा—हुई उर्दू, और सारे राष्ट्र की लिपि—वास्तविक राष्ट्र-लिपि—हुई उर्दू लिपि)।

६. कांग्रेसी प्रान्त दोनों लिपियों वाली हिन्दुस्तानी को राष्ट्र-भाषा मानें, लीगी प्रान्त उर्दू को। (किर यह 'हिन्दुस्तानी' न मालूम किस राष्ट्र की 'राष्ट्र-भाषा' है! शैर-पाकिस्तान या 'हिन्दुस्थान' को तो 'हिन्दी' ही राष्ट्र-भाषा रूप में स्वीकार थी और है।)

७. कांग्रेस वाले अर्थात् ६५ प्रतिशत हिन्दू दोनों लिपियों वाली हिन्दुस्तानी को सीखें, लीग वाले अर्थात् ६५ प्रतिशत मुसलमान केवल उर्दू सीखें (किर यह 'हिन्दुस्तानी' न मालूम किस प्रकार हिन्दू-मुसलमानों की 'कामन-भाषा' होगी! सब हिन्दुओं की कामन-भाषा तो हिन्दी ही अधिक सुगमता से हो सकती थी, सब हिन्दुओं को तो हिन्दी ही राष्ट्र-भाषा रूप में स्वीकार थी और है)। बर्मा, दक्षिण भारत हि० प्र० तथा, आदि की हिन्दुस्तानी परीक्षाओं में सौ हिन्दू बैठें और एक मुसलमान। श्री श्रीमन्नानारायण सफाई पेश करते हुये फरमाते हैं कि वे तो हिन्दी वालों और उर्दू वालों पर समान जोर देते हैं, यदि अधिक उर्दू वाले हिन्दी नहीं सीखते तो वे क्या करें? (अवश्य ही वे सब हिन्दुओं को उर्दू सिखाकर उर्दू को डीफैक्टो राष्ट्र-भाषा बना दें! अथवा क्या वे हिन्दुओं को उर्दू पढ़ाकर मुसलमानों का हृदय द्रवित करने की सोच रहे हैं!)

इन सब बातों का एक ही परिणाम होना है। उर्दू की राष्ट्र-भाषा-पद पर प्रतिष्ठा, और हिन्दी का सर्वनाश। हिन्दी वाले यह ही न समझें कि हिन्दी केवल राष्ट्र-भाषा-पद से हटाई जा रही है। हिन्दी अपने घर—युक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य प्रान्त—से भी निकाली जा रही है—वहाँ भी उसे अपना प्राप्य राजभाषा का पद नहीं मिलेगा। हिन्दी वाले राष्ट्र-भाषा का ख़ाब ही देखते रहेंगे और इधर हिन्दी को उसके घर से ही निकाल दिया जायगा। इस प्रकार हिन्दी को बिलकुल समाप्त किया जा रहा है। अधिक से अधिक वह साहित्य की भाषा या कवियों की भाषा और हिन्दुओं की धार्मिक भाषा* होकर रह सकती है। यदि हिन्दुओं को अब हिन्दी जीवित रख मिले, तो वे उसे बस आपस में लिखकर घर में बैठ कर पाठ कर लें। गांधीजी ने स्पष्ट कहा है, “मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि दोनों (अर्थात् हिन्दी और उर्दू) हमारे नाम की (या ‘काम’ की ?) हो जायें।” उर्दू पर बस चलता नहीं, इसलिये केवल हिन्दी को ‘अपने नाम का’ या ‘अपने काम का’ बनाया जा रहा है। राष्ट्रीयता और राष्ट्र-भाषा की इस ‘हिन्दुस्तानी’ वाली नई परिभाषा पर केवल हिन्दी की बलि दी जा रही है। यह कांग्रेस की राजनीतिक ‘अपीजमेन्ट पालिसी’ का भाषा के क्षेत्र में पसराना है। इस राष्ट्रीयता के हिमायती (गांधीजी के इशारे पर आज की कांग्रेस इसी राष्ट्रीयता की हिमायती है) केवल हिन्दी के पीछे हाथ धोकर पड़ गये हैं। उन्हें अब हिन्दी में ‘साम्प्रदायिकता’ की बू आने लगी है। वे अब हिन्दी को एक प्रान्त-भाषा, जनता के एक भाग की भाषा का स्थान भी नहीं देना चाहते। कांग्रेस सब की भाषाओं (और संस्कृतियों) की रक्षा

अब वह भी नहीं। गांधीजी अब वर्धा में हिन्दुओं के विवाह-संस्कार संस्कृत में नहीं, हिन्दी में भी नहीं, अपनी ‘हिन्दुस्तानी’ में सम्पादित करते हैं, और हिन्दुओं के देवताओं की प्रार्थना-वन्दना ‘हिन्दुस्तानी’ में करते हैं। विशुद्ध राष्ट्रवादी उनका अनुकरण कैसे न करें ?

करेगी, और उन्हें उचित स्थान देगी, बस केवल हिंदी को नहीं देगी। (जिस प्रकार कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व करती है, सबके हितों की रक्षा करती है, बस केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, उनके हितों की रक्षा करने के लिये तैयार नहीं।) हिंदी को कांग्रेस अपनी हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्रीयता के रोलर के नीचे पीस डालना चाहती है। यदि कोई अपनी प्रांतीय भाषा (जैसे बंगला, तामिल इत्यादि) में बोले तो कुछ नहीं कहा जायगा; अधिक से अधिक यह कहा जायगा कि उसे राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' सीख लेनी चाहिये। परन्तु यदि कोई हिंदी में बोले तो कहा जायगा कि यह अनुचित है, अराष्ट्रीय है, साम्प्रदायिक है। हिंदीवालों से उम्मीद की जाती है कि वे तो 'हिन्दुस्तानी' में ही बोलें। (उर्दू वालों से 'राष्ट्रवादी' क्या कहें ? वे तो उर्दू में ही बोलेंगे। उन्हें स्वयन् अपने मुँह से अपने को 'साम्प्रदायिक' घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं। उनके लिये तो यह गर्व का विषय है।) वर्षों की संस्थाओं में प्रांतीय भाषाओं का स्थान है, और 'हिन्दुस्तानी' का स्थान है। हिंदी का कोई स्थान नहीं। इसकी देखा देखी सरकार ने भी वैसा ही किया। उसने रेडियो में और इन्फर्मेशन फिल्मों में प्रांतीय भाषाओं को स्थान दिया और 'हिन्दुस्तानी' को। यह बात दूसरी है कि उसने 'हिन्दुस्तानी' को उर्दू से अभिन्न मान लिया (वह करती भी क्या ? हिन्दुस्तानी वालों ने अपनी हिन्दुस्तानी की कोई रूप-रेखा तो सामने रखी नहीं। जिसके जी में जैसी आवे वैसी भाषा हिन्दुस्तानी समझ ले। क्या उर्दू 'हिन्दुस्तानी' नहीं है ?) अब कांग्रेसवाले यह कहने को भी तैयार नहीं हैं कि सरकार को अन्य प्रांतीय भाषाओं की भाँति ही हिन्दी को स्वतन्त्र स्थान देना चाहिये (नई केन्द्रीय असेम्बली के सन् १९४६ वाले बजट अधिवेशन पर नज़र डाल लीजिये। यदि पुलिस ने किसी के दो डंडे अधिक जमा दिये तो कांग्रेसी सदस्यों ने असेम्बली में प्रश्नों की झड़ी लगा दी, परन्तु एक विशाल समाज की भाषा के प्रति सरकारी अन्याय के विरुद्ध उनके मुँह से

एक शब्द नहीं निकला। वह तो 'साम्प्रदायिकता' होती !) उनकी नई राष्ट्रीयता तो यह चाहती ही है कि हिन्दी की सुन्नत हो जाय जिससे 'हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य' स्थापित हो सके*। यदि सरकार ने 'हिन्दुस्तानी' को उर्दू से अभिन्न मान लिया तो उस पर भी कांग्रेसवालों को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि मुसलमान इस 'हिन्दुस्तानी' के साथ तभी तक हैं जब तक 'हिन्दुस्तानी' उर्दू का ही दूसरा नाम है, और जिस दिन 'हिन्दुस्तानी' उर्दू से कुछ भिन्न हुई उस दिन उनका हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानीवाली राष्ट्रीयता का ढको-सला एक घंटा नहीं टिक सकेगा। उन्हें अपना ढकोसला अधिक प्रिय है, इसलिये कुछ नहीं बोलते। मुसलमान तो अति सन्तुष्ट हैं ही—चलो उर्दू की उर्दू रही और 'हिन्दुस्तानी' नाम के प्रताप से हिन्दी की जड़ ही कट गई। हिन्दुस्तानीवाले क्यों बोलें ? उनकी तो मनचीती ही झोरही है न। X

* यह निश्चित है कि केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार भी इस व्यवस्था को नहीं बदलेगी। वह आज की भाँति इन्फर्मेशन फिल्म, न्यूज़ फ़िल्म, आदि का निर्माण भी प्रान्तीय भाषाओं और 'हिन्दुस्तानी' में करेगी, हिन्दी में नहीं। (देखिये उत्तर-परिशिष्ट २)

X यदि कोई हिन्दुस्तानीवालों से पूछे कि हिन्दुस्तानी कहाँ है, तो वे उत्तर देंगे, फिलहाल हिन्दुस्तानी के दो प्रचलित रूप हैं—हिन्दी और उर्दू, परन्तु वे रेडियो से यह कहने को तैयार नहीं कि वे दोनों प्रचलित रूपों में ख़बरें ब्राडकास्ट करे। वे रेडियो से यह कहने का भी कष्ट नहीं करते कि वह हमारी 'हिन्दुस्तानी' में ही ब्राडकास्ट करे। हाँ, कभी कभी यह सोचकर कि कहीं हिन्दीवाले 'हिन्दुस्तानी' से बेतरह न भड़क उठें श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल यह अवश्य कह देते हैं कि रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' उर्दू है। परन्तु क्या वे यह बताने का कष्ट करेंगे कि रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' में ऐसे शब्द कौन से हैं जो उनके 'हिन्दुस्तानी अदब' (श्री श्रीमन्नारायण ने हाल में एक लेख में बताया है कि 'हिन्दुस्तानी' के नमूने रखने के लिये वर्धा में हि. प्र. सभा कुछ 'हिन्दुस्तानी अदब' तैयार करा रही है) में नहीं हैं, अर्थात् रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' प्रयुक्त होनेवाले ऐसे शब्द कौन से हैं जिन्हें वे गैर-हिन्दुस्तानी करार देंगे ?

(जिसकी वे अभी तक केवल कल्पना कर रहे हैं उसे ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष कर दिखाया !)

रेडियो का मामला हमें हिन्दुस्तानी-आन्दोलन के दूसरे पहलु पर ले आता है। वह है इस 'हिन्दुस्तानी' का स्वरूप। आखिर वह 'हिन्दुस्तानी' जो सब जगह से—केन्द्र से और प्रान्तों से—हिन्दी को निकाल रही है और उसका स्थान लेना चाहती है, कैसी होगी ? रेडियो की हिन्दुस्तानी को हम जानते हैं। उसे कांग्रेस और हिन्दुस्तानी वालों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसे सिद्ध करने के लिये हमें यह देखने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस वाले और हिन्दुस्तानी वाले क्या कहते हैं, बरन् यह देखने की जरूरत है कि वे क्या करते हैं। कांग्रेस ने अपने उच्च आसन से क्या किया अथवा क्या करना चाहती है, इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। अन्य हिन्दुस्तानी वालों ने क्या किया है, इसे सुन लीजिये। सम्मेलन द्वारा संचालित आन्दोलन में उन्होंने कभी सहायता तो नहीं दी ही, उन्होंने सम्मेलन के मार्ग में रोड़े अटकाये हैं, और सम्मेलन की माँग को अराष्ट्रीय घोषित किया है। इस सम्बन्ध में पं० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द जैसे हिन्दुस्तानी के दिग्गजों का नाम लेना काफी है। रेडियो वाले इन्हीं हिन्दुस्तानी वालों के बल पर कूद रहे हैं, और इन्हीं का सहारा पाकर अपनी नीति पर दृढ़ हैं। पिछले दिनों सर मुलतान अहमद ने अपनी नीति के समर्थन में गांधी जी का नाम लिया, परन्तु गांधी जी फिर भी चुप रहे। इस सबसे सिवाय इसके कि कांग्रेस और हिन्दुस्तानी वालों को रेडियो की हिन्दुस्तानी मान्य है (ऊपरि मन से ईद बकरीद चाहे जो कुछ कह दिया करते हों) और क्या निष्कर्ष निकल सकता है ? अच्छा, यदि ज़रा

नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्वयम् उनकी हिन्दुस्तानी के कोई सिद्धांत नहीं हैं। (यदि होते तो 'शिक्षा' के स्थान में 'तालीम' और 'साहित्य' के स्थान में 'अदब' कैसे आ बैठता ?) वे रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' को उर्दू तो केवल हिन्दी वालों को फुसलाने के लिये बतलाते हैं।

देर के लिये रेडियो की हिन्दुस्तानी को छोड़ भी दिया जाय, तो क्या हिन्दुस्तानी वालों ने 'हिन्दुस्तानी' के स्वरूप के विषय में कोई सिद्धान्त निश्चित किया है, क्या उन्होंने अपनी नीति स्पष्ट की है ? नहीं। उनकी राय में प्रत्येक हिन्दी शब्द और प्रत्येक उर्दू शब्द 'हिन्दुस्तानी' है, कोई शब्द गैर-हिन्दुस्तानी नहीं, कोई शब्द ऐसा नहीं जो 'हिन्दुस्तानी' में न आ सकता हो। फिर 'हिन्दुस्तानी' क्या है ? कोई व्यक्ति यह तो कह नहीं सकता कि जैसी हिन्दुस्तानी मैं लिखता हूँ वही 'हिन्दुस्तानी' है *। सिद्धांतों की अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति अपनी हिन्दुस्तानी के नमूने में भाषा की सम्पूर्ण शब्दावली को रख भी नहीं सकता जिससे टंटा मिट जाय। परन्तु 'हिन्दुस्तानी' चाहिये अभी ही। सरस्वती कब प्रकट होगी (और होगी भी या नहीं), कब जनता 'हिन्दुस्तानी' का एक सर्वमान्य, निश्चित स्वरूप स्थिर करेगी—यह सब तो भविष्य की बातें हैं, परन्तु 'राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी है', यह नारा लगानेवालों को और अपनी राष्ट्रीयता का ढोल पीटनेवालों को विभिन्न स्थलों पर प्रयुक्त करने के लिये एक 'राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी' चाहिये अभी ही। गांधीजी, मौलाना आज़ाद, पं० नेहरू, पं० गोविन्द वल्लभ पंत, श्रीमोहनलाल सक्सेना, आदि जैसी भी भाषा बोलें, उस सबको 'हिन्दुस्तानी' का नाम तो दे दिया, परन्तु इतने से काम नहीं चलता। सरकारी तौर से प्रयुक्त करने के लिये भी तो एक हिन्दुस्तानी चाहिये। सो इसके लिये हिन्दुस्तानी वालों ने एक अत्यन्त सरल और व्यावहारिक फार्मूला तैयार कर लिया। वह यह कि जहाँ पहले से उर्दू नहीं बैठी हुई

* इस मामले में हिन्दुस्तानी वाले गांधी जी को 'हिन्दुस्तानी' को भी आदर्श नहीं मान सकते। उन्हें गांधी जी का हिन्दुस्तानी-वाद प्रिय है, गांधी जी को 'हिन्दुस्तानी' नहीं। (और गांधी जी की हिन्दुस्तानी भी ऐसी इसलिये है कि उन्हें अभी तक यथेष्ट उर्दू आती ही नहीं। वे उर्दू सीख रहे हैं, अभी उसमें पारंगत नहीं हुये।)

है अर्थात् नये कामों के लिये हिन्दुस्तानी है “उर्दू लिपि में शुद्ध उर्दू और देवनागरी में उर्दू जिसमें यहाँ वहाँ दो चार उर्दू परिभाषिक शब्दों के स्थान में हिन्दी परिभाषिक शब्द रख दिये गये हों”, और जहाँ जहाँ उर्दू पहले से मौजूद है वहाँ के लिये हिन्दुस्तानी है वही भाषा अर्थात् उर्दू जिसका नाम बदल कर हिन्दुस्तानी कर दिया जाय और दोनों लिपियों में लिखने की इजाजत दे दी जाय। पहले प्रकार की हिन्दुस्तानी के नमूने हैं बर्धा की हिन्दुस्तानी (देखिये परिशिष्ट ४), दक्षिण भाग हि० प्र० सभा की हिन्दुस्तानी (देखिये परिशिष्ट ५), बिहार की हिन्दुस्तानी (सुपरिचित महमूद गीडरें, बुनियादी तालीम का माध्यम, आदि), युक्त प्रान्त की हिन्दुस्तानी, आदि। दूसरे प्रकार की हिन्दुस्तानी के नमूने हैं रेडियो और इन्फर्मेशन फिल्मस् की ‘हिन्दुस्तानी’, भारतीय सेना की (रोमन) ‘हिन्दुस्तानी’, केन्द्रीय सरकार की सरकारी ‘हिन्दुस्तानी’, युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा, सरकारी दफ्तरो की भाषा, पुलिस की भाषा, म्यूनिस्-पैलिटियों की भाषा, आदि। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह सोचना व्यर्थ है कि केन्द्र की राष्ट्रीय सरकार रेडियो और इन्फर्मेशन फिल्मन् की ‘हिन्दुस्तानी’ को, जो कभी उर्दू नहीं कहलाई अर्थात् जो जन्म से ही ‘हिन्दुस्तानी’ नाम से

॥ युक्त-प्रान्त की हिन्दुस्तानी के सैकड़ों नमूने देखने का स्वयम् लेखक को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके उत्कृष्ट नमूने युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठकों के विवरण और बुलेटिन और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियाँ हैं। युक्त-प्रान्त के पिछले कांग्रेसी मन्त्रिमंडल के समय में सरकारी विज्ञप्तियाँ ‘हिन्दुस्तानी’ में लिखकर दोनों लिपियों में लीथो करके पत्रों को प्रकाशनार्थ भेज दी जाती थीं। उनकी भाषा २५ प्रतिशत उर्दू अर्थात् उर्दू ही होती थी जिसमें दो चार ऐसे हिन्दी शब्द जो उर्दू लिपि में लिखे जा सकें धर दिये जाते थे। जो हिन्दुस्तानी दोनों लिपियों में लिखी जा सके वह इससे भिन्न हो ही कैसे सकती है। राष्ट्र-भाषा के रथ में देवनागरी और फारसी लिपि जैसे असमान बोड़े जोतने का ऐसा परिणाम होना अवश्यंभावी है।

प्रसिद्ध है, बदल देगी। रेडियो के सर्वेसर्वा श्री ए० एस० बोखारी के सहोदर भ्राता श्री ज़ड० ए० बोखारी ने (जो सेना की 'हिन्दुस्तानी' निर्मित करने के लिये नियुक्त हुये थे) भारतीय सेना की रोमन उर्दू का यथाविधि नामकरण 'रोमन हिन्दुस्तानी' कर दिया है, और अब यही नाम चलता है। यह सोचना केवल दुराशा है कि केन्द्र की राष्ट्रीय सरकार इस 'हिन्दुस्तानी' में या केन्द्र की सरकारी 'हिन्दुस्तानी' में कोई परिवर्तन करेगी। जिन्हें राष्ट्रीय सरकारों से बहुत आशा है, उनका स्वप्न भंग करना आवश्यक है। युक्त-प्रान्त के पिछले कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय में प्रान्तीय असेम्बली के एक सदस्य श्री चरणसिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेसी पार्लामेन्टरी सेक्रेटरी ने फरमाया (७ फरवरी, १९३६), "अदालती भाषा हिन्दुस्तानी है, और सरकार दोनों लिपियों को समान महत्व देगी", अर्थात् कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अदालतों की भाषा में केवल इतना 'सुधार' किया कि उसका नाम जो अभी तक उर्दू था बदलकर 'हिन्दुस्तानी' रख दिया, और गर्व के साथ युक्त-प्रान्त में उर्दू लिपि को अनन्त काल तक देवनागरी के समान महत्व देने की स्पष्ट घोषणा करके अपनी राष्ट्रीयता, निष्पक्षता एवं न्याय-प्रियता का परिचय दिया। इन बातों में एक बड़ी गहरी चाल है। वह यह कि अगर नाम उर्दू रहेगा तो हिन्दी वाले माँग करेंगे कि हिन्दी क्यों नहीं, और इस प्रकार हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्रीयता खटाई में पड़ जायगी, बस चट से नाम 'हिन्दुस्तानी' धर दो, कट गई हिन्दी वालों की माँग की जड़। और भाषा ? उसमें कोई परिवर्तन कैसे किया जा सकता है ? मुसलमान जो रष्ट हो जायेंगे। और, हिन्दुओं में विरोध करने का साहस कहाँ। वे तो राष्ट्रीयता के शिकजे में जकड़े हुये हैं (अगर कुछ कहें तो 'साम्प्रदायिक', 'तंग-खयाल' न घोषित किये जाँय ?)। और फिर हिन्दू तो इस भाषा को अब तक सहन करते ही आ रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक यह मालूम पड़ेगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु मुसलमान तो कहेंगे, 'यह हिन्दू राज है, हिन्दू रिवाज-

बलिष्ठ हैं, आदि। वस, एक हजार साल से गुलामी का बोझा ढोने वाले हिन्दू चुनचाप सहन कर लेते हैं। वे भाषा का महत्व कैसे समझें ? हिन्दुस्तानी वाले तर्क भी बहुत सुन्दर उपस्थित कर देते हैं। एक प्रेम प्रतिनिधि के प्रश्न के उत्तर में पं० सुन्दरलाल ने बताया, “अदालतों की भाषा ऐसी होनी चाहिये जिसे हिन्दू मुसलमान दोनों समझें, परन्तु दोनों लिपियों में काम करने की छूट होनी चाहिये” (क्योंकि अभाग्यवश उन्होंने कोई लिपि तो कामन बनाई नहीं !) । चूँकि अदालतों की भाषा पिछले सौ वर्षों से उर्दू है और इसलिये चूँकि जिन्हें—हिन्दू और मुसलमान—अदालतों से काम पड़ता है वे सब इसी को समझते हैं, पं० सुन्दरलाल के कथन का सीधा अर्थ यह है कि वही भाषा बनी रहे। अदालतों की भाषा के विषय में एक हिन्दी वाले से बातचीत के सिलसिले में पं० गोविन्दवल्लभ पंत ने कहा, “आप ‘अदालत’ रखेंगे, ‘मुकदमा’, ‘वकील’, ‘मुद्दा’, ‘मुद्दालह’ रखेंगे या नहीं ? आपका सिद्धान्त तो ठीक है, परन्तु जब जनता के एक भाग की भावना प्रतिकूल हो तो क्या किया जाय ?” हिन्दीवाले यह आशा त्याग दें कि पंत का मंत्रिमंडल अदालतों, दफ्तरों, पुलिस, म्यूनिसिपैलटी, आदि की भाषा में कोई परिवर्तन करेगा * । कांग्रेसी मंत्रिमंडल लीगी

* पंत जी के राजनीतिक भाषा-शास्त्र का एक और नमूना देखिये। बातचीत के सिलसिले में उनसे कहा गया कि युक्त-प्रान्त में एक भाषा और लिपि को कामन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन प्रांतों में एक से अधिक भाषायें और लिपियाँ हैं वहाँ सब की सब राजभाषा भी नहीं बनाई जा सकती, और प्रांतीय जीवन को एक सूत्र में बाँधने के लिये भी एक कामन भाषा और लिपि की आवश्यकता पड़ेगी ही, और वह प्रांत की मुख्य भाषा और लिपि ही हो सकती है, जैसे हैदराबाद में तेलगू, मराठी, कन्नड़ और तामिल हैं, चारों भाषायें और लिपियाँ राजभाषा नहीं हो सकतीं, और यद्यपि प्रत्येक हैदराबादी को अपनी मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, हैदराबाद की राजभाषा और कामन भाषा वहाँ की मुख्य

मुसलमानों को अप्रसन्न करने का साहस कर भी ले, परन्तु मौलाना आज़ाद, श्री आसफ़अली और श्री रफीअहमद किदवाई से किस प्रकार निबटे ? ये लोग न कहने लगेंगे, “क्यों, क्या यही तुम्हारी असलियत है ?” कांग्रेस में होने का वे इतना लाभ भी न उठावें ? पंजाब, सिन्ध, आदि में जो होता है सो तो ‘लीगी’ मुसलमान करते हैं, कांग्रेस को तो ‘साम्प्रदायिक’ न होना चाहिये। उसे तो ‘नेशनलिस्ट’ मुसलमानों का ध्यान रखना ही चाहिये। वस, यही उर्दू बहाल रहेगी, केवल नाम ‘हिन्दुस्तानी’ धर दिया जायगा जिससे सदा के लिये ‘हिन्दी उर्दू’ का भगड़ा खत्म हो जाय। सब जगह तर्क भी वही पं० सुन्दरलाल या पं० पंत वाले दिये जायेंगे, अर्थात्, “कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ‘बादी’, ‘प्रतिवादी’ समझते हैं, और कितने हिन्दू ऐसे हैं जो ‘मुद्दई’ ‘मुद्दालह’ नहीं समझते ? रेडियो का ऐसा कौन हिन्दू सुनने वाला है जो सुनते सुनते ‘आशार्या’, ‘व्यासी’ और ‘नामानिगार’ नहीं समझने लगा है, और ऐसे मुसलमान सुनने वाले कितने हैं जो ‘दशमलब’, ‘राजनीतिक’ और ‘संवाद-दाता’ समझ लेंगे ? हिन्दी वालों की माँग ‘साम्प्रदायिक’ है, ‘अराष्ट्रीय’ है, फूट डालने वाली है, आदि।” चलो छुड़ी हुई। अब तक विदेशी सरकार ने उर्दू लाद रक्खी थी, किन्तु बड़ी बड़ी आशाएँ थीं कि राष्ट्रीय सरकारें इस अन्याय को दूर कर जनता की हिन्दी को प्रतिष्ठित करेंगी। अब राष्ट्रीय सरकारें ही उर्दू का नाम ‘हिन्दुस्तानी’ धर कर, उस पर ‘राष्ट्रीयता’ की छाप लगा कर उसे जमो रहने देंगी। बोलो ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी’ की जय !

कांग्रेस और हिन्दुस्तानी वालों की सरकारी नीति के अनुकरण पर और लोग भी ऐसा ही करते हैं। सब जगह लोग प्रायः यह प्रस्ताव करते

भाषा तेलगू होगी, और उसकी शिक्षा प्रत्येक हैदराबादी के लिये उसी प्रकार अनिवार्य होनी चाहिये जिस प्रकार ब्रिटिश भारत में अँगरेज़ी की है। मूट से उत्तर मिला, “क्या शुद्ध तेलगू, बिना मराठी, तामिल आदि मिलाये हुये ?”

देखे जाते हैं कि यह काम 'हिन्दुस्तानी' में होना चाहिये, "यह कार्रवाई हिन्दुस्तानी में होनी चाहिये, अँगरेजी में नहीं", आदि। वे ऐसा शायद अपने को राष्ट्रीय घोषित करने के लिये कहते हैं, परन्तु चूँकि यह बतलाने का कष्ट कोई नहीं करता कि उसका 'हिन्दुस्तानी' से किस और कैसी भाषा से अभिप्राय है और चूँकि 'हिन्दुस्तानी' वज़ात-ए-खुद कोई चीज़ नहीं, फल यह होता है कि वह 'हिन्दुस्तानी' उर्दू ही होती है। बहुत बार तो वहाँ पहले से ही उर्दू जमी हुई होती है और इसलिये इस 'हिन्दुस्तानी' का उर्दू होना अनिवार्य हो जाता है। जहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ मुसलमानों को खुश करने के लिये 'हिन्दुस्तानी' को उर्दू मान लिया जाता है, क्योंकि हिन्दुओं के लिये तो वह भाषा अपरिचित होती नहीं। मुसलमान भी इन प्रस्तावों का अनुमोदन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि इन 'हिन्दुस्तानी' का स्वरूप क्या होगा और वास्तव में उनका अनुमोदन है भी तभी तक। रोज़ ख़बरें आती हैं कि युक्त-प्रान्त की अनुक संस्था, अनुक म्यूनिसिपल बोर्ड ने, अनुक स्कूल की कमेटी ने अपने नियम, आदि 'हिन्दुस्तानी' में छापने का निश्चय किया। वह शब्द 'हिन्दुस्तानी' शायद अँगरेजी के विरोध में आता है—यह दिखाने के लिये कि अँगरेजी में नहीं, वरन् 'हिन्दुस्तानी' में, परन्तु यह 'हिन्दुस्तानी' शुद्ध उर्दू होती है। वस, केवल 'हिन्दुस्तानी' नाम धर के हिन्दी की जड़ काट दी जाती है क्योंकि जब 'हिन्दुस्तानी' है तो 'हिन्दी' क्यों? हाँ, छगई देवनागरी लिपि में भी हो जाती है क्योंकि इस पर मुसलमानों को आपत्ति नहीं होती—यदि हिन्दी और हिन्दू प्रांतों की बात हो तो। *

* यदि उर्दू और मुस्लिम प्रान्तों की बात हो, तो मुसलमानों को यह भी सहन नहीं है कि हिन्दुस्तानी उर्फ उर्दू के लिये देवनागरी लिपि भी स्वीकृत हो। अभी हाल में सिन्ध की ज़ीगी सरकार ने राष्ट्रीयता और हिन्दुस्तानी की दुहाई देते हुये सब सिन्धी मुसलमानों के लिये 'हिन्दुस्तानी'

यह है उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप जिसे राष्ट्रीय अथवा विदेशी, सरकारी, अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा हिन्दी-प्रदेश पर बतौर मातृ-भाषा और प्रान्त-भाषा के और सारे देश पर बतौर राष्ट्र-भाषा के लादा जा रहा है। अरबी फारसी का जो रेलाल 'हिन्दी' नाम ने रोक रक्खा था, वह गांधीजी, हिन्दुस्तानी वालों और कांग्रेस द्वारा खोले हुये 'हिन्दुस्तानी' के फाटक में से अर्रा कर हिन्दी संस्कृति और हिन्दी भाषा को गर्क करना चाहता है।

हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार हिन्दुस्तानी आन्दोलन और 'हिन्दुस्तानी' वाली राष्ट्रीयता हिन्दी को राष्ट्रीय और प्रान्तीय जीवन के प्रत्येक विभाग से जड़ सहित निकाल रही है। उसके स्थान में या तो ६० प्रतिशत उर्दू वाली 'हिन्दुस्तानी' है (उदाहरण, बर्धा की हिन्दुस्तानी, बिहार की हिन्दुस्तानी, युक्त-प्रान्त की हिन्दुस्तानी), या हिन्दुस्तानी नामधारी शुद्ध उर्दू है (उदाहरण, रेडियो, इन्फर्मेंशन फिल्मस, आदि की हिन्दुस्तानी)। उर्दू अपनी जगह पर वैसी ही स्थिर है। उसका बाल भी बाँका नहीं हुआ है और न हो सकता है। यह 'कामन भाषा', 'राष्ट्र-भाषा' केवल हिन्दी को चट कर जाना चाहती है। यह है हिन्दुस्तानी आन्दोलन का सच्चा स्वरूप। जो मुसलमान इस आन्दोलन के साथ हैं, वे इसलिये हैं कि उनकी उर्दू

की शिक्षा अनिवार्य कर दी। शीघ्र ही वह सब सिन्धी हिन्दुओं के लिये भी अनिवार्य कर दी जायगी। यह हिन्दुस्तानी कैसी है, यह बताने की ज़रूरत नहीं। परन्तु मझे की बात यह है कि सिन्ध सरकार ने इस हिन्दुस्तानी के लिये केवल उर्दू लिपि उठराई। तर्क दिया, "क्योंकि यही लिपि सिन्धी लिपि से मिलती जुलती होने के कारण सिन्धियों के लिये सबसे सुगम है"। इस पर कांग्रेस वाले, हिन्दुस्तानी वाले सब चुप हैं। वे केवल बिहार में कैथी जाननेवाले बिहारियों के लिये या महाराष्ट्र में देवनागरी जानने वाले मराठियों के लिये हिन्दुस्तानी की लिपि केवल देवनागरी कभी न होने देंगे। वहाँ 'दोनों लिपि' अवश्य ढूँसी जायगी !

को जहाँ होना चाहिये वहाँ तो उर्दू रहेगी ही, वस जहाँ हिन्दी को होना चाहिये वहाँ ही 'हिन्दुस्तानी' होगी जो ६० प्रतिशत उर्दू और कालान्तर में शुद्ध उर्दू होगी, और होगी उनकी उर्दू लिपि। 'हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी की जड़ काटेगी, भारत के कोने कोने में उर्दू और उर्दू लिपि को ले जायगी जहाँ उन्हें एक हजार वर्ष का मुस्लिम शासन भी न ले जा सका, और प्रत्येक हिन्दू को उर्दू लिपि और उर्दू सीखने के लिये चिबरा करेगी। भला ऐसा 'पैकट' उन्हें क्यों न भायेगा? वस, केवल हिन्दुओं के गले के नीचे इस पैकट को उतारना बाकी है। सो 'राष्ट्रीयता' में भली भाँति मान कर उतारा जा रहा है। बेचारे हिन्दू तो कांग्रेस की जेब में हैं। भापा तो भापा है, यदि कल गांधीजी यह कहने लगें कि स्वराज्य-प्राप्ति का सबसे सरल उपाय यह है कि भारत में एक ही धर्म के अनुयायी हों और चूँकि मुसलमान हिन्दू हो नहीं सकते इसलिये सब हिन्दू मुसलमान हो जायँ, तो जैसे आज कांग्रेस वालों को उर्दू पढ़ाने के लिये मौलवी ढूँढ़े नहीं मिलते, कल से हिंदुओं को कलमा पढ़ाने के लिये मुल्लाओं की कमी पड़ जायगी। परन्तु फिर भी क्या स्वराज्य मिल जायगा? मिले या न मिले, गांधी-दर्शन के अनुसार विरोधी के हृदय को पिघलाने का शुद्ध अहिंसात्मक उपाय तो यही है, और भापा के मामले में इसी का हिंदुओं को उपदेश दिया जा रहा है। यदि वे उपदेश मानें तो 'राष्ट्रीय' हैं, यदि न मानें तो उन्हें "स्वराज्य की इच्छा नहीं है।"

॥ श्री श्रीमन्नायण अपने हिन्दुस्तानी-वाद की सफाई यह कह कर देते हैं कि जिस प्रकार हिन्दी पत्रों में 'हिन्दुस्तानी' के विरुद्ध प्रचार हो रहा है, उसी प्रकार उर्दू पत्र 'हिन्दुस्तानी' का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह धोखा है, हिन्दुस्तानी का अर्थ हिन्दी-प्रचार है, (कहाँ कहाँ?) आदि। ठीक है, उर्दू पत्र ऐसा क्यों न कहें? उन्हें इस प्रकार कहते रहने में ही लाभ है। मुसलमानों को अपनी ब्लैकमेल की नीति से किस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ है?

२. हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी

यह तो सबको मालूम ही है कि नियमित हिन्दुस्तानी चक्र-प्रवर्तनम् गांधी जी के फरवरी, १९४५ में वर्षा में हुये 'हिन्दुस्तानी प्रचार कान्फ्रेंस' से हुआ। इस कान्फ्रेंस का कुछ हाल परिशिष्ट ६ से मिल सकता है। इस कान्फ्रेंस में गांधीजी ने यह विश्वास दिलाया कि "हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ कुछ काम न होगा", परन्तु शीघ्र ही स्वयम् गांधीजी ने 'मुखातिब' का श्रीगणेश सम्मेलन से त्याग-पत्र देकर कर दिया। वस, हिन्दुस्तानी वालों को शह मिली, और उन्होंने अपना प्रथम कर्तव्य अपने प्रतिद्वन्द्वी सम्मेलन को धराशायी करना समझ लिया। बड़े बड़े राष्ट्रकर्मों जो अब तक हिन्दी के प्रचारक और समर्थक थे रातों रात कलाबाज़ी खाकर हिन्दुस्तानी के प्रचारक और समर्थक हो गये, और हिन्दुस्तानी के प्रति अपने नये उत्साह में हिन्दी के विरोधी भी हो गये। सबसे पहला हमला दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा पर हुआ जिसकी अगुवानी स्वयम् गांधीजी ने की। जो सभा पिछले २५ वर्षों से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा और देवनागरी को राष्ट्र-लिपि मान कर दक्षिण में हिन्दी और देवनागरी का प्रचार कर रही थी, २४ घंटे के अन्दर अपनी २५ वर्ष पुरानी विचार-धारा त्यागने पर उतारू हो गई। अपनी रजत-जयन्ती के अवसर पर सभा ने अपने नये प्रोग्राम की नियमित घोषणा कर दी। इसी अवसर पर जयन्ती-समारोह के सभापति गांधीजी ने सभा को अपना पुराना नाम बदल कर 'दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' नाम धरने की सलाह दी। (श्रीयुत बरेलवी फूले न समाये होंगे!) हिन्दुस्तानी विचार-धारा के पीछे गांधीजी के अतिरिक्त लगभग आधे दर्जन व्यक्ति और हैं जिन्होंने देश पर हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि लादने की ज़िद पकड़ ली है (इनमें प्रमुख हैं काका कालेलकर, पं० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द)। जहाँ कहीं हिन्दुस्तानी की वकालत करने का मौका होता है, वहाँ ये सज्जन पहुँच जाते हैं और अपने विचारों से उपस्थित जनता को कृतार्थ करते हैं।

अतः सभा की जयन्ती के अवसर पर भी ये सज्जन पहुँचे। खास तौर से पं० सुन्दरलाल और काका कालेलकर ने हिन्दी प्रचारकों के सामने लम्बे चौड़े भाषण दिये जिनमें उन्होंने हिन्दी प्रचारकों को हिन्दी का बाना उतारकर हिन्दुस्तानी का बाना धारण करने का आदेश दिया और गांधी-पुराण के अनुसार उसका माहात्म्य समझाया। अस्तु, हिन्दुस्तानी वालों ने गांधीजी के प्रताप से राष्ट्र-भाषा हिन्दी के एक प्रमुख गढ़ पर येन केन प्रकारेण कब्जा कर लिया*।

दूसरा हमला सम्मेलन द्वारा सञ्चालित महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति पर हुआ। इस हमले का कुछ हाल एक पत्र में मालूम हो जाता है जो 'देशदूत' में छपा था। इस पत्र की नकल परिशिष्ट ८ में दी गई है। इस पत्र के छपने से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा के कार्यालय-मंत्री श्री श्रीनाथ जोशी खीज उठे और उन्होंने एक पत्र में (जो १६-१२-४५ के 'देशदूत' में छपा) सम्मेलन को बुरा भला और 'अराष्ट्रीय' कहा, और महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति को हिन्दू महासमाजवादी घोषित करते हुए अपने को शुद्ध काँग्रेसवादी, राष्ट्रवादी ठहराया। इस पत्र का उत्तर श्रीधर्यप्रकाश ने ३०-१२-४५ के 'देशदूत' में प्रकाशित एक पत्र में दिया जिसकी नकल परिशिष्ट ९ में दी गई है। परन्तु हिन्दुस्तानी वालों के शुद्ध काँग्रेस-वाद और राष्ट्र-वाद की असली पोल ३-२-४६ के 'देशदूत' में प्रकाशित श्रीगंगाधर इंदूरकर के एक लेख से खुली। इस लेख का महत्वपूर्ण अंश परिशिष्ट १० में दिया गया है। इस पोलखाने के बाद कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, परन्तु यह सोचकर कि शायद महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष, सराठी के

* दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की रजत-जयन्ती के अवसर पर केरल (कालीकट) के साप्ताहिक पत्र 'मातृ-भूमि' ने लेखक से एक लेख माँगा था। वह लेख अब भी सभा के कार्य-कर्त्ताओं के लिये लाभदायक हो सकता है, यह सोचकर उसे परिशिष्ट में जोड़ दिया गया है (देखिये परिशिष्ट ७)।

महान् विद्वान् पोतदारजी को मराठी की रत्ना के विषय में और महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों की राष्ट्रीयता की परिभाषा के विषय में कुछ शलतफहमी हुई हो, उनके लाभार्थ ३१-३-४६ के 'देशदूत' में प्रकाशित श्रीसूर्यप्रकाश के एक लेख का कुछ अंश परिशिष्ट ११ में दे दिया गया है। अस्तु, हिन्दुस्तानी वालों ने महाराष्ट्र से सम्मेलन को निकाल बाहर करने में कुछ कसरनहीं उठा रखी है।

अब तीसरे हमले का हाल सुनिये जो लेखक को मालूम हुआ है। अभी हाल में लेखक ने आसाम राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के मंत्री श्रीकमलनारायण से एक पत्र लिखकर आसाम में हिन्दुस्तानी प्रचार का हाल पूछा था। उत्तर में उन्होंने लिखा कि आसाम की जनता हिन्दुस्तानी नहीं चाहती, वह हिन्दुस्तानी का विरोध भी करती है, परन्तु निष्क्रिय रूप से। उसके कुछ समय बाद लेखक ने उन्हें एक पत्र और लिखा। उसके उत्तर में श्रीकमलनारायण का जो पत्र आया (ता० १५-४-४६) वह आँखें खोलनेवाला है। उसका महत्वपूर्ण अंश निम्नलिखित है :

“काका साहब ने श्रीगोपीनाथ बरदले को ही अपना सिपहसालार बनाकर हमारी समिति पर बुरी तरह हिन्दुस्तानी का हमला चलाया। वे राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति को हिन्दुस्तानी के चंगुल में जकड़कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बरदले उनके हाथों में कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मेरे ऊपर राष्ट्रीयता के नाम पर तरह तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं—फुसलाते हैं, धमकी भी देते हैं। काका साहब सरकार के साथ भी साँठ-गाँठ जोड़ चुके हैं। मैं—सिर्फ मैं—अड़ा हूँ, नहीं तो यहाँ कब को लुटिया डूब गई होती। मैंने आज ही पू० आनन्दजी को तार दिया है।..... वे सरकारी ताकत का भय दिखाकर मुझसे हिन्दुस्तानी जैसी बोगस-बाँझ भाषा का समर्थन कराना चाहते हैं। काका कालेलकर के इस अन्याय का मुकाबला हमें करना ही होगा।.....आप लोगों को मदद तो करनी ही है। कहिये किस तरह? मौका आ गया है।”

यह है 'जनता की भाषा हिन्दुस्तानी', 'राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी' की सेवा ! हिन्दुस्तानी वाले गांधीजी के नाम और उनके साथ अपने सम्पर्क से लाभ उठाकर सरकार द्वारा अपनी 'हिन्दुस्तानी' और उर्दू-लिपि अनिच्छुक जनता के ऊपर लादना चाहते हैं—यह सब राष्ट्रीयता की ओट में ! ऊपर ने कहते यह हैं कि हिन्दुस्तानी का स्वरूप तो करोड़ों जनता निश्चित करेगी ! उन्हें यह भी सह्य नहीं कि सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति स्वतंत्रता-पूर्वक अपना काम करती रहे और वे अपना कार्य करें । उन्हें ने साम दाम दण्ड भेद से सम्मेलन के राष्ट्र-भाषा प्रचार के पूरे संगठन को अपनी सुझी में करने का और सम्मेलन के कार्य-कर्त्ताओं को फोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया है । उन्हें भय है कि यदि राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति भी मैदान में रही तो जनता हिन्दुस्तानी को पूछेगी ही नहीं, इसलिये उनका प्रथम ध्येय राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के संगठन को ध्वस्त करना है और इसकी पूर्ति में उन्होंने अपनी समस्त 'राष्ट्रीय' शक्ति लगा दी है । अस्तु, वे इस प्रकार गांधीजी के इस वाक्य का पालन कर रहे हैं कि "सम्मेलन के खिलाफ कुछ काम न होगा ।" कुछ लोग शायद कहेंगे कि स्वयम् गांधीजी को अपने अनुयायियों के ये ढंग पसंद नहीं आयेंगे । परन्तु क्या गांधीजी को अपने अनुयायियों की करतूतों का पता नहीं है ? और फिर क्या स्वयम् गांधीजी ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार बन्द कराके हिन्दुस्तानी प्रचार कराने के लिये सब कुछ नहीं किया, अथवा क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वह उनके सामने नहीं हुआ ? रही सरकारों पर जोर डालने की बात, सो क्या स्वयम् गांधीजी ने कांग्रेसी मंत्रि मण्डलों पर अपने सिद्धान्तों पर चलने के लिये जोर नहीं डाला है ? मद्य-निषेध ही का उदाहरण दिया जा सकता है । अस्तु, काका कालेलकर ने आसाम में जो कुछ किया और करना चाहते हैं, वह हिन्दुस्तानीवालों की नीति का एक प्रमुख अंग है । उनकी नीति में वह भी शामिल है कि यह सब हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में ही किया जाय । काका

कालेलकर आसाम गये और श्रीगोपीनाथ बरदले से मिलकर उन्होंने अपना चक्र चलाने का प्रयत्न किया। सीमा-प्रान्त में भी कांग्रेस सरकार है, परन्तु काका कालेलकर सीमा-प्रान्त जाकर डा० खान साहब के ज़रिये अपनी 'हिन्दुस्तानी' और देवनागरी का प्रचार कराने की बात कभी नहीं सोच सकते। वहाँ उन्हें क्या मिलना है ! व्यवहार-कुशल और चतुर पठान एक भाषा और दो लिपियों के भाँसे में आ ही कैसे सकता है। यह गुण तो केवल हिन्दुओं में है कि राष्ट्रीयता में लपेटकर चाहे विप की गोली दे दो, वे निगल जायेंगे। इसी कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा की शाखायें भी पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिन्ध में नहीं, काशी, प्रयाग, बिहार, मध्य-प्रान्त, महाराष्ट्र और दक्षिण में स्थापित की जा रही हैं, और हिन्दू और हिन्दी प्रान्तों में ही हिन्दुओं के रुपये से हिन्दुओं द्वारा हिन्दुओं को उर्दू और उर्दू लिपि सिखाने का काम जोर शोर से हो रहा है। व्यवहार में हिन्दुस्तानी प्रचार केवल उर्दू और उर्दू लिपि का प्रचार है, क्योंकि जहाँ जहाँ हिन्दुस्तानी का जाल फैलाया जा रहा है वहाँ वहाँ हिन्दी और देवनागरी तो पहले ही से हैं—केवल 'पूरी राष्ट्रीयता' का सार्टीफिकेट लेने के लिये हिन्दी और देवनागरी जाननेवालों को उर्दू और फारसी लिपि सीखने के लिये उकसाया जा रहा है*। जहाँ जहाँ उर्दू और फारसी लिपि पहले से हैं

* नवम्बर, १९४५ में बम्बई में बिड़ला-भवन में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के सदस्यों को आदेश देते हुए गांधीजी ने स्पष्ट कहा, वैसे तो सभा का उद्देश्य हिन्दी और उर्दू दोनों ही का प्रचार करके राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी की स्थापना करना है, परन्तु जहाँ तक बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र, आदि प्रदेशों का सम्बन्ध है, नागरी लिपि का ज्ञान तो वहाँ के लोगों को है ही, इसलिये उन प्रदेशों में उर्दू लिपि के अनिवार्य प्रचार का कार्य ही हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्य-कर्त्ताओं के सामने प्रमुख रूप से आता है। यह है हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का वास्तविक, व्यावहारिक रूप और कार्य-क्रम, और यह है श्री श्रीमन्नारायण के इस कथन का अर्थ कि "गांधीजी का जोर

अर्थात् पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिन्ध, वहाँ हिन्दुस्तानी प्रचार हिन्दी और देवनागरी नहीं ले जा रहा है। वास्तव में गांधीजी का हिन्दुस्तानी प्रचार बंद कर रहा है जो ३०० वर्ष लम्बा मुस्लिम शासन न कर सका और जो आगामी ३०० वर्ष में अंजुमन-तरक्की-उर्दू न कर पाता। यह है हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी।

३. हिन्दुस्तानी वालों के हथकंडे

भोली भाली जनता को बश में करने के लिये और सीधे सादे हिन्दी वालों को फाँसने के लिये हिन्दुस्तानी वालों ने अपने भोले में कुछ सिद्ध बूटियाँ, भुभते हुये चुटकुले और 'राष्ट्रीयता' में सराबोर टटके रख छोड़े हैं जिनका वे वारी वारी से प्रयोग करते हैं। यहाँ उनमें से कुछ का उल्लेख करना बधेष्ट होगा।

(१) सम्मेलन अराष्ट्रीय है।

हिन्दी और उर्दू दोनों पर है, एक पर नहीं" ! गांधीजी ने यह थोड़े ही कहा कि पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिन्ध के लोगों को जिन्हें उर्दू लिपि पहले से ही आती है देवनागरी सिखाना भी हि० प्र० सभा का एक प्रमुख कार्य होना चाहिये। इन पाकिस्तानी प्रान्तों में हि० प्र० सभा को पृष्ठता ही कौन है, और वहाँ पर काम करने के लिये सभा के पास कार्य-कर्त्ता ही कौन से हैं ? अस्तु, वहाँ जो भी हो, बम्बई में हि० प्र० सभा के प्रमुख सदस्य श्री बी० जी० खेर, जो अब बम्बई के प्रधान-मंत्री और शिक्षा-मंत्री हैं, अवश्य गांधीजी के आदेश का पालन करेंगे और बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रत्येक निवासों के लिये उर्दू और उर्दू लिपि का सीखना अनिवार्य कर देंगे। ऐसा ही अन्य हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में होगा। चूँकि उर्दू और मुस्लिम प्रान्तों में ऐसा पहले से ही है, चलिये हो गई उर्दू लिपि समूचे राष्ट्र की लिपि और उर्दू समूचे राष्ट्र की भाषा। हि० प्र० सभा का सोचा हुआ राष्ट्र-भाषा की समस्या का यही तो आदर्श, व्यावहारिक हल है ! ऊपर से तुरी यह है कि अपने हिन्दुस्तानी-वाद की सफ़ाई पेश करते हुये श्री श्रीमन्नारायण कहते हैं कि यदि उर्दू वाले हिन्दी नहीं सीखते या कम सीखते हैं तो यह दूसरी बात है !

इसका जिक्र पहले हो चुका है। कुछ हिन्दुस्तानी वाले साफ साफ ऐसा कहते हैं, और जो साफ साफ कहना नहीं चाहते (जैसे श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल) वे इशारे से कहते हैं। यह घोषणा करके कि हमारा कार्यक्रम ही राष्ट्रीय है, हिन्दुस्तानी वाले अप्रत्यक्ष रूप से भी यह प्रदर्शित करते हैं कि जिनका कार्यक्रम इससे भिन्न है वे अराष्ट्रीय हैं। उनका लक्ष्य सम्मेलन होता है *। यह नारा कि सम्मेलन अराष्ट्रीय है, गांधीजी के भक्त तभी से लगाने लगे हैं जब से गांधी जी ने सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया। उसी दिन से सम्मेलन 'अराष्ट्रीय' हो गया (गांधीजी की बात क्यों नहीं मानी? यह क्या कम अपराध है?), इससे पहले उन्हें सिद्धान्तों के होते हुये वह परम राष्ट्रीय था। यह याद रखना चाहिये कि जब गांधीजी ने सम्मेलन से सहयोग करना आरम्भ किया, तब उन्होंने कहा था, "हिन्दी का काम मेरा अपना काम है। हिन्दी से स्वराज्य-प्राप्ति में सहायता मिलेगी"। वे काफी लम्बी अवधि तक सम्मेलन के सदस्य रहे, अर्थात् तब तक उन्हें सम्मेलन के सिद्धान्त मान्य थे। वे सम्मेलन के सभापति भी हुये। उन्होंने ही इस वाक्यांश को प्रचलित किया, "हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी"। उन्होंने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। परन्तु विचार बदल जाने के कारण गांधीजी के सम्मेलन के त्याग-पत्र देते ही २४ घंटे में सम्मेलन 'अराष्ट्रीय' हो गया! (गांधीजी के भारत के विभाजन और पाकिस्तान के विषय में भी विचार बदले हैं, परन्तु जिनके नहीं बदले हैं वे क्या अराष्ट्रीय हैं?) अस्तु, यहाँ सम्मेलन की राष्ट्रीयता प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिये सम्मेलन के पिछले २५ वर्षों के सफल इतिहास की ओर इङ्कित करना यथेष्ट है। सम्मेलन के कारण हिन्दी का जो प्रचार हुआ है,

ॐ अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू नहीं, जो उर्दू को राष्ट्र-भाषा मानता है। इस अंजुमन का कार्य ही तो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा 'हिन्दुस्तानी' नाम से कर रही है। केवल सम्मेलन को गालियाँ सुनाई जाती हैं।

हिन्दी ने राष्ट्रीय भावना और स्वातन्त्र्य-प्रेम को जागृत करने में जो सहायता दी है और सम्मेलन के राष्ट्र-भाषा प्रचार ने अहिन्दी भाषियों को हिन्दी भाषियों के साथ भाषा के बन्धन में बाँधकर देश में जो ऐक्य स्थापित किया है, वह कहने की नहीं, अनुभव करने की चीज़ है। और सम्मेलन के कार्यक्रम और सिद्धान्तों से देश को कोई हानि तो पहुँची ही नहीं। फिर सम्मेलन अराष्ट्रीय कैसे हो सकता है? देखना यह है कि सम्मेलन को अराष्ट्रीय घोषित करने वाले कितने गहरे में हैं, उनका कार्यक्रम और उनके सिद्धान्त कहाँ तक राष्ट्रीय हैं। जहाँ तक उनके कार्यक्रम का सम्बन्ध है, वहाँ तक उनकी कारगुजारी पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। जो बात सबसे अधिक स्पष्ट है वह यह है कि जिनको खुश करने के लिये हिन्दी छोड़ 'हिन्दुस्तानी' का नारा बुलन्द किया गया है वे, अर्थात् मुसलमान, हिन्दुस्तानी के कार्यक्रम से रत्ती भर प्रभावित नहीं हुये हैं और न हो सकते हैं। हिन्दुस्तानी का प्रचार केवल हिन्दुओं और हिन्दू-प्रान्तों तक सीमित है और रहेगा। सोचने की बात है कि हिन्दुओं और हिन्दी प्रान्तों में तो भाषा-ऐक्य हिन्दी ही स्थापित कर सकती है, कहीं अच्छी तरह और आसानी से स्थापित कर सकती है और सफलता के साथ स्थापित कर ही रही थी। हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने केवल हिन्दुओं में भी फूट डाल दी, और जो कार्य हिन्दी कर रही थी उसमें भी बाधा उपस्थित कर दी। हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केवल इतना ही परिणाम हुआ है। हिन्दुस्तानी आन्दोलन केवल आर्य समाज, नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के करे करारे पर पानी फेर रहा है। यह कैसी 'राष्ट्रीयता' है? हिन्दुस्तानी बालों को चाहिये तो यह था कि वे यह कहते कि जो हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मानकर हिन्दी पढ़ना चाहें वे हिन्दी पढ़ें, और जो उर्दू पढ़ना चाहें वे उर्दू पढ़ें। यह कदम हमें और आगे ले जाता। इसके बजाय उन्होंने हिन्दी उर्दू दोनों और दोनों लिपि अनिवार्य करके उनको भी राष्ट्र-भाषा पढ़ने से रोक दिया जो राष्ट्र-भाषा

हिन्दी पढ़ रहे थे या पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी हिन्दुस्तानी लादने का प्रयत्न केवल महाराष्ट्र, दक्षिण, बंगाल, आसाम ऐसे प्रान्तों में ही किया जिनके निवासियों के लिये सबसे सरल हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है और सबसे सुगम लिपि देवनागरी। यह 'राष्ट्रीयता' की कैसी परिभाषा है? हिन्दुस्तानी वालों को चाहिये तो यह था कि वे परंपरागत हिन्दो का सौष्ठव नष्ट करने का प्रयत्न न करते, और हिन्दी और उर्दू दोनों से काम लेते। इसके बजाय उन्होंने हिन्दी उर्दू में सौदा पटाकर 'हिन्दुस्तानी' गढ़ी जो न हिन्दी वालों को पसन्द है और न उर्दू वालों को, और चूँकि उनका उद्देश्य सुसलमानों को पठाना था, उन्होंने धीरे धीरे हिन्दुस्तानी को उर्दू का ही दूसरा रूप बना दिया और हिन्दी के मूल पर कुठाराघात किया। यह हिन्दुस्तानी वालों के कार्यक्रम की बात हुई। अब उनके सिद्धान्तों को लीजिये। प्राचीन, बहु प्रचलित, स्वदेशी शब्दों को निकाल निकाल कर उनके स्थान में विदेशी शब्द भरना और उन्हें जनता पर लादना कहाँ की राष्ट्रीयता है? जनता में प्रचलित अरबी फारसी शब्द तो हिन्दी ने ले ही लिये हैं। प्राचीन, बहु-प्रचलित, वैज्ञानिक स्वदेशी लिपि के होते हुये उसकी छाती पर एक विदेशी लिपि बैठाना और उसे जनता पर लादना कहाँ की राष्ट्रीयता है? एक निरक्षर देश में जहाँ की ६० प्रतिशत जनता को अपनी मातृ-भाषा का ज्ञान भी नहीं, प्रत्येक के लिये दो राष्ट्र-भाषाओं (हिन्दी और उर्दू) और दो राष्ट्र-लिपियों का ज्ञान अनिवार्य करना कैसी राष्ट्र-सेवा है? इससे तो केवल राष्ट्र-भाषा-प्रचार का कार्य और कठिन हो रहा है, व्यावहारिक कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं और गुत्थियाँ और उलझ रही हैं। यहाँ एक उदाहरण देना असंगत न होगा। अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन के पाँचवे अधिवेशन (फरवरी, १९४६) में एक सम्पादक ने प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन की कार्रवाई 'हिन्दुस्तानी' में होनी चाहिये। सम्मेलन में बहुमत 'राष्ट्रीय' पत्रों के सम्पादकों का ही था, परन्तु प्रस्ताव

गिर गया। इससे अप्रसन्न होकर श्रीगंगाधर इन्दूरकर ने एक लेख लिख नारा, जिसमें उन्होंने अँगरेज़ी पत्रों के सम्पादकों को खूब खरी खोटी सुनाई। यह लेख अनेक हिन्दी पत्रों में छपा। सम्मेलन ने यह प्रस्ताव अस्वीकृत करके अन्ध्रा किया या बुरा, वहाँ इस पर विचार नहीं करना है। देखना यह है कि प्रस्ताव के विरुद्ध जो तर्क दिये गये, उनमें कहाँ तक सार है, और हिन्दुस्तानी-वाद इन तर्कों का उत्तर देने में कहाँ तक समर्थ है। श्रीइन्दूरकर अपने लेख * में लिखते हैं, “हिन्दू सुसज्जमानों के भगड़े की तरह हिन्दी-उर्दू का भगड़ा सामने आया”। ऐसा होना स्वाभाविक था। हिन्दुस्तानी आखिर है किस भाषा का नाम जो हिन्दी उर्दू का भगड़ा न उठे? ‘हिन्दुस्तानी’ इस भगड़े की ही तो साकार नृति है। जहाँ जहाँ हिन्दुस्तानी जायगी, वहाँ इस भगड़े को साथ ले जायगी। जैसा श्रीचन्द्रवल्ली पाँडे ने कहा है, जब तक हिन्दुस्तानी की मोहनी सामने रहेगी, तब तक हिन्दी उर्दू बालों में सम्मिलित हो ही नहीं सकता। दोनों को इस हिन्दुस्तानी से खतरा है, और दोनों ही इसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। क्या इन्दूरकरजी गारंटी कर सकते हैं कि जिस ‘हिन्दुस्तानी’ में उर्दू पत्रों के सम्पादक बोलते उसी में हिन्दी पत्रों के सम्पादक बोलते? औरों की बात जाने दीजिये, क्या हिन्दी-सम्पादक ही उर्दू-सम्पादकों की ‘हिन्दुस्तानी’ और उर्दू-सम्पादक हिन्दी-सम्पादकों की ‘हिन्दुस्तानी’ समझ लेते? एक दूसरे को अँगरेज़ी को तो उन्होंने समझ लिया। सम्मेलन की जो अँगरेज़ी में कार्रवाई अँगरेज़ी पत्रों में छपी, उसकी भाषा तो सब अँगरेज़ी पत्रों में बही थी, और साधारण अँगरेज़ी जानने वाले प्रत्येक पाठक ने उसे किसी भी अँगरेज़ी पत्र में पढ़ लिया और समझ लिया। सम्मेलन की जो ‘हिन्दुस्तानी’ में कार्रवाई ‘हिन्दुस्तानी’ के पत्रों (?) में छपती (या छपी), क्या उसकी भाषा भी सब ‘हिन्दुस्तानी’ के पत्रों में एक सी होती (या थी) और साधारण ‘हिन्दुस्तानी’ जाननेवाला प्रत्येक पाठक उसे किसी

भी 'हिन्दुस्तानी' के पत्र में पढ़ लेता और समझ लेता ? स्पष्ट है कि यदि अँगरेज़ी का सफल विरोध करना है तो उसके बदले में एक ऐसी भारतीय भाषा देनी पड़ेगी जिसका स्वरूप अँगरेज़ी की भाँति काश्मीर से कन्या कुमारी तक और आसाम से सीमा-प्रान्त तक निश्चित और एक हो, और इस भाषा का ऐसा नाम रखना पड़ेगा जिससे भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक एक ही भाषा और उसके एक ही स्वरूप का बोध हो। यह भाषा 'हिन्दुस्तानी' नहीं है और चाहे जो हो।* अब प्रश्न यह होता है कि सम्मेलन में इस 'हिन्दुस्तानी' कार्रवाई का रिकार्ड स्टेनोग्राफर किस लिपि में लेते, और सम्मेलन का अन्य कार्य किस लिपि में होता—देवनागरी में या फारसी लिपि में ? (और क्या फारसी लिपि में सब 'हिन्दुस्तानियों' का लिखना संभव होता ?) इससे क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अँगरेज़ी की अकेली लिपि रोमन की भाँति अँगरेज़ी की जगह लेनेवाली भारतीय भाषा की भी केवल एक लिपि देवनागरी हो ? इन्दूरकरजी अपने लेख में आगे लिखते हैं,

* जितने हिन्दुस्तानीवाले हैं उतने प्रकार की हिन्दुस्तानियाँ हैं और उतने ही प्रकार की हिन्दुस्तानियों की कल्पना है। किसी हिन्दुस्तानीवाले ने कोई सा हिन्दी शब्द बदलकर उर्दू शब्द रख दिया और किसी ने कोई सा। वस्तुतः यदि सम्पूर्ण हिन्दी कोष और सम्पूर्ण उर्दू कोष मिलाकर रख दिया जाय तो वही प्रचलित 'हिन्दुस्तानियों' का कोष कहलाने का दावा कर सकेगा। एक अखिल भारतीय सम्मेलन में ऐसी 'हिन्दुस्तानी' अँगरेज़ी को कैसे निकाल सकती है ?

| जिसमें रोमन की भाँति 'हिन्दुस्तानी' ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के समाचार, आदि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजे जा सकें। अभी तो इस क्षेत्र से रोमन को निकाल कर एक भारतीय लिपि को ही प्रतिष्ठित करना कठिन मालूम होता है। दोनों लिपि कैसे प्रतिष्ठित होंगी ? अथवा क्या हिन्दुस्तानी वाले विदेशी भाषा अँगरेज़ी को तो अपदस्थ करना चाहते हैं किन्तु विदेशी लिपि रोमन को नहीं ?

“देशी नरेशों के प्रश्न की तरह सम्पादक सम्मेलन के कुछ लोग हिन्दुस्तानी नहीं जानते, वह प्रश्न भी सामने लाया गया”। क्या वह बात झूठ थी ? अवश्य ही, क्या सम्मेलन में कोई ऐसा सम्पादक भी था जो अँगरेज़ी न जानता हो ? अँगरेज़ी के भाषण, अँगरेज़ी की कार्रवाई तो सम्मेलन में उपस्थित प्रत्येक सम्पादक ने समझ ली। अब प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय सभाओं और सम्मेलनों में उपस्थित प्रत्येक भारतीय एक भारतीय भाषा समझ सके, वह परिस्थिति हिन्दी उर्दू दोनों और दोनों लिपि अनिवार्य करने से शीघ्रतर उत्पन्न होगी या एक राष्ट्र-भाषा और एक राष्ट्र-लिपि की शिक्षा अनिवार्य करने से ? प्रस्ताव का विरोध ‘नेशनल हेराल्ड’ के सम्पादक श्रीरामा राव ने भी किया। उनके विषय में इंदूरकरजी लिखते हैं, “आपने टूटी फूटी हिन्दुस्तानी में भाषण यह दिखाने के लिये ही किया कि हिन्दुस्तानी गंभीर विचारों का प्रतिपादन नहीं कर सकती। आपने अन्त में यह भी कहा कि मैं हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकता”। इस पर इंदूरकर जी टिप्पणी करते हैं, “मेरी समझ में नहीं आया कि १० साल यू० पी० में रहने के बाद भी श्रीरामा राव हिन्दुस्तानी क्यों न सीख सके ?” ठीक है, यदि कोई यू० पी० में रहने के कारण ही गंभीर विचारों के प्रतिपादन करने योग्य ‘हिन्दुस्तानी’ सीख सकता होता तो यू० पी० में पैदा होने वाले किसी बालक को तो स्कूल में ‘हिन्दुस्तानी’ पढ़ाने की आवश्यकता ही न होती ! जिन १२ करोड़ व्यक्तियों की ‘मातृ-भाषा’ गांधीजी ‘हिन्दुस्तानी’ बताते हैं, उनको भी ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी’ में पारंगत करने के लिये हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को कल ग और अलिफ वे के सिवा और कुछ पढ़ाने का कष्ट न करना पड़ता ! और विलायत का एक अपठ्ठ देहली दिना किसी स्कूल में अँग्रेज़ी पढ़े चर्चिल का भाषण समझ लेता और ऐटली के समान बोलकर पालामेन्ट को मुग्ध कर लेता ! वास्तव में श्रीरामा राव के कथन से श्री इंदूरकर को सोचना तो यह चाहिये था कि एक अहिन्दी

के लिये अकेली हिन्दी ही बोलना और सीखना कितना कठिन है। यू० पी० में दस साल रहने के बाद भी श्रीरामा राव जैसे शिक्षित व्यक्ति केवल उतनी ही हिन्दी सीख सके जितनी उन्होंने यू० पी० के बाज़ारों और गलियों में सुनी, और वह भी टूटी फूटी। अहिन्दियों को राष्ट्र-भाषा के बंधन में बाँधने के लिये और उन्हें राष्ट्र-भाषा सीखने की प्रेरणा देने के लिये उन पर हिन्दी उर्दू दोनों या अपरिचित शब्दों से लदी हुई हिन्दुस्तानी, और दो लिपियाँ जिनमें से एक उनके लिये नितांत अपरिचित है, लादना ज्यादा अच्छा होगा या केवल हिन्दी और देवनागरी ? फिर इंदूरकरजी लिखते हैं, “हिन्दुस्तानी परिपूर्ण भाषा नहीं है, यह तर्क भी उपस्थित किया गया”। इस तर्क में क्या अत्युचित है ? साहित्य और समृद्धि की दृष्टि से अँगरेज़ी का मुकाबला बेचारो हिन्दी भी नहीं कर सकती, हिन्दुस्तानी की जिसके साहित्य की कौन कहे, स्वरूप की भी रूप रेखा तैयार नहीं हुई है, क्या विसात है। अँगरेज़ी को निकालने के लिये अँगरेज़ी के समान समृद्ध भाषा देनी ही पड़ेगी। सोचना यह है कि अँगरेज़ी का मुकाबला थोड़ी बहुत सफलता के साथ ही हिन्दी कर सकती है या ‘न अरबी फारसी न संस्कृत’ वाली ‘हिन्दुस्तानी’ ? इन सब बातों के कारण यदि सम्पादक सम्मेलन के सभापति श्री तुषार कान्ति घोष ने कहा कि प्रस्ताव अव्यावहारिक है, वापस लिया जाय, तो अनुचित तो नहीं कहा। यह कदापि नहीं माना जा सकता कि सम्मेलन में ‘राष्ट्रीयता’ केवल प्रस्तावक और समर्थकों के पल्ले पड़ी थी, और शेष

॥ जब मदरास के पिछले मंत्रि-मंडल ने स्कूलों में ‘हिन्दुस्तानी’ का विषय अनिवार्य किया तब उसी के विरुद्ध मदरासियों ने कठोर सत्याग्रह किया। वह हिन्दुस्तानी वर्धा की वर्तमान हिन्दुस्तानी की अपेक्षा हिन्दी अर्थात् तामिल और तेलगू के अधिक निकट थी। अब यदि वर्धा की हिन्दुस्तानी और दोनों लिपियाँ अनिवार्य की गईं, तो इसका मदरास में और भी तीव्र विरोध होगा, इसमें संदेह नहीं। इस हिन्दुस्तानी-वाद से क्या राष्ट्र का हित होगा ?

‘राष्ट्रीयता’ में कोरे थे। (क्या पं० नेहरू अपना ‘अधिकांश कार्य अँगरेज़ी में नहीं करते, अथवा क्या वे कहने से सब काम ‘हिन्दुस्तानी’ में करने लगेंगे ? पं० नेहरू या ‘हिन्दुस्तानी’ के एक अन्य धनी धोरी डा० राजेन्द्र प्रसाद अपने प्रसारार्थ (ब्राडकास्ट होने वाले) भाषण अँगरेज़ी में सोचकर, अँगरेज़ी में लिखकर पहले उनका अपनी सड़ी सी ‘हिन्दुस्तानी’ में अनुवाद सुनाकर फिर उन्हें अँगरेज़ी में क्यों सुनाते हैं ? जब श्रीलियाकतअलीख़ाँ रेडियो पर वज्र के सम्बन्ध में बोलने गये तब उन्होंने तो डकें की चाँट ‘उर्दू’ में—रेडियो की घोषणा के अनुसार ही—भाषण किया और अँगरेज़ी में अनुवाद सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी।) प्रश्न यह है कि जिन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण प्रस्ताव गिर गया उन्हें हिन्दुस्तानी-वाद बढ़ाता है या घटाता है ? इस प्रश्न का उत्तर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के शब्दों में सुनिये: दोनों लिपि के प्रस्ताव से केवल रोमन लिपि का जयजयकार होने वाला है*। और हिन्दुस्तानी केवल भारत में अँगरेज़ी की जड़ और गहरी करेगी। यही होगा हिन्दुस्तानी वालों के सिद्धान्तों का अन्तिम परिणाम, और यही होगा उनकी ‘राष्ट्रीयता’ की चरम पराकाष्ठा !

श्री इंदूरकर ने अपने लेख के अन्त में प्रश्न किया है, “क्या हम हिन्दी उर्दू तथा हिन्दुस्तानी वालों का भी इसके प्रति कोई कर्तव्य है ?” है—प्रत्येक बात में गांधीजी की अन्ध-भक्ति छोड़कर कभी अपनी अकल से भी काम लेना।

(२) सम्मेलन साम्प्रदायिक है।

क्यों ? क्या इसलिये कि सम्मेलन में अधिकतर हिन्दू हैं ? परन्तु हिन्दुस्तानी की फौज में ही कितने मुसलमान हैं ? अथवा क्या सम्मेलन इसलिये साम्प्रदायिक है कि वह एक ‘साम्प्रदायिक भाषा हिन्दी’ का प्रचार करता है ? परन्तु सम्मेलन तो न हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा मानता है और न उर्दू

को केवल मुसलमानों की। 'हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की', यह प्रचार करके साम्प्रदायिकता तो हिन्दुस्तानी वाले फैला रहे हैं (देखिये परिशिष्ट १२)। वे शायद समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी हिन्दुस्तानी की दीनइलाही के लिये रास्ता साफ हो जायगा। वे अपनी 'हिन्दुस्तानी' को आगे ठेलने के लिये हिन्दी और उर्दू को केवल साम्प्रदायिक भाषाएँ ही घोषित नहीं करते हैं, बरन हिन्दी और उर्दू को एक दूसरे के समकक्ष रख देते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रवादियों के लिये यह फैशन हो गया है कि वे अपनी राष्ट्रीयता और निष्पक्षता प्रदर्शित करने के लिये एक ही साँस में मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा को कोसें, दोनों को एक समान साम्प्रदायिक संस्थाएँ घोषित करें, उसी प्रकार हिन्दुस्तानी वाले अपनी हिन्दुस्तानी के गुणों का बखान करने के लिये संस्कृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी या हिन्दी और फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी या उर्दू को एक ही साँस में कोसते हैं, और दोनों को एक समान साम्प्रदायिक करार देते हैं। जिस प्रकार कांग्रेसी राष्ट्रवादियों को भारत को एक अखण्ड देश और भारतीयों को एक अखंड राष्ट्र माननेवाली हिन्दू महासभा और भारत के टुकड़े टुकड़े चाहनेवाली और भारतीयों को दो राष्ट्र मानने वाली मुस्लिम लीग में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हिन्दुस्तानी वालों को मुसलमानों के आगमन से भी पुरानी अपनी संस्कृत-निष्ठ परंपरा पर आरुढ़ और अन्य भारतीय भाषाओं के समान संस्कृत-निष्ठ हिन्दी में, और जबर्दस्ती स्वदेशी शब्द निकाल निकाल कर अस्वाभाविक रूप से फारसी-निष्ठ की हुई हिन्दी अर्थात् उर्दू में कोई अन्तर नहीं देखता। उनके लिये हिन्दी उर्दू दोनों एक समान दोषी हैं, और निर्दोष है उनकी ६५ प्रतिशत फारसी और ५ प्रतिशत संस्कृत वाली हिन्दुस्तानी (जो विभिन्न राष्ट्रीय प्रकरणों में चल रही है)। उनके लिये यह कहना फैशन हो गया है कि हिन्दुस्तानी वास्तव में पहले एक थी (कैसी थी यह नहीं बताया जाता), और बाद में एक ओर उसे हिंदुओं ने

संस्कृत-निष्ठ और दूसरी ओर मुसलमानों ने फारसी-निष्ठ किया। यदि वे सच्ची बात अर्थात् यह कि संस्कृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी को बाद में बदल कर मुसलमानों ने उसे फारसी-निष्ठ किया, कहने लगे, तो उनकी 'साम्प्रदायिक' ६५ प्रतिशत उर्दू + ५ प्रतिशत हिन्दी=हिन्दुस्तानी का आधार जो नष्ट हो जाय।

हिन्दुस्तानी वालों का साम्प्रदायिकता-प्रचार लिपि के मामले में और भी प्रत्यक्ष है। हम हिन्दी वाले तो चाहते हैं और प्रयत्न करते हैं कि राष्ट्र-भाषा ही नहीं, बरन् सारी भारतीय भाषायें एक ही लिपि देवनागरी में लिखी जायँ (इस प्रयत्न में हमें अहिन्दियों से भी सहयोग मिला है), परन्तु हिन्दुस्तानी वाले राष्ट्र-भाषा की भी दो लिपियाँ रखना चाहते हैं, और 'देवनागरी हिन्दुओं की लिपि है, फारसी लिपि मुसलमानों की', यह नारा लगा कर भारत के कोने कोने में लिपि-साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं, और सब जगह देवनागरी-फारसी लिपि का भगड़ा पैदा कर रहे हैं। वे शायद समझते हैं कि ऐसा करने से उनके 'हिन्दुस्तानी की दो लिपि' वाले सिद्धांत के लिये रास्ता साफ हो जायगा। वे इस सिद्धांत को स्वीकृत कराने के लिये देवनागरी और फारसी लिपि को केवल साम्प्रदायिक लिपियाँ ही घोषित नहीं करते हैं, बरन् देवनागरी और फारसी लिपि को एक दूसरे के समकक्ष रख देते हैं। उन्हें स्वदेशी, पूर्ण और वैज्ञानिक लिपि देवनागरी और विदेशी, अपूर्ण और अवैज्ञानिक फारसी लिपि में कोई अन्तर नहीं दीखता। उनके लिये यह कहना फौशन हो गया है कि हिन्दुस्तानी की दो लिपियाँ हैं, इसलिये दोनों साम्य होनी चाहिये। यदि वे सच्ची बात अर्थात् यह कि हिन्दुस्तानी की लिपि केवल एक देवनागरी थी, और बाद में मुसलमानों ने उसे फारसी लिपि में लिखना शुरू किया, तो उनके दोनों लिपि वाले सिद्धांत का साम्प्रदायिक आधार जो नष्ट हो जाय। आश्चर्य नहीं यदि दोनों लिपि के साम्प्रदायिक नारे के फल-स्वरूप प्रत्येक भारतीय भाषा की दो दो लिपियाँ

हो जायँ—एक हिन्दुओं की और एक मुसलमानों की। इस साम्प्रदायिक कुपरिणाम का कुल उत्तरदायित्व हिन्दुस्तानी वालों पर होगा, 'साम्प्रदायिक' घोषित किये जाने वाले सम्मेलन पर नहीं।

(३) हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज़ हैं।

यदि ऐसा है, तो यह सब हिन्दुस्तानी की हाथ तोबा क्या केवल नाम बदलने के लिये है? वास्तविकता तो यह है कि हिन्दुस्तानी हिन्दी नहीं है, इसीलिये हिन्दुस्तानी की रट लगाई जा रही है। राष्ट्र-भाषा हिन्दी नहीं हो सकती (और राष्ट्र-लिपि देवनागरी नहीं हो सकती), यह प्रदर्शित करने के लिये ही 'राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी है', यह नारा लगाया जा रहा है। 'हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी' को गांधी जी ने अब छोड़ दिया है (देखिये परिशिष्ट १२)। 'जीवन-साहित्य' में एक सम्पादकीय लेख में श्री हरिभाऊ उपाध्याय राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हुये लिखते हैं, "हिन्दी या हिन्दुस्तानी दोनों का एक ही मतलब है। जो माने आज हिन्दुस्तानी के किये जाते हैं वही किसी दिन हिन्दी के किये जाते थे। लेकिन आज अगर हिन्दुस्तानी के नाम में ज्यादा सहूलियत है तो उसे मान लेने में क्या बुराई है?" इस पर श्री भदन्त आनन्द कौसल्यापन ने ठीक ही आलोचना की है, "क्या सचमुच हिन्दी के स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' स्वीकार करना नाम मात्र का ही परिवर्तन है? क्या यह केवल सहूलियत की ही बात है? आपने हिन्दुस्तानी पत्र का जिस ढंग से समर्थन किया है, हमें सन्देह है कि स्वयं महात्मा जी को उस पर आपत्ति न हो"। वास्तव में बात यह है कि जो हिन्दुस्तानी वाले 'हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज़ हैं' का मंत्र पढ़ते हैं, वे या तो हिन्दी वालों की अकल बहुत कम कृतते हैं जो वे यह समझते हैं कि इस प्रकार हिन्दीवाले हिन्दुस्तानी के जाल में फँस जायँगे या वे मुसलमानों की अकल बहुत कम कृतते हैं जो वे यह समझते हैं कि वे हिन्दी का नाम हिन्दुस्तानी रख कर उसे मुसलमानों से राष्ट्र-भाषा के रूप में

मनचा लेंगे। लिपि के मामले में उन्हें यह कहना ज़रा कठिन मालूम देता है कि देवनागरी और फारसी लिपि एक ही चीज़ हैं, इसलिये इन मामलों में दूसरी तरकीब से काम लिया जाता है। श्रीहरिभाऊ उपाध्याय ने ही अपने सम्पादकोप लेख में आगे लिखा है, “लिपि के सवाल ने ज्यादा जोश पैदा किया है। इसमें शक नहीं कि वैज्ञानिकता व गुण-सम्यक्ता की दृष्टि से नागरी लिपि फारसी लिपि से बड़ी चढ़ी है। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब खुद फारसी लिपि के प्रेमी व हामी भी यह मानने व कहने लगें कि इससे तो नागरी बाक़ई श्रेष्ठ है। अतः आज तो युग-धर्म के सत्य को अंगीकार कर लेना चाहिये।” फारसी लिपि के प्रेमियों व हामियों ने पिछले दो सौ साल में तो देवनागरी को श्रेष्ठता को स्वीकारा नहीं (उल्टे देवनागरी के प्रचलित होते हुये फारसी लिपि को प्रचलित किया), अब यह सोचता कि अगले दस बीस बरों में स्वीकार कर लेंगे, अपने आप को धोखा देना है। फिर श्रेष्ठता का सवाल ही कब है, श्रेष्ठता को कौन पढ़ता है? बाक़ई राष्ट्र-भाषा का प्रश्न क्या वैज्ञानिकता और श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से जाँचा जा रहा है? अस्तु, भविष्य में जो कुछ भी हो, उपाध्यायजी ने यह तो बतलाया ही नहीं कि आज ‘उनकी हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी’ फारसी लिपि में लिखी ही कैसे जाय? अतः हम कौसल्यायनजी की टिप्पणी दोहराना यथेष्ट समझते हैं: ‘काश, युग-धर्म का सत्य इतनी सस्ती वस्तु न बनता!’*

*यह ‘युग-धर्म का सत्य’ भी केवल लिपि तक सीमित है। यदि यह कहा जाय कि ‘इसमें शक नहीं कि राष्ट्रीयता व सम्पूर्ण राष्ट्र की सुविधा की दृष्टि से हिन्दी उर्दू से बड़ी चढ़ी है। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब खुद उर्दू के प्रेमी व हामी यह मानने व कहने लगें कि बाक़ई राष्ट्र-भाषा तो हिन्दी ही हो सकती है। अतः आज तो युग-धर्म के सत्य को अंगीकार कर हिन्दी और उर्दू दोनों को राष्ट्र-भाषा मान लेना चाहिये’, तो यह युग-धर्म

अभी हाल में बिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६वें अधिवेशन के अवसर पर राष्ट्र-भाषा के स्वरूप के विषय में भाषण करते हुये बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने कई आति उत्पन्न करने वाली बातें कही हैं। उन्होंने पहले कहा*, “मैं इस बात को मानता हूँ कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्र-भाषा है” (शायद ‘हिन्दी’ से उनका मतलब ‘खड़ी बोली’ से था), और फिर उन्होंने हिन्दी को तीन बर्गों में बाँटा—(१) साहित्य की भाषा, (२) समाचार-पत्रों की भाषा, (३) बोलचाल की भाषा। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों की भाषा उच्च साहित्य की भाषा से भिन्न होती है, और बोलचाल की भाषा एक तीसरे प्रकार की होती है, और अहिन्दी प्रान्तों में इसी तीसरी कोटि की भाषा राष्ट्र-भाषा के रूप में प्रचारित होगी। इस बोलचाल की भाषा को ही वे ‘हिन्दुस्तानी’ नाम से पुकारना चाहते हैं। इस प्रकार बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने घुमा फिरा कर यही कहा कि हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है। परन्तु जिन तीन कोटियों में उन्होंने हिन्दी को विभाजित किया, क्या वे केवल हिन्दी भाषा की विशेषतायें हैं ? बिलायत के बाजारों में जो अँगरेज़ी बोली जाती है उसी में बिलायत के अखबार नहीं छपते, और शेक्सपियर तथा मिल्टन ने उसी अँगरेज़ी में नहीं लिखा जिसमें अँगरेज़ी पत्र छपते हैं, परन्तु क्या इस कारण किसी ने अँगरेज़ी को आधो दर्जन कोटियों में विभाजित किया अथवा क्या उनके भिन्न भिन्न नाम रखे ? अँगरेज़ी बस अँगरेज़ी है। उसी प्रकार हिन्दी बस हिन्दी है और उसे विभिन्न कोटियों में नहीं बाँटा जा सकता, और न किसी कोटि की हिन्दी का ‘हिन्दी’ से भिन्न कोई नाम रक्खा जा सकता है। प्रत्येक भाषा में विषय और पाठकों

का सत्य हिन्दुस्तानी वालों को न दूचेगा। भाषा के मामले में उनका युग-धर्म ‘हिन्दुस्तानी’ की त्रिवेणी खोद कर प्रकट करना है।

* देखिये अप्रैल, १९४६ की ‘राष्ट्र-भाषा’ और अप्रैल, १९४६ की ‘सरस्वती’।

के ज्ञान के अनुरूप शैली बदला ही करती है, परन्तु इस कारण न भाषा का नाम बदलता है और न उसकी शब्दावली। हिन्दी में भी ऐसा ही होता है। जिस प्रकार अँगरेज़ी का 'लिटरेचर' शब्द नहीं बदल जाता, उसी प्रकार हिन्दी में उच्च साहित्य में आने वाला शब्द 'साहित्य' समाचार पत्रों में जाकर 'अदब' नहीं हो जाता। प्रचार के मामले में भी वही बात है। जो अँगरेज़ी अँगरेज़ बच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अँगरेज़ी साहित्य वाली अँगरेज़ी से भिन्न नहीं होती, और जो अँगरेज़ी गैर-अँगरेज़ बच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अँगरेज़ बच्चों को पढ़ाई जानेवाली अँगरेज़ी से भिन्न नहीं होती। जैसी अँगरेज़ी इङ्ग्लैंड की भाषा है वैसी ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्य-भाषा है, और वैसी ही संसार-भाषा है। इसी प्रकार हिन्दी प्रान्तों में पढ़ाई जानेवाली हिन्दी साहित्य की हिन्दी से भिन्न नहीं हो सकती, और अहिन्दी प्रान्तों में प्रचारित की जानेवाली हिन्दी हिन्दी प्रान्तों की हिन्दी से भिन्न नहीं हो सकती, अर्थात् राष्ट्र-भाषा हिन्दी प्रान्त-भाषा हिन्दी या मातृ-भाषा हिन्दी से भिन्न नहीं हो सकती (देखिये परिशिष्ट १२)। और, हिन्दी प्रान्तों की वह बोलचाल की भाषा क्या है, कैसी है, सब जगह एक सी है अथवा नहीं, उसका सबसे अधिक सुलभ स्वरूप क्या है, और वह किस लायक है, इन सब बातों पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। वास्तव में बात यह है कि हिन्दुस्तानी के समर्थक अन्य राजनीतिक नेताओं की भाँति बाबू राजेन्द्रप्रसाद भी राष्ट्र-भाषा की समस्या पर अपने राजनीतिक दृष्टि-कोण को अलग रखकर विचार करने में असमर्थ हैं।*

* बाबू राजेन्द्रप्रसाद की राजनीतिक उलझन के कुछ और नमूने देखिये—
(१) अपने भाषण में पहले उन्होंने कहा, "भाषा के स्वरूप निर्धारण पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भाषा बनाने की चीज़ नहीं है। वस्तु, काल, आदि से प्रभावित होकर वह स्वयं बनती है और स्वयं भू-राष्ट्र-भाषा हो सकती है", और आगे चलकर कहा, "आज इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि बंगाल, पंजाब, मद्रास, आदि देश के विभिन्न

प्रमाण यह भी है कि श्रीहरिभाऊ उपाध्याय ने तो लिपि के मामले का जिक्र भी किया, परन्तु कुशल राजनीतिज्ञ वा० राजेन्द्रप्रसाद ने अपने भाषण में

भागों में समझी जानेवाली एक सरल राष्ट्र-भाषा का निर्माण किया जाय ।' वास्तव में भाषा-निर्माण ही तो हिन्दुस्तानी वालों का पेशा है—भाषा स्वयं बनती है यह तो कभी कभी कहने की बात है । इसीलिये वर्धा की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी, बिहार की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी, आदि हिन्दुस्तानी वालों ने स्वयं स्थापित की हैं, और इसीलिये वे रेडियो की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी में विराज रहे हैं । और चूँकि 'स्वबंभू' राष्ट्र-लिपि नहीं हो सकती, इसलिये बंगाल, पंजाब (?), मद्रास, आदि देश के विभिन्न भागों में सबके गले के नीचे दो लिपियाँ उतारी जा रही हैं ! (२) उन्होंने कहा कि अगर मैं हिन्दुस्तानी का पक्षपाती हूँ तो मेरी हिन्दुस्तानी का स्वरूप कठिन दुरूह उर्दू नहीं और न कठिन संस्कृतमयी हिंदी है । परन्तु क्या विशेषण 'कठिन' हटा देने से उर्दू उर्दू नहीं रहेगी और हिंदी हिंदी नहीं रहेगी और दोनों एक चीज़ 'हिन्दुस्तानी' हो जायँगी, अथवा क्या इस विशेषण के न रहने से उर्दू अक्रारसीमयी और हिंदी असंस्कृतमयी होजायगी ? सीधो सी बात तो यह है कि उनकी हिन्दुस्तानी है हिंदी+उर्दू । (३) "राष्ट्र-भाषा का सुगम होना जरूरी है । दुरूह और

कठिन हिंदी को मैं हिन्दुस्तानी नहीं मानता" । हम तो दुरूह और अनावश्यक रूप से कठिन हिंदी को केवल झराब हिंदी मानते हैं । 'साहित्य' के स्थान में 'अदब' और 'राजनीति' के स्थान में 'स्यासत' धर देने से कठिन और दुरूह हिन्दी सरल राष्ट्र-भाषा थोड़े ही हो जायगी । कठिन और सरल हिंदी के बीच में कहीं रेखा तो नहीं खींची जा सकती, फिर भी क्या जैसी हिंदी वे चाहते हैं, उसे वे हिन्दी के पहले विशेषण 'सरल' लगाकर नहीं पुकार सकते ? 'हिन्दुस्तानी' नाम धरके क्यों आंति और मगड़ा पैदा करते हैं? जो कुछ भी हो, जैसी हिन्दी को वे 'हिन्दुस्तानी' पुकारना चाहते हैं, क्या उसी को सुसज्जमान स्वीकार करने को तैयार हैं ? (४) 'तेलंगू और फ्रांटियर के भाई भी जिसे समझ सकें वही भाषा राष्ट्र-भाषा है । साहित्य सम्मेलन की ओर से इस राष्ट्र-भाषा का जब विरोध होता है तो मुझे बड़ा अक्रसोस होता है" । यदि कोई ऐसी राष्ट्र-भाषा होती तो मगड़ा ही क्यों होता ? मद्रास और

लिपि के प्रश्न को छुआ तक नहीं। राष्ट्र-भाषा के स्वरूप के विषय में उन्होंने जिन सिद्धांतों या गड़बड़भालों का प्रतिपादन किया, उनकी रक्षा राष्ट्र-लिपि के मामले में करना किस प्रकार संभव होता? बकालत का यह एक साधारण नियम है कि जिस जगह पानी मरता हो, उसका जिक्र ही न करो।

शब्दजाल रचना कठिन काम नहीं। जैसी 'हिन्दुस्तानी' वास्तव में, व्यवहार में, चलाई जा रही है, वह कैसी है, इस पर प्रकाश पहले डाला जा चुका है। हिन्दी वालों को 'हिन्दुस्तानी और हिन्दी एक ही चीज़ हैं', इस भाँसा-पट्टी से सावधान रहना चाहिये। (देखिये परिशिष्ट १३)

(४) हिन्दुस्तानी का उद्देश्य हिन्दी को नष्ट करना या उसे विकृत

सीमा-प्रान्त में राष्ट्र-भाषा-प्रचार की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? तेलगू भाई 'अन्तर्राष्ट्रीय', 'साहित्य' और 'कविता' समझते हैं, सरहदी भाई 'बैतुल-अकवामी', 'अदब' और 'नउम' समझते हैं। जिस राष्ट्र-भाषा को दोनों भाई समझ सकें, उसमें इनमें से किन शब्दों को लिया जाय? तेलगू प्रांत में प्रचलित सब संस्कृत शब्दों को और सीमा-प्रांत में प्रचलित उनके सब अरबी-फ़ारसी पर्यायों को राष्ट्र-भाषा में कैसे ले लिया जाय? (यदि ले ही लिया जाय तो वह किस काम की राष्ट्र-भाषा होगी, और उससे ऐसी कौन सी समस्या हल होगी जो वर्तमान हिन्दी और उर्दू से, उनके अलग अलग रहते, हल नहीं हो सकती?) एक न एक भाई को तो नये शब्द सीखने ही पड़ेंगे, क्यों न वे शब्द लिये जायँ जिन्हें सबसे अधिक भाई समझते हैं? ऐसी राष्ट्र-भाषा हिन्दी है और उसी का प्रचार सम्मेलन करता है। सम्मेलन की ओर से ऐसी सर्वाधिक सुलभ राष्ट्र-भाषा का नहीं (जिसका प्रचार वह स्वयं करता है), वरन् वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' का (जिसके बा० राजेन्द्रप्रसाद स्वयं एक जनक हैं) विरोध होता है जो स्वयं भू भाषा नहीं, प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों पर निर्मित राष्ट्र-भाषा नहीं, बस केवल एक पैक्ट की कृत्रिम भाषा है जो अब गढ़ी जा रही है। और सम्मेलन की ओर से विरोध होता है "दोनों लिपि" वाले सिद्धान्त का। क्या 'तेलगू और सीमा-प्रान्त के भाई' दोनों लिपि जानते हैं? यदि नहीं जानते तो दोनों लिपि क्यों, और यदि जानते हैं तो एक ही लिपि से काम क्यों न लिया जाय?

करना नहीं है। वह तो केवल राष्ट्र-भाषा होगी। हिन्दी वाले शुद्ध हिन्दी में लिखने और बोलने के लिये स्वतंत्र होंगे।

‘लोकवाणी’ में एक लेख में (दिसम्बर, १९४५ की ‘हिन्दी’ में उद्धृत) श्रीकाका कालेलकर लिखते हैं, “हम जो राष्ट्र-भाषा का प्रचार करने वाले हैं हमारी भी अपनी अपनी जन्मभाषा यानी स्वभाषा है। उसे शुद्ध रखने का, उसकी परंपरा सँभालने का और उसका साहित्य समृद्ध करने का हम भी प्रयत्न करते रहते हैं। मराठी का ही उदाहरण लीजिये। ब्रिटिश-राज के प्रारम्भ के दिनों में जब मिशनरियों ने मराठी द्वारा अपना धर्म प्रचार करने के लिये उस भाषा में बोलना और लिखना शुरू कर दिया तब उन्होंने मराठी का स्वरूप बहुत कुछ बिगाड़ा। उस समय हम लोगों ने मिशनरियों का ऐसा घोर विरोध किया कि उन्होंने फिर से मराठी का वैसा अपराध करने की हिम्मत नहीं की। गुजराती में भी जब कभी किसी ने गुजराती की शैली बिगाड़ी है तब गुजरात के लोगों ने अपनी भाषा शुद्धि के लिये कुछ न कुछ आवाज़ उठाई है। अतः हम लोग हिन्दी की स्वाभाविक शैली को बिगाड़ने का प्रस्ताव हरगिज़ नहीं करेंगे। हिन्दी साहित्य की जो परंपरा तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूपण, रसखान, रहिमन, आदि लेखकों द्वारा प्रवृत्त हुई है, उसे तोड़ने का प्रयत्न हमसे कभी भी नहीं होगा। भाषा हर एक जाति का आत्मिक धन है। भाषा-शुद्धि का आग्रह चरित्र-शुद्धि के आग्रह के समान ही है।”

विचार तो बहुत ठीक हैं*, परन्तु क्या उनके अनुसार कार्य हो रहा है? क्या वास्तव में ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी’ का आन्दोलन हिन्दी, जो हमारी जन्मभाषा यानी स्वभाषा है, को स्वाभाविक शैली को नहीं बिगाड़

* चलो, काका जी को इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में हिन्दी की शैली को पवित्र और शुद्ध करने के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसके विरुद्ध कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही।

रहा है और नहीं बिगाड़ेगा, अथवा उसके स्वरूप को विकृत नहीं करेगा और उसकी प्राचीन परंपरा को नहीं तोड़ेगा ? क्या 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक विकृत शैली नहीं है, और क्या 'हिन्दुस्तानी' लिखने, बोलने और प्रचार करने का प्रयास मिशनरियों द्वारा विकृत मराठी लिखे और बोले जाने के समान नहीं है ? जैसा घोर विरोध श्री काका कालेलकर के सहभाषियों ने मिशनरियों का किया, क्या हिन्दुस्तानी वालों का वैसा ही घोर विरोध करना हम हिन्दी वालों के लिये उचित नहीं, जिससे उनकी हिन्दी के प्रति ऐसा अपराध करने की फिर हिम्मत न हो ?

मामले के इस पहलू को अच्छी तरह से समझ लेना अति आवश्यक है । हिन्दी वालों के लिये तो आवश्यक है ही, उन हिन्दुस्तानी वालों के लिये भी आवश्यक है जिनके चित्त में वास्तव में यह धारणा जम गई हो कि हिन्दुस्तानी से हिन्दी को हानि नहीं पहुँचेगी, और जो इस प्रकार हिन्दी की ओर से निश्चिन्त हो एक झूठी राष्ट्रीयता का लबादा ओढ़े हुये आन्दोलन के प्रभाव में आकर हिन्दुस्तानी वालों के गिरोह में जा मिले हों । 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्न कोई भाषा नहीं । यदि वह हिन्दी से उसी प्रकार एक भिन्न भाषा होती जिस प्रकार बँगला या मराठी हैं, तो उसके प्रचार से हम हिन्दी वालों को उससे अधिक चिन्ता न होती जितनी बँगला या मराठी या गुजराती या अन्य संस्कृत-निष्ठ भाषा-भाषियों को इस समय है । परन्तु 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक भ्रष्ट शैली है, और वह राजनीतिक और साम्प्रदायिक हेतुओं को सिद्ध करने के लिये और एक झूठे राष्ट्र-धर्म का प्रचार करने के लिये हिन्दी की स्वाभाविक शैली को हो मनमाने तौर से बिगाड़ कर, परिवर्तित और तोड़-मरोड़ कर बनाई जा रही है । वह हिन्दी की 'सगी' दुश्मन है । हिन्दी पर 'हिन्दुस्तानी' का हमला दो प्रकार से हो रहा है, और होगा । एक का उद्देश्य हिन्दी के अस्तित्व को अर्थात् हिन्दी की स्वाभाविक शैली के अस्तित्व को एकदम मिटा

डालना है, और दूसरे का उद्देश्य हिन्दी को धीरे धीरे ज़हर देकर मारना है। पहले पहले हमले को लीजिये। यह पहले बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी को अपने घर से ही निकाल रही है, और किस प्रकार हिन्दी का नाम प्रांतीय भाषाओं की सूची में से ही काटा जा रहा है, और उसका स्थान 'हिन्दुस्तानी' को दिया जा रहा है। यह सब इसी कारण संभव है कि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक शैली है। उदाहरण के लिये, यदि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्न कोई भाषा होती, तो रेडियो के लिये हिन्दी में एक दिन भी समाचार ब्राडकास्ट न करना असम्भव हो जाता—उसी प्रकार जिस प्रकार 'हिन्दुस्तानी' में समाचार ब्राडकास्ट होने पर भी उसके लिये बँगला में समाचार ब्राडकास्ट न करना असम्भव है। अब यह कौन कह सकता है कि हिंदी प्रान्तों में और केन्द्रीय प्रकरणों में हिंदी की स्वाभाविक शैली का अस्तित्व है ? (और यह कौन कह सकता है कि हिंदी वालों को इस 'हिन्दुस्तानी' को सुनने के लिये मजबूर करके हिंदी की स्वाभाविक शैली को नहीं बिगाड़ा जा रहा है—वहाँ पर भी जहाँ उसका अस्तित्व शेष है ?) अपने अपने प्रान्त में अपनी अपनी जन्म भाषा यानी स्वभाषा का बोल बाला है, बेचारे हिंदी वालों के प्रांत में 'राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी' का बोलबाला है। केन्द्र में भी सबकी जन्मभाषायें यानी स्वभाषायें हैं, वस केवल हिंदीवालों की हिंदी नदारद है*। इस हमले की बारीकी को समझ लेना चाहिये। यह हमला फ़िलडाल सब कामकाज में हिंदी को निकाल, 'हिन्दुस्तानी' बैठा कर

* क्या काका काबेलकरजी और उनके साथी हिन्दुस्तानी वाछे हम हिन्दी वालों से मिलकर रेडियो से यह कहने को भी तैयार हैं कि वह 'हिन्दुस्तानी' में जो कुछ ब्राडकास्ट करके हिन्दी की स्वाभाविक शैली को बिगाड़े सो बिगाड़े, परंतु हिन्दी की स्वाभाविक शैली में भी समाचार ब्राडकास्ट करे ? देखें, इसी कसौटी पर काका काबेलकरजी का 'तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूषण, रसखान, रहिमान द्वारा प्रवृत्त हिन्दी की स्वाभाविक शैली और परम्परा' के प्रति प्रेम खरा उत्तरता है या नहीं।

हिंदी को केवल साहित्य अर्थात् कविता की भाषा बना देना चाहता है, ताकि बाद को साहित्य में भी हिंदी धीरे धीरे आप मर जाय, या बोलचाल से, जो सदैव कामकाज की भाषा अर्थात् 'हिंदुस्तानी' से प्रभावित होगी, इतनी दूर होती जाय कि उसे साहित्य में भी कोई न पूछे, और इस प्रकार साहित्य में भी धीरे धीरे 'हिंदुस्तानी' घुस जाय। हिंदी प्रान्तों में असेम्बलियों की भाषा 'हिंदुस्तानी' देने, राजकाज, दफ्तरों, कचहरियों, पुलिस और म्यूनिसिपैलिटियों की भाषा 'हिंदुस्तानी' देने, हिंदी में केवल कवि लोग घर बैठकर कविता करें। सोचना यह है कि इस परिस्थिति में कवि लोग भी कब तक हिंदी में कविता करेंगे? वह जमाना गया जब कवि और साहित्यिक संसार से दूर रहकर अमर साहित्य की रचना किया करते थे, यद्यपि उस जमाने में भी साहित्य की सबसे अधिक उन्नति उसी समय हुई है जब साहित्य की भाषा ही राजभाषा और लोकभाषा थी और साहित्यिक राजद्वार में प्रतिष्ठा और धन पाते थे (उदाहरण—कालिदास का युग)। राज्याश्रय मामूली चीज़ नहीं। आज के आर्थिक युग में राज्याश्रय का महत्व पहले से हजार गुना है। आज के युग में कोई राज्याश्रय-बिहीन भाषा अधिक उन्नति नहीं कर सकती, और रेडियो, सिनेमा, आदि के इस आधुनिक युग में सड़ी से सड़ी भाषा भी राज्याश्रय पाकर संस्कारी से संस्कारी भाषा का जड़ से नाश कर सकती है। इतनीलिये हिंदुस्तानी वाले 'हिंदुस्तानी' के लिये राज्याश्रय प्राप्त करने के लिये इतने उत्सुक हैं। आजकल राज्याश्रय का अर्थ कवियों को आर्थिक सहायता देना नहीं, बरन् भाषा को राजकाज के लिये अपनाना है। यही हिंदुस्तानी वाले कर रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि जिस प्रकार साम्राज्य-भाषा अँगरेज़ी मातृभाषा अँगरेज़ी या इंग्लैंड की भाषा अँगरेज़ी से भिन्न नहीं रह सकती, और अँगरेज़ी साहित्य बिना अँगरेज़ों के सहयोग के जीवित नहीं रह सकता और फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार राष्ट्र-भाषा 'हिंदुस्तानी' भी प्रान्त-भाषा हिंदी से अधिक दिनों तक भिन्न नहीं रहसकती और 'हिंदुस्तानी' साहित्य

बिना हिन्दियों के सहयोग के नहीं फल फूल सकता, इसलिये 'हिन्दुस्तानी' की सफलता के लिये वे उसे प्रथम हिंदी प्रान्तों की राजभाषा बनाना चाहते हैं* । अब कल्पना कीजिये—हिंदी प्रान्तों में राज-व्यवहार में सब तरफ 'हिंदु-

* इसी कारण वे केन्द्र में, जैसे रेडियो में, हिन्दुस्तानी को प्रान्तीय भाषाओं (जिनमें हिन्दी उर्दू भी शामिल हैं) के अतिरिक्त बतौर राष्ट्रभाषा के नहीं बरन् बतौर एक प्रदेश अर्थात् हिंदी प्रांतों की भाषा के प्रयुक्त करना चाहते हैं । रेडियो से अन्य प्रांतीय भाषाओं में खबरें होती हैं, हिंदी और उर्दू में नहीं । उनकी जगह 'हिन्दुस्तानी' है । क्यों ? इसलिये कि अगर आज हिन्दी और उर्दू में भी खबरें होने लगे तो 'हिन्दुस्तानी' की खबरें कौन सुनेगा, उन्हें सुननेवाला कौन रह जायगा ? इसी कारण सर अकबर हैदरी की रेडियो कमेटी में डा० ताराचन्द ने 'हिन्दुस्तानी' के 'Experiment' (प्रयोग) की सफलता के लिये हिन्दी और उर्दू में खबरें न देना आवश्यक करार दिया । वे 'हिन्दुस्तानी' को पहले एक प्रान्तीय भाषा मनवाना चाहते हैं ताकि उसकी जड़ जम जाय । यह बात दूसरी है कि सरकार ने भी लाखों व्यक्तियों द्वारा निश्चित हिन्दी और उर्दू शैलियों का जन्मसिद्ध अधिकार छीनकर डा० ताराचन्द और उनके आशे दर्जन साथियों की अभीष्ट 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित करना उचित समझा, अथवा लाखों व्यक्तियों की माँग से डा० ताराचन्द की माँग को अधिक महत्व दिया । इसमें सरकार का खुद अपना स्वार्थ है । क्या है, यह रेडियो की नीति से परिचित हिन्दीवाले भलीभाँति जानते हैं । केन्द्र में हिन्दुस्तानीवालों की आज चल रही है; हिन्दी प्रान्तों में अब धावा बोला जा रहा है । आज कहा जा रहा है, हिन्दी उर्दू में खबरें और अन्य सरकारी प्रोग्राम ब्राडकास्ट नहीं हो सकते (हाँ, बक़ौल ताराचन्द रेडियो कमेटी के, उनका उद्देश्य 'हिन्दी उर्दू' के साहित्यिक प्रोग्राम जैसे कविता-पाठ, आदि बन्द करना नहीं है— देखिये न ! , कोई केन्द्रीय व्यवहार हिन्दी उर्दू में नहीं हो सकता—केवल 'हिन्दुस्तानी' और प्रान्तीय भाषाओं में होगा; कल कहा जायगा कि युक्त-प्रांत, बिहार, आदि में हिन्दी या हिन्दी उर्दू दोनों को राज-व्यवहार में कोई स्थान नहीं मिल सकता, केवल 'हिन्दुस्तानी' चलेगी, हाँ, हिंदी उर्दू में साहित्य रचना और कविता-पाठ नहीं रोक जायगा ।

स्तानी' चल रही है, ऐसी अवस्था में हिंदी की स्वाभाविक शैली का क्या होगा ? यहाँ इतिहास से कुछ मदद मिल सकती है, यद्यपि आज के युग में राज्याश्रय पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक फ़ारसी राजभाषा रही, तब तक फ़ारसी का बोलबाला रहा—उसी प्रकार जिस प्रकार आज अँगरेज़ी का है, 'पढ़ें' फ़ारसी पढ़ें तेल, वह देखो बिधना के खेल', वह कहावत बनी*, तेल बेंचने से बचनेवालों ने फ़ारसी पढ़ी, संस्कृत और देशी भाषाओं की पूछ न रही, खूब फ़ारसी का प्रचार हुआ और देशी भाषाओं पर फ़ारसी का खूब प्रभाव पड़ा। फ़ारसी का वह बटाटोम क्या हटा ? जब १८३७ में फ़ारसी से राज्याश्रय हटा। फ़ारसी से राज्याश्रय हटाकर जब देशी भाषाओं को राज्याश्रय दिया गया, तब देशी भाषाओं की पूछ शुरू हुई—उससे पहले नहीं। हिन्दी प्रांतों में तुर्की-तुर्क उर्दू और उर्दू लिपि को राज्याश्रय मिला, हिन्दी और देवनागरी की नहीं। उसका जो परिणाम हुआ है, वह इस समय जीवित बहुत से हिंदीवालों ने अपने जीवन में ही अनुभव किया है। खूब उर्दू का प्रचार हुआ, वही शिक्षा-समाज की भाषा समझी जाने लगी, अँगरेज़ों और विदेशियों ने भी उर्दू ही सीखी, विदेशों में उर्दू का ही प्रचार हुआ हिंदी गँवारु हो गई, उर्दू लिपि के कारण खूब शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट हुआ, हिंदुओं ने हिंदी को त्यागा, हिंदी साहित्य को त्यागा, हिंदी साहित्य रचना त्यागा, अपने आचार विचार और देश-भूषा को त्यागा, हिंदू अपनी सम्यता और संस्कृति से दूर होते चले गये, रामायण तक उर्दू में पढ़ने लगे, एक मामूली सा पत्र भी देवनागरी में लिखना भूल गये, और उर्दू का पंडित होने में गर्व का अनुभव करने लगे। यह है राजभाषा और राज्याश्रय का प्रभाव ! उस पीढ़ी के

* उसी परिस्थिति में जिसमें आज अँगरेज़ी पास प्रेजुडेंट को जूतों पर पालिश करते देखकर महान आश्चर्य होता है और हम धारोधार आँसू बहाते हैं, परन्तु एक हिंदी साहित्य-रत्न को भूखों मरते देख कर हमें कुछ आश्चर्य नहीं होता।

हिन्दू अब भी कचहरियों और दफ्तरों में भरे हुये हैं। कुछ अपनी अवस्था का अनुभव कर अब पश्चात्ताप कर रहे हैं और अपने बाप-दादों को कोस रहे हैं, और कुछ हिन्दुस्तानी बालों के मुखिया बन बैठे हैं (कारण स्पष्ट हैं)। वास्तव में उर्दू के पिछले सौ वर्ष लम्बे अखण्ड राज्य में हिन्दी प्रांतों (मुख्यतः युक्त-प्रांत) के हिन्दुओं और हिन्दू-संस्कृति का जो धेर पतन हुआ है, वह कई सौ वर्ष लम्बे मुस्लिम-शासन और फारसी के राज्य में भी नहीं हुआ था। क्यों? इसीलिये कि उर्दू हिन्दी की ही एक विकृत शैली होने के कारण हिन्दी का नाश करने में फारसी की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ थी। जनता को वह इतनी बुराह नहीं मालूम पड़ी जितनी फारसी; उसका विदेशीपन धीरे धीरे भूलने लगा और अन्त में बहुत से उसे ही वास्तविक हिन्दी मानने लगे। आज भी उर्दू को ही वास्तविक हिन्दी या हिन्दुस्तानी मानने वाले मौजूद हैं, और वे ही युक्त-प्रांत में हिन्दुस्तानी बालों के दल का संचालन कर रहे हैं। अच्छा, हिन्दी का उत्थान कब से आरम्भ हुआ? जब से उस पर थोड़ी बहुत राज-कृपा हुई और वह स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। और देवनागरी का प्रचार तब से बढ़ा जब महामना मालवीय जी के उद्योग से राजभाषा उर्दू को पाजामा के साथ साथ धोती भी पहनाने का हुक्म हुआ (उसका भी कितना विरोध हुआ—डा० ताराचन्द और पं० सुन्दरलाल के पूर्वजों की ओर से ही!) फिर भी बीस-पच्चीस वर्ष पहले तक स्कूलों में हिन्दी पढ़नेवाले छात्रों की संख्या उङ्गलियों पर गिनी जा सकती थी। कक्षा में हिन्दी वाले छात्रों की संख्या होती थी पाँच, और उर्दू वाले छात्रों की संख्या होती थी पचास जिनमें से चालीस हिन्दू होते थे और दस मुसलमान। यह सब उर्दू के राज्याश्रय के कारण हुआ। आज भी जो कायस्थ बच्चे स्कूलों में प्रथम भाषा उर्दू पढ़ते देखे जाते हैं, वह केवल उर्दू के राज्याश्रय के ही कारण, क्योंकि वैसे एक हिन्दू बच्चे के लिये हिन्दी के मुकाबले उर्दू में रती-

भर आकर्षण नहीं है। जब तक केवल उर्दू को राज्याश्रय प्राप्त रहेगा, तब तक ऐसा ही रहेगा। अन्त, जो कुछ हिन्दी प्रांतों में उर्दू के राजभाषा होने के कारण पिछले सौ वर्षों में हुआ, विलकुल वही अब राजभाषा हिन्दुस्तानी होने के कारण फिर घटित होगा, और कहीं अधिक द्रुत-गति में घटित होगा। हिन्दी ने इतनी कठिनाइयों के होते हुये भी जो उन्नति की है, उस पर पानी फिर जायगा। अन्तर केवल इतना होगा कि इस बार 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी को पीछे धकेलेगी, और धकेल रही है। जब हिन्दी प्रांतों में चारों ओर, राज-काज में और व्यवहार में, 'हिन्दुस्तानी' का अखण्ड आधिपत्य होगा, तब क्या अधिकाधिक अखबार और पुस्तकें हिन्दी की स्वाभाविक शैली में प्रकाशित होंगी ? ५० वर्ष पहले उर्दू के मुकाबले में ही हिन्दी के कितने अखबार और पुस्तकें प्रकाशित होती थीं ? (और आज राजभाषा अँगरेज़ी, जो नितांत विदेशी भाषा है और जिसके सीखने में कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ता है, के राज्य में अँगरेज़ी के मुकाबले हिन्दी के कितने पत्र और पुस्तकें छपती और विकती हैं ?) क्या ऐसी स्थिति में हिन्दी के कवि और साहित्यिक हिन्दी की स्वाभाविक शैली छोड़कर व्यवहार हिन्दुस्तानी में अपनी रचना करना अधिक लाभदायक न समझेंगे ? (आज भी कितने शिक्षित व्यक्ति राजद्वार में प्रतिष्ठित अँगरेज़ी, जिसे अपेक्षाकृत कम लोग समझते हैं, छोड़ कर देशी भाषा में लिखते हैं ?) जब रेडियो में 'हिन्दुस्तानी' का बोलवाला होगा, तो कौन हिन्दी लेखक अपना भाषण, रूपक या नाटक ब्राडकास्ट करने के लिये हिन्दी की स्वाभाविक शैली में लिखेगा ? (आज ही देख लीजिये, हिन्दीवाले रेडियो में जाकर पैसे के लोभ से उर्दू बूँक आते हैं ।) उस अवस्था में 'हिन्दुस्तानी' के मुकाबले में हिन्दी की स्वाभाविक शैली को कौन पूछेगा ? जब रेडियो, सिनेमा, सरकारी मंत्रियों के भाषण, जजों के

* सन् १८८६ और सन् १८९६ के बीच में ३६१ हिन्दी की और २६९ पुस्तकें उर्दू की प्रकाशित हुई थीं ।

फैसले, सरकारी सूचनायें, इत्यादि 'अदब' सुना सुनाकर उसे प्रचलित कर देंगी, तब हिन्दी की स्वाभाविक शैली में ही क्या 'साहित्य' के स्थान में 'अदब' न आ बैठेगा ? अर्थात् जिस प्रकार राजभाषा उर्दू ने हिन्दी में विदेशी शब्द घुसेड़े, बोलचाल में विदेशी शब्द घुसेड़े (यहाँ तक कि दिल्ली और लखनऊ की शिक्षित वर्ग की बोलचाल ही उर्दू हो गई), और अब राजभाषा अँगरेज़ी एक नितान्त भिन्न भाषा होते हुये हिन्दी में विदेशी शब्द घुसेड़ रही है, बोलचाल में विदेशी शब्द घुसेड़ रही है (यहाँ तक कि शिक्षित वर्ग की बोलचाल ही आधी हिन्दी आधी अँगरेज़ी या इङ्गलिस्तानी हो गई है), क्या उसी प्रकार राजभाषा 'हिन्दुस्तानी' शिष्ट समाज की बोलचाल की भाषा नहीं हो जायगी, और हिन्दी की स्वाभाविक शैली को नहीं ले डूवेगी ? कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी प्रान्तों में राज-व्यवहार की भाषा 'हिन्दुस्तानी' होने पर साहित्य में भी हिन्दी नहीं रह सकती। हिन्दी पर 'हिन्दुस्तानी' के पहले प्रकार के आक्रमण का यही रहस्य है। इस आक्रमण का अन्तिम सर्ग होगा हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम 'हिन्दुस्तानी' बनाना (आरम्भ हो चुका है—देखिये परिशिष्ट १७)। उस सर्ग की समाप्ति पर केवल कुछ शोध-विद्यार्थी प्राचीन हिन्दी साहित्य का संस्कृत साहित्य की भाँति अध्ययन करेंगे। हिन्दी भाषा का विषय ही न रहेगा, और यदि रहेगा भी तो 'हिन्दुस्तानी' भाषा के विषय को, यदि वह अनिवार्य न हुआ तो भी (यद्यपि राष्ट्रभाषा के नाते वह सबके लिये अनिवार्य होगा), प्रथम भाषा के रूप में लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबले में हिन्दी भाषा के विषय को लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या उँगलियों पर गिनने लायक होगी—उसी प्रकार जिस प्रकार बीस-पच्चीस वर्ष पहले तक उर्दू लेने वालों के मुकाबले में हिन्दी लेने वालों की संख्या नगण्य थी। वस, हिन्दी की स्वाभाविक शैली का इतना ही अस्तित्व शेष रहेगा। (और इस स्वाभाविक शैली का स्थान लेने

बालों 'हिन्दुस्तानी' का क्या स्वरूप है और होगा, यह पहले बतलाना ज़ाचुका है)।

हिन्दी पर 'हिन्दुस्तानी' के दूसरे प्रकार का हमला भी साधारण नहीं है। हिन्दुस्तानी की शैली हिन्दी की स्वाभाविक शैली पर अवश्य धीरे धीरे प्रभाव डालेगी और उसे विकृत करेगी। एक भाषा की दो शैलियों (वे परस्पर विरोधी ही क्यों न हों) का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। नितान्त भिन्न भाषाएँ तक परस्पर सम्पर्क में आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं (उदाहरण—फ़ारसी का हिन्दी पर प्रभाव, अँगरेज़ी का सब देशी भाषाओं पर प्रभाव), फिर एक भाषा की दो शैलियों का दो रूपों का कहना ही क्या है। जो 'हिन्दुस्तानी' शैली बघों में, 'नया हिन्द' के सम्पादकीय कलमों में और

असल में 'पुडीटोरियल', 'पुडीटरी' या 'पुडीटरीय' कलम या 'कलम-पुडीटरान' होना चाहिये, क्योंकि 'नया हिन्द' के हिन्दुस्तानी विशेषज्ञों ने 'पुडीटर' शब्द को हिन्दुस्तानी माना है, 'सम्पादक' को नहीं। पाठकों को शायद मालूम न हो, पुण्य-तीर्थ प्रयाग की स्वनामधन्य 'हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी' ने 'हिन्दुस्तानी बोली' और 'दोनों लिखावटों में एक 'माहवारी' 'नया हिन्द' निकालने का निश्चय किया है। 'पुडीटर बोर्ड' के दो माननीय 'मेम्बर' हैं पं० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द्र। 'हिन्दुस्तानी बोली' में लिखी हुई 'हि० कलचर सोसाइटी' के 'संकेतरी' पं० सुन्दरलाल की 'नया हिन्द' विषयक सूचना, जिसे ज्यों का त्यों छापकर हिन्दी पत्रों ने 'हिन्दुस्तानी बोली' के प्रचार का पुण्य कमाया, से अनुमान होता है कि 'हिन्दुस्तानी बोली' से अभिप्राय है उर्दू—उर्दू की शैली, उर्दू के मुहावरे, उर्दू का वाक्य—जिसमें कहीं कहीं उर्दू 'लिखावट' में लिखे जाने योग्य हिन्दी शब्द धर दिये जायँ। नमूना देखिये: "...यह माहवारी हिन्दुस्तान की पूरी आज़ादी का हाज़ी होगा जिसे सुक की सभी पाठियों हासिल करना चाहती हैं। साथ ही हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी के मकसद को सामने रखते हुये यह पाठियों के छोटे छोटे और दो दिन के आपसी मग़हों से अलग रहने की कोशिश करेगा। सुस्थियों का सुलझाना भी इसका काम होगा सिर्फ़ इसलिये कि कुछ बने और

अन्य कारखानों में तैयार की जा रही है, उससे हिन्दी की स्वाभाविक शैली को वैसा ही खतरा है जैसा मिशनरियों की मराठी से मराठी की स्वाभाविक शैली को उत्पन्न होगया था। इसका जिक्र पहले किया जा चुका है। प्रश्न किया जा सकता है कि उर्दू भी तो हिन्दी की एक शैली है, उसके प्रभाव से हिन्दी की स्वाभाविक शैली को बचाने के लिये क्या किया जा रहा है ? ठीक है, हिन्दी पर उर्दू का भी बुरा प्रभाव पड़ा है और आगे और पड़ेगा। हम उससे भी हिन्दी को बचाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। इस पुस्तक का प्रथम भाग इसी दिशा में एक कदम है। हम उर्दू को भी हिन्दी की एक अस्वाभाविक शैली मानते हैं (जो विशिष्ट जनों में प्रचलित है), और हम उसका प्रचार नहीं करते। परन्तु उर्दू और 'हिन्दुस्तानी' में बड़ा भारी अन्तर है। उर्दू शैली अपनी भिन्न लिपि के कारण आगे बढ़ी। यदि हिंदी एक भिन्न लिपि में न लिखी जाती तो भाषा भी भिन्न न होती। परन्तु जहाँ एक भिन्न लिपि ने एक भिन्न शैली को जन्म दिया, वहाँ उसने उस शैली को हिन्दी की स्वाभाविक शैली से पृथक् भी रक्खा। जिन्होंने उर्दू शैली में लिखना चाहा उन्होंने उसे फ़ारसी लिपि में लिखा, यहाँ तक कि फ़ारसी लिपि 'उर्दू लिपि' कहलाने लगी। लिपि ने एक पार्थिव बाधा का काम किया। लिपि के कारण हिन्दी उर्दू के अत्यधिक प्रभाव से बच गई, और रूप ले। जिन बातों में सब जमातों और फ़िर्कों के लोग एक राय हैं उन्हें चमकाने की कोशिश करेगा"। पता नहीं, 'नया हिन्द' की बिसमिल्लाह — 'हिन्दुस्तानी बोली और दोनों लिखावट'—पर ही 'सब जमातों और फ़िर्कों के लोग' एकमत हैं या नहीं, हाँ, प्रयाग में हिन्दुस्तानी वालों का एक लाउड-स्पीकर अवश्य लग गया।

('नया हिन्द' का प्रकाशन आरम्भ हो गया है और उक्त अनुमान की पुष्टि भी होगई है। इसकी 'हिन्दुस्तानी' है उर्दू जिसमें, श्रीभदन्तआनन्द कौसल्या-यन के शब्दों में, "बीच बीच में कुछ हिन्दी वाक्य हैं जो देवनागरी में शुद्ध और उर्दू लिपि में शुद्ध नहीं लिखे जा सके हैं" ।)

उसने अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रक्खा। किन्तु यह 'हिन्दुस्तानी' तो उसी लिपि में अथवा उस लिपि में भी लिखी जायगी जिसमें हिन्दी लिखी जाती है। फिर हिन्दी की स्वाभाविक शैली 'हिन्दुस्तानी' से भिन्न कैसे रह सकती है? आज भी एक साधारण व्यक्ति 'उर्दू लिपि' में लिखा हुआ देखकर कहता है, 'उर्दू में है,' और 'हिन्दी लिपि' में लिखा हुआ देखकर कहता है, 'हिन्दी में है' (जिस प्रकार रोमन लिपि में लिखा हुआ देखकर—जैसे स्टेशनों के नाम—कहता है 'अँगरेज़ी में है')। जब 'हिन्दुस्तानी' भी देवनागरी में लिखी मिलेगी तो वह भी 'हिन्दी' कहलायेगी और इस प्रकार 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की स्वाभाविक शैली को राक कर देगी। 'हिन्दुस्तानी' देवनागरी में प्रकट होकर हिन्दी की स्वाभाविक शैली को दिखाइ रही है। उर्दू और हिन्दुस्तानी दोनों ही हिन्दी की दुश्मन हैं—अन्तर केवल यह है कि उर्दू बाहर से हिन्दी के अधिकारों पर हाथ साज करना चाहती है और वर्तमान सरकार अर्थात् ब्रिटिश सरकार उसकी मदद पर है, परन्तु 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी को अन्तर से नष्ट करना चाहती है और भावी सरकार अर्थात् कांग्रेस सरकार 'राष्ट्रीयता' का लेविल चिपकाये उसकी मदद पर है। पाठक स्वयं निर्णय कर लें कि दोनों में से कौन अधिक घातक है। उर्दू के प्रभाव को हम आज रो रहे हैं, परन्तु 'हिन्दुस्तानी' के हमले के सफल होने पर कोई रोने वाला ही न रहेगा।

कहा जायगा कि 'हिन्दुस्तानी' उर्दू लिपि में प्रकट होकर उर्दू पर भी तो चोट करेगी। शायद, परन्तु यह कोई तर्क नहीं हुआ कि हम आपको इसलिये मारना चाहते हैं कि हम किसी दूसरे को भी मार रहे हैं। हमें उर्दू ने मतलब? हम उर्दू पर मोहित नहीं; एक अस्वाभाविक शैली उर्दू के स्थान पर एक ज़रा उन्नित अस्वाभाविक शैली 'हिन्दुस्तानी' का आ जाना (क्योंकि उर्दू लिपि तो हिन्दुस्तानी की एक लिपि बन कर बैसी की बैसी रहेगी ही) हमारे लिये कोई दिलचस्पी नहीं रखता। परन्तु यथार्थ तो यह है कि यह कहना बिल्कुल

शलत है कि 'हिन्दुस्तानी' से उर्दू की भी वही हानि होगी जो हिन्दी की। यह पहले कहा जा चुका है कि राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी को खा जाना चाहती है। उर्दू 'हिन्दुस्तानी' के दोनों प्रकार के हमलों से इसलिये सुरक्षित है कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो पंजाब, सीमा-प्रान्त, आदि उर्दू प्रान्तों में उर्दू के स्थान में 'हिन्दुस्तानी' (और दोनों लिपि) को राजभाषा बनवा सके, और दूसरे प्रकार के हमले से उर्दू अपनी लिपि के कारण सुरक्षित है क्योंकि उर्दू-लिपि में हिन्दी के अधिकांश संस्कृत शब्द लिखे ही नहीं जा सकते। यह पहले बतलाया जा चुका है कि जो 'हिन्दुस्तानी' उर्दू लिपि में प्रकट होती है, वह शुद्ध उर्दू से भिन्न नहीं होती। इसका कारण बहुत हद तक उर्दू लिपि है। उर्दू से कुछ भिन्न हिन्दुस्तानी केवल देवनागरी में प्रकट होती है, क्योंकि उसी में प्रकट हो सकती है। उर्दू वाले एक तो वैसे ही हिन्दी नहीं जानते और न जानने की पर्वाह करते हैं (वरन् उससे घृणा करते हैं), दूसरे उनकी लिपि की अपूर्णता एवं अवैज्ञानिकता हिन्दी के विरुद्ध एक अतिरिक्त किले का काम करती है। हिन्दी के साहित्यिक ही उर्दू सीखते हैं और वे ही 'हिन्दुस्तानी' की धुन में हिन्दी में उर्दू शब्द भरकर हिन्दी को विकृत कर सकते हैं। अतः सब प्रकार से 'हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी की दुश्मन है। इसका प्रमाण दिया जा सकता है। 'हिन्दुस्तानी' के प्रभाव से केवल हिन्दी उर्दू शब्दों से लदती जा रही है, जब कि उर्दू पहले की भाँति विशुद्ध है। 'हिन्दुस्तानी' ने हिन्दी के साहित्यिक ही हिन्दी से छीने हैं, उर्दू के नहीं (आज 'हिन्दुस्तानी' लिखने वालों में कितने उर्दू लेखक दिखाई देते हैं ? और जो दिखाई देते हैं उनकी हिन्दुस्तानी क्या उर्दू से भिन्न है ?), हिन्दी के साहित्यिकों पर ही हिन्दुस्तानी वाले दबाव डाल रहे हैं। सम्मेलन त्याग कर कितने ही हिन्दी वाले 'हिन्दुस्तानी' की सेना में भरती हो गये, परन्तु अंजुमन-तरक़ी-उर्दू से किसी ने त्याग-पत्र नहीं दिया। हिन्दी प्रचारकों को ही पकड़-पकड़ कर 'हिन्दुस्तानी' की

दीक्षा दी जा रही है। एक हिन्दी पत्र 'विश्ववार्ता' ने ही अपनी भाषा हिन्दी बदल कर डंके की चोट 'हिन्दुस्तानी' कर दी। इत्यादि, इत्यादि।

“‘हिन्दुस्तानी’ का उद्देश्य हिन्दी की शैली को नष्ट करना या विकृत करना नहीं है,” यह हिन्दी वालों को मोह-निद्रा में सुलाने के लिये एक अफीम की गोली है, अथवा यों कहिये, पीछे से हिन्दी का शिकार खेलने के लिये एक धोखे की टट्टी है। इस टट्टी को खड़ा करने वाले हिन्दुस्तानी के सेना-नायक हिन्दी पर 'फ्रांटल अटैक' न करके (या इतना साहस न होने के कारण) उसे 'फ्लैंक मूवमेन्ट' द्वारा घेरना चाहते हैं।*

४. क्या करें ?

हिन्दुस्तानी की दला का स्वरूप भली भाँति देख लिया। हिन्दी वालों को इस दला का अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना ही है। परन्तु किस प्रकार ? यह दला साधारण नहीं है। इसने अपने पीछे राष्ट्रीय आन्दोलन की समस्त शक्ति को लगा लिया है; इसलिये बिना किसी संगठन और योजना के 'हिन्दुस्तानी' का विरोध करना केवल शक्ति का अपव्यय सिद्ध होगा। शत्रु जितना अधिक बलशाली हो, उतनी ही अधिक अपनी शक्ति को संगठित और केन्द्रित करने की आवश्यकता होती है। इस समय ज़रूरत इस बात की है कि सब हिन्दी-प्रेमी एकत्र होकर समस्या पर गहरा विचार करें, और 'हिन्दुस्तानी' का मुकाबला करने के लिये संगठित रूप से उचित कदम उठावें। ये कदम क्या होने चाहिये, इस विषय में लेखक अपने विचार अन्यत्र प्रकट कर चुका है। यहाँ केवल कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करना यथेष्ट होगा।

*श्री श्रीमन्नारायण का यह कथन कि हिन्दी उट्टू वाले अपनी-अपनी भाषा को चाहे जैसा रक्खें पर उन्हें हिन्दुस्तानी रूपी एक मिली जुली शैली का विरोध करने की आवश्यकता नहीं, भी इसी कोटि का है और उसका भी यही उत्तर है।

किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिये पहले एक 'बेस' (base) की, या कहिये एक किले की, आवश्यकता होती है। हिन्दी को भी हिन्दुस्तानी का मुकाबला करने के लिये एक गढ़ की ज़रूरत है। यह गढ़ हिन्दी का अपना घर ही हो सकता है। हिन्दी को पहले अपने घर पर पूर्ण रूप से अधिकार करना चाहिये। यदि हिन्दी अपने घर में ही अपने पैर न जमा सकी, तो किसी बाहरी शत्रु का मुकाबला कैसे करेगी? हिन्दी का घर मध्य-देश है जिसमें युक्त-प्रान्त, मध्य-प्रान्त, बिहार और राजस्थान स्थित हैं। हिन्दी के साम्राज्य की यही राजधानी है, यहीं से हिन्दी के कार्य का संचालन हो सकता है। साम्राज्य की सीमाओं पर कुछ भी हो जाय, जब तक राजधानी सुरक्षित है तब तक आशा है। यदि हिन्दी अपनी राजधानी में से ही निकाल दी गई, तो समझ लीजिये इस संसार से हिन्दी उठ गई। जैसा पहले बतलाया जा चुका है, हिन्दी को अपने घर में ही अपदस्थ करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। हिन्दी को पहले इस प्रयत्न को विफल करना होगा, हिन्दुस्तानी की परछाई तक को अपने घर से दूर भगाना होगा। पहले हिन्दी का अपने घर में अखण्ड राज्य स्थापित होना चाहिये। यह कार्य भी साधारण नहीं रह गया, और जितनी देर की जायगी उतना ही कठिनतर होता जायगा। एक पल भी देर करने का समय नहीं है। सबसे पहले हिन्दी को हिन्दी प्रान्तों में राजभाषा अर्थात् असेम्बली की, दफ्तरों, कचहरियों, पुलिस, म्युनिसिपैल्टी, आदि की भाषा बनाना होगा—व्यवहार में और कानून में। हम कानून में 'हिन्दुस्तानी' शब्द तक नहीं रहने दे सकते। यह सब करना हमारे हाथ में है, और हमें करना ही होगा। हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी के लिये राज्याश्रय प्राप्त करना ही होगा। कुछ हिन्दी-प्रेमी कहते हुये सुने जाते हैं कि हिन्दी बिना राज्याश्रय के आगे बढ़ी है और उसे राज्याश्रय की आवश्यकता नहीं, परन्तु शायद इससे बढ़कर कोई दूसरी मूर्खता की और हिन्दी के हित में घातक बात नहीं हो सकती। क्या हम उस उन्नति से

संतुष्ट हैं जो आज तक हिन्दी ने की है ? क्या उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि वह बिना राज्याश्रय के फल फूल सके ? जैसा पहले बतलाया जा चुका है, राज्याश्रय साधारण बात नहीं। अब तक हिन्दी ने जो उन्नति की है वह भी बहुत कुछ राज-कृपा के ही कारण। आज राज्याश्रय पर ही दारो-न्दार है। बिना राज्याश्रय के हिन्दी निट जायगी, उसका विकास बिलकुल रुक जायगा। आजकल भरपूर राज्याश्रय न होने लगे भी हिन्दी राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण बढ़ी, परन्तु जब राष्ट्रीय सरकार स्थापित होने पर भी हिन्दी को राज्याश्रय न मिलेगा, तब हिन्दी को किसका सहारा रह जायगा ? जिस शक्ति ने आज तक हिन्दी को आगे बढ़ाया, जब वही राज-काज में हिन्दी के स्थान में हिन्दुस्तानी की प्रतिष्ठा करेगी, तब हिन्दी कैसे जीवित रह सकेगी ? और वह स्वराज्य ही किस काम का, जिसमें स्वभाषा का स्वदेश में राज्य न हुआ ? हमें अपने घर में हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना ही होगा। हमें हिन्दी प्रान्तों की सरकारों से, चाहे वे राष्ट्रीय सरकारें क्यों न हों, साफ साफ कहना चाहिये कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा है अथवा नहीं, वह प्रान्त-भाषा अवश्य है, और उसे अपने प्रान्तों में राजभाषा के पद से

और तो और, जब तक हिन्दी राजभाषा न होगी तब तक शिक्षित वर्ग की बोलचाल की भाषा का ही सुधार न हो सकेगा, और उसमें से राजभाषा अंगरेज़ी के जरिये घुसे-हुये अंगरेज़ी शब्द और राजभाषा उर्दू के जरिये घुसे-हुये अरबी फ़ारसी के शब्द बढ़ाए न निकल सकेंगे। फिर जो हिन्दुस्तानी प्रतिष्ठित की जायगी उसमें इसी 'बोलचाल' के नाम पर यही उर्दू शब्द धरे जायेंगे और यही भाषा जनता पर लदती चली जायगी। यह कोई न पड़ेगा कि जनता के लिये सुगम शब्द कौन से हैं। अर्थात् यही उर्दू सबकी बोलचाल की भाषा होती चली जायगी। जैसा पहले कहा जा चुका है, 'हिन्दुस्तानी' नाम रहते राजभाषा उर्दू का कचहरियों, दफ़्तरों, आदि में प्रचलित कोई शब्द नहीं बदला जा सकता, और किसी भी उर्दू शब्द के स्थान में हिन्दी का नया शब्द नहीं रक्खा जा सकता।

वंचित नहीं किया जा सकता। जब तक हिन्दी-प्रान्तों में अधिकांश जनता कौ भाषा हिन्दी है, तब तक राज-व्यवहार में उसका स्थान किसी दूसरी भाषा या शैली को नहीं दिया जा सकता। किसी सरकार को एक नई भाषा या शैली गढ़कर जनता पर लादने का अधिकार नहीं, और न वह एक नई लिपि लाद सकती है। आगे चलकर जनता हिन्दी शैली को चाहे बिगाड़े चाहे बनावे, उसमें चाहे जो परिवर्तन करे, परन्तु इस समय जनता ने हिन्दी की जो शैली निश्चित कर रखी है अर्थात् जिस शैली में अधिकांश लेखक लिखते हैं, आज वही शैली राजभाषा की शैली हो सकती है। कोई सरकार उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जो 'हिन्दुस्तानी' शैली की रूप-रेखा निश्चित करने की बात कहते हैं, उन्हें बता देना चाहिये कि जनता आज तक बैठी नहीं रही, उसने अपनी हिन्दुस्तानी की शैली या शैलियाँ निश्चित कर ली हैं—और वे हैं हिन्दी और उर्दू। आज एक दर्जन आदमियों की गढ़ी हुई 'हिन्दुस्तानी' शैली आठे दर्जन आदमियों की ज़िद के कारण किसी भी प्रकरण में इन दो शैलियों को अपदस्थ नहीं कर सकती। हिन्दी प्रान्तों में उर्दू शैली को भी स्थान मिल सकता है, परन्तु कोई 'हिन्दुस्तानी' शैली हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती।

यह बात याद रखनी चाहिये कि यदि हिन्दी-प्रान्तों में हिन्दी का बोल-वाला रहा, और वह राजभाषा हुई (अकेली या उर्दू के साथ साथ), तो राष्ट्र-भाषा भी 'हिन्दुस्तानी' नहीं हो सकती। इस तथ्य पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। राष्ट्र-भाषा की शैली प्रान्त-भाषा की शैली से भिन्न रह ही नहीं सकती। 'हिन्दुस्तानी' का जन्म ही न होगा। अहिन्दी लोग हिन्दुस्तानी को गढ़ कर उसे जीवित रख ही नहीं सकते। जो खड़ी बोली हिन्दी प्रान्तों में चलेगी, अन्त में वही राष्ट्र-भाषा होगी। यदि हम हिन्दी वाले अपने प्रान्तों में हिन्दुस्तानी को ठुकरा कर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तो उससे भिन्न हिन्दी राष्ट्र में चल ही नहीं सकेगी (आज तक

भी केन्द्र को 'हिंदुस्तानी' प्रान्तों की राजभाषा 'हिंदुस्तानी' (अर्थात् उर्दू) से भिन्न नहीं रही है) । ऐसी अवस्था में यदि हमारी हिन्दी में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति हुई, और उसमें राष्ट्र-मुक्तभता भी हुई, तो वह मध्यदेश की भाषा होने के कारण अपने आप फैलते फैलते वास्तविक राष्ट्र-भाषा हो जायगी, हिंदुस्तानी वाले उसके विरुद्ध चाहे जितनी चिल्ला पों मचावें । हमें भी हिंदुस्तानी पर 'क्रांटल अटैक' करने की जरूरत नहीं, वस 'फ्लैक सूवमेन्ट' को विकल कर अपने हिंदी-प्रान्तों में सर्वत्र हिंदी को प्रतिष्ठित करें, और केन्द्र में प्रान्त-भाषा के नाते हिंदी के लिये अन्य प्रान्तीय भाषाओं जैसे अधिकार प्राप्त करें (उदाहरण के लिये, रेडियो में, सरकारी फ़िल्मों में, आदि) । लेखक दावे से कह सकता है कि इतना होने पर हिंदुस्तानी वाले लाख सिर पटकने पर भी अपनी 'हिंदुस्तानी' को बाध नर भी आगे न बढ़ा सकेंगे—या तो राष्ट्र-भाषा केवल हिन्दी होगी, या हिन्दी और उर्दू दोनों राष्ट्र-भाषा होंगी ।

स्पष्ट है, सब प्रकार से हिंदी का भविष्य स्वयं हिन्दीवालों के हाथ में है । हमें राष्ट्र-भाषा हिन्दी के पन्धे में पड़कर प्रान्त-भाषा हिन्दी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिये । इस कड़ी के हाथ में रहते पूरी अशंका अनायास खिचती चली आयेगी, और यदि यह कड़ी हाथ से छूट गई तो सर्वनाश निश्चित है । यदि देश को हमारी हिन्दी राष्ट्र-भाषा के रूप में मान्य नहीं है, तो राष्ट्र-भाषा जाय भाड़ चूल्हे में । हम अपनी हिन्दी क्यों दिगाड़ें ? और कौन अपनी प्रान्तीय भाषा को दिगाड़ रहा है ? या तो देश हमारी हिन्दी को राष्ट्र-भाषा स्वीकार करे, हिन्दी की वर्तमान शैली (और केवल देवनागरी लिपि) से आरम्भ करे, काम होते-होते हिन्दी राष्ट्र की दृष्टि से आवश्यक शब्द, धातु, मुहावरे, आदि अन्य भारतीय भाषाओं से अपने आप आत्मसात करती चली जायगी, और नहीं तो हम अहिन्दियों से प्रार्थना करेंगे कि खुदा के वास्ते वे हमारी हिन्दी को बरूश दें और किसी अन्य भाषा पर (मिसाल के

लिये गान्धीजी अपनी गुजराती पर) अपने राजनीतिक प्रयोग करें। यदि उन्होंने हमारी हिन्दी को बिगाड़ने का प्रयत्न किया ही, तो गहरा भगड़ा होगा। किसी भी भाषा को विकृत करने या उसे अपने अधिकारों से वञ्चित करने का प्रयत्न मज़ाक नहीं है। हम राष्ट्र-भाषा की वेदी पर अपनी हिन्दी की बलि देने के लिये तैयार नहीं। हम 'हिंदुस्तानी' की खातिर किसी भी प्रान्तीय या केन्द्रीय प्रकरण में हिन्दी—जैसी भी हमारी हिन्दी आज है अर्थात् जिस भाषा का आज 'हिन्दी' नाम से बोध होता है—छोड़ नहीं सकते। यदि अहिन्दियों को हिन्दी की किसी भी शैली को गढ़कर राष्ट्र-भाषा के रूप में ग्रहण करने का अधिकार है, तो हमें भी अधिकार है कि हम उसे राष्ट्र-भाषा न मानें, अपने घर में उसे न घुसने दें, उसे न पढ़ें और न अपने बच्चों को पढ़ने दें और उसका भरपूर विरोध भी करें। रक्खें वे अपनी 'हिन्दुस्तानी' अपने पास, और यदि रख मिले तो उसे जीवित रखें। (परंतु उन्हें जीवित रख नहीं मिलेगी*।) हिन्दी केवल हिन्दीवालों के हाथ में है।

* अगर उन्हें अपनी 'हिन्दुस्तानी' जीवित रख भी मिली, तो कमसे कम अन्य प्रान्तीय भाषाओं के समान हमारी अपनी विशिष्ट संस्कृति का प्रतीक हिन्दी भी तो अपने क्षेत्र में रहेगी। यदि हिन्दी राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती, तो अन्य प्रान्तीय संस्कृतियों और भाषाओं की भाँति हमारी विशिष्ट संस्कृति और उसका प्रतीक हमारी विशिष्ट भाषा हिन्दी तो रहनी ही चाहिये, और उसे अन्य प्रान्तीय संस्कृतियों और भाषाओं के समान अपने क्षेत्र में और केन्द्र में वही स्थान तो मिलना ही चाहिये।

यदि आज कोई 'किंग्स इंग्लिश' छोड़कर एक संसार-भाषा गढ़ने के निमित्त संसार की पाँच छै तरह की अङ्गरेज़ियों जैसे अङ्गरेज़ों की अङ्गरेज़ी, अमरीकन अङ्गरेज़ी, बाबू अङ्गरेज़ी, पिजिन (Pidgin) अङ्गरेज़ी, आदि को मिला कर तुर्की, चीनी और जापानी का छौक देकर और अङ्गरेज़ी के आधे ग्रीक और लैटिन शब्द निकाब कर उनके स्थान में संस्कृत और अरबी शब्द धरकर एक 'मिळी जुळी' अङ्गरेज़ी शैली गढ़े (और उसे पाँच छै लिपियों में लिखे), तो कम से कम अङ्गरेज़ तो उसे संसार-भाषा न मानेंगे, उसे इङ्गलैंड में किसी रूप

वे ही उसे बिगाड़ सकते हैं। दूसरा कोई उसे अधिक समय तक बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। सब हिन्दीवाले दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें कि वे सदैव शुद्ध हिन्दी में लिखेंगे और बोलेंगे। उदाहरण के लिये, यदि युक्त-प्रान्त की असेम्बली में या युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में या केन्द्रीय असेम्बली में या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में या सभा सभाद्वियों में सब हिन्दीवाले शुद्ध हिन्दी में बोलें, तो क्या कोई उनकी ज़वान पकड़ लेगा ? यदि विधान में शब्द 'हिन्दुस्तानी' ही धरा हो, तो क्या हिन्दी हिन्दुस्तानी नहीं है ? उस पर आपत्ति करने का कौन साहस कर सकता है ? क्यों नहीं हिन्दीवाले हिंदी में बोलते ? वे इस मामले में सुसलमानों से ही सबक क्यों नहीं लेते ? वे क्यों हिन्दुस्तानी में बोलने का प्रयत्न करके अपने दर्शों अपनी भाषा की छीछालेदार करते हैं, और हास्यास्पद करते हैं ? जो जाति अपनी भाषा नहीं छोड़ती, उसी की भाषा जीवित रहती है। उसकी भाषा को कोई नहीं नार सकता। हाँ, यदि हिन्दी वाले ही हिन्दी नहीं बोलेंगे, और हिन्दुस्तानी के पचड़े में पड़कर हिन्दी को विकृत करेंगे, तो ब्रह्मा भी हिन्दी को नहीं बचा सकते। अतः हमें किसी दूसरे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम स्वयं सावधान हो जायँ, अपना सारा काम हिन्दी में करें, प्रत्येक अवसर पर और बोलचाल में सदैव शुद्ध हिन्दी में बोलें और लिखें, अपने घर में हिन्दुस्तानी

में न घुसने देंगे, अपने बच्चों को उसे किसी भी रूप या हँसियत में पढ़ाने को तैयार न होंगे, बी० बी० सी० से उसमें खबरें या अन्य कोई प्रोग्राम कदापि ब्राडकास्ट न होने देंगे और उसका भरपूर विरोध भी करेंगे, क्योंकि उसके प्रचार से अङ्गरेज़ी की स्टैंडर्ड शैली तो फिर भी विकृत होगी ही (आज भी किसी भारतीय अङ्गरेज़ी पत्र के किंग्स इङ्गलिश के प्रति ज़रा सा अपराध करते ही चिल्ला-पों मचने लग जाती है। अङ्गरेज़ी जैसी जमी हुई भाषा के विषय में जब यह होता है, तो बेचारी कल की हिंदी की तो बात ही क्या है)। 'हिन्दुस्तानी' के प्रति हिन्दियों का यही सख्त होना चाहिये।

बालों की चाल को विफल करें और अपनी हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। वरु, यही हिन्दुस्तानी-मारक अमोघ अस्त्र है।

अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी प्रान्तों में उर्दू का क्या स्थान होना चाहिये? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं*, परन्तु इस सम्बन्ध में दो बातें बिलकुल स्पष्ट हैं। पहली यह कि हिन्दी प्रान्तों में उर्दू को उससे अधिक स्थान कदापि नहीं मिल सकता जो अन्य प्रान्तों में अल्पमत की भाषाओं को दिया जायगा, और दूसरी यह कि वह स्थान भी उर्दू को तभी मिल सकता है जब उर्दू प्रान्तों में, खास तौर से पंजाब में, हिन्दी को वही स्थान दिया जाय। पहली बात के सम्बन्ध में न्याय का तकाज़ा है कि व्यावहारिक दृष्टि से जहाँ तक संभव हो सरकार प्रत्येक को कम से कम आरम्भिक शिक्षा अपनी मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा प्राप्त करने की सुविधा दे, परन्तु साथ ही साथ प्रान्त की एक कामन भाषा और लिपि हो (जो उस प्रान्त की मुख्य भाषा और लिपि हो) जिसे उस प्रान्त की राज-भाषा बनाया जाय और जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवार्य किया जाय। इन सिद्धान्तों को हिन्दी प्रान्तों पर लागू करने से यह निष्कर्ष निकलता है (जनपद आन्दोलन को ध्यान में रखते हुये) —

(१) युक्त-प्रान्त में ब्रज, अवधी, बुन्देली, आदि मुख्य बोलियों में, बिहार में भोजपुरी, मैथिली और मगही में, और मध्य-प्रान्त में कोशली में प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। हिन्दी और बिहारी की सब बोलियों की लिपि केवल एक, देवनागरी, होगी।

(२) यदि किसी पर्याप्त विशाल जनपद का बहुमत जनपदीय बोली में प्राथमिक शिक्षा को माँग करता है, तो उस जनपद के उसी बोली को बोलने वाले किसी अल्पमत सम्प्रदाय को (जिसमें सम्भवतः अधिकतर

* देखिये 'राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन', पृष्ठ १४१-४६ और पृष्ठ १६०।

सुसलमान होंगे) किसी भिन्न भाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कारण, १. ऐसा करना अव्यावहारिक होगा; २. जहाँ एक ओर प्रत्येक को मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वहाँ किसी का अपनी मातृ-भाषा छोड़कर भिन्न भाषा की माँग करने का भी अधिकार नहीं है (उदाहरण के लिये दक्षिण का सुसलमान नहीं कह सकता कि मैं तामिल के राजा उर्दू के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करूँगा)। जनपद की सीमा वैज्ञानिक दृष्टि से अर्थात् भाषा-विज्ञान की दृष्टि से निर्धारित की जानी चाहिये।

(३) व्यावहारिक दृष्टि से यह बांछनीय है कि प्राथमिक शिक्षा के माध्यमों की संख्या कम से कम हो। अतः यदि किसी जनपद या क्षेत्र का बहुमत जनपदीय बोली के राजा हिन्दी वा उर्दू से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहे, तो उस समस्त जनपद में हिन्दी तथा उर्दू प्राथमिक शिक्षा के माध्यम बनाये जायें। प्रत्येक स्कूल में, यदि हिन्दी वा उर्दू माध्यम लेने वाले छात्रों की संख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, दोनों माध्यमों का प्रबन्ध होना चाहिये। हिन्दी स्कूल अलग और उर्दू स्कूल अलग भी खोले जा सकते हैं (जैसे दम्बई शहर में गुजराती स्कूल अलग और मराठी स्कूल अलग हैं)।

(४) माध्यमिक और उच्च शिक्षा के माध्यम हिन्दी और उर्दू हों। जिन स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में दोनों माध्यमों का प्रबन्ध होगा, उनमें हिन्दी माध्यम वालों के अलग और उर्दू माध्यम वालों के अलग कक्षाएँ लेना पड़ेंगे। इस व्यवस्था से छात्रों की संख्या के अनुसार प्रत्येक नगर में हिन्दी और उर्दू स्कूल वा कालेज अलग अलग स्थापित करना कहीं श्रेयस्कर होगा। विश्वविद्यालयों के साथ भी यही बात लागू है। उदाहरण के लिये इस समय युक्त-प्रान्त में लखनऊ और प्रयाग विश्व-विद्यालय दोनों में दोनों माध्यमों का प्रबन्ध करने से यह कहीं अच्छा,

सुविधाजनक और सस्ता होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में दोनों माध्यमों का प्रबन्ध हो और प्रयाग विश्वविद्यालय का माध्यम केवल हिन्दी हो। युक्त-प्रान्त में हिन्दी माध्यम वाले और उर्दू माध्यम वाले छात्रों में ऐसा अनुपात है कि प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल छात्रों से फिर भी अधिक ही होगी। आवश्यकतानुसार प्रयाग विश्व-विद्यालय के अध्यापकों का लखनऊ विश्वविद्यालय को और लखनऊ विश्व-विद्यालय के अध्यापकों का इलाहाबाद को तबादला किया जा सकता है। (आगरा विश्वविद्यालय केवल परीक्षक विश्वविद्यालय है और इसलिये उस विश्वविद्यालय की समस्या वास्तव में केवल उसके अन्तर्गत कालेजों की समस्या है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का माध्यम उर्दू और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का माध्यम हिन्दी तो होगा ही।)*

(५) तीनों हिन्दी प्रान्तों—युक्त-प्रान्त, विहार और मध्य प्रान्त—की कामन भाषा और राजभाषा इन प्रान्तों की मुख्य साहित्यिक भाषा नागरी हिन्दी होगी और इन प्रान्तों के प्रत्येक निवासी के लिये हिन्दी भाषा का विषय अनिवार्य होगा (जिस प्रकार आजकल अँगरेज़ी भाषा का विषय सबके लिये अनिवार्य है)। स्पष्ट है, हिन्दी माध्यम लेने वालों को हिन्दी विषय अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, परन्तु उर्दू माध्यम वालों को पढ़ना पड़ेगा। उनके लिये हिन्दी भाषा का विषय माध्यमिक स्टेज से रक्खा जाय, और उसका स्टैंडर्ड कम से कम इतना हो कि माध्यमिक पढ़ाई समाप्त होने तक हिन्दी में इतनी योग्यता आ जाय जितनी आज प्रथम भाषा हिन्दी लेने वाले छात्र को हाई स्कूल पास करने तक आती है। पढ़ाई का बोझ सब पर समान करने के हेतु हिन्दी माध्यम वाले छात्रों के लिये माध्यमिक स्टेज

❀ भारत के विभाजन से जो नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें हिन्दी प्रान्तों में उर्दू को भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत नहीं किया जा सकता। देखिये परिशिष्ट १७।

से प्रमुख भारतीय भाषाओं में से (जिनमें उर्दू भी शामिल होगी) किसी एक भाषा को पढ़ाई के लिये छाँट लेना अनिवार्य किया जा सकता है; परन्तु इसका ईमानदारी के साथ पालन करने के लिये आवश्यक होगा कि माध्यमिक स्कूलों में बँगला, तामिल, मराठी, गुजराती, आदि भाषाओं को पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय—यह नहीं कि सूची में तो सब भाषायें हों परन्तु प्रबन्ध हो केवल उर्दू का । (चूँकि हिन्दी-उर्दू प्रान्तों को छोड़कर अन्य प्रान्तों में प्रत्येक छात्र को माध्यमिक स्टेज से मातृ-भाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा का विषय लेना होगा, सब भारतीय छात्रों पर एक समान बोझ पड़ेगा ।) इस प्रकार हिन्दी प्रान्त-वासी अन्य प्रान्तों की भाषायें भी सीख सकेंगे, और हिन्दी पर उनका जो श्रृण होगा उसे चुका सकेंगे ।*

(६) राजभाषा हिन्दी का अर्थ है कि सब सरकारी व्यवहार जैसे सेक्रेटेरियट, तथा अन्य दफ्तरों का काम, पुलिस, म्युनिसिपैलटी, कचहरियों, आदि का काम नागरी हिन्दी में होगा । असेम्बली, आदि में प्रत्येक बक्ता को किसी भी भारतीय भाषा में बोलने की स्वतंत्रता दे दी जाय, क्योंकि परिस्थिति अपने आप प्रत्येक बक्ता को हिन्दी में बोलने के लिये प्रेरित करेगी ।

इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार उर्दू प्रान्तों में, जिनमें इस समय पंजाब, सीमा-प्रान्त और दलूचिस्तान शामिल हैं, और यदि सिन्धी का समुचित विकास न हुआ तो सिन्धी भी शामिल हो जायगा, हिन्दी को यह अधिकार मिलना चाहिये—

जहाँ जहाँ उर्दू प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत हो, वहाँ वहाँ हिन्दी माध्यम भी स्वीकृत हो, और वहाँ के प्रत्येक

* भारत के विभाजन से जो नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें हिंदी प्रांतों में हिंदी का विषय सबके लिये प्राथमिक स्टेज से अनिवार्य करना होगा । देखिये परिशिष्ट १७ ।

स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय में, यदि हिन्दी माध्यम वाले छात्रों की संख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, वास्तव में, व्यवहार में हिन्दी माध्यम का प्रबन्ध हो। (यह हो सकता है कि किसी क्षेत्र में बहुमत के माँगने पर शिक्षा का केवल एक माध्यम पंजाबी या पश्तो या सिन्धी स्वीकृत हो, तब वहाँ न उर्दू माध्यम होगा न हिन्दी माध्यम।)*

ऊपर की योजना दार्शनिक और तार्किक दृष्टि से आदर्श और निर्दोष नहीं कही जा सकती। इसकी समालोचना करना आसान है। परन्तु मनुष्य का जीवन भी पूर्ण और निर्दोष नहीं है। परिस्थितियों और व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुये, गहरा विचार करने के बाद लेखक निश्चित रूपसे कह सकता है कि इस योजना से मूलतः भिन्न कोई दूसरी योजना संभव नहीं।X।

* पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने जो घोषणायें की हैं उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि उर्दू प्रांतों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल उर्दू होगी। यद्यपि सिंध के शिक्षा-मंत्रों ने यह कहा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जायगी, इसकी कोई आशा प्रतीत नहीं होती कि पाकिस्तान सरकार पंजाब, सिंध और सीमा-प्रांत में हिंदी भाषियों के लिये हिन्दी द्वारा प्राथमिक शिक्षा ही देने का प्रबंध करेगी। देखिये परिशिष्ट १७।

X अच्छा हो यदि हिन्दी वाले और उर्दू वाले मिल कर बैठें और आपस में हिन्दी तथा उर्दू प्रांतों के लिये एक समान व्यवस्था तय कर डालें, जिसमें हिन्दी और उर्दू के साथ, एक भाषा के दो रूप होने के नाते, समान व्यवहार किया जाय, और फिर हिन्दी तथा उर्दू प्रांतों में ईमानदारी के साथ प्रत्येक विभाग में हिन्दी और उर्दू को अपना अपना तय पाया हुआ स्थान दे दिया जाय। हिन्दी उर्दू के व्यर्थ के झगड़े को मिटा डालने का यही एक मात्र उपाय है। यदि ऐसा कर लिया गया तो हिन्दुस्तानी वाले टापते रह जायेंगे। वे हिन्दी उर्दू के झगड़े से लाभ उठाते हैं। हमें उर्दू वालों से कहना चाहिये कि इस हिन्दुस्तानी से हिन्दी और उर्दू दोनों को खतरा है, हम हिन्दी और

हिन्दीयों को जिन बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि

उर्दू दोनों को राष्ट्रभाषा मानने को तैयार हैं, और प्रत्येक को स्वतंत्रता देना चाहते हैं कि वह इनमें से चाहे जिसको राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ने के लिये चुन ले, मगर शर्त यह है कि जो सुविधा हिन्दू प्रान्तों में सरकार की ओर से राष्ट्रभाषा उर्दू पढ़ने वालों को दी जाय, वही सुविधा मुस्लिम प्रान्तों—पंजाब, सीमाप्रान्त, सिन्ध, बलूचिस्तान और बंगाल—में ईमानदारी के साथ, राष्ट्रभाषा हिन्दी पढ़ने वालों को दी जाय। हमारी बात व्यावहारिक होगी, उसमें सत्य होगा, धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होगी, और संभव है हमारा उर्दू वालों से समझौता हो जाय। हिन्दुस्तानी वालों से उनका या हमारा समझौता होना असंभव है। हिन्दुस्तानी वालों के आधारभूत सिद्धान्त शकत हैं, बनावटी और दिखाऊ हैं और वास्तविकता से बहुत दूर हैं। 'हिन्दुस्तानी' धोखे की दही है। हिन्दुस्तानी प्रचार से हम जितने सट और असतुष्ट हैं, उतने ही उर्दू वाले उससे सशक्त हैं। हिन्दी और उर्दू दोनों राष्ट्रभाषा मान ली जाने पर इनमें से जिसमें अधिक जान होगी, राष्ट्रधरा की अधिक अभिव्यक्ति होगी, अधिक राष्ट्र-सुलभता होगी, वह कालान्तर में अपने आप प्रधान हो जायगी और एक समय आ सकता है जब उर्दू वाले भी हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार कर लें। विज्ञान और यथार्थ की उपेक्षा अधिक समय तक संभव नहीं। परन्तु इस समय हिन्दी और उर्दू दोनों को राष्ट्रभाषा मान लेना ही राष्ट्र-भाषा की समस्या के समाधान का एकमात्र सच्चा और ईमानदारी का रास्ता है, अन्य कोई नहीं। प्रत्येक प्रान्त की एक कामन भाषा तो होगी ही, जिसके द्वारा अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार संभव होगा। केवल अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार की और केन्द्रीय सरकार की दो भाषायें हिन्दी और उर्दू होंगी। जो चाहेंगे जिन्हें कुरसत होगी अथवा जिन्हें आवश्यकता पड़ेगी, वे अपने आप हिन्दी और उर्दू दोनों सीख लेंगे।

(भारत के विभाजन से परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। इसमें हिन्दी वालों और उर्दू वालों के बीच में समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत के विभाजन का राष्ट्र-भाषा की समस्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे उत्तर-परिशिष्ट ३ (पृष्ठ ६३) में देखिये, और हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा के नाभ्यन के प्रश्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे परिशिष्ट १७ में देखिये।)

यह योजना तो ठीक है, और हिन्दो प्रान्तों में इसको कार्यान्वित करना भी उनके हाथ में है, परन्तु यदि उर्दू प्रान्त इस योजना के अनुसार अपने यहाँ हिन्दी को स्थान न दें, तो क्या किया जायगा ? यह प्रान्तीय स्वायत्त शासन (प्रार्विशियल आटोनमी) का जमाना है, शिक्षा का विषय न केन्द्रीय सरकार के पास है और न कभी होगा, अर्थात् केन्द्रीय सरकार राष्ट्रभाषा या प्रान्तों की भाषा के मामले में अपना फैसला प्रान्तों पर लादने में असमर्थ है (केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक यह तय कर सकती है कि केन्द्र का सरकारी व्यवहार किस भाषा में हो), और प्रत्येक प्रान्त भाषा के विषय में अपने यहाँ मनचाही व्यवस्था करने में पूर्ण स्वतन्त्र है। हिन्दियों को भूलना नहीं चाहिये कि लक्ष्णों से मालूम होता है कि उर्दू प्रान्त उर्दू लिपि के सिवा किसी दूसरी लिपि को, और उर्दू के सिवा किसी दूसरी हिन्दुस्तानी को, बतौर राष्ट्रभाषा के या बतौर अपने यहाँ की जनता के एक भाग की भाषा के, कोई स्थान देने को तैयार नहीं। उर्दू प्रान्तों में इस मामले में हस्तक्षेप करने में कांग्रेस भी असमर्थ है—केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उर्दू प्रान्तों की प्रान्तीय सरकारों द्वारा, और असमर्थ रहेगी। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार उर्दू प्रान्त गांधी जी की हिन्दुस्तानी के मार्ग में बाधक हैं, उसी प्रकार ये प्रान्त ऊपर वाली योजना के मार्ग में भी बाधक हैं। उर्दू प्रान्त इस योजना के अनुसार हिन्दी को स्थान आसानी से कभी न देंगे। इतना ही नहीं, उल्टे उर्दू वाले हिन्दो प्रान्तों में बड़े जोर शोर से यह आन्दोलन करेंगे कि उर्दू का सब जगह हिन्दी के समकक्ष स्थान दिया जाय, अर्थात् हिन्दी के साथ साथ उर्दू भी राजभाषा बनाई जाय, उर्दू माध्यम वालों के लिये हिन्दी भाषा का विषय अनिवार्य न किया जाय, और यदि किया जाय तो हिन्दी माध्यम वालों के लिये उर्दू भाषा का विषय अनिवार्य किया जाय, आदि। अपनी 'अपीजमेन्ट पालिसी' के कारण कांग्रेस इस आन्दोलन से सहयोग करेगी। हिन्दियों को अपने रास्ते में

पड़ने वाली सहायता को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । आज उर्दू प्रांतों की मुसलमान जनता और मुसलमान सरकारें गांधीजी की 'राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' को छूना तक नहीं चाहतीं, मगर इस कारण कांग्रेस और गांधीजी हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में अपनी हिन्दुस्तानी, या हिन्दी उर्दू दोनों, और 'दोनों लिपि' का प्रचार करने से नहीं हिचके । उर्दू प्रांतों की सरकारों ने हिन्दुस्तानी और देवनागरी की बात नहीं पूछी, मगर इस कारण हिन्दी प्रांतों की कांग्रेसी सरकारें हिन्दी प्रांतों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में और राज-भाषा के रूप में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' लादने में दाज्ञ न आई । इन बातों को देखते हुये वह आशा कैसे की जा सकती है कि यदि हिन्दी-जन हिन्दी प्रांतों में 'हिन्दुस्तानी' का विरोध करने में सफल हो भी गये, तो कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिये हिन्दी उर्दू दोनों को हिन्दी प्रांतों की राजभाषा न बनाएगी, उर्दू को हिन्दी के समकक्ष न रखे देगी और हिन्दी वालों पर उर्दू न लादेगी—उर्दू प्रान्त चाहे अपने वहाँ से रही

ॐ इसका परिणाम, जैसा पहले इङ्गित किया जा चुका है, यह होगा कि उर्दू और उर्दू लिपि ही वास्तविक राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि होंगी । यदि गांधीजी के हिन्दुस्तानी प्रचार ने हिन्दी उर्दू दोनों के बजाय वर्धा की हिन्दु-स्तानी का ही हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में प्रचार किया, तो भी उर्दू लिपि तो सम्पूर्ण भारत की वास्तविक राष्ट्रलिपि या कामन लिपि होगी ही, वर्धा की हिन्दुस्तानी भी उर्दू से भिन्न नहीं रह सकती, क्योंकि जब तक राष्ट्र का एक भाग, अर्थात् उर्दू-प्रान्त, उर्दू के सिवा किसी दूसरी हिन्दुस्तानी को नहीं समझता, और न सीखने का तैयार है, तब पूरे राष्ट्र को एक भाषा के बन्धन में बाँधने का केवल एक ही उपाय है—राष्ट्र के शेष भाग की हिन्दुस्तानी को भी उर्दू बना दो । जान बूझ कर बनाओ या न बनाओ, वह धीरे-धीरे अपने आप उर्दू हो जायगी क्योंकि उर्दू प्रान्तों की उर्दू में कोई हिन्दी शब्द घुसने नहीं दिया जा सकता और शेष प्रान्तों की हिन्दुस्तानी में किसी उर्दू शब्द के घुसने पर रोक लगाई नहीं जा सकती, किसी उर्दू शब्द को गैर-हिन्दुस्तानी करार दिया नहीं जा सकता । (देखिये उत्तर—परिशिष्ट ३)

सही हिन्दी भी निकाल फेंकें ? युक्त-प्रान्त और बिहार की वर्तमान कांग्रेसी सरकारों की नीति इसी बात की सूचना देती है ।

हिन्दियों को अपने कर्तव्य का ज्ञान और अपने कार्य के गुरुत्व का अनुमान हो गया होगा । एक ओर उन्हें अपने प्रान्तों से हिंदुस्तानी को निकाल भगाना है, और दूसरी ओर उन्हें उर्दू-बाजों की अनुचित माँगों और उनके अन्याय का विरोध करना है । हम दोनों बातों में से किसी से सुँह मोड़ नहीं सकते । पहली बात तो बहुत साफ़ हो चुकी है, दूसरी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । हम १३ प्रतिशत^x मुसलमानों के कारण, जिनमें से अधिकांश हिंदी बोलते या समझते हैं, न हिंदी की सुन्नत करने को तैयार हैं, और न हम हिंदी प्रान्तों की दो दो राजभाषायें और राजलिपियाँ बनाकर अपने प्रान्तों की भाषी उन्नति पर सदैव के लिये कुठाराघात कर सकते हैं—इस कारण और भी नहीं कि उर्दू प्रान्त भी ऐसा करने को तैयार नहीं हैं । ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि उर्दू प्रान्तों की एक कामन भाषा उर्दू और एक कामन लिपि फ़ारसी लिपि हो, अन्य प्रान्तों की कामन भाषायें अपनी अपनी प्रान्तीय भाषायें हों, परन्तु हिंदी प्रान्तों की या तो कामन भाषा हो 'हिंदुस्तानी', या कोई कामन भाषा न हो, और लिपि हर हालत में कोई कामन न हो । ऐसी स्थिति में हमारे हिंदी-प्रांत अन्य प्रान्तों के मुकाबले में पिछड़ जायेंगे, और हमारे प्रांतीय जीवन का समुचित सांस्कृतिक विकास और संगठन न

* पंजाब के कांग्रेसी संयुक्त मंत्रि-मंडल ने या सीमाप्रांत की कांग्रेसी सरकार ने हिन्दी के लिये न उँगली उठाई है और न उठायेगी । सिन्ध का तो जिक्र करना ही बेकार है । बहुत हुआ तो डा० खान साहब कह देंगे कि वे तो सीमा-प्रांत की जनता के नौकर हैं, जनता का बहुमत चाहेगा तो हिन्दी होगी । हाँ, पं० गोविन्दवल्लभ पंत, श्रीकृष्ण सिन्हा और पं० रविशंकर शुक्ल वह करेंगे जो कांग्रेस हाई कमांड, मौलाना आज़ाद और गांधीजी चाहेंगे ।

x युक्त-प्रांत, बिहार और मध्य-प्रांत में कुल मिलाकर ६ करोड़ ४० लाख (६४ मिलियन) हिन्दू हैं और १ करोड़ ४० लाख (१४ मिलियन) मुसलमान हैं । (देखिये उत्तर-परिशिष्ट ३)

हो सकेगा। हम हिन्दी प्रांतों में उर्दू को जो स्थान देने को तैयार हैं, वह उदारता की सीमा है, उर्दू के न्यायोचित प्राप्ति से कहीं अधिक है। उससे और आगे जाना हमारे लिये अत्यन्त हानिकारक है, हमारी उन्नति में बाधक है। हिन्दी की विशुद्धता और अबाध विकास के लिये भी वह आवश्यक है कि वह अन्य प्रांतीय भाषाओं के समान हिन्दी प्रांतों में एकमात्र राजभाषा हो और कामन भाषा हो, जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवार्य हो (जिस प्रकार पंजाब में प्रत्येक के लिये उर्दू पढ़ना अनिवार्य है), अन्यथा वह दूषित और विकृत होती चली जावगी, हिन्दुस्तानी के रोलर के नीचे दबती चली जावगी और उन अधिकारों से भी वञ्चित होती चली जावगी जो अन्य प्रांतीय भाषाओं को प्राप्त हैं। उर्दू प्रांतों में उर्दू का अग्रगण्य साम्राज्य है, और वह विशुद्ध रहेगी, हिन्दी चाहे अपने आपको मिटा डाले।

हिन्दीवां को इससे अधिक करना है। उर्दू प्रांतों में, अन्य प्रांतों में, सुविन्न गिरासतों में और केन्द्र में 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर या बिना किसी आड़ के हिन्दी के साथ जो आन्ध्र हो रहा है, उसका भी प्रतिकार उन्हें करना है, और हिन्दी गिरासतों पर ध्यान देना है। घर की राज्य-व्यवस्था सँभाल कर साम्राज्य की व्यवस्था ठीक करना है। इसके लिये हिन्दीवालों को उर्दू प्रांतों, अन्य प्रांतों और गिरासतों में प्रबल आन्दोलन तो करना ही पड़ेगा, एक और उपाय का अवलम्बन करना पड़ेगा। जब तक उर्दू प्रांत अपने वहाँ हिन्दी को न्यायोचित स्थान न दें, तब तक हमें भी हिन्दी-प्रांतों में उर्दू के साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो उर्दू प्रांत हिन्दी के साथ करेंगे। हम कायों को अहिंसा और दिल-निबलाच-योग में विश्वास नहीं कर सकते। हम उर्दू प्रांतों में सुसज्जन आकाश्यों के सामने बहुत नाक रगड़ चुके, परन्तु बदले में सिखा केवल तिरस्कार और अवज्ञा। सुसज्जन केवल एक ही तर्क समझते हैं, और वह है शक्ति का। उर्दू प्रांतों ने यदि अपनी हिन्दी-बोली नीति न त्यागी, तो हम भी युक्त-प्रान्त और विहार से उर्दू को

मिटा देंगे। हम नहीं चाहते कि उर्दू, यद्यपि वह विदेशियत से ओत-प्रोत है, के साथ अन्याय हो, हम उर्दू के साथ न्याय से नहीं, उदारता से पेश आना चाहते हैं, परन्तु हिंदो के साथ अन्याय हो, यह हमें असह्य है। हिंदी-प्रांतों में उर्दू को अपने प्राप्य से कहीं अधिक स्थान प्राप्त है, अब यदि कलह और संघर्ष होता है तो उसकी कुल जिम्मेदारी उर्दू प्रान्तों पर और उनके पृष्ठ-पोषकों पर होगी। मुस्लिम रियासतों जैसे काश्मीर (काश्मीर में हिन्दू राजा के होते हुये भी चलती श्रीगुलामसैयदेन की ही है*) भोपाल और हैदराबाद, आदि में हिन्दो के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, और हिन्दू जनता के रुपये से उर्दू का जो अनर्गल पोषण हो रहा है उसका भो यही इलाज है। हिन्दी प्रान्तों की भाँति हिन्दी रियासतों में हिन्दियों को हिन्दी की प्रतिष्ठा करनी चाहिये, और जब तक मुस्लिम रियासतें हिन्दी के साथ न्याय न करें, तब तक उर्दू के साथ वही व्यवहार करना चाहिये जो मुस्लिम रियासतों में हिन्दी के साथ किया जाय। अन्य हिन्दू प्रान्तों में यद्यपि उर्दू के साथ वही व्यवहार करना हमारे हाथ में नहीं है जैसा बंगाल में लीगी-सरकार हिन्दी के साथ करती है,×

❧देखिये 'राष्ट्रभाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन परिशिष्ट ४।

× बंगाल की लीगी सरकार के सेकंडरी एजुकेशन बिल का असली उद्देश्य बंगाल में उर्दू और 'मुस्लिम बंगला' प्रचार के सिवा और कुछ नहीं है। उर्दू प्रान्तों में मुसलमान जो चाहते थे सो कर चुके, सिन्ध में भी जो चाहते थे सो कर चुके (सिन्धी का अरबीकरण), अब केवल बंगाल बाकी है, इस लिये वहाँ भी भाषा को एकदम उर्दू में बदल देने का या कम से कम उसका मुस्लिम संस्करण बनाने का आयोजन लीगी सरकार कर रही है। बंगाल की समस्त हिन्दू जनता, जो वहाँ ४५ प्रतिशत से अधिक है, के विरोध के बावजूद लीगी सरकार अपनी चन्द अधिक वोटों के बल पर सेकंडरी एजुकेशन बिल पास कराने पर तुली हुई है। ऐसा क्यों न हो ! मुसलमान भाषा का महत्व समझते हैं, वे जानते हैं कि मुस्लिम-संस्कृति-प्रचार की पहली सीढ़ी भाषा का इस्लामी करण है। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह सब देख सुनकर भी

परन्तु हम कम से कम हिन्दी के लिये उतना स्थान माँग सकते हैं जितना उन्होंने उर्दू को दिया है अथवा देंगे। बम्बई सरकार महाराष्ट्र में मराठी भाषी मुसलमानों को, गुजरात में गुजराती भाषी मुसलमानों को, और उड़ीसा सरकार उड़िया-भाषी मुसलमानों को अपनी अपनी मातृ-भाषा छोड़कर उर्दू पढ़ने की छूट देकर (जैसा सुनने में आया है कि उन्होंने किया है) अपने यहाँ भाषा की समस्या उत्पन्न करें या न करें, वह उनके सोचने की बात है, परन्तु यदि वे ऐसा करती हैं तो उन्हें हिन्दी चाहने वालों को हिन्दी पढ़ने की छूट भी देनी पड़ेगी। केन्द्र में यद्यपि हिन्दुस्तानी के प्रयोग को बन्द कराना हमारे हाथ में नहीं है, परन्तु फिर भी दो बातें हमारे हाथ में हैं—(१) हम केन्द्रीय असेम्बली से ऐसे प्रतिनिधि चुन कर भेजें जो हिन्दुस्तानी का विरोध करें, और हिन्दी को उसका प्राप्य अधिकार दिलायें, अर्थात् हमें हिन्दी को केन्द्रीय चुनाव का एक मुद्दा (issue) बना देना चाहिये; (२) हिन्दी प्रान्तों की सरकारें केन्द्र से कहें कि वह हिन्दुस्तानी में जो चाहे सो करे, परन्तु वह जो कुछ अन्य प्रान्तीय भाषाओं में करेगा उसे उनकी प्रान्तीय भाषा हिन्दी में भी करना पड़ेगा। केन्द्र के लिये इस माँग का विरोध करना संभव न होगा। उदाहरण के लिये, यदि आज हिन्दी प्रान्तों की सरकारें केन्द्रीय सरकार के पास यह मेमोरैंडम भेजें कि रेडियो से खबरें तथा अन्य सरकारी प्रोग्राम अन्य प्रान्तीय भाषाओं की भाँति हमारी प्रान्तीय भाषा हिन्दी में भी होने चाहिये, 'हिन्दुस्तानी' से हमें कोई मतलब नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार इनकार करने का साहस कर सकती है ? जिस प्रकार हम रेडियो में

हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों की कांग्रेस सरकारें नहीं चेततीं। उल्टे वे हिन्दी प्रान्तों में उर्दू को स्वीकृत भाषा करार दे रही हैं।

॥केन्द्र से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार से है। दिल्ली-प्रान्त हिन्दी प्रान्तों में शामिल है।

उर्दू का विरोध नहीं करते, केवल हिन्दी का स्थान माँगते हैं, उसी प्रकार यदि हम रेडिया में हिन्दुस्तानी के प्रयोग का सफल विरोध करने में असमर्थ हैं, तो भी हम अपनी प्रान्तीय भाषा हिन्दी की माँग तो कर ही सकते हैं*। फिर 'हिन्दुस्तानी' किसके लिये हो, यह केन्द्र सोचे—हम 'हिन्दुस्तानी' के लिये जिम्मेवार नहीं। यदि आज युक्त-प्रान्त को सरकार केन्द्रीय सरकार को यह लिख कर भेजे कि लखनऊ से प्रोग्राम केवल युक्त-प्रान्त को जनता के लिये होते हैं, उनसे किसी दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिये कम से कम लखनऊ स्टेशन की भाषा-नीति युक्त-प्रान्त की सरकार के सलाह मशविरे से तय होनी चाहिये, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन्कार कर सकती है ?

सारांश यह कि सब प्रकार से हिन्दी की रक्षा और हिन्दी का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि हिन्दी-जन स्वयं अपने प्रान्तों में हिन्दी की कैसी प्रतिष्ठा करते हैं, और हिन्दी प्रान्तों की सरकारें भाषा के विषय में हिन्दियों की भावना का किस हद तक प्रतिनिधित्व करती हैं और हिन्दी के लिये क्या कुछ करने को तैयार हैं। अतः हमारा कार्यक्रम क्या होना चाहिये, यह स्पष्ट है। हमें हिन्दियों को जागृत करना चाहिये, उनमें हिन्दुस्तानी-वाद के विरुद्ध ऐसे तीव्र विरोध का संचार करना चाहिये कि हिन्दुस्तानी वालों की अकल ठिकाने आ जाय। हमें हिन्दी प्रान्तों में आग लगा देनी चाहिये। हमें हिन्दियों को खोलकर स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि हिन्दुस्तानी हिन्दी और केवल हिन्दी के अस्तित्व पर कुठाराघात है। इतिहास में किसी भी भाषा को नष्ट या विकृत करने के प्रयत्न से उस भाषा-भाषी जाति में सदैव घोर असन्तोष फैला है। हिन्दुस्तानी से हिन्दी को क्या खतरा है, हिन्दियों को यह बताना हमारा काम है। हिन्दी में हमारा क्या है, यह भी हमें सोई हुई जनता को बताना होगा। हम सूर और तुलसी की देन को छोड़ नहीं सकते। हम भारतेन्दु का उपदेश "निज भाषा उन्नति अहै, सब

उन्नति का मूल" भूल नहीं सकते। यदि हमारे मुकाबले में कांग्रेस अपनी समस्त शक्ति से उठ जाय तो भी हमें खत्म ठीक कर भिड़ जाना चाहिये। इस संघर्ष में यदि हम सफल हुये, तो हम केवल अपनी मातृभाषा के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे, और यदि हम पीस डाले गये तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कायुरुप न टहरा सकेंगी—यह न कह सकेंगी कि उन्होंने बुद्धि होते हुये, भविष्य को जानते हुये भी बाप दादा की दी हुई भाषा को नष्ट होने से बचाने का प्रयत्न नहीं किया। हो सकता है, हमें अन्त में गांधीजी के विरुद्ध उन्हीं के दिये हुये हथियार सत्याग्रह का प्रयोग करना पड़े। हमें इसके लिये भी तैयार हो जाना चाहिये। यह वाद रखना चाहिये कि यदि अरबकी हिन्दी डूबी तो फिर नहीं उबरने की। पीछे पड़ना तो कुछ हाथ न आवेगा। वह समय चुप बैठे रहने का नहीं, नर मिटने का है। हमें वर्त्तमान कांग्रेसी सरकारों से आशा त्याग देनी चाहिये। शायद हमें इन्हीं का मुकाबला करना पड़े। अपनी भाषा की रक्षा स्वयं अपने हाथों से करनी होगी।

कुछ और कहने से पहले 'हम' से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट करना उचित होगा। 'हम' से अभिप्राय समस्त हिन्दी प्रेमियों से है। विशेष रूप से 'हम' से अभिप्राय हिन्दी लेखकों और साहित्यिकों से है। हिन्दी का नेतृत्व सदैव हिन्दी के साहित्यिकों ही ने किया है। अब भी उन्हें ही करना है। अब तक उन्हें विदेशी सरकार के उर्दू-प्रचार से लड़ना पड़ा, अब उन्हें कांग्रेस के 'हिन्दुस्तानी'-प्रचार से लड़ना है। हिन्दी को राजनीतिक नेताओं से न कभी सहायता मिली, और न अब मिल सकती है। वास्तव में 'हिन्दुस्तानी' की जड़ में राजनीतिक नेता ही हैं जो हिन्दी को अपनी हिन्दू-मुस्लिम राजनीतिक दाँव-पैचों का शिकार बनाना चाहते हैं। 'हम' में अगर कोई शामिल नहीं है, तो वस यही राजनीतिक नेता।

हिन्दी प्रांतों में कुछ खास काम जो हमें तुरंत करने चाहिये ये हैं—

(१) प्रत्येक जिले में एक हिन्दी-रक्षा-संघ स्थापित किया जाय, जिसका उद्देश्य बिहार (मुजफ्फरपुर) के मुद्दत-संघ की भाँति सब उपायों से 'हिन्दुस्तानी' का विरोध और हिन्दी की रक्षा करना हो। एक शब्द में, ये हिन्दी-रक्षा-संघ ही हमारे हिन्दी आन्दोलन के हाथ पैर होंगे। इन संघों की नीति को संगठित रूप से संचालित करने के लिये प्रत्येक हिन्दी प्रान्त में एक प्रान्तीय हिन्दी-रक्षा-संघ स्थापित किया जाय जिसमें प्रान्त के सब संघों के प्रतिनिधि हों।

(२) हिन्दी जनता में प्रबल आन्दोलन किया जाय कि वह अपने बच्चों को 'हिन्दुस्तानी' या उर्दू और उर्दू लिपि पढ़ाने से साफ इन्कार कर दे। जिन सरकारी स्कूलों में माध्यम 'हिन्दुस्तानी' हो, उनमें हिन्दी जनता अपने बच्चों को न भेजे। यदि सरकार 'हिन्दुस्तानी' या उर्दू की शिक्षा अनिवार्य करे, तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिये हिन्दी जनता को तैयार किया जाय। हम न अपने बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर किसी को उर्दू का अतिरिक्त और अनावश्यक बोझ डालने दे सकते हैं (अँगरेज़ बच्चों को देखिये—उन्हें एक ही भाषा और लिपि सीखनी पड़ती है) और न उन्हें 'हिन्दुस्तानी' पढ़ने दे सकते हैं।

(३) अगले प्रांतीय चुनाव के लिये हिंदी जनता को अभी से तैयार करना आरम्भ कर देना चाहिये। हिंदी को चुनाव को एक मुद्दा (issue) बना देना चाहिये। हमें हिंदी जनता में ऐसी भावना भरनी चाहिये कि वह अगले चुनाव में प्रांतीय असेम्बलियों में ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे जो हिंदी प्रांतों से 'हिंदुस्तानी' को समूल निकालने की प्रतिज्ञा करें, हिंदी को हिंदी-प्रांतों की एकमात्र राजभाषा एवं कामन भाषा और देवनागरी को एकमात्र राजलिपि एवं कामन लिपि बनाये, उर्दू को उससे अधिक स्थान न दे जो उर्दू प्रांतों में हिंदी को दिया जाय, और दफ्तरों, पुलिस, कचहरियों आदि में अँगरेज़ी के साथ उर्दू को भी निकाल कर शीघ्र से

शीघ्र हिंदी की प्रतिष्ठा करें। इसके लिये युक्त-प्रांत की जनता में विशेष रूप से आन्दोलन करना पड़ेगा।*

(४) अगले केंद्रीय चुनाव के लिये भी हिंदी जनता को तैयार करना चाहिये। केंद्र के लिये कैसे प्रतिनिधि चुने जाँय, यह पहले बताया जा चुका है।

(५) हमें इसका प्रयत्न करना चाहिये कि यूनिवर्सिटीयों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के जो चुनाव समय-समय पर होते हैं, उनमें ऐसे ही आदमी चुनकर भेजे जायँ जो, वर्तमान विधान के अन्तर्गत ही, हिंदी का प्रवेश कराने की प्रतिज्ञा करें।

(६) वकीलों तथा अदालतों लोगों में आन्दोलन किया जाय कि वे अपना सारा काम यथाशक्ति (अर्थात् जब तक हिन्दी के रखने की व्यावहारिक बाधाओं को सरकार दूर नहीं करती) शुद्ध हिन्दी और देवनागरी में करें। कानूनी पुस्तकों, फार्मों, आदि का हिंदी में स्टैंडर्ड अनुवाद किया जाय, सरकार से उसे स्वीकृत कराया जाय और अदालतों में सम्मेलन की टाइप-राइटर योजना चालू की जाय। इस मिलसिले में प्रत्येक नगर में स्थानीय वकीलों की एक सभा स्थापित करना सहायक होगा X।

(७) एक हिंदी प्रचारक मंडल स्थापित किया जाय जो हिंदी जनता से बमोष्ठ घन एकत्र करे और हिंदी प्रचारक तैयार करे जो हिंदी प्रांतों में

* जैसा श्रीसम्पूर्णानंदजी ने कहा है, हिंदी वालों को सरकारी कागज़ों की जांच करके एक पुस्तक भी प्रकाशित करनी चाहिये जिसमें यह बतलाया जाय कि राजभाषाओं के विषय में सन् १८३७ की सरकारी आज्ञा क्या थी, उसके अनुसार युक्त-प्रांत में किस भाषा और लिपि को कचहरियों, आदि की भाषा और लिपि होना चाहिये था और उस आज्ञा का उल्लंघन करने के लिये कौन जिम्मेदार था। इस पुस्तक से हिंदी आन्दोलन को बड़ी सहायता मिलेगी।

X परिशिष्ट १६ भी देखिये।

दौरा करके सर्वत्र हिंदी का प्रचार करें । इन प्रचारकों के कुछ विशेष काम ये होंगे:—१. जनता में यह आन्दोलन करना कि जनता अपने दैनिक जीवन में हिंदी का व्यवहार करे, अपना कुल निजी काम, वही-खाते, कारोवारी काम, पत्र-व्यवहार, आदि हिंदी में करे और व्यापारी-गण अपनी दूकानों पर साइनबोर्ड केवल हिंदी में लगावें, मोटरों और लारियों पर केवल हिंदी में लिखवावें, सिनेमा के इशितहार, साइनबोर्ड हिंदी में निकालें आदि, आदि; २. शिक्षित समाज में यह आन्दोलन करना कि प्रत्येक शिक्षित परिवार में कम से कम हिंदी का एक पत्र या पत्रिका अवश्य आवे; ३. सरकार ने इस समय भी हिंदी के लिये जो सुविधायें दे रखी हैं उनसे पूरा लाभ उठाने के हेतु पुलिस, म्यूनिसिपैलटी, रेलवे, मालगुजारी के दफ्तर, कोर्ट आफ़ वार्डस् के दफ्तर तथा अन्य दफ्तरों और महकमों में हिंदी की स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करके उसे प्रमाण सहित अधिकारियों के सामने पेश करना और उन पर उचित कार्रवाई करने के लिये ज़ोर डालना (हमारा उद्देश्य यह है कि केवल लिपि ही देवनागरी न हो बरन् भाषा भी हिंदी हो), ४. बकीलों में यह आन्दोलन करना कि वे सब अदालती काम हिंदी में करें, और उनकी सुविधा के लिये हिंदी का अदालती शब्द-कोष, फ़ारम, आदि प्रस्तुत करना; ५. धारा सभाओं के सदस्यों से मिलकर उनसे धारा-सभाओं में हिंदी के विषय में प्रश्न पुछवाना और सरकार पर यह ज़ोर डालवाना कि वह एक हिंदी जाँच कमेटी की नियुक्ति करे जो राज-व्यवहार और राज-काज में हिंदी की स्थिति की जाँच करके यह बतावे कि हिंदी को उचित स्थान देने के लिये सरकार को क्या करना उचित है, और इस विषय में अपनी सिफ़ारिशें पेश करे; ६. शिष्ट-मण्डल बनाकर सरकारी अधिकारियों से मिलना और उन पर हिंदी के रास्ते की रुकावटें दूर करने के लिये और हिंदी को सर्वत्र उचित स्थान देने के लिये ज़ोर डालना; ७. सार्वजनिक सभाओं में हिंदी के समर्थन में प्रस्ताव पास कराना और उनकी नक़लें तथा अख़बारों की कतरनें

सरकारी अधिकारियों के पास भेजना; ८. जनता में और विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों, धारा-सभाओं के सदस्यों और नेताओं में 'हिंदी बोली' प्रचार करना (देखिये पृष्ठ ६६-८१); ९. जनता में, विशेष रूप से कायस्थों और काश्मीरियों में, यह आन्दोलन करना कि वह अपने बच्चों को स्कूलों में हिंदी ('बनाक्यूलर' के रूप में) दिलावे; १०. जनता में जोरदार आन्दोलन करना कि वह केवल हिंदी के चित्र देखे और उर्दू तथा 'हिंदुस्तानी' के चित्रों का, जो अधिकतर गन्दे और अश्लील भी होते हैं, बहिष्कार करे; आदि ।

हिंदी प्रान्तों के बाहर अन्य प्रान्तों में भी हिंदुस्तानी प्रचार के विरुद्ध नेतृत्व हिंदियों को ही ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी ने सबसे अधिक हानि हिंदियों को ही है । इस सम्बन्ध में कुछ खास खास बातें जो हमें करनी चाहिये ये हैं:—

(१) अहिंदियों को 'हिंदुस्तानी' का ऊँच-नीच समझाया जाय, यह बतलाया जाय कि जैसा हिंदुस्तानी-प्रचार हो रहा है उसका परिणाम केवल यह होगा कि उर्दू और उर्दू लिपि वास्तविक राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि बन जायँगी । ऐसा होने पर हमसे कहीं अधिक अनुविधा उन्हीं को होगी । उसने राष्ट्र का कल्याण कदापि न होगा ।*

(२) *अहिन्दियों को समझाया जाय कि ऐसी बात नहीं है कि हिन्दुस्तानी से केवल हिंदी को खतरा है । 'हिंदुस्तानी' से अन्य संस्कृत-निष्ठ प्रांतीय भाषाओं को भी घोर हानि पहुँचेगी । परस्पर सम्पर्क होने पर दो भाषाओं का एक दूसरे की शब्दावली को प्रभावित करना अनिवार्य है । कालान्तर में राष्ट्र-भाषा का भारत की सबसे प्रमुख, शक्तिशाली और प्रभावशाली भाषा हो जाना भी अनिवार्य है । सब से ज्यादा साहित्य राष्ट्र-भाषा का ही होगा, और देश के सब बड़े बड़े कान राष्ट्र-भाषा में ही होंगे और उसका पढ़ना व्यवहार में प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिये अनिवार्य होगा (जैसे आज कल

* उत्तर-परिशिष्ट ३ भी देखिये ।

अँगरेज़ी का है)। ऐसी अवस्था में यदि राष्ट्र-भाषा यह 'हिन्दुस्तानी' हुई, तो जिस प्रकार आज सार्वदेशिक भाषा अँगरेज़ी के सैकड़ों अनावश्यक शब्द प्रांतीय भाषाओं में घुसते चले जा रहे हैं, प्रांतीय भाषाओं और अँगरेज़ी के मेल से खिचड़ी भाषाओं की ('बाबू हिन्दुस्तानी' या इङ्गलिस्तानी की भाँति) सृष्टि हो रही है, और ये खिचड़ी भाषायें ही शिक्षित समाज की बोलचाल की भाषायें होती जा रही हैं और अँगरेज़ी शब्दों का निकालना अत्यन्त कठिन साबित हो रहा है, उसी प्रकार सार्वदेशिक भाषा 'हिन्दुस्तानी' के प्रभाव के कारण 'हिन्दुस्तानी' द्वारा 'हिन्दुस्तानी' के सैकड़ों अनावश्यक अरबी फारसी शब्द प्रांतीय भाषाओं में उनके अपने शब्दों को निकाल कर उनके स्थान में जा बैठेंगे (मुसलमान आग्रह के साथ बैठायेंगे), और इस प्रकार हिन्दी के समान संस्कृत-निष्ठ अन्य भाषायें जैसे बँगला, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलगू, तामिल, कन्नड़ और मलयालम, आदि भी विकृत होती चली जायँगी, और उनका पुराना साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिये अपरिचित और दुरूह होता चला जायगा। राजभाषा फारसी के समय में छोर की भाषाओं बँगला और तामिल तक में अनेक अरबी फारसी शब्द घुसे; राजभाषा अँगरेज़ी के प्रभाव के कारण प्रांतीय भाषाओं की दुर्दशा आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, आगे राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' के समय में प्रांतीय भाषाओं में हजारों अनावश्यक विदेशी अरबी फारसी शब्दों का घुसना अनिवार्य है। इसी आने वाले खतरे की कल्पना करके श्रीयुत के० एम० मुंशी ने कहा है कि 'हिन्दुस्तानी' से गुजराती को हानि पहुँचेगी, और डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने कहा है कि 'हिन्दुस्तानी' का बँगला पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अहिन्दी लोग ज़रा सोच समझ कर काम करें। गांधी जी के कहने से भाषावेश में आकर अपने पैर में अपने हाथों से कुल्हाड़ी न मारें। (देखिये परिशिष्ट ११)

'हिन्दुस्तानी' और हिन्दुस्तानी-वाद से प्रांतीय भाषाओं को एक और

बड़ा भारी खतरा है। राष्ट्रभाषा 'हिन्दुस्तानी', या हिन्दुस्तानी की एक शैली उर्दू, और उसकी एक लिपि फारसी लिखने के बाद विभिन्न प्रांतों के सुसलमान अपनी अपनी मातृ-भाषायें छोड़ कर उर्दू अपना देंगे, उर्दू को ही अपनी मातृ-भाषा बनाने की चेष्टा करेंगे और माँग करेंगे कि प्रत्येक प्रांत में उर्दू की प्रांतीय जीवन में भी प्रांतीय भाषा के समस्त स्थान दिया जाय।

युक्त-प्रांत, विहार और मध्य-प्रांत में ऐसा हो चुका है, बम्बई, गुजरात और उड़िसा में आज ऐसा हो रहा है, बंगाल में शीघ्र ही होने वाला है, और यदि दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा अपने हिन्दुस्तानी प्रचार में सफल हो गई, तो दक्षिण में भी होकर रहेगा *। इस प्रकार प्रत्येक प्रांत की एकता खण्ड खण्ड हो जायगी, प्रत्येक प्रांत में हिन्दी-उर्दू का सा भगड़ा उठ खड़ा होगा, प्रत्येक प्रांत में भाषा की समस्या वही रूप धारण कर लेगी जो आज युक्त-प्रांत और विहार में है—बल्कि इससे भी भीषण क्योंकि हिन्दी और उर्दू की आधार-भूत मूल भाषा तो एक ही हैं परन्तु उर्दू और प्रांतीय भाषायें सर्वथा भिन्न भाषायें होंगी। इसके लिये जिम्मेदार होंगे स्वयं अहिन्दी जन जो आज हिन्दुस्तानी के जोर में अपने सुसलमान भाइयों को अपने पैने से उर्दू या 'हिन्दुस्तानी' और उर्दू लिपि लिखाना दुरवकाश समझते हैं। फिर जब उर्दू प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय भाषा के समान ही बन जायगी, तो उसके समक में आकर प्रांतीय भाषा के विहृत होने की शक्ति और भी बढ़ जायगी—उसी प्रकार जिस प्रकार आज हिन्दी प्रांतों में हिन्दी उर्दू ने प्रभावित हो रही है, और पंजाब में पंजाबी उर्दू ने प्रभावित हो रही है

* अभी हाल का (अक्टूबर, १९४६) का समाचार है कि आंध्र के सुसलमानों ने माँग की है कि उनकी शिक्षा का माध्यम तेलगू के बजाय उर्दू हो। वस्तुतः इस समाचार ने यहाँ जो कुछ कहा गया है उसकी पुष्टि कर दी है। इस माँग से अहिन्दी प्रांतों के सुसलमानों की मनोवृत्ति स्पष्ट है। (देखिये उत्तर—परिशिष्ट ३)।

(यहाँ तक कि आधुनिक पंजाबी ने अपना प्राचीन संस्कृत-बहुल स्वरूप बिलकुल त्याग कर अपने को अरबी फारसी के रंग में रंग लिया है) ।

यदि मुसलमानों ने मातृ-भाषा छोड़ कर उर्दू को न अपनाया, तो भी इतना तो निश्चित है कि वे राष्ट्र-लिपि फारसी सीखने के बाद अपनी अपनी मातृ-भाषायें प्रांतीय लिपियाँ छोड़ कर फारसी लिपि में लिखना आरम्भ करेंगे, प्रत्येक प्रांतीय भाषा की दो दो लिपियाँ हो जायँगी (एक 'हिन्दू लिपि' और एक 'मुस्लिम लिपि') और प्रत्येक प्रांत में हिन्दी लिपि-उर्दू लिपि जैसा भगड़ा पैदा हो जायगा* । मुसलमानों को कहने का बहाना मिलेगा कि इससे एक राष्ट्र-लिपि फारसी का प्रचार बढ़ता ही तो है, क्यों न हिन्दू भी अपनी अपनी मातृ-भाषा देवनागरी में लिखें जिससे देश में केवल दो लिपियाँ देवनागरी और फारसी लिपि रह जायँ ? अहिन्दी स्वयं सोच देखें, वे अपनी अपनी मातृ-लिपि छोड़ना चाहते हैं या नहीं, और प्रत्येक प्रांतीय भाषा की दो दो लिपियों का हो जाना चाहते हैं या नहीं । लिपि-विभाजन के बाद यह निश्चित

❧ यह कोरी कल्पना नहीं है । सिन्ध में मुसलमानों ने सिन्धी को देवनागरी छोड़कर फारसी लिपि में लिखना आरम्भ किया, और जब सिन्ध में उनका बहुमत हो गया तो उन्होंने हिंदू सिन्धियों को भी देवनागरी छोड़कर फारसी लिपि ग्रहण करने पर मजबूर किया । इसको केवल सौ वर्ष बीते हैं । फलतः सिन्धी की लिपि फारसी हो गई, और किसी को अब याद भी न रहा कि उसकी पुरानी लिपि क्या थी, यद्यपि पुरानी सिन्धी पुस्तकें देवनागरी में अब भी मिलती हैं । विभिन्न हिन्दू प्रान्तों में चूँकि मुसलमानों का अल्पमत होगा, प्रांतीय भाषाओं की लिपि अकेली फारसी लिपि तो नहीं होगी वरन् दो दो लिपियाँ होंगी—एक वर्तमान लिपि और एक फारसी लिपि । पंजाब में मुसलमान पंजाबी फारसी लिपि में लिखते हैं, यद्यपि सिख अपने धर्म के कारण अभी तक गुरुमुखी से चिपके हुये हैं । पंजाब विश्वविद्यालय ने पंजाबी की दोनों लिपियों को स्वीकार कर लिया है । गुरुमुखी आज ही केवल सिक्खों की धार्मिक लिपि कहलाती है, आश्चर्य नहीं यदि कुछ समय बाद पंजाबी की सांसारिक लिपि केवल एक, फारसी लिपि, मानी जाय । (देखिये उत्तर—परिशिष्ट ३) ।

है कि सुसलमान माँग करेंगे कि प्रान्तीय जीवन में भी प्रान्तीय भाषा की दोनों लिपियों को एक ला स्थान दिया जाय (जैसा आज सुसलमान हिन्दी प्रान्तों में कहते हैं, और दक्खि कांग्रेसी सरकार इस माँग को ही पूरा नहीं करती, बरन् हिन्दुओं को भी 'अरबी मातृ-भाषा' की दोनों लिपियाँ सीखने के लिये मजबूर करती है) । इस सबके लिये भी स्वयं अहिन्दी जन जिम्मेदार होंगे जो आज गांधीजी के इशारे से अपने पैने में उर्दू लिपि का प्रचार करना परम राष्ट्रीय कार्य समझते हैं । उर्दू लिपि के कारण प्रान्तीय भाषाओं में उच्चारण की भी जो दुर्दशा होगी, वह हम हिन्दी वाले प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं ।

प्रान्तीय भाषाओं की लिपि का विभाजन होने के बाद उनकी शैली का विभाजन होता भी अनिवार्य है । प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो शैलियाँ हो जायँगी—एक 'हिन्दू शैली' और एक 'मुस्लिम शैली'—विलकुल हिन्दी उर्दू की तरह (फिर क्या गांधीजी प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की 'सर्वस्वता' प्रकट करने का भगीरथ प्रयत्न करेंगे ?) । उर्दू शैली हिन्दी शैली से लिपि भिन्न होने के कारण ही भिन्न हुई ; 'मुस्लिम बंगला' का आन्दोलन अब तक लिपि एक रहने के कारण ही सफल न हो सका है (आगे की राम जाने—संभवतः बंगाल की लोगी सरकार अब 'मुस्लिम बंगला' फारसी लिपि में लिखेगी) । पारसियों की गुजराती रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की गुजराती से सर्वथा भिन्न है, और गोआ के ईसाइयों की कोंकणी रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की कोंकणी (देवनागरी में लिखित) से सर्वथा भिन्न है । लिपि और भाषा का अटूट सम्बन्ध होता है । जिस प्रकार रोमन लिपि के प्रभाव से अँगरेजी शब्द पारसी गुजराती और इताई कोंकणी में अनायास धर करते चले जाते हैं, उसी प्रकार फारसी लिपि के प्रभाव से उर्दू शब्द प्रान्तीय भाषाओं को मुस्लिम शैली में (फारसी लिपि में लिखित) अनायास धर करते चले जायँगे । 'हिन्दुस्तानी' की शब्दावली

फारसी लिपि के प्रभाव से सिन्धी अरबी फारसी में ऐसी रंगी है और

इसमें सहायक होगी। मुस्लिम शैलियों के बनने के बाद प्रत्येक प्रान्तीय भाषा में हिन्दी उर्दू का सा कलह आरम्भ होगा, और मुसलमान माँग करेंगे कि प्रान्तीय जीवन में उनकी शैली हिन्दू शैली के समकक्ष रखी जाय। (उस समय गांधीजी हिन्दुओं के आँसू पोछेंगे, और काका कालेलकरजी कहेंगे कि भारत में मुसलमान भी तो हैं, उनकी भाषा और संस्कृति को कैसे छोड़ा जा सकता है !)

अहिन्दुओं को ये सब बातें खोलकर समझानी चाहिये। उन्हें दूसरी ओर हिन्दी का महत्व भी समझा देना चाहिये। हिन्दी और देवनागरी के प्रचार से किसी प्रान्तीय भाषा को कोई ख़तरा नहीं, हिन्दी और देवनागरी के राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि होने पर प्रान्तीय भाषाओं को उल्टे और मदद मिलेगी। क्यों ? हिन्दी और देवनागरी पर मुसलमान मोहित नहीं, विभिन्न प्रान्तों के मुसलमान अपनी अपनी मातृ-भाषा छोड़कर हिन्दी अपनाना कभी न चाहेंगे, और न कभी अपनी अपनी मातृ-लिपि छोड़कर अपनी अपनी मातृ-भाषा देवनागरी में लिखना पसन्द करेंगे, और हिन्दुओं को तो अपनी अपनी मातृ-भाषा और मातृ-लिपि से अगाध प्रेम है ही (होना ही चाहिये), हिन्दुओं का कोई भाग तो अपनी मातृ-भाषा या मातृ-लिपि छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हिन्दी का किसी प्रान्तीय भाषा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता, यह भी स्पष्ट है। हिन्दी और विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं का हृदय एक है, आत्मा एक है और संस्कृति एक है। सब संस्कृत के वातावरण में

रंगती जा रही है कि न जाननेवाले समझने लगे हैं कि वह संस्कृत परिवार की भाषा ही नहीं है। फारसी लिपि के प्रभाव से मुस्लिम पंजाबी और उर्दू में केवल क्रियाओं और विभक्तियों का अन्तर रह गया है। सिन्ध में सिन्धी की हिन्दू शैली हिन्दुओं के अल्पमत में होने के कारण शर्क हो गई, सिक्खों की पंजाबी अभी तक जीवित है, विभिन्न प्रान्तों में प्रान्तीय भाषाओं की हिंदू शैलियाँ शर्क तो न होंगी, बस प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो शैलियाँ हो जायँगी। (देखिये उत्तर—परिशिष्ट ३) ।

हज़ारों साल तक बढ़ी हैं, सबने एक ही माता का दूध पिया है। हिन्दी तो किसी संस्कृत-निष्ठ या संस्कृत-बहुल प्रांतीय भाषा को विकृत कर ही नहीं सकती। यही कारण है कि श्रीयुक्त मुंशी जो हिन्दुस्तानी-प्रचार में गुजराती का अनिष्ट देखते हैं, और डा. सुनीतिकुमार चटर्जी जो हिन्दुस्तानी-प्रचार में बँगला का अनिष्ट देखते हैं, दोनों ही राष्ट्र-भाषा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी के प्रबल समर्थक हैं। प्रांतीय भाषाओं को हिन्दी से मद्ध बर्धो मिलेगी, यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये। प्राचीन काल में मध्य-देश की भाषा संस्कृत ने जो किया वह आज मध्य-देश की भाषा हिन्दी ही कर सकती है। 'हिन्दी संस्कृत की अखण्ड पीढ़ी में उतर आती है'। हिन्दी ही सांस्कृतिक एकता स्थापित कर सकती है। हिन्दी ही विभिन्न संस्कृत-निष्ठ और संस्कृत-बहुल प्रांतीय भाषाओं के पारस्परिक आदान प्रदान का साधन और साधन बन सकती है। हिन्दी ही परम शक्तिशालिनी, समृद्ध और विकसित सार्वदेशिक भाषा होकर प्राचीन काल में संस्कृत की भाँति और आधुनिक काल में अँगरेज़ी की भाँति विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का एक प्रधान समकाल बन सकती है। इस सम्बन्ध में संस्कृत का महत्त्व कम न होगा, किन्तु स्पष्ट है कि आज संस्कृत वह काम नहीं कर सकती जो हमने पहले किया है। आज हिन्दी ही विभिन्न प्रांतीय भाषाओं को एक सूत्र में पिरो सकती है। हिन्दी के अभाव में प्रांतीय भाषाएँ अलग अलग हो जायेंगी, छिन्न भिन्न हो जायेंगी, और उनकी सांस्कृतिक एकता नष्ट हो जायगी। दुनो रास्दों में, अहिन्दो जन 'हिन्दुस्तानी' द्वारा हिन्दी को जो हानि पहुँचायेंगे, वह कौट कर उन्हीं के सिर ही जायगी। "यदि हिन्दी टूट गई तो हिन्दू संस्कृति, आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति टूट जायगी"—ये शब्द प्रत्येक अहिन्दी के मानस-बटल पर अंकित कर देने चाहिये।

(३) हिन्दियों को अन्य प्रांतीय भाषाओं का गहरा अध्ययन करना चाहिये, उनकी समृद्धि, शक्ति और सौन्दर्य हिन्दी में लाना चाहिये, उनके

साहित्य का सच्चा दिग्दर्शक होता चला जायगा। शुरुआत हिन्दी वालों को करनी है। उन्हें प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यिकों से सम्पर्क बढ़ाना चाहिये, उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के शब्दों में उन्हें 'साहित्यिक सगाइयाँ' करनी चाहिये। हर्ष का विषय है कि हिन्दी साहित्य सभा, नई दिल्ली ने इस दिशा में कदम उठाया है। परन्तु काम बहुत बड़ा है। सब हिन्दीवालों को मिलकर प्रान्तीय भाषाओं में साहित्यिक मेलजोल बढ़ाने की योजना बनानी चाहिये। एक काम जो हिन्दी वाले तुरन्त कर सकते हैं वह है भारतीय साहित्य परिषद की पुनः स्थापना और 'हंस' जैसे पत्र का पुनः संचालन। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि श्रीमन्त्रि की 'सर्व-भाषा-मंदिर योजना' शीघ्र कार्य रूप में परिणत हो।

ऊपर के काम से हिन्दी के राष्ट्र-भाषा-पद प्राप्त करने में भी वह सहायता मिलेगी जो किसी अन्य उपाय द्वारा संभव नहीं। अन्य भाषा-भाषियों पर हिन्दी का महत्व अपने आप प्रकट हो जायगा। 'हाथ कंगन को आरसी क्या' ? वे देख लेंगे कि जो काम हिन्दी कर सकती है, वह न उर्दू कर सकती है और न 'दोनों लिपि' वाली 'हिन्दुस्तानी'।

(४) एक हिन्दी प्रचार विद्यालय खोलना चाहिये जो हिन्दी प्रचारक तैयार करे। इस विद्यालय में केवल वे ही लिये जायँ जिनकी मातृ-भाषा हिंदी हो। इस विद्यालय की परीक्षा पास करके प्रचारक विभिन्न अहिन्दी प्रान्तों में जाकर राष्ट्र-भाषा हिंदी का संगठित रूप से प्रचार करें। अच्छा हो यदि यह विद्यालय सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के तत्वावधान में खोला जाय। (हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वधा भी हिन्दुस्तानी प्रचारक तैयार करने के लिये वधा में एक विद्यालय खोल रही है)। इस समय हिन्दियों का कर्तव्य है कि वे विभिन्न प्रांतों में राष्ट्र-भाषा हिंदी के प्रचार के काम में हाथ बटावें। राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के संगठन पर हिन्दुस्तानी वालों के जो प्रहार हो रहे हैं, उनका प्रतिकार हिन्दियों को करना होगा। राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति

रेडियो-आन्दोलन के विषय में एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिये। सम्मेलन ने रेडियो से सहयोग करनेवाले साहित्यिकों का बहिष्कार किया सो तो ठीक, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता उन हिन्दी साहित्यिकों का बहिष्कार करने की है जो रेडियो में जाकर रेडियो वालों के समझाने फुसलाने से, डराने धमकाने से या पैसे के लालच से या रेडियो वालों को खुश करने के इरादे से अपनी स्वाभाविक हिन्दी शैली छोड़कर रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' बूकने लगते हैं। वे हिन्दी पर शर्म का ऐसा बोझ लादते हैं जो किसी के उठाने नहीं उठ सकता। जिन स्वाभिमानी हिन्दी वक्ताओं या लेखकों से रेडियो वाले अपनी शैली में परिवर्तन करने के लिये कहें, उन्हें उचित है कि वे पांडुलिपि रेडियो वालों के सिर पर पटक कर पत्रों में खबर दें, और रेडियो वालों की नीति का भण्डाफोड़ करें। किसी आँगरेजी वाले से तो रेडियो वाले कुछ कहने का साहस न करेंगे। हमारे ही देश में हमारी भाषा का यह अपमान !

रेडियो के बाद सिनेमा का नम्बर है। जो जो बातें रेडियो के लिये कही जा सकती हैं, वही सिनेमा के लिये कही जा सकती हैं। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ रेडियो सरकार द्वारा संचालित है, वहाँ सिनेमा आदर्शहीन पूँजीपतियों द्वारा संचालित है, जहाँ हिन्दी पत्र रेडियो की नीति का विरोध करना अपना कर्तव्य समझते हैं, वहाँ वे सिनेमा की भाषा-नीति के विरुद्ध एक शब्द कहना नहीं चाहते। क्यों, यह राम जाने।

यदि हिन्दी पत्र पैसे और विज्ञापन के लालच में न आकर चित्रों की भाषा की निष्पक्ष और मुँहफट समालोचना करें, तो कोई कारण नहीं उनकी भाषा क्यों न सुधरे। ऐसा करने के बजाय वे बँधे हुये लेखकों की समालोचनाएँ छाप देते हैं जिन्हें 'हिन्दुस्तानी' के सिवा कोई दूसरा शब्द नहीं मालूम, जो चित्र की भाषा की ओर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं समझते, और यदि ध्यान देते हैं, तो 'हुमायूँ' की भाषा को भी 'हिन्दुस्तानी' लिख

देते हैं, जनता बेचारी जाकर उस 'हिन्दुस्तानी' को समझे चाहे न समझे ! अब तक जितने तथाकथित 'हिन्दुस्तानी' चित्र बने हैं, उनमें से अधिकांश की भाषा 'अच्छी उर्दू', खराब उर्दू, भद्दी उर्दू, खराब हिन्दी या भद्दी हिन्दी' है, अच्छी हिन्दी के चित्र शायद ही कुछ बने हैं। यदि चित्र-समालोचक सब चित्रों की भाषा को इस 'हिन्दुस्तानी' का पासपोर्ट न देकर चित्र की भाषा को इन्हीं विशेषणों से सम्बोधित करें, तो जनता का भी लाभ हो और फिल्म निर्माताओं का भी। हिन्दी जनता या तो एक 'उर्दू' चित्र देखने ही न जायगी (वे ही जायेंगे जो उर्दू समझ सकते हैं), और यदि जायगी भी तो उसे मालूम रहेगा कि वह किस भाषा का चित्र देख रही है। हिन्दी जनता को भी समायें करके चित्रों की भाषा के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करना चाहिये। वह सब होने पर सिनेमा के मालिक पूँजीपतियों को हवा का रख पहचानते देर न लगेगी। जब वे हमारे पैसे से ही मोटे होते हैं, तो उन्हें वह देना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, वह हम बतलावें तो।

हिन्दी वालों को अधिकाधिक संख्या में सिनेमा कम्पनियाँ खोलनी चाहिये, जो चित्रों में हिन्दी और हिन्दी संस्कृति की रक्षा करें और मुद्रि का पूरा ध्यान रखें। जनता का सांस्कृतिक स्तर उठने वाला है, जनता शीघ्र ऐसे चित्रों की माँग करेगी। हिन्दी साहित्यिकों और लेखकों को भी अधिकाधिक संख्या में सिनेमा में प्रवेश करना चाहिये, और सिनेमा की दुनिया पर अधिकार करना चाहिये। सिनेमा दुरदुराने से नहीं, अपनाने से सुधरेगा। सिनेमा का राष्ट्र की शिक्षा और सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम में इतना ऊँचा स्थान है कि वह अच्छे से अच्छे साहित्यिक के सर्वथा योग्य है, और यदि इस समय नहीं है तो अब हमें बनाना है। परन्तु सिनेमा के वर्तमान या भविष्य के हिन्दी लेखकों से हमारा एक नम्र निवेदन है। वे अपनी कला को सिनेमा की टेक्नीक के अनुकूल अवश्य बनावें।

परन्तु कृपा करके वे अपनी भाषा की हत्या न करें। उन्हें सदैव अच्छी हिन्दी में लिखने का प्रण करना चाहिये। जब उनकी हिन्दी हिन्दी-प्रदेश की बहुसंख्यक जनता की भाषा और वास्तविक राष्ट्र-भाषा है तो उन्हें डर क्या, हिन्दी लिखने में संकोच क्यों ? उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी हिन्दी बिगाड़ना स्वीकार न करना चाहिये। उन पर बहुत कुछ हद तक हिन्दी का भविष्य निर्भर है, फिर वे हिन्दी की अवहेलना कैसे कर सकते हैं ? चित्रों में हिन्दी शब्दों के साथ-साथ लगे हुये क्लिष्ट कर्ण-कटु अरबी फारसी शब्दों को सुनकर हृदय में शूल सा चुभता है। 'रामशास्त्री', 'चित्रा-बली', 'हमराही' जैसे चित्रों की भाषा सुनकर अत्यन्त क्लेष होता है। यह बात नहीं है कि हिन्दी लेखकों को अपनी भाषा से प्रेम न हो, परन्तु वे बहुत जल्दी, ज़रा से इशारे पर अपने शब्द छोड़ देते हैं और विदेशी शब्द भट अपना लेते हैं—लिखने में भी और बोलचाल में भी। उन्हें इस मामले में उर्दू लेखकों से शिक्षा लेनी चाहिये जो सरल से सरल उर्दू लिखना मंजूर कर लेंगे, परन्तु लिखेंगे उर्दू ही—एक भी हिन्दी शब्द नहीं अपना सकते।

(६) हिन्दी प्रान्तों के अथवा अहिन्दी प्रान्तों के हिन्दी पत्रों को हिन्दुस्तानी प्रचार और हिन्दुस्तानी वालों के विचारों के प्रचार का साधन कदापि न बनने देना चाहिये। हिन्दुस्तानी वालों के पास वैसे ही अपरिमित साधन हैं, कम से कम हिन्दी पत्र तो उन्हें योग न दें और हिन्दी का ध्यान रखें। उन्हें हिन्दुस्तानी-प्रचार से सम्बन्धित सब समाचार तो निष्पक्ष होकर देना चाहिये (यह समाचार पत्रों का प्रथम कर्त्तव्य है), परन्तु उन्हें 'हिन्दुस्तानी' की वकालत न करना चाहिये, और 'हिन्दुस्तानी' को वकालत करने वाले लेख, 'हिन्दुस्तानी' में लिखे हुये लेख, सूचनायें, आदि न छापना चाहिये। महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के समाचार ही छापना बन्द कर दिया; इतना ही नहीं,

उन्होंने उसे बदनाम करने का प्रयत्न किया (देखिये परिशिष्ट १०) । हिंदी पत्रों को इसका कम से कम इतना जवाब तो देना चाहिये । हिन्दी पत्रों को अपने हाथ से अपने गले में मौत का फन्दा न डालना चाहिये ।

हिंदी पत्रों को इससे अधिक करना है । उन्हें हिंदी की बकासत करना चाहिये, हिंदुस्तानी-वाद का विरोध करना चाहिये (इस प्रकार नहीं कि उसका और विज्ञापन हो), हिंदुस्तानी वालों की कारगुजारी में, उनके हथकंडों से और कार्यकलाप से हिंदी जनता को परिचित कराना चाहिये, हिंदी जनता को 'हिंदुस्तानी' के खतरे से सूचित करना चाहिये, हिंदी की रक्षा में पूर्ण सहयोग देना चाहिये, 'हरिजनसेवक' × और 'नया हिन्द' + जैसे 'हिन्दुस्तानी' के पत्रों से हिन्दी जनता को सावधान करना चाहिये, और हिन्दी प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों की 'हिंदुस्तानी' विषयक नीति का तीव्र विरोध करना चाहिये । आधुनिक युग में प्रेस की बहुत बड़ी शक्ति है । हमें हिंदी प्रेस से पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये ।

हिन्दियो, उठो, जागो, अपनी शक्ति एकत्र करो और हिन्दी की रक्षा में, हिन्दी की सेवा में जुट जाओ । तुम हिंदी भाषा की उपेक्षा करके एक शताब्दी तक अग्रमानित हुये, लज्जित हुये और पतन के गर्त में और

* यदि अँगरेज़ी पत्रों को कोई ख़राब अँगरेज़ी में लेख या सूचना लिख कर भेजे, तो अँगरेज़ी पत्र तो उसे न छापेंगे, और यदि छापेंगे तो उसकी भाषा शुद्ध करके छापेंगे । हिन्दी पत्र ही ख़राब हिन्दी, जानबूझ कर ख़राब की हुई हिन्दी अर्थात् 'हिन्दुस्तानी' के लेख, आदि क्यों छापें ? हिन्दी पत्रों को भी अपनी भाषा का उतना ही ध्यान रखना चाहिये । चूँकि उन ख़राब हिन्दी के लिखने वाले कोई पं० सुन्दरलाल या डा० ताराचंद हैं, इस कारण वह ग्राह्य थोड़े ही हो जायगी । (देखिये पृष्ठ ५६-५७)

× देखिये परिशिष्ट १४ ।

+ पं० सुन्दरलाल और डा० ताराचंद द्वारा सम्पादित 'हिन्दुस्तानी' का एक नया मासिक (देखिये पृष्ठ १५१) ।

परन्तु कृपा करके वे अपनी भाषा की हत्या न करें। उन्हें सदैव अच्छी हिन्दी में लिखने का प्रण करना चाहिये। जब उनकी हिन्दी हिन्दी-प्रदेश की बहुसंख्यक जनता की भाषा और वास्तविक राष्ट्र-भाषा है तो उन्हें डर क्या, हिन्दी लिखने में संकोच क्यों ? उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी हिन्दी बिगाड़ना स्वीकार न करना चाहिये। उन पर बहुत कुछ हद तक हिन्दी का भविष्य निर्भर है, फिर वे हिन्दी की अवहेलना कैसे कर सकते हैं ? चित्रों में हिन्दी शब्दों के साथ-साथ लगे हुये क्लिष्ट कर्ण-कटु अरबी फारसी शब्दों को सुनकर हृदय में शूल सा चुभता है। 'रामशास्त्री', 'चित्रावली', 'हमराही' जैसे चित्रों की भाषा सुनकर अत्यन्त क्लेष होता है। यह बात नहीं है कि हिन्दी लेखकों को अपनी भाषा से प्रेम न हो, परन्तु वे बहुत जल्दी, ज़रा से इशारे पर अपने शब्द छोड़ देते हैं और विदेशी शब्द ऋट अपना लेते हैं—लिखने में भी और बोलचाल में भी। उन्हें इस मामले में उर्दू लेखकों से शिक्षा लेनी चाहिये जो सरल से सरल उर्दू लिखना मंज़ूर कर लेंगे, परन्तु लिखेंगे उर्दू ही—एक भी हिन्दी शब्द नहीं अपना सकते।

(६) हिन्दी प्रान्तों के अथवा अहिन्दी प्रान्तों के हिन्दी पत्रों को हिन्दुस्तानी प्रचार और हिन्दुस्तानी वालों के विचारों के प्रचार का साधन कदापि न बनने देना चाहिये। हिन्दुस्तानी वालों के पास वैसे ही अपरिमित साधन हैं, कम से कम हिन्दी पत्र तो उन्हें योग न दें और हिन्दी का ध्यान रक्खें। उन्हें हिन्दुस्तानी-प्रचार से सम्बन्धित सब समाचार तो निष्पन्न होकर देना चाहिये (यह समाचार पत्रों का प्रथम कर्तव्य है), परन्तु उन्हें 'हिन्दुस्तानी' की वकालत न करना चाहिये, और 'हिन्दुस्तानी' को वकालत करने वाले लेख, 'हिन्दुस्तानी' में लिखे हुये लेख, सूचनायें, आदि न छापना चाहिये। महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के समाचार ही छापना बन्द कर दिया; इतना ही नहीं,

उन्होंने उसे बदनाम करने का प्रयत्न किया (देखिये परिशिष्ट १०) । हिंदी पत्रों को इसका कम से कम इतना जवाब तो देना चाहिये । हिन्दी पत्रों को अपने हाथ से अपने गले में मौत का फन्दा न डालना चाहिये ।

हिंदी पत्रों को इससे अधिक करना है । उन्हें हिंदी की वकालत करना चाहिये, हिंदुस्तानी-वाद का विरोध करना चाहिये (इस प्रकार नहीं कि उसका और विज्ञापन हो), हिंदुस्तानी वालों की कारगुजारी से, उनके हथकंडों से और कार्यकलाप से हिंदी जनता को परिचित कराना चाहिये, हिंदी जनता को 'हिंदुस्तानी' के खतरे से सूचित करना चाहिये, हिंदी की रक्षा में पूर्ण सहयोग देना चाहिये, 'हरिजनसेवक'× और 'नया हिन्द' जैसे 'हिन्दुस्तानी' के पत्रों से हिन्दी जनता को सावधान करना चाहिये, और हिन्दी प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों की 'हिंदुस्तानी' विषयक नीति का तीव्र विरोध करना चाहिये । आधुनिक युग में प्रेस की बहुत बड़ी शक्ति है । हमें हिंदी प्रेस से पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये ।

हिन्दिबो, उठो, जागो, अपनी शक्ति एकत्र करो और हिन्दी की रक्षा में, हिन्दी की सेवा में जुट जाओ । तुम हिंदी माता की उपेक्षा करके एक शताब्दी तक अपमानित हुये, लज्जित हुये और पतन के गर्त में और

* यदि अँगरेज़ी पत्रों को कोई ख़राब अँगरेज़ी में लेख या सूचना लिख कर भेजे, तो अँगरेज़ी पत्र तो उसे न छापेंगे, और यदि छापेंगे तो उसकी भाषा शुद्ध करके छापेंगे । हिन्दी पत्र ही ख़राब हिन्दी, जानबूझ कर ख़राब की हुई हिन्दी अर्थात् 'हिन्दुस्तानी' के लेख, आदि क्यों छापें ? हिन्दी पत्रों को भी अपनी भाषा का उतना ही ध्यान रखना चाहिये । चूँकि उन ख़राब हिन्दी के लिखने वाले कोई पं० सुन्दरलाल या डा० ताराचंद हैं, इस कारण वह ग्राह्य धोड़े ही हो जायगी । (देखिये पृष्ठ २६-२७)

× देखिये परिशिष्ट १४ ।

+ पं० सुन्दरलाल और डा० ताराचंद द्वारा सम्पादित 'हिन्दुस्तानी' का एक नया मासिक (देखिये पृष्ठ १२१) ।

गहरे गिरते गये। अब तुम फिर हिंदी नहीं छोड़ सकते, उसकी हिन्दुस्तानी नहीं कर सकते। प्राचीन काल में संस्कृत ने तुम्हें सर्वोच्च स्थान पर बैठाया था, आज तुम हिन्दी को भी विकृत नहीं होने दे सकते। “संस्कृत के स्वर्ग का संचय आज गिरते गिरते तुम्हारी हिंदी की आधार-शिला पर रुका है।” हिंदी, शुद्ध हिंदी तुम्हारी कम से कम आवश्यकता है—तुम शुद्ध हिंदी से कम कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुमने हिंदी को विकृत होने दिया, तो अन्य प्रान्तों के वासी तो अपनी अपनी शुद्ध संस्कारी भाषाओं से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, केवल तुम्हीं एक अनागे होगे। तुम हिंदी की गोद में पलकर बड़े हुये हो, हिंदी के अंचल में तुम्हारे पूर्वजों के वैभव का शृंगार लिपा हुआ है, तुम उसे भुत्ताकर जीवित नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, हिंदी के साथ, उसकी शुद्धता के साथ सम्पूर्ण भारत की, विशेष रूप से सम्पूर्ण हिंदू भारत की संस्कृति जुड़ी हुई है। हिंदी पर हिंदुत्व और हिन्दुस्तान का भविष्य निर्भर है। यदि आज कुछ अहिंदी भाई इने भूल बैठे हैं तो तुम्हें तो न भूलना चाहिये, तुम्हें तो अपने और अपनी भाषा के ऐतिहासिक महत्त्व का ध्यान रखना चाहिये।

×

×

×

हिंदी पर ख़तरा आना चाहता है और वह भी राष्ट्रीयता का जामा पहन कर। ख़तरे की घंटी बज रही है। शिकोहाबाद में युक्तप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का उद्घाटन करते हुये श्रीसम्पूर्णानन्दजी ने व्यर्थ ही नहीं कहा, “हिंदी ख़तरे में है। वह सहायता के लिये पुकार रही है।” हिन्दी वालो, सावधान !

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

हिन्दी की कृतियों में मुसलमान पात्रों का उर्दू में कथोपकथन

(लेखक—श्री शान्तिकुमार एम० एम० सी०)

हिन्दी में कहानियों, उपन्यासों, इत्यादि में मुसलमान पात्रों से उर्दू में वातचीत कराने की एक परिपाटी सी हो गई है। हिन्दी के कितने ही प्रतिष्ठित लेखक ऐसा करते हैं। प्रेमचन्द को जाने दीजिये। आजकल के लेखकों में उदाहरण के लिये राय कृष्णदाम के कहानी-संग्रह “आँखों की थाह” की ‘नई दुनिया’ शीर्षक कहानी को लीजिये। इस कहानी में दो ही पात्र हैं—चिरागी और गजरा। दोनों मुसलमान हैं। कहानी के आरम्भ से लेकर अंत तक उन दोनों का कथोपकथन चलता रहता है। एक प्रकार से यह कथोपकथन ही कहानी का विषय है। लेखक बीच बीच में बर्णन, टीका टिप्पणी, इत्यादि तो शुद्ध हिन्दी में करता है, परन्तु चिरागी और गजरा की वातचीत ठेठ उर्दू में होती है। इस वातचीत में प्रयुक्त शब्दों के कुछ नमूने ये हैं—

“निसार, रहमत, खसलत, इजहार, मुवितला, तलब, दोज़ाबी, मेज़बानी, मिन्मत, ज़हमत, गुमराह, बेखुदी, दयानतदारी, आनाकलाना”, इत्यादि। चिरागी और गजरा के कथोपकथन को छोड़ कर कहानी में बहुत कम बच रहता है। ऐसी अवस्था में यह सोचने की बात है कि इस कहानी को हिन्दी की कहानियों के संग्रह में क्यों स्थान दिया गया। केवल हिन्दी लिपि में छान देने से तो कहानी हिन्दी की हो नहीं जायगी। किसी भी पत्र,

पत्रिका या पुस्तक को उठा कर देखिये, जहाँ कहीं भी मुसलमान पात्र आ जाते हैं, वहाँ उनका वार्तालाप प्रायः उर्दू में कराया जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा मालूम होता है कि लेखक अपना उर्दू का पांडित्य दिखाने के लिये ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि सुगम, मुसलमानों में भी प्रचलित हिन्दी शब्दों के होते हुये भी अरबी फारसी शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है।

इस परिपाटी के बचाव में लेखक ने केवल एक ही उक्ति सुनी है। वह यह कि ऐसा स्वाभाविकता और वास्तविकता (local colour) लाने के लिये किया जाता है। यह उक्ति बिल्कुल सारहीन है। इसका मतलब तो वह होगा कि हिन्दी की कृतियों में अँगरेज़ी पात्रों से अँगरेज़ी में बातचीत कराई जाय, चीनी पात्रों से चीनी में, अरबों से अरबी में, या कम से कम हिन्दी में क्रमशः अँगरेज़ी, चीनी, और अरबी के खूब शब्द चुसे जाँय। किन्तु वास्तविकता के ये भक्त ऐसा करते तो नहीं देखे जाते। इन्होंने तो केवल मुसलमानों के लिये ही वास्तविकता रिजर्व कर रखी है, मानों सब मुसलमान उर्दू ही बोलते हैं, और कोई हिन्दू उर्दू नहीं बोलता। इस उक्ति का मतलब यह भी होगा कि या तो हिन्दी के पाठक और लेखक दोनों ही संसार भर की भाषाओं के पंडित हों या हिन्दी वाले हिन्दी प्रदेशों और हिन्दी भाषियों को छोड़कर संसार के किसी अन्य देश या जाति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की आशा ही छोड़ दें। कम से कम मुसलमानों को तो तभी लाया जा सकेगा जब हिन्दी के पाठक और लेखक दोनों उर्दू के भी पंडित हों। और, बंगाली हिन्दुओं को भी तभी रखा जा सकेगा जब बँगला का पूरा ज्ञान हो, और मद्रासी हिन्दुओं को रखने के लिये तामिल और तेलगू के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। ऐतिहासिक पात्रों से कथोपकथन कराना तो बिल्कुल असंभव हो जायगा, क्योंकि अभाग्यवश यह मालूम करने का कोई साधन नहीं है कि ये पात्र उर्दू-ए-मुअल्ला बोलते थे, या खड़ी बोली हिन्दी या कुछ और।

आश्चर्य तो इस बात का है कि इस 'लोकल-कलर' का सबसे अधिक खयाल हिन्दी वालों को है। आज तक कोई अँगरेज़ी का लेखक अँगरेज़ी की कृतियों में अँगरेज़ी को छोड़कर हिन्दुस्तानी पात्रों से किसी भारतीय भाषा में या चीनियों से चीनी भाषा में बातचीत कराता हुआ देखने में नहीं आया। यही बात सत्तरवीं अन्य भाषाओं के विषय में कही जा सकती है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, उर्दू के लेखक भी ऐसी शक्ती नहीं करते कि हिन्दू पात्रों से हिन्दी में बातचीत करावें। कुछ ऐसे शब्दों की बात दूसरी है जो एक देश विशेष अथवा जाति विशेष में ही सम्बन्ध रखते हैं और किसी विशेष गुण या वस्तु को जानने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं और जिनका उनकी ध्वनि नष्ट किये बिना सरलता से अनुवाद नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों का अर्थ प्रायः कोष्ठकों में या पाद-टिप्पणियों में दसष्ट कर दिया जाता है, और अँगरेज़ी में प्रायः ऐसे शब्दों को इटैलिक्स (italics) में यह जानने के लिये लिखा जाता है कि ये विदेशी शब्द हैं, और किसी विशेष कारण से ही प्रयुक्त किये गये हैं। लेकिन हिन्दी की कृतियों में मुसलमानों की बातचीत उर्दू में बेवटके और बेरोकटोक कराई जाती है, और उर्दू शब्दों के अर्थ को भी स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि यह समझा जाता है कि यह तो हिन्दी ही है और हिन्दी-पाठक इसे समझते ही होंगे, और यह लेखक की मेहरबानी है कि उसने आदि से अन्त तक सब जगह ऐसी हिन्दी नहीं लिखी !

इस सम्बन्ध में दो एक बातें और विचारणीय हैं। 'नई दुनिया' शीर्षक कहानी में चिरागी और गजरा समाज की बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं। इन निम्न श्रेणियों में शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली उर्दू नहीं बोली जाती, फिर इनका साहित्यिक उर्दू में बोलना ही कहाँ तक स्वाभाविक है और कहाँ तक वास्तविकता से सम्बन्ध रखता है? ये दोनों व्यक्ति बनारस के रहनेवाले दिखाये गये हैं। तो क्या इनसे पूर्वी या किसी और देहाती बोली में बोलवाना कहीं

ज्यादा स्वाभाविक न होना ? खड़ी बोली बोली ही कितने क्षेत्र में जाती है ? यदि 'लोकल कलर' देने के यही माने हैं कि पात्र वास्तविक भाषा में बोले तो खड़ी बोली के प्रदेश के बाहर के सब पात्रों का कथोपकथन खड़ी बोली में न होकर देहाती बोलियों में होना चाहिये । ऐसा क्यों नहीं किया जाता ? अप्रैल, १९४४ की 'माधुरी' में श्रीयुत शैल लिखित एक कहानी 'मिलन' छपी है । इस कहानी के पात्र युनिवर्सिटी के तीन छात्र सुरेश, जमीला और रम्लीक हैं । जमीला और रम्लीक का बातें ठेठ उर्दू में होती हैं । युनिवर्सिटी के छात्र कहीं ठेठ उर्दू या ठेठ हिन्दी में बात करते नहीं देखे जाते । इनके कथोपकथन में तो 'लोकल कलर' तब होता जब श्रीयुत शैलजी इनसे बात-चीत आधी अँगरेजी आधी हिन्दी यानी 'इङ्गलिस्तानी' नामक भाषा में करते । आजकल के शिक्षित वर्ग की तो यही भाषा है ।

यह तर्क भी कि उर्दू हिन्दी की एक शैली विशेष ही है और इसलिये हिन्दी की कृतियों में मुसलमान पात्रों से उर्दू का प्रयोग कराना क्षम्य है, कुछ नाने नहीं रखता । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से चाहे वह ठीक हो, परन्तु व्यवहार में आज उर्दू हिन्दी की शैली विशेष नहीं कही जा सकती । एक भाषा की दो शैलियाँ संसार के किसी देश में दो लिपियों में नहीं लिखी जाती और न उनकी आपस में गुटबन्दी होती है, न उनके लेखक अलग-अलग होते हैं और न उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अलग-अलग होती है, और न ऐसा होता है कि जो पाठक भाषा की एक शैली समझ सकता हो वह कोई दूसरी शैली न समझे । आज हिन्दी और उर्दू में तो इतना अन्तर है (लिपि-भेद तथा कुछ अन्य छोटी बातों को छोड़कर भी) कि क्रियाओं, क्रिया-विशेषणों, विभक्तियों तथा थोड़े से अन्य शब्दों को छोड़कर हिन्दी और उर्दू की शब्दावलियाँ विलकुल भिन्न हैं । एक भाषा की दो शैलियों में कहीं ऐसा अन्तर नहीं होता, और न दो शैलियों में इस प्रकार धर्म की भित्ति पर भेद किया जाता है । मुसलमानों से उर्दू और हिन्दुओं से हिन्दी बुलवाने

के माने तो यही हैं कि ये दो शैलियाँ दो धर्मों के अनुयायियों के लिये रिज़र्व हैं, और हम सहमत हैं कि हिन्दी केवल हिन्दुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की, और हिन्दी के पाठक तथा लेखक हिन्दी और उर्दू दोनों जानते और समझते हैं।

एक विकट कठिनाई और है। अगर एक हिन्दू पात्र की मुसलमान पात्र से बातचीत कराना पड़े तो किस भाषा में कराई जाय ? अगर हिन्दू पात्र हिन्दी में बोले और मुसलमान पात्र उर्दू में जवाब दे तब तो अत्यन्त हास्यास्पद होगा। पढ़ने वाले या सुनने वाले को अत्यन्त भद्दा भी लगेगा। दुनिया भर में सब जगह दो मनुष्य एक ही भाषा में बात करते हैं और एक ही शब्दावली प्रयुक्त करते हैं। भाषा है ही आपस में भाव प्रकट करने के माध्यम का नाम। यदि यही माध्यम दो व्यक्तियों का भिन्न-भिन्न है, तो उनकी आपस में बातचीत कैसी ? शलत सिद्धान्त पर चलने से यह कठिनाई अवश्य पड़ेगी। इस सिद्धान्त को माननेवाले कुछ लेखकों ने इस कठिनाई को ऐसे अवसरों पर हिन्दू पात्र और मुसलमान पात्र दोनों से उर्दू दुलबा कर हल किया है ! 'मिलन' कहाना में सुरेश जमीला या रफीक से उर्दू में बात करता है। इसके माने यह हुये कि हिन्दू जब आपस में बात करें तब तो हिन्दी में, लेकिन जब मुसलमानों से बात करें तब उर्दू में, और मुसलमान आपस में भी उर्दू में बात करें, अर्थात् उर्दू ही राष्ट्र-भाषा या कामन भाषा है क्योंकि इसे हिन्दू भी बोल सकते हैं, मुसलमान तो बोलते ही हैं और हिन्दी को मुसलमान बोल नहीं सकते ! ऐसी दशा में राष्ट्र-भाषा के प्रश्न पर हिन्दी उर्दू को लेकर हाथ तोड़ा मचाना व्यर्थ है, क्योंकि हिन्दी उर्दू एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं जिनमें से उर्दू शैली हिन्दू मुसलमान दोनों ही समझते हैं ! आश्चर्य तो यह है कि फिर भी हिन्दी उर्दू का अलग-अलग बोल पीटा जाता है, यू० पी० शिक्षा-विभाग द्वारा लड़कियों के लिये उर्दू अनिवार्य रूप से द्वितीय भाषा बनाये जाने पर हिन्दी पत्रों में बवंडर उठाया

जाता है, और महासभा डेढ़ हजार वालंटियर उर्दू का विरोध करने के लिये जयपुर भेजती है।

हिन्दी के ऐतिहासिक लेखों तथा पुस्तकों में भी यही बात देखने में आती है। हिन्दू या भारतीय पात्र तो हिन्दी में बोलते हैं लेकिन सब विदेशी पात्र, वे चाहे यूनानी हों, चाहे दूण चाहे अँगरेज़, उर्दू में बोलते हैं। उदाहरण-स्वरूप श्रीगुरुदेवविहारी मिश्र कृत 'पुष्प मित्र' का नाम लेना काफ़ी होगा। ऐसे लेखों तथा पुस्तकों में भी जब हिन्दू या भारतीय पात्र किसी विदेशी पात्र से बात करता है तो दोनों उर्दू में बोलते हैं। यह भी भुला दिया जाता है कि सदैव विजित विजेता की भाषा अपनाता है, विजेता विजित की नहीं। हिन्दी में तो ऐसा अन्वेष है कि जब यूनानी सेनापति सेल्यूकस चन्द्रगुप्त के द्वार में पकड़ कर लाया जाता है तब चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस का संवाद उर्दू में होता है—दोनों उर्दू बोलते हैं। हृद हो गई! सांगंश यह कि हिन्दी के ऐतिहासिक विषयों (मुसलमान पात्रों से रहित अथवा सहित) पर लिखने के लिये और उन्हें समझने के लिये भी हिन्दी के लेखकों तथा पाठकों को उर्दू का पंडित होना आवश्यक है। ये सब बातें करके हिन्दी वाले सबके सामने अपनी मूर्खता तो प्रकट करते ही हैं, अपने मुँह से हिन्दी के मुकाबले उर्दू को महानता देते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि हिन्दी तो केवल हिन्दू भारतीयों की भाषा है, उर्दू दुनिया भर के सब विदेशियों की भाषा है, और भारतीयों तथा विदेशियों की 'कामन भाषा' भी है (जिसे हिन्दी के सब पाठक और लेखक सदैव जानते और समझते रहे हैं और अब भी जानते और समझते हैं!)।

मैं समझता हूँ कि जिन कारणों का ऊपर निर्देश किया गया है, वे यह दिखलाने के लिये पर्याप्त हैं कि हिन्दी कृतियों में मुसलमान या विदेशी पात्रों से आपस में, या हिन्दुओं और मुसलमानों, अथवा भारतीयों और विदेशियों के बीच में उर्दू में बातलाप कराना बिल्कुल अनुचित, मूर्खता-

पूर्ण और संसार की सभी भाषाओं के नियमों के विरुद्ध है। भाषा विचारों को प्रकट करने का एक साधन है, और भाषा यह तभी कर सकती है जब उसका एक प्रचलित, सर्वमान्य और निश्चित स्वरूप हो। जब हम किसी भाषा में अपने विचार प्रकट करने बैठते हैं तो हम काल के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार भाषा नहीं बदलते चल सकते। बात चाहे आज की हो, चाहे हजार वर्ष पहले की, व्यक्ति चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, भाषा का स्वरूप वही रहता है। फिर हिन्दी में ही मुसलमानों ने या विदेशियों ने उर्दू में कथोपकथन क्यों कराये जाते हैं? आशा है विद्वान लेखक इस ओर ध्यान देंगे, और हिन्दी को इस दोष से बचावेंगे। कम से कम पत्रों के सम्पादक यह कर सकते हैं कि इस दोष से दूषित लेखों को लौटाने का कारण बताते हुये वापस कर दें, या उनके उर्दू संवादों को हिन्दी में अनुवाद करके छापें।

(नितम्बर, १९४५ की 'माधुरी' से)

परिशिष्ट २

THE 'VERNACULAR' OF UNITED PROVINCES

(*By Ravi Shankar Shukla*)

The Government of the United Provinces has reminded its subordinates of the order that the use of the obnoxious term 'vernacular' should be abandoned. So far so good. But what is the 'vernacular' of the U. P., i.e., which name is to take the place of the term 'vernacular' when applied to the language of this province ? The Government has suggested the name 'Hindustani'. But 'Hindustani' is not the vernacular or the mass language of the U.P. The vernacular or the mass language of this province can only be called by the name 'Hindi'—a name which Muslims gave to it many centuries ago and which has superseded its old name 'Bhasha' or 'Bhakha'. Hindustani, also called by the names 'Dehlavi' and 'Khariboli', is a dialect of Western Hindi and is spoken in the Upper Gangetic Doab. Hindustani is thus the vernacular or mass language of only a few districts round Delhi. In other districts of the U. P., various dialects of Western Hindi like Braj, Bundeli, Kanauji and Eastern Hindi, Avadhi or Kosali, are spoken. The vernacular or the mass language of the province is therefore Hindi. Any linguist will say that. In the Language Survey of India the language of this province has

been identified as Western and Eastern Hindi and these terms have since been consistently used in the census reports for the indigenous mass language of this province. It is indeed preposterous to call the vernacular of this province by the name 'Hindustani', the name of a single spoken dialect of the U. P. and itself a dialect of Hindi.

URDU NOT INDEPENDENT LANGUAGE

As for Urdu, it is only a literary form of Khariboli Hindi. It is not an independent language and cannot be said to be the mass language of any district. The name 'Urdu' does not appear anywhere on the language map of India. At the most it can claim as its own the Khariboli Hindi districts, and there too it will have to share its place with High Hindi, i.e., modern literary Khariboli Hindi. Speakers of Hindustani or Khariboli can indeed be found all over the province, specially in the towns and cities, but so can also the speakers of other dialects of Hindi. It is only a consequence of the modern means of communication and economic forces. In our polygot towns speakers of even extra-provincial languages like Bengali, Punjabi, English, etc., can also be found. All this does not alter the mass language or the vernacular of any place. Hindustani is the mother tongue or home language, i.e., the vernacular of very few families outside Khariboli districts. No doubt High Hindi and Urdu are used as literary languages for purposes of education, public life and administration all over the province, but this fact has nothing to do with the mass language or the vernacular of the province. English

proposed for official use of this part of the province will be 'Hindis'—for 'Hindustani'—greater use of the name 'Hindustani' language in India (where it is more than to the south) surely the name 'Hindustani' alone can culture and

There is a name as in this subject of the language applied to the High Hindustani (and not to a curio-

literary language for purposes of life and administration all over the Hindi, Marathi and Punjabi communities in the province use their own literary language for their purposes. High Hindi is literary languages for many purposes in provinces as Bombay, Punjab, Bihar, C. P. and Rajasthan, but it is not used to call the vernacular of Bihar, but by the name 'Hindustani'. A name in use at any place does not necessarily denote the vernacular of that place. In the case of the languages in the U.P., the fact that is noted is that several spoken dialects, notably Braj and Avadhi, have led to the literary existence and possess very distinct characteristics of great beauty and richness. These languages have very close affinities in respect of construction and vocabulary with the literature, i.e., High Hindi literature, and the literature. These literatures in fact have the affinities and likenesses with modern literature of a dialect is bound to the literature of another dialect of the same region and they are part and parcel of the literature and not of Urdu literature or of any other literature. Similarly, folk literature of

this province in the various dialects bears close affinities with modern Hindi literature and is a part and parcel of 'Hindi' literature and not of Urdu literature or of any 'Hindustani' literature.

HIND AND HINDUSTAN

All the provinces or, more correctly, territorial divisions of India with the exception of U.P., C.P. and N. W. F. P. have got their distinctive names which signify the spoken, indigenous mass language or 'vernacular' of the area as also the indigenous people inhabiting the area. For the Madras province has been recognised, particularly by the Congress, as consisting of Andhra, i. e. the Telegu speaking part, Tamil Nad i. e., the Tamil speaking part and Carnatic i. e., the Kannada speaking part. Bombay province is similarly regarded as consisting of Gujarat i. e., the Gujarati speaking part and Maharashtra i. e., the Marathi speaking part. Even in C. P., thanks to the efforts of Pt. Dwarka Prasad Misra, a Minister in the present as well as in the last Congress Ministry of C. P., the old name of the Hindi speaking part, viz, Mahakoshal (Koshali or Eastern Hindi is the mass language of the Hindi speaking C. P.) has been officially recognised. The Marathi speaking part of the C. P. is, linguistically speaking, a part of Maharashtra. 'N. W. F. P.' is more a political phrase than a name, and is bound to be appropriately renamed soon. So the U. P. is the only province which has no name signifying the distinctive language, culture and the people of the province. During the previous Congress regime the name 'Hind' was

proposed for this province (whether officially or non-officially I cannot say). This name is not only most appropriate but has actually been in use to a greater or lesser extent since the old name, Madhyadesha, of this part of India fell into disuse. The vernacular of the province is Hindi; the name of the province will be 'Hind', and its people will be known as 'Hindis'—so it is all right. The same cannot be said for 'Hindustani', for 'Hindustan' is to-day in much greater use than 'Hind' for the whole of India; the name 'Hindustani' is sought to be applied to the language of Hindustan, i. e., to the *lingua franca* of India (whatever shape it might ultimately take) rather than to the language of any particular province, and surely the people of the U. P. cannot reserve the name 'Hindustanis' for themselves. The name 'Hindi' alone can and does signify the distinctive language, culture and the people of this province.

EVERYTHING IN A NAME

There is one more reason why the term 'Hindustani' must not be used for the language of this province. Some might be inclined to ask: What is there in a name? But often there is everything in a name, as in this case. To-day the term 'Hindustani' is the subject of a great controversy which is more political than linguistic in nature. This term is sometimes applied to High Hindi, sometimes to Urdu, sometimes to High Hindi plus Urdu (as, for example, by the Hindustani Academy, U. P. and the Lucknow University), and now it is increasingly sought to be applied to a curious (or political) mixture of Hindi and Urdu,

the veritable 'third stream', being evolved by some bodies. The vernacular of this province has never been, is not and can never be so ambiguous, dual, and shifty as the name 'Hindustani' would imply. The name of the vernacular of the U. P. cannot be made the subject of a controversy, as it is not controversial. It is quite definite. It is 'Hindi'. The result of the substitution of the true name 'Hindi' by the name 'Hindustani' would be that the artificial mixture of Hindi and Urdu (and possibly of other Indian languages) called 'Hindustani', which is being made to suit various tastes—the tastes of the different provinces and of the different communities—so as to be acceptable as *lingua Indica* to the 400 millions of India speaking widely different languages, will automatically be thrust upon this province as the 'vernacular', *the* language of the province, and will be used, in the name of 'unity' and so forth, as the language of education and administration of the province, so that the real vernacular of the province Hindi, as also Urdu, will greatly suffer and may even be swamped by 'Hindustani'.

WHAT OF HINDI ?

Hindi is the indigenous language, the vernacular, of U. P. and U. P. alone (barring a part of C. P. and of Punjab). When U. P. will be described as 'Hindustani speaking area' (as has already been started in certain so called nationalist contexts; to make confusion worse confounded, even Bihar and C. P. are often included in this 'Hindustani speaking area'), which province, which region of India will be des-

cribed as 'Hindi speaking' ? When the people of U. P. will be described as 'Hindustani speaking', who in India will be described as 'Hindi speaking' ? Will a language as old as Hindi disappear overnight by a mere stroke of the pen of the U. P. Government ? Will the territory that has so long been marked 'Hindi' in the language map of India be now marked 'Hindustani', and Hindi, of all Indian languages, become conspicuous by absence after having been there for the past so many centuries ? It is a pity that while the Marathi speaking people of India are holding Maharashtra Unity Conferences with a view to unite together the Marathi speaking parts, and are giving a mandate to the Marathi speaking members of the Constituent Assembly to work for an united Maharashtra, the Hindi speaking Ministers of the U. P. Government should think of effacing Hindi from Hind whose undisputed vernacular it has been for the past thousand years. One might have rather thought that they would convene a Hind Unity Conference to agitate for cession of the Hindi speaking parts of the Punjab and C. P. to U. P. But strange things happen in this province where everybody, from Congress Ministers downwards, seems to view everything through a haze of politics-cum-communalism.

UNITY THROUGH HINDI

It must be made absolutely clear that there is no intention to harm the interests of Urdu in U. P. Urdu is a form of Hindi, and the U. P. Government is at liberty to allow those in U. P. who want Urdu and its script to cultivate Urdu and to give facilities for

the teaching of Urdu. It may even grant the same facilities to other language groups in the province, but let the vernacular of the province remain what it is, i. e. Hindi. Truth must not be sacrificed. Urdu or Hindustani is certainly not the vernacular of this province. A time may come when those who want Urdu and its script to-day may take kindly to the vernacular of this province, i. e., their real mother tongue, and to its natural script, thus ushering in the era of complete linguistic unity in this province; just as in the Punjab where Urdu too is medium of instruction, language of administration, etc., a time may come when adherents of Urdu, despite late Sir Sikandar Hayat Khan's frantic declaration regarding Urdu being the 'national language of Punjab', may take kindly to and adopt Punjabi, their mother tongue and the vernacular of Punjab, provided that Punjab remains 'Punjab' and Punjabi is not renamed 'Hindustani' or something like that. Thus 'Hindi' has got seeds of unity in it. But 'Hindustani', besides being an untruth, will, with its shifty and shifting meaning and its concomitant, the 'two scripts' clause, never allow this province to be one in the matter of language and script, will be a permanent obstacle on the way of progress and thus defeat the very purpose for which this untruth is (probably) sought to be imposed on this province. We appeal to the Congress that plumes itself in truth to do away with this palpable untruth, which seems to be inspired by political opportunism but which has infinite potentialities for permanent wrong-doing and injustice. It must give up its attempt to give a habitation to its concoction 'Hindustani' at the cost of

Hindi. It must desist from dealing a death blow to the existence of Hindi even as a provincial language in its mad desire to appease reactionaries and communalists, if it attaches any importance to the solemn pledges given in its election manifesto regarding the protection of the language and culture of every linguistic group and of every linguistic area. No Government, popular or unpopular, Congress or non-Congress, has a right to alter the old name of the vernacular of this province, specially when the new name suggested for it has already a definite meaning, denotes a definite and a mere spoken dialect of the province and has unfortunately gathered and is gathering about it new associations which are not only unpleasant but positively dangerous to the unity and welfare of the province.

APPEAL TO HINDIS

Lovers of the language and culture of this province, the various literary and cultural institutions of the province, specially the premier literary institution of the province, the All India Hindi Sahitya Sammelan, the Hindi speaking people generally, specially those who have been returned to the provincial Assembly by the votes of the masses, who know no 'Hindustani', nothing, except their rustic Hindi, are requested to take up the matter with the Government, and to see that the vernacular of this province is called by its proper name Hindi in official papers, correspondence, census reports and other official publications, etc.. The mischief must be nipped in the bud. It will be a poor consolation if this hated term 'vernacular' is

replaced by the controversial, wrong, misleading and dangerous term 'Hindustani', wiping Hindi off the language map of India. Agitation should also be started for securing official recognition for the name 'Hind' for this province in the place of 'United Provinces' which is no name at all. Unofficial bodies and nationalist newspapers should invariably refer to the vernacular of this province by the name 'Hindi', and they should also start using the name 'Hind' for U.P. without waiting for its official recognition.

परिशिष्ट ३

हम हिन्दी वाले !

(लेखक—श्रीमदनगोपाल मिश्र)

ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का ही यह घोषित सिद्धांत रहा है कि उनके प्रभुत्व में प्रत्येक भारतीय जन-समुदाय की भाषा सुरक्षित रहेगी। लेकिन इधर कुछ समय से ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी जन-संख्या की भाषा है और जो प्रत्येक दृष्टिकोण से निष्पक्ष विचार करने पर राष्ट्र-भाषा बनने के योग्य एक मात्र भाषा सिद्ध होती है, इस सिद्धांत का अपवाद हो गई है। इधर लगभग दस वर्षों से हिन्दी पर अनेक कठोर प्रहार हुये हैं। सीमा-प्रदेश, पंजाब, काश्मीर, सिन्ध और हैदराबाद में हिन्दी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वह पाठकों को विदित ही होगा। लेकिन हिन्दी पर इधर जो सबसे भयानक आक्रमण हो रहा है वह है 'आल इंडिया रेडियो' का। 'हिन्दुस्तानी' शब्द की ढाल की आड़ में वह हिन्दी की इस्ती तक को संसार की आंखों के सामने से मिटा देना चाहता है। हिन्दीवालों की ओर से आल इंडिया रेडियो की इस नीति का विरोध हुआ, यहाँ तक कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने जहाँ एक ओर 'लैंग्वेज पालिसी आफ आल इंडिया रेडियो' नामक पुस्तक लिख कर आल इंडिया रेडियो की धींगा-धींगी पर से परदा उठाया, वहाँ दूसरी ओर 'राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन' नामक पुस्तक लिख

कर बड़े बड़े भारतीय नेताओं और विद्वानों तक को भ्रांति में डाल देनेवाले 'हिन्दुस्तानी' शब्द के हृदय रूप का भण्डाफोड़ किया, लेकिन आल इंडिया रेडियो की नीति अब भी वहाँ की तहाँ है—उसके अधिकारियों ने हिन्दी-भाषा को बहिष्कृत करने का बीड़ा सा उठा लिया है। हिन्दुस्तानी के जाल में फँसे हुए लोग अभी स्वतंत्र हुये हैं कि नहीं, यह हमें अभी देखना है। उससे मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है कि वे परिडत रचिश्करजी की पुस्तकों को पढ़ लें। मैं तो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी और देश-भक्त का यह कर्तव्य समझता हूँ कि वह इन पुस्तकों को पढ़ें और हिन्दुस्तानी के बाँधे से शीघ्र सावधान हो जाय।

मनुष्य, क्या हम हिन्दीवालों ने कभी यह भी सोचा है कि हमारी भाषा पर होनेवाले इन अत्याचारों के लिये स्वयं हमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक है? हमारे किन अपराधों और हमारी किन कुटियों और निर्दयताओं के कारण हिन्दी इस अपमानित स्थिति में आ पड़ी है? हमने हिन्दी का स्नातक ऊँचा करने के लिये अभी तक क्या किया है? इन प्रश्नों का उत्तर हिन्दी प्रदेशों के केन्द्र संयुक्त-ग्राम पर ही नज़र डालने से मिल जायगा—

(१) पाँच प्रचलित अँगरेज़ी के समाचार-पत्र—लेकिन क्या इनमें से किसी का भी सम्पादक हिन्दी की गोद में तुलनाया और पला हुआ व्यक्ति है? यदि होता तो आल इंडिया रेडियो की हिन्दी-विरोधी नीति एक पग भी आगे न बढ़ सकती। इनमें से किस समाचार-पत्र ने किसी हिन्दी-विरोधी नीति के विरुद्ध आन्दोलन किया है? वह विराम करने को मरगा जो नहीं चाहता कि अब तक अँगरेज़ी समाचार-पत्रों के सम्पादन की योग्यता रखनेवाला कोई हिन्दी का लाइला पैदा ही नहीं हुआ।

(२) हमारे प्रांत के सबसे बड़े उर्दू-विख्यात नेता को हमारी प्रमुख प्रांतीय भाषा हिन्दी के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं—शायद वह दूरी फ़री हो हिन्दी लिख सकता हो। और उसकी इस उदासीनता ने हमारे अन्दर

प्रान्तीय नेताओं को अपनी भाषा के प्रति कहाँ तक उदासीन न बना दिया होगा ? फिर हिन्दी को क्यों न ठोकरें लगाई जायँ ?

(३) हमारी कचहरियों और पुलिस के बिभागों में हिन्दी पढ़े-लिखे वकील और अफसर अपनी और जनता की भाषा को छोड़कर एक ऐसी भाषा को निस्संकोच अपना लेते हैं जिसे सुनकर किसी भी साधारण नागरिक को आश्चर्य हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'प्रथम', 'द्वितीय' और 'तृतीय' तो दूर रहे, 'पहले', 'दूसरे' और 'तीसरे' के स्थान पर जब तक वे 'अव्वल', 'दोयम' और 'सोयम' नहीं लिख लेते, उन्हें चन नहीं पड़ता— कितना करुण दृश्य !

(४) हमारे प्रान्त के सबसे बड़े वेरिटर, जो अपनी योग्यता के लिये इसी प्रान्त में नहीं, सारे भारतवर्ष में और लन्दन में भी विख्यात हैं, एक बार एक सहाय्य से एक सभा में, जिसके वे सभापति थे, 'सभापति' शब्द से सम्बोधित किये जाने पर बेतरह दिगड़ उठे थे ! संस्कृत और हिन्दी उनके लिये कितनी असहनीय है ! प्रान्त की जनता की भाषा के प्रति उनका यह व्यवहार ! इस प्रान्त के एक दूसरे नेता और ऐडवोकेट गान्धीजी के शब्दों में हिन्दी कठिनाता से लिख सकते हैं। तो फिर हिन्दी का तिरस्कार क्यों न हो ? यद्यपि हम गान्धीजी को यह सूचित कर देना चाहते हैं कि हमारे वाप-दादों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव में भले ही हिन्दी न पढ़ी हो, परन्तु उनके वचन अपने जीवन और देश से सामंजस्य रखने वाली हिन्दी ही पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। चारों ओर से हिन्दी पर किये जाने वाले प्रहार उनकी आँखें और भी खोल देंगे।

(५) भारतवर्ष में सिनेमा-कम्पनियाँ एक बड़ी संख्या में खुल गई हैं, लेकिन हिन्दी-प्रान्तों में हिन्दी वालों द्वारा कोई कम्पनी क्या अभी तक खुली है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यही कारण है कि हिन्दी की आत्मा की गुंता-रक्षा करने वाले चित्र बहुत कम बने हैं, यद्यपि सबसे उत्कृष्ट चित्र वे ही

समझे गये हैं जिनमें इस रक्षा का ध्यान रखा गया है। ग्रामोफोनरिकार्ड-कम्पनियों के साथ भी यही बात लागू है।

(६) हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों में सिनेमा-भवनों के मालिक शायद ही कोई हिन्दी वाले मिलें। सिनेमा के पोस्टरों, आदि की भाषा अथवा उनमें किया जाने वाला हिन्दी का तिरस्कार हमें बराबर इसी बात का स्मरण दिलाते हैं। इस तिरस्कार की ओर हम टुकुर-टुकुर दबते हैं—उसका विरोध करने का भी बल हममें नहीं रह गया है।

(७) इस प्रान्त की शिक्षा-संस्थायों तथा अन्य विभागों में हमारे अन्य प्रान्तीय भाई विभिन्न पदों पर एक बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। इनमें से कुछ ने हिन्दी की बहुमूल्य सेवा की है और अब भी कर रहे हैं, इस बात का हमें गर्व है। हिन्दी अब हमारी ही नहीं, प्रत्येक सच्चे भारतीय की है, और फिर उन व्यक्तियों के, जिनकी भाषा हिन्दी को ही सगो बहिन हो और जो हिन्दी प्रान्तों में जीविकोपार्जन करते हों, हिन्दी के प्रति अनेक दृष्टि-दिग्बुद्धों से विरोध कर्त्तव्य है—(१) हिन्दी पर संकट का अर्थ है संस्कृत पर घोर संकट, फिर क्या संस्कृत की पुष्टियाँ—हिन्दी की अन्य वहन—उसने बच सकती हैं ? (२) हिन्दी प्रान्त में, हिन्दी वालों के बीच, उन्हीं के निमित्त, और उन्हीं के सहयोग से रह कर उनका यह धर्म हो जाता है कि वे अपनी भाषा के साथ-साथ हिन्दी को भी अपनायें। (३) केवल यही नहीं, भारतीयता के नाते उनका यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वे हिन्दी के सन्देश को अपने अपने प्रान्तों में पहुँचायें और उसके प्रति जनमत को जाग्रत करें। हमें खेद है, उनमें से बहुतों का पूर्ण सहयोग हिन्दी को प्राप्त नहीं है, बहुत से उसके प्रति उदासीन हैं, कुछ उसने स्पर्धा भी रखते हैं, यहाँ तक कि कुछ हिन्दी वालों को ही हिन्दी के प्रति निरुत्साहित करने में भी संकोच नहीं करते। हिन्दी वालों का कर्त्तव्य है कि वे अपने इन पथ-भ्रष्ट भाइयों को रास्ते पर लावें, और उन्हें हिन्दी के सन्देश की सत्यता में विश्वास

दिलावें। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हीं का अपराध है। अन्य प्रान्तों की कोई भी भाषा अपने ही घर में इस प्रकार की अपमानित परिस्थिति नहीं है। घर पहुँक तमाशा देखने की नीति हिन्दी वालों को ही सख्य होती है, औरों को नहीं।

(८) इस प्रान्त के अनेक ईसाइयों और अँग्रेजों की शिक्षा-संस्थाओं केवल उर्दू ही पढ़ाई जाती है, हिन्दी को उनमें स्थान नहीं। फिर भी हिन्दी वाले अपने बच्चों को उनमें पढ़ाते हैं, बिना इस बात का आन्दोलन किये हुये कि वहाँ हिन्दी पढ़ाने का भी प्रयत्न होना चाहिये। इस प्रकार हिन्दी वालों के ही बच्चे अपनी मातृ-भाषा और अपने संस्कृति से वंचित हो जाते हैं। आगे चलकर इन्हीं बच्चों के कर्मों पर मैंने उनके माता-पिताओं को भीकते हुये भी देखा है—परन्तु अपराध किनका ?

अब कुछ आँखों देखे दृश्यों पर भी विचार कीजिये—

(१) जनता की सरकार के समय की संयुक्त-प्रान्तीय असेम्बली के अधिवेशन का एक बैठक। एक सदस्य जी उठे, हिन्दी में बोलना चाहा, हिन्दी के विरोधियों ने आपत्ति की और उनकी भाषा दिगड़ गई। एक हिन्दी वाले ही 'पार्लामेंटरी' सचिव उठे और उन्होंने बड़े जोश के साथ फारसी से लदा हुआ एक ऐसा भाषण दे डाला कि अधिकतर श्रोता मुँह बाएँ ही रह गये। हिन्दी के विरोधी तो अतनी भाषा में बोले ही—किसका साहस था कि चूँ कर जाय। उनके हिन्दी के विरोध का शायद सम्मान हुआ, और यदि कोई हिन्दी वाला आपत्ति कर देता तो उसी क्षण उस पर शायद साम्प्रदायिकता, अराष्ट्रीयता, आदि के अपराध लगा दिये जाते। उर्दू तो ठीक, अंगरेज़ी तो भी ठीक, और हिन्दी तो राम राम !—क्या खूब !!

(२) साक्षरता-दिवस (कांग्रेस सरकार के समय में)—एक पार्क में एकत्र नगर की सारी शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थी। अधिकतर हिन्दी वाले।

कुछ सुलमान सज्जनों ने भाषण दिये—उर्दू में, ठीक है ऐसा तो होता ही। अब उठे एक एक करके हमारे दो नेता—दोनों हिन्दी के यशस्वी विद्वान् और लेखक। कुछ मनचले साहसी छोकरो ने आवाज़ लगाई 'उर्दू, उर्दू'—और यह लीजिये उर्दू। फिर क्या था, वे छोकरे बिजब ने फूल गए और हिन्दी वाले विद्यार्थी मुँह बाये, मुँह ताकते रह गये। हमने मौलाना अबुलकलाम आजाद, श्री रफी अहमद किदवाई, आदि किसी भारतीय मुस्लिम नेता को हिन्दी में लिखते-बोलते न देखा है और न सुना है। क्यों ? क्योंकि उर्दू अपने नाम से अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से उर्दू ही रहता चाहती है, हिन्दी अपने को चाहे नष्ट कर डाले।

(३) लखनऊ की बड़ी प्रदर्शिनी (१९३३)—एक पंडाल के नीचे 'हिन्दुस्तानी ऐकेडमी' की एक बैठक में हिन्दुस्तानी की समस्या हल हो रही थी। जा बैठे। देखा क्या है कि 'आमनहम जुवान' हिन्दुस्तानी का ही समर्थन करते हुए उर्दू वाले बड़े जोश खरोश से फारसी बूँक रहे थे—और दिलमिल हिन्दी वाले भी, जिनमें हिन्दी के कुछ दिग्गज विद्वान भी थे। (कदाचित् तकल्लुक में आकर) उर्दू में ही भाषण देने का प्रयत्न कर रहे थे। हिन्दुस्तानी तो कुछ थी ही नहीं, हिन्दी भी न रही, रह गई केवल कोरी उर्दू—न रहेगा बाँस और न बजेगी बाँसुरी। उठा, और इन हिन्दी वालों ने कुछ कुमिर्त, कुछ निराश, कुछ इन पर हँसता और कुछ इन अशुभ लक्ष्णों से हिन्दी पर आगे आने वाले संकट का अनुमान करता अपने घर चल दिया।

सारांश यह कि जब तक हिन्दी वाले स्वयं अपने ही इन अपराधों से मुक्त न होंगे, तब तक हिन्दी-भाषा अपने ऊपर दूसरों द्वारा किए हुये अत्याचारों पर कम रोवेगी, अपने ही पुत्रों की निष्क्रियता और कर्तव्यहीनता पर सिर पटकती रहेगी। यदि उसके ही बेटे ऐसे न होते तो कैसे कोई उसका अपमान कर सकता ? अभी बहुत देर नहीं हुई है—क्या हम अपने

हिन्दी वाले भाइयों और भारत-भक्तों से आशा करें कि वे अपनी मातृ-भाषा अथवा राष्ट्र-भाषा का मस्तक ऊँचा उठाने में अपना तन, मन, धन अर्पित कर देंगे ?

(मई, १९४६ की 'सरस्वती' से)

परिशिष्ट ४

वर्धा की हिन्दुस्तानी

(लेखक—श्रीभूदेव विद्यालंकार)

हिन्दी की राष्ट्रीयता पर इस समय दो ओर से प्रबल आक्रमण हो रहे हैं। एक आक्रमण बाहर की ओर से हो रहा है, और उस समुदाय की ओर से हो रहा है जो हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता तथा हिंदू आचार-विचार का विद्वेषी है और जिसे हिंदुओं की उन्नति फूटी आँखों भी नहीं सुहाती है। इस आक्रमण का करनेवाला ऐङ्गलो-मुस्लिम सरकारी गुट है जिसकी एक शाखा केन्द्रीय भारत सरकार का सूचना तथा प्रचार विभाग है। इसके सर्वसर्वा वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य सर अकबर हैदरी हैं। इनने पहले सर नुत्तान अहमद थे। यह विभाग अपने लेखों, तथा प्रचार के सर्वाधिक शक्तिशाली साधन आकाश-वाणी (रेडियो) द्वारा अगदी-आरसी-बहुल उर्दू भाषा को 'हिंदुस्तानी' का नाम देकर उसके प्रचार और प्रसार में प्राणपण से जुटा हुआ है। सरकारी विभाग की इस उर्दू पद्धतियों तथा हिन्दी विरोधिता नीति के विरुद्ध एक प्रबल आन्दोलन हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा हिंदी साहित्य सेवियों द्वारा कई वर्षों से चल रहा है। यह आन्दोलन अब तक सफल होगया होता यदि 'हिंदुस्तानी' का पोषक एक दूसरा आन्दोलन हिंदुओं के ही भीतर खड़ा न होगया होता। इस दूसरे आन्दोलन के कारण हिंदी विरोधी सरकारी दल के काँपते हुये हाथ और लड़खड़ाते हुये पैर फिर से

दृढ़ होगये हैं, और हिंदी की राष्ट्रीयता के प्रचार में कुछ समय के लिये बाधाएँ और बढ़ गई हैं।

यह खेद और दुःख की बात है कि यह दूसरा हिन्दी विरोधी हिन्दु-स्तानी का आन्दोलन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया जा रहा है जो किसी समय हिन्दी की राष्ट्रीयता का प्रबल समर्थक, प्रचारक और पोषक था। इस हिन्दुस्तानी का केन्द्र है वर्धा और वहाँ के महात्मा ही इसके प्रवर्तक, पोषक, प्रचारक, प्रसारक और प्रेरक हैं। वर्धा से होने वाला हिन्दी पर यह आक्रमण सरकारी गुट्ट के आक्रमण से कहीं अधिक घातक है क्योंकि यह प्राथमिक और माध्यमिक श्रेणियों से ही हिन्दुस्तानी का प्रचार हमारे बालक-बालिकाओं में करने का उपक्रम कर रहा है। सरकारी विभाग की 'हिन्दुस्तानी' और वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' में केवल नाम साम्य ही नहीं है, प्रत्युत हिन्दी में प्रचलित सरल और सुबोध संस्कृत शब्दों के भी बहिष्कार तथा अरबी फारसी बहुल उर्दू शब्दों के विशेष व्यवहार और प्रयोग में भी दोनों में आश्चर्यजनक साम्य है।

वर्धा की हिन्दुस्तानी क्या है? कैसी है? इसे समझने के लिये वर्धा-शिक्षा-योजना से सम्बन्ध रखने वाली तथा वहाँ से प्रकाशित पुस्तकों में से दो-चार का अध्ययन ही पर्याप्त है। इस सम्बन्ध में १-शिक्षा में अहिंसक क्रांति, २-एक कदम आगे, ३-बुनियादी तालीम के दो साल, ४-गरीब का काम, भाग पहला, ५-खेती शिक्षा, ६-ओटना, तुनना व धुनना, ७-नई कित द (हिन्दी), ८-कताई गणित (हिन्दी), ९-तकली (हिन्दी), १०-नई कितान (उर्दू), ११-कताई का हिसाब (उर्दू), १२-तकली (उर्दू), इन बारह पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यदि वर्धा की हिन्दुस्तानी का विरोध न किया गया और वह सफल हो गई तो हिन्दी का स्वरूप इतना विकृत हो जायगा कि उसे पहचानना भी कठिन हो जायगा, यहाँ तक कि हिन्दी की उपजीव्य संस्कृत के सरल और सुबोध

शब्दों का भी बहिष्कार होकर उनके स्थान पर अरबी फारसी बहुत उर्दू शब्दों को इतनी भरमार हो जायगी कि वह वही हिन्दुस्तानी बन जायगी जो ऐंग्लो-नस्तिज गुट्ट की अभीष्ट है।

हम यह मानते हैं कि उच्चतम भाषा पड़ाव भाषाओं के ही नहीं प्रत्युत विदेशी भाषाओं के शब्दों से भी अपने शब्द-भाण्डार का भरने में आगा-पीछा नहीं करती। पर इनका यह अभिप्राय कभी नहीं है कि अपने आत्मसात किये हुये शब्दों का या उपजाव भाषा के शब्दों का बहिष्कार करके दूसरी भाषा के शब्दों को अनायास जाय, उनके पीछे दौड़ा जाय।

बर्धा की हिन्दुस्तानी केना साहित्य निर्माण कर रही है, इसके कुछ उदाहरण देखिये :—

‘खेती की शिक्षा’—एक सौ तीन पृष्ठों की ग्यारह अध्यायों में विभक्त यह एक पुस्तक है। यह ‘खेती की शिक्षा’ नाम की मराठी पुस्तक का अनु-बाद है। इसके प्रथम दो अध्यायों में ही उर्दू के शब्दों तथा वाक्यांशों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, देखिये :—दास दासचे, ताकतु, नज-दीकी सम्बन्ध, बारी, मौजू, नददगार साबित होग, कदरत, जिन्दगी गुजा-रनी, इम्तहानों, वेमज, वेहद ताकतवर, खुदा को शान, जिन्दगी की अज-मत, गुजरेग, कदरत के ये एलच, होशियारी, चीज में खुदसूती, ताकती जरूर हांगी, शोर करने का ताकत, हासिल, वजह, बाक्यादा सोचने का मादा पैदा होगा, बवान, खयालों की जाहिर करना, पावन्दी, एहसास, सुस-ज्वरी, आवाज, बारीक, इबादा मजबूत, खसकर, चूँकि इबादातर, कौनी फायदा, शखो, कौनी निराह, सुतादिक, दस्ताकारी के जरिये, बक, नादरी जवान, नज़म, सुक़दम थेंदे, मजदूनों की तरह, जरूरी, सामिल, जमाती, मक़सद, गुंजाइश, और हलाल सुआकिक ही, तनखवाह, पैदावार का सवाल, गुलामी, बदनाम, नसाब, बदकिदमती, आज द का तरज, तालीम, शानदार, खास पहलुआ, खास मरकज़, सिर्फ, जरूरी पहलुओं पर खास ध्यान, काम-

याव या नाकामयाव, अहम सवान, इन्कलाव, सादा मिज़ाज, मेहनती, दिमाग, दिलचस्पी, आज़ाद तवियत, लाज़मी, एतकाद, रोशनी पैदा करनी, पैदा-यशी, बलिक तज़ावे के मुताबिक, हौसलों को कामयाव बनाने, काफ़ी मौका, आबन्दा इत्यादि। ये उद्धरण केवल प्रथम दस पृष्ठों से ही दिये गये हैं।

उर्दू शब्दों के प्रचार के लिये इस पुस्तक में अनेक हिन्दी के शब्दों के उर्दू पर्याय भी अनेक स्थानों पर दिये गये हैं मानों संस्कृत शब्दों के प्रयोग का प्रावृत्ति किया गया हो। जैसे चित्रकला (मुसव्वरी), इन्द्रिय ज्ञान (एहसास), राष्ट्रीय (कौमी), गणित (हिसाब), काव्य (नज़्म), भूगोल (जुगराफ़िया), मातृभाषा (मादरी ज़वान), व्यवसाय (सुक़दम धन्दे), मुख्य केन्द्र (ख़ास मरकज़), महत्वपूर्ण (अहम), क्रान्तिकारक (इन्कलाबी), श्रद्धा (एतकाद)। ये उद्धरण भी इन्हीं दस पन्नों के भीतर के हैं।

इस पुस्तक के पाँचवें अध्याय का शीर्षक 'कुछ इत्तलायें' है। अब दूसरी पुस्तक उठाइये, 'नई किताब'। यह ६० पन्नों की है। इसके प्रकाशक हैं श्रीआर्यनायकम्। पुस्तक के निवेदन में आपने लिखा है—

“बुनियादी स्कूलों के तीसरे दर्जे के बच्चों के हाथों में इस किताब को रखते हुये मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यह किताब ख़ासकर बिहार के बुनियादी स्कूलों के बच्चों के लिये तैयार की गई है”। आगे आप फिर लिखते हैं—
“भाषा सरल हिंदुस्तानी रक्खी गई है।” अब इसकी ‘सरल हिंदुस्तानी’ देखिये—

“बुनियादी स्कूल, किताब, बुनियादी तालीम, ख़ास साहित्य, समिति मुक़रर की गई, बुनियाद सही है, दायरे, क़दम, शुरू से आख़ीर तक शौक़ पैदा करेगी, हरदम अपने दिलके अन्दर ऐसी ताक़त जो भर दे नाउम्मीदों में भी जान, हरदम, मज़बूत, कमज़ोर, बल, मुताबिक, बदल, ख़ासे बड़े, ताज़्जुब, फ़ौरन, ग़ौर से, ख़जाना, साफ़, खुश, ताज़ा, बदलू, बस्ती, तन्दुरुस्त,

सुसोवत, उत्ताव, एकमानियत, तारीफ, विक्रम, अकलमन्त्री, काशी, आदाव
बन्दगी, सलाम अलै, रोज की तरह, आदत के मुताबिक, रास्ता, होशियारी,
खतम, इन्तिजाम, हमेशा, मेलाद की सजलिस, ज़िन्दगी के हालात, दुश्मन
मेहमान हुआ, सलूक, दोस्त, दुश्मन, सख्त, बाक़्दा, तकलीफ़, मिज़ाज, सुह-
व्यत, एहसान, इन्साफ़, ज़नायतन, मज़, मेहरबानी ।”

यह सूची और लम्बी हो सकती है पर इन्में से ही पुस्तक की हिन्दुस्तानी
का अनुमान किया जा सकता है । अनेक हिंदी शब्दों के उर्दू पर्याय इसमें
भी लिखाये गये हैं । इस पुस्तक में इनके अतिरिक्त एक दो और भी विशेष-
तायें हैं जिनकी और में पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । पहली
विशेषता तो यह है कि २३ पाठों और १२० पृष्ठों की इस पुस्तक में “सुह-
म्मद साहब से दुश्मन को दोस्त बनाया”, इन नवें पाठ के अतिरिक्त और
किसी ऐतिहासिक महापुरुष के चरित्र का कहीं वर्णन नहीं किया गया है ।
किसी ऐतिहासिक धार्य या हिंदू राजा के चरित्र के वर्णन को तो बात ही
दूर है । दूसरी विशेषता यह है कि इसमें केवल दो कविताएँ छापी गयी हैं—
एक प्रारम्भ में और एक अन्त में । प्रारम्भ की ‘प्रार्थना’ काव्यता ‘बहार उर्दू’
से ली गई है, और अन्तिम कविता ख़ासिर सुहम्मद इक़बाल की प्रसिद्ध
“हिन्दोस्तान हमारा” है जिसे नागरी विषय की सूची में “राष्ट्रिय गीत” तथा
उर्दू में ‘बौनी तराना’ लिखा गया है । तीसरी विशेषता इस पुस्तक में यह
है जो हिन्दुस्तानी के सीछे कान करनेवाली मनीवृत्ति के वास्तविक रूप को
प्रकट कर देती है । वह है हमारी राष्ट्रीयता का रूप, यथा—

बर्धों की हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में कुछ ऐसी धारणा फैली हुई है कि
उसकी भाषा का रूप एक है और वही नागरी तथा उर्दू लिपि में छाप दी
जाती है । परन्तु ऐसा है नहीं, यह केवल भ्रम है । यह सम्भव है, एक प्रकार से
निश्चित भी है, कि हिन्दी को सहोदरा भाषाओं की लिपियों में इन पुस्तकों
का प्रकाशन करते हुये इसी हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया जाय, परन्तु उर्दू

लिपि में जाते ही इसकी पक्की मुसलमानी हो जाती है । इस पर बुगका पड़ जाता है और विगुद्ध उर्दू हो जाती है । इस 'नई किताब' की नगरी तथा उर्दू में प्रकाशित संस्करणों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है :—

पहले पन्ने से ही देखते चलिये—

नागरी

१—

२—नागरी-प्रकाशक

३—पहला संस्करण

४—(नोट नहीं है)

५—निवेदन

६—बुनियादी स्कूलों के तीसरे दर्जे के बच्चों के हाथों में इस नई किताब को रखते हुये मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।

७—यह किताब खास करके

८—पर मुझे आता है

९—जब से बुनियादी तालीम का प्रयोग शुरू हुआ

१०—एक नये साहित्य की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं

उर्दू

१—लिटरेचर कमेटी मुकर्ररगुदह मिनजानिब बेसिक एजुकेशन बोर्ड, विहार ।

२—उर्दू-नामर

३—तलय अव्वल

४—(नोट) अर्ज़ अडीटर—मैं निहायत मसरत के साथ इस बात का अयतगफ़ करता हूँ—इत्यादि ।

५—अर्ज़ हाल

६—मुझे बुनियादी स्कूलों के तीसरे दर्जह के हाथों में इस 'नई किताब' को देते हुये बेहद मसरत हो रही है ।

७—यह किताब मखसूस तौर पर

८—लेकिन मुझे उम्मीद है

९—जब से बुनियादी तालीम का तजरबह शुरू हुआ

१०—एक नये अदब की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं

- | | |
|--|---|
| ११—क्या बच्चों के लिये और
क्या शिक्षकों के लिये | ११—क्या बच्चों के लिये और
क्या मौलवियों के लिये |
| १२—सच्चे शिक्षा साहित्य का
अभाव है | १२—सच्चे तालीमी अदब का
फकदान है |
| १३—विषय सूची | १३—फेहरस्त मज़ामीन |
| १४—प्रार्थना | १४—दुआ |
| १५—यहाँ चाहता हूँ मैं ईश्वर | १५—यहाँ चाहता हूँ मैं या रब्ब |
| १६—बाद तुम्हारे ईश्वर, इसका
ही हरदन कहलाऊँ मैं | १६—बाद तुम्हारे या रब इसका
एक खादम कहलाऊँ मैं |
| १७—तकली की गति (चाल) के
अनुसार (नुतादिक) ही सूत | १७—तकली की रफ्तार के
नुतादिक ही सूत |
| १८—यह सूत कितना समान
(एकसाँ) है | १८—यह सूत कितना एकसाँ है |
| १९—प्रणाम, नामाज़ी | १९—आदाब, मानूज़ान
(यहाँ ध्या। देन की बात
है कि कहने वाला केदार
हिन्दू है और अपने मामा
से कह रहा है) |
| २०—सूत की समानता (एकसा-
नियत) पर वह ध्यान नहीं
दे रहा था । | २०—सूत इसका एकसाँ नहीं
हो रहा था । |

ये उद्धरण 'निबंदन' या 'अर्ज हाल' को केवल प्रथम ८-१० पंक्तियों के हैं। वम इतने से ही समझ लीजिये कैसी 'हिन्दुस्तानी' है।

लेख का कलेवर बड़ रहा है इसलिये इसे यही समान्त करना हूँ। अन्य पुस्तकों के सम्बन्ध में फिर लिखूंगा। अन्त में इतना अवश्य लिखूंगा कि

ये उद्धरण स्पष्ट कह रहे हैं कि बर्धा की हिन्दुस्तानी की भाषा एक नहीं है। नागरी लिपि में जिस प्रकार हिन्दी शब्दों के उर्दू पर्याय कोष्ठों में लिख कर उर्दू के शब्दों का परिचय, व्यवहार तथा प्रयोग बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है, उर्दू लिपि के संस्करणों में इस प्रथा को क्यों नहीं अपनाया गया ? क्यों नहीं उर्दू शब्दों के संस्कृत प्रयायों से उर्दू पढ़ने वालों को परिचित कराने का प्रयत्न किया गया ? क्या यह उर्दू के साथ पक्षपात तथा संस्कृत के बहिष्कार का द्योतक नहीं है ? क्या इस हिन्दुस्तानी द्वारा हिन्दी के साथ न्याय हो रहा है ? क्या यह प्रथा हिन्दी के सर्वनाश का कारण न होगी ? क्या इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उर्दू शब्दों का व्यवहार बढ़ाना, उर्दू का प्रचार करना नहीं है ?

(जनवरी, १९४६ की 'हिन्दी' से)

(आगे टिप्पणी देखिये)

परिशिष्ट ४ पर टिप्पणी

(लेखक—रविशंकर शुक्ल)

बर्बा की हिन्दुस्तानी के पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है वह तो ऊपर के लेख में प्रकट है ही, इस लेख में बिहार की हिन्दुस्तानी पर भी भरपूर प्रकाश पड़ता है। यह है बिहार जैसे हिन्दी प्रान्त की उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप जो बिहारों जनता पर 'राष्ट्रीय सरकार' द्वारा लादी जा रही है और बिहारों बालकों के मस्तिष्क में प्रारम्भ में हो पैठाई जा रही है ! देवनागरी पुस्तकों में हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की जो दुर्दशा की गई है उससे अधिक आश्चर्य फारसी लिपि की पुस्तकों की भाषा देख कर होता है। इन उर्दू पुस्तकों में हिन्दी के साधारण से साधारण देशज शब्द तक के लिये स्थान नहीं। उनके स्थान में भी ढूँढ़ ढूँढ़ कर अरबी फारसी शब्दों को ठँसा गया है, और जहाँ यह संभव नहीं वहाँ अँगरेज़ी शब्द रक्खा गया है (जैसे 'अडीटर'—'सम्पादक' सह्य नहीं) और वस्तुतः क्रियाओं और विभक्तियों को छोड़ कर भाषा में कोई भी भारतीय तत्व न रहने दिया गया है। ऊपर से तुराँ यह कि इस भाषा का नाम रक्खा गया है 'हिन्दुस्तानी' और उसे जनता की सरल भाषा कह कर लादा गया है बिहारों जनता पर जिसकी (हिन्दू या मुसलमान) जाति-भाषाएँ भोजपुरी, मैथिली और मगही हैं और जिसने अपनी बाणी विद्यापति ऐसे कवि से पाई है ! यदि पंजाब, सिन्ध या सीमा-प्रान्त का समानता होता तो वहाँ तो वैदिक स्कूलों की 'हिन्दुस्तानी' बनाई जाती उर्दू और पुस्तकों की देवनागरी लिपि में भी न

छापा जाता (उदाहरण के लिये पंजाब के वेसिक स्कूलों में प्रचलित 'हिन्दुस्तानी' की पुस्तकें देख लीजिये), परन्तु बिहार में प्राथमिक शिक्षा से भी एक दर्जा नीचे वेसिक शिक्षा के लिये मैथिली और मगही बोलने वाले मुसलमान बालकों के हाथ में ऐसी पुस्तकें दी जाती हैं जिन की उर्दू को वे क्या, युक्त-प्रान्त और पंजाब में भी मुसलमान बालक नहीं समझ सकते । यह है 'मातृ-भाषाओं द्वारा शिक्षा' वाले नारे का व्यावहारिक रूप ! जैसी उर्दू की बिहारी मुसलमान स्वयं न माँग करते उससे अधिक क्लिष्ट उर्दू उन पर थोपी जा रही है, और बिहारी जनता को भाषा और लिपि के पाकिस्तानों में बाँटा जा रहा है, और यह सब 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर ! ऐसा क्यों न हो ? बिहार की 'राष्ट्रीय सरकार' में डा० सैयद महमूद शिक्षा-मन्त्री क्या व्यर्थ के लिये बने थे, और इस बार शिक्षा का पोर्टफोलियो दबोचे रहने का जीतोड़ प्रयत्न उन्होंने क्या तकलुफ़ में आकर किया था ? संसार भर में भारत ही तो एक ऐसा अभाग्य देश है जहाँ बिहार जैसे हिंदी प्रान्त का शिक्षा-मन्त्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाना सम्भव है जो अपनी मातृभाषा हिंदी न बताता हो, जिसे हिंदी का ज्ञान न हो, हिंदी से प्रेम न हो बरन् जिसे हिंदी से द्वेष हो—और वह भी एक ऐसी सरकार द्वारा जो राष्ट्रीयता का दम भरती हो, जनता की सरकार होने का दावा करती हो ! इंग्लैंड की प्रतिगामी से प्रतिगामी सरकार भी एक ऐसे व्यक्ति को इंग्लैंड का शिक्षा-मन्त्री बनाने का साहस न करेगी जो अँगरेज़ी का विद्वान न हो और जिसे अँगरेज़ी से प्रेम न हो, परन्तु भारत में तो कांग्रेसी राष्ट्र-वादियों को काँटिनी मुसलमानों के सहयोग का मूल्य हिंदुओं की जेब से चुकाना ही है ।

क्या हम बिहार की नई सरकार से यह निवेदन कर सकते हैं कि वह बिहार में भाषा और लिपि का पाकिस्तान, जिससे वह अभी तक बचा रहा है, खड़ा करके, बिहार की जनता के टुकड़े टुकड़े न करे और उसकी भावी उन्नति

में भयंकर बाधा न डाले ? यदि उसने ऐसा किया तो बिहार की अगनी पीढ़ियाँ उसे इस महान् अपराध के लिये कभी क्षमा नहीं करेंगी । बिहार प्रांत में प्रांतीय कोलियों के बाद हिंदी के सिवा किसी अन्य हिन्दुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, और देवनागरी के सिवा किसी दूसरी लिपि का कोई स्थान नहीं, चाहे मुसलमानों का मामला हो, चाहे ईसाइयों का और चाहे किसी और का । बिहार की हिन्दुस्तानी हिंदी है । बिहार के १४ प्रतिशत मुसलमानों, जो हिंदी समझते हैं, के द्वाराग्रह के कारण बिहार में शिक्षा या राजकाज में उर्दू और उर्दू लिपि को हिंदी और देवनागरी के समकक्ष स्थान देकर या हिंदी से भिन्न किसी हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि को स्थान देकर बुद्धि का दिवालियापन प्रकट करना है । दुश्च की बात है कि जब पंजाब (जिसके कई जिलों की मातृभाषा ही हिन्दी है) की सरकार २० प्रतिशत जनता के कहने पर भी राजकाज, कचहरियों, आदि में उर्दू के सिवा किसी दूसरी हिन्दुस्तानी और फारसी लिपि के सिवा किसी दूसरी लिपि को कोई स्थान देने को तैयार नहीं, बिहार की सरकार गिने चुने मुसलमानों को खुरा करने के लिये अपनी राजभाषा और राजलिपि को दो दो में विभक्त चाहती है*, और हिंदी को सुन्नत करना चाहती है । जोभ का विषय है कि जब शारदा लिपि के देश काश्मीर और गुजमुनी के देश पंजाब में मुसलमान केवल एक लिपि फारसी यह कहकर रखना चाहते हैं कि दो लिपियों में जनता दो भागों में बँट जायगी और मिलकर कभी एक न हो सकेगी, और

* कुछ वर्ष हुए बिहार की इन्टरिम (मध्यकालीन) गवर्नमेंट के समय में (१९३५ के विधान के लागू होने से पूर्व) अपनी तीन सहीने की सुलतानी में सर सुलतान अहमद ने मौजूा पाकर उर्दू को भी बिहार की राजभाषा, कचहरियों की भाषा, आदि घोषित कर दिया ! इस बात का कोई चिन्ह नज़र नहीं आता कि बिहार की राष्ट्रीय सरकार एक कठपुतली सरकार की इस प्रति-क्रियावादी आज्ञा को, जिसको केवल दस वर्ष हुए हैं, रद्द करके बिहार को दुभाषी भाषा से मुक्त कर देगी । उसकी 'राष्ट्रीयता' में इतना दम कहाँ ?

जब सिन्ध की सरकार सिन्ध में 'हिंदुस्तानी' की केवल एक लिपि फारसी यह कहकर रखती है कि सिन्धो लिपि से मिलती जुलती होने के कारण वही सिन्धियों के लिये उपयुक्त है, बिहार की राष्ट्रीय सरकार देवनागरी के देश बिहार में कैथी जाननेवाले बिहारियों पर देवनागरी के साथ एक दूसरी लिपि जबरदस्ती थोपना चाहती है, और जो जनता आज एक है उसे अब दो भागों में बाँटना चाहती है । राष्ट्र-भाषा हिंदुस्तानी की दो लिपियाँ होंगी, परन्तु बिहार की भाषा की दो लिपियाँ क्यों हों ? राष्ट्र-भाषा हिंदुस्तानी की दो लिपियाँ होंगी, वधों द्वारा उसका स्वरूप निश्चित किया जायगा, उसमें उर्दू प्रान्तों को रिश्त दी जायगा आदि, परन्तु बिहार की प्रान्तीय हिंदुस्तानी हिंदी से भिन्न क्यों हो ? क्या अन्य प्रान्त अपने अपने यहाँ राष्ट्र-भाषा के बजाय अपनी अपनी प्रान्त-भाषा और प्रान्त-लिपि की स्थापना न करेंगे ? बिहार की ही प्रान्त-भाषा और प्रान्त-लिपि का आदर्श वर्षा की राष्ट्र-भाषा क्यों हो ? जो बात बिहार के साथ लागू है, वह महाकोशल, जिसकी मातृ-भाषा ही कोशली अर्थात् पूर्वी हिंदी है, के साथ और भी दृढ़ता के साथ लागू है । वहाँ केवल ६ प्रति शत तुल्यमान हैं, उनकी मातृभाषा भी हिन्दी है, परन्तु वहाँ भी हिंदुस्तानी के नाम पर भाषा और लिपि का पाकिस्तान खड़ा किया जा रहा है और हिंदी को विकृत किया जा रहा है (देखिये विद्यामन्दिर योजना) । जो प्रान्त अब तक भाषा की दृष्टि से एक रहे हैं, उनमें अब हिंदुस्तानी के नाम पर भाषा और लिपि की फूट डाली जा रहा है, और अपने हाथों समस्या को जटिल बनाया जा रहा है । यह बुद्धि का दिवालियापन है । इस युक्त-प्रान्त में 'हिंदुस्तानी बोलचाल' नाम से हिंदुस्तानी की जो पुस्तकें स्कूलों में जारी की गई हैं, उनकी भाषा भी बिहार की राजेन्द्र सीरीज़ और महमूद सीरीज़ की 'हिंदुस्तानी' पुस्तकों की भाषा से भिन्न नहीं है । आश्चर्य तो इस बात का है कि कामन भाषा 'हिंदुस्तानी' चलाने की फिक्र हिन्दी प्रान्तों में की जाती है जहाँ ६० प्रतिशत

ने अधिक की भाषा हिन्दी है। इन प्रान्तों को हिन्दी को बनावे रखने की सजा दी जाती है। पंजाब में जाकर 'हिन्दुस्तानी' चलाने की फिर कोश नहीं करता। वहाँ तो उर्दू ही सबकी 'हिन्दुस्तानी' होकर रहना चाहती है और कांग्रेस इससे सहमत है।

जहाँ एक ओर फारसी लिपि स्वयं राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रचलित की जा रही है, वहाँ दूसरी ओर बिहार और मध्य-प्रान्त में आदिवासी, तथालों तथा अन्य पिछड़ी हुई और जंगली जातियों में निशानरी रोमन लिपि का प्रचार कर रहे हैं जो उनके ऐसाइत प्रचार का ही एक अंग है, क्योंकि इस प्रकार वे इन जातियों को अनायास भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में डूब ले जाते हैं। इन प्रान्तों में रोमन लिपि की समझा भीषण रूप धारण करने वाली है, और लिपि का एक ओर पाकिस्तान बनने वाला है। भारत राष्ट्रीय सरकार डकड़-डकड़ देख ही नहीं रही है, रोमन लिपि के प्रचार में सहायता दे रही है *। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि इस देश की भाषा बने उर्दू और लिपि हो रोमन। इसी रोमन उर्दू को बड़े पैमाने में, सरकारी दफ्तरी में, रेडियो, आदि में प्रचारित कर रही है। इसी कारण बिहार और मध्य-प्रान्त में ही नहीं, आसाम, बंगाल, आदि में भी पिछड़ी हुई जातियों में और ट्राइबल एरियाज में जो स्वयं बक्सराव के आशय हैं रोमन लिपि का जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। इधर युक्त-प्रान्त को सरकार ने रोमन

* बिहार के पिछले कांग्रेसी मंत्रि-मंडल के समय में बिहार प्रान्तीय निरक्षरता निवारण संघ ने सचाल बच्चों की पाठ्य पुस्तकें रोमन लिपि में छपाईं। संचाल परगना में रोमन लिपि प्रचार को सरकार से पूरी सहायता मिल रही है। इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर निकाल कर संथाली स्कूलों की आरंभिक कक्षाओं में रोमन लिपि को अनिवार्य कर दिया है। इस सब में डा० सैयद महमूद का हाथ प्रत्यक्ष है। उनकी राय में जहाँ फारसी लिपि को अकेले या देवनागरी के साथ चलाना संभव नहीं, वहाँ रोमन लिपि का बड़े-छोटे सब हो जाय तो अच्छा।

लिपि प्रचार का उपक्रम किया है और रोमन लिपि में पुस्तकें छपा कर कुछ स्कूलों में जारी करा भी दो हैं। ब्रिटिश सरकार की इस दुरभिसन्धि में मुस्लिम गुट मिला हुआ है। हिन्दुस्तानी वालों के तर्क 'दोनों लिपि' के कारण राष्ट्रीय सरकार भी कुछ करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती। चाहे एक विदेशी ईसाई आकर जनता में भाषा और लिपि की फूट डाले, चाहे एक स्वदेशी मुसलमान राष्ट्रीय सरकार की नाक तले ऐसा करे, राष्ट्रीय सरकार की 'राष्ट्रीयता' दोनों के सामने पंगु है। जनता की भाषा और लिपि के प्रति अन्याय को दूर करना तो दूर रहा, वह उसमें योग देती है। जनता के शत्रु मौका पाते ही उसकी भाषा और लिपि पर प्रहार करने से नहीं चूकते, परन्तु जनता के प्रतिनिधि उनके प्रहारों का प्रतिकार करने में असमर्थ हैं। एक विदेशी सरकार एक विदेशी लिपि को हुक्म निकाल कर अनिवार्य करार दे सकती है, परन्तु स्वदेशी सरकार एक स्वदेशी लिपि को अनिवार्य करार नहीं दे सकती। उसमें उसकी 'राष्ट्रीयता' बाधक है। परन्तु ऐसी राष्ट्रीयता से न किसी राष्ट्र का उद्धार हुआ है और न हो सकता है।

परिशिष्ट ५

हिन्दुस्तानी

(लेखक—श्री भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन)

“————हिन्दुस्तानी हिन्दू-मुस्लिम पैक्ट की भाषा है, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की नहीं—एकदम बनावटी। उसका उद्देश्य है—ऐसी भाषा लिखने का प्रयत्न करना, जिसमें न संस्कृत के शब्द हों न अरबी फारसी के, और जो दोनों लिपियों में लिखी जा सके। उत्तर-भारत में काशी आर्य समाजी साहित्य प्रचलित है जो ठेठ हिन्दी है, लेकिन उसे उर्दू लिपि में लिखकर छाप दिया गया है—वहाँ तक कि आर्य समाज को संस्कृत संध्या को भी। उर्दू लिपि में लिखा होने मात्र से क्या वह साग साहित्य “हिन्दुस्तानी” समझा जायगा ? यदि नहीं, तो इधर जो कुछ साहित्य पैदा होने लगा है, जो ठेठ उर्दू है, लेकिन जिसे देवनागरी अक्षरों में भी छाप दिया जाता है वह कैसे हिन्दुस्तानी कहला सकता है ? मेरे एक आदरणीय मित्र हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जो देवनागरी अक्षरों तथा उर्दू हरफ़ दोनों में छपी है। मैंने उस किताब को हस्तलिपि के रूप में देखा। वह उर्दू में लिखी गई थी और एक दिन उन्होंने मुझमें पूछा कि अब बताओ उसमें कहाँ-कहाँ कौन-कौन शब्द काटकर बदल दिये जायँ जिससे वह देवनागरी में भी छप सके। मैंने कहा, मुझे यह अत्यन्त अस्वाभाविक मालूम होता है : इससे उर्दू शैली का प्रभाव नष्ट होता है और हिन्दी का तो आ ही

नहीं सकता। तो भी हुआ वही जो वह चाहते थे। जहाँ तहाँ कुछ शब्दों की जगह 'हिन्दी' शब्द लिख दिये गये और वह पुस्तक देवनागरी अक्षरों में भी छप गई।

एक और उदाहरण—

दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा ने 'हिन्दुस्तानी' नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की है। उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उर्दू में लिखा हुआ एक 'दीवाचा' है जो देवनागरी अक्षरों में भी ज्यों का त्यों 'दीवाचा' ही है। 'दीवाचा' शब्द फारसी का है; उसे फारसी में जगह है और हिन्दुस्तान की उर्दू में भी; लेकिन हिन्दुस्तान ही जिनको जन्म-भूमि है ऐसे ये दो शब्द, 'प्रतापना' और 'भूमिका', आप कृपया कहें कि अब कहाँ शरण देंगे? हिन्दुस्तान में तो अब उनको शरण मिलेगी नहीं, क्योंकि वे 'हिन्दुस्तानी' नहीं हैं!

और क्या यह 'न संस्कृत, न अरबी फारसी' भाषा लिखने का प्रयत्न सफल होता है? यदि आपको नारे साहित्य में "मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ" जैसे दो दो शब्दों के वाक्यों से ही काम लेना हो तो बात दूसरी है, अन्यथा आप जरा गहराई में उतरें तो आप को अपनी 'न संस्कृत, न अरबी फारसी' वाली बात तुरंत छोड़ देनी होगी। मैं इस 'हिन्दुस्तानी' किताब से ही, जो एकदम बच्चों के लिये लिखी गई है, दो उदाहरण देता हूँ। एक जगह फुटनोट है—“मुजकर मुचन्नस की वजह से इफ्तयाल में जो फर्क पैदा होता है उस्ताद उसे समझाये और मश्क कराये।” हिन्दुस्तानी आदर्शवादियों ने उसे देवनागरी अक्षरों में कैसे लिखा है—“पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की वजह से क्रियाओं में जो फर्क पैदा होता है उस्ताद उसे समझाये और मश्क कराये।” दोनों लिपियों में लिखी जाने योग्य भाषा बनाने के फेर में देवनागरी में भी 'कारण' न लिखकर 'वजह' लिखा गया है, 'अभ्यास' न लिखकर 'मश्क' लिखा गया है, 'अध्यापक' न लिखकर 'उस्ताद' लिखा

गया है, मानों ये शब्द पहले सब शब्दों की अपेक्षा मूल्य हों, 'आमरहम' हों, लेकिन तब भी क्या दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखी जा सकती? देवनागरी में 'क्रियाश्री' है, उर्दू में 'इक़्श्रात' है ('क्रि' का बहुवचन 'क्रितो' हो जाता लेकिन तब तो वह हिन्दी व्याकरण के अनुसार होता!), देवनागरी में 'पुल्लिंग' है तो उर्दू में 'सुन्नकर' है, देवनागरी में 'स्त्रीलिंग' है तो उर्दू में 'सुबन्नस' है।

दूसरा उदाहरण लें—पृष्ठ १४ पर—“सुनकल्लम-हाजिर-गायब हासलों की मश्क फंते-हाल के सुन्नकर सुबन्नस की सूरतों में करा दी जाय।” दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखने के इच्छुकों को देवनागरी में इसे यूँ लिखना पड़ता है—“उत्तम और मध्यम पुरुष की मश्क वर्तमान-काल के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों में करा दी जाय।” दोनों वाक्यों में एक ‘मश्क’ शब्द को छोड़कर कौन सा विशेष शब्द समान है? यदि हम ‘अम्बास’ की जगह इस ‘मश्क’ शब्द को ही अपनी भाषा में जगह दें और हिन्दुस्तानी की खातिर ‘अम्बास’ को देश निकाला भी दे दें तब भी क्या इससे वह हिन्दी ‘हिन्दुस्तानी’ हो जाती है?

अभी अभी दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा के १९३०-१३वें वरदा-दान के अवसर पर जनाब सैयद अब्दुल्ला बरेलवी साहब ने एक तकरीर प्रस्तुत की है। उसमें आपने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को नेक सलाह दी कि वह अपना नाम ‘हिन्दी प्रचार सभा’ न रखकर ‘हिन्दुस्तानी प्रचार सभा’ में तब्दील कर दे। आर प्रस्तावते हैं—“हिन्दी नाम से पैदा होने वाले भ्रम को हटाने के लिये मैं अपनी असील पर जोर दूँगा, खास करके इसलिये कि मुझे यकीन है कि इस तवादले से मुसलमानों के मन पर अच्छा असर पड़ेगा।” कुछ लोग कहा करते हैं कि नाम में क्या रक्ता है, लेकिन बरेलवी साहब नाम के तवादले से ही मुसलमानों के मन पर बड़ा अच्छा असर पैदा करने की उम्मीद करते हैं। आपने अपनी तकरीर में प्रस्तावित है कि

कौमी ज़वान को उसके जो तीन नाम मिले हैं—हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी—वे तीनों मुसलमानों के दिये हुये हैं। यदि यह बात ठीक है तो 'हिन्दुस्तानी' नाम में वह कौन सी खासियत है जिसको वजह से मुसलमान भाई 'हिन्दी' और 'उर्दू' दोनों नामों पर उसे तरजीह देंगे? आज आप मुसलमानों पर 'अच्छा अस्तर पड़ेगा' की बात कहकर राष्ट्रभाषा को 'हिन्दुस्तानी' कहने की सलाह दे रहे हैं, कल आप उसे उर्दू ही कहने का सलाह भी दे ही सकते हैं। १९४२ में गांधीजी ने जब 'हिन्दुस्तानी सभा' की नींव डाली तब उसके ३८ बुनियादी मेम्बरों में कितने मुसलमान भाई मेम्बर बने थे? स्वयं बरेलवी साहब तो खर उसमें थे ही नहीं, कसम खाने के लिये तीन नाम दिखाई देने हैं, लेकिन ऐसे जिन में से कोई भी भाषा सम्बन्धी शोधों के लिये प्रसिद्ध नहीं—न आजाद हैं, न जाकिरहुसैन हैं, न मौलाना अब्दुलहक हैं।

हमें जमा किया जाय, यह 'हिन्दुस्तानी' आन्दोलन हमारे मान्य राजनीतिक नेताओं की सूझ है और किसी राजनीतिक आवश्यकता का ही परिणाम भी। लेकिन शर्तों पर आश्रित एकता—बनावटी एकता—स्थायी नहीं होती।”

(बम्बई हिन्दी विद्यापीठ के प्रमाणपत्र-वितरणोत्सव के अवसर पर १९४४ में दिये दीक्षान्त भाषण से)

परिशिष्ट ६

“हिन्दुस्तानी का प्रचार क्यों ?”

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की रिपोर्ट पर एक दृष्टि

(लेखक—श्रीप्रसूदयाल नीतल, प्रधान मन्त्री, वज्र-साहित्य-संजाल)

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को ओर से निम्नलिखित वर्ष ता. २६ जनवरी, १९४५ को वर्षा में ‘अखिल भारत हिन्दुस्तानी-प्रचार सम्मेलन’ हुआ था। महात्मा गांधी उसके सभापति थे। इस सम्मेलन की रिपोर्ट ‘हिन्दुस्तानी-प्रचार क्यों?’ नाम से अब पुस्तकाकार प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट से हिन्दुस्तानी-प्रचार के सम्बन्ध में आवश्यक बातें ज्ञात हो सकती हैं।

इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य बतलाते हुये मन्त्री श्री श्रीमन्नारायण जी अग्रवाल ने कहा—

“हमने यह महसूस किया कि हिन्दुस्तानी भाषा का रूप तय करने और हिन्दुस्तानी में जरूरी साहित्य तैयार करने के लिये सभा के मेम्बरों के अलावा हिन्दी और उर्दू के हमारे विद्वानों और साहित्यों की जरूरत है। इस विचार को मैंने पूज्य गान्धीजी के सामने रक्खा। उन्होंने भी उसे पसन्द किया। इसलिये यह कान्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया।”

सम्मेलन के प्रथम दिन उसके सभापति महात्मा गांधी का मौन-दिवस था, अतः उनका निश्चित संदेश पढ़ने पर कार्यवाही प्रारम्भ हुई। अपने संदेश में महात्माजी ने आगत सज्जनों को उपस्थिति पर प्रसन्नता प्रकट करते हुये दो सज्जनों की अनुपस्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया। पहले सज्जन

डाक्टर अब्दुल हक थे, जो दूसरे दिन सम्मेलन में उपस्थित हो गये थे। दूसरे सज्जन श्रीपुरुषोत्तमदास टंडन थे, जो बीमार होजाने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

सम्मेलन की कार्रवाई आरम्भ करते हुये डा० सैयद महमूद ने हिंदुस्तानी के विषय में अपने विचार प्रकट किये। उसके नामकरण के सम्बन्ध में आपने कहा—

“मैं खुद तो कौमी ज़वान के लिये ‘हिन्दी’ नाम को ही पसन्द करूँगा क्योंकि यह बड़ा आसान और खूबसूरत लफ्ज़ है। मगर चूँकि यह नाम अब संस्कृत शब्दों से भरी हुई ज़वान के मानी रखता है, इसलिये उसको छोड़कर ‘हिन्दुस्तानी’ नाम को अपनाना पड़ रहा है।”

‘उर्दू’ शब्द की उत्पत्ति के विषय में आपने कहा—

“अँगरेज़ों ने हमको बताया है कि ‘उर्दू’ लफ्ज़ के मानी ‘वाज़ार’ या ‘छाबती’ के हैं और वह तुर्की लफ्ज़ है। मगर मैंने एक जगह पढ़ा है कि उर्दू संस्कृत का एक लफ्ज़ है, जिसके मानी मिले हुये या मिक्सचर या कम्पाउन्ड के हैं और यह यहीं का लफ्ज़ है। शायद ज़्यादा खोज तलाश करने के बाद यह साबित होजायगा कि यह लफ्ज़ उर्दू इत्नी लफ्ज़ ‘उर्दू’ से निकला है।”

इस सम्मेलन में जो भी भाषण हुये उन सबमें हिन्दुस्तानी का समर्थन किया गया। भाषणकर्ता चाहे वे हिन्दू थे, चाहे मुसलमान, चाहे वे हिन्दी के विद्वान थे और चाहे उर्दू के माहिर, उन सबने उर्दू शब्दों की भरमार की थी। सभी वक्ताओं ने हिन्दुस्तानी को फ़ारसी और नागरी दोनों लिपियों में लिखे जाने का समर्थन किया। केवल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा के प्रधान मंत्री श्रीमदन्त आनन्द कौसल्यायन और धारवाड़ के श्रीसिद्धनाथ पंत ने दोनों लिपियों का विरोध करते हुये नागरी के समर्थन में अपने विचार प्रकट किये।

श्रीग्रामनन्द कौमल्यायनजी ने कहा—

“कल और आज मैंने जो भाषण सुने, उनमें सभी आशा की वनिस्वत निराशा ही अधिक हुई। ‘हिन्दी’ और ‘उर्दू’ शब्दों में तो मेरे दिमाग में कुछ अर्थ निकलता है, मगर ‘हिन्दुस्तानी’ क्या चीज़ है ? मुख्य प्रश्न लिपि का है। मेरी समझ में नहीं आता कि एकता के नाम पर हम जो बात भाषा के नाम पर कहते हैं, वही लिपियों के बारे में क्यों न कहें ? एक भाषा की तरह एक लिपि का आग्रह हम क्यों न रखें ?”

श्रीसिद्धनाथजी पंत ने कहा—

“लिपि के बारे में यह तय किया जाय कि जिसे जो लिपि पसन्द होजाय, उसे वह स्वीकार करे। दोनों लिपियाँ लाज़िमी करने से फायदा न होगा। ‘राष्ट्रभाषा एक, राष्ट्रलिपि अनेक’ वाला नया नारा देश में काशी गड़बड़ी करेगा। दक्षिण भारत में हमने निम्नले २५-२६ वर्षों में देवनागरी के द्वारा प्रचार करते हुये बड़ी सफलता पाई है, और हम देवनागरी के देशव्यापी प्रचार के कायल हो गये हैं। इसलिये हमें देवनागरी के द्वारा हिन्दुस्तानी का प्रचार करने को आज़ादी मिलनी चाहिये।”

इस सम्मेलन में मौकाना नैयद सुलेमान तन्वी, डा० जाफर हसन, श्रीसरयनारायण, डा० अब्दुल हक और डा० नाराचन्द्र के बड़े कन्वे चौड़े भाग्य हुये, जिनमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा की ज़रूरत बकालत की।

इस सम्मेलन में दो ‘उद्घाटन’ सत्र हुये थे। पहला उद्घाटन पं० सुन्दरलाल ने पेश किया—

“इस कान्फरेन्स की राय में हिन्दुस्तानी ज़बान को फैलाने और तर्की देने के लिये इस बात की ज़रूरत है कि हिन्दी जाननेवाले उर्दू लिखावट को और उर्दू जाननेवाले नागरी लिखावट को जल्दी से जल्दी सीख लें और जो लोग इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानते, वह भी दोनों ही को सीखें, ताकि सब लोग हिन्दुस्तानी के रूपों—हिन्दी और उर्दू को—पढ़

और समझ सकें और इस तरीके से हिन्दुस्तानी का विकास और प्रचार हो सके।”

इस प्रस्ताव पर बोलते हुये पं० सुन्दरलाल जो ने कहा—

“मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ पूरे दिल से न ‘अंजुमन-तरकी-ए-उर्दू’ है, न ‘हिन्दी साहित्य सम्मेलन’, पर इससे मुझे अचरज नहीं होता। अचरज तो इस बात का है कि इतने लोग भी हमारे साथ कैसे हैं।”

इस प्रस्ताव के समर्थन में कई भाषण हुये। श्रीभदन्त आनन्द कौसल्या-यन ने फिर इसके विरोध में अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा—

“बोली जानेवाली ज़बान में तो लिपि का सवाल ही नहीं उठता; मैं यह पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा सीखने के लिये वह ज़रूरी है कि दो लिपियाँ सीखनी ही चाहिये?.....मैं यह कहूँगा कि दोनों लिपियों को लाज़मी तौर पर सीखने की बात को हटा दिया जाय तो अच्छा होगा।”

श्री तिवारामशरण जी गुप्त ने दबी ज़बान से पूछा—

“इस सभा के कार्य से हिन्दी या उर्दू का विरोध तो नहीं होगा?”

इसके उत्तर में महात्मा गांधी जी ने कहा—

“इसका जवाब वाद में दूँगा। श्री आनन्द जी ने जो कहा वह मैं समझ गया। उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा।”

अंत में राय लेने पर प्रस्ताव पास हो गया।

डा० ताराचन्द्र जी ने दूसरा ‘ठहराव’ पेश किया—

“देश के सब लोग इस बात को मानते और समझते हैं कि हमारे कौमी जीवन को मजबूत करने और अलग अलग खूबों के लोगों में मेल-जोल और व्यवहार की एक भाषा बनाने के लिये चाहिये कि हिन्दुस्तानी ज़बान को तरक्की दी जावे और उसकी रूप-रेखा ठीक की जावे, क्योंकि इस बात के लिये यही भाषा सब से ब्योदा काम की है।

यह कान्फ़रेन्स फैसला करती है कि पन्द्रह तक मेम्बरों की एक कमेटी

बनाई जाये, जो हिन्दुस्तानी भाषा की डिक्शनरियाँ तैयार करे, भाषा के कायदे तय करे, उसके लफ्जों का भण्डार बढ़ावे, उनके रूप बँटें, और उसमें अच्छी-अच्छी और काम की कितनी लिखवावे।”

यह प्रस्ताव भी नास हो गया।

अन्त में महात्मा जी ने अपनी भाषण दिया—

“मैं नहीं चाहता कि हिन्दी मिट जाय या उर्दू नष्ट हो जाय। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि दोनों हमारे नाम की हो जाँय। आनन्द जी कहते हैं कि सबको दो लिपियाँ सीखने में बड़ी सुविधा उठानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। और अगर हाँ भी तो उसे पार करना ही होगा। ... मैं हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये जीता हूँ। मैं जानता हूँ कि हिन्दुस्तानी के प्रचार में हिन्दू मुस्लिम एकता होगी, मगर इस वक़्त मैं आपको यह लाजब नहीं दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हिन्दी और उर्दू दोनों का भला हो। इन दोनों से मुझे काम लेना है। हिन्दी वाले चाहते हैं कि मैं हिन्दी की ही नौबत बघाता रहूँ, उर्दू का नाम न लूँ। मगर मैं तो अहिंसा का माननेवाला सत्याग्रही हूँ। मैं वह कैसे कर सकता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ कोई काम न होगा। पर दोनों लिपियाँ सीखने की तकलीफ़ तो ग़ारा करनी ही होगी। मैं तो आनन्द जी से भी काम लेना चाहता हूँ।”

मदके अन्त में उर्दू भाषा के प्रयत्न समर्थक पं० ब्रजमोहन दत्तात्रेय ‘कैसी’ ने अपनी ‘नज़्म’ पढ़ कर सुनाई। नज़्म का कुछ भाग इस प्रकार है—

“जो उल्टी समझ है तो है काम उल्टा,
कि वह सीधी बातों को उलझा रहे हैं।
नई उलझनों और पड़ती हैं आकर,
वह क्या सुविधाएँ आप सुझा रहे हैं।

किधर जा रहे हैं, नहीं इसकी सुध-बुध,
जो हैं अपनी धुन में चले जा रहे हैं।”

इस सम्मेलन के पश्चात् हिन्दुस्तानी प्रचार का जितना कार्य हुआ, यह तो हमको ज्ञात नहीं है, किन्तु इस सम्मेलन के बाद ही महात्मा जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया और उनके अनुकरण पर अन्य कई सज्जनों ने भी त्याग-पत्र देकर हिन्दी प्रचार के कार्य से वैराग्य ले लिया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, जो अहिन्दी प्रान्तों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी, अब इस हिन्दुस्तानी आन्दोलन के कारण अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकने की स्थिति में नहीं है। दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा, जो पिछले २८ वर्ष से दक्षिण में हिन्दी प्रचार का प्रशंसनीय कार्य कर रही थी, अब अपना नाम ‘दक्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा’ में बदल कर दोनों लिपियों वाली हिन्दुस्तानी का कार्य करने का संकल्प कर चुकी है। अब तक हिन्दी का कार्य एक राष्ट्रीय कार्य समझा जाता था, किन्तु अब उसे साम्प्रदायिक कह कर उसका महत्व कम किया जा रहा है। समस्त हिन्दी हितैषियों को हिन्दी पर आये हुये इस महान् संकट का दूर करने का उपाय सोचना चाहिये।

(१७ मरचरी, १९४६ के ‘देशदूत’ से)

परिशिष्ट ७

दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किधर ?

(लेखक—गविशंकर शुक्ल)

लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गांधी ने एक राष्ट्र-भाषा और एक राष्ट्र-लिपि की आवश्यकता अनुभव की। उन्हें हिन्दी और देवनागरी क्रमशः राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि होने योग्य जँचीं। वे इस निष्कर्ष पर देश की भाषा-स्थिति पर निष्पक्ष भाव से विचार करके पहुँचे। उस समय आज जैसा साम्प्रदायिकता का दौर दौरा नहीं था। गांधीजी ने दक्षिण को उत्तर से राष्ट्र-भाषा के वर्धन में बाँधने के लिये दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से भी प्रकट है, दक्षिण भारत में राष्ट्र-भाषा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी का प्रचार करना था। सभा अपने उद्देश्य में पूर्ण सकल रही है। अपनी रजत जयन्ती के अवसर पर आज दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी जिन्दगी के विद्युत् २५ वर्षों पर सन्तोष भरी दृष्टि डाल सकती है। अब सभा की जिन्दगी का दूसरा दौर—हिन्दुस्तानी वाला दौर—आरम्भ होना चाहता है, अर्थात् सभा अब गांधीजी की नई परिभाषा के अनुसार दक्षिण में हिन्दी और उर्दू दोनों और देवनागरी और फारसी लिपि दोनों का प्रचार करेगी, और राष्ट्र-भाषा मानने के इच्छुक प्रत्येक दक्षिण-वासी को हिन्दी उर्दू दोनों और दोनों लिपियाँ सीखनी पड़ेंगी। इस दूसरे दौर के आरम्भ होने के अवसर पर सभा और हिन्दी के हितैषियों के विचार सभा के कार्य-कर्त्ताओं और संचालकों के सामने रखना अनुचित न होगा।

यह तो स्पष्ट ही है कि गांधीजी ने राष्ट्र-भाषा की अपनी पहली परिभाषा अर्थात् हिन्दी मुसलमानों द्वारा मान्य न होने के कारण ही दूसरी परिभाषा अर्थात् हिन्दुस्तानी की है। परन्तु क्या यह नई परिभाषा मुसलमानों को मान्य है? उत्तर है—‘नहीं।’ हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी केवल हिन्दू रट रहे हैं, हिन्दू ही आपस में हिन्दी और हिन्दुस्तानी के मसले को लेकर बाद-बिवाद कर रहे हैं, और हिन्दुस्तानी प्रचारकों की फौज में सब हिन्दू ही हिन्दू हैं। मुसलमानों को इस हिन्दुस्तानी से भी कोई सरोकार नहीं। हिन्दुस्तानी की धूम हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में ही सुन पड़ती है। जहाँ जहाँ मुसलमानों के हाथ में शक्ति है, अर्थात् काश्मीर, पंजाब, सीमा-प्रान्त, सिन्ध और हैदराबाद में, वहाँ सब शान्त है, या यों कहिये, वहाँ उन्होंने उर्दू-हिन्दुस्तानी और उर्दू-लिपि को पहले से ही राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि—डीकैक्टो राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि—बना रक्खा है, और उनमें उन्हें हिन्दी और देवनागरी जोड़ने की न जरूरत है और न यह उन्हें पसन्द है। यह श्रुत सत्य है कि इन पाकिस्तानी प्रान्तों और रियासतों में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी और देवनागरी को उर्दू और उर्दू लिपि के समकक्ष स्थान कभी नहीं मिलेगा, और न वहाँ उर्दू और उर्दू लिपि के साथ साथ हिन्दी और देवनागरी का सोचना किसी के लिये अनिवार्य किया जायगा। गांधी जी का हिन्दुस्तानी प्रचार भी महाराष्ट्र, विहार, दक्षिण, आदि हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों तक ही सीमित है, और रहेगा।

ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केवल एक ही परिणाम होगा। वह है—असलियत में अर्थात् व्यवहार में केवल उर्दू का राष्ट्र-भाषा और केवल उर्दू लिपि का राष्ट्र-लिपि हो जाना। क्योंकि जब पाकिस्तान के सब निवासी केवल उर्दू और उर्दू लिपि और ‘हिन्दुस्थान’ के सब निवासी हिन्दुस्तानी प्रचार की बदौलत हिंदी उर्दू दोनों और दोनों लिपियाँ जानते होंगे, तो कामन भाषा और कामन लिपि अपने आप उर्दू और उर्दू-लिपि

होंगे। एक अखिल भारतीय सभा में जो बह्ता सबको अपने विचार सम-
झाना चाहेगा वह अपने आप उर्दू में बोलेगा, और जो लेखक अपनी पुस्तक
सम्मत भारत के लिये सुलभ करना चाहेगा वह अपने आप उर्दू और उर्दू-
लिपि में लिखेगा। एक राजनीतिक आन्दोलन के कारण उर्दू और उर्दू-लिपि
का इस देश की राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि हो जाना कितना अस्वा-
भाविक, अप्राकृतिक एवं अन्याय पूर्ण होगा वह बतलाने की जरूरत नहीं।
और उर्दू के राज्य में प्राचीन भाषाओं की और भारतीय संस्कृति की क्या
दशा होगी, वह समझने के लिये आज अँगरेजों के राज्य के कारण प्राचीन
भाषाओं और भारतीय संस्कृति पर जो गुजर रही है, उसे जान लेना काफी
होगा। यदि दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को यही अभीष्ट है तो वह
'दक्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा' (सभा का राबि की द्वारा प्रस्तावित
नया नाम) बने, और हिन्दी के प्रचारक हिन्दी का वाता उत्तर का हिन्दु-
स्तानी का वाता धारण करें, और दक्षिण वालों को उर्दू के सम्वन्ध में उर्दू
और उर्दू लिपि सिखावें।

तानी एक हाथ से नहीं बजती। एकता और मेल दो व्यक्तियों में होता
है। जब तक सुसलमानों को एकता अभीष्ट नहीं, तब तक केवल हिन्दुओं
के हिन्दी और हिन्दुस्तानी वाले दो दलों का आगत में कोई समझौता कुछ
अर्थ नहीं रखता। जब तक उर्दू प्रान्तों की सरकारें उर्दू के स्थान में अपनी
दो लिपियों सहित 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित करने के लिये तैयार नहीं, तब
तक हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी उर्दू के समन्वय का अर्थ है केवल हिन्दी का
नाश और उसका उर्दू में परिवर्तित हो जाना, और जब तक सुसलमानों
को हिन्दुस्तानी का मूल मंत्र—दोनों 'शैलियाँ' और दोनों लिपियाँ—मान्य
नहीं, तब तक हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में दोनों शैलियों और दोनों लिपियों
के प्रचार का अर्थ है उर्दू और उर्दू लिपि को डीपैक्टो राष्ट्र-भाषा और
राष्ट्र-लिपि बताना।

गांधीजी की नई परिभाषा कितनी अव्यावहारिक—विशेषकर इस निरक्षर देश के लिये—और अवैज्ञानिक भी है, इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। यह कहने की भी जरूरत नहीं कि दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा दक्षिण वालों पर हिन्दी और देवनागरी, जो उनके लिये अपेक्षाकृत सुगम हैं, के साथ साथ उर्दू और उर्दू लिपि का बोझ डालकर उनके साथ विशेष अन्याय करेगी, और उतनी सफलता भी कदापि प्राप्त न कर सकेगी जो उसने सन् २५ वर्षों में प्राप्त की है। वह कदाचित् उतनी लोक-प्रिय भी न रहेगी। एक बहुत बड़े नेता की बात भी प्रकृति से ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकती। दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा अपना कलेवर बदलने से पहले एक बार ठंडे दिल से फिर विचार कर ले।

परिशिष्ट ८

महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष क्यों ?

(लेखक—ग० स० आनंद)

विलम्बित दिनों महात्मा गांधी के पुना में निवास करने तथा समय-समय पर नेताओं के आगमन से राष्ट्रभाषा-प्रचार कार्य में कुछ सगर्मी दिखाई देने लगी है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के हिन्दी प्रचार का कार्य यहाँ कासी अरसे से हो रहा है और पुना में उसका एक गढ़ सा बन गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार की शिक्षाओं में महाराष्ट्र प्रांत के काजी विद्यार्थी परीक्षा देते और उत्तीर्ण होते आये हैं। महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे विद्वानों का इस कार्य में दगादर सहयोग रहा है, किन्तु जब से गांधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग हुए हैं तब से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का भी काम यहाँ ज़ोरों से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता श्री शंकरराव देव तथा वयई के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री बी० जी० खेर, श्री दत्तो बामन पोटार, आदि नेता और विद्वान हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं, इससे इस ओर कासी प्रगति दिखाई दे रही है। पहले तो हिन्दुस्तानी प्रचार का काम यहाँ एकदम ठप्प सा हो गया था क्योंकि अकेले काका साहेब कालेलकर कहाँ तक इसका भार वहन कर सकते थे, किन्तु जब से उसे देश की कुछ महान् शक्तियों का दल मिला है तब से हिन्दुस्तानी प्रचार के काम में चेतना आई है। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के काम में किसी तरह की शिथिलता आ गई हो, किन्तु आज के वातावरण से यह

साफ़ ज़ाहिर हो गया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचार आन्दोलन के कार्य में एक किस्म का संघर्ष आरम्भ हो गया है। एक ओर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा और दूसरी ओर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अपने अपने उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रभाषा के काम में लगी हुई हैं। पूना में अब दो दल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यों में सहयोग देने लगा है, और दूसरा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर रहा है।

मुझे तो आश्चर्य होता है कि हिन्दी के पत्रकारों को यह पता भी नहीं है कि महाराष्ट्र में इस समय राष्ट्रभाषा संबंधी प्रगति किधर जा रही है। हिन्दी पत्रकार केवल हिन्दी के नाम पर धारोधार आँसू बहा सकते हैं या आपसी तू-तू में-में में पत्रों के कालम रँग सकते हैं, किन्तु वे शायद यह नहीं जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में हिन्दी आन्दोलन का मुहड़ा थामने की बड़ी आवश्यकता है। हिन्दी वालों को यह पता नहीं है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की परीक्षाओं के समान ही हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने भी महाराष्ट्र में प्रचारक परीक्षाएँ प्रारम्भ कर दी हैं। दोनों की परीक्षाओं के नाम भी एक ही से हैं। हाँ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की परीक्षाओं के फार्मों के नामों में परिवर्तन है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा संगठित महाराष्ट्र की प्रचार समिति के कई विद्वान् और प्रचारक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्य में शरीक हो गये हैं। आचार्य दत्तो वामन पोद्दार इसके प्रधान हैं।

पिछले दिनों श्री भद्रन्त कौसल्यायन पूना आये थे और एक समान परीक्षाओं की प्रतिद्वंद्विता देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुरानी की जगह एक नई समिति संगठित की है जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा होने वाली परीक्षाओं का संचालन और सम्मेलन की नीति के अनुसार राष्ट्रभाषा-प्रचार का काम करेगी। श्रीयुत नने पहले राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से काम करते थे, किन्तु अब वह हिन्दुस्तानी प्रचार समिति में

शरीक हो गये हैं। उनके स्थान पर श्री मोन् ताई काखे की नियुक्ति हुई है। नूतन मराठी विद्यालय के कुछ प्रमुख अधिकारी भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कार्य में सहयोग दे रहे हैं।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के आदर्शों में जैक भिन्नता है, इसलिये संघर्ष होना अनिवार्य भी है। हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के पास धन की कमी नहीं, और राष्ट्र तथा महाराष्ट्र के नेता उसके साथ हैं। दूसरी ओर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पास धन तो नहीं है, किन्तु श्रेष्ठ कार्य-कर्त्ताओं का उसमें अभाव नहीं है। इन संस्थाओं के वर्त्तमान संघर्ष का क्या फल होगा, इस पर कोई भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, किन्तु हिन्दी-पत्रकार और हिन्दी के घनो-धोरी अगर अपनी कुल्हड़ में रुड़ फोड़ने की नीति को त्याग कर सचेत न हुए तो एक न एक दिन सत्रास की भाँति महाराष्ट्र भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रचार-क्षेत्र से अपने को स्वतन्त्र बना लेगा। क्योंकि बेचारे भदंत जी अकेले कहाँ कहाँ प्राण देते करेंगे ?

मैंने यह विचार आपके पत्र द्वारा इसलिये व्यक्त किये हैं कि 'देशदूत' हिन्दी जनता में हिन्दी का प्रयत्न समर्थन और व्यापक प्रचार करता आया है। उसके द्वारा हिन्दी संसार को यह ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा की प्रगति आज किधर जा रही है, हिन्दी वालों के कानों तक यह समाचार पहुँचे तो !

(२ दिसम्बर, १९४५ के 'देशदूत' से)

परिशिष्ट ६

महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार

(लेखक—श्री सूर्यप्रकाश एम० ए०)

गत १६ दिसम्बर के 'देशदूत' में श्रोयुत श्रीपाद जोशी का पत्र पढ़कर खेद भी हुआ और ग्लानि भी। न मालूम वेचारे सम्मेलन ने क्या अपराध किया है कि हर किसी ने उसे गाली सुनाना अपना जन्मसिद्धि अधिकार समझ लिया है। जोशी जी पूछते हैं, "हिन्दी साहित्य सम्मेलन राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में अपनी टाँग क्यों अड़ाता है?" जोशी जी को टाँग अड़ाने का अधिकार है, उनकी महाराष्ट्र प्रचार समिति का अधिकार है, परन्तु करोड़ों हिन्दी भाषी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन को नहीं! मानो हिन्दी का क्षेत्र देश में है ही नहीं, और उस क्षेत्र के निवासियों का राष्ट्रभाषा से कोई सम्बन्ध नहीं! हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का काम केवल 'हिन्दुस्तानी साहित्य' की उन्नति और विकास करना न होकर राष्ट्रभाषा के मामले में हस्तक्षेप करना हो सकता है, परन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपना वर्तमान नाम रहते इस मामले में नहीं बोल सकता! हिन्दुस्तानी प्रचार सभा अपनी परिभाषा की राष्ट्रभाषा का प्रचार सम्पूर्ण भारत में कर सकती है, परन्तु सम्मेलन को अपनी परिभाषा की राष्ट्रभाषा का अहिन्दी प्रान्तों में प्रचार करने का अधिकार नहीं! ऐसा करना उसके लिये 'जिद' है!

सम्मेलन आज भी वही कर रहा है जो २५ वर्षों से करता आ रहा है। महात्मा गांधी को भी उसकी नीति मान्य रही है। गांधी जी के सम्मेलन से त्याग-पत्र देते ही गांधीजी के भक्तों की दुनिया एकदम बदल गई, और सम्मेलन

अंग्रेजी ही गया ! उनकी हिन्दुस्तानी की परिभाषा भी 'कांग्रेस की परिभाषा' हो गई ! क्या जोशीजी बतलाने को कृपा करेंगे कि कांग्रेस ने किस प्रस्ताव में राष्ट्रभाषा की परिभाषा दी है, और क्या देश के पाकिस्तानी प्रान्त भी अब तक गांधी जी के कारण सम्मेलन का 'खिराज' देने रहे हैं और अब गांधी जी के हट जाने के कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को 'खिराज' देने लगे हैं ? क्या जोशी जी को विश्वास है कि हिन्दुस्तानी की परिभाषा को पाकिस्तानी प्रान्तों ने मान लिया है, अथवा क्या उनके 'सारे देश' में वे प्रान्त और वे लोग शामिल हैं ही नहीं ?

जोशी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का हिन्दुस्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध नहीं है और उनकी परिभाषा भी अलग है । सम्बन्ध नहीं है तो हो जायगा । परिभाषा भी शीघ्र वही हो जायगी । इसीलिये तो वह सम्मेलन से अलग हुई है । परिभाषा में और पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते करते ही तो होगा । अभी तो पाठ आरम्भ हुआ है ।

विभिन्न प्रान्तों की राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ अलग अलग होकर अलग अलग परिभाषा को मानकर चाहे जिस भाषा का अपने अपने प्रान्त में प्रचार करें, परन्तु वे उन्हें 'राष्ट्रभाषा' कैसे कह सकती हैं ? महाराष्ट्र की जोशी जी वाली राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ही अपने आपको इस नाम से क्यों सम्बोधित करती है ? क्या उसे विश्वास है कि देश के हिन्दी प्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों ने भी उसकी परिभाषा को मान लिया है ? जोशी जी के महाराष्ट्र ने यह कैसे समझ लिया कि हिन्दी प्रान्तों को अहिन्दी प्रान्त पर अपनी राष्ट्रभाषा लादने का अधिकार नहीं है लेकिन अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी प्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों पर अपनी परिभाषा लादने का अधिकार है ?

हिन्दुस्तानी आन्दोलन से जो होना था सो हो रहा है । प्रत्येक प्रान्त की अलग अलग परिभाषा होगी, एक एक प्रान्त में दो-दो राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ हो जायँगी, और 'हिन्दुस्थान' की राष्ट्रभाषा खटाई में पड़ जायगी।

इसके बरक्स ज़रा पाकिस्तान पर नज़र डालिये । उसने अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू पहले से ही बना ली है । वहाँ न किसी ने उर्दू के मामले में चीन्चपड़ की (बल्कि कहिये उन्होंने आग्रह दिखलाया), और न पाकिस्तानियों में आपस में राष्ट्रभाषा के मसले को लेकर झगड़ा हुआ । पाकिस्तानियों ने न गांधी जी की पहले वाली राष्ट्रभाषा को माना था और न उन्हें गांधी जी की नई परिभाषा से कोई सरोकार है और न होगा—उन्हें जरूरत ही क्या है ? (यदि जोशीजी को इसमें सन्देह है तो वे पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिंध की सरकारों से अब या कभी भविष्य में देवनागरी लिपि भी, और अपनी ५०-५० प्रतिशत वाली अथवा 'ग्रामफहम' हिन्दुस्तानी मनवा देखें) । 'हिन्दुस्थान' में अलवत्ता 'राष्ट्रवादी' राष्ट्र-भाषा के टुकड़े टुकड़े कर डालें, उर्दू और उर्दू-लिपि की प्रतिष्ठा करें, 'कंग्रेस परिभाषा में निवास करने वाले' मराठे प्रतिवर्ष हजारों रुपये देकर महाराष्ट्र में उर्दू और उर्दू-लिपि का प्रचार करें, और 'हिन्दुस्थान' की राष्ट्रभाषा भी उर्दू बनावें, क्योंकि वह तभी पाकिस्तान और 'हिन्दुस्थान' दोनों की कामन 'ग्रामफहम' हिन्दुस्तानी होगी, अन्य कोई उपाय नहीं । ईश्वर हिन्दुओं को शीघ्र सद्बुद्धि प्रदान करे !

जोशीजी अच्छी तरह समझ लें कि महाराष्ट्र के जिन व्यक्तियों ने गांधीजी के पीछे आँख मूँद कर, राष्ट्रीयता की दुहाई देते हुये चलना ही अपना धर्म नहीं समझ लिया है, उन्हें सम्मेलन से सहयोग पाने का अधिकार है, और उन व्यक्तियों को अपना सहयोग देना सम्मेलन तथा हिन्दी भाषी जनता का कर्त्तव्य है । जोशीजी यह भी समझ लें कि यदि उनकी प्रचार-समिति को भी खड़ी बोली, जिसको वे हिन्दुस्तानी कहते हैं, के ही आधार पर राष्ट्रभाषा बनाना है तो उसे भी झूल मार कर हिन्दी भाषियों की भाषा और साहित्य को आदर्श मानना पड़ेगा—यदि उसे एक जीवित राष्ट्रभाषा और एक जीवित साहित्य अभिष्ट है तो । जोशीजी यह विश्वास रखें कि महाराष्ट्र में सम्मेलन की परिभाषा वाली राष्ट्रभाषा का प्रचार पहले भी

महाराष्ट्रों ने किया था और अब भी वे ही करेंगे। सभावाद और कांग्रेसवाद का भेद करना व्यर्थ है। 'राष्ट्रीयता' केवल जोशीजी और उनकी प्रचार-समिति के ही पल्ले नहीं पड़ी है। यदि मौलाना आज़ाद, सरोजि नेता अंजुमन-तरक्की-उर्दू, जो उर्दू को राष्ट्रभाषा मानता है, के सदस्य होते हुये कांग्रेस में रह सकते हैं तो वरम राष्ट्रीय वृत्ति के व्यक्ति सम्मेलन में रह सकते हैं। 'राष्ट्रीयता' हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वालों की दमोटी नहीं है। गांधीजी ने भी सम्मेलन को अराष्ट्रीय बतलाने का साहस नहीं किया है। श्री मुंशी के कथनानुसार जिसके सिद्धान्त में सत्य होगा अन्त में उसी की विजय होगा। श्री जोशीजी धैर्य धारण करें। उन्हें जो अच्छा लगे, वह अवश्य करें, परन्तु दूसरे जो करना चाहें उसे यदि वे परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अराष्ट्रीय कहकर रोक्ये वड़े मनने का लोभ संवरण कर सकें तो अच्छा हो। वे वह भी याद रखें कि वे जिस आज और शक्ति से बातें करते हैं वह उनकी अपनी नहीं बल्कि उधार ली हुई है।

अन्त में हम जोशीजी से इतना और पृच्छना चाहेंगे कि जिस भाषा में उन्होंने अपना पत्र लिखा है वह 'साहित्यिक हिन्दी' है अथवा 'आमफहम हिन्दुस्तानी' ? यदि वह 'आमफहम हिन्दुस्तानी' है तो उनकी और हमारी परिभाषा में कोई अन्तर नहीं, केवल नाम का भेद है जो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिये महाराष्ट्र की दोनों प्रचार समितियों को हाथ मिला लेना चाहिये। यदि वह 'साहित्यिक हिन्दी' है, तो अच्छा होता यदि वे उसे 'आमफहम हिन्दुस्तानी' में लिखते। 'सारे देश' को मालूम तो हो जाना कि वह अब किस 'आमफहम हिन्दुस्तानी' को राष्ट्रभाषा मानने लगा है, देश के ४० करोड़ में से कितनों के लिये वह 'आमफहम' है, अथवा 'साहित्यिक हिन्दी' समझने वालों से कितने अधिक दूर नाशियों के लिये वह 'आमफहम' है, और वह किस लायक है ? (परन्तु गांधीजी तो कहते हैं कि 'सरस्वती' अभी प्रकट होने की है। प्रकट होने से पहले ही वह 'आमफहम' कैसे हो गई ?)

खैर, कोई बात नहीं, अगला पत्र 'आमफहम हिन्दुस्तानी' में भेजें, और यदि कोई और पत्र नहीं भेजना है तो इसी पत्र का 'आमफहम हिन्दुस्तानी' में अनुवाद करके भेजें। हमें विश्वास है 'देशदूत' के सम्पादकजी उसे छाप देंगे परन्तु शर्त यह है कि वह छपेगा केवल एक लिपि देवनागरी में ही।

(३० दिसम्बर, १९४५ के 'देशदूत' से)

परिशिष्ट १०

महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या

(लेखक—श्रीगङ्गाधर इन्दूरकर)

“.....हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यालय मन्त्री श्री श्रीनाद जोशी का एक पत्र 'दिशदूत' के निम्नले एक अंक में प्रकाशित हुआ था। उसमें जोशी जी ने महाराष्ट्र में इस समय होनेवाले राष्ट्रभाषा सम्बन्धी मतभेद की चर्चा करते हुये सम्मेलन को साम्प्रदायिकतापूर्ण कहने का प्रयत्न किया है। आपने जिस ढंग से सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं उसके संबंध में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। हाल ही में मैं अपने निजी काम से पूना गया था। रास्ते में बर्धा में भी रुका था। जब बर्धा में जोशीजी से मेरी मुलाकात हुई तब आपने कहा था कि हम लोगों ने अब यह निश्चय कर लिया है कि 'सम्मेलन साम्प्रदायिक संस्था है' इस बात का प्रचार किया जाय। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप का यह निश्चय हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति से हुआ है, या तबय उनके दिसाग की उपज है? आपके इस निश्चय से आपके कथन को कितना सहज दिया जाय यह सोचने की बात है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बर्धा की परीक्षाओं द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी का कामी प्रचार हुआ है। प्रति वर्ष केवल महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा की परीक्षाओं में लगभग १४-१५ हजार विद्यार्थी बैठते हैं। महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हिंदी का काम सम्मेलन के ही विचारों के अनुसार करते हैं। महात्माजी के सम्मेलन ने अलग होने के बाद भी महाराष्ट्र के लोग सम्मेलन के विचारों

से सहमत रहे हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में सम्मेलन की अभी काफी शक्ति है। हिंदुस्तानी का प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कहा जाय तो वह असह्य हो गया है, और उन्होंने मतभेद के बीज बोने शुरू कर दिये हैं। दुर्भाग्य से वे महाराष्ट्र सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को फोड़ने में भी सरल हुए हैं। हमारी समझ में महाराष्ट्र की विचारधारा हिंदुस्तानी को स्वीकार नहीं कर सकती। महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का बर्धा समिति से अपना सम्बन्ध विच्छेद करने का यही रहस्य है। सम्मेलन की शक्ति महाराष्ट्र में नष्ट करने के बाद हिंदुस्तानी प्रचार का कार्य सरल हो जायगा। हिंदुस्तानी के पृष्ठपोषकों का और कार्यकर्ताओं का इसमें पड़्यन्त्र है। इसके मेरे पास अनेक प्रामाणिक सबूत हैं। केवल कुछ इस बात का है कि महाराष्ट्र के अनेक प्रामाणिक कार्यकर्ता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सम्मेलन से अलग हुई महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष श्रीदत्तोबासन पोतदार अत्यन्त प्रामाणिक व्यक्ति हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा केवल बोलचाल की भाषा है। उन्हीं के शब्दों में तान्गैवालों की भाषा समझने के लिये ही राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है; यदि राष्ट्रभाषा का अधिक प्रचार होगा तो मराठी भाषा के अस्तित्व पर खतरा आयेगा। पोतदारजी मराठी के एक प्रमुख साहित्यिक होने के नाते मराठी की रक्षा के लिये जो जान से प्रयत्न करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में श्रीपोतदारजी का एक विशेष स्थान है। श्रीपोतदार के नाम का उपयोग करके महाराष्ट्र के लोगों को वहकाने में परदे की आड़ में हिंदुस्तानी के प्रचारक इस समय अवश्य सफल होंगे हैं। जब परदे की जबरत न समझी जायगी, और महाराष्ट्र में सम्मेलन की शक्ति यदि कम होगई तो श्रीपोतदारजी की क्या स्थिति होगी, इसे विधाता ही जाने।

जिन्हें सिद्धान्त का विशेष आकर्षण नहीं है, उन्हें विशेष लोभ देकर सम्मेलन के संगठन से अलग करने का प्रयत्न हो रहा है। भारतवर्ष की

वर्तमान सरीदी में पैसा का बड़ा महत्व है। किसी घर में अधिक पैसा देखकर दास-बेटे या भाई-भाई को लड़ाने के लिये जा चालें चली जाती हैं, उन्होंने सबको पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में की जा रही है। इस काम के लिये हिन्दुस्तानी के समर्थकों को हिंदी का मोहरा मिला गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार के कार्य में वतारस में गये हुये श्री गो० न० नेने विशेष श्रियशाली हैं।

महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों ने वातदार समिति को राष्ट्रीय और सम्मेलन के प्रयत्नों को अराष्ट्रीय कहना मुसक कर दिया है। इतना ही नहीं, सम्मेलन को हिन्दू-समावादी संस्था बताया जा रहा है। जिसको राष्ट्रभाषा के कार्य की जानकारी नहीं, जो राष्ट्रभाषा बोल नहीं सकते, जिन्हें वर्तमान मतभेदों में कुछ लेना देना नहीं, ऐसे कांग्रेसी नेताओं के हस्ताक्षर से एक विशिष्ट तिकाली जाती है जिसमें राष्ट्रीयता की बुढ़ाई देकर वातदार समिति को सहायता देने की सूरंग की जाती है। इसका तात्पर्य महाराष्ट्र के राष्ट्रभाषा हिन्दी के कार्यकर्ताओं में बुढ़ि-भेद पैदा करना नहीं तो और क्या है ?

सम्मेलन की ओर से इस समय महाराष्ट्र में जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति काम कर रही है, उसके समाचार छापना कांग्रेसवादी पत्रों ने बन कर दिया है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के हिन्दू-समावादी पत्र यदि उस समाचारों को छापते हैं, तो वह कहा जाता है कि सम्मेलन हिन्दू-समावादी संस्था है, नहीं तो उसके समाचार हिन्दू-समावादी पत्र क्यों छापते ? वास्तव में राष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचार की समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है। इस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्या कर रहा है, हमें पता नहीं। केवल कार्य समिति अथवा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा किसी प्रकार के प्रस्तावित कर देने से ही काम न चलेगा।"

(३ फरवरी, १९४६ के 'देशदूत' से)

परिशिष्ट ११

महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा समस्या

(लेखक—श्री सूर्यप्रकाश एम० ए०)

“-----महात्माजी बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र के निवासियों को उर्दू लिपि सीखने का उपदेश देते हैं, परन्तु सिन्ध, पंजाब और सीमा-प्रान्त के निवासियों को देवनागरी सीखने के लिये नहीं कहते। महाराष्ट्र और मद्रास में हिंदी जानने वालों को उर्दू सिखाने के लिये हिंदुस्तानी प्रचार सभाओं की स्थापना होती है, परन्तु सिन्ध, पंजाब, आदि में उर्दू जानने वालों को हिन्दी सिखाने के लिये कुछ करना आवश्यक नहीं समझा जाता। हिन्दु-तानी वाले चाहे यह चाहते हों या न चाहते हों, इसका फल केवल यही होगा कि वास्तविक राष्ट्र-भाषा होगी उर्दू और वास्तविक राष्ट्र-लिपि होगी फारसी लिपि। उस समय पोतदार जी मराठी की रक्षा के लिये क्या करेंगे ?

एक बात महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्र-भाषा प्रचार-समिति के अध्यक्ष श्री पोतदार से भी कहना चाहता हूँ। मराठी भाषा के अस्तित्व पर हिन्दी से नहीं बरन् हिन्दुस्तानी से खतरा है। हिन्दी और मराठी तो सगी बहनें हैं। हिन्दी और मराठी की क्रियाओं और विभक्तियों का सम्मिश्रण तो हो ही नहीं सकता, अधिक से अधिक हिन्दी की शब्दावली का मराठी पर प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु हिन्दी और मराठी की शब्दावली समान है और दोनों का एक ही स्रोत है। यदि मराठी के कुछ शब्दों में अदल-बदल हो भी जाय तो इससे मराठी के स्वरूप और संस्कृति में कोई अन्तर नहीं आवेगा। परन्तु आज जिस प्रकार अँगरेज़ी के प्रभाव के कारण भारतीय भाषाओं में

अंगरेज़ों शब्द खुसते चले जा रहे हैं उस प्रकार जब हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी-उर्दू की खिचड़ी के प्रभाव के कारण मराठी में उर्दू शब्दों का प्रवेश होगा, उस दिन पोतदारजी समझेंगे कि उन्होंने अपने हाथ में अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। जब महाराष्ट्र के लोग हिन्दुस्तानी के नाते देवनागरी और उर्दू लिपि दोनों भीख जायेंगे और महाराष्ट्र के मराठी भाषी सुसलमान उर्दू लिपि में मराठी लिखना आरम्भ करेंगे तब पोतदार जी के किये कुछ न होगा, और उनकी सन्तान उर्दू को कोसेगी कि उन्होंने अपने हाथों हिन्दी-उर्दू का सा भगड़ा मराठी में उत्पन्न किया। पोतदार जी तथा मराठी के अन्य शुभचिन्तक भली भाँति सोच देखें जिससे उन्हें दाद में पड़ताना न पड़े। हम हिन्दी वाले मराठी की सम्मोन्नति चाहते हैं और इसी उद्देश्य में प्रेरित होकर महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के कार्यधारी को यह चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझते हैं। संस्कृत के द्वारा जिस प्रकार हमारे पुग्खों ने राष्ट्र की भाषा-एकता तथा सांस्कृतिक एकता साधी थी, उसी प्रकार आज सम्मेलन हिन्दी द्वारा भाषा तथा सांस्कृतिक की एकता साधना चाहता है। यदि उनका वही विश्वास है कि राष्ट्र-भाषा के अत्यधिक प्रचार से मराठी को हानि पहुँचेगी, तो इसके लिये हिन्दी का बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का बाना धारण करने की जरूरत नहीं, और देवनागरी के साथ उर्दू लिपि का प्रचार करने की जरूरत नहीं। वे सरल हिन्दी का प्रचार करें। वही ताँगे वालों की, और सजदूर किसानों की भाषा है। और देवनागरी तो वे मराठी की लिपि होने के कारण जानते ही हैं। यदि उनको उर्दू लिपि द्वारा विनाश का बीज बोना ही अभीष्ट है, तो उनकी इच्छा। इस लिपि-विनाशन के कल को हम हिन्दी वाले तो भोग ही रहे हैं, वे भी चख देखें।”

महाराष्ट्र के कोषेसी पत्रों के विषय में क्या कहा जाय ? प्रत्येक पत्र का यह प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक घटना की खबर जनता को

निष्पन्न हों कर दे, उसके बाद उस पर चाहे जैसी टिप्पणी अपनी ओर से करे। परन्तु महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार-समिति के समाचार छापना ही वन्द कर दिया है। यह खुलेआम फैसिज्म है जो अपने विरोधी का अस्तित्व तक सहन नहीं कर सकता। ये पत्र हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग के समाचार छापना निषिद्ध नहीं समझते, परन्तु राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के समाचार नहीं छाप सकते। इसका कारण शायद यह है कि वे हिन्दू महासभा को कमज़ोर समझते हैं, उससे नहीं डरते, परन्तु सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति से डरते हैं। परन्तु अपने बलवान् प्रतिद्वन्द्वी को घराशर्था करने का यह तरीका कांग्रेस और हिन्दु-स्तानी-वाद का नाम किसी प्रकार उज्ज्वल नहीं कर सकता। इन पत्रों की इस मनोवृत्ति के विरुद्ध और उनके पङ्ख्यन्त्र का भण्डाफोड़ करने के लिये तथा हिन्दी की मान-रक्षा के लिये हिन्दी भाषियों, हिन्दी पत्रों तथा हिन्दी प्रान्तों के पत्रों का क्या कर्तव्य है, इसे वे ही सोच देखें।

(३१ मार्च, १९४६ के 'देशदूत' से)

परिशिष्ट १२

भारत की राष्ट्रभाषा की समस्या

(लेखक—श्री भद्रनाथ आनन्द कौमल्यायन)

अन्य किसी भी स्लेटफार्म की अपेक्षा तुल्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्लेटफार्म से कुछ भी कहने से अधिक प्रसक्तता होती है। इस स्लेटफार्म पर खड़े होकर योजने समय में अनुभव करता हूँ कि योजने वाले के पैरों में न किसी धार्मिक सम्प्रदायवाद की वेड़ी पड़ी है और न किसी राजनीतिक सम्प्रदाय की।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन कुछ विचारों का नाम है और एक विशिष्ट संगठन का। किसी स्लेट का और उसकी काँटेदार बाड़ का जो सम्बन्ध है वही किसी संस्था के विचारों और उसके संस्थान का। स्लेट के गिर्द यदि बाड़ न हो तो उसे कोई भी चर जा सकता है—और यदि स्लेट की उपज इस योग्य ही न हो कि उसके गिर्द बाड़ लगाई जाय तो बाड़ बेकार है। उसी प्रकार यदि विचार-विरोध की रक्षा करने वाला कोई सङ्गठित संगठन न हो तो विचार छिन्न भिन्न हो जाता है, और यदि विचार ही दो कौड़ी का हो तो उसकी रक्षा करने वाले संगठन का कोई मूल्य नहीं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपने स्थापना-दिवस से, जिसे आज पूरे पचास वर्ष हो गये हैं, राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि देवनागरी का प्रचारक रहा है। उसकी प्रथम निवसमावली में ही 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' और 'राष्ट्रलिपि नागरी' शब्द आये हैं। उसके इस कथन का विरोध अँगरेजी ने करना चाहा, लेकिन उसने बता दिया कि जब तक विदेशी हुकूमत है तब तक अँगरेजी भले ही शासन की भाषा अथवा राजभाषा बनी रहे किन्तु वह

हिन्दी की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। उर्दू की ओर से भी यह आवाज़ बुलन्द हुई कि उर्दू ही इस देश की कौमी ज़वान है। हिन्दी का उर्दू से कोई विरोध नहीं, विरोध हो ही नहीं सकता। हिन्दी उर्दू के सर्वनाम, प्रत्यय, क्रियायें सब कुछ एक हैं। हिन्दी अपनी ही एक शैली उर्दू का विरोध कैसे करे ? परन्तु पिछले वर्षों हिन्दी का जो राष्ट्रव्यापी प्रचार हुआ है उसने हिन्दी का देश में जो स्थान है वह निश्चित कर दिया और उसके साथ उर्दू का भी। भारतवर्ष में ही नहीं, मैं तो कहता हूँ संसार के इतिहास में यह एक असाधारण बात है कि दक्षिण और रोप भारत के लाखों अहिंदी भाषा भाषी विद्यार्थी राष्ट्रभाषा हिन्दी के अध्ययन में लगे हुये हैं और उसकी परीक्षाएँ पास कर रहे हैं और ऐसी परीक्षाएँ कि जिनके पास करने के साथ किसी सरकारी नौकरी, आदि मिलने का लालच नहीं जुड़ा हुआ है। राष्ट्रभाषा हिन्दी की इस प्रगति को उसके आज तक के समर्थक भी यदि चाहें तो अब नहीं रोक सकते।

यह सब सही है लेकिन अँगरेज़ी और उर्दू के बाद इधर दो तीन वर्ष से एक नई विचार-धारा ने अपना सिर उठाया है। उसका नाम है हिन्दुस्तानी विचार-धारा। जिस प्रकार किसी दोतल पर लगा हुआ लेबिल बना रहे लेकिन उसके अन्दर की चीज़ बदल जाय वही हाल हिन्दुस्तानी लेबिल का है। हम इस शब्द को हिन्दी के साथ-साथ काम में लाते रहे हैं—जैसे 'हिन्दी हिन्दुस्तानी', और यह हिन्दी का पर्यायवाची भी रहा है, जैसे "हिन्दी 'अथवा' हिन्दुस्तानी"। लेकिन इधर इस 'अथवा' में आमूल परिवर्तन हो गया है। पहले इसका मतलब था कि चाहे हिन्दी कहो, चाहे हिन्दुस्तानी कहो, बात एक ही है। लेकिन अब इस 'अथवा' का अर्थ किया जा रहा है कि हिन्दी और हिन्दुस्तानी दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। यदि हिन्दी का, तो हिन्दुस्तानी का नहीं, और यदि हिन्दुस्तानी का, तो हिन्दी का नहीं।

हमारे इस प्रांतीय सम्मेलन के द्वार पर आप सबसे देखा होगा लिखा है 'जय हिन्द'। यह इस समय का हमारा राष्ट्रीय उद्घोष है। जिस प्रकार हम 'जय हिन्द' कहते हैं उसी प्रकार हमें 'जय हिन्दी' भी कहना चाहिये।

हम हिन्दी वाले वरों से प्रचार करते आये हैं कि चूँकि हिन्दी राष्ट्र-भाषा है इसलिए प्रत्येक हिन्दी को, प्रत्येक भारतवासी को इसे सीखना चाहिये। इस नई विचार-धारा ने जिससे हमें सावधान रहना चाहिये कहना शुरू किया है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की। यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की। यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुओं की भी भाषा है किन्तु हिन्दुओं की ही नहीं—और इसी प्रकार उर्दू भी मुसलमानों की ही नहीं। सर तेजबहादुर सप्रू उर्दू के सुप्रसिद्ध समर्थक हैं। वे मुसलमान नहीं, काश्मीर के ब्राह्मण हैं। और अहुमन तरकी-ए-उर्दू की मुख्य पत्रिका 'हमारी ज़बान' के सम्पादक भी श्री ब्रजमोहन दत्तात्रेय हैं। उर्दू लिपि में अपना गौरव ठीक ठीक लिखा ही नहीं जा सकता। कोई भी भाषा किसी धर्म की दौलती नहीं। जो लोग हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा कहकर और उसी प्रकार उर्दू को मुसलमानों की भाषा कह कहकर हिन्दुस्तानी के द्वारा हिन्दू-मुसलिम ऐक्य के सम्पादन की बात करते हैं, मुझे भय है कि इतिहास ऐसे लोगों की साम्प्रदायिकता के असाधारण प्रचारक न सिद्ध करे।

'हिन्दी' के राष्ट्रभाषा होने पर एक और आपत्ति उठाई जा रही है। उसके गुण को उनका दोष कहा जा रहा है। कहा जाता है कि ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, जिसमें न संस्कृत के शब्द हों, न अरबी फारसी के। यदि हमारी राष्ट्रभाषा को वह सब काम करने है जो आज दिन हम अँगरेज़ी के माध्यम से करते हैं तो ऐसी भाषा जिसमें न संस्कृत के शब्द हों न अरबी फारसी के, हमारे लिये न तो कौड़ी काम की भाषा होगी। हमें यह निर्णय करना ही होगा कि विशेष शब्द आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होने पर कहाँ से लें? स्वयं में बैंक को 'धनसार' कहते हैं और नोट को

‘धन-पत्र’। हम भारत में यदि इसी प्रकार बोलें और लिखें तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ?

एक और मजे की आपत्ति यह है कि लोगों की मातृभाषा हिन्दी में और लोगों की राष्ट्रभाषा हिन्दी में अन्तर होना चाहिये। अर्थात् जो हिन्दी किसी की मातृभाषा है वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकता। स्काटलैंड और वेल्स के लोगों का अँगरेज़ी से वही सम्बन्ध कहा जा सकता है जो मराठा भाषा-भाषी अथवा गुजराती भाषा-भाषी लोगों का हिन्दी से है। इंगलिश इंगलैंड के लोगों की मातृभाषा होते हुये भी सारे ब्रिटेन की राज्य-भाषा है और सारे ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्य-भाषा। अब क्या एक तरह की अँगरेज़ी अँगरेज़ों की मातृभाषा और दूसरी तरह की अँगरेज़ी ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा और तीसरी तरह की अँगरेज़ी ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यभाषा है ? अँगरेज़ी अँगरेज़ी है। आप उसे चाहे मातृभाषा मानकर सीखें, चाहे राष्ट्रभाषा मानकर सीखें चाहे साम्राज्यभाषा मानकर सीखें। किन्तु हम पराधीन हिन्दुओं को सुझाया जाता है कि हिन्दी के दो रूप होने चाहिये— एक मातृभाषा वाला रूप, एक राष्ट्रभाषा वाला रूप। सच्ची बात यह है कि मातृभाषा के अर्थ में तो हिन्दी भारत के कुल चार-पाँच ज़िलों की भाषा होगी, शेष समस्त भारत की तो हिन्दी राष्ट्रभाषा ही है। और उसका स्वरूप निश्चित है। हमें आज उसका प्रचार करना है, उसमें नये आवश्यक ग्रन्थों का निर्माण करना है और जो काम हमें नहीं करने बैठना है वह है उसके स्वरूप की चर्चा।

फिर यह भी कहा जाने लगा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को क्या अधिकार है कि वह देश की राष्ट्रभाषा का निर्णय करे—यह काम तो हमारी राष्ट्रीय सरकार का है और जब तक उसकी स्थापना नहीं होती तब तक राष्ट्रीय महासभा का है। सरकार, चाहे फिर वह राष्ट्रीय ही क्यों न हो, किसी पर कोई भाषा लाद नहीं सकती। श्रीशिवप्रसाद गुप्त ने जब

काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्था के लिये दस लाख रुपये का दान दिया तो उस दान की शर्तों में एक शर्त यह थी कि यह विद्यापीठ स्वराज्य सरकार ने भी कभी किसी प्रकार की सहायता न लेगा। विदेशों में अनेक संस्थानों ने अपने आपको सरकारी सहायता के दुष्परिणाम से बचाये रखने के लिये प्रयत्नशील रहती हैं। जिस प्रकार शिक्षा को सरकारी प्रभाव से स्वतन्त्र रखने की आवश्यकता है वैसे ही भाषा को भी। कोई सरकार, भले ही वह राष्ट्रीय क्यों न हो, हमें यह नहीं बता सकती कि यह तुम्हारी मातृभाषा है और यह राष्ट्रभाषा। जहाँ तक आज की कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने कभी भी महात्मा गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' की कल्पना—दोनों शैलियों और दोनों लिपियों के अनिवार्य शिक्षण—का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजाद तक इस 'हिन्दुस्तानी' की नई कल्पना के साथ नहीं हैं। इतना होते हुये भी जिस बात के साथ महात्मा गांधी का व्यक्तित्व जुड़ जाता है उस पर हम सबको विचार करना अनिवार्य हो ही जाता है। क्योंकि गांधीजी गांधीजी हैं। कौन है जो स्वीकार नहीं करेगा कि पिछले पच्चीस वर्षों का इतिहास महात्मा गांधी का जीवन चरित्रमात्र है।

यू भाषा ही मुख्य वस्तु है, किन्तु इस नये हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने भाषा की अपेक्षा लिपियों की ही प्रधानता बढ़ा दी है। हमारे देश की सभी भाषाओं की लिपियाँ नागरी लिपि ही हैं, केवल उर्दू लिपि या फारसी लिपि एक अपवाद है। राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम में जहाँ एक भाषा की बात की जाती है, वहाँ एक की लिपि नहीं। लिपियों के बारे में कहा जाता है कि बिना दोनों लिपियों के ज्ञान के हम एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और दोनों लिपियों के ज्ञान के प्रसार का मतलब व्यवहार में उर्दू लिपि प्रचार-मात्र ही दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा कि "जो उर्दू लिपि को पसन्द नहीं करता वह स्वराज्य नहीं चाहता।" अब महात्माजी के इस कथन को कोई क्या कहे !

हिन्दुस्तानी की इस नई परिभाषा और कार्यक्रम के पीछे जो भावना है वह निस्सन्देह राष्ट्र-हित की ही है, किन्तु किसी कार्यक्रम का हितकर व अहितकर होना भावना पर ही निर्भर नहीं करता, कुछ उस कार्यक्रम पर भी निर्भर करता है। हिन्दुस्तानी भाषा के बारे में कहा जाता है कि जब हिन्दी वाले उर्दू और उर्दू वाले हिन्दी सीख लेंगे, तब दोनों के मेल से एक नई 'सरस्वती' पैदा होगी। कलियुग में तो आप जानते हैं 'सरस्वती' के पैदा होने की आशा नहीं। मेरा तो जी चाहता है कि यदि किसी का जी न दुखे तो हिन्दुस्तानी की नई विचारधारा की उपमा प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्यप से दूँ। उसे वरदान प्राप्त था कि न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न अन्दर मरूँ, न बाहर मरूँ, न आदमी के हाथ से मरूँ, न किसी पशु के हाथ से मरूँ। उसका क्या हाल हुआ ? उसी की तरह हिन्दुस्तानी भाषा का भी कहना है कि 'मैं वह भाषा हूँ जिसमें न संस्कृत के शब्द रहते हैं, न अरबी-फारसी के, जो न हिन्दुओं की भाषा है, न मुसलमानों की; और न देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, न उर्दू लिपि में ही।' यह सब हिरण्यकश्यप के नकारात्मक वचाव हैं। अभी तक इस हिरण्यकश्यप रूपी हिन्दुस्तानी के प्रचार के प्रयत्नों का जो प्रभाव देखने में आया है वह इतना ही कि अनेक कार्यकर्त्ताओं में बुद्धि-भेद पैदा हो गया है, और इतना निश्चय से कहा जा सकता है कि यदि हिन्दुस्तानी किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकेगी तो अहिन्दी प्रान्तों में कुछ न कुछ लोगों को राष्ट्र-भाषा हिन्दी पढ़ने से रोक अवश्य सकेगी।

जिनके लिये राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार-कार्य एक जीवन व्रत है उनके लिये यह चिन्तन का ही विषय नहीं, कुछ करने का आह्वान है।

(२० जनवरी, १९४६ के 'देशदूत' में प्रकाशित, मध्यप्रांतीय विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन के अवसर पर किये हुये भाषण से)

परिशिष्ट १३

‘हिन्दुस्तानी’ का वेदान्त

(लेखक—श्री मूर्त प्रकाश एम० ए०)

‘हिन्दुस्तानी’ के समर्थकों अथवा अर्थ-समर्थकों में एक दल ऐसे व्यक्तियों का है जो कल तक राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थक थे, हिन्दी और देवनागरी छोड़ कर हिन्दुस्तानी या उर्दू लिपि का नाम नहीं लेते थे, मुबहिन्दी और देवनागरी का प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदय उनके मस्तिष्क में अधिक दलवान था, और यदि उनका मस्तिष्क राष्ट्र और राष्ट्रीयता के साथ था तो हृदय गांधी के साथ था, और इस लिये जो आज अपने आप को हिन्दुस्तानी के कैम्प में खड़ा पाते हैं। परन्तु पुरानी आदतें जल्दी नहीं छूटती, और इसलिये वे अपने आप को नये दन्दोदन्त में फिट करने में ज़रा दिक्कत महसूस करते हैं—हृदय और मस्तिष्क के बीच में एक संघर्ष का अनुभव करते हैं। इस संघर्ष को शान्त करने के लिये, अपने अंतःकरण की आवाज़ को दबाने के लिये, अपने मन की संतुष्टि देने के लिये अर्थात् अपने आप को धोका देने के लिये उन्होंने एक ‘हिन्दुस्तानी वेदान्त’ की सृष्टि कर ली है। इस वेदान्त के अनुसार हिन्दी भी बही है, उर्दू भी बही है, हिन्दुस्तानी भी बही है—तीनों एक ही तत्व हैं अथवा एक ही ब्रह्म-तत्व के तीन नाम हैं, तीनों के उपासक एक ही गति को प्राप्त होते हैं, वस केवल आजकल हिन्दुस्तानी पूजा का अधिक साहाय्य है और इस कारण उन्होंने अपने इष्ट-देवता (या आराध्य देवी ?) राष्ट्रभाषा का नाम भर ‘हिन्दुस्तानी’ रख लिया है। इस दर्शन का दर्शन कीजिये—

मई, १९४६ की 'राष्ट्रभाषा' में श्री आचार्य दादा धर्माधिकारी लिखें हैं—“राष्ट्रभाषा का अर्थ जो बीस पचीस वरस पहले था वह आज नहीं है। पहले राष्ट्रभाषा सिर्फ “हिन्दी” नाम से पहचानी जाती थी, जिसका “हिन्दी हिन्दुस्तानी” नामकरण हुआ और अब हिन्दुस्तानी! एक ही राष्ट्रभाषा का भिन्न भिन्न नामकरण इन ५० सालों में हुआ, इस कारण क्या है? जीवन प्रगतिशील है—वह नित्य गतिमान है। उसकी गति का लक्ष्य है पूर्णता अथवा मृत्यु। राष्ट्रभाषा भी अपने जीवन में प्रगतिशील रही है। वही कारण है कि वह उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। जिसका परिचय हमें उसके बदलते हुये नामों में मिल रहा है।”

इस ‘प्रगतिशीलता’ का क्या कहना! न मालूम इंग्लैंड-भाषा, साम्राज्य भाषा, संसार-भाषा ‘अंगरेज़ी’ का नाम उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होने पर भी क्यों नहीं बदला! और ‘एक ही राष्ट्रभाषा’ का भिन्न भिन्न नामकरण कैसा कि, वकौल श्री भदन्त जी, अब या ‘हिन्दी’ चुन लो या ‘हिन्दुस्तानी’ चुन लो, या हिन्दी साहित्य सम्मेलन में रह लो या हिन्दुस्तानी प्रचार सभा में! यह तो स्पष्ट ही है कि ‘राष्ट्रभाषा का जो बीस-पचीस वरस पहले था वह आज नहीं है’। उस राष्ट्र का भी जिसकी राष्ट्रभाषा से मतलब है, अब वह अर्थ नहीं है। पहले उसका नाम ‘हिन्दुस्तान’ था, फिर एक ‘फीडरेशन’ हुआ और अब ‘कानफीडरेशन’ है। उसमें रहने वाले पहले ‘हिन्दुस्तानी’ नाम से पहचाने जाते थे, फिर वे ‘हिन्दू-मुसलमान’ कहलाये और अब ‘हिन्दू’ और ‘मुसलमान’ यह सब ‘प्रगतिशीलता’, ‘पूर्ण राष्ट्रीयता’ के लक्ष्य की प्राप्ति का द्योतक तो है! इसी कारण ‘राष्ट्र’ भी उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली जा रहा है! राष्ट्रभाषा के प्रगतिशील, पूर्णता-गामी और उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होने की एक और पहचान है। पहले उसकी लिपि

एक था, अब दो हैं (अथवा क्या ‘देवनागरी’ और ‘फारसी’ एक ही राष्ट्र-लिपि का भिन्न भिन्न नामकरण है ?), यीशू ही तीन (रोमन भी) हो जायेंगी। तब वह और ‘शक्तिशालिनी’ हो जायगी। न मालूम अंगरेजी एक ही लिपि में क्यों संतुष्ट है। याददा वह गतिशील नहीं, और मृत्यु को मात हो रही है !

धर्माधिकारी जी आगे लिखते हैं : “अगर हिन्दुस्तान का हिन्दू कहने लगे कि हम उर्दू नहीं बोलेंगे और हिन्दुस्तान या मुसलमान कहे कि हम हिन्दी नहीं बोलेंगे, तब इन दोनों को एक दूसरे को यह बताने के लिये कि हम तुम्हारी भाषा नहीं बोलेंगे किसी तीसरी भाषा की सहायता लेनी पड़ेगी और वह होगा अंगरेजी।”

अरे, क्या ‘हिन्दी’ और ‘उर्दू’ एक ही भाषा के दो नाम नहीं रहे ? जो भी हो, अगर हिन्दू कहे हम फारसी लिपि में नहीं लिखेंगे और मुसलमान कहे हम देवनागरी में नहीं लिखेंगे तो एक दूसरे को तब लिखने के लिये किसी तीसरी लिपि का सहायता लेनी पड़ेगी और वह होगा रोमन ! (प्रत्येक से कहते हो दोनों लिपि सीखो, प्रत्येक से यह भी क्यों न कहा हिन्दी उर्दू दोनों सीखो ? वह ‘हिन्दुस्तानी’ का खतरा क्या है ? जैसे देवनागरी और फारसी लिपि दोनों राष्ट्र-लिपि, वैसे हिन्दी और उर्दू दोनों राष्ट्र-भाषा रही। क्या मुसलमान वर्ग की इस ‘हिन्दुस्तानी’ बोलने की ही तैयारी है ?)

मई, १९४६ की ‘राष्ट्र-भाषा’ में श्री हृषीकेश रमा दक्षिण-भारत हिन्दू प्रचार समा के रजत-जयन्ती उत्सव का वर्णन करते हुये लिखते हैं, “हिन्दी के नाम का, जिसे यह नाम सदियों पहले मुसलमान मुसलमानों ने हा दिया था, छाड़कर यहाँ ‘हिन्दुस्तानी’ नया नाम मात्र दे दिया गया है”, और उसके बाद रजत-जयन्ती में हुए भाषणों में से कुछ हिन्दी वाक्यांश चुनकर उदाहरण-स्वरूप पेश करते हैं और फिर तपाक से कहते हैं, “इसे हिन्दी कह

लीजिये, चाहे हिन्दुस्तानी।” आखिर फिर पुराना, परिचित, सुसलमानों का ही दिया हुआ नाम ‘हिन्दी’ छोड़कर ‘हिन्दुस्तानी’ नाम क्यों रक्खा गया ? इसका कोई विशेष कारण तो होगा ही। क्या शर्माजी की समझ में अभी तक नहीं आया कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी का फाटक किनके प्रवेश करने के लिये खोला गया है ? दक्षिण में अभी पं० सुन्दरलाल और काका कालेलकर जी हिन्दी वाक्यांश न बोलें तो उनकी बकालत समझे कौन ? अभी जरा ठहरिये, अभी तो हिन्दुस्तानी का पाठ आरम्भ हुआ है, उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें छपना शुरू हुई हैं। विश्वास न हो तो अभी ही पंडित सुन्दरलाल को पंजाब या युक्त-प्रान्त में ‘हिन्दी कह लीजिये चाहे हिन्दुस्तानी’ बोलते हुए सुन लें (या उनकी ‘विश्व-वाणी’ का सम्पादकीय या ‘नया हिन्द’ का अग्र-लेख पढ़ लें)। और क्या “दोनों लिपियों का आप प्रयोग करें”, यह भी नाम मात्र के लिये कहा गया, और दक्षिण भारत हि. प्र. सभा दोनों लिपियों की शिक्षा क्या नाम मात्र के लिये ही अनिवार्य कर रही है ?

शर्मा जी आगे लिखते हैं, “हिन्दी ने उर्दू के लोकोपयोगी सैकड़ों मुहावरों और हजारों प्रचलित सरल शब्दों को सदियों से अपने कुटुम्ब कबीले में ऐसा मिला लिया है कि वे किसी के हटाने से हट नहीं सकते और किसी की मेहरबानी या रहम के बल पर वे रह नहीं सकते।”

शायद इसीलिये हिन्दी को उर्दू की एक और खूराक जवरदस्ती पिला कर ‘हिन्दुस्तानी’ बनाया जा रहा है, और अनुपयोगी शब्दों ‘साहित्य’ और ‘शिक्षा’ को निकाल कर लोकोपयोगी सरल शब्दों ‘अदब’ और ‘तालीम’ को बैठाया जा रहा है, और दक्षिण वासियों को उर्दू के हजारों पारिभाषिक शब्दों से परिचित कराया जा रहा है ! शर्मा जी कहते हैं, “हिन्दी ने न कभी भाषा का पाकिस्तान बनाया और न बनने देगी।” यह तो ठीक, परंतु लिपि का पाकिस्तान कौन बना रहा है ? ‘उर्दू शैली’ प्रत्येक पर अलग से कौन लाद रहा है ?

अन्त में शर्मा जी लिखते हैं, “यही हिन्दी की ग्यारसवीं है, उसका लोच है। यह काका जी की ‘सबकी बोली’ है, मु० बाबू जी की हिन्दुस्तानी है, राष्ट्रपति आजाद साहब की कौमी उद्दान है और श्रद्धेय टंडन जी की राष्ट्रभाषा है”, अर्थात् हिन्दी भी वही है, उर्दू भी वही है (देखिये न ‘लोच’, ‘कौमी’ और ‘जवान’ वही तीनों शब्द हैं जो ‘राष्ट्र’ और ‘भाषा’—जरा अन्तर्दृष्टि से देखिये !), और हिन्दुस्तानी भी वही है। यह है मुझ ‘हिन्दुस्तानी का वेदान्त’ (अफसोस, इसे श्रद्धेय टंडन जी और राष्ट्रपति आजाद नहीं समझ पाते !)। इस वेदान्त की अन्तिम कड़ी यों है—वेचनागरी भी वही है, जारसी लिपि भी वही है। धैर्य धारण कीजिये, इसको सिद्ध करने वाला शंकराचार्य भी शीघ्र प्रकट हो जायगा।

(अक्टूबर, १९४७ की ‘सम्बन्धी’ से)

परिशिष्ट १४

‘हरिजनसेवक’

(लेखक—रविशंकर शुक्ल)

गांधीजी का साप्ताहिक पत्र ‘हरिजन’ जो अब तक हिंदी, परंपरागत हिंदी, में निकलता था, अब ‘हिन्दुस्तानी’ में निकलने लगा है। उसके देवनागरी संस्करण का नाम है ‘हरिजनसेवक’। गांधी जी उसके द्वारा अपनी ‘हिन्दुस्तानी’, जिसे वे राष्ट्र-भाषा मानते हैं, का रूप राष्ट्र के सामने रख रहे हैं। राष्ट्र-भाषा का दृष्टि गांधी जी ने ही आरम्भ किया था, ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दी, और राष्ट्र-लिपि देवनागरी’ गांधी जी की ही देन है, और ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी और राष्ट्र-लिपि दोनों’ के पीछे भी सबसे प्रबल शक्ति गांधी जी की है, अतः ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ का विशेष महत्व है।

कहना न होगा कि ‘हिन्दुस्तानी’ के विषय में जो कुछ पहले कहा गया है, वह सब ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ पर सच्चा उतरता है, और ‘हिन्दुस्तानी’ के विषय में हिन्दुस्तानी वाले जो भी दावे करते हैं, उन सबको ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ झूठा साबित कर देती है। ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ न आमफहम है, न ‘न संस्कृत और न अरबी फ़ारसी’ मयी, न ‘न हिन्दी न उर्दू’, न ‘अकृत्रिम’ और न ‘बोलचाल की भाषा’, और न उसे हिन्दी समझने वालों से अधिक व्यक्ति समझते हैं। वह हिन्दी और उर्दू का एक मनमाना घोल है जिसके कोई सिद्धान्त नहीं, नियम नहीं, आदर्श नहीं। इस घोल का ‘आमफहम’ होना तो दूर रहा, उसे समझने के लिये, और लिखने के लिये भी, अकेली हिन्दी या अकेली उर्दू

की भी नहीं बगन् हिन्दी और उर्दू दोनों के ज्ञान की आवश्यकता है, अर्थात् वह हिन्दी या उर्दू में कूनी कठिन है। वाग्व्यवस्थ है। ‘हरिजनसेवक’ की भाषा के कोई सिद्धान्त, नियम या आदर्श तो हैं नहीं, अतः सब कुछ सम्पादक या लेखक की इच्छा पर निर्भर है। वह चाहे कोई हिन्दी शब्द और चाहे कोई उर्दू शब्द उठाकर धर सकता है। ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ में प्रत्येक हिन्दी शब्द और प्रत्येक उर्दू शब्द आ सकता है और आता है। एक बार एक पाठक ने गांधी जी से प्रश्न किया कि ‘हरिजनसेवक’ की भाषा में ‘एतकाद’, ‘तहरीक’ और ‘कम्फारा’ क्यों आये, ‘अब्दा’, ‘आन्दोलन’ और ‘मायश्चित’ क्यों नहीं? गांधी जी ने उत्तर दिया कि ‘एतकाद’, ‘तहरीक’ और ‘कम्फारा’ तीनों शब्द ‘उत्तर के लोगों की बोलचाल’ में धर कर लिये हैं। (गांधी जी ने यह नहीं बतलाया कि फिर भी स्वयं उनका, जिन्होंने उत्तर के दौरे में आधा जीवन व्यतीत किया है, इन शब्दों से कितना पुराना परिचय है!) अस्तु, चूँकि हिन्दी का या उर्दू का ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके बारे में कहा जा सके कि उत्तर के लोग उसे नहीं बोलते, और चूँकि लड़ी बोली की क्रियाओं का प्रत्येक जानकार ‘उत्तर की बोलचाल’ का ठेकेदार बन सकता है, गांधी जी के उत्तर का सीधा सादा अर्थ है कि ‘हिन्दुस्तानी’ में हिन्दी और उर्दू का प्रत्येक शब्द आ सकता है, ‘हिन्दुस्तानी’ समझने के लिए हिन्दी-कोष और उर्दू-कोष दोनों का धाटने की आवश्यकता है, ‘हिन्दुस्तानी’ का कोष हिन्दी-कोष-उर्दू-कोष है। फिर ‘हिन्दुस्तानी’ न हिन्दी न उर्दू या न संस्कृत, न अरबी-फारसी नयी कैसे हो सकती है? ‘हरिजनसेवक’ की भाषा में वही हिन्दी के संस्कृत शब्द वर्तमान हैं और वही उर्दू के अरबी-फारसी शब्द दिखाई देते हैं, वन, केवल १०० संस्कृत या १०० अरबी-फारसी शब्दों के स्थान में ५० संस्कृत और ५० अरबी-फारसी शब्द हैं, और कौन से संस्कृत और कौन से अरबी-फारसी, इसको कोई ठीक नहीं। लेखक को केवल यह आदेश है

कि हिन्दी का और उर्दू का पलड़ा बराबर रहे। यदि दो तीन हिन्दी शब्द आ गये तो उनके बाद दो तीन उर्दू शब्दों का आना आवश्यक है, अन्यथा 'राष्ट्र-भाषा' की सील नहीं लगेगी और 'राष्ट्र-भाषा-विशारद' का सार्टीफिकेट छिन जायगा। ज़रा चूके कि 'अराष्ट्रीयता' के लड्डू में गिरे और आपकी भाषा 'सच्ची राष्ट्र-भाषा' के बजाय हिन्दी या उर्दू कहलाई! जो एक हाथ में हिन्दी-कोप और एक हाथ में उर्दू-कोप ले कर सीधा संतुलन करता हुआ तलवार की धार पर नहीं चल सकता, वह राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' का लेखक नहीं हो सकता। इसके बाद भी वर्धा का सार्टीफिकेट लेना ज़रूरी है। 'हिन्दुस्तानी' का रहस्य कोई कोई जानते हैं (परन्तु वह है फिर भी 'राष्ट्र-भाषा'—सारे राष्ट्र की भाषा), और ऐसे महात्माओं का प्रधान आश्रम वर्धा में ही है। वह सार्टीफिकेट भी सब प्रार्थियों को नहीं मिलता। तपस्या करनी पड़ती है। 'हरिजनसेवक' के सम्पादक ही सच्ची 'राष्ट्र-भाषा' लिखने के अयोग्य साबित होने के कारण कई बार बदले जा चुके हैं। 'सरस्वती' वर्धा में प्रकट होती है और वहीं लुप्त हो जाती है।

'हरिजन सेवक' की 'हिन्दुस्तानी' कृत्रिम है या अकृत्रिम, अब इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह उतनी ही कृत्रिम है जितनी उर्दू। उर्दू दिल्ली के दरबार में गढ़ी गई थी, 'हिन्दुस्तानी' वर्धा में गढ़ी जा रही है। इसकी कृत्रिमता का भी कोई ठिकाना है! यदि वह अकृत्रिम, स्वाभाविक भाषा होती तो साहित्य-शून्य क्यों होती और उस पर इतनी वन्दिशें क्यों लगाई जाती? यदि हिन्दी अपने लिखित रूप में कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होती, तो 'हरिजनसेवक' की 'हिन्दुस्तानी' भी इसी रूप में कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होती। रही बोधगम्यता की बात, सो क्या हिन्दुस्तानी वाले साबित कर सकते हैं कि 'हरिजनसेवक' की 'हिन्दुस्तानी' को ही फ्रांटियर के पठान और तेलगू भाई दोनों समझते हैं, अथवा यह कि वह देहातियों के लिये हिन्दी की अपेक्षा अधिक सरल

है ? इसमें कौन सी समस्या दल होती है ? हिन्दुस्तानी वाले स्वीकार करें या न करें, परन्तु इसमें सन्देह करने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही कि ‘हिन्दुस्तानी’ का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से भाषा में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को थुमेड़ कर सुसलमानों को खुश करना है। परन्तु अफसोस ! यह उद्देश्य भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि सुसलमान ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। शायद अब १०० में ७५ शब्द उर्दू के रक्खे जायें !—और फिर पूरे १०० !!

‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ में प्रायः हिन्दी शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके उर्दू पर्याय, और उर्दू शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके हिन्दी पर्याय दिये जाते हैं। इस प्रकार शब्दों के जोड़े दे कर हिन्दुस्तानी वालों ने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ‘हिन्दुस्तानी’ कोई अलग चीज नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जो हिन्दी और उर्दू दोनों से भिन्न हो और सबकी समझ में आती हो, और ‘हिन्दुस्तानी’ कोई भाषा नहीं, वह हिन्दी और उर्दू लिखाने या सबक भले ही हो। उन्होंने वह भी स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान में ‘एतकाद’ ‘तहरीक’ और ‘कफ्तारा’ जैसे शब्दों को कोषों में से छौंटा-छौंटा कर फिर उन्हें उनके पुराने, प्रचलित स्वदेशी पर्यायों द्वारा लिखाने का नाम ही ‘राष्ट्रीयता’ है।

गांधीजी ने ‘उत्तर की बोलचाल’ का हवाला दिया। दक्षिण की बोलचाल क्यों छोड़ दी ? उत्तर में भी बंगाल और आसाम को क्यों छोड़ दिया ? कौन सी भारतीय भाषा का ऐसा कौनसा शब्द है जो भारत के किसी न किसी भाग की बोलचाल में घर न कर चुका हो ? फिर भारत की राष्ट्र-भाषा में सब शब्दों को समान स्थान क्यों नहीं दिया जाता ? केवल ‘हिन्दी शब्द’ और ‘उर्दू शब्द’ ही क्यों ? कोष्ठक में केवल हिन्दी या उर्दू पर्याय ही क्यों दिया जाता है, सभी भारतीय पर्याय (जिनमें द्रविड़ पर्याय भी शामिल हैं) और अंगरेजी पर्याय भी (क्योंकि लाखों भारतीय, उत्तर में भी और दक्षिण

में भी, अँगरेज़ी भी बोलते हैं और इङ्गलिस्तानी में खड़ी बोली ही की क्रियाओं के साथ अँगरेज़ी शब्दों का प्रयोग करते हैं) क्यों नहीं दिये जाते ? साफ़-साफ़ यह घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता कि 'हिन्दुस्तानी' से तात्पर्य केवल खड़ी बोली की क्रियाओं और विभक्तियों से है, शेष शब्द चाहे जो हों ? हमें घोर दुःख है, राष्ट्र-भाषा यज्ञ को पूर्ण होने से पूर्व उसे उसे आरम्भ करने वाले ने ही भ्रष्ट कर दिया !

'हरिजनसेवक' के उर्दू-लिपि वाले संस्करण के विषय में इतना और कहना पर्याप्त होगा कि उसे पढ़ना भी सरल नहीं, समझना तो वाद की बात है । जो पाठक संस्कृत या हिन्दी पढ़ा हुआ नहीं है, वह इसे नहीं पढ़ सकता । इसमें आये हुये हिन्दी संस्कृत शब्दों को पारखी ही पहचान सकते हैं । पहचानने पर भी उनका शुद्ध रूप उन्हें तब तक नहीं मालूम हो सकता जब तक उन्हें अलग से न बताया जाय या वे पहले से न जानते हों । यह है इस 'राष्ट्र-लिपि' में 'राष्ट्र-भाषा' का हाल ।

'हरिजनसेवक' एक बात और स्पष्ट कर रहा है । वह यह कि हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी का (और उर्दू का भी) अस्तित्व मिटाना चाहते हैं । उनका यह कहना कि हिन्दी (और उर्दू) प्रान्तीय भाषा के बतौर अपने क्षेत्र में फल-फूल सकती है, झूठ और भुलावा मात्र है । यह इससे जाना जा सकता है कि गांधीजी अपना पत्र 'हरिजन' अँगरेज़ी के अतिरिक्त गुजराती, मराठी, आदि प्रान्तीय भाषाओं में तो (प्रत्येक भाषा के अपने अपने परम्परागत शुद्ध रूप में) निकालते हैं, परन्तु 'हिन्दी' में नहीं निकालते । 'हिन्दी' के स्थान में निकालते हैं 'देवनागरी-हिन्दुस्तानी' में जिसका हाल ऊपर बतलाया गया है । यदि 'हिन्दुस्तानी' का उद्देश्य, जैसा कि गांधीजी ने स्वयं कहा है, हिन्दी (और उर्दू) को मिटाना नहीं है और यदि यह सत्य है कि 'हिन्दुस्तानी' में केवल अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार होगा और वह किसी प्रान्तीय भाषा का स्थान नहीं लेगी, तो या तो 'हरिजन' को केवल

‘गण्डू-भाषा हिन्दुस्तानी’ में (और किसी भी प्राणीय भाषा में नहीं) निकालना चाहिये था और या उसे अन्य प्राणीय भाषाओं की भाँति हिन्दी में भी निकालना चाहिये था, हिन्दी के अतिरिक्त ‘हिन्दुस्तानी’ में निकाला जाता अथवा न निकाला जाता। यदि गांधीजी यही समझते हैं कि ‘हरिजन-सेवक’ को ‘हिन्दुस्तानी’ हिन्दी में अधिक व्यापक है, तो वे ‘हरिजनसेवक’ को हिन्दी में भी निकाल कर हिन्दी ‘हरिजन सेवक’ की और देवनागरी-‘हिन्दुस्तानी’ ‘हरिजनसेवक’ की विकने वाली प्रतिष्ठों की संख्याओं का मुकाबला करके देख लें। (उर्दू के साथ भी यह कर के देख लें।) सत्य के पृजानी को हमारी यह सत्य की चुनौती है। वे हमारी चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो हम ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ की गांधीजी की व्यक्तिगत जिद और हिन्दी के प्रति अन्याय, हिन्दी के अस्तित्व पर कुदराघात, साहित्यिक अन्याचार एवं अनाचार मानने के किये बाध्य होंगे। एक अन्य के किये आग्रह ‘सत्य-आग्रह’ नहीं कहा जा सकता।

×

×

×

×

हिन्दी पत्रों से एक विशेष निवेदन करना आवश्यक जान पड़ता है। हिन्दी पत्र-पत्रिकायें प्रायः ‘हरिजनसेवक’ से अवतरण, लेख, आदि ज्यों की त्यों उद्धृत करती हुई देखी जाती हैं। वे ऐसा शायद उनके गांधी जी के पत्र होने के कारण करती हैं। ‘हरिजनसेवक’ के लेखों का अवश्य विशेष महत्व है, परन्तु उन्हें य्यों का त्यों अर्थात् मूल ‘हिन्दुस्तानी’ में क्यों उद्धृत किया जाता है ? ‘हिन्दुस्तानी’ यदि हिन्दी से भिन्न कही और बतलाई जाती है, और ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ हिन्दी से भिन्न है भी, तो वह हिन्दी के पत्र में कैसे स्थान पा सकता है ? हिन्दी पत्रों को सर्वैव ‘हरिजनसेवक’ के लेखों, आदि को हिन्दी में न्यास्तमित करके देना चाहिये। उन्हें शायद यह लालच होगा कि वे गांधी जी के विचार उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की भाषा में (या उन्हीं की ‘हिन्दुस्तानी’ में) वे रहे हैं, परन्तु बात ऐसी

भी नहीं है। गांधी जी अपने अधिकांश मूल लेख गुजराती या अँगरेज़ी में लिखते हैं। 'हरिजनसेवक' में उनका 'हिन्दुस्तानी' विशेषज्ञों द्वारा किया हुआ 'हिन्दुस्तानी' अनुवाद भर रहता है (लेखों के नीचे इसका उल्लेख भी रहता है) *। ऐसी स्थिति में हिन्दी पत्रों के सम्पादक गांधी जी के मूल लेख से अपनी हिन्दी में अनुवाद करके क्यों नहीं छापते ? यदि वे मूल लेख तक जाना नहीं चाहते या मूल लेख से अनुवाद नहीं कर सकते, तो 'हरिजनसेवक' में दिये हुये 'हिन्दुस्तानी' अनुवाद से ही अपनी हिन्दी में अनुवाद करके दें। वे किसी दूसरे की 'हिन्दुस्तानी' को अपनी हिन्दी पर तरजीह क्यों देते हैं ? ज़रा सी आरामतलबी में आकर वे हिन्दी को विकृत करने में क्यों न दें। हिन्दी पत्रों में 'हिन्दुस्तानी' के लेख, अवतरण, आदि देने के विषय में बहुत कुछ पहले कहा जा चुका है।

* 'हरिजनसेवक' में गांधीजी के अतिरिक्त अधिकांश अन्य लेखकों के मूल लेख भी 'हिन्दुस्तानी' में लिखे हुये नहीं होते बल्कि मूल लेखों का 'हिन्दुस्तानी' अनुवाद होता है।

† देखिये पृष्ठ २६-२७ और १६२-१६३।

परिशिष्ट १५

हिन्दुस्तानी का उद्गम

(लेखक—पं० रामचन्द्र शुक्ल)

साहित्य किसी जाति की रचित वाणी को वह अखंड परंपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप को रक्षा करती हुई जगत् की गति के अनुसर उत्तरोत्तर उसका अंतर्बिकसम करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस माया में और इस सफाई के साथ मिल होता चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी वहाँ से वहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है। अब कि साहित्य व्यक्त वाणी या वाग्विभूति का संचित भंडार है तब पहले भाषा ही पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। व्यक्त वाणी का वह संचय असंख्य जातियों में तो केवल मौखिक रहता है, पर सभ्य जातियों में पुस्तकों के भीतर दिकाजत के साथ बंद रखा जाता है। मौखिक अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, पर पुस्तकस्थ होकर हजारों वर्ष तक चला चलता है।

साहित्य की अखंड दीर्घ परंपरा सभ्यता का लक्षण है। वह परंपरा शब्द की भी होती है और अर्थ की भी। शब्द परंपरा भाषा को स्वरूप देती है और अर्थ-परंपरा साहित्य का स्वरूप निर्दिष्ट करती है। ये दोनों परंपराएँ अभिन्न होती हैं। इन्हें एक ही परंपरा के दो पक्ष समझिए। किसी देश की शब्द-परंपरा अर्थात् भाषा कुछ काल तक चलकर जो अर्थ-विधान करती है वही उस देश का साहित्य कहलाता है। कुछ काल तक लगातार चलते रहने में शब्द-परंपरा या भाषा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है

और अर्थ-परंपरा या साहित्य को भी। इस प्रकार दोनों के स्वरूपों का सामं-जस्य रहता है। इस सामंजस्य में यदि बाधा पड़ी तो साहित्य देश की प्राकृतिक जीवन-धारा से विच्छिन्न हो जायगा और जनता के हृदय का स्पर्श न कर सकेगा। यदि अर्थ-परंपरा का स्वरूप बनाए रखकर शब्द-परंपरा का स्वरूप बदला जायगा तो परिणाम होगा “कोयल का नगमा” और “महात्मा जी के अलफ़ाज़”। यदि शब्द-परंपरा स्थिर रखकर अर्थ-परंपरा या वस्तु-परंपरा बदली जायगी तो आप के सामने “स्वर्ण अवसर” आएगा, “हृदय के छाले” फूटेंगे और “हुपट्टे फाड़े जायेंगे।”

भाषा या साहित्य के विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करने का अभिप्राय यह नहीं है कि उसमें बाहर से आए हुए नए शब्द और नई नई वस्तुएँ न मिलें। उसमें नए नए शब्द भी बराबर मिलते जाते हैं और नए नए अर्थों या वस्तुओं की योजना भी होती जाती है, पर इस मात्रा में और इस दब से कि उसका स्वरूप अपनी विशिष्टता बनाए रहता है। हम यह बराबर कह सकते हैं कि वह इस देश का, इस जाति का और इस भाषा का साहित्य है। गंगा एक क्षीण धारा के रूप में गंगोत्तरी से चलती है; मार्ग में न जाने कितने नाले, न जाने कितनी नदियाँ उसमें मिलती जाती हैं, पर सागर-संगम तक वह ‘गंगा’ ही कहलाती है, उसका ‘गंगापन’ बना रहता है।

हमारे व्यावहारिक और भावात्मक जीवन से जिस भाषा का संबंध सदा से चला आ रहा है वह पहले चाहे जो कुछ कही जाती रही हो, अब हिन्दी कही जाती है। इसका एक एक शब्द हमारी सत्ता का व्यंजक है, हमारी संस्कृति का संपुट है, हमारी जन्मभूमि का स्मारक है, हमारे हृदय का प्रतिबिम्ब है, हमारी बुद्धि का वैभव है। देश की जिस प्रकृति ने हमारे हृदय में रूप-रंग भरा है उसी ने हमारी भाषा का भी रूप-रंग खड़ा किया है। यहाँ के वन, पर्वत, नदी, नाले, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी सब इसी हमारी बोली में अपना परिचय देते हैं और अपनी ओर हमें खींचते हैं। इनकी सारी रूप-

छटा, सारी भाषाएँ हमारी भाषा में और हमारे साहित्य में समाई हुई हैं। यह वही भाषा है जिसकी धारा कभी संस्कृत के रूप में बहती थी, फिर प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में और इधर हजार वर्ष से इस वर्तमान रूप में—जिसे हिंदी कहते हैं—लगातार बहती चली आ रही है। यह वही भाषा है जिसमें सारे उत्तरीय भारत के बीच चंद और जगतिक ने बीरता की उमंग उठाई; कबीर, सूर और तुलसी ने भक्ति की धारा बहाई; बिहारी, देव और पद्माकर ने शृंगार रस की बगीची; भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र ने आधुनिक युग का आभास दिया और आज आज व्यापक दृष्टिकोणों से संपूर्ण मानव-जगत के मेल में लानेवाली भाषनाएँ भर रहे हैं। हजारों वर्ष से यह दीर्घ परम्परा अखंड चली आ रही है। ऐसी भव्य परंपरा का गर्व जिसे न हो वह भारतीय नहीं।

हमारा गर्व यह सोचकर और भी बढ़ जाता है कि यह परंपरा इतनी प्रबल और शक्तिशालिनी सिद्ध हुई कि इधर सौ वर्ष से—अर्थात् अंग्रेजों राज्य के पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाने के पीछे—इसे बंद करने के तरह तरह के प्रयत्न कुछ लोगों के द्वारा समय समय पर होते आ रहे हैं, पर यह अपना मार्ग निकालती चली आ रही है। इस विरोध का मूल हमारे उन सुलझा हुआ भाइयों की निमूल आशंका है जो अपनी भाषा और अपने साहित्य को विदेशी सौँचे में ढाल कर अपने लिये अलग रखना चाहते हैं। यदि वे अपनी भाषा और अपने साहित्य की एक अलग परंपरा रखना चाहते हैं तो हमारे लिये यह प्रसन्नता की बात है। इधर अपनी भाषा की छटा, अपने साहित्य की विभूति हमारे सामने रहेगी, उधर उनके साहित्य के चमत्कार से भी हम अपना मनोरंजन करेंगे। यही सोचा उन्हें भी रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र एक से दो रहें तो और अच्छी बात है। यही स्थिति सुलझानी असलदारी में रही है। दिल्ली और दक्षिण के बादशाह फारसी कविता का भी आनंद लेते थे और परंपरागत हिंदी कविता का भी। फारसी के स्थान पर जब उर्दू की शायरी होने लगी तब भी यही बात रही। अनेक-

भी थी, जिसमें बहुत चलते संस्कृत शब्दों के साथ-साथ ठेठ दरेन्दु शब्द भी रहते थे।

यह तो हुई कविता और साहित्य की बात। सदैम अधिक ध्यान देने की बात यह है कि सर्वसाधारण सुलभमान जनता में इस्लाम के धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिये चार सौ वर्ष पहले जिस भाषा का प्रयोग वे अपनी किताबों में करते थे, उसमें वहाँ के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में आनेवाले इन्द्रिय, विकार आदि शब्द तक भी कभी-कभी लाते थे—

(१) सराहना नेवाजना खुदा को बहुत कि बोनालनहार है आलम का (शरह मरगुबुल कलूब-शाह मीर्जाजी बीजापुरी सन् १४२५ के पहले)।

(२) स्वाल—यह तन अलाधा (अलहदः) दलिक सनंतर (स्वतंत्र) विकार रूप दिखता है। एक तिल कणार नहीं ज्यों मरकट रूप।

जवाब—ऐ आरिफ़, ज़ाहिर तन के फल से गुज़रया व नातिन करनय बिपे। दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार व चेष्टा करनहारा..... सुख-दुख भोगनहारा। जेता विकार रूप वही दूसरा तन.....। यह तन ज़हम सँ गुज़रया तो गुन उसका क्यों रहे ?

(कलामतुल हक़ायक़, शाह बुरहानुद्दीन बीजापुरी सन् १५२२)

उर्दू के इतिहास-लेखक उर्दू का उत्थान बीजापुर और गोलकुंडा की दक्खिनी रियासतों से मानते हैं। वहाँ शीया सुलतानों की अधिक दस्ती थी। इससे इमाम हुसैन की कथा को लेकर दक्खिनी उर्दू के कवियों ने कई मसनवियों या प्रबन्ध-काव्यों की रचना की। इनमें से एक का नाम है 'करवल-कथा' (करवला की कथा)। यह 'कथा' शब्द भला आजकल उर्दू में कभी जगह पा सकता है ? शृङ्गार की प्रेम-कहानियों की रचना भी दक्खिनी उर्दू में बहुत कुछ हुई है। जैसे 'बजही' की 'मसनवी कुतुब-मुश्तरी' जिसकी पद्य-रचना का रूप देखिए—

न भुईँ पर वसे वह न असमान में ।
 रहा शाह उसी नार के ध्यान में ॥
 मुलाई चंचल धन व यों शाह केँ ।
 कि लुभवाए ज्यों कहरवा काह केँ ॥
 लग्या शाह उसासाँ भरन आह मार ।
 कि नजदीक ना हैं व गुनवंत नार ॥

‘वजही’ की गजल का नमूना यह है—

पिउ अपने केँ आज मैं निस सपने देखी सोयकर ।
 जब पिउ चलिया सेंति सेज तब सोते उड़ी रोयकर ॥
 ना पूछूँ वहसन जोयसी कव मिलना पिउ सों होयसी ।

‘वजही’ का रचना-काल सन् १६०० से १६३५ तक माना जाता है ।
 इसके उपरान्त सन् १६२० के लगभग ‘नसरती’ का समय आता है, जो कुछ
 दिनों तक तो दक्खिनी शायरी की उपर्युक्त परम्परा पर चला पर आगे
 चल कर वह ‘हिन्दवीपन’ को बहुत कुछ दूर हटाकर फ़ारसी रूप देने में
 लगा । अपना यह प्रयत्न उसने स्पष्ट स्वीकार किया है और कहा है—
 “दखिन के शायरों की मैं रबिश पर शेर बोल्या नहीं ।” एक स्थान पर और
 कहता है—

“मअरानी की सूत की है फ़ारसी ।
 दखिन का किया शेर जूँ फ़ारसी ।
 फ़साहत में गर फ़ारमी खुश कलाम ॥
 धरे फ़ख हिन्दी वचन पर मुदाम ।
 मैं इस दो हुनर के खुलासों को पा ॥
 किया शेर ताजः दोनों फ़न मिला ॥”

‘नसरती’ ने जो रास्ता दिखलाया उस पर कुछ लोग धीरे धीरे चलने
 लगे, पर दक्खिनी शायरी की देशी परम्परा कुछ दिनों तक चलती रही ।

सन् १९६१ ई० में अकब्र ने हिन्दी-गीतकाव्य-परम्परा के अनुसार 'शब्द-मासा' लिखा जिसकी भाषा इस ढंग की है—

सखी रे, चेत गिठ आई मुहाई । अजहुँ उम्मीद मेरी घर न आई ।
रहे हैं भँवर फूलों के गले लाग । मेरे सीन: मुदाई की लगी आग ।
सखी दिन रैन मुझ नागिन डसत है । फिरोँ दौरी तमामे जग हँसत है ।

सन् १७०० के पीछे बली ने और दक्खिनी शायरी के समान कुछ दिनों तक हिन्दीपन को रहने दिया । उसकी उन रचनाओं में हिन्दी-काव्य-परम्परा के कुछ शब्द, भारतीय कथा-प्रसंगों के कुछ संकेत, प्रेम-व्यापार में स्त्री-पुरुष का भेद आदि कुछ बातें बनी रहीं । जैसे—

इस रैन अँधेरी में मत भूल पहुँ तिसनै ।
ठुक पाँव के बिलुबों का आवाज सुनाती जा ॥
मुझ दिल के कवूतर कोँ पकड़ा है तेरी लटनै ।
यह काम घरम का है ठुक इसको छुड़ानी जा ॥
तुझ मुख की परस्तिश ने गई उम्र मेरी तारा ।
ऐ वुत का पुजनहारा इस वुत को पुजानी जा ॥
"मुख बात बालता हूँ शिकव: तेरे कपट का ।
तुझ नैन देखने को दिल टाँठ कर चुका था ॥

पोछे शाह सादुल्लाह गुलशन ने 'बली' को हदायत की कि "ये इतने फ़ारसी के मज़मून जा बेकार पड़े हैं, इन्हें काम में ला" । फिर तो बली ने अपना खूब ही पसंद दिया और वे इस तरह के कलाम सामने लाने लगे—

जब सनम को खयाले बाग हुआ । तालिबे नशअ इरात हुआ ।
प्रौज उश्शाक़ देख हर जानिव । नाज़नी साहवे दिसात हुआ ।
अशक़ सँ तुझ लवों की सुरखी के । ज़िगर लाल: दास दाग़ हुआ ।
पहले के दक्खिनी शायर तो देश श्रुको ति-रुचि के अनुसार जगह को

‘जाधा’ और ‘अलहदः’ को ‘अलाधा’ तक लिखते थे। फारसी शब्दों के बहुवचन आदि हिंदी व्याकरण के अनुसार रखते थे, पर बली ने ‘आशिक’ का बहुवचन अरबी के कायदे पर ‘उश्शाक’ रखा है और फारसी समान के ढंग पर ‘नशए-फराश’ और ‘साहवे दिमाश’। बली सन् १७०० ई० में दिल्ली आए। कायम ने सन् १७२० ई० में बली के दीवान का दिल्ली पहुँचना लिखा है।

यहाँ से अब दिल्ली के शायरों की परंपरा उर्दू-साहित्य में चली है। सन् १७०० ई० में दिल्ली में हातिम नाम के एक शायर थे। इन्होंने फिर हिंदी के शब्दों की लुँटाई की, जिसका वर्णन उन्होंने आप ही इस प्रकार किया है—

“लस्सान अरबी व ज़वान फारसी के क़रीबुलफ़हम व कसीरुल इस्तअमाल वाशद व रोज़नर्रा देहली कि मिर्ज़ायाने हिंद व फ़सीहाने रिंद दर महावरः दारंद मंज़ूर दाश्तः। सिवाए आँ ज़वान हिंदवी कि आँरा भाखा गोयंद मौकूफ़ करदः”।

तात्पर्य यह कि हातिम ने अरबी फारसी के शब्द ला लाकर रखे और हिंदी वा भाषा के शब्दों को निकाल फेंका। अरबी-फारसी के बीच हिंदी के वे ही शब्द और मुहावरे रहने पाये जिन्हें शाहजादे और सरदार लोग दरबार में बोलते थे। इस प्रकार उर्दू एक दरबारी भाषा भर रह गई। इतना होने पर भी इनको कविताओं में भारतीय कथा-प्रसंगों के संकेत पाए जाते हैं—

खुदा के नूर का मथकर ससुन्दर। यही चौदह रतन काढ़े हैं बाहर।

अगर फ़हमीदः हिकमत आशना है। इसीनुसखे में चौदह विदवा है॥

हातिम ही के समय में उर्दू के महाकवि ‘सौदा’ हुए हैं, जो पहले हिन्दू-पन से सटी हुई शायरी ही नहीं सर्व-साधारण में प्रचलित हिन्दी भाषा की कविता भी करते थे और अच्छी करते थे। कुछ उद्धृत किए बिना आगे नहीं बढ़ते बनता।

सौदा की हिन्दी गजल—

निकल के चौखट में घर की प्यारे जोर की ओम्भल टिठकरहा है,
सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ घटक रहा है।
अग्नि ने तेरे विरह की जव में झुलझा दिया है कलत्रा मेरा,
हिये की घड़कन में क्या बनाऊँ यूँ कोवला ना चटक रहा है।
जिन्हों की छाती से पार बरछी हुई है रन में वो सूना है,
पड़ा वो सावंत मन में जिसके विरह का काँटा लटक रहा है।
मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिग्गड दे है तो सोचता हूँ,
व क्योंकि सूरज की जोत आगे हर एक तारा लटक रहा है।
हिलोरी यों लेतो ओम की दूँद लग के हूँ की काँकड़ी में,
तुम्हारे कानों में जिस तरह से हर एक मोती लटक रहा है।
कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कटर दे मानी,
न जानूँ पेड़ी की धूल में हूँ जो मुझ से सुलता भटक रहा है।
कभू लगा है न आते जाते जो बैठकर टुक इमे निकालूँ,
सजन, जो काँटा है तुझ गली का सो पग में मेरे भटक रहा है।
कोई जो मुझसे व पूछता होय क्यों तू रोना है कह तो हमसे,
हर एक आँसू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है।
गुनी हो कैसा ही ध्यान जिसका तेरे गुनों में लगा है प्यार,
ग्यान परवत भी है जो उसका तो छोड़ उसको लटक रहा है।
जो बाट मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे मिरीजन,
तुम्हारी बटियों में आज बरसों से यह बटोही भटक रहा है।
जो मैंने 'सौदा' से जाके पूछा तुझे कुछ अपने भी मन की सुधबुध,
य रोके मुझसे कहा किसी की लटक में लट की लटक रहा है।

सौदा के हिन्दी दोहे—

कारी रैन डरावनी, घर तें होई निरास।

जंगल में जा सो रहे, कोऊ आस न पास ॥
 बैरी पहुँचै आइके, तेरी देहली पास ।
 बेग खबर लो या नवी! अब पत की नहि आस ॥
 खीझ खीझ चहुँ ओर से, पड़े वह ज़ालिम दूट ।
 बेबों को डरपाय के, ले गए घर को लूट ॥
 कहै हरम सर पीट कर, खोकर अपनी लाज ।
 माटी में तूरल गयो, दीन दुनी के लाज ॥
 खोयौ तैंने नीर बिन, नवी के मन को चैन ।
 ज़ालिम तेरे हाथ से, प्यासी गयो हुसैन ॥

उक्त दोहे मरसियों में आ गए हैं । उन्हीं में से अलग किए गए हैं । सौदा की पहेलियों की भाषा हिन्दी है । पर उनकी और सब रचनाएँ हातिम की ही सरणी पर चलती हैं । उर्दू की शायरी में जो थोड़ा बहुत हिन्दीपन लुका छिपा था, वह लखनऊ जाने पर नासिख के हाथ में दूर किया गया । फिर तो वह हिन्दी से ऐसी हटी कि उसने अपना एक दायरा ही अलग कर लिया । उस दायरे से जगत, चंचल, नार, गुन, अकास, धरम, धन, करम, दया, वीर, बली ऐसे शब्द एकदम निकाल बाहर हुए । इसी प्रकार वस्तुओं में न कमल और न भँवरे रह गए, न वसंत और कोकिल; न वर्षा ऋतु रह गई न सावन की हरियाली; न भीम और अर्जुन रह गए, न कर्ण और भोज । इस प्रकार यहाँ की परम्परागत भाषा के आधे हिस्से से और परम्परागत साहित्य के सर्वांश से अर्थात् देश के सामान्य जीवन से उर्दू दूर हटा दी गई । ज़बरदस्ती जान बूझकर हटाई गई, आप से आप नहीं हटी ।

उर्दू के इस रूप में आने का परिणाम यह हुआ, कि अपना प्रसार करने की स्वाभाविक शक्ति उसमें न रह गई । वह अपने को बनाये रखने के लिये मकतबों और सरकारी दफ्तरों को सहताज हो गई । वह बात अँगरेज़ी असलदारी के प्रतिष्ठित हो जाने पर हमारे नवशिक्षित मुसलमान भाइयों का

सरद दिखलाई पड़ने लगी और ये उसकी रजा और प्रसार के इत्तिम साधनों का अवलम्बन करने में लगे। मुसलमानों अमलदारी में सरकारी दफ्तर फारसी में थे। अतः ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी कुछ दिनों तक सरकारी दफ्तरों की जवान फारसी ही रहने दी। पर पीछे अधिकारियों को यह बात खटकने लगी कि दफ्तरों की भाषा सर्वसाधारण की भाषा में मिलकुल अलग है। उनका ध्यान देश की प्रचलित भाषा की ओर गया। १८३६ ई० में हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड में एक इशतहारनामा निकला, जो इस प्रकार था—

इशतहारनामः बोर्ड सदर—

पञ्चाह के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है, कि कचहरी के सब काम पारसी जवान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत दर्ज पड़ता है और बहुत कलप होता है, और जब कोई अपनी अर्ज़ी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने चाहे तो बड़ी बात होगी। सब को जैन आगम होगा। इसलिये हुक्म दिया गया है कि सन् १२४४ की कृपार बंदी प्रथम से जिसका जो नामला सदर बोर्ड में हो सो अपना अपना सवाल अपनी हिन्दी की बोली में और पारसी के नागरी अच्छरन में लिख के दाखिल करे कि डाक पर भेजे और सवाल जोत अच्छरन में लिखा हो तौने अच्छरन में और हिन्दी बोली में उसपर हुक्म लिखा जायगा। मिति २६ जुलाई सन् १८३६ ई०।

खेद की बात है कि यह व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमान भाइयों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी हुसने न पाये, उर्दू चलाई जाय। अन्त में सन् १८३७ ई० में उर्दू दफ्तरों की भाषा कर दी गई। इसके उपरान्त जब सर्वसाधारण की शिक्षा के लिये सरकार की ओर से जगह जगह सदरसे खुलने की बात उठी और सरकार ने यह निश्चय किया कि संस्कृत की कच्चाएँ तोड़ दी जाय और हिन्दी भाषा का पढ़ना सब विद्यार्थियों

के लिये आवश्यक कर दिया जाय, तब भी मुसलमान भाइयों की ओर से विरोध खड़ा किया गया और सन् १८४८ में उनकी प्रेरणा से कंपनी को सरकार ने यह आज्ञा निकाली कि “ऐसी ज़वान का इल्म तमाम तुलबा के लिये लाज़िम करार देना जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी ज़वान नहीं है, हमारी राय में दुरुस्त नहीं। अलावः इसके मुसलमान तुलबा जिनकी तादाद इस देहली कालेज में बड़ी है, इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे।” हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। वहाँ तक कोशिश की गई कि बर्नाब्यूलर स्कूलों में उसकी शिक्षा जारी ही न होने पाये। हिंदी की रक्षा के लिये राजा शिवप्रसाद को कितना यत्न करना पड़ा था, यह हिंदी प्रेमी मात्र जानते हैं। सकार की ओर से ज्ञान की वृद्धि के लिये एक संस्था (Society for the promotion of knowledge in India through the medium of vernacular language) स्थापित हुई थी, जिसका उद्देश्य था अँगरेज़ी, फ़ारसी, संस्कृत आदि की पुस्तकों का देशी भाषा में अर्थात् हिंदी, उर्दू और बँगला में अनुवाद करना। पर उर्दू को छोड़कर न हिंदी में कोई अनुवाद होने पाया, न बँगला में।

सर सैयद अहमद साहब वास्तव में उर्दू को क्या समझते थे, वह उन्हीं की जवान से सुनिये। वे फरमाते हैं—“चूँकि यह जवान ख़ास बादशाही बाज़ारों में सुरब्बज थी इस वास्ते इसको ज़वान उर्दू कहा करते थे। और बादशाही अमीर-उमरा इसको बोलते थे। गोया हिन्दुस्तान के मुसलमानों की यह ज़वान थी”। इस प्रकार उर्दू को उन्हीं ने केवल दरवारी अमीर-उमरा और मुसलमानों की जवान तसलीम किया है।

मुसलमान किस तरह पहले अपने मजहब की तालीम के लिये थोड़ी अरबी-फ़ारसी मिली एक ख़ास ढंग की हिंदी काम में लाए; फिर धीरे-धीरे हिंदीपन निकालते निकालते बिल्कुल एक विदेशी ढाँचे की भाषा गढ़कर अपने लिखने की भाषा एकदम अलग करली, यह बात अब स्पष्ट हो गई

होगी। नूरुद्दीनशाह के समय तक इस नई रादी हुई भाषा का, जो पीछे उर्दू कहलाई, साहित्य-रचना के लिये प्रचार न हो सका था। इसका आभास हिंदी के सूफ़ी कवि नूरुद्दीनशाह ने अपनी उस पुस्तक में दिया है जो उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'इंद्रावती' के पीछे लिखी। पुस्तक का नाम है 'अनुगाग-वाँसुरी'।* नूरुद्दीनशाह के समय में मुसलमान देश की प्रचलित भाषा, हिंदी से किनारा खींचने लगे थे और मुसलमानों के लिये फ़ारसी में रचना करना ही जायज समझने लगे थे। 'इंद्रावती' लिखने पर उन्हें उनके मुसलमान भाइयों ने यह कहकर फटकारना शुरू किया कि 'तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्यों लिखने गए।' इसी से बेचारे को 'अनुगाग-वाँसुरी' में अपनी सफाई इन शब्दों में देनी पड़ी—

जानत है वह निरजनहारा। जो किछु है नन सरन हमारा ॥

हिंदू-मग पर पाँव न राखेउँ। का जौ बहुते हिंदी भाखेउँ ॥

जिसे उर्दू कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, यह नूरुद्दीनशाह के इस कथन में साफ़ झलकता है—

† कामयाब कहँ कौन जगावा। फिर हिंदी भाखै पर आवा ॥

छाँड़ि फ़ारसी कंद न बाँतैं। अरुमाना हिंदी-रस-बाँतैं ॥

जनता से अपने को बिल्कुल अलग दिखाने के लिये मुसलमानों ने ही अपने लिये विदेशी ढाँचे की एक अलग भाषा और साहित्य खड़ा किया, यह इतनी प्रत्यक्ष बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उर्दू की प्राचीनता दिखाने के लिये दक्खिनी शायरों की जो लंबी सूची सामने लाई गई है उसमें कोई हिंदू भी है? शायद एक या दो। और जाने दीजिये, 'आवे हयात' ही उठा लीजिये। उसमें सब के सब शायर मुसलमान ही तो हैं। अब और सवृत क्या चाहिए? इतने पर भी न जाने किस सुँह से यह

* यह पुस्तक अप्रकाशित है।

† नूरुद्दीनशाह फ़ारसी की रचनाओं में अपना तखल्लुस 'कामयाब' रखते थे।

कहा जाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के मेल से उर्दू पैदा हुई। मेल से पैदा हुई चीज़ की यही सूरत होती है ?

आज सब से बढ़कर खेद तो तब होता है जब कोई कानून-पेशा हिंदू, पेट के पीछे जिसके धराने का लगाव देश की परंपरागत संस्कृति और साहित्य से बिल्कुल टूट गया हो, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा केवल फारसी तथा अदालती भाषा उर्दू की हुई हो, किसी जलसे या मुशायरे में उर्दू को हिन्दू-मुसलिम कलचर के मेल से बज्र में आई हुई एक सुस्तरकः जवान बताने लगता है। हम पूछते हैं कि जब तुम 'हिन्दूकलचर' से कोसों दूर पड़ गए हो तब उसका मेल कहाँ और कितना है, यह क्या पहचान सकते हो ? बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि के साहित्य की तुम्हें कुछ खबर है ? जब तुम ऐसे कूप-मंडूक हो कि अपने तंग घेरे के बाहर नजर ही नहीं फैला सकते, तब इस रोशनी के जमाने में चुप क्यों नहीं रहते ? साहित्य की जो देश-व्यापक परंपरा बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि और प्रांतों में चली आ रही है, वही परंपरा तो हिन्दी की भी है—अर्थ-परंपरा भी और शब्द-परंपरा भी। इसी अर्थ-परंपरा और शब्द-परंपरा से इस देश की दस बारह करोड़ जनता परिचित है। इसी को वह अपना समझती आई है। जिसने उर्दू नहीं पढ़ी है उसे जरा अपनी 'सुस्तरकः आमप्रहम' में कोई 'सदासी तकरीर' सुनाइए तो पता लगे। हमें सबसे बढ़कर जोभ उस समय हुआ था जब हिंदुस्तानी के किसी जलसे में एक साहब यह परमा गए थे कि "मैं तुलसी और कबीर को तो समझ लेता हूँ। पर आज कल की हिन्दी बहुत कम समझ पाता हूँ।" इस प्रलाम का भी कहीं ठिकाना है ? जो आजकल के साहित्य की भाषा नहीं समझता वह भला तुलसी की भाषा क्या समझेगा ? संस्कृत शब्दों की जो परंपरा सूर, तुलसी आदि की रचनाओं में चली आई थी वही आजकल भी चली आ रही है।

जिस प्रकार 'हिन्दवीपन' निकाल निकालकर एक विदेशी ढाँचे की

भाषा खड़ी करने का समयतः इतिहास है उसी प्रकार उस भाषा को मचके गले मचने के लिये किसी को दूर रखने के योग प्रयत्न का भी त्याग इतिहास है, जो उस समय से शुरू होता है जब देश का पूरा सामन औरंगजेबों के दाम में आया। इन दोनों इतिहासों का संक्षेप में उल्लेख करके छद्म में वर्तमान परिस्थिति पर आता हूँ। अब तक शिक्षा का मुख्य अधिकार सरकारी नौकरी रहा है। अतः इस बात का प्रयत्न बराबर होता रहा है कि दफ्तरी में हिन्दी न खुलने पाए। दफ्तरी की भाषा जब तक उर्दू रहेगी तब तक भ्रम्य मार लोगों को अपने बच्चों को उर्दू की शिक्षा देती रहेगी और यह कहने का नौका रहेगा कि उर्दू पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। अतः दफ्तरी की भाषा होना ही प्रचलित भाषा होने का प्रसार है तब भी सरकारी भी, जो कई सौ वर्ष तक दफ्तरी की भाषा रही है, देश की प्रचलित भाषा मानी जानी चाहिए।

जिस समय उर्दू के साथ साथ—उसे हटाकर नहीं—किसी को भी स्थान दिलाने के लिये सर ऐंटनी मैकडानल के समय में आंदोलन उठा उस समय भी मुसलमानों की ओर से पूरा विरोध खड़ा किया गया। अवाकतो से ही नहीं शिक्षा-पद्धति में भी हिन्दी को हटाने के प्रयत्न बराबर होते रहे हैं, यह दिखाया जा चुका है। अब आज कल की परिस्थिति देखिए। जो लोग राजनीतिक दृष्टि से हिन्दू-मुसलिम एकता अत्यन्त आवश्यक समझते हैं वे एक बीच का रास्ता पकड़कर 'हिन्दुस्तानी' लेकर उठे हैं। इस हिन्दुस्तानी का समर्थन कुछ उदार समझे जानेवाले मुसलमान और उर्दू की गोद में पले हिन्दू भी कर रहे हैं। हम भोली भाली जनता को इस 'हिन्दुस्तानी' से सावधान करना अत्यन्त आवश्यक समझते हैं। जो हिन्दुस्तानी इन लोगों के ध्यान में है वह थोड़ी छुनी हुई उर्दू के सिवा और कुछ नहीं है। उर्दू के सब लक्षण—जैसे वाक्य-रचना की आगमा शैली, अरबी फारसी के अप्रचलित मुंशी-फहम शब्द, अरबी-फारसी काबजे

के बहु-वचन—उसमें वर्त्तमान रहेंगे तब तो यह 'हिन्दुस्तानी' कहलाएगी,
अन्यथा नहीं। —————

(काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित
इसी नाम की पुस्तिका से)

परिशिष्ट १६

युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा

(लेखक—रविशंकर शुक्ल)

कुछ दिन हुए, लन्दनज विश्वविद्यालय की इंगलिश लिटरेरी सोसइटी के सभने भाषण करते हुये युक्त-प्रान्त के न्याय-मन्त्री डा० काटवू ने कहा, "If I had the power to enact laws I would prohibit the use of even a syllable of English in the Courts." ("यदि मेरे हाथ में कानून बनाने की शक्ति हो तो मैं अदालतों में अँगरेजी के एक शब्दांश के भी प्रयोग का निषेध कर दूँ।") यदि वह शक्ति अभी उनके हाथ में नहीं है तो शीघ्र ही आने वाली है, और हमें आशा तथा विश्वास है कि वे यथासम्भव अर्थात् जहाँ तक हमारी अपनी भाषा में काम चल सकता है वहाँ तक अँगरेजी, अँगरेजी शब्दों और रोमन लिपि को अदालतों से निकालने में कसर न उठा रखेंगे। परन्तु क्या हम पूछ सकते हैं कि अदालतों से फ़ारसी और अरबी शब्द, फ़ारसी मुहावरें और शैली और फ़ारसी लिपि निकालने के विषय में उनके क्या विचार हैं और इन विषय में वे क्या करने का इरादा रखते हैं? अँगरेजी, अँगरेजी शब्दों और रोमन लिपि को विदेशी और अहिष्कार-योग्य और उनके प्रयोग को 'symbol of our slavery' (उनके भाषण से उद्धृत) बताने परन्तु अरबी-फ़ारसी शब्दों और लिपि को स्वदेशी और उनके प्रयोग को 'symbol of our freedom' बताने की चेष्टा तो शायद वे न करेंगे। उन्होंने अपने उसी भाषण में आगे कहा, "The Englishman's love

of liberty and love of all things English runs through all English literature. This is something which we must emulate.” अदालतों के प्रकरण में वे स्वयं ‘love of all things Indian’ के आदर्श को किस प्रकार और कहाँ तक निभाने का इरादा रखते हैं ?

डा० काटजू ने अपने उसी भाषण में विद्यार्थियों पर “....to study, master and use Hindustani as the vehicle of expression” के लिये जोर दिया। हम इस ‘हिन्दुस्तानी’ की परिभाषा चाहते हैं। क्या यह वही ‘हिन्दुस्तानी’ है जो युक्त-प्रान्त की अदालतों में सरकारी भाषा के तौर पर व्यवहृत हो रही है ? यदि नहीं, तो इस वर्तमान ‘हिन्दुस्तानी’ को निकाल कर अपनी मनचीती हिन्दुस्तानी, वह जो भी हो, को प्रतिष्ठित करने के विषय में उनका क्या विचार है, क्या इरादा है और क्या कार्यक्रम है ? इस ‘हिन्दुस्तानी’ का क्या स्वरूप होगा, कहाँ तक वह वास्तव में हिन्दुस्तानी होगा, उसे कौन गढ़ेगा और उसके पीछे क्या सैंकशन होगा और उसकी लिपि क्या होगी, यह भी बताने की कृपा करें। इस प्रश्न को पूछने का कारण यह है कि हम युक्त-प्रान्त में किसी ऐसी ‘हिन्दुस्तानी’ से परिचित नहीं जो स्कूलों और कालेजों में पढ़ाई जाती हो और जिसे ‘study’ और ‘master’ करके हम उनके आदेश का पालन कर सकें और अपने को धन्य मानें। यदि ‘हिन्दुस्तानी’ से उनका मतलब युक्त-प्रान्त के गली-कूचों, हाट-बाज़ारों, चौरहों और चौपालों में बोली जाने वाली बोली से है, तो उसे तो हम बोलते ही हैं और उसे ‘study’ और ‘master’ करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरे, हम साधारण व्यक्तियों की तुच्छ बुद्धि में वह भी नहीं आता कि अँगरेज़ी, जो ‘symbol of our slavery’ है, के स्थान में इस बोली का प्रयोग कैसे और क्योंकर करें, और माननीय मन्त्रियों से भी इस दिशा में हमें कोई सहायता नहीं

लिखती, कुछ ग्रन्थ-प्रदर्शन नहीं होता। यदि 'हिन्दुस्तानी' से उनका तात्पर्य 'हिन्दी और / या उर्दू' ही है, तो निम्नलिखित और उगने वाले 'हिन्दी' और 'उर्दू' के बजाय इस एक शब्द 'हिन्दुस्तानी' का प्रयोग क्या उन्होंने नहीं अपने आप को और औरों को दोनों और मुलायम में जायते के लिये किया था और करते हैं ? फिर, आँगरेज़ों के स्थान में किसका प्रयोग करें— हिन्दी का या उर्दू का या दोनों का एक साथ, और किस लिपि का व्यवहार करें ? हिन्दी और उर्दू के कान पकड़ कर उन्हें एक करने की शक्ति तो उनमें या उनके आचार्य गांधी जी में है नहीं, और देवनागरी और जारसी लिपि को एक ही लिपि साधित करना अथवा 'जारसी' लिपि को 'हिन्दुस्तानी' होने का सर्टीफिकेट दिलाना बड़े से बड़े कादमी दिमाग की पहुँच के बाहर है। तीसरे, युक्त-प्रान्त के लोग फिर किस 'हिन्दुस्तानी' के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे के सामने रखेंगे और किस 'हिन्दुस्तानी लिपि' से एक दूसरे को लिखेंगे ? और किस 'हिन्दुस्तानी' और किस लिपि से अदालतों में सरकारी और गैर-सरकारी काम होगा ? यदि हिन्दुस्तानी और गैर-हिन्दुस्तानी का ख्याल न करके हिन्दी और उर्दू दोनों और 'दोनों लिपियों' में ही काम होगा, तो वह शुभ दिन कब आयेगा जब

(१) अदालतों के जजों से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारियों के लिये हिन्दी जानना और नियुक्ति से पहले उर्दू की परीक्षा के समान स्टैंडर्ड की हिन्दी विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य करार दिया जायगा और वर्तमान कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के भीतर हिन्दी की इस परीक्षा को पास करने का आदेश दिया जायगा, जिस आदेश को मंग करने के दंडस्वरूप उनकी पदोन्नति और वेतन-वृद्धि रोक दी जायगी :

(२) अदालतों के नव रेकार्ड कानूनन हिन्दी में भी—देवल देव-नागरी लिपि में नहीं बरन् हिन्दी भाषा में—रखे जायँगे, और सब अदालती नोटिस हिन्दी में भी दिए जायँगे तथा अन्य काम हिन्दी में भी होंगे।

('लीडर' में देवनागरी में छपे हुये 'Court Notices' की भाषा तो न्याय-मंत्री ने देखी ही होगी—यह भी क्या बेचारी 'जनता' का दोष है और जनता के करने की चीज़ है !%):

(३) डिग्रियों, अन्य अदालती कागज़ों, आदि की सब नकलें बिना हील-हुज्जत, रोक-टोक या बाधा के हिन्दी में सरलतापूर्वक मिल सकेंगी ;

(४) सरकार की ओर से कानूनी पंडितों के एक बोर्ड द्वारा अँगरेज़ी तथा उर्दू की सब कानूनी पुस्तकों तथा कानूनों का हिन्दी में अधिकृत अनुवाद कराया जायगा ; और

(५) अदालत के सब कागज़ों, पत्रों, हुक्मनामों, सम्मनों और फामों, आदि में देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जायगा ?

उदाहरण के लिये १२ अक्टूबर, १९४६ के 'लीडर' से देवनागरी में छपे हुये कोर्ट नोटिस की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं :

“.....वाजेह हो कि मुद्दै ने आपके नाम एक नालिश दफा २६/६१ दायर की है, लिहाज़ा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख १७ माह अक्टूबर सन् १९४६ ब-वक्त १० बजे बसुकाम बलिया असाबतन या मारफत वकील के जो मुकदमा के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल अमूर अहम मुतल्लका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज़िर हूजिये और जवाबदेही दावा की कीजिये—और हरगह वही तारीख जो आपकी हाज़िरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज़ हुई है। पस आपको लाज़िम है कि उस रोज़ अपने जुमला गवाहों को जिनकी शहादत पर नीज़ जुमला दस्तावेज़ जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्तदलाल करना चाहते हैं उसी रोज़ पेश कीजिये। और आपको इत्तिहा दी जाती है कि अगर बरोज़ मज़कूर आप हाज़िर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाज़िरी आपके मससूअ और फैसल होगा।

बसबत मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत के आज बतारीख २८ माह ८ सन १९४६ ई० जारी किया गया।”

ये सब जनता के करने की नहीं, सरकार के करने की बातें हैं। जनता को यह कहकर धोखा नहीं दिया जा सकता कि सरकार ने तो हिन्दी को उर्दू के समकक्ष रख दिया है, हिन्दी में काम करने की छूट दे दी है, फिर जनता हिन्दी में काम क्यों नहीं करती? सोचने की बात यह है कि जनता हिन्दी में अधिक सुविधा का अनुभव करते हुए भी अदालती काम हिन्दी में क्यों, किस कारण, नहीं करती अर्थात् नहीं कर पाती और जनता की सरकार का क्या कर्तव्य है। यदि हमारे माननीय मंत्री आये दिन अँगरेज़ी का मौखिक विरोध और किसी अनजानी और अज्ञात 'हिन्दुस्तानी' की वकालत करके सस्ती नामवरी हासिल करने के बजाय थोड़ी मात्रा जिसागी में काम लें, स्पष्ट बोलें, स्वयं आदर्श रखें और अपने करने का काम पूरा करें, तो अँगरेज़ी और भूठी हिन्दुस्तानी को हटाकर सच्ची हिन्दुस्तानी को अपना पद प्राप्त करने में ज्यादा आसानी हो।

परिशिष्ट १७

हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम

(लेखक—रविशंकर शुक्ल)

१

गत वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किया। उसकी देखा-देखी पटना विश्वविद्यालय ने भी यही निर्णय किया। यह 'हिन्दुस्तानी' क्या चीज़ है? वह कहाँ पढ़ाई जाती है? क्या एक ऐसी भाषा जो स्कूलों और कालेजों में कहीं नहीं पढ़ाई जाती विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम हो सकती है? दोनों में से किसी विश्वविद्यालय ने इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट करने का कष्ट नहीं किया। ज़रूरत भी क्या थी! 'हिन्दुस्तानी' का दम भर कर यूनीवर्सिटी कोर्ट के 'राष्ट्रीय' सदस्यों को कांग्रेसी नेताओं से बाहबाही लूटनी थी, वह उन्हें मिल गई, शेष यूनीवर्सिटी के अध्यापक जानें और जानें यूनीवर्सिटी के छात्र। अतः उनके प्रस्ताव से 'हिन्दुस्तानी' का अर्थ प्रकट होने की आशा करना बेकार है। प्रस्ताव ने केवल यह पता चलता है कि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी नहीं है और वह उर्दू भी नहीं है, और वह दोनों लिपियों में लिखी जाती है। याद रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'हिन्दुस्तानी' के लिये रोमन लिपि भी स्वीकृत की, अतः कहना पड़ेगा कि इन प्रस्तावों से 'हिन्दुस्तानी' के विषय में केवल इतना पता चलता है कि 'हिन्दुस्तानी' में और कुछ आता हो या न आता हो, खड़ी बोली की क्रियायें और विभक्तियाँ अवश्य रहती हैं, और वह देवनागरी, फारसी लिपि या रोमन लिपि में लिखी जाती है।

अध्यापक-गण भी केवल इतने में बाध्य हो सकते थे, अतः लखनऊ विश्व-विद्यालय में इस समय जो पढ़ाई 'हिन्दुस्तानी' में हो रही है उसका समुदाय यह है: "अगर एक वाड़ी पर दो इंकुअल फोसेज आर्गोजिट डाइरेक्शन्स में ऐक्ट करें तो वह ऐट रेस्ट हो जाता है....."। और इस समय लखनऊ विश्व-विद्यालय में जो कुछ काम 'हिन्दुस्तानी' में हो रहा है वह सब रोमन लिपि में हो रहा है। अध्यापकों या छात्रों को ठोप देना बेकार है। 'हिन्दुस्तानी' की दोरथी माया में फँस कर वे इसके सिवा कुछ और कर ही नहीं सकते। हिन्दुस्तानी वालों की खोखली राष्ट्रीयता और हिन्दी और उर्दू का अन्तर न देखने की उनकी ज़िद का एक ही परिणाम हो सकता है—इंगलिस्तानी और रोमन लिपि का जयजयकार। और यही लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहा है, और जब तक 'हिन्दुस्तानी' रहेगी तब तक होता रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता।

कुछ लोग कहेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने प्रस्ताव में पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी और उर्दू में तैयार करने का आदेश भी तो दिया है, और इसलिये इंगलिस्तानी के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, पर तो फिर 'हिन्दुस्तानी' क्या है? प्रस्ताव में पाठ्य-पुस्तकों के विषय में जो कहा गया है, उसका तो यही अर्थ निकल सकता है कि 'हिन्दुस्तानी' से अभिप्राय हिन्दी-उर्दू से है। अगर यही बात है तो 'हिन्दुस्तानी' का वकौसला किस लिये? सुपरिचित और अर्थ-युक्त नामों 'हिन्दी' और 'उर्दू' के बजाय 'हिन्दुस्तानी' नाम का प्रयोग करने की ज़रूरत? 'हिन्दी' और 'उर्दू' एक ही चीज़ तो हैं नहीं, फिर 'हिन्दुस्तानी', 'हिन्दुस्तानी' रट कर एकता का स्वाँग भगने का कारण? फिर एक ही विश्वविद्यालय में एक ही दरजे में दो माध्यमों हिन्दी और उर्दू के द्वारा पढ़ाई कैसे होगी?

शायद लखनऊ विश्वविद्यालय के 'हिन्दुस्तानी' माध्यम वाले प्रस्ताव की इसी विचित्रता का अनुभव करके संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मंत्री ने कुछ दिन

हुये (मार्च, १९४७ में) प्रान्तीय असेम्बली में कहा कि मैं 'हिन्दुस्तानी' की कामन उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दावली गढ़ने के विषय पर विचार करने के लिये प्रान्त के विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलरों की एक कान्फ्रेंस बुला रहा हूँ। प्रस्ताव में प्रयुक्त 'हिन्दुस्तानी' शब्द का यह गढ़ात्मक प्रभाव पड़ना हो था। परन्तु आज तक तो 'हिन्दुस्तानी' बन न सकी। वाइस-चांसलरों की कान्फ्रेंस को सफलता मिल जायगी, इसकी आशा कैसे की जा सकती है ? हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों के स्रोत अलग, उर्दू के अलग। 'हिन्दुस्तानी' के पारिभाषिक शब्द किन स्रोतों से और किन सिद्धान्तों के अनुसार बनाये जायें ? स्पष्ट है, हिन्दी वालों और उर्दू वालों के बीच में न आज तक कोई समझौता हो सका है और न अब हो सकता है। पता चला है कि इस कान्फ्रेंस में भाँति भाँति के तर्क देकर यह प्रस्ताव पेश किया जायगा कि 'हिन्दुस्तानी' के लिये उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्द संस्कृत और अरबी-फारसी के धातुओं से गढ़ने के बजाय अँगरेजी से ले लिये जायें, और यही प्रस्ताव स्वीकृत हो जायगा। अर्थात् जो 'इंगलिस्तानी' लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रही है उस पर सरकारी स्वीकृति की सुहर लग जायगी ! चूँकि उच्च पारिभाषिक शब्दों और अपारिभाषिक शब्दों के बीच में कोई बेलगा रेखा नहीं खींची जा सकती, दूसरे शब्दों में, चूँकि वह नहीं कहा जा सकता कि 'वाडी' और 'फोर्स' भी उच्च पारिभाषिक शब्द हैं या नहीं, वह इंगलिस्तानी वर्तमान इंगलिस्तानी से कोई विशेष भिन्न नहीं हो सकती। परन्तु कठोर सत्य यह है कि समस्या फिर भी हल नहीं होती। उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दावली के अँगरेजी से लिये जाने पर भी हिन्दी और उर्दू का वर्तमान अन्तर तो रहेगा ही। एक सीमा तक हिन्दी और उर्दू की उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ भी या पहले से मौजूद हैं या अलग-अलग बन चुकी हैं, और यह सीमा दिन पर दिन आगे ही बढ़ेगी और बढ़ रही है। कुछ विषयों (जैसे धर्म,

वर्णन, इतिहास) की तो हिन्दी और उर्दू को उच्च से उच्च पारिभाषिक शब्दावलियाँ इस समय भी मौजूद हैं, और एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। और लिपियाँ तो भिन्न हैं ही। मगर यह कि शिक्षा-मंत्री की योजना के मुकल हो जाने के बाद भी हिन्दी और उर्दू की सठह दस्तकें उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दों को छोड़कर वास्तव में हिन्दी छोड़ उर्दू में ही होंगी। इन सब बातों की गौराती में लगतज विश्वविद्यालय के प्रभाव का यह अर्थ निकलता है कि शिक्षा के माध्यम दो ही हिन्दी और उर्दू, लिपि दो ही, शब्द-दस्तकें हिन्दी और उर्दू में हों, मरन्द काल एक ही और अध्यापक एक ही। दोन अध्यापक पर छोड़ दिया जाय—जिस तरह उसे एक ही काल में एक ही बरत में दोनों माध्यमों का काम निभे उस तरह वह पढ़ाये, अध्यापक वह केवल खड़ी बोली को लिखाये बोलने के लिये बाध्य हो, उनके साथ वह चाहे हिन्दी शब्दों का प्रयोग करे चाहे उर्दू शब्दों का—चाहे वह 'अनुवाद' करे, चाहे 'परमुना'; चाहे 'विरत', चाहे 'मादम'; चाहे 'राजनीति', चाहे 'म्यामन'; चाहे 'दशमलव' चाहे 'दशमशतक', आदि, और बोर्ड पर चाहे जिन लिपि में—देवनागरी या अरबी लिपि—में लिखे ('हिन्दुस्तानी' के अँगरेजी शब्दों की कानूनी सीमा बँटने के बाद और रोमन लिपि का कानूनी परिष्कार करने के बाद सहस्रों शब्दों के जो दो पर्याय और दो लिपियाँ तो फिर भी बच गइँगी न)।

● संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री श्रीसम्पूर्णानन्द जी द्वारा संयोजित संयुक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के वादम-वासल्लों की यह कांफरेन्स २ अगस्त, १९४७ को हो गई। इस कांफरेन्स को बुलाने की घोषणा शिक्षा-मन्त्री ने मार्च में की थी, हुई यह अगस्त में और इस बीच में भागत का विभाजन हो चुका था और उसके बाद यह भी सुनाई पड़ने लगा था कि संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया है, अतः आशा की जाती थी कि यह कांफरेन्स अब 'हिन्दुस्तानी' का बखेदा समाप्त कर हिन्दी को प्रान्त के विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाने

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि 'हिन्दुस्तानी' के शिक्षा का माध्यम होने का यह भी अर्थ निकलता है कि—(१) प्रोफेसरों के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों का पूर्ण पंडित होना अनिवार्य करार दिया जाय, अर्थात् यदि एक प्रोफेसर एम० एम सी० (M. Sc.) क्लास को हिन्दी में भौतिकशास्त्र पढ़ा सकता है तो उसमें एम० एस सी० क्लास को उर्दू में भी भौतिकशास्त्र पढ़ाने की योग्यता का होना आवश्यक होगा—२० वर्ष तक भौतिकशास्त्र में शोध-कार्य करने के बाद अब वह उर्दू सीखे, उर्दू का पंडित बने, अन्यथा प्रोफेसरी की आशा त्याग दे। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और

का निर्णय करेगी। परन्तु इस कांफरेन्स में हुये निर्णयों के विषय में सरकार की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति निकली है, उसमें हिन्दी का नाम तक नहीं है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कांफरेन्स में यह तथ्य हुआ कि “मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली तुरन्त अपना ली जाय”। चूँकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है (शायद जानबूझ कर) कि “मातृ-भाषा” से अभिप्राय किस भाषा से है, और चूँकि स्पष्टतः यह कांफरेन्स शिक्षा-मन्त्री की उसी घोषणा के आधीन हुई जो उन्होंने मार्च में की थी, मानना पड़ेगा कि “मातृ-भाषा” से अभिप्राय ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् हिन्दी+उर्दू से है (वैसे भी, इस प्रान्त के जो लोग उर्दू को अपनी “मातृ-भाषा” बताते हैं—और सरकार यह मानती रही है कि उनकी मातृ-भाषा उर्दू है—, उन्हें कांफरेन्स का यह निर्णय हिन्दी की “वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली” को मंजूर करने के लिये कैसे बाध्य कर सकता है ? और हिन्दी+उर्दू वाली ‘हिन्दुस्तानी’ की कोई ‘वर्तमान पारि-

भाषिक शब्दावली’ है ही नहीं)। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि कांफरेन्स में यह भी तथ्य हुआ कि “मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली” के अलावा जिन पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता है उनमें से ऐसे शब्द जिनका अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन है “अपनी भाषा की प्रकृति और ध्वनि-प्रणाली” के अनु-रूप ढालकर ग्रहण कर लिये जायँ (यहाँ भी “अपनी भाषा” से किस भाषा से अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है; हिन्दी और उर्दू की ध्वनि-प्रणालियों में अधिक नहीं तो क, ख, ग, ङ की ध्वनियों का अन्तर तो है

लेखकारों की नियुक्ति की यह एक बात होगी कि वे हिन्दी और उर्दू दोनों के पूर्ण ज्ञाता हों और अपना विषय हिन्दी और उर्दू दोनों में पढ़ाने की योग्यता रखते हों (उन्हें हिन्दी बालों और उर्दू बालों दोनों को पढ़ाना होगा न, और दोनों की कानियाँ जाँचनी और देखनी होंगी; दोनों नियमों में उल्लंघन होना तो परमावश्यक होगा) । थोड़े दिन हुए, यहाँ से कुछ था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कोर्ट में शीघ्र ही यह प्रस्ताव पेश होने वाला है कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक के लिये 'भाषा की दोनों बनावटयुक्तियों' का जानना आवश्यक करार दिया जाय । स्पष्ट है यह प्रस्ताव बात को पक्की

ही), और शेष शब्दों के "भारतीय पर्याय" गढ़े जायें । चूँकि उर्दू अमरातीय भाषा नहीं कही जा सकती, "भारतीय पर्यायों" में अरबी-फ़ारसी पर्यायों के लिये गुंजाइश रहती ही है, परन्तु इरा देर के लिये मान लीजिए कि "भारतीय पर्यायों" में अरबी-फ़ारसी के लिये गुंजाइश नहीं है और "मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली" को छोड़कर शेष पारिभाषिक शब्दावली एक ही और भारतीय होगी । पर मातृ-भाषा हिन्दी और मातृ-भाषा उर्दू की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावलियों, जो सर्वथा भिन्न हैं, पर तो स्वीकृति की सुहर लग ही गई । और लिपि के विषय में विज्ञप्ति में कुछ नहीं कहा गया है, जिसका अर्थ है कि 'हिन्दुस्तानी' की 'दोनों लिपियों' ज्यों की त्यों बहाल रहती हैं (वैसे भी 'मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली' के साथ 'मातृ-भाषा की वर्तमान लिपि' आवेगी ही, और यह कौन नहीं जानता कि मातृ-भाषा उर्दू की लिपि 'उर्दू लिपि' है) । दूसरे शब्दों में, इस कांफ़रेन्स से 'हिन्दुस्तानी' की दोरधी समस्या का समाधान नहीं होता, और परिस्थिति ज्यों की त्यों अर्थात् वही रहती है जिसका विवेचन ऊपर लेख में किया गया है । ऊपर जो अनुमान किये गए थे उनकी पुष्टि भी हो गई ।

(लेखक ने उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के बाद संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-विभाग के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर यह पृष्टा था कि विज्ञप्ति में आये हुए शब्दों 'मातृ-भाषा' और 'अपनी भाषा' से किस भाषा से अभिप्राय है । उस पत्र का उत्तर अभी तक नहीं आया । और न अब आने की आशा है । शायद यह सामंजस्य 'high policy' का और गोपनीय है ! लेखक का

करने के लिये पेश किया जा रहा है; (२) ट्रेनिंग कालेजों में अध्यापकों को हिन्दी और उर्दू दोनों के माध्यम से शिक्षा देने की ट्रेनिंग दी जाय; (३) विद्यार्थियों के लिये आरंभ से ही हिन्दी और उर्दू दोनों अनिवार्य विषय कर दिये जायँ, और दोनों की समान स्टैंडर्ड की शिक्षा दी जाय, ताकि वे सब अध्यापकों के लेक्चर, चाहे कोई अध्यापक हिन्दी में लेक्चर दे और चाहे कोई उर्दू में, समझ सकें। यदि ऐसा न किया गया तो अध्यापकों को अपने लेक्चर में आने वाले प्रत्येक हिन्दी शब्द का उर्दू पर्याय और प्रत्येक उर्दू शब्द का हिन्दी पर्याय बताना पड़ेगा, और बोर्ड पर पहले देवनागरी में लिख कर फिर उसीको उर्दू लिपि में लिखना पड़ेगा।

विश्वास है कि यह कांग्रेस की दिलमिल नीति का एक और उदाहरण है—तुष्टीकरण की नीति में पगी हुई, बलहीन कांग्रेसी सरकार हिन्दुस्तानी छोड़ना नहीं चाहती, 'हिन्दुस्तानी' से डिग नहीं सकती, परन्तु साथ ही यह अनुभव करती है कि इधर जनता की तीव्र भावना हिन्दी के पक्ष में हो गई है, इसलिए जनता को धोखे में रखने के लिए और 'हिन्दुस्तानी' नाम से जो बलेड़ा पैदा होगा उससे बचने के लिए गोल-मोल शब्द 'मातृ-भाषा' की शरण ली गई है। बाद को कुछ जनता की आँख बचाकर, कुछ कांग्रेसी 'राष्ट्रीयता' और गांधीजी की जय बोलकर धीरे-धीरे 'हिन्दुस्तानी' प्रतिष्ठित कर दी जायगी। नाम लेकर इस समय झगड़ा क्यों मोल लिया जाय ?—ऐसा सरकार सोचती है। इसी कारण संयुक्त-प्रान्त की असेम्बली के अगले अधिवेशन में पेश होने वाले शिक्षा के पुनर्संगठन विषयक बिल का जो मसविदा अभी अभी छपा है, उसमें कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम "प्रान्त की भाषा" होगा। क्या सरकार को इस प्रान्त की भाषा का नाम नहीं मालूम, अथवा क्या इस प्रान्त की भाषा का कोई नाम है ही नहीं ? परन्तु नहीं, सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि इस प्रान्त की 'वर्नाक्युलर' को 'हिन्दुस्तानी' नाम से पुकारा जाय। सरकार सोचती है, फिर बिल में 'हिन्दुस्तानी' नाम लेकर सोने वालों को क्यों जगाया जाय, और जागने वालों को क्यों व्यर्थ और भड़काया जाय ? और इस 'प्रान्त की भाषा' की लिपि क्या होगी, पूर्वयोजनानुसार इसका जिक्र ही नदारद है। कैसी दयनीय अवस्था है !

(उदाहरण के लिये गणित के सत्राक को पहले देवनागरी में हल करके फिर उसे उर्दू लिपि में हल करना पड़ेगा), और गहाना लगभग असम्भव हो जायगा; (४) यदि शिक्षा-विभाग की ओर से बोलने वाले (Talkie) शिक्षा-फिल्म तैयार किये जायें, तो या तो प्रत्येक फिल्म अलग अलग हिन्दी और उर्दू में बनाया जाय (या फिर प्रत्येक हिन्दी शब्द के साथ उर्दू पर्याय और प्रत्येक उर्दू शब्द के साथ हिन्दी पर्याय बोला जाय जो लगभग असम्भव है), या किसी निश्चित अनुपात में कुछ फिल्म हिन्दी में तैयार किये जायें और कुछ उर्दू में, इत्यादि, इत्यादि ।

इन सब बातों का क्या अर्थ है और उनका क्या परिणाम होगा, अब इस पर हिन्दी वालों के दृष्टि-कोण से विचार कीजिये । इनका अर्थ है कि चूँकि हिन्दी प्रान्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू माध्यम की मनाई करते हैं, इतना ही नहीं कि हिन्दी वालों के पैरों में ही उनके लिये अलग उर्दू माध्यम का प्रवन्ध कर दिया जाय, बल्कि हिन्दी वालों को यह भी अधिकार नहीं रहा कि उनके अपने अल्पमात्र-भाषियों की भाँति शुद्ध हिन्दी के माध्यम द्वारा सीधी-सादी तौर से शिक्षा प्राप्त कर सकें—इतना ही नहीं कि उर्दू को भी वही अधिकार दे दिये जायें जो हिन्दी को दिये जायें, बल्कि हिन्दी विकृत की जाय, उसकी 'हिन्दुस्तानी' की जाय, और 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर इंगलिस्तानी प्रतिष्ठित की जाय (हिन्दी-उर्दू के द्वन्द्व से बचने के लिये अँगरेजों से शब्द लेकर, जबकि इनमें से अधिकांश शब्द अन्य प्रान्तीय भाषाओं में देशी लोतों से बनाये जायेंगे, और 'हिन्दुस्तानी' की दला सिर पर सवार न होती तो हिन्दी में भी देशी लोतों से बनाये जाते), और सम्भवतः हिन्दी की वर्तमान शब्दावली की भी काट-छाँट करके उर्दू शब्दों को मिलाकर ('समझौते' के लिये) एक कामन शब्दावली बनाई जाय । और उर्दू लिपि के कारण हिन्दी शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट किया जाय । जबकि अन्य प्रान्तों के दलक केवल अपनी अपनी प्रान्तीय भाषाएँ सीखकर उच्च से उच्च

शिक्षा प्राप्त करेंगे, हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी बालकों पर उर्दू का अतिरिक्त बोझ डालकर उनके समय, शक्ति और पैसे का घोर अपव्यय किया जायगा, और उनके कोमल मस्तिष्क को व्यर्थ कमजोर किया जायगा, अथवा क्लास में उर्दू वाले विद्यार्थियों के कारण अध्यापकों से हिन्दी शब्दों के साथ साथ उर्दू पर्याय बलवाकर और देवनागरी के साथ साथ उर्दू लिपि में लिखवा कर उनका समय नष्ट किया जायगा, और उनकी भाषा को विकृत किया जायगा। जबकि अन्य प्रान्तों में अध्यापक केवल प्रान्तीय भाषा द्वारा अपना विषय पढ़ाने की योग्यता प्राप्त करेंगे और केवल प्रान्तीय भाषा का ज्ञान प्राप्त कर अपना शेष समय और शक्ति अपने निपट में पारंगत होने में लगायेंगे, हिन्दी प्रान्तों में अध्यापकों पर हिन्दी और उर्दू दोनों का बोझ डालकर उनके समय, शक्ति और पैसे का घोर अपव्यय किया जायगा। दो लिपियों और दो माध्यमों के कारण पढ़ाई में, प्रयोगशालाओं में, दफ्तर के कार्य में और अन्य कार्यों में जो घोर असुविधा और पैसे का अपव्यय होगा सो अलग। इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि हिन्दी प्रान्त अन्य प्रान्तों, जो एकभाषा-भाषी होंगे, के मुकाबले में पिछड़ जायेंगे, हिन्दी बालक विद्या और बुद्धि की दौड़ में अन्यभाषा-भाषी बालकों के मुकाबले में पिछड़ जायेंगे, और प्रान्त का जीवन भी दो टूक हो जायगा तथा प्रान्त की एकता भंग हो जायगी। शिक्षा के माध्यम के रूप में लिपि और भाषा का जो द्वैत पैलेगा वह धीरे धीरे राजभाषा के रूप में, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में—प्रान्तीय जीवन के प्रत्येक पहलू में—व्याप्त हो जायगा। प्रान्त में शिक्षा का खर्च व्यर्थ बढ़ जायगा। प्रान्त में वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में तथा टेक्निकल उन्नति में विकट बाधा पड़ जायगी। हिन्दी भाषा और संस्कृति की दुर्गति हो जायगी। हिन्दी वैसी उन्नति कभी न कर सकेगी जैसी अपने अपने प्रान्तों में अखंड राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषायें करेंगी। आदि, आदि।

अब प्रश्न होता है कि हम 'हिन्दुस्तानी' के ढोंग में क्या काम करायें ? हम 'हिन्दुस्तानी' माध्यम में तो कहीं अपेक्षक यह है कि हिन्दी प्राप्ति में हिन्दी और उर्दू दोनों का सामान्य शिक्षा का माध्यम स्वीकृत कर लिया जाय, और दोनों का अलग-अलग प्रबन्ध किया जाय—सहरी में आवश्यकतानुसार कुछ शिक्षा संस्थाओं का माध्यम उर्दू हो, जंगल हिन्दी; गाँवों में यदि एक स्कूल में उर्दू माध्यम की माँग करने वाले छात्रों की संख्या एक निश्चित अनुपात (मान लीजिये १५ प्रतिशत) में पहुँच जाय तो उसमें उर्दू माध्यम का भी अलग प्रबन्ध किया जाय; और अन्धियारा प्राचीन शिक्षा-संस्थाओं (जैसे विष्णुविद्यालयों) में आवश्यकतानुसार कुछ का माध्यम उर्दू हो, शेष का हिन्दी (यद्यपि आवश्यकतानुसार एक ही शिक्षा-संस्था में दोनों माध्यमों का प्रबन्ध किया जा सकता है)। क्योंकि वही दो लिपियाँ रहेगी, वही हिन्दी और उर्दू में मुख्य सुनकी छड़ेगी, शिक्षा-प्रकारान का वही सुनकी रहेगा—मग बात कहीं रहेगी, मगद छात्रों और अध्यापकों दोनों की 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के ढोंग में पैदा होने वाली असीम सुविधाएँ और सुनकीएँ उलट जावेंगी। हिन्दी की शुद्धता की रक्षा और हिन्दी भाषियों के अधिकारों की आंशिक रक्षा भी हो जायगी। यदि हमसे शिक्षा का व्यव कुछ बढ़ जायगा—जैसे मान लीजिये कि एक शिक्षा-संस्था में 'हिन्दुस्तानी' के एक प्रोफेसर के बजाय उसी विषय को पढ़ाने के लिये दो प्रोफेसरों, एक हिन्दी जानने वाला और एक उर्दू जानने वाला, की नियुक्त कानी पड़ेगी, तो यह नहीं भूलना चाहिये कि 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के मिलमिले में हिन्दी और उर्दू दोनों के दोन्ने के कारण छात्रों तथा अध्यापकों के समय और शक्ति का जो अप्रबन्ध होगा उसका भी खयाल आना चाहिये कि नष्ट कला जा सकता है। फिर यदि एक 'हिन्दुस्तानी' का प्रोफेसर हिन्दी और उर्दू दोनों के माध्यम में पढ़ाने की योग्यता रखता है (या रख सकता है) तो वही एक प्रोफेसर हिन्दी बोलने वालों और उर्दू बोलने वालों दोनों को एक ही कक्षा में एक ही घंटे में

पढ़ाने के बजाय उन्हें अलग अलग पढ़ा सकता है। छात्रों का समय क्यों नष्ट किया जाय ? यह भी नहीं भूलना चाहिये कि शिक्षा का प्रसार होने पर छात्रों की संख्या यही नहीं रहेगी और प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को कई सेक्शनों में बाँट कर पढ़ाना पड़ेगा (जैसे आजकल भी स्कूलों में प्रत्येक कक्षा के दो दो सेक्शन होते हैं)। प्रत्येक सेक्शन में हिन्दी वालों और उर्दू वालों दोनों को एक साथ पढ़ाने के बजाय हिन्दी वालों को एक या अधिक सेक्शनों में इकट्ठा करके अलग और उर्दू वालों को एक या अनेक सेक्शनों में इकट्ठा करके अलग पढ़ाया जा सकता है। हिन्दी और उर्दू दोनों को स्पष्ट रूप से शिक्षा का माध्यम स्वीकृत करने से एक लाभ यह भी होगा कि उर्दू प्रान्तों जैसे पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिन्ध में भी हिन्दी को अलग शिक्षा का माध्यम स्वीकृत कर लिया जायगा या कराने का अवसर रहेगा, अन्यथा इन प्रान्तों में हिन्दी प्रान्तों का हवाला देकर कागज़ पर 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम घोषित किया जायगा परन्तु व्यवहार में उसे शुद्ध उर्दू से अभिन्न बना दिया जायगा, और 'दोनों लिपि' को अव्यावहारिक बता कर देवनागरी को उड़ा दिया जायगा, और इस प्रकार हिन्दी की विलकुल जड़ काट दी जायगी।

सारांश यह कि लखनऊ विश्वविद्यालय का 'हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का माध्यम घोषित करना एकता का ढकोसला मात्र है क्योंकि 'हिन्दुस्तानी' से मतलब किसी एक ही सुनिश्चित भाषा और एक ही लिपि से नहीं है, और इस 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम स्वीकृत करना हिन्दी और उर्दू दोनों को माध्यम स्वीकृत करने से किसी भी बात में श्रेयस्कर नहीं है। और जहाँ तक 'हिन्दुस्तानी' माध्यम से तात्पर्य किसी वर्तमान या भविष्य में गढ़ी जाने वाली हिन्दी, उर्दू और अँगरेज़ी की खिचड़ी भाषा से है, वहाँ तक वह हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी पर और हिन्दी भाषियों के अधिकारों पर क्रूर कुठाराघात है। कहना न होगा कि राष्ट्र-भाषा के प्रकरण में कांग्रेस ने जिस वाद को

अवस्था था और वह जिस रास्ते पर चल रही थी, हमने प्रकट था कि 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के हमारे अर्थ पर जोर दिया जाता, और अहिंसी सरकारें 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के नाम पर हिन्दी की मुलत करके उसे दोनों लिपियों में हिन्दी प्रांतों में शिक्षा के माध्यम के रूप पर प्रचलित करनी। श्री सम्पूर्णानन्द का 'हिन्दुस्तानी' की पारिभाषिक सूचनायुक्त गढ़ने के लिये संयुक्त-प्रांत के विश्वविद्यालयों के वाइस-चान्सेलरी की कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना इस ओर एक कदम था। विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रांतीय भाषाएँ शिक्षा का माध्यम होतीं, पंजाब, सीमा-प्रांत और निरख में उर्दू शिक्षा का माध्यम होतीं परन्तु हिन्दी कहीं शिक्षा का माध्यम नहीं होती—हिन्दी प्रांतों में भी नहीं। इस क्षेत्र में हिन्दी का अस्तित्व उठ जाने के बाद अन्य सब क्षेत्रों में हिन्दी का अस्तित्व स्वतः उठ जाता क्योंकि जहाँ जहाँ ही मुक्त जाती तो वहाँ ही हिन्दी रह सकते थे।

२

परन्तु अब परिस्थिति निकलना बदल चुकी है। देश के विभाजन के बाद कांग्रेस के हिन्दुस्तानीवाद के लिये कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अधिक कहने की जरूरत नहीं। भारतीय विधान-मण्डल की कांग्रेस पार्टी ने हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि बनाने के पक्ष में फैसला देकर इस सत्य को स्वीकार कर लिया है। हमें स्पष्ट अवश्य है कि कांग्रेस की आँखें खोलने के लिये देश के विभाजन पैसी हृदय को चिरीनी करने वाली और कलेजा मनोमते वाली घटना की जरूरत नहीं। अस्तु, अब हिन्दुस्तानीवाद का सर्वथा अन्त हो जाना चाहिये। इसके बाद अब हिन्दी प्रांतों में शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल हिन्दी और उर्दू पर विचार करना योग्य रह जाता है। परन्तु हिन्दी प्रांतों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों माध्यम के रूप में स्वीकृत नहीं जा सकतीं। कारणों की ओर ऊपर इशारा किया जा चुका है। चाहे दोनों माध्यम वाली

को 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर एक ही क्लास में पढ़ाया जाय (जैसा लखनऊ विश्वविद्यालय ने सोचा है) और चाहे हिन्दी माध्यम और उर्दू माध्यम का अलग अलग प्रबन्ध किया जाय *, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के हिन्दी और उर्दू, दो माध्यम होने से प्रांत की एकता भंग हो जायगी, प्रांत की उन्नति रुक जायगी, प्रान्त पिछड़ जायगा, प्रान्त पर शिक्षा के व्यय का भार बढ़ जायगा, आदि, आदि। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। हिन्दी प्रान्तों के लिये शिक्षा के दो माध्यमों के होने से बढ़कर बुरी और घातक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। यह शाश्वत सत्य है, अर्थात् यह पढ़ले भी सत्य था। परन्तु बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में तो हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी और उर्दू दोनों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम कदापि, किसी भी हालत में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। देश के विभाजन से हिन्दी प्रान्तों में उर्दू को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत न करने के जो विशेष कारण उत्पन्न हो गये हैं, उनमें से एक लेखक के निजी अनुभव पर आधारित है। कुछ दिन हुए, लेखक ने एक मुसलमान रंगसाज़ से, जो उसके यहाँ काम करने आया

* ऊपर के विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि हिन्दी वालों और उर्दू वालों दोनों को एक ही क्लास में पढ़ाना संभव नहीं—विशेष रूप से माध्यमिक और ऊँचे स्टेजों में। इसके अतिरिक्त छात्रों और अध्यापकों पर हिन्दी और उर्दू दोनों सीखने का बोझ नहीं डाला जा सकता, और न क्लास में उर्दू वाले छात्रों की उपस्थिति के कारण उर्दू शब्दों को भी बोल-बोल कर और उर्दू लिपि में भी लिख-लिख कर हिन्दी छात्रों का समय नष्ट किया जा सकता है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में यह सब और भी असह्य है। दूसरे शब्दों में, हिन्दी और उर्दू दोनों को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत करने का यही अर्थ है कि हिन्दी माध्यम का अलग और उर्दू माध्यम का अलग प्रबंध करना होगा, और शिक्षा पर बिल्कुल दूना व्यय होगा। इस व्यय का अधिकांश हिन्दी कर्दाताओं की जेब से ही आवेगा, अर्थात् हिन्दी कर्दाताओं के खर्च से उर्दू माध्यम का अलग प्रबंध करना पड़ेगा।

था, पूछा कि तुम वहीं रहोगे या पाकिस्तान जाओगे ? उसने कहा, हम तो वहीं रहेंगे, पाकिस्तान में रोज़गार जमाने के लिये करना कहाँ से लावें ? लेखक ने कहा कि इसमें कठिनाता नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान में व्यापारियों और कारीगरों की कमी है। उसने जवाब दिया कि हाँ साहब, यह तो ठीक है कि बड़े बड़े शहर सब निकल गये। वह एक गरीब, अनाद मुसलमान की मनोवृत्ति है जो स्वयं कबता है कि मुझे वहीं रहना है ! वह दिल में अपने श्री वहाँ का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नागरिक मानता है, और उसकी सहायता, प्रेम तथा देशभक्ति पाकिस्तान के साथ है। लेखक ने उससे फिर पूछा, तो फिर क्या साहब ने पाकिस्तान लिया क्यों ? उसका उत्तर सुनकर लेखक तो स्तब्ध रह गया। उसने कहा, बल्कि यों कहिये उसके मुँह से ऐसा कहा निकल गया, हमें तो पूरे हिन्दुस्तान पर कब्ज़ा करना है ! परन्तु होता है कि इन मुसलमान की मनोवृत्ति में अन्तर क्या और उर्दू माध्यम का प्रयत्न करके डाल सकते हैं ? कहाँ से नहीं। वह तो केवल उसकी सहवाकांक्षाओं को और प्रबल करते हैं, उसे अपने को अन्य प्रान्त-वासियों से पृथक् अनुभव कराने में, देश के विरुद्ध प्रवृत्त करने में और पाकिस्तान में चलने वाले संकेतों और कुत्तकों को मनोवृत्त कराने में सहायक होगा। उर्दू माध्यम वाले स्कूल और कॉलेज (अथवा उर्दू माध्यम वाले क्लास) किम्वद कालम वालों के खेत, उनके शिक्षा-ग्रह, उनके अड्डे और दिमाग बल जायेंगे। उर्दू माध्यम का प्रयत्न करना अपने हाथ में अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना होगा। अगर हम इन मुसलमानों को अपने में मिलाना और खपाना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हिन्दी प्रान्तों का जीवन साम्प्रदायिकता और द्वैत में मुक्त हो जाय, तो उसका एक ही उपाय है— प्रान्त भर के लिये, सबके लिये केवल हिन्दी माध्यम स्वीकृत किया जाय। इसी प्रकार प्रान्त में राष्ट्रीय और एकजुट जीवन का निर्माण हो सकता है, एकता की नींव इसी आधार पर रखी जा सकती है, इसी प्रकार प्रान्त

दो-दो भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के दुष्परिणाम, अनन्त बखेड़े, परेशानियों और फिजूल खर्च से बच सकता है, इसी प्रकार हिन्दी और हिन्दी संस्कृति की शुद्धता की रक्षा हो सकती है, इसी प्रकार हिन्दी अपने अपने प्रदेश में अखण्ड राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषाओं की भाँति अव्यथ उन्नति कर सकती है, और इसी प्रकार हिन्दी प्रान्त अन्य एकभाषा-भाषी प्रान्तों की भाँति उन्नति कर सकते हैं। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। शहरों में रहने वाले थोड़े से मुसलमानों (और थोड़े से हिन्दुओं) के कारण हिन्दी प्रांतों का भविष्य नहीं विगाड़ा जा सकता और हिंदू करदाताओं का रुखा नहीं लुटाया जा सकता। अल्पसंख्यकों के साथ न्याय अथवा उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा का अर्थ यह नहीं है कि प्रान्त का जीवन दो टुक कर दिया जाय और प्रान्त के लिये असीम कठिनाइयाँ पैदा कर दी जायँ। हिन्दी प्रान्तों में मुसलमानों की संस्कृति और भाषा (उनकी मातृ-भाषा क्या है!) की रक्षा का अर्थ यही हो सकता है कि पाठ्य-क्रम में उर्दू वैकल्पिक विषय रहे ताकि जो विद्यार्थी चाहे वह उर्दू भाषा और साहित्य का विषय ले सके। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में, जैसे एक स्कूल में एक निश्चित अनुपात से अधिक संख्या में विद्यार्थियों के माँगने पर, प्राथमिक शिक्षा उर्दू के माध्यम से भी देने की सुविधा दे दी जाय (यह सुविधा भी तभी दी जा सकती है जब पाकिस्तान में हिन्दी वालों को हिन्दी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाय)। पाकिस्तान की सरकार भी, यदि वह अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत उदार हुई और उसने उनकी संस्कृति की रक्षा करने के विषय में दिये हुये अपने आश्वासनों को पूरा किया तो, हद से हद वह करेगी कि पाठ्य-क्रम में हिन्दी भाषा और साहित्य का विषय वैकल्पिक विषय के रूप में रख देगी, परन्तु वहाँ शिक्षा का माध्यम उर्दू ही होगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर डा० ज़ियाउद्दीन (जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने ऐसे मुसलमान

इंजीनियरों, सुसलमान वैज्ञानिकों और अन्य सुसलमान टेकनिकल व्यक्तियों को सूची बनाने का काम सौंपा है जो पाकिस्तान की सेवा करने को तैयार है) ने स्पष्टतः घोषित कर दिया है कि पाकिस्तान के सब विश्व-विद्यालयों (अर्थात् लाहौर विश्वविद्यालय का भी) की शिक्षा का माध्यम उर्दू होगा, और यह भी कहा है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी माध्यम उर्दू होगा। सिन्ध के शिक्षा-मंत्री ने बताया है कि कराची विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम तो उर्दू होगा ही, सिन्ध में, और पाकिस्तान भर में, माध्यमिक शिक्षा का भी माध्यम उर्दू होगा और उर्दू का विषय प्राथमिक स्तर में ही सबके लिये अनिवार्य होगा, अत्यन्त प्राथमिक शिक्षा मात्र-मात्र के माध्यम में ही जायगी (यह देखना चाहिये कि प्राथमिक शिक्षा के लिये ही हिन्दी भी माध्यम के रूप में स्वीकृत की जाती है या नहीं)। सिन्ध सरकार ने हिन्दुओं की शिक्षा-संस्थाओं को, जो संभव था हिन्दी की शिक्षा का माध्यम बताती, स्पष्ट धमकी दी है कि यदि उन्होंने माध्यम के विषय में सरकारी नीति का अनुकरण न किया तो सरकारी मदद बिलकुल बन्द कर दी जायगी, और यह भी घोषित कर दिया गया है कि सिन्ध की जो भी शिक्षा-संस्था, चाहे उसे सरकार एक पैस की भी मदद न देती हो, कराची विश्वविद्यालय से अत्यन्त सम्बन्ध नहीं जोड़ेगी, (अर्थात् जो उर्दू की शिक्षा का माध्यम नहीं बनावेगी), उसे सरकारी स्वीकृति (recognition) प्राप्त नहीं होगी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान ने उच्च शिक्षा का माध्यम केवल एक रखकर अनुचित नहीं किया है। सभी उत्पत्ति-शील और प्रजातांत्रिक देशों में जहाँ एक अल्पसंख्यक दल को चुनकरने के लिये उसके साथ विशेष व्यवहार करना और उसे फिर पर बैठाना राष्ट्रीयता नहीं समझा जाता, ऐसा हो होता है। अमरीका की ही मिसाल दी जा सकती है, जहाँ जर्मन, डच, फ्रांसीसी, अँगरेज आदि सभी नागरिकों की शिक्षा का माध्यम केवल एक, अँगरेजी, है। राष्ट्रीय

जीवन का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण इसी प्रकार होता है, और आधुनिक युग में किसी देश में या किसी प्रान्त या शासन-क्षेत्र (administrative area) में उच्च शिक्षा का काम, वैज्ञानिक और टेकनिकल अनुसंधान, वैज्ञानिक, टेकनिकल और दौढ़िक उन्नति तथा अन्य आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी प्रकार हो सकती है। फिर, यदि हम आज हिन्दी प्रान्तों में सुसलमानों के लिये उर्दू माध्यम स्वीकृत कर लेते हैं, तो क्या कल हमें सरकारी खर्च पर ही प्रान्त में बसे हुये बंगालियों के लिये बँगला माध्यम, पंजाबियों और सिखों के लिये पंजाबी माध्यम, आदि स्वीकृत नहीं करने पड़ेंगे? इसका अन्त कहाँ होगा? हिन्दुस्थान के किन दूसरे प्रान्तों में ऐसा भ्रमेला पाला जायगा (पाकिस्तान में तो नहीं पाला जायगा हो)? यह उदारता, आदि का सवाल नहीं है। यह व्यावहारिकता, राष्ट्रीयता और आत्म-रक्षा का सवाल है। व्यावहारिकता और राष्ट्रीयता की बात पहले कही जा चुकी है। आत्म-रक्षा के विषय में दूर न जाकर अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर नजर डालना काफी है। अभी हाल में (८ जौलाई, १९४७) श्री क० मा० मुंशी ने एक सार्वजनिक सभा में एक भाषण करते हुये कहा, “—— For the sake of a worn-out and discredited nationalism of yesterday we cannot sacrifice homogeneity, otherwise we shall not be able to withstand the religious nationalism of a neighbouring nation.” ये शब्द बार बार विचार करने योग्य हैं। ‘Homogeneity’ (एकरसता) के लिये सबसे अधिक आवश्यक है शिक्षा के माध्यम का एक ही होना। स्पष्ट है, जिस परिस्थिति में संयुक्त-प्रान्त की पिछली कांग्रेसी सरकार द्वारा बैठाई हुई नरेन्द्रदेव कमेटी ने संयुक्त-प्रान्त के लिये हिन्दी और उर्दू दो माध्यमों की सिफारिश की थी (अन्य हिन्दी प्रान्तों में भी इसी सिफारिश पर चला जाता), अब वह नहीं

रही। इस सिफारिश को मानना अव्यावहारिक और राष्ट्र-व्यापक और प्रान्त-व्यापक तो होगा ही, आज की परिस्थिति में आत्म-व्यापक होगा।

हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा के माध्यम के प्रसंग में एक और बात ध्यान देने योग्य है। हिन्दी और उर्दू दोनों के शिक्षा के माध्यम स्वीकृत होने के बाद स्वाभाविकतया वह भाग देश की जायगी कि हिन्दी और उर्दू दोनों प्रान्त की राज-भाषा, कचहरियों, दफ्तरों की भाषा, आदि के रूप में स्वीकृत की जायँ। इससे कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, इसका सख्त में अनुमान किया जा सकता है। प्रान्त का काम चलना अस्मभव-साय हो जायगा (क्योंकि आड़े आने के लिये आज की भाँति अँगरेज़ी तो होगी नहीं)। इससे दूरकम यदि हिन्दी प्रान्तों में हमें केवल हिन्दी को राज-भाषा, कचहरियों, दफ्तरों, अस्मभव-साय, आदि की भाषा बनाना है (संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने तो यह निर्णय कर भी लिया है), तो इसकी एक कारोबारी यह है कि हिन्दी प्रान्तों में साधनिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी हो, क्योंकि तभी राजकार्य चल सकता है, कचहरियाँ, दफ्तरों आदि के लिये योग्य कर्मचारी, क्लर्क आदि (हिन्दू और मुसलमान) मिल सकते हैं और प्रान्त के जीवन में सब समान रूप से भाग ले सकते हैं। यदि सबकी साधनिक और उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी को न माना बनाया गया, तो कम से कम हिन्दी भाषा का विषय तो सबके लिये आरंभ से ही अनिवार्य करना ही पड़ेगा। फिर साधनिक स्तर में पहुँच कर सबको हिन्दी के माध्यम से ही शिक्षा क्यों न दी जाय ? उसमें क्या कठिनाई होगी ? वहाँ उर्दू को अलग माध्यम बनाकर अलग परीक्षानियाँ और कठिनाइयाँ क्यों नहीं दी जायँ ? एक बात और है। हिन्दी हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भाषा होने का नहीं है। इस नाम से हिन्दी का महत्व कम न होगा। देश भर में सबके लिये हिन्दी भाषा का विषय अनिवार्य होगा (जिस प्रकार आज अँगरेज़ी का विषय अनिवार्य है)। देश का सब केन्द्रित काम और अन्तर्देशीय

व्यवहार हिन्दी में होगा। अतः सोचना तो यह है कि सब प्रान्तों में हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना कहाँ तक वांछनीय और आवश्यक है। एक ही प्रान्त में उच्च शिक्षा के दो माध्यमों के होने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती।

अन्त में एक बात और स्पष्ट करने की आवश्यकता मालूम होती है। शायद यह कहा जाय कि 'हिन्दुस्तानी' नाम रहने दिया जाय, वह होगी हिन्दी ही। पर इसकी आवश्यकता? यह तो हृद दर्जे की कमजोरी का प्रदर्शन और धोखा देना होगा। हिन्दी के लिये 'हिन्दुस्तानी' नाम कभी स्वीकृत नहीं किया जा सकता। कारण ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों हैं। कोई कारण नहीं यह नाम-परिवर्तन क्यों किया जाय। फिर, 'हिन्दुस्तानी' नाम रहते हिन्दी भाषा कभी आ ही नहीं सकती (शायद इसीलिये 'हिन्दुस्तानी' पर इतना जोर दिया जाता है)। चूँकि 'हिन्दुस्तानी' व-ज्ञात-ए-खुद कोई चीज़ नहीं, उसका कोई इतिहास या निजी थाती नहीं, उसका अर्थ तो या हिन्दी+उर्दू लगाया जायगा या $\frac{\text{हिन्दी+उर्दू}}{२}$ । संयुक्त-प्रान्त में 'हिन्दुस्तानी' साहित्य की उन्नति के लिये स्वीकृत (५०,०००) के विषय में जो सरकारी घोषणा हुई है, उसमें स्वयं सरकार ने 'हिन्दुस्तानी' का यह अर्थ लगाया है ('हिन्दी' और 'उर्दू' साफ साफ रक्खी गई हैं और $\frac{\text{हिन्दी+उर्दू}}{२}$ के लिये "_____and what is recognised as Hindustani" कह कर गुंजाइश रक्खी गई है)। और फिर लिपि के मामले में तो 'हिन्दुस्तानी' का अर्थ अवश्य हो देवनागरी+फ़ारसी लिपि लगाया जायगा। यह सब अब नितान्त असम्भव है। हिन्दुस्तानी-वाद के साथ साथ अब 'हिन्दुस्तानी' नाम का भी सर्वथा अन्त हो जाना चाहिये।

संक्षेप में—

(१) हिन्दी प्रान्तों की भाषा-समस्या (जो ज़बरदस्ती पैदा की गई है)

और 'सिविल-सर्विस' (जो 'हिन्दुस्तानी' के भरोसे के बाद भी यहाँ की स्था-
नही है) का एक मात्र व्यावहारिक और राष्ट्रीय हल, तथा देश के विभा-
जन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का तकाजा यह है कि हिन्दी प्रान्तों में
माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी होनी चाहिये । जो
गैर-सरकारी शिक्षा-संस्था ऐसा करना स्वीकार न करे, उसे न सरकार मदद
दे और न उसे सरकार स्वीकृत (recognise) करे ।

(२) माध्यमिक स्टेज में हिन्दी के शिक्षा का माध्यम होने का अर्थ है
कि हिन्दी भाषा का विषय प्राथमिक (primary) स्टेज में ही सबके लिये
अनिवार्य हो (अन्यथा माध्यमिक स्टेज में हिन्दी के माध्यम में शिक्षा कैसे
दी जायगी ?), और कम से कम माध्यमिक स्टेज के अन्त तक (आजकल
के इन्टरमीडिएट तक) सबके लिये अनिवार्य रहे, और तदनुसार आजकल
की 'नेचुरल इङ्गलिश' का भाँति 'संयोजित हिन्दी' का विषय सब के लिये
अनिवार्य हो ।

(३) विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के लिये उर्दू, बँगला, आदि
के माध्यम का भी प्रयत्न किया जा सकता है । परन्तु हिन्दी भाषा का विषय
फिर भी सबके लिये अनिवार्य होगा । अवश्य ही यह उर्दू, बँगला, आदि के
माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त
बोझ होगा, और परिणामस्वरूप अधिक से अधिक विद्यार्थी हिन्दी माध्यम
से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे । यह बांझनीय है ।

(४) उर्दू भाषा और साहित्य का विषय माध्यमिक स्टेज से वैकल्पिक
विषयों की सूची में रक्खा जाय । बँगला, पंजाबी या अन्य प्रान्तीय भाषाएँ
भी माध्यमिक स्टेज से वैकल्पिक विषयों की सूची में रक्खी जायँ ।

(५) रेडियो के स्कूली प्रोग्राम, शिक्षा-फिलम, आदि सब हिन्दी में हों
और बनें ।

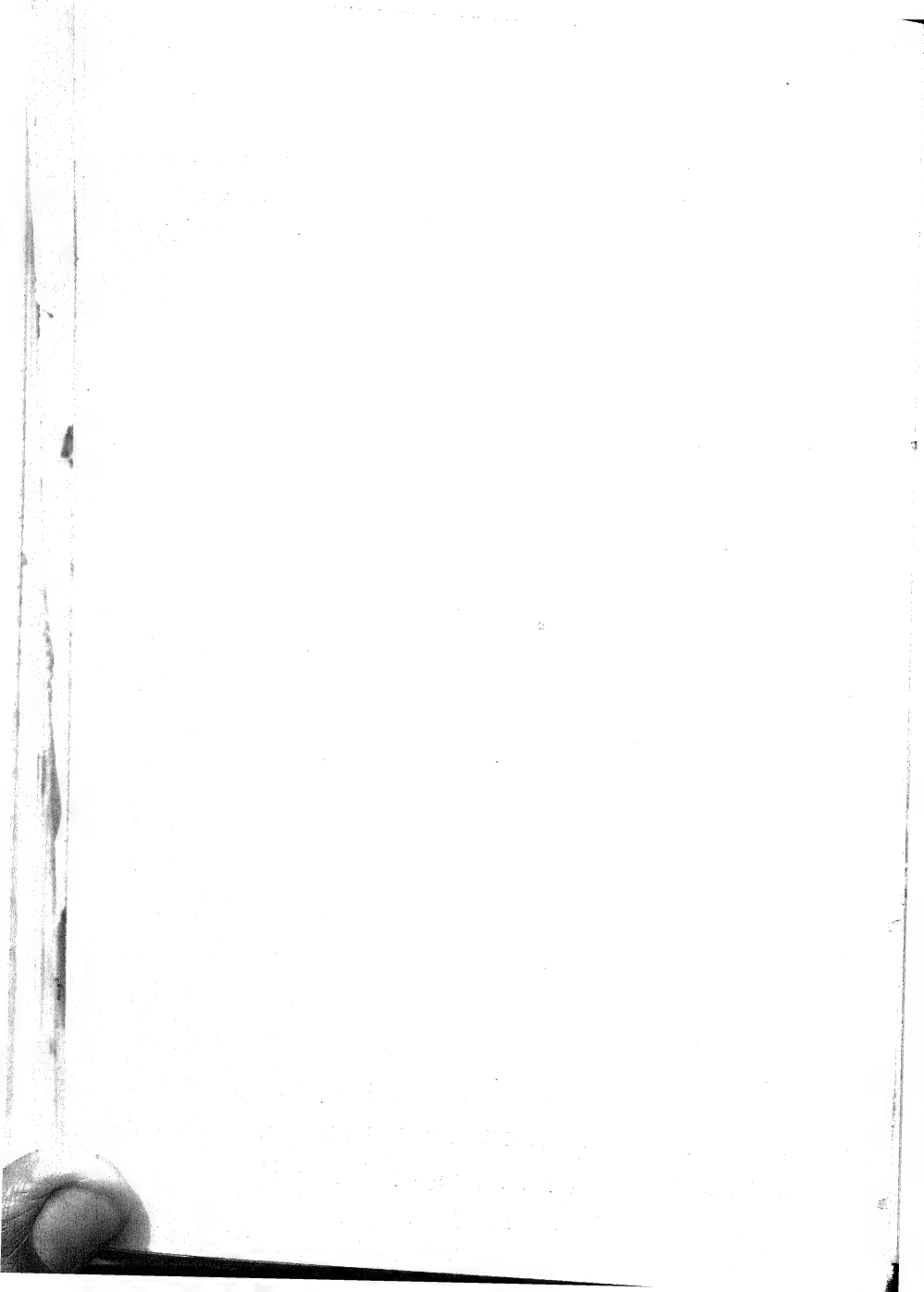
(६) आजकल संयुक्त-प्रान्त में ऐंग्लो-वर्नाकुलर स्कूलों में छात्रों के लिये

आठवीं कक्षा तक हिन्दी और उर्दू दोनों पढ़ने की, और अध्यापकों के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों की विभागीय परीक्षाएँ पास करने की जो अनिवार्यता है वह तुरन्त हट जानी चाहिये। यह हिन्दी वालों के साथ सरासर अन्याय है। हिन्दी प्रांतों में कुछ लड़के उर्दू पढ़ते हैं, यह हिन्दी वालों का कसूर नहीं है जिसके दंडस्वरूप उन पर (यहाँ तक कि हिन्दी बालिकाओं पर भी) उर्दू का भी बोझ डाला जाय। किसी दूसरे प्रान्त में ऐसा नहीं होता (यहाँ तक कि पंजाब में उर्दू लेने वालों पर वहाँ की असंदिग्ध मातृ-भाषा पंजाबी का भी बोझ नहीं डाला जाता)। जब उर्दू प्रांतों में उर्दू वालों के लिये हिन्दी अनिवार्य नहीं है, तब हिन्दी प्रांतों में हिन्दी वालों के लिये उर्दू अनिवार्य करके उर्दू का अन्तर्गल प्रचार नहीं किया जा सकता। पहले (अर्थात् जब राजद्वार में उर्दू का बोलचाल था) उर्दू की चाहे जो आवश्यकता रही हो, अब हिन्दी प्रांतों में हिन्दी वालों को उर्दू की कोई आवश्यकता भी नहीं रह गई। हिन्दी राष्ट्र-भाषा है अतः सबको पढ़ना पड़ेगी और सबकी कामन भाषा होगी। हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी राजभाषा, शिक्षा का माध्यम, आदि और इस कारण सबके लिये अनिवार्य विषय और सबकी कामन भाषा होगी ही। उर्दू वालों को हिन्दी पढ़नी पड़ेगी, हिन्दी वालों को उर्दू नहीं पढ़नी पड़ेगी। हिन्दी वाले अपनी बची हुई शक्ति अन्य विषयों में क्यों न लगावें ? और शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने पर अध्यापकों के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों की विभागीय परीक्षाएँ पास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

(७) हिन्दुस्तानी-वाद और 'हिन्दुस्तानी' नाम का तुरन्त अन्त हो जाना चाहिये। लखनऊ और पटना विश्वविद्यालय तुरन्त अपना पारसाल वाला निर्णय बदलकर देवनागरी में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने की घोषणा करें। स्कूलों से 'हिन्दुस्तानी बोलचाल', 'महमूद सीरीज़', 'राजेन्द्र सीरीज़', आदि की 'हिन्दुस्तानी' की पुस्तकों का बिलकुल बहिष्कार हो जाना

चाहिये। 'ऐंग्लो-हिन्दुस्तानी' स्कूलों का नामकरण 'ऐंग्लो-हिन्दी स्कूल' और अँगरेजी के हटने पर 'हिन्दी स्कूल' होना चाहिए। संयुक्त-प्रान्त की 'बर्ना-क्युलर' सब जगह 'हिन्दी' लिखी व बताई जाय, 'हिन्दुस्तानी' नहीं। संयुक्त-प्रान्त की सरकार को अपना वह आर्डर वापस ले लेना चाहिये जिसमें संयुक्त-प्रान्त की 'बर्नाक्युलर' को 'हिन्दुस्तानी' नाम से पुकारने का आदेश दिया गया है, और 'हिन्दुस्तानी' साहित्य की उन्नति के लिए स्वीकृत ५०,०००) हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिए दे देना चाहिये। अच्छा ही यदि संयुक्त-प्रान्त का नाम हिन्द-प्रान्त या हिन्द रक्खा जाय।

(८) इस पर विचार किया जाय कि देश भर में उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम केवल एक (जो हिन्दी ही होगी) होना कहाँ तक वांछनीय, आवश्यक और व्यावहारिक है। यह नहीं भूलना चाहिये कि अमरीका और रूस में ऐसा ही है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। कम से कम यह तो नितान्त आवश्यक है कि देश भर में विज्ञान तथा अन्य विषयों की उच्च पारिभाषिक शब्दावली एक ही और कामन हो। यह शब्दावली हिन्दी की ही हो सकती है। इसके निर्माण में नेतृत्व हिन्दी वालों को ही ग्रहण करना है। इस विषय में लाहौर की इन्टरनेशनल एफो-डेमी आफ इंग्लिश कलाचर के अन्तर्गत डाक्टर गुरुशिर का कार्य अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री को चाहिये कि वे अपनी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में केवल पटना, दिल्ली और मौगोर विश्वविद्यालयों का ही नहीं बरन् देश के सब विश्वविद्यालयों का सहयोग प्राप्त करें ताकि देश भर के लिए एक सर्वसम्मत, कामन शब्दावली का निर्माण हो सके। यह शब्दावली देश भर के विश्वविद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा का माध्यम स्वीकृत कराने की ओर पहला कदम होगी। इस काम में केन्द्रीय सरकार को भी हाथ बैटाना चाहिए।



उत्तर-परिशिष्ट १

रोमन लिपि का जयजयकार

(लेखक—रविशंकर मुखर्जी)

हिन्दुस्तानी-बाद या वदियात करते हुए प्रसिद्ध भाग्यवेत्ता डॉ॰ लुनाति कुमार चतर्जी ने एक बार कहा था, 'हमारी जी के 'डोरो लिपि'बाद के परिणाम-स्वरूप 'देवनागरी' रोमन लिपि का जयजयकार होना पड़ता है।' मालूम पड़ता है कि उनकी भविष्यवाणी सच होने जा रही है। इन पंक्तियों का लेखक पाठकों का ध्यान दो बातों की ओर प्रमुख रूप से खींचना चाहता है—पहले तब तक उनसे निष्कर्ष निकाल लें।

१

यह सबको मालूम है कि हमारी वर्तमान 'राष्ट्रीय' सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मन्त्र हैं। इस निमित्त देश की केन्द्रीय सरकार में शिक्षा मन्त्र का पद सँभालने के बाद मौलाना साहब की जो सबसे पहला और सबसे आवश्यक काम पैदा है वह है रोमन लिपि का प्रचार। १८ फरवरी, १९४७ को एक प्रेस कॉन्फ़रेन्स में उन्होंने रोमन लिपि की जोरदार वकालत की। इन पंक्तियों के लेखक ने न रहा गया। उन्होंने यह अनुभव करते हुए भी कि नकारखाने में तूती की कोई नहीं छुनेगा, मौलाना आज़ाद को एक पत्र लिखा। मौलाना आज़ाद कितने पानी में हैं, रोमन लिपि के विषय में उनके क्या विचार हैं और उनका क्या कार्यक्रम है, और सत्य क्या है तथा उसकी किस प्रकार हत्या की जा रही है, वह सब उस पत्र व्यवहार से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है जो वर्तमान लेखक और केन्द्रीय

(२) मौलाना आज़ाद के प्राइ

का लेखक को पत्र, ता०

इस पत्र को सम्पूर्ण रूप में और
क्योंकि संभव है अनुवाद में वांछित

"Dear Sir,

Please refer to your letter of 1947, addressed to the Secretary of this Deptt. regarding the script for Hindustani. I have seen through the proceedings held by the Hon'ble Member there you will find that I have expressed the opinion that it is desirable Indian should learn both Devanagari. But during the War almost all were made literate by the use of the Roman script and that they could acquire Hindustani in about three years. There is a feeling that this would be able to achieve if the Devanagari had been used. Roman has the problem of finding alternative script for the ent provinces and if these

अनुरयुक्त है और भारतीय ध्वनियों को प्रकट करने में असमर्थ है। हम राष्ट्र के ऊपर एक और विदेशी लिपि लादे जाने का तीव्र विरोध करते हैं।.....

हम देवनागरी के साथ साथ उर्दू लिपि के अनिवार्य रूप से ठीक जाने के भी विरुद्ध हैं, क्योंकि वह बिल्कुल अनावश्यक है और समय तथा शक्ति के अपव्यय का कारण है। जब ध्यान कम से कम समय में हिन्दुस्तानी सीखने पर इतना जोर देते हैं, और ठीक ही जोर देते हैं, तब आप किस मुँह से अनिवार्यतः दो लिपियों के सीखने के लिये कहते हैं, जब जरूरत केवल एक ही लिपि की है? मुझे यहाँ संदेह अती बिलगामी सदस्य मुसलमान वद्वानों के मत को दोहराने की जरूरत नहीं जिन्होंने कहा है कि उर्दू लिपि की घुटियाँ स्वयं उर्दू के प्रचार में सबसे बड़ी बाधा हैं। — अस्ल की बात यह है कि उर्दू के लिये देवनागरी स्वीकृत कर ली जाय, न कि यह कि देश पर रोमन लिपि लादी जाय। जो भी हो, यह अच्छा मजक है कि पहले तो खुद एक अनावश्यक और बेकार लिपि, जो दुर्भाग्यवश अत्यन्त दूरूह और कष्ट-साध्य भी है, साथ लगा कर हिन्दुस्तानी का सीखना जानबूझ कर कठिन कर दिया जाय और फिर 'सुलभता', 'सरलता', 'कम समय' आदि की दल लें पेश करके रोमन लिपि की वकालत की जाय !

अपने सेना की 'रोमन उर्दू' को 'रोमन हिन्दुस्तानी' कह कर जनता को भ्रम में डालने का जो प्रयत्न किया है, हम उसका भी कड़ा विरोध करते हैं। राष्ट्र-भाषा के रूप में राष्ट्र जी तथा कांग्रेस जिस हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हैं वह और उर्दू एक ही चीज नहीं है। और यह सदाका एक जमाने से सलूम है कि सेना की भाषा रोमन उर्दू है, और सत्कारी तौर से भी अभी तक इसी नाम का प्रयोग किया गया है। सेना की 'उर्दू' को निकाल कर सच्चा हिन्दुस्तानी को प्रस्ताव करना है और तभी वह 'हिन्दुस्तानी' कहलाने की अवधारणा होगी।

(२) मौलाना आज़ाद के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री टी. यस. कृष्णमूर्ति
का लेखक को पत्र, ता० १-३-४७

इस पत्र को सम्पूर्ण रूप में और मूल अँगरेजी में देना ठीक होगा,
क्योंकि संभव है अनुवाद में वांछित अर्थ और ध्वनि में अन्तर पड़ जाय:—

'Dear Sir,

Please refer to your letter dated the 22nd Feb. 1947, addressed to the Hon'ble Member incharge of this Deptt. regarding the adoption of the Roman script for Hindustani. I believe you have not gone through the proceedings of the Press Conference held by the Hon'ble Member on the 18-2-47, for there you will find that the Hon'ble Member expressed the opinion that it is desirable that every Indian should learn both Devnagri and Urdu scripts. But during the War almost two millions of soldiers were made literate by the Army through the use of the Roman script and their experience showed that they could acquire working knowledge of Hindustani in about three to six months' time. There is a feeling that this would have been impossible to achieve if the Devnagri or the Urdu script had been used. Roman has thus solved the problem of finding alternative scripts for men of different provinces and if these men who have been made

literate during their service in the Army are not to lapse into illiteracy, they must be provided with suitable literature in Roman Hindustani. It will take time for every person to learn both Devnagri and Urdu scripts and till this is achieved, it would be worth considering whether the use of Roman as a supplementary script may not be a temporary expedient. There are millions of Bengalees, Madrasis, Oriyas, Assamese and men speaking other languages who can understand Hindustani and pick it up quickly but for the impediment in their progress because of the script. It is the case of these people that Hon'ble Member had in mind when he referred to the use of the Roman script for Hindustani."

(वाक्य रेखांकित लेखक ने किये हैं)

(३) लेखक का श्री टी. वस. कृष्णनूति को पत्र. ता० २-३-४७

प्रिय महोदय.

आपका १-३-४७ का पत्र मिला। धन्यवाद। अगला पत्र लिखने में पूर्व मैंने १-२-४७ को प्रेस कान्फेरेन्स का विवरण भली भाँति पढ़ लिया था। आपको मेरे पिछले पत्र में उन सब तर्कों का उल्लेख मिलेगा जो माननीय शिक्षा-सदस्य ने रोमन लिपि के पक्ष में उपस्थित किये थे और जिन्हें आपने अपने पत्र में दोहराया है।

सैनिकों के लाभार्थ अस्थायी रूप से रोमन लिपि को प्रयुक्त करने के अतिरिक्त और उससे निकटतम अलग शिक्षा-सदस्य रोमन लिपि को बढ़ावा

देना और उसे स्थायी रूप से हिन्दुस्तानी के लिये अपनाना चाहते हैं, इस विषय में यदि कुछ सन्देह था भी तो वह आपके पत्र के इन वाक्यों से मिट गया है, “—There is a feeling.....provinces.” और “—There are millions of.....use of the Roman script for Hindustani.” इन मंतव्यों का उत्तर देना जरूरी है।

यह भावना कि देवनागरी द्वारा सैनिकों को हिन्दुस्तानी की काम चलाऊ शिक्षा तीन से लेकर छै महीने में देना संभव न होता, आपके विभाग और सेना-विभाग के वेतन-भोगी कर्मचारियों की है, देश की नहीं और न यह सत्य पर आधारित है। रोमनलिपि के मुकाबले देवनागरी की उत्कृष्टता को पश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकारा है। मुझे यह देख कर दुख होता है कि पहली राष्ट्रीय सरकार का शिक्षा-सदस्य जिसे इस शुद्ध, स्वदेशी वस्तु की उत्कृष्टता, जिसे विदेशियों ने भी माना है, पर गर्व होना चाहिये था, रोमन लिपि का गुणगान करता है और उसे देवनागरी से उत्तम बताता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय शिक्षा-सदस्य ने देवनागरी को बिना मौका दिये और उसकी अपेक्षाकृत उत्कृष्टता या निकृष्टता की अमल में वास्तव में जाँच किये बिना ही अपने वेतन-भोगी अप्सरों का मत मान लिया। वे लड़ाई के समय में तीन चार वर्षों में अर्जित सेना-विभाग के ‘experience’ की बात करते हैं, परन्तु यह भूल जाते हैं कि देश में जो गैर-सरकारी संस्थाएँ देवनागरी में हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार कर रही हैं, विशेषरूप से अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन और दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा जिसे गांधीजी ने इसी उद्देश्य से २५ वर्ष पूर्व स्थापित किया था, उनका मत है कि यदि उन्होंने देवनागरी के बजाय किसी दूसरी लिपि से काम लिया होता तो उन्हें इतनी अधिक सफलता कदापि न मिलती। यदि वे इन्हीं दो संस्थाओं की रिपोर्टों के आँकड़ों को देखें, तो उनका मत बदल जाय। इन संस्थाओं के लिये ‘तीन से लेकर छै महीने’ से भी कम

समय में हिन्दुस्तानी को काम चलाऊ दिखा देना संभव हुआ है। जार्ज बर्नार्ड शा ने कहा है कि रोमन लिपि की अपूर्णता और चुरियों के कारण अँगरेजी सीखने में अँगरेज बच्चों का बहुत सा असुल्य समय नष्ट होता है। फिर वह हिन्दुस्तानी जैसी एक भारतीय भाषा के लिये कितनी अपूर्ण, अपर्याप्त और अनुपयुक्त होगी, इसकी सहज में कल्पना की जा सकती है। काश, हम राजनीतिक दासता के साथ साथ सांस्कृतिक और मानसिक दासता से भी छुटकारा पा जाते !

विभिन्न प्रान्तों के लोगों के लिये एक सामन लिपि की समस्या को हल करने का काम एक विदेशी सरकार के शिक्षा-विभाग या लेना-विभाग के लिये नहीं छोड़ रक्खा गया था। इस समस्या को हल हुये हजारों वर्ष हुये—वह तभी हल हो गई जय ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ जिससे देवनागरी निकली है और जिसके विभिन्न रूपों में आज विभिन्न प्रान्तीय भाषायें लिखी जाती हैं। देवनागरी रोमनलिपि से प्रत्येक दास में केवल उत्कृष्ट ही नहीं है, विभिन्न प्रान्तों के लोग उससे या उसके विभिन्न रूपों से पहले से ही परिचित हैं और इस कारण उन्हें देवनागरी सीखने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती। रोमन लिपि पूर्णतया विदेशी है और उसका किसी भारतीय लिपि से कोई नाता, लगाव या सादृश्य नहीं। लाखों बंगाली, मदरासी, उडिया, आसामी आदि जो हिन्दुस्तानी समझ लेते हैं, रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी में लिखित हिन्दुस्तानी कहीं जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। यदि माननीय शिक्षा-सदस्य का मतलब अँगरेजी पढ़े-लिखे लोगों से है, तो वे यह भी कह सकते हैं कि अँगरेजी ने विभिन्न प्रान्तों के लिये एक सामन भाषा की समस्या हल कर दी है। फिर वे हिन्दुस्तानी को ही क्यों नहीं निकाल देते ? अँगरेजी के मुकाबले में हिन्दुस्तानी के पक्ष में जो कोई भी तर्क उपस्थित किया जा सकता है वह रोमन लिपि के मुकाबले में देवनागरी के पक्ष में और भी ज्यादा जोर के साथ उपस्थित किया जा सकता है।

जह
का सम्ब
उपयुक्त
सैनिकों
की, जिन्हें
साहित्य
साहित्य
वह उस
हिन्दुस्तानी
अतिरिक्त
लिपि अ
देवनागरी
में हिन्दु
सैनिकों
शक्ति
देवनागरी
स्तानी व
सीखते
की जिन्हें
दाता अ
प्रस्तुत
नहीं, अ
हिन्दुस्तानी
चाहूँ र
देश पर

मार्थ
रूप से रोमन लिपि के उपयोग
ने देवनागरी जैसी अधिक
हुए विदेशी रोमन लिपि द्वारा
रा के साथ बहुत बड़ी ज्यादाती
में रोमन लिपि में बिल्कुल हिन्दुस्तानी
देवनागरी में डेरों पुराना और नया
लोकप्रिय शिक्षा-सदस्य से आशा थी कि
कि यह कि वह उसे बनाये रखेगा और
के प्रयोग को और बढ़ावा देगा। इसके
तर्क सारहीन हैं। जिन सैनिकों ने रोमन
तीन से लेकर छह महीने में सीख लीं, वे
से सीख सकते हैं। क्या रोमन लिपि
दो महीने से भी कम समय लगेगा ?
हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण में जो
कहीं अधिक सदुपयोग सैनिकों को
था है। स्पष्टतः उन्हें देवनागरी हिन्दु-
ई जायगी। इसलिये देवनागरी सीखते-
जायगी। फिर वह साक्षरता किस काम
खर्चें पर, और वह भी ग्राम कर-
नित्य रोमन लिपि में नया साहित्य
लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य छुपता
है। जहाँ एक ओर रोमन लिपि में
क का रूप धारण कर लेगा, जिसे
जरूरत पड़ेगी और इसलिये जो
यगा, वहाँ दूसरी ओर सैनिकों को

देवनागरी मात्र सिखाने के बाद शिक्षा-विभाग को और ध्यान देने की आवश्यकता न रह जायगी और इसलिये वह देश का स्थायी लाभ होगा। रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य सुलभ होने पर सैनिक किसी दूसरी लिपि सीखने के प्रति उदासीन भी हो जायेंगे और इसलिये रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की संगत शिक्षा-सदस्य की इस इच्छा से नहीं बैठती कि सब हिन्दुस्तानी राष्ट्र में शीघ्र देवनागरी और उर्दू लिपि सीख लें। फिर, सेना के बीच लाख सैनिक अब एक ही छत्र तले नहीं हैं। उनमें से अधिकांश अलग किये जा चुके हैं और उन्होंने अपने नागरिकों को भीति विभिन्न नागरिक देशों अखिलभार कर लिये हैं। स्वाभाविक रूप से अब उनका आकर्षण अपनी अपनी प्रान्तीय भाषा और साहित्य के प्रति है उन्हें अब रोमन लिपि में प्रकाशित सरकारी हिन्दुस्तानी साहित्य की प्रवाह नहीं, जो उन्हें केवल अपने सहनागरिकों से और देश में प्रचलित हिन्दुस्तानी साहित्य से भी दूर रखने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय शिक्षा-सदस्य ने स्वयं कहा है कि लाखों बंगाली, मद्रासी, आसामी, महाराष्ट्री ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी समझते हैं। उनकी साक्षरता जिस तरह भी हो उस तरह कायम रखने का सवाल ही नहीं उठता। केन्द्रीय शिक्षा-विभाग को चाहिए कि वह उन्हें देवनागरी सिखाने के लिये कदम उठाये। शेष सब अपने आप हो जायगा। यह रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की अपेक्षा साक्षरता और हिन्दुस्तानी प्रचार की कहीं बड़ी, स्थायी और अल्पव्यय सापेक्ष सेवा होगी। जब हम भारत की भाषा के लिये एक कास्तर लिपि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, अवश्य ही माननीय शिक्षा-सदस्य का यह इरादा नहीं हो सकता कि कृत्रिम उपध्यों से और जान बूझ कर एक तीसरी लिपि डुमैड कर—और वह भी कठगताओं के लिये पर—समस्या को और जटिल बना दिया जाय और हिन्दुस्तानी जानने वाली जनता तथा हिन्दुस्तानी साहित्य को तीन भागों में बाँट दिया

जाय। किस लिपि को भारत की कामन लिपि का पद प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय, इस विषय में रंच-मात्र सन्देह नहीं हो सकता। वह लिपि देवनागरी है। कारणों को दोहराने की आवश्यकता नहीं।

सब भारतीयों के लिये दोनों लिपि सीखना क्यों बांछित है, इस प्रश्न का भी आपने अपने पत्र में कोई उत्तर नहीं दिया। बांछित तो प्रत्येक भारतीय के लिये भारत की सब लिपियाँ सीखना भी हो सकता है, परन्तु राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दुस्तानी के साथ दो लिपियाँ क्यों लगाई जायँ और हिन्दुस्तानी सीखने की इच्छा करने वाले प्रत्येक भारतीय से दो लिपियाँ सीखने के लिये क्यों कहा जाय, विशेषरूप से तब जब समय के पहलू को इतना महत्व प्रदान किया जा रहा है और ठीक ही किया जा रहा है? इसके अतिरिक्त उर्दू लिपि जैसी लिपि के व्यवहार को बढ़ावा देना अन्य कारणों से भी अबांछित है। अदालतों की लिपि के प्रकरण में मानियर विलियम्स जैसे विद्वानों ने उर्दू लिपि के विषय में जो सम्मतियाँ दी हैं, उन्हें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं।

आपने अपने पत्र में मेरे इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया कि माननीय शिक्षा-सदस्य ने सेना की उर्दू को 'हिन्दुस्तानी' नाम से क्यों पुकारा। जैसा मैं अपने पिछले पत्र में कह चुका हूँ, सेना की उर्दू के लिये इस नाम का प्रयोग भ्रामक और धोखे में डालने वाला है और इसलिये तुरन्त बन्द हो जाना चाहिए।

अन्त में, शिक्षा-सदस्य की रोमन लिपि की बकालत से देश में जो तीव्र क्षोभ उत्पन्न हुआ है उसे और राष्ट्रीयता, संस्कृति तथा उपयोगिता के दृष्टिकोण से इस मामले की महत्ता को देखते हुए मैं जोर दूँगा कि देश पर स्थाई रूप से अथवा अस्थायी रूप से रोमन लिपि लादने की दिशा में कोई कदम उठाने से पूर्व देश के विद्वानों तथा नेताओं की सम्मति एवं अनुमति ली जाय।”

इस पत्र का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया और न अब आने की आशा है। मौलाना आज़ाद के प्राइवेट सेक्रेटरी के पत्र (पत्र संख्या २) की एक नकल वर्तमान लेखक ने गांधीजी के पास भेजी थी। उनके पास से भी कोई उत्तर नहीं आया। आने भी क्यों लगा? अकेली देवनागरी न सुझाने के कारण राष्ट्र-लिपि के मामले पर गांधी जी सम्मेलन से त्याग-पत्र दे सकते हैं, और टंडन जी से खुद ठान सकते हैं, पर एक तीसरी विदेशी लिपि के मामले पर मौलाना आज़ाद या डा. अब्दुल हक से खुद नहीं ठान सकते। राष्ट्र-लिपि के बने बनावे घर में, जिसे बनाने में स्वयं उनका हाथ कम नहीं था, 'दोनों लिपि' की फूट डालकर ये अब तटस्थ हो गये हैं, और दूर से बंदरगाँव का तमाशा देखने में संतुष्ट हैं।

२

यह सर्व-विदित है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अँगरेजी माध्यम को बदल कर 'हिन्दुस्तानी' की शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला किया है। अन्य विश्वविद्यालय भी 'हिन्दुस्तानी' को कर रहे हैं। पता नहीं यह 'हिन्दुस्तानी' क्या है, परन्तु हमारे माननीय नेताओं को इसका मोह कुछ ऐसा लगा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में परिचित और अर्थ-युक्त शब्दों 'हिन्दी' और 'उर्दू' के बजाय 'हिन्दुस्तानी' बनाने में स्वयं टंडन जी का बड़ा हाथ था। इससे जो होता था सो हो रहा है। अर्थात् एक ओर हिन्दी के एक अन्य प्रबल समर्थक श्री नृपूणानन्दजी 'हिन्दुस्तानी' की पारिभाषिक शब्दावली गढ़ने के लिये विश्वविद्यालयों के बह्मन्नासलरों की एक कन्फ्रेंस का आयोजन करके 'हिन्दुस्तानी' के विछले इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और दूसरी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय के कोर्ट में शीघ्र ही यह प्रस्ताव पेश होने वाला है कि सब अध्यापकों के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों का पूर्ण पण्डित होना अनिवार्य होगा, और स्वाभाविकतः बाद की इस अभागे हिन्दू प्रांत में जो हिन्दुओं का होते हुये भी हिन्दुओं के

हाथ में नहीं है और हिन्दी का होते हुये भी हिन्दी का नहीं किमी 'हिन्दुस्तानी' का है, १४% मुसलमान छात्रों के कारण सब छात्रों के लिये भी यही शर्त लागू की जायगी। 'हिन्दुस्तानी' के भक्त 'हिन्दुस्तानी' माध्यम को किस प्रकार सिद्ध करने का इरादा रखते हैं, इसे छोड़ कर अब जरा वर्तमान पर दृष्टिपात कीजिये। मालूम हुआ है कि लन्दनल विश्वविद्यालय में बहुत से दर्जों में 'हिन्दुस्तानी' में पढ़ाई आरंभ हो गई है और उसका स्वरूप यह है—“साइंस ने अब तक जो प्रोग्रेस की है—”; “अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक परपेन्डीकुलर ड्राप किया जाय और सिकसटी डिग्रीज का एंगिल बनाती हुई एक दूसरी लाइन खींची जाय—”; “अगर एक मेटल के दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर दो टुकड़े मिलाये जायें तो एक वेल्डेज क्रियेट हो जाता है और इलेक्ट्रीसिटी की एक करेन्ट फ्लो होने लगती है—”; “हिन्दुस्तान की हिस्ट्री की जो किताबें इंडियन लैंग्वेज में मिलती हैं या जो ट्रांसलेशन हुये हैं—”, आदि, आदि। * अस्तु, हिन्दी की क्रियाओं के साथ किसी भी भाषा के शब्दों को प्रयुक्त करके 'हिन्दुस्तानी' का ढिंढोरा पीटना तो संभव था, परन्तु लिपि के मामले में क्या किया जाता अर्थात्

* एंग्लो-‘हिन्दुस्तानी’ स्कूलों में भी जहाँ ‘हिन्दुस्तानी’ को माध्यम ठूबे काफी समय हो चुका है और जहाँ हिन्दी लेने वाले और उर्दू लेने वाले विद्यार्थियों को एक साथ एक ही दर्जे में ‘हिन्दुस्तानी’ के माध्यम से गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, आदि विषय पढ़ाये जाते हैं, यही हाल है। यह ‘इङ्गलिस्तानी’ का जयजयकार है ! अध्यापकों को दोष देना बेकार है। ‘हिन्दुस्तानी’ की दारोमी नाया में पढ़कर बेवारे क्या करें ? ‘हिन्दुस्तानी’ कोई मंत्र तो है नहीं जिसे पढ़ने से हिन्दी और उर्दू का अंतर छू-मंतर हो जायगा, परन्तु हिन्दुस्तानी वाले इस अंतर को मानने को और उसे मान कर उचित व्यवस्था करने को तैयार नहीं। उनकी जिद का जो परिणाम हो सकता है वही हो रहा है। रेडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ में भी ‘इङ्गलिस्तानी’ की चाहनी कम नहीं।

दर्जे में किस लिपि में पढ़ाया जाता ? इस भीषण कठिनाई का अनुभव 'हिन्दुस्तानी' वाली राष्ट्रीयता के ठेकेदारों ने भी किया, अतः लखनऊ विश्वविद्यालय के उसी प्रस्ताव में जिस में 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम बनाना स्वीकार किया गया है, 'हिन्दुस्तानी' के लिये तीन लिपियाँ स्वीकार की गई हैं—देवनागरी, फारसी लिपि और रोमन। और नाल्लू नुआ है कि इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में जितनी पढ़ाई 'हिन्दुस्तानी' में हो रही है, और जितना अन्य काम (जैसे विश्वविद्यालय के नोटिस, आज्ञा-पत्र, आदि) 'हिन्दुस्तानी' में हो रहा है, उस सब में अक्षरों और केवल रोमन लिपि का प्रयोग हो रहा है। ऐसा होना अनिवार्य है। 'दानो किमि' बंद हो रहे हैं। इस विषय को देखते ही कहा जाता है कि हमें पहले सन्तुष्टि की आवश्यकता है। जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहा है वही 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम प्रदान करके नाम लूटने वाले अन्य विश्वविद्यालयों में होगा। 'हिन्दुस्तानी' की वही 'हिन्दुस्तानी' पैदा होनी !

पाठकों का ध्यान एक और तीसरी बात की ओर भी खींचना उचित जान पड़ता है। कुछ दिन पूर्व (अप्रैल, १९४३), पत्रों में आया था कि विधान परिषद की अल्पसंख्यक-परामर्श समिति (Advisory Committee for Minorities) ने कच्ची तौर पर यह तय किया है कि भारत की राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' हो जो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी जाय, तथा इस पर यह सुझाव पेश किया गया है कि 'हिन्दुस्तानी' की लिपि रोमन हो क्योंकि 'इससे अभारतीयों को भारतीय मामले समझने में आसानी होगी', और समिति ने अभी तक इस सुझाव पर अपना निर्णय नहीं दिया है। अनुमान करना कठिन नहीं कि इस सुझाव को पेश करने वाले कौन हैं। उनकी राय में भारतीयों की अपेक्षा अभारतीयों को भारतीय मामले समझाना ज्यादा जरूरी है, और चूँकि करोड़ों भारतीयों को एक नई विदेशी लिपि सीखना पड़े परन्तु थोड़े से विदेशियों को एक भारतीय

लिपि न सीखना पड़े। और किसी दूसरी बात का कोई महत्व है ही नहीं। जो भी हो, लक्षणों से यही जान पड़ता है कि अपने 'दोनों लिपि'-वाद के कारण समिति को या तो यह सुभाव मान लेना पड़ेगा, या रोमन लिपि को भी 'हिन्दुस्तानी' के लिये स्वीकृत करना पड़ेगा जिसका भी वही परिणाम होगा। यह सब क्यों न हो ! जिस दिन इस राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता चूका और उसने 'दोनों लिपि' की ज़िद पकड़ी, इस देश की राष्ट्रीयता में घुन तो उसी दिन से लग गया। मौलाना आज़ाद ने अपना वर्तमान पद संभालने के बाद प्रान्तीय सरकारों को आदेश भेजे कि वे 'दोनों लिपियों' का अधिकाधिक प्रचार करें। उन्हें मालूम था कि कौन सी प्रान्तीय सरकारें इन आदेशों का पालन करेंगी और कौन सी नहीं, अतः उर्दू लिपि के प्रचार के लिये इसमें बढ़कर दूसरी ओट नहीं मिल सकती थी। परन्तु उन्हें भय है कि देवनागरी अपने गुणों के कारण कहीं फिर भी उर्दू लिपि पर हावी न हो जाय। उन्हें यह भी मालूम है कि पाकिस्तान 'दोनों लिपि' की बीमारी से आक्रान्त नहीं, और वहां रोमन लिपि का कोई सवाल हो नहीं—उर्दू लिपि वहाँ पूर्णतया सुलित है, अतः उधर से निश्चिन्त हो 'हिन्दुस्थान', और 'हिन्दुस्थान' के मुसलमानों को हिन्दुई देवनागरी के प्रकोप से बचाने के लिये और अपने दिल के डर को जड़ से निकाल डालने के लिये उन्होंने रोमन लिपि को शरण गही, और उसे हिन्दुस्थान का गद्दो पर बैठाने के लिये अपने पद और अपनी कांग्रेसी प्रतिष्ठा का उपयोग कर रहे हैं। परन्तु मूर्ख हिन्दू कांग्रेस की 'दोनों लिपि' वाली बाढ़ियातगी और उसकी ओट से मुसलमानों द्वारा खेले जाने वाले शिकार को कब तक 'राष्ट्रीयता' के चश्मे से देखते रहेंगे ? जब लेखक यह सोचने लगता है तो उसकी व्यथा का अन्त नहीं रहता।

उत्तर-परिशिष्ट २

‘राष्ट्रीय’ सरकार की रेडियो की भाषा विषयक नीति

(लेखक—राजशंकर शुक्ल)

१

हिन्दी वालों को डालने के लिये सर अकबर हैदरी ने एक हिन्दी-उर्दू परामर्श समिति बना दी थी जो प्रति दो महीने वाद एक बैठक करके कुछ करने का नाट्य करती थी। इस समिति में एक सम्मेलन का प्रतिनिधि था, एक अंगुमन-तरक्की-उर्दू का और एक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा का, और अध्यक्ष तथा संयोजक ये श्री दोस्त्रानी। पहला प्रश्न तो वही उठता है कि हिन्दी और उर्दू का ‘हिन्दुस्तानी’ ने क्या वाला था, और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा देश में भाषा और साहित्य के जगत में किसका प्रतिनिधित्व करती थी या करती है ? ‘हिन्दुस्तानी’ में अखबार नहीं निकलते, पुस्तकें नहीं छपती, कहीं पढ़ाई नहीं होती, ‘हिन्दुस्तानी’ के लेखक नहीं, साहित्य नहीं, फिर यह हिन्दुस्तानी प्रचार सभा जिसे स्थापित हुये केवल एक वर्ष हुआ है किसकी ओर से सोचने का दावा कर सकती है ? अस्तु, सर अकबर हैदरी का उद्देश्य यह था कि ‘हिन्दुस्तानी’ का बखेड़ा खड़ा करके मामले को उलझा दिया जाय और ‘हिन्दुस्तानी’ का आड़ में पूर्ववत् उर्दू का दोलबाला रहे, इसलिये उन्होंने इस बेजड़ और नवीन संस्था हि० प्र० सभा का प्रतिनिधित्व लेना आवश्यक समझा। हुआ भी वही जिसे सोचकर यह किया गया था, अर्थात् यह समिति मामला न हल हो सकी और तीनों सदस्यों ने ‘हिन्दुस्तानी’ के शब्दों की तीन भिन्न सूचियाँ पेश कर दीं। यदि सर अकबर हैदरी की सरकार

होती तो वह उर्दू वाले की सूची पर 'हिन्दुस्तानी' की मोहर लगाकर रेडियो की प्रचलित 'हिन्दुस्तानी' को चालू रखती। पर भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से उस सरकार के स्थान में एक 'राष्ट्रीय' सरकार आ चुकी थी जिसमें रेडियो के सदस्य थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ठहरे कांग्रेस के एक बड़े नेता, गांधी जी के अनन्य अनुयायी और इसलिये कांग्रेस की 'हिन्दुस्तानी' तथा हिन्दुस्तानी-वाद के एक भक्त। उनकी पीठ पर स्वयं हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के सभापति डा० राजेन्द्रप्रसाद थे, अतः उनके लिये 'हिन्दुस्तानी' की हिमायत करना और रेडियो को 'हिन्दुस्तानी'-प्रचार का साधन बना कर गांधीजी का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। उन्होंने हिन्दी-उर्दू परामर्श समिति की सिफारिशों पर वही निर्णय दिये जिनकी उनसे आशा थी। इन निर्णयों की घोषणा फरवरी, १९४७ में हुई और वही घोषणा 'राष्ट्रीय' सरकार की रेडियो की भाषा विषयक नीति का आधार है। संक्षेप में, इस नीति के आरंभ में 'हिन्दुस्तानी' है, मध्य में 'हिन्दुस्तानी' है, और अन्त में 'हिन्दुस्तानी' है। कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार और उसके अधीनस्थ हिन्दुस्तानी सरकारों ने हिन्दी का भाग छीन कर उर्दू को दिया था और उसका नाम 'हिन्दुस्तानी' रखवा था, इस 'राष्ट्रीय' सरकार ने हिन्दी का स्थान अपनी 'हिन्दुस्तानी' को दिया है जो आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में ज़रा छनी हुई उर्दू है। घोषणा की 'हिन्दुस्तानी' विषयक मुख्य बातों पर ध्यान दीजिये : (१) समाचार केवल 'हिन्दुस्तानी' में होंगे, हिन्दी में नहीं (२) स्त्रियों और बच्चों के प्रोग्राम तथा इसी प्रकार के जो अन्य प्रोग्राम हिन्दी में होंगे उनका एक 'बड़ा भाग' 'हिन्दुस्तानी' में होगा, (३) हिन्दी-प्रदेश के सब स्टेशनों से उर्दू के अतिरिक्त एक निश्चित अनुपात में 'हिन्दुस्तानी' के प्रोग्राम होंगे—पेशावर से ५ प्रतिशत, लाहौर से ७½ प्रतिशत, दिल्ली से २० प्रतिशत और लखनऊ से १० प्रतिशत।

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ‘हिन्दुस्तानी’ के नाम पर सब भारतीय भाषाओं में से केवल हिन्दी के साथ अन्याय किया जायगा। सब भारतीय भाषाओं में खबरें होंगी, वहाँ तक पंजाबी और पश्तो में भी खबरें होंगी, परन्तु हिन्दी में खबरें नहीं होंगी। नव प्रान्तीय भाषाओं में निबन्धों, यानकों, आदि के प्रोग्राम अन्वय रूप से होंगे, परन्तु हिन्दी के प्रोग्रामों का ‘बड़ा भाग’ ‘हिन्दुस्तानी’ में होगा। इस घोषणा का सबसे भयंकर भाग वह है जिसमें ‘हिन्दुस्तानी’ के समर्थन में तर्क दिये गये हैं। प्रत्येक हिन्दी प्रेमी दिल पर हाथ रखकर सोचे कि इन तर्कों का क्या मतलब है और वे तर्क हिन्दी के कौन अधिकारी की ओर संकेत करते हैं। मुख्य तर्कों पर ध्यान दीजिये :

(१) ‘हिन्दुस्तानी’ उत्तरी भारत में आम और में बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है जो देवनागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती है। (उर्दू लिपि फिर ‘उर्दू लिपि’ क्यों कहलाई !) अपने दिल के चोर को न छिपा सकने के कारण घोषणा के अन्त में सरकार कहती है, “हिन्दुस्तानी की यह परिभाषा दोनों रेडियो-कमेटियों ने की है।”

(२) सरकार अनुभव करती है कि बहुत से सुनने वाले यह नहीं चाहते कि ऐसी (‘यह’ नहीं !) भाषा हिन्दीवालों और उर्दूवालों के विवाद में मिस जाय।

(३) अतः सरकार चाहती है कि आम जनता और आम सुनने वालों के लिये, साहित्यिक हिन्दी और साहित्यिक उर्दू के अतिरिक्त और उनसे अलग, ‘सरल हिन्दुस्तानी’ में प्रोग्राम हों, तथा साहित्यिक रुचि वालों के लिये हिन्दी और उर्दू में प्रोग्राम हों।

(४) सरकार को आशा है कि उसके निर्णय आम जनता को पसंद आवेंगे, यद्यपि संभव है उनसे उन दो दलों को पूर्ण संतोष न हो जिनके बीच में विवाद है।

इन तर्कों का स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार की दृष्टि में हिन्दी उत्तरी

भारत में बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा नहीं है, हिन्दी केवल कविता और साहित्य की भाषा है और केवल साहित्यिक रुचि वालों के काम की है। आम जनता और आम सुनने वालों के मतलब की भाषा 'हिन्दुस्तानी' है।

इन पंक्तियों का लेखक नहीं कह सकता कि हिन्दी वालों ने इन सरकारी तर्कों का पूरा अर्थ समझा है या नहीं, क्योंकि इनका खंडन करने वाले लेख उसके देखने में नहीं आये। लेखक इतना अवश्य कह सकता है कि 'राष्ट्रीय' सरकार ने हिन्दी की अर्थों तैयार कर ली है, बस केवल उसे फूँकने की देर है। और हिन्दी के रिक्त सिंहासन पर 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित करने का पूर्ण आयोजन हो चुका है।

हिन्दां वाले शायद यह सोचते होंगे कि और कुछ न सही, लखनऊ से ७० प्रतिशत प्रोग्राम तो हिन्दी में होंगे ! जिन तर्कों के बल पर आज सरकार अलग हिन्दी में समाचार देने को तैयार नहीं, हिन्दी में स्त्रियों, बच्चों, आदि के प्रोग्राम देने को तैयार नहीं और आज लखनऊ से १० प्रतिशत प्रोग्राम 'हिन्दुस्तानी' में दे रही है, उन्हीं तर्कों के बल पर यदि सरकार कल यह कहे कि रेडियो आम जनता के लिये है, मुट्ठी भर 'साहित्यिक रुचि' वालों के लिये नहीं और इसलिये १० प्रतिशत से अधिक प्रोग्राम हिन्दी में नहीं हो सकते, तो उस समय हिन्दी वाले क्या उत्तर देंगे ? सब की समझ में आने वाली 'सरल हिन्दुस्तानी' जब है ही, तो कोई भी प्रोग्राम कुछ की समझ में आने वाली हिन्दी में क्यों किया जाय ? होगा इसका कोई उत्तर हिन्दी वालों के पास ? भाला गड़ने से पहले सदैव भाले की नोक गड़ती है। शत्रु को दुर्बल समझनेवाला सदैव अन्त में मारा गया। जिसने भी झूठी उदारता या प्रमाद में आकर शत्रु को कंधे पर हाथ रखने दिया, उसने धोखा खाया।

२

हिन्दुस्तानीवाले हिन्दी को सामने से न घेर कर 'फ्लैक मूवमेन्ट' द्वारा

नारना चाहते हैं। उनकी चाल यह है कि हिन्दी को कविता की भाषा घोषित करके एक किनारे कर दिया जाय और सारा काम-काज ‘हिन्दुस्तानी’ में किया जाय। आगे चल कर हिन्दी अपने आप कविता की भाषा भी नहीं रहेगी। कांग्रेसी सरकारें इसी चाल को चल रही हैं। वे हिन्दी को एक प्रांतीय भाषा के अधिकार से भी वंचित कर रही हैं। आज केन्द्र की ‘राष्ट्रीय’ सरकार हिन्दी में समाचार, आदि देने को तैयार नहीं। कल कहा जायगा कि युक्त-प्रान्त, बिहार, मध्य-प्रान्त, आदि में सारा राज-काज, शिक्षा-कार्य, आदि सबकी समझ में आने वाली ‘हिन्दुस्तानी’ में होगा, साहित्यिकों और कवियों के बिलास की भाषा हिन्दी में नहीं। सरदार पटेल की रेडियो की भाषा-विषयक घोषणा हिन्दी के अस्तित्व पर बुरा कुठाराघात है। हिन्दी पर कांग्रेसी सरकारों और कांग्रेसी नेताओं की ओर से आये हुये और आने वाले इस महान् संकट का मुकाबला करने के लिये हिन्दी वालों को तैयार हो जाना चाहिये। जहाँ तक सरदार पटेल की रेडियो की भाषा-विषयक नीति का संबंध है, हमें भी ‘हिन्दुस्तानी’ का सामने से विरोध करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु हिन्दी की रक्षा के लिये युद्ध छानना ही पड़ेगा। सरकार को रेडियो में हिन्दी को एक प्रादेशिक भाषा के नाते स्वतंत्र स्थान देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार अन्य प्रांतीय साहित्यिक भाषाओं में समाचार, स्त्रियों, वृत्तों, आदि के प्रोग्राम होते हैं उसी प्रकार हिन्दी में समाचार, स्त्रियों, वालकों, आदि के अवाध प्रोग्राम होना परम आवश्यक है। रही ‘हिन्दुस्तानी’ की बात, तो हम किसी ऐसी ‘हिन्दुस्तानी’ से परिचित नहीं जिससे रेडियो का काम चल सके। मजे की बात यह है कि एक ओर सरकार ‘हिन्दुस्तानी’ के गुण गाती है, उसे ऐसी और वैसी भाषा बताती है, परन्तु दूसरी ओर उसकी शब्दावली बनाने के लिए कमेटी बैठती है और उसके शब्द निरन्तर गढ़ते और बनाने के लिए एक स्थायी परामर्श समिति बनाने का इरादा प्रकट करती है। यदि ‘हिन्दुस्तानी’ कोई प्रचलित

सम्मेलन का प्रतिनिधि लिया गया था, के सामने ‘हिन्दुस्तानी’ का राय देना का सवाल ही नहीं था। उसे तो केवल ‘हिन्दुस्तानी’ का शब्दावली गढ़ने का आदेश दिया गया था, और वह वह कार्य न कर सकी। उसने अंग्रेज सरकार की उर्दू के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि ‘हिन्दुस्तानी’ का किसी खम्बे किया जाय और हिन्दी और उर्दू में अलग अलग समाचार हों, तथा सम्मेलन के प्रतिनिधि ने इसका अनुमोदन किया। सरकार ने इन बातों को क्यों लिखा लिया? दो सदस्यों की एक राय होते हुये अकेले सदस्य अर्थात् हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रतिनिधि की बात सरकार ने क्यों मानी? ऊपर से तुरा यह है कि सरकार ने हिन्दी और उर्दू के समर्थकों को विवादास्पद उहराया है और आप निष्पक्ष मध्यस्थ बनने का दावा किया है। भगड़ा केवल दो दलों—हिन्दी वालों और उर्दू वालों—के बीच में नहीं है। भगड़े में हिन्दुस्तानी वालों की पार्टी भी उतनी ही शामिल है। परन्तु सरकार ने इस तीसरे भगड़ालू दल का नाम नहीं लिया। उल्टे वह इसके साथ एकाकार हो गई है। वह निष्पक्ष जज नहीं रही बरन् इस तीसरी पार्टी का बर्कीज बन गई है। सरकार के ‘हिन्दुस्तानी’ के साथ घोर पक्षपात का एक और सबूत है। सरकार घोषणा में स्वयं कहती है कि पत्र-पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आधार पर प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी और उर्दू प्रोग्रामों का अनुपात निर्धारित किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वे ‘हिन्दुस्तानी’ की पत्र-पत्रिकाएँ कौन सी हैं जिनके सर्कुलेशन के आधार पर सरकार ने सब स्टेशनों में ‘हिन्दुस्तानी’ को पृथक् प्रतिनिधित्व दिया है, यहां तक कि दिल्ली में २० प्रतिशत दिया है? हम तो ‘हिन्दुस्तानी’ की एक भी पत्रिका का नाम नहीं जानते*। फिर, दूसरी रेडियो कमेटी ने यह कहीं नहीं कहा।

* केवल नाम रखने से भाषा ‘हिन्दुस्तानी’ नहीं हो जाती। गांधी जी के ‘हरिजनसेवक’ या पं० सुन्दरलाल की ‘विश्ववाणी’ या डा० ताराचन्द्र के ‘नया हिन्द’ की भाषा हिन्दुस्तानी की किसी भी परिभाषा पर खरी नहीं उतरती। वह है ख़राब उर्दू, रेडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ से भी बदतर।

है कि हिन्दुस्तानी नाम की ऐसी कोई भाषा है जिसमें समाचार हो सकते हैं, रेडियो का काम चल सकता है या कोई अन्य गम्भीर कार्य हो सकता है। इस कमेटी ने केवल इतना ही कहा है कि हिन्दुस्तानी एक बोली है जो उत्तरी भारत में बोली और समझी जाती है। इसका दूसरा नाम 'खड़ी बोली' है। इसी बोली के आधार पर हिन्दी और उर्दू खड़ी हैं और यह दोनों में निहित है। इस बोली से रेडियो का काम नहीं चल सकता। रेडियो का काम हिन्दी और उर्दू से चल सकता है। हिन्दी और उर्दू में ही उत्तरी भारत में सब काम होता है, पत्र, आदि निकलते हैं, और 'कामन मैन' इन्हें ही पढ़ता है और ये ही पढ़ाई जाती हैं। सरकार यह आदेश अवश्य दे सकती है कि रेडियो में सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उर्दू का प्रयोग हो, परन्तु सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उर्दू एक ही चीज नहीं। सरकारी घोषणा पर रोष प्रकट करने के लिये जब केन्द्रीय असेम्बली में नवाब सिद्दीकअली ख़ाँ ने कटौती का प्रस्ताव रक्खा तब वहस का जवाब देते हुये सरदार पटेल ने बड़े तपाक से कहा कि अच्छा हो यदि साहित्यिक हिन्दी और उर्दू के हिमायती जनता के लाभार्थ निर्मित रेडियो को अपने विवाद में न घसीटें, और "मुझे 'literary flourishes of Urdu or of Sanskrit' से कोई वास्ता नहीं," और इस पर कांग्रेसी सदस्यों ने बड़े जोर से तालियाँ भी पीट दीं मानो जनता की बड़ी भारी विजय हो गई हो और आल इन्डिया रेडियो, जो वर्षों से 'जनता की भाषा' की विजय को प्रत्यक्ष कर ही रहा था, सदा के लिये भारत की राजधानी में इस विजय का साक्षात् प्रतीक बन कर गड़ गया हो। परन्तु सच यह है कि बड़ा अच्छा हो यदि राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिये भाषा और साहित्य के मामले में दखल न दें, और भाषा के साथ मनमानी न करें। यह 'literary flourishes of Urdu or of Sanskrit' का नहीं, भाव और अर्थ को प्रकट करने के लिये आवश्यक कम से कम शब्दों

का सवाल है। सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उर्दू में जड़ भेद फिर भी रहेगा जो राजनीति, साहित्य, प्रतिनिधि, दशमलव, भाषण, सम्वाद-दाता, मन्त्रि-मंडल, प्रदर्शन, भविष्य, केन्द्र, सभासति, सम्मेलन, प्रज्ञान-विद्यार्थी, आदि, आदि और स्वासत, अदय, तुमायन्दा, आशाया, तर्करी, नामानिगार, वज्रागत, सुजाहिग, सुरतकविल, सरकज, सदर, सहजाय, जम्हूरियत, तालिय हल्म आदि, आदि में है। इनमें अधिक सरल और ‘literary flourishes of Urdu or of Sanskrit’ में रहित शब्द कहाँ से आये, अथवा, जब ये दोनों प्रकार के शब्द उत्तरी भारत में प्रचलित हैं, इन्हें छोड़कर इनके पर्यायवाची नये शब्द क्यों गढ़े जायें (यदि गढ़ना संभव भी हो तो) और वे कैसे ‘सबकी समझ में आनेवाले’ या ‘उत्तरी भारत में आमतौर से बोले और समझे जानेवाले’ हो जायेंगे, अथवा कुछ शब्द हिन्दी के और कुछ शब्द उर्दू के कैसे और क्यों छूटे जायें और क्या वह मिश्रण ‘सबकी समझ में आने वाला’ या ‘ब्यादा लोगों की समझ में आनेवाला’ या ‘उत्तरी भारत में आम तौर से बोला और समझा जानेवाला’ होगा ? स्पष्ट है, सरकार को उत्तरी भारत की जनता तक पहुँचने के लिये हिन्दी और उर्दू—अवश्य ही सरलतम हिन्दी और सरलतम उर्दू—दो भाषाओं या ‘शैलियों’—का उसी प्रकार आश्रय लेना पड़ेगा जिस प्रकार अहिन्दी प्रांतों में प्रचलित भाषाओं का। सरकार को एक तीसरी भाषा या शैली, देश में प्रचलित भाषाओं या शैलियों से निराली भाषा या शैली, गढ़ने का कोई अधिकार नहीं। यह केवल प्रचलित भाषाओं या शैलियों का उपयोग कर सकती है। यदि वह एक नई भाषा या शैली गढ़ना ही चाहती है तो प्रथम वह अपने समर्थन में ‘कामन मेन’ का नाम न ले—‘कामन मेन’ के लिये हिन्दी और उर्दू जमाने से बन् चुकी हैं और ‘कामन मेन’ उन्हीं को गढ़ता है। दूसरे, सरकार हिन्दी का हक खीन कर ‘हिन्दुस्तानी’ को नहीं दे सकती। यह तो एक विचित्र बात है कि जिस हिन्दी में सैकड़ों अस्वर निकलते हैं जिन्हें लाखों व्यक्ति पढ़ते हैं, उसमें समाचा

ब्राडकास्ट न हों, परन्तु एक नई 'हिन्दुस्तानी' में हों जिसमें कोई अखबार नहीं निकलता और जो केवल सरकार के दिमाग में है। सरकार अपनी 'हिन्दुस्तानी' के समर्थन में बहुत से 'कामन मैनों' और 'कामन लिसनरों' की दुहाई देती है, परन्तु उन लिसनरों, आदि को क्यों भूल जाती है जो वपों से हिन्दी में पृथक समाचारों की माँग कर रहे हैं? उन पर सरदार पटेल, जो 'कांग्रेस किसी को मजबूर नहीं कर सकती' इस सिद्धान्त को मानकर देश के विभाजन के लिये भी तैयार हैं, अपनी 'हिन्दुस्तानी' क्यों लादना चाहते हैं? जब सरकार हिन्दी के पृथक अस्तित्व और व्यापकता से इन्कार नहीं करती—सबूल यह है कि उसने स्वयं हिन्दी को सब स्टेशनों में पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, और लखनऊ में ७० प्रतिशत तक दिया है—तो वह उन्हीं कारणों से और उन्हीं के लिये जिनके लिये विभिन्न स्टेशनों से ये सब हिन्दी के प्रोग्राम होंगे, हिन्दी में पृथक समाचार क्यों नहीं देगी? जिन हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आधार पर सरकार ने प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी का अनुपात निर्धारित किया है, उन्हीं के आधार पर हिन्दी में पृथक समाचार भी होने चाहिये। एक मामूली रेडियो रखनेवाला एक मामूली अखबार पढ़नेवाले से कम अपढ़ नहीं होता, और न हिन्दी के अखबारों में केवल साहित्यिक चर्चा होती है और न उन्हें केवल 'साहित्यिक रुचि' वाले पढ़ते हैं। हिन्दी केवल साहित्य और साहित्यिक रुचि वालों के काम नहीं आ रही है। हिन्दी में सब काम हो रहा है और सरकार की दिमागी 'हिन्दुस्तानी' के सुकावले कहीं अधिक काम हो रहा है। हिन्दी का हिन्दी प्रदेश में बोली जानेवाली साधारण बोली या हिन्दुस्तानी से वही संबंध है जो साहित्यिक बँगला का बंगाल में बोली जानेवाली साधारण बोली से, या साहित्यिक गुजराती का गुजरात में बोली जानेवाली गुजराती से, आदि, आदि। केवल हिन्दी के पीछे 'साहित्यिक' विशेषण लगाकर सरकार उसे क्यों बदनाम करना चाहती है? आज सरकार कहती है कि 'कामन मैनों'

हिन्दी नहीं चाहता, हिन्दी नहीं समझता, ‘हिन्दुस्तानी’ चाहता और समझता है, कल सरकार कहेंगी कि हिन्दी प्रदेश का ‘कामन मैन’ तुलसी और तुर को नहीं समझता, रामचरित-मानस पढ़ता नहीं चाहता बल्कि उसका ‘हिन्दुस्तानी’ में सरकारी अनुवाद पढ़ना चाहता है ! जिस प्रकार सरकार ने हिन्दी के प्रोपामों को ‘साहित्यिक रसि’ वालों के निमित्त बनाकर हिन्दी को एक किनारे कर दिया है उसका तो वही अर्थ निकलना है कि सरकार को राय में जो भी व्यक्ति हिन्दी पढ़ता है वह ‘साहित्यिक रसि’ वाला है और सिवा ‘साहित्यिक रसिवालों’ के कोई और हिन्दी नहीं समझता ! जो भी हो, जब सरकार ने स्वयं हिन्दी, उर्दू और ‘हिन्दुस्तानी’ का पृथक पृथक अस्तित्व स्वीकार किया है और तीनों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, तो सरकार तीनों में पृथक समाचार भी क्यों नहीं देगी ? जब सरकार बंगला जाननेवालों के लिये (साहित्यिक) बंगला में, गुजराती जाननेवालों के लिये (साहित्यिक) गुजराती में वहाँ तक कि अँगरेजी जाननेवालों के लिये (साहित्यिक) अँगरेजी में खबरें देगी और दे रही है, तो हिन्दी जाननेवालों के लिये हिन्दी में खबरें क्यों नहीं देगी ? हिन्दी के साथ ही विशेष व्यवहार क्यों ? क्या हिन्दी समझनेवालों की संख्या अँगरेजी समझनेवालों की संख्या में भी कम है ? क्या ‘कामन मैन’ और ‘कामन लिसनर’ उस अँगरेजी को समझता है जिसमें खबरें होती हैं, परन्तु हिन्दी नहीं समझता ? यदि सरदार पटेल को ‘कामन मैन’ का इतना चिन्ता है तो वे अँगरेजी की खबरें और अँगरेजी के प्रोग्राम क्यों नहीं बन्द करते ? लखनऊ से, उदाहरण के लिये, अँगरेजी में भी खबरें होती हैं । क्या सरकार कोई कारण बता सकती है कि इन अँगरेजी की खबरों के स्थान में हिन्दी की खबरें प्रायःकाय करने से ‘कामन मैन’ का अधिक लाभ क्यों न होगा ? स्पष्ट है, सरकार हिन्दी के साथ भारत की अन्य भाषाओं के साथ किये गये व्यवहार से भिन्न व्यवहार नहीं कर सकती । जिस प्रकार सरकार बंगालियों, गुजरातियों, आदि

से यह नहीं कह सकती कि तुम्हें अपनी चिर-परिचित बँगला और गुजराती के स्थान में किसी सरकारी और नई बँगला और गुजराती में खबरें सुननी पड़ेंगी और तुम्हारी स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों का 'बड़ा भाग' किसी सरकारी और नई बँगला और गुजराती में होगा, उसी प्रकार सरकार हिन्दीयों से यह नहीं कह सकती कि तुम्हें अपनी चिर-परिचित हिन्दी के स्थान में सरकारी 'हिन्दुस्तानी' में खबरें सुननी पड़ेंगी और तुम्हारी स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों का 'बड़ा भाग' सरकारी 'हिन्दुस्तानी' में होगा। यदि सरकार हिन्दुस्तानी गढ़ना ही चाहती है तो भारत के सभी प्रमुख विद्वानों की समिति बना कर उससे गढ़वाये और जब वह गढ़ जाय और उसे सब स्वीकार कर लें तब—उससे पहले नहीं—उसे भारत भर के स्टेशनों में समान स्थान दे और अँगरेज़ी के स्थान में उसका प्रयोग करे। हिन्दी में पृथक समाचारों की और स्त्रियों, बालकों, आदि के अबाध प्रोग्रामों की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये। हम यहाँ यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि अँगरेज़ी के समान समृद्ध तो 'हिन्दुस्तानी' की कौन कहे, आज तक की साहित्यिक हिन्दी भी नहीं है। आजकल हमें पूरा अर्थ और ध्वनि जानने के लिए अँगरेज़ी की खबरों को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यदि केन्द्रीय सरकार के कांग्रेसी सदस्य दिखाने के लिये पहले सड़ी सी 'हिन्दुस्तानी' में भाषण देकर फिर असली भाषण अँगरेज़ी में देकर संतुष्ट हैं, तो उनकी 'हिन्दुस्तानी' उन्हें म्यारक हो। हमें अँगरेज़ी की खबरें सुनने के लिये विवश न किया जाय। हम पूरा अर्थ, ठीक ठीक भाव और ध्वनि जानने के लिये भी अपनी हिन्दी में खबरें चाहते हैं। जो 'हिन्दुस्तानी' में खबरें सुनना चाहते हैं या 'हिन्दुस्तानी' की खबरें सुनकर संतुष्ट हैं, वे शौक से 'हिन्दुस्तानी' में सुनें। सरकार हिन्दी का गला काट कर रेडियो को एक राजनीतिक दल की भाषा के प्रचार का साधन नहीं बना सकती। देश में हिन्दी भी है और उसे भी रेडियो में अपना उचित स्थान और रेडियो द्वारा प्रोत्साहन पाने का पूरा अधिकार है।

हिन्दी-प्रेमियों को इन्हीं तर्कों और युक्तियों को अपने दाल और तलवार बनाकर आगे बढ़ना चाहिये।

३

सरकार की घोषणा को कुछ अन्य बातों पर भी दृष्टि डालना आवश्यक है। सरकार ने बम्बई, पेशावर, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी, उर्दू और ‘हिन्दुस्तानी’ के प्रोग्रामों का सापेक्षिक अनुपात निर्धारित कर दिया है—पेशावर में पश्तो को ५० प्रतिशत, उर्दू को ४५, हिन्दुस्तानी को ५ प्रतिशत, हिन्दी को शून्य; लाहौर में पंजाबी को २५ प्रतिशत, उर्दू को ५६½, हिन्दी को ११½, हिन्दुस्तानी को ७ प्रतिशत; दिल्ली में हिन्दी को ४०, उर्दू को ४०, हिन्दुस्तानी को २० प्रतिशत; लखनऊ में हिन्दी को ७०, उर्दू को २०, हिन्दुस्तानी को १० प्रतिशत; और बम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी को बराबर बराबर। अर्थात् सब जगह हिन्दी को अपने प्राप्य से बहुत कम और उर्दू को अपने प्राप्य से बहुत अधिक दिया गया है, और हिन्दुस्तानी प्रिया को सब जगह बिना किसी तर्क या सिद्धान्त के यों ही बुसा दिया गया है—कालान्तर में हिन्दी और उर्दू को बिलकुल चट कर जाने के लिये। क्या सरकार इस बात से इन्कार कर सकती है कि सोमा-प्रान्त की ‘आम तौर से बोली’ और समझी जाने वाली भाषा पश्तो, पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बँगला, और बम्बई की मराठी हैं? फिर पेशावर, लाहौर, कलकत्ता, ढाका और बम्बई में इन भाषाओं के बजाय ‘हिन्दुस्तानी’ में कोई भी प्रोग्राम क्यों किया जाय? क्या इन प्रान्तों का ‘कामन सैन’ या ‘कामन लिसेनर’ इन भाषाओं की अपेक्षा ‘हिन्दुस्तानी’ को ज्यादा अच्छी तरह समझता है? इन प्रान्तों में तो केवल हिन्दी और उर्दू को पठित साहित्यिक भाषाओं के नज्दे स्थान मिल सकता था। फिर इन प्रान्तों में जो भी हिन्दुस्तानी बोली या समझी जाती है उसका स्वरूप सब प्रान्तों में एक सा नहीं। उदा-

हरण के लिये, बंगाल और बम्बई में 'आम तौर से बोली और समझी जाने वाली' हिन्दुस्तानी, जिसे वहाँ का 'कामन मैन' समझ सकता है, हिन्दी से भिन्न नहीं, फिर कलकत्ता, ढाका और बम्बई में 'हिन्दुस्तानी' को हिन्दी से पृथक् प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया और हिन्दी को उर्दू के समकक्ष क्यों रख दिया गया ? क्या हम कम से कम यह आशा रखें कि न्याय के नाते इन स्टेशनों में 'हिन्दुस्तानी' की चीजें उन्हीं को दी जायँगी जो प्रान्त के स्थायी निवासी हैं और जिनकी मातृभाषा प्रान्तीय भाषा है ? यदि इन सब स्टेशनों में 'हिन्दुस्तानी' को 'राष्ट्र-भाषा' के नाते स्थान दिया गया है तो मद्रास और ट्रिची में भी स्थान क्यों नहीं दिया गया, और क्या 'हिन्दुस्तानी' की शब्दावली के विषय में परामर्श देने वाली स्थायी समिति में सब प्रान्तीय भाषाओं के विद्वान् लिये जायँगे और क्या प्रान्तीय स्टेशनों में 'हिन्दुस्तानी' की सब चीजें प्रान्त के स्थायी निवासियों को, जिनकी मातृ-भाषा प्रान्तीय भाषा हो, दी जायँगी ? क्या 'राष्ट्र-भाषा' का यही अर्थ और न्याय का यही तकाज़ा नहीं है ?

अब हिन्दी और उर्दू को लीजिये । नवाब सिद्दीकअलीख़ाँ के कठौती के प्रस्ताव पर बोलते हुये सरदार पटेल ने असेम्बली में स्वयं स्वीकार किया कि उर्दू को 'वेटेज' दिया गया है । हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया । क्या अब तक रेडियो में उर्दू की जो तृती बोल रही थी उसका यही तकाज़ा था ? फिर, यदि सरकार ने उर्दू को वेटेज दिया ही, शायद इसलिये कि उर्दू अल्पमत में है, तो सरकार ने हिन्दी को वहाँ वेटेज क्यों नहीं दिया जहाँ हिन्दी अल्पमत में है अर्थात् लाहौर और पेशावर में, और वह कहाँ का न्याय है कि अल्पमत को इतना वेटेज दिया जाय कि वह बहुमत के बराबर हो जाय जैसा कि दिल्ली में किया गया है ? दिल्ली पूरे भारत का स्टेशन है, दिल्ली भारत भर में सुना जाता है और इस समय बिहार, मध्य-प्रान्त, पूर्वी युक्तप्रान्त और राजस्थान जैसे हिन्दी-प्रधान क्षेत्रों में दिल्ली के

अलावा कोई दूसरा स्टेशन नहीं पहुँचता। और देश में अथवा इन हिन्दी-प्रधान ज़ोंवों में हिन्दी का प्रचार उर्दू के प्रचार से कई गुना है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में हिन्दी और उर्दू को बराबर प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया ? लाहौर और पेशावर में हिन्दी को बेटेज देना तो दूर रहा, सरकार ने हिन्दी को उसके प्राप्य से भी कम दिया है। पंजाब में सब हिन्दू बालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी पढ़ती और जानती हैं। लाहौर में हिन्दी को १५ प्रतिशत तो केवल इसी आधार पर मिलना चाहिये, परन्तु सच यह है कि बालकों के मामले में भी पंजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी की परीक्षाओं में बैठने वालों की संख्या उर्दू की परीक्षाओं में बैठने वालों से अधिक है। ऐसी स्थिति में लाहौर में हिन्दी को क्या उर्दू के मुकामिले में मिलना चाहिये था ? और पेशावर में हिन्दी बिलकुल नकार है, यद्यपि सीमा-प्रान्त में अनेक हिन्दी स्कूल हैं और वहाँ की सब हिन्दू बालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी ही पढ़ती और जानती हैं और बहुत से हिन्दू बालक भी हिन्दी पढ़ते और जानते हैं। लखनऊ में भी हिन्दी को उसके प्राप्य से कम दिया गया है, और ‘हिन्दुस्तानी’ का पूरा भाग हिन्दी के हस्तों में से छीना गया है। यह है सरदार पटेल का ‘राष्ट्रीय न्याय’ ! एक हिन्दू के लिए हिन्दी का गला काट कर उर्दू का थर भरना और हिन्दी के भाग को कम करके उर्दू के साथ उदारता दिखाना उससे भी निकृष्ट साम्प्रदायिकता है जितनी हिन्दी को उसके प्राप्य से अधिक देना होती।

घोषणा की कुछ अन्य उल्लेखनीय बातें ये हैं (१) घोषणा में कहा गया है कि ‘हिन्दुस्तानी’ के प्रोग्रामों की व्यवस्था हेडक्वार्टर का स्तर करेगा, परन्तु यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार करेगा। ‘हिन्दुस्तानी’ का कोई निश्चित स्वरूप नहीं, ‘हिन्दुस्तानी’ के लेखक नहीं, फिर लेखकों को ‘हिन्दुस्तानी’ की चीज़ें सरकारी हिन्दुस्तानी में लिखने के लिये कैसे विवश किया जायगा ? यदि इस दिशा में कुछ न किया गया और लेखकों को अपनी

मनमानी हिन्दुस्तानी में लिखने दिया गया तो इसकी क्या गारंटी है कि उनकी भाषा हिन्दी या उर्दू न हो जायगी और वही भगड़ा फिर न खड़ा हो जायगा जिसके कारण आज हिन्दी और उर्दू प्रोग्रामों का अनुपात निर्धारित किया गया है। विशेषरूप से रेडियो के वर्तमान उर्दू-पक्षपाती और हिन्दी-द्रोही स्टाफ पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? अथवा क्या हम सरकार के कथन का यह अर्थ समझें कि 'हिन्दुस्तानी' की सब चीजें रेडियो का वेतन भोगी स्टाफ लिखेगा? * (२) सरकार ने यह नहीं बतलाया कि 'हिन्दुस्तानी' की चीजें, खबरें, आदि किस लिपि में लिखी जायँगी। यदि उर्दू लिपि में भी लिखने की छूट होगी तो उसमें हिन्दी के अधिकांश शब्द और हिन्दुओं के नाम किस प्रकार लिखे जायँगे, शुद्ध उच्चारण का क्या प्रबन्ध किया जायगा और वर्तमान घोर अशुद्ध उच्चारण का किस प्रकार सुधार किया जायगा? चूँकि रेडियो के दफ्तर में 'हिन्दुस्तानी' की चीजें किस लिपि में लिखी जाती हैं, इससे जनता और सुननेवालों को कोई मतलब नहीं, और चूँकि सरकार स्वयं कहती है कि 'हिन्दुस्तानी' वाले स्टाफ के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों का जानना आवश्यक होगा, हम यह जानना चाहते हैं कि शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से सरकार यह आज्ञा क्यों नहीं दे सकती कि 'हिन्दुस्तानी' की खबरें, घोषणायें,

* इस समय अवस्था यह है कि 'हिन्दुस्तानी' की चीजें वही पुराने लेखक लिख कर दे रहे हैं और उनकी भाषा या हिन्दी है (कुछ की), या उर्दू—रेडियो के पत्रों में जिन चीजों के आगे स्पष्टतः 'हिन्दी में' और 'उर्दू में' लिखा जा रहा है उनकी भाषा से बिल्कुल भिन्न नहीं। केवल सरकार की जिद पूरी करने के लिये प्रोग्राम वाले 'हिन्दुस्तानी' के लिये निश्चित अनुपात में कुछ हिन्दी की और शेष उर्दू की मनमानी चीजें छँटकर उनके ऊपर 'हिन्दुस्तानी में' को सुहर लगा देते हैं। अर्थात् वही पुराना भगड़े का मूल बना हुआ है जिसके कारण सरकार को हिन्दी और उर्दू का अनुपात निश्चित करने के लिये विवश होना पड़ा।

सूचनायें और अन्य चीजें सदैव देवनागरी में लिखी और पढ़ी जायें ? (३)
 घोषणा में कहा गया है कि रेडियो के वर्तमान स्थायी स्टाफ को हिन्दी और
 उर्दू दोनों जानने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता । क्यों ? यदि यह
 किसी कारण संभव नहीं, तो कम से कम हिन्दी न जानने वाले अस्थायी
 स्टाफ को अलग करना और अस्थायी रूप से उच्च पदों पर आर्मान हिन्दी
 न जाननेवाले व्यक्तियों को अपने स्थायी पदों पर वापस भेजना तो संभव है ।
 हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों की कर्मा की इस प्रकार पूरा क्यों नहीं किया
 जाता ? श्री बोखारी ने तो कितने ही कर्मचारियों को इस ‘कमूर’ पर निकाल
 दिया कि उनका उर्दू का ज्ञान विलुप्त नहीं था, क्या राष्ट्रीय सरकार हिन्दी
 के लिये इतना भी नहीं कर सकती ? फिर, हिन्दी और उर्दू दोनों के ज्ञान
 की जाँच क्या और किस प्रकार होगी ? क्या देवनागरी में चार भक्तियाँ लिख
 और पढ़ सकना हिन्दी की योग्यता का प्रमाण मान लिया जायगा ? ‘हिन्दु-
 स्थानी’ वाले स्टाफ की हिन्दी और उर्दू की योग्यता की जाँच करने के लिये
 सरकार एक निपट और बाहरी परीक्षा-बोर्ड द्वारा समान स्टेण्डर्ड की हिन्दी
 और उर्दू की विभागीय परीक्षाओं की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती ?
 (४) सरकार ने इस बात को मान लिया है कि हिन्दी के प्रोग्रामों की व्यवस्था
 करने के लिये स्टाफ में हिन्दी की विशेषतः योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की
 संख्या काफी हो, परन्तु सरकार ने इस बात को असली रूप देने का कोई
 प्रबंध नहीं किया है। कम से कम सरकार यह आदेश दे सकती थी कि भविष्य
 में स्टाफ में केवल हिन्दी जाननेवालों की भरती हो जब तक उनकी संख्या
 विशेष न हो जाय । (५) यद्यपि सरकार ने यह स्वकार किया है कि उर्दू
 गज़लों के सुकायले हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ कवियों की कवितायें गाई जायें,
 परन्तु किस अनुपात में गाई जायें, यह रेडियो के वर्तमान उर्दू-संगीत स्टाफ
 पर छोड़ दिया गया है । (६) रेडियो-कमेटी की इस सिलसिला पर कि
 ‘आदाबअर्ज’, ‘खुदा हाफिज़ है’, आदि अभिवादनों का प्रयोग विलकुल

बन्द कर दिया जाय, सरकार ने निर्णय दिया है कि जनता में आमतौर से प्रचलित (‘popularly used’) अभिवादन का प्रयोग किया जाय, परन्तु यह नहीं बतलाया कि किस स्टेशन में किस अभिवादन का प्रयोग किया जाय। यह रेडियो के बोझारी-परस्त अफसरों पर छोड़ दिया गया है।

४

यह लेख इसका आभास दिये बिना पूर्ण न होगा कि घोषणा होने के तीन महीने बाद भी आज उसका पालन किस प्रकार हो रहा है। इससे घोषणा की कितनी ही अस्पष्ट बातों का उत्तर भी मिल जायगा। खबरों की भाषा में कोई उल्लेखनीय या निश्चित परिवर्तन नहीं हुआ है। वही लिखने वाले हैं, वही पढ़ने वाले। स्टाफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और पुराने स्टाफ से किसी सुधार की आशा करना दुराशा मात्र है। यहाँ तक कि कोई घोषक (announcer) भी, जो स्थायी छोड़ अस्थायी नौकर भी नहीं है बरन् कलाकारों की भाँति नियुक्त किये जाते हैं, नहीं बदला गया है। ‘हिन्दुस्तानी’ की सब लिखाई पूर्ववत् उर्दू लिपि में हो रही है और उच्चारण का भी वही हाल है। रेडियो के किसी घोषक के मुँह से ‘रामायण’ या ‘नारायण’ तो स्वप्न में भी नहीं निकल सकता। ‘हिन्दी और उर्दू दोनों का जानना आवश्यक होगा’, यह केवल फाइलों में धरा हुआ है। स्वयं सरकार ने अभी तक ‘हिन्दुस्तानी’ की परामर्श-समिति का निर्माण नहीं किया है। कब कमेटी बनेगी, कब वह बैठेगी और कब वह ‘हिन्दुस्तानी’ का निर्माण करेगी! एक ओर राष्ट्रीय सरकार हिन्दी में खबरें देने को तैयार नहीं, दूसरी ओर रेडियो की वर्तमान ‘हिन्दुस्तानी’ बदलने के लिये क्रियाशील नहीं। निचोड़ यह है कि हम ‘राष्ट्रीय सरकार’ के व्यर्थ, अनुचित और निराधार हिन्दुस्तानीवाद के कारण इसी वर्तमान ‘हिन्दुस्तानी’ नामधारी उर्दू को सुनने के लिये विवश हैं। ‘हिन्दुस्तानी’ की सूचनाओं, घोषणाओं, आदि की भाषा में तो कोई अन्तर हुआ ही नहीं है। केवल लखनऊ से

(दिल्ली से वह भी नहीं) ‘मजलिस’ शब्द निकाल दिया गया है, मगनु चौक हिन्दुस्तानी ‘मभा’ नहीं समझ सकते, उसके स्थान में ‘सुभू का प्रोग्राम’, ‘दोपहर का प्रोग्राम’ और ‘शाम का प्रोग्राम’ धर दिया गया है । ‘हिन्दुस्तानी’ की चीजें पूर्ववत् उर्दू वालों और मुसलमानों को दी जा रही हैं और उनकी भाषा पूर्ववत् शुद्ध उर्दू है जिसका अर्थ यह है कि उर्दू देगावर, लाहौर, दिल्ली, और लखनऊ में ४५, ५६½, १० और २० प्रतिशत नहीं, ५०, ६३½, ६० और ३० प्रतिशत है, और दम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी के बराबर नहीं, इन्हीं हैं, और स्त्रियों, बालकों, आदि के तथाकथित हिन्दी प्रोग्रामों का दो-तिहाई भाग उर्दू में होता है । देगावर और दम्बई में स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों को हिन्दी में अलग किया ही नहीं गया है, अर्थात् वहाँ के पूर्ववत् केवल ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् उर्दू में हो रहे हैं । इसी प्रकार मैसूरों के प्रोग्राम, प्रवासी भारतीयों के प्रोग्राम, आदि भी हिन्दी में अलग नहीं किये गये हैं और पूर्ववत् केवल ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् उर्दू में हो रहे हैं । हिन्दी वालों को उनके पत्रों के उत्तर भी ‘प्रवासी’, ‘स्त्रियों’ गण पूर्ववत् अपनी ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् उर्दू में सुना रहे हैं । रेडियो की किसी सूत्रिका से वह भी पता नहीं चल सकता कि कौन सा स्त्रियों या बालकों का प्रोग्राम हिन्दी का है, और कौन सा उर्दू का । रेडियो वालों को रात में दोनों प्रोग्राम सब स्त्रियों या बच्चों के लिये एक समान उपयुक्त है और सरकार ने सहज सजाक के लिये इन प्रोग्रामों को अलग-अलग हिन्दी और उर्दू में करने के लिये कहा है, और इसीलिये सप्ताह के दोनों स्त्रियों (या बालकों) के प्रोग्रामों में कोई अन्तर नहीं—दोनों के संचालक वही दुगने उर्दूवाँ लोग (‘आया’, ‘दाजी’, आदि) हैं जो हिन्दी के पत्रों के उत्तर भी पहले दम्बर से उनकी उर्दू में नकल करा कर देते हैं, दोनों में वही ‘आयादखत्री’ चलता है और दोनों में हिन्दी और उर्दू की चीजें मिली-जुली होती हैं, अर्थात् केवल एक बार के बजाय दो बार प्रोग्राम होता है, और कुछ नहीं । प्रत्येक

प्रोग्राम का समय भी पहले का आधा है। 'आदावअर्ज' और 'खुदा हाफिज़ है' का सब स्टेशनों में पूर्ववत् प्रयोग हो रहा है। रेडियो वाला की राय में पेशावर से पटना तक और दिल्ली से जबलपुर तक की जनता में यही अभिवादन 'आम तौर से प्रचलित' है, और 'नमस्कार', 'नमस्ते', 'प्रणाम', या 'राम राम' केवल दो चार तिलकधारी पंडित करते हैं। संगीत का भी वही हाल है। पन्द्रह दिन का संगीत का प्रोग्राम देख डालिये, उर्दू का ऐसा कोई कवि नहीं मिलेगा जिसका 'कलाम' दो-चार दफे न गाया गया हो, परन्तु हिन्दी के प्राचीन कवियों में केवल तुलसी, सूर और मीरा के और आधुनिक कवियों में केवल वचन, कोकिल और एक-दो और के नाम मिलेंगे और वे भी कहीं कहीं और कभी कभी। शायद रेडियो वाले हिन्दी के किसी और कवि का नाम जानते ही नहीं। पूर्ववत् अब्दुलमाजिद भट्टी, सलाम मछलीशहरी, हफीज़ जलन्धरी, तनवीर, अख्तर शीरानी, अल्ताफ़, कैफ़, गुलशन, आदि उर्दू कवियों के सड़े हुये, अर्थहीन, विना सिर-पैर के थोड़े से हिन्दी गीत भी गाये जा रहे हैं। इन कवियों ने आशा, जीवन और आकाश जैसे दो-तीन दर्जन हिन्दी शब्द याद कर लिये हैं और उनकी कला की पराकाष्ठा है इन शब्दों को घुमा फिरा कर किसी प्रकार तुकबन्दी में पिरो देना। हिन्दी कवियों ने न कभी गीत लिखे न लिखना जानते हैं, इसलिये हिन्दी गीतों के लिये मिला हुआ रुपया भी उर्दू कवियों की जेब में पहुँचना आवश्यक है! वे ही तो हिन्दी के 'स्टैंडर्ड' कवि हैं!

यह कहना अत्युक्ति न होगा कि अमल में सरकारी घोषणा से रेडियो की दुनिया में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

५

अन्त में 'राष्ट्रीय' सरकार, सरदार पटेल और उनके सहयोगियों से एक बात पूछे बिना नहीं रहा जाता। कांग्रेस के गर्जन-तर्जन, वर्षों तक हिन्दुओं की गर्दन रेतने और मुसलमानों की खुशामद तथा जिन्ना साहब के तलवे सह-

लाने के बावजूद पाकिस्तान तो बन कर रहा, और उन्हें ही जिन्होंने जन्म भर अपने आन को हिन्दू नहीं बरन् ‘हिन्दुस्तानी’ नाम की किसी चिड़िया, और हिन्दुओं के नहीं बरन् ‘हिन्दुस्तानी’ नामक किसी जानि का प्रतिनिधि सिद्ध करने में एड़ी-चोटी का जोर लगाया है, हम अभाग्य और मूर्ख हिन्दुओं की ओर से पाकिस्तान के उद्वेग पर सहो करना पड़ी। अन्तु, पाकिस्तान का रेडियो तो डके की चाँद शुद्ध उर्दू में बोलेंगे। क्या अब भी अभाग्य हिन्दुओं के इस अभाग्य ‘हिन्दुस्थान’ के रेडियो में कांग्रेसी नेताओं के परम ‘राष्ट्रीय’ अधिनायकत्व में इस कमबख्त ‘हिन्दुस्तानी’ का रगड़ा रहेगा और बेचारा हिन्दों को कहीं ठौर न होगी? और इसी प्रकार दिल्ली में ‘हिन्दो उर्दू पैरिडी’ रहेगी? और ‘हिन्दुस्तान’ की राष्ट्रभाषा यही कांग्रेस-वृजित ५० प्रतिशत हिन्दी ५० प्रतिशत उर्दू वाली ‘हिन्दुस्तानी’ तथा राष्ट्रलिपि ‘देवनागरी और फारसी (!) लिपि दोनों’ रहेंगी? नेता दिल पर हाथ रखकर उत्तर दें।

उत्तर-परिशिष्ट ३

‘हिन्दुस्तानी’ का रहस्य

—एक हिन्दी के मुख से—

१

अहिन्दी प्रान्त और ‘हिन्दुस्तानी’

अभी हाल में (अक्टूबर, १९४६) पत्रों में यह समाचार पढ़ने को मिला कि आन्ध्र के ‘नेशनलिस्ट’ मुसलमानों का एक शिष्ट-मंडल मौलाना आज़ाद से मिला और यह इच्छा प्रकट की कि आन्ध्र के मुसलमानों की शिक्षा का माध्यम तेलगू के बजाय उर्दू कर दिया जाय, और मौलाना आज़ाद ने उसके दृष्टिकोण का आदर किया और मद्रास के प्रधानमंत्री से उसकी माँग मान लेने की सिफारिश की है। इस समाचार से शायद बहुतों को आश्चर्य हुआ होगा, परन्तु भारतीय मुसलमानों की तो यही मनोवृत्ति है। विचित्र बात यह नहीं है कि मुसलमानों ने—‘राष्ट्रीय’ अथवा लीगी, क्योंकि उर्दू के मामले में दोनों में कोई अंतर नहीं—ऐसी माँग पेश की है; विचित्र बात यह है कि मौलाना आज़ाद ने इस माँग का समर्थन किया है। अन्तु, आशा है अब हिन्दुस्तानीवालों को इसका विश्वास हो जायगा कि कांग्रेसी मुसलमान भी (जो दाल में नमक के बराबर बैसे ही हैं) भाषा के मामले में अन्य मुसलमानों के साथ हैं। यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि ऐसी माँगें सभी अहिन्दी प्रान्तों—तामिल नाद, महाराष्ट्र, गुजरात,

उड़ीसा, बंगाल, आसाम, आदि—के मुसलमानों द्वारा पेश की जायेंगी। इन माँगों का अर्थ भी समझ लेना चाहिये। आन्ध्र को ही लीजिये। आन्ध्र के मुसलमानों की माँग का सीधा-सादा अर्थ यह है कि आन्ध्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को बीच से दो-टुक कर दिया जाय, साम्प्रदायिक अलगाव और कटुता के बीज बोये जायें, करदमाओं का तपया (जो हिन्दुओं की जेब से ही आयेगा) अलग उर्दू स्कूल और कॉलेज खोलने में फँका जाय, शिक्षा के व्यय को व्यर्थ वृत्ता किया जाय और शासन की कठिनाइयाँ सहल सुना बढ़ाई जायें, क्योंकि यह निश्चित है कि इस माँग के बाद वह माँग पेश की जायगी कि राजकार्य में उर्दू को तेलगू के समकक्ष स्थान दिया जाय। एक ओर तो भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्निर्माण की चर्चा जोरों में चल रही है, दूसरी ओर गांधीजी हिन्दी की 'हिन्दुस्तानी' करने और उर्दू लिपि के प्रचार में इस उद्देश्य से जुट हुये हैं कि मुसलमान खुश हो जायें और भाषा की 'एकता' स्थापित हो जाय, और इधर मुसलमान एक ऐसे प्रान्त में ही भाषा का पाकिस्तान बनाने की माँग कर रहे हैं जो अब तक भाषा और संस्कृति की दृष्टि से एक रहा है! पना नहीं, डा० पट्टाभि सीतारमैया को, जो तेलगू भाषी आन्ध्र को भाषा के आधार पर एक पृथक् प्रान्त बनाने के लिये यत्नशील हैं, आन्ध्र के भीतर ही एक अलग उर्दूस्तान बनाने की माँग कहाँ तक रचेगी, और गांधीजी, जो प्रान्तीय प्रकरणों में प्रान्तीय भाषा के प्रयोग पर और राष्ट्रीय प्रकरणों में राष्ट्र-भाषा (अर्थात् अपनी 'हिन्दुस्तानी') के प्रयोग पर जोर देते हैं, अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों की इस प्रकार की माँगों का कहाँ तक समर्थन करेंगे।

कहना कठिन है कि विभिन्न अहिन्दी प्रांतों (बंगाल को छोड़कर, जहाँ की लीगी सरकार 'हिन्दुई भाषा' बंगला को निकाल कर उर्दू की प्रतिष्ठा करने में कोई कसर नहीं उठा रकवेगी) की कांग्रेसी सरकारें इस

प्रकार की प्रतिक्रियावादी मांगों का क्या उत्तर देंगी। ज़रा देर के लिये मान लीजिये कि वे मौलाना आज़ाद की सिफ़ारिश की भी पर्वाह न कर कम से कम इस मामले में अपनी 'अपीज़मेंट पालिसी' का परित्याग कर इन माँगों को ठुकरा देंगी। परन्तु असली प्रश्न यह है कि यदि कांग्रेसी सरकारें राष्ट्र-भाषा की गांधीजी की दी हुई नई परिभाषा मान कर उनकी

'हिन्दुस्तानी' ($= \frac{\text{हिन्दी} + \text{उर्दू}}{2}$) और देवनागरी के साथ उर्दू लिपि

को स्कूलों में अनिवार्य (या वैकल्पिक ही, क्योंकि मुसलमान अवसर चुकने वाले नहीं) विषय के रूप में धर देते हैं, तो क्या उस प्रकार से ही अहिन्दी मुसलमानों का वह उद्देश्य पूर्ण न हो जायगा जो इन माँगों में निहित है? जब अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान इस प्रकार सरकारी खर्च से ही उर्दू लिपि सीख लेंगे तो उन्हें शुद्ध उर्दू सीखने से, प्रान्तीय भाषा के साहित्य को छोड़कर उर्दू साहित्य अपनाने से, अपना सारा काम काज प्रान्तीय भाषा के बजाय उर्दू में करने से, अर्थात् प्रान्तीय भाषा त्याग कर उर्दू अपनाने से कौन रोक सकेगा? सरकारी खर्च से ही 'हिन्दुस्तानी' की शिक्षा के द्वारा उन्हें उर्दू शब्दों, उर्दू के ढाँचे, व्याकरण, आदि का जो ज्ञान होगा उसके कारण उनके लिये अपना लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान हो जायगा, और चूँकि हिन्दू भी उर्दू लिपि और ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' जानते होंगे, उनके मार्ग की एक बाधा और दूर हो जायगी। इसके अतिरिक्त अहिन्दी हिन्दू भी अन्ततः गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' को, जिसे वे केवल स्कूलों में पढ़ेंगे, नहीं बरन् उस 'हिन्दुस्तानी' को (अर्थात् उर्दू) अपनायेंगे जिसे वे नित्य अपने पड़ोसी मुसलमानों के मुख से सुनेंगे। उपदेश से उदाहरण में अधिक बल होता है। एक नई भाषा पढ़ने की अपेक्षा सुनने से ज्यादा जल्दी आती है। चूँकि मुसलमान प्रान्तीय भाषा का वहिष्कार कर उर्दू पर जोर देंगे और चूँकि हिन्दुओं को 'हिन्दुस्तानी' के ज्ञान के

कारण उर्दू समझने में कोई विशेष अड़चन नहीं पड़ेगी, उर्दू अपने आप प्रान्त की कामन भाषा हो जायेगी, और फलस्वरूप सारे देश की वास्तविक राष्ट्र-भाषा भी हो जायेगी। लिपि के मामले में भी वही होगा। अपने उस कराँड़ अखंड अनुयायियों के बल पर उर्दू भारत की सब से अधिक शक्ति-शाली भाषा और उसका साहित्य सबसे अधिक समृद्ध हो जायेगा, और उसके सामने सभी प्रान्तीय भाषाएँ और उनके साहित्य नीके पड़ जायेंगे। दूसरे शब्दों में, उर्दू सब प्रान्तीय भाषाओं पर अमरवेजि की तरह छा जायेगी। उर्दू की विदेशी संस्कृति, विदेशी प्रवृत्ति, वातावरण, राजशाहों और साज-सज्जा का प्रान्तीय भाषाओं और उनके द्वारा प्रविवक्षित होने वाली स्वदेशी संस्कृति पर अत्यन्त विनाशकारी प्रभाव रहेगा—उसी प्रकार जिस प्रकार आज अँगरेज़ी का पड़ रहा है, केवल उर्दू का प्रभाव इसमें भी अधिक पड़ेगा।

वह भी निश्चित है कि कुछ समय बाद सुसलमान प्रान्तीय भाषा में अनावश्यक उर्दू शब्द छुटेड़ना आरम्भ करेंगे, और इस प्रकार प्रान्तीय भाषा की एक अलग शैली की ही सृष्टि कर डालेंगे, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू बँगला—मुस्लिम बँगला, हिन्दू तेलगू—मुस्लिम तेलगू जैसी समस्याएँ प्रकट हो जायेंगी। उत्तर में सुसलमानों ने ऐसा ही किया। उन्होंने हिन्दी में से हिन्दी शब्द निकाल निकाल कर अरबी और फारसी के शब्द ढँके, और इस प्रकार उर्दू की सृष्टि कर डाली, और इन का परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा, राजकार्य आदि आदि के क्षेत्रों में हिन्दी—उर्दू समस्या नीपण रूप धारण कर रही है। प्रान्तीय भाषा को मुस्लिम शैली का निर्माण इस कारण और भी सरल होगा कि हिन्दू भी 'हिन्दुस्तानी' द्वारा उर्दू शब्दों से परिचित होंगे। यदि प्रान्तीय भाषा को विवृत करने का जानबूझ कर प्रयत्न न भी किया गया, तो भी ऐसा ही होगा क्योंकि प्रांत की व्यापक भाषा, राष्ट्र की कामन भाषा और सुसलमान पड़ोसियों की भाषा के नाते

उर्दू का प्रान्तीय भाषा पर अत्यन्त व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा सदैव हुआ है। भूतकाल में राज-भाषा फारसी का प्रान्तीय भाषाओं पर प्रभाव पड़ा और वर्त्तमान काल में तो अँगरेज़ी का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि प्रान्तीय भाषाओं की आधी देशी और आधी अँगरेज़ी बाबू शैलियाँ ही बन गई हैं। यदि 'हिन्दुस्तानी' उर्दू में परिणित न भी हुई, तो 'हिन्दुस्तानी' की अर्ध अरबी-फारसी शब्दावली प्रान्तीय भाषा को विकृत करने और उसके साहित्य को आने वाली पीढ़ियों के लिये मृत-साहित्य बनाने के लिये पर्याप्त होगी। यह भी निश्चित है कि उर्दू लिपि सीख जाने के बाद मुसलमान प्रान्तीय भाषा को उर्दू लिपि में लिखेंगे। बहुत संभव है कि प्रान्तीय भाषा की लिपि के विभाजन से ही उसकी शैली के विभाजन का श्रीगणेश हो *। चूँकि हिन्दू भी 'हिन्दुस्तानी' की एक लिपि के नाते उर्दू लिपि जानते होंगे, उन्हें भी उर्दू लिपि में लिखित प्रान्तीय भाषा को स्वीकार करने में या कम से कम उसे सहन करने में कठिनता महसूस न होगी।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह कोरी कपोल-कल्पना नहीं है। भारतीय

लिपि का भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उर्दू के पृथक् विकास का एक कारण यह था कि मुसलमानों ने हिन्दी फारसी लिपि में लिखी। पारसियों की गुजराती रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की गुजराती से सर्वथा भिन्न है और गोआ के ईसाइयों की कोंकणी रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की कोंकणी (देवनागरी में लिखित) से सर्वथा भिन्न है। लिपि और भाषा का अटूट संबंध होता है। जिस प्रकार रोमन लिपि के प्रभाव से अँगरेज़ी शब्द पारसी-गुजराती और ईसाई-कोंकणी में अनायास घर करते जाते हैं और फारसी लिपि के प्रभाव से फारसी शब्द सिन्धी और उर्दू में, और उर्दू शब्द मुस्लिम (!) पंजाबी में घर करते जाते हैं, उसी प्रकार फारसी लिपि के प्रभाव से उर्दू शब्द प्रान्तीय भाषाओं की मुस्लिम शैली में (फारसी लिपि में लिखित) अनायास घर करते जायँगे। प्रान्तीय भाषा के बहुत से शब्दों का उर्दू लिपि में न लिखे जा सकने के कारण बहिष्कार होगा। शेष शब्दों का उच्चारण अष्ट होगा, सो अलग।

मुसलमानों की मनोवृत्ति और उर्दू के प्रति उनके अनुचित आकर्षण के इतने सबूत मिल चुके हैं कि इसमें सन्देह करने की कोई गुंजाइश नहीं कि विभिन्न अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान प्रान्तीय भाषायें त्याग कर उर्दू अपनायेंगे, और इसके वही परिणाम होंगे जो ऊपर बतलाये गये हैं। उर्दू और उर्दू लिपि के सदीमरोलर के नीचे काश्मीर, पंजाब और हैदराबाद की देशी भाषायें और लिपियाँ पिस चुकी हैं। पंजाबी पर उर्दू का इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है कि उसका मूल संस्कृत-बहुल रूप बिलकुल बदल गया है। पंजाबी मुसलमान जब पंजाबी लिखते ही हैं तो उसे उसकी स्वाभाविक लिपि गुरुमुखी के 'पंजाब उर्दू' लिपि में लिखते हैं, और पंजाब विश्व-विद्यालय को पंजाबी के लिये गुरुमुखी और उर्दू लिपि दोनों को स्वीकार करना पड़ा है। सीमा-प्रान्त में पश्तो पर उर्दू छाती जा रही है। सिन्ध में मुसलमानों को सिन्धी तभी सह्य हुई जब उन्होंने उसमें जी भर कर अरबी और फारसी टँस ली और उसकी मूल लिपि देवनागरी हटा कर फारसी लिपि धर ली। सिन्धी का अरबीकरण अब भी जारी है, और चूँकि सिन्ध में मुसलमानों का बहुत बड़ा बहुमत है, उन्होंने सिन्धी हिन्दुओं को भी अपनी अरबी-फारसी-मयी सिन्धी और फारसी लिपि स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया है। तिस पर भी सिन्ध में उर्दू को खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है।* यह कहना बिलकुल यथार्थ होगा कि गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' नहीं 'वरन् उर्दू', और 'दोनों लिपि' नहीं, वरन् केवल उर्दू लिपि इस समय भी पूरे पश्चिमी पाकिस्तान की और उसके अलग अलग भागों—पंजाब, काश्मीर, सीमा-प्रान्त, बलूचिस्तान—की भी, कामन भाषा और लिपि बन चुकी है। उर्दू पूरे हैदराबाद की भी डीफैक्टो कामन भाषा और साहित्यिक भाषा है। उर्दू के प्रभाव के कारण हैदराबाद की देशी भाषाओं मराठी और तेलगू का

* अब तो सिन्धी का बिलकुल बहिष्कार किया जा रहा है और उसके स्थान में उर्दू की प्रतिष्ठा की जा रही है। आगे 'पुनर्लेख' देखिये।

स्वरूप अत्यन्त विकृत और कलुषित होता जा रहा है।..... बंगाल में 'हिन्दू बंगला' और 'मुस्लिम बंगला' के नाम अभी से सुनाई पड़ने लगे हैं*,

६ फरवरी, १९४७ के 'मार्डेन रिव्यू' में प्रोफेसर हेमन्तकुमार सरकार लिखते हैं :

"The writing of primary text-books has been taken up by the League Government. A new type of language advocated by newspapers like the *azad* with Arabic and Persian words preponderating is coming to vogue. The peculiar phonetics and Islamic idioms are absolutely foreign to Bengalis. Primary schools are now called *Mukhtabs*; it is likely that the secondary schools, mostly built up by the money and energy of the Hindus, will be called *Madrassas*..... The Hindus will soon have to read accounts of 'Janab' Ramchandra and his 'Begum' Sita" अर्थात्

"(बंगाल में) लीगी सरकार ने प्राथमिक पाठ्य-पुस्तकों का लेखन-कार्य अपने कब्जे में कर लिया है। भाषा का एक नया रूप जिसकी वकालत 'आज़ाद' जैसे अख़बार करते हैं और जिसमें अरबी और फ़ारसी शब्द भरे हुये हैं, सामने आ रहा है। इसकी विचित्र ध्वनि-प्रणाली और सुसलमानी मुहावरे तथा शब्द-विन्यास बंगालियों के लिये बिल्कुल विदेशी और अपरिचित हैं। प्राइमरी स्कूलों को अब 'मक़तब' कहा जाता है और संभावना है कि सेकण्डरी स्कूलों का, जो अधिकतर हिन्दुओं के रुपये और श्रम से स्थापित हुये हैं, नामकरण 'मद्रसा' होगा। हिन्दुओं को अब शीघ्र ही 'जनाब' रामचन्द्र और उनकी बेगम सीता की कहानियाँ पढ़नी पड़ेंगी।"

जहाँ-जहाँ मुसलमानों के हाथ में शक्ति है वहाँ-वहाँ उन्होंने भारतीय भाषाओं का अरबी और फ़ारसी-करण या तो कर लिया है या अब कर रहे हैं, और फ़ारसी लिपि को भी या तो घुसेड़ लिया है या अब घुसेड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ हिन्दुओं का बहुमत है वहाँ-वहाँ यही काम अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' द्वारा करने का ज़िम्मा कांग्रेस ने ले लिया है !

जो हिन्दुस्तानी वाले इस अम में हैं कि हिन्दुस्तानी-वाद के पीछे सबसे

और चूँकि उर्दू को जोर शोर से सकारा प्रोत्साहन मिल रहा है, धीरे धीरे एक उर्दू-बंगाला समस्या आकार धारण करती जा रही है। बंगाल की लीगी सरकार के 'सेकंडरी एजुकेशन बिल' का एक गुप्त उद्देश्य उर्दू का प्रचार और प्रसार है। बम्बई प्रान्त में मुसलमानों ने अभी से अपनी मानु-भाषाएँ मराठी और गुजराती त्याग कर उर्दू को अपना लिया है; और उदाहरण के लिये बम्बई सरकार ने उनके लिये पृथक् उर्दू स्कूलों का प्रबन्ध कर दिया है। अभी हाल में जब बम्बई में एक मराठी विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा चल रही थी, बम्बई में एक उर्दू कांफ्रेंस (जिसको गांधीजी ने भी आशीर्वाद दिया) बुलाई गई और उसमें यह प्रस्ताव पेश की गई कि बम्बई-प्रान्त के मुसलमानों के लिये एक अलग उर्दू विश्वविद्यालय खोला जाय, क्योंकि 'मराठी के कारण मुसलमानों की संस्कृति स्वतरे में पड़ जायगी।' जब राष्ट्रवादी आँगरेजी का पूर्ण बहिष्कार कर देंगे तब देखेंगे बम्बई की अस्मयली कैसे अर्थात् किस भाषा में अपना कान करती है जिसने वह सब सदस्यों की समझ में आजाय, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि वहाँ वही स्थिति रही, और यदि श्रीयुत खेर ने जो प्रधान-मंत्री और शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ गांधी जी की हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के एक प्रमुख सदस्य हैं, बम्बई में गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' का प्रचार किया, तो उर्दू बम्बई-प्रान्त की डीफैक्टो कामन भाषा हो जायगी, और उसके नीचे मराठी और गुजराती की तुलना होती चली जायगी। यह सर्व-विदित है कि मुसलमान वक्ता शुद्ध उर्दू के बिना अधिक बोधगम्यता का सिद्धान्त है, वे भी आँखें खोलकर देख लें कि यह बोधगम्यता का नहीं, संस्कृति का सवाल है, नहीं तो बंगाली मुसलमान आज बंगाला के अपने चिरपरिचित संस्कृतज शब्दों को निकाल कर उनके स्थान में अपरिचित विदेशी शब्द न भरता। 'हिन्दुस्तानी' को मुसलमानों से संजूर कराने के लिये उसे अरबी और फारसी मथ कर बनाना पड़ेगा।

किसी दूसरी हिन्दुस्तानी में नहीं बोलते, और उत्तर में ही नहीं, प्रयत्न करके बंगाल और मद्रास में भी उर्दू में (गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' या कांग्रेस के हिन्दू नेताओं की ५०-५० प्रतिशत वाली हिन्दुस्तानी में नहीं) भाषण करते हैं, चाहे वे प्रादेशिक भाषा क्यों न जानते हों। इससे मुसलमानों की मनो-वृत्ति पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। रहा सहा सन्देह आन्ध्र के मुसलमानों की इस माँग से दूर हो जाता है कि उनकी शिक्षा का माध्यम तेलगू के बजाय उर्दू कर दिया जाय।

क्या हम अहिन्दी प्रांतों की कांग्रेसी सरकारों से और गांधीजी के हिन्दुस्तानी-प्रचार के पीछे मतवालों से पूछ सकते हैं, कि यदि अहिन्दी प्रांतों के मुसलमानों को राष्ट्र-भाषा के रूप में 'हिन्दुस्तानी' के बजाय हिन्दी, और राष्ट्र-लिपि के रूप में 'दोनों लिपि' के बजाय केवल देवनागरी सिखाई जाय, तो भी क्या उन्हें अपनी मातृ-भाषा और प्रान्त-भाषा को निरादृत करने, त्यागने या विकृत करने की अथवा उसे उसकी स्वाभाविक लिपि के बजाय किसी दूसरी लिपि में लिखने की कोई प्रेरणा होगी अथवा साधन ही लभ्य होंगे? उस हालत में भी क्या उन्हें सार्वदेशिक प्रकरण के सिवा दूसरे प्रकरण में राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रयोग करने की इच्छा होगी? रही अहिन्दी हिन्दुओं की बात, सो वे तो अपनी मातृ-भाषाओं और लिपियों से प्रेम करते हैं। उनके द्वारा तो प्रान्तीय भाषाओं की हानि कभी हो ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त हिन्दी, और बंगला, आसामी, उड़िया, तेलगू, तामिल मराठी, गुजराती, आदि प्रान्तीय भाषाओं की संस्कृति, प्रवृत्ति और शब्दावली में इतना साम्य है कि उनका एक दूसरे पर प्रभाव एक दूसरे के लिये लाभ-दायक ही सिद्ध हो सकता है।

समस्या को भली भाँति समझ लेना चाहिये। हिन्दी और उर्दू एक भाषा की केवल दो शैलियाँ हों अथवा न हों, वे भाषा की दो सर्वथा भिन्न दिशाएँ अवश्य हैं। एक की दिशा भारत की ओर जाती है और दूसरी की

फारस और अरब की ओर, केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक महत्वपूर्ण बात में—शब्दों के रूपों में, अलंकारों में, उपमाओं में, छन्दों में, व्याकरण में, संस्कृति में और लिपि में। जब तक दोनों की दिशा एक न हो, तब तक उनका एक होना और गांधीजी की सरस्वती का प्रकट होना असंभव है। और बात यह है कि हिन्दी की दिशा या प्रवृत्ति वही है जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं की। प्रत्येक प्रान्तीय भाषा और उर्दू में संघर्ष का यही मूल कारण है। 'यह हिन्दी—उर्दू की समस्या' नहीं, भाषा के क्षेत्र में हमारी वही चिर-परिचित हिन्दू—मुसलिम समस्या है। अभी यह हिन्दी—उर्दू के संघर्ष के रूप में दिखाई देती है, शीघ्र ही वह उर्दू—बंगला संघर्ष, उर्दू—तेलगू संघर्ष, उर्दू—तामिल संघर्ष, उर्दू—मराठी संघर्ष, उर्दू—गुजराती संघर्ष, आदि के रूप में दिखाई पड़ने लगेगी। वम्बई में उर्दू—मराठी और उर्दू—गुजराती युद्ध अपनी मध्यम अवस्था में पहुँच चुका है, बँगाल में उर्दू और बँगला का युद्ध आरम्भ हो गया है और मद्रास में उर्दू—तेलगू और उर्दू—तामिल युद्ध आरंभ होने जा रहा है। गांधी जी ने बीमारी की जड़ तक न पहुँच कर बीमारी के एक चिन्हमात्र की चिकित्सा करनी चाही है, और उनका इलाज—५०-५० प्रतिशतवाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'—बीमारी से भी अधिक भयंकर है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, उससे बीमारी और बढ़ेगी। गांधी जी का हिन्दुस्तानी-वाद उर्दू और विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के युद्ध में सभी प्रांतीय भाषाओं के परास्त और पददलित होने का कारण बनेगा। वह केवल हिन्दी की अस्वच्छता, शुद्धता और अस्तित्व पर ही नहीं, बरन् सभी प्रांतीय भाषाओं की अस्वच्छता, शुद्धता और अस्तित्व पर कुठाराघात है। हिन्दुओं की शक्ति विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के बीच में, उनके पृथक् पृथक् विकास और साहित्य की अभिवृद्धि करने में कैसे ही बँटी हुई थी, आज गांधी जी ने हिन्दी के कैम्प में जो कूट डाली है और जिस वाद को 'राष्ट्रीयता' का जामा पहनाया है, उसका

परिणाम यही होगा कि उर्दू इस वाद को अपनी ढाल और तलवार दोनों बनाकर पहले हिन्दी को और फिर एक एक करके प्रान्तीय भाषाओं को चौपट कर देगी। दूसरे शब्दों में, गांधी जी, कांग्रेस और अन्य हिन्दुस्तानी वालों ने अपने हिन्दुस्तानी-आन्दोलन द्वारा हिन्दी को जो क्षति पहुँचाई है और पहुँचा रहे हैं, वह केवल हिन्दी की नहीं, सब प्रान्तीय भाषाओं की क्षति है। आज सब भारतीय भाषाओं में से केवल हिन्दी वह भाषा है ही जो संस्कृत का उत्तराधिकार प्राप्त करके संस्कृत की भाँति विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं को एक बंधन में बाँधने का ऐतिहासिक कर्त्तव्य पूरा करने में समर्थ है, वह उर्दू के प्रहारों से प्रान्तीय भाषाओं की रक्षा के लिये उनका बाहरी दुर्ग भी है। अहिन्दी जन इस दुर्ग को नष्ट करके स्वयं अपनी भाषाओं के विनाश का मार्ग खोलेंगे। अभी हाल की (अक्टूबर, १९४६) की खबर है कि मद्रास की कांग्रेसी सरकार ने मद्रास-प्रान्त के सब स्कूलों के लिये राष्ट्र-भाषा के रूप में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा का प्रबन्ध करना अनिवार्य करार दे दिया। कहना कठिन है यह 'हिन्दुस्तानी' कौनसी हिन्दुस्तानी है। यदि यह उत्तरी-भारत की बोलचाल की हिन्दुस्तानी, जिसे बोलचाल की हिन्दी कहना अधिक उचित होगा, है और मद्रास सरकार यह समझती है कि उससे राष्ट्र का काम चल सकता है और वह सार्वदेशिक भाषा के रूप में अँगरेज़ी को निकालने में समर्थ है तो वह भ्रम में है। अगर यह कोई साहित्यिक हिन्दुस्तानी है जिससे वक्ताओं को कहानियों के अतिरिक्त कोई और काम भी निकल सकता है, तो कहना कठिन है वह क्या है, क्योंकि यहाँ उत्तर में तो हमें हिन्दी और उर्दू के अतिरिक्त किसी साहित्यिक हिन्दुस्तानी का अथवा हिन्दी साहित्य या उर्दू साहित्य के अतिरिक्त किसी 'हिन्दुस्तानी' साहित्य का पता नहीं। उत्तर के स्कूलों में तो कोई 'हिन्दुस्तानी' नहीं, बरन् 'हिन्दी' और 'उर्दू' पढ़ाई जाती है। हमें किसी ऐसी साहित्यिक 'हिन्दुस्तानी' का (या उसके सिद्धान्तों का) भी पता नहीं जिसे पूरे देश ने

राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया हो। यदि मद्रास-सरकार यह समझती है कि उत्तर की परवाह न करके वह अपनी अलग साहित्यिक हिन्दुस्तानी का और उसके साहित्य का निर्माण कर सकती है और उसे जीवित भी रख सकती है, तो फिर उसे बोर भ्रम हुआ है (कन से कन फिर उसे वह 'राष्ट्र-भाषा' कहकर तो न पुकारे)। जो कुछ भी हो, वह तो स्पष्ट है कि वह 'हिन्दी' नहीं है। शायद वह हिन्दी और उर्दू का एक बैसा हो। मनमाना धोल है जैसा गांधीजी के पत्र 'हरिजन-सेवक' में काम में लाया जाता है, जिसके कोई सिद्धांत नहीं, कोई आदर्श नहीं और जो कुछ व्यक्तियों की ज़िद रखने के लिये तैयार किया गया है (इन धोल के विशेषज्ञ सब जगह, या सीखे सिखाये नहीं मिलते—खास तौर से तैयार किये जाते हैं)। और उर्दू लिपि तो साफ़ साफ़ रक्की ही गई है। अतः यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि मद्रास की कांग्रेसी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो तामिल और तेलगू का सत्यानाश करके रहेगा। ऊपर से तुरा यह है कि फिर भी इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि स्थिति यह है कि मुसलमान प्रान्त फिर भी शुद्ध उर्दू के सिवा किसी भी दूसरी हिन्दुस्तानी को और उर्दू लिपि के सिवा किसी दूसरी लिपि को आश्रय देने को तैयार नहीं (मिन्ध का उदाहरण सामने है जहाँ लोनी सरकार ने अभी हाल में 'हिन्दुस्तानी' नाम धरकर उर्दू को शिक्का का अनिवार्य विषय घोषित कर दिया, और चूँकि लिपि के मामले में धोखा देना संभव न था। इसलिये उस 'हिन्दुस्तानी' के लिये लिपि उनके को चोट

७ दक्षिण भारत हिन्दी (?) प्रचार सभा की 'हिन्दुस्तानी' पुस्तकों का 'हिन्दुस्तानी' का पता तो निश्चित रूप से लग गया है। उसके विधाना सभा के प्रधान-मंत्री श्री सत्यनारायण तथा कुछ अन्य दक्षिण-स्थित व्यक्ति हैं, और वह है उर्दू लिपि में शुद्ध उर्दू और देवनागरी में उर्दू जिसमें कहीं कहीं अकले या कोष्ठकों में उर्दू पर्यायों के साथ हिन्दी के सरल शब्द धर दिये गये हों।

केवल उर्दू लिपि स्वीकृत की; गांधीजी, कांग्रेस और आचार्य कृपलानी चुप हैं)। बम्बई और अन्य अहिन्दी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारें वही करेंगी जो मद्रास सरकार ने किया है। ऐसी स्थिति में एक हिन्दी-प्रेमी और विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के प्रेमी का अहिन्दी भाषी जनता और जन-नायकों से वही निवेदन है, तनिक ठहरो और विचार करो; प्रचलित नारों और कुछ व्यक्तियों में, वे चाहे कितने ही महान क्यों न हों, अन्ध-विश्वास मत करो और अपने ही हाथों अपने रुपये और साधनों से बह न करो जो तुम्हारे मूल पर ही कुठाराघात करेगा, इस प्राचीन देश की हज़ारों वर्ष पुरानी संस्कृति पर भयंकर आघात करेगा और जिससे उस उद्देश्य का सफल होना तो दूर रहा जिसे लेकर तुम यह करना चाहते हो, उल्टे प्रतिक्रियावादियों और राष्ट्र-द्रोहियों को प्रतिगामी माँगों की पूर्ति हो जायगी। हम उत्तरवासी तो किसी प्रकार अपना काम चला लेते हैं क्योंकि हिन्दी और उर्दू फिर एक ही बोली के आधार पर खड़ी हैं, परन्तु उर्दू—बंगाला, उर्दू—तेलगू, उर्दू—तामिल, उर्दू—मराठी जैसी समस्याएँ तुम्हारी प्रगति के मार्ग में ऐसी रुकावटें बनकर खड़ी हो जायँगी जिनका कोई इलाज न होगा।

२

कांग्रेस और 'हिन्दुस्तानी'

यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारें कांग्रेस के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दबाव के कारण ही गांधीजी के हिन्दुस्तानी-कार्यक्रम को अपना रही हैं, अतः कांग्रेस की हिन्दुस्तानी विषयक नीति के सम्बन्ध में भी कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। कहना न होगा, राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस की अपीज़मेंट पालिसी पूर्णतः असफल रही है। उससे केवल साम्प्रदायिकता को और शह मिली है। और कितनी ही नई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

भाषा के क्षेत्र में अप्रीजेन्ट पालिसी—'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'—बाद अप्रीजेन्ट के सिवा और कुछ नहीं—की भी वही गति होगी। उससे केवल समस्या और दुर्गुह होगी (पहले बतलाया जा चुका है) और देश की वास्तविक राष्ट्र-भाषा हिन्दी का घोर अहित होगा। सुसलमान, जिनके लिये ही यह सब बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, हिन्दुस्तानी-बाद से रत्तो भर प्रभावित नहीं। उनकी मातृ-भाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे बँगला, तेलगु, तामिल, मराठी या गुजराती, उन्हें उर्दू छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी से और उर्दू लिपि छोड़कर किसी दूसरी लिपि से कोई मतलब नहीं। वे 'दोनों लिपि' और गांधीजी के 'हरिजनसेवक' की हिन्दुस्तानी भी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। 'हिन्दुस्तानी' का रहस्य उसी दिन खुल गया जिस दिन रोडियो हिन्दी-उर्दू सलाहकार कमेटी में अंजुमन-तरक्की-उर्दू के प्रतिनिधि ने घोषित किया कि उसकी और अंजुमन की राय है कि 'हिन्दुस्तानी' के प्रयोग में समय लपट न किया जाय। इस मामले में कांग्रेसी सुसलमान और 'मिरानलिट' सुसलमान लीगी सुसलमानों के साथ हैं। यह पहले कहा जा चुका है कि मौलाना आज़ाद ने आन्ध्र के सुसलमानों की प्रतिक्रियावादी साँग का समर्थन किया। जब सब से बड़े कांग्रेसी सुसलमान का यह हाल है तो दूसरे सुसलमानों का क्या कहना। एक दूसरा सबूत यह है कि यद्यपि हिन्दू कांग्रेसी नेता अपने भाषणों में निश्चलता, उदारहृदयता, 'एकता'-प्रियता और न जाने क्या क्या दिखाने को उर्दू शब्द जानबूझ कर भरते हैं, कांग्रेस के सुसलमान नेता सर्वेसुख उर्दू में बोलते हैं (लीगी सुसलमानों के मुकाबले में कांग्रेसी सुसलमानों का कोई विशेष महत्व नहीं, यह बात अलग है।) फलतः राष्ट्रीय प्रकरणों में या वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' चलती है या उर्दू। हिन्दी कहीं दिखाने नहीं देती। आज की अन्तर्कालीन सरकार को ही देख लीजिये। उसमें या उर्दू पर जान देनेवाले हैं या 'हिन्दुस्तानी' पर मरने वाले अर्थात् आधे उर्दू शब्द और देवनागरी के साथ साथ उर्दू लिपि का प्रचार करने वाले और चाहने

वाले। बेचारी हिन्दी को पूछनेवाला कोई नहीं है। इन सब बातों का परिणाम यह हो रहा है कि उर्दू, उर्दू शब्दों और उर्दू लिपि का प्रचार हो रहा है, हिन्दी कमजोर पड़ रही है और कमबख्त 'हिन्दुस्तानी' फिर भी राष्ट्र-भाषा नहीं होती। 'हिन्दुस्तानी' तो कुछ हुई नहीं, बस केवल हिन्दी का वहिष्कार हो गया। गांधी-वादी और कांग्रेस-वादी हिन्दू शायद पूछेंगे, यदि मुसलमान 'हिन्दुस्तानी' स्वीकार नहीं करते तो हम कैसे राष्ट्रीयता से च्युत हो जायें? प्रथम तो यह समझ में नहीं आता कि 'हिन्दुस्तानी' 'राष्ट्रीय' किस प्रकार है? अपनी लिपि और शब्दों के द्वैतवाद (प्रत्यक्ष है) के कारण 'हिन्दुस्तानी' तो भाषा का साक्षात् पाकिस्तान है जिसमें दो लिपियाँ इस कारण रक्खी जाती हैं कि एक हिन्दुओं की लिपि है और एक मुसलमानों की, और शब्दों के जोड़े इस कारण रक्खे जाते हैं कि संस्कृत हिन्दुओं की पवित्र भाषा है और अरबी मुसलमानों की (और फारसी?)। भला कहीं इस द्वैतवाद से 'एक राष्ट्र' की राष्ट्रीयता सध सकती है? द्वितीय, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तानी नारे के विरुद्ध लड़कर मुस्लिम लीग को अपनी 'अखंड हिन्दुस्तान' की राष्ट्रीयता स्वीकार करने पर तो मजबूर कर लिया (या ऐसा करने का दावा करती है) *परन्तु वह मुसलमानों को 'हिन्दुस्तानी' में बोलने और लिखने के लिये कैसे विवश करेगी, और मुस्लिम प्रान्तों के मुसलमानों को 'हिन्दुस्तानी' और देवनागरी कैसे सिखायेगी? क्या कांग्रेस आज भी यह आशा करती है कि यदि कांग्रेसी हिन्दू इसी प्रकार 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर हिन्दी को हत्या करते रहेंगे, तो भविष्य में मुसलमान भी दिल पिघलाव-योग के वशीभूत होकर 'हिन्दुस्तानी' में बोलने लगेंगे?

जैसा पहले कहा जा चुका है, उर्दू की दिशा या प्रवृत्ति हिन्दी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं की दिशा या प्रवृत्ति से मूलतः भिन्न है। ज़रूरत

*अब वह बात भी नहीं रही। आगे 'पुनश्च' देखिये।

उर्दू की दिशा बदलने की है, हिन्दी की दिशा बदलने की नहीं। अगर उर्दू अपनी दिशा बदलने को तैयार नहीं, तो उसका दंड हमें न दिया जाय—हमें अपनी दिशा में चलने दिया जाय। उर्दू वालों को उर्दू छोड़कर हिन्दी ग्रहण करने पर तैयार करना है, हमें हिन्दी छोड़कर आधी उर्दू, आधी विदेशी 'हिन्दुस्तानी' ग्रहण करने पर नहीं। हम पर 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' न लादी जाय। हमारा कांग्रेस में कावद्य निवेदन है कि वह मुझ साम्प्रदायिकता को राष्ट्रीयता समझने की भूल न करे और अस्थायी लाभ, जो भी संदिग्ध है, की खातिर राष्ट्रीयता को सर्वत्र के लिये पंगु न करे। यदि मुसलमान अपनी पर-देश-भक्ति (extra-territorialism) नहीं छोड़ सकते, तो क्या कांग्रेस 'एकता' के नारे लगाकर हमें भी भारत और भारतावता से कम प्रेम करना सिखावगी? यदि अन्य देशों के अपने सङ्घमियों की भाँति (उदाहरणार्थ फारसी मुसलमान, जो फारसी में से अनावश्यक अरबी शब्द चुन चुन कर निकाल रहे हैं—वहाँ तक कि यदि कोई फारसी मुसलमान भूल से अपनी अर्जी में किसी दहिङ्कृत अरबी शब्द का प्रयोग कर देता है तो सरकार उसकी अर्जी अस्वीकृत कर देती है) भारतीय मुसलमान राष्ट्रीय दृष्टि-कोण नहीं अपना सकते, तो क्या कांग्रेस 'एकता' के नाम पर हमें भी अराष्ट्रीय दृष्टि-कोण अपनाने पर विवश करेगी?

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहती है और ठीक कहता है, स्वतन्त्रता और राजनैतिक एकता सुस्लिम लॉग को और कंसेशन देने से नहीं हो सकती। हम कहते हैं, भाषा की एकता भी उर्दू वालों को और कंसेशन देने से नहीं हो सकती। यह विशेष कंसेशन है कि उर्दू वालों को उर्दू और उर्दू लिपि सीखने पढ़ने दिया जाय, परन्तु राष्ट्र-भाषा हो 'हिन्दुस्तानी' एक 'और कंसेशन' है। यह विशेष कंसेशन है कि उर्दू को हिन्दी न बनाया जाय, परन्तु "हिन्दी को 'हिन्दुस्तानी' बनाया जाय" एक 'और कंसेशन' है जो राजनीतिक 'और कंसेशनों' की भाँति निष्फल तो होगा ही, हिन्दी और हिन्द की असीम

हानि करेगा और 'एकता' फिर भी उतनी ही दूर रहेगी जितनी पहले थी।

साम्प्रदायिक समस्या पर दृष्टिपात करते हुए आचार्य कृपलानी ने मेरठ में अपने राष्ट्रपति के पद से दिये गये भाषण में कहा, "..... हम जो कुछ भी करें उसमें हमें राष्ट्रीयता और जनतंत्र पर साम्प्रदायिक और जनतंत्र-विरोधी सिद्धान्तों को विजय नहीं पाने देना चाहिए। मेरा विश्वास है कि यदि हमने पृथक-निर्वाचन के अराष्ट्रीय और अजनतंत्रात्मक सिद्धान्त को मानने से साफ़ साफ़ इनकार कर दिया होता, तो हम अपनी वर्तमान सुनीवत से बहुत कुछ बच गये होते।” भाविष्य के लिये चेतावनी देते हुए उन्होंने फिर कहा, "..... संभव है, तात्कालिक कठिनाई से दबने के लिए हम फिर ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार कर लें जो राष्ट्रीयता और जनतंत्र के मूल पर कुठाराघात करने वाले हों। मैं आशा करता हूँ कि भाविष्य में हमारे वयोवृद्ध नेता स्वयं सावधान रहेंगे और देश को भी सावधान रखेंगे कि कहीं वे दक्कन या कहने-सुनने में आकर राष्ट्र-घाती, अजनतंत्रात्मक समझौते न कर दें।” हम कांग्रेस के वयोवृद्ध नेताओं और सबसे वयोवृद्ध नेता महात्मा गांधी से प्रार्थना करते हैं कि वे हिन्दी-उर्दू समस्या को, जिसे सब एक साम्प्रदायिक समस्या मानने को तैयार होंगे, और अपने हिन्दुस्तानीवाद को राष्ट्रपति की इन उक्तियों की रोशनी में देखें। राष्ट्र-भाषा में एक स्वदेशी शब्द, जिसे ८० व्यक्ति समझते हों, के बजाय एक विदेशी शब्द, जिसे केवल २० व्यक्ति समझते हों, रखना कहाँ तक राष्ट्रीय है और कहाँ तक जनतंत्रात्मक है ? और राष्ट्र-भाषा के निमित्त एक विदेशी, अवैज्ञानिक, अनुपयुक्त और अपूर्ण लिपि को जिसे अधिक से अधिक ३ करोड़ व्यक्ति जानते या मानते हों और जिसे त्यागना फरस और तुर्की जैसे मुसलमान देशों ने ही अपनी उन्नति के लिए आवश्यक समझा हो, एक स्वदेशी, वैज्ञानिक, उपयुक्त और पूर्ण लिपि, जिसे कम से कम १४ करोड़ व्यक्ति मूल रूप में और लगभग १० करोड़ व्यक्ति और

कुछ परिवर्तित रूपों में जानते या मानते हों, के समान स्थान देना कहाँ तक राष्ट्रीय, जनतन्त्रात्मक या विज्ञान-मम्मन ही है ? क्या राष्ट्र-भाषा के निमित्त दो लिपि के सिद्धान्त को मान कर केवल तात्कालिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र-भाषा, अ-जनतन्त्र तत्त्व समझौता नहीं किया जा रहा है, और क्या यह अवावहारिक होने के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, जनतन्त्र और एकता के मूल पर कुठाराघात नहीं करता और क्या इसे मानने से, यदि देश को ऐसी सुसंस्कृतों से वंचना है जिनका अंत कभी न होगा, हमें साफ इन्कार न कर देना चाहिये ?

३

'हिन्दुस्तानी' का रहस्य

—भाषा-वेत्ताओं के मुख से—

हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान श्रीचन्द्रबली पांडे अपने 'True Genesis of Hindusthani' शीर्षक लेख में लिखते हैं :—

"It is generally alleged that the question of high Hindi first sprang up from the establishment of Fort William College (1800) under the patronage of Dr. Gilchrist. But the policy as regards Hindi, Urdu and Hindustani followed by the Fort William College, as it has been explained by Gilchrist himself was that—
"In the Hindustani, as in other tongues, we might enumerate a great diversity of styles, but for brevity's sake, I shall only notice three here, leaving their sub-divisions to be discussed along, with the history of the language which has been reserved for the second volume First, the High Court or Persani

style. Second, the middle or genuine Hindustani style; third, the vulgar or Hinduwee.

"In the more elevated poems of Sauda, Wulee and others and in the affected, pompous, pedantic language or literature and politics, the first is predominant and leans to Arabic and Persian agreeably to circumstances.

"The elegy of Miskeen, the satires of Sauda, Hindustani Tales and Articles of War in the Oriental Linguist, the speech of wellbred Hindustani Munshees and servants are the best specimens I can recollect of the middle style, while the third or Hinduwee is evident in Mr. Foster's unaffected translations of the Regulations of Government, in all or greatest part of Hindustani Compositions written in the Nagri character, in the dialect of the lower order of servants and Hindus, as well as among the peasantry of Hindustan. The preference which I give to the middle style over the others, must appear in every page of my works, as it is in truth central regulator or tongue by which we perceive the ascending and descending scales on either side." (From Appendix to Gilchrist's Dictionary).

It must be noted here that the regulations of the Government of Fort William were translated into the genuine Hindi language and Nagari character commonly spoken and used by the Indian masses.

But the authorities of the Fort William College gave preference to the Munshee's Hindustani about which Sir. C. E. Trevelyan (afterwards the Governor of the Madras Presidency) in 1834 remarks that:—

“The Arabian Hindustani, which has grown up at Calcutta under the fostering patronage of Government, and is spoken by the Munshees of the College of Fort William, and the Maulvees and students of the Mohamedan College, is quite a different language from that which prevails in any other part of India.” (From the History of the Application of the Roman Alphabet, by M. Williams, Published by Longmans, London, 1859, page 29.)

And it is no wonder that in the middle of the 19th century Hindoostani becomes the synonym for Urdu. Sir Richard Temple (the Governor of Bombay, 1877-1880) observes that—

“The tongue of Moslems in India was most largely to be Persian, but since the middle of the century it has become Hindustani, formerly called Urdu, which is still the official language of the Courts in the districts round Lahore, Delhi, Agra, Lucknow. Elsewhere the official language of the Courts is the language of the region, that is to say, Bengali for Bengal, Oriya for Orissa, Hindi for Bihar and Benares. Maharatti for Nagpore and the Central Deccan to

Bombay, Gujrati for the Western Coast, Telegu for the Southern Deccan and the Eastern Coast, Kanarees for the South Western Coast and Tamil for the Southern Peninsula. Of these main languages, all save Hindustani and the Tamil are derived from Sanskrit." (From Progress of India, Japan and China in the Century, W. and B. Chambers, Ltd., London, 1902, p. 181).

And that is why the Concise Oxford Dictionary maintains: "Hindustani—Language of Mohammedan conquerors of Hindustan, Urdu."

प्रसिद्ध भाषा-वेत्ता डा० हुनीतिकुमार चटर्जी अपनी पुस्तक 'इण्डोएरियन ऐंड हिन्दी' (Indo-Aryan and Hindi) में लिखते हैं—

“बारहवीं और तेरहवीं शताब्दियों की तुर्क-विजयों के पश्चात् उत्तरी भारत (पूर्वी पंजाब से लेकर बंगाल तक) की प्रचलित भाषा के नामों में से हिन्दी सबसे प्राचीन और सरल नाम है, और मैं इसका प्रयोग इसी पुराने अर्थ और ध्वनि में करता हूँ और जनता में भी अभी तक इस नाम से यही भाव ग्रहण किया जाता है। 'हिन्दुस्तानी' बहुत बाद की और अधिक बोझिली उपज है—शुद्ध फ़ारसी शब्द के नाते अब यह शब्द मुसलमानी हिन्दी अर्थात् उर्दू, जिसमें फ़ारसी और अरबी शब्दों की भरमार रहती है और देशज हिन्दी तथा संस्कृत शब्द यथाशक्ति न्यून और बहिष्कृत रहते हैं, का पर्याय हो गया है। भारतीय भाषाओं के कुछ विद्यार्थियों और कांग्रेस तथा अन्य संस्थाओं के राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की ओर से इस फ़ारसी शब्द 'हिन्दुस्तानी' को अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करने का और उसे साहित्यिक हिन्दी (नागरी हिन्दी) और उर्दू दोनों की आधार-

भूत बोली के अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्न हुआ है, परन्तु इन कोशिशों के बावजूद लगभग सब अँगरेज़ और अन्य विदेशी लोग* अब भी ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘उर्दू’ दोनों शब्दों को हिन्दी भाषा की एक ही शैली अर्थात् उस शैली का बोधक समझते हैं जो फारसी लिपि में लिखी जाय और जिसमें अरबी फारसी शब्दावली प्रयुक्त की जाय ।’

कांग्रेस की हिन्दुस्तानी के विषय में डा० चटर्जी उसी पुस्तक में आगे फिर लिखते हैं—

“अब कांग्रेस हिन्दुस्तानी के ठेठ आधार अर्थात् खड़ी बोली, जिस पर साहित्यिक हिन्दी और उर्दू दोनों की नींव रखी हुई है, के आधार पर एक नई भाषा या साहित्यिक शैली गढ़ने का विचार इस कथित इरादे के साथ कर रही है कि विदेशी अरबी-फारसी शब्दों, जिन पर मुस्लिमान नेता जोर देते हैं, और देशज हिन्दी और संस्कृत शब्दों, जिन पर हिन्दुस्थानी-भाषी क्षेत्र के तथा शेष भारत के हिन्दू जोर देते हैं, के बीच में एक उचित और न्याय्य सन्तुलन रखा जाय । परन्तु व्यवहार में वह फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी बन रही है जिसे गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्री, उड़िया और दक्षिण के लोग नहीं समझ पाते (परन्तु फिर भी उनसे हिन्दुस्थानी के इस रूप को राष्ट्र-भाषा के रूप में ग्रहण करने के लिये कहा जाता है)+ और जिसमें विहार और

* उदाहरण के लिये बी० बी० सी०, मास्का रेडियो, अंकारा रेडियो और अन्य विदेशी रेडियो स्टेशनों की ‘हिन्दुस्तानी’ सुन लीजिये, जो शुद्ध उर्दू है—
आल इंडिया रेडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ नामधारी अपेक्षाकृत पतली चाशनी वाली उर्दू भी नहीं ।

+अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली, आसामी, उड़िया और दक्षिण भारतीय सदस्य प्रायः यह शिकायत करते सुने जाते हैं कि हम पं० बालकृष्ण शर्मा और श्री टण्डनजी के हिन्दी भाषण तो काफी अच्छी तरह समझ लेते हैं परन्तु पं० नेहरू, मौलाना आज़ाद और आचार्य कृपलानी की ‘हिन्दुस्तानी’ ठीक ठीक हमारी समझ में नहीं आती ।

का दो-टुक महत्व है। इन प्रान्तों में ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और देवनागरी का न कोई स्थान है और न कमी होगा। उर्दू, शुद्ध उर्दू, और उर्दू लिपि इस समय भी उनकी डी फैक्टो कामन भाषा और कामन लिपि हैं। कैबिनेट मिशन ने जो विधान-योजना प्रस्तुत की है, उसके अनुसार इन प्रान्तों पर सदैव मुस्लिम बहुमत वाली सरकारों का जो शासन लीगी ही होगी, राज्य होगा। केन्द्रीय सरकार के पास इन प्रान्तों की सरकारों को अपने अपने प्रान्त के स्कूलों में वर्धा को 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये या अपनी दोनों लिपियों सहित वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का एक अनिवार्य विषय करार देने के लिये मजबूर करने का कोई वैधानिक साधन न होगा। फिर ये प्रान्त एक ग्रुप (ग्रुप 'बी') बनायेंगे, और यह निश्चित है कि उर्दू और उर्दू लिपि ग्रुप की कामन या राष्ट्र-भाषा और लिपि घोषित की जायेंगी और उनका पढ़ना और सीखना ग्रुप के प्रत्येक निवासी के लिये अनिवार्य करार दिया जायगा। ऐसी परिस्थिति में सारे राष्ट्र को एक कामन राष्ट्र-भाषा के बन्धन में बाँधने का इसके सिवा कोई दूसरा उपाय न होगा कि ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' नहीं बरन् शुद्ध उर्दू, और उर्दू लिपि कांग्रेस प्रान्तों अर्थात् हिन्दुस्तान-ग्रुप (ग्रुप 'ए') की भी कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा और लिपि घोषित कर दी जायें, और उनका पढ़ना और सीखना ग्रुप के प्रत्येक निवासी के लिये अनिवार्य करार दिया जाय। यदि आरंभ में कांग्रेस ने किसी उर्दू से कम फारसीमयी 'हिन्दुस्तानी' को ही ग्रुप 'ए' की कामन भाषा करार दिया, तो भी परिस्थितियाँ और आवश्यकतायें उसे शीघ्र ही उर्दू से अभिन्न बना देंगी, क्योंकि एक ओर तो 'हिन्दुस्तानी' के स्वरूप को निर्धारित करने वाले कोई नियम या सिद्धान्त नहीं हैं और प्रत्येक उर्दू शब्द उसमें लिया जा सकता है, और दूसरी ओर ग्रुप 'बी' की सरकार या सरकारें उर्दू के स्वरूप में कोई परिवर्तन न होने देंगी और उसमें कोई हिन्दी संस्कृत

शब्द न घुसने देंगी। और यदि आरंभ में कांग्रेस ने दोनों लिपियों को ही ग्रुप 'ए' की कामन राष्ट्र-लिपि करार दिया, तो उर्दू लिपि अपने आप वास्तविक राष्ट्र-लिपि अर्थात् सारे राष्ट्र की लिपि तो हो ही गई, देवनागरी को थोड़े दिनों बाद बेकार बताकर छोड़ भी दिया जायगा। यदि उसे न भी छोड़ा गया (जिसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि बेकार और अनावश्यक चीज़ें कभी अधिक समय तक नहीं टिकती) तो हिन्दू यह सोच-सोच कर पुनः-कायमान तो न होंगे कि ग्रुप 'बी' के हिन्दू-मुसलमानों को देवनागरी नहीं सीखनी पड़ती तो न सही, ग्रुप 'ए' के मुट्ठी भर मुसलमानों को तो उर्दू लिपि के साथ साथ देवनागरी सीखनी पड़ती है। फिर यदि ग्रुप 'ए' के निवासियों को यह विकल्प ही दिया गया कि जो चाहे वह उर्दू लिपि और जो चाहे वह देवनागरी सीखे, तो इससे या तो "एक कामन राष्ट्र-भाषा जो सब भारतीयों द्वारा सीखी हुई दो लिपियों में से किसी में लिखी जाय" का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा या ग्रुप 'ए' के हिन्दू अमल में उर्दू लिपि चुनने पर बाध्य होंगे या किये जायेंगे और वही सारे राष्ट्र की डीपैक्टो कामन लिपि या राष्ट्र-लिपि होगी। यह भी स्पष्ट है कि इस परिस्थिति में हिन्दी और उर्दू दोनों को ग्रुप 'ए' को राष्ट्र-भाषा घोषित करने से भी समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा उर्दू को ही वास्तविक राष्ट्र-भाषा अर्थात् सारे राष्ट्र की भाषा बनाना, और चूँकि हिन्दी की कोई आवश्यकता न होगी, उसे शीघ्र ही एक बेकार का बोझ समझ कर हटा भी दिया जायगा। यदि उसे न भी हटाया गया, तो हिन्दू यह सोच-सोच कर आत्म-संतोष में विभोर तो न होंगे कि ग्रुप 'बी' के हिन्दू-मुसलमानों को हिन्दी नहीं सीखनी पड़ती तो न सही, ग्रुप 'ए' के मुट्ठी भर मुसलमानों को तो उर्दू के साथ साथ हिन्दी भी सीखनी पड़ती है। और यदि ग्रुप 'ए' के निवासियों को यह विकल्प ही दिया गया कि जो चाहे वह उर्दू सीखे और जो चाहे वह हिन्दी सीखे तो इससे या तो "सम्पूर्ण राष्ट्र की एक कामन राष्ट्र-भाषा

जिसे सब भारतीय जानते और सीखते हो" का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा या ग्रुप 'ए' के हिन्दू अमल में उर्दू चुनने पर बाध्य होंगे या क्रिये जायेंगे और वही सारे राष्ट्र की डी पैक्टो कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा होगी।

प्रत्यक्ष है, परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के हिन्दुस्तानी-वाद का अर्थ है उर्दू और उर्दू लिपि को पिछवाड़े के रास्ते से प्रविष्ट कर राष्ट्र पर राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में लाद देना।

यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके सत्य होने के लिये कैबिनेट मिशन की योजनानुसार ग्रुपों का बनना आवश्यक नहीं है। ग्रुप 'बी' में वही प्रान्त ही तो हैं जिन्होंने न आज तक वर्धा के हिन्दुस्तानी वाद से वास्ता रक्खा है, और न कभी रक्खेंगे, चाहे वे अलग अलग रहें और चाहे एक ग्रुप में आवद्ध हो जायँ। और ग्रुप 'ए' में वही प्रान्त हैं जिनकी पृथक् पृथक् सरकारें कांग्रेसी होने के नाते उसी नीति का अनुसरण करेंगी जो उन सब की एक कांग्रेसी, सम्मिलित केन्द्रीय सरकार की हो सकती है। कैबिनेट मिशन की ग्रुप-योजना ने केवल उसी बात को स्पष्ट-तर कर दिया है जो भाषा के मामले में उसके बिना ही काफी स्पष्ट थी और है। इसके अतिरिक्त, यदि मन के लड्डू फोड़ना छोड़ दिया जाय तो इसका कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता कि प्रान्तों के ग्रुप नहीं बनेंगे, अथवा यदि बनेंगे तो वे भाषा और संस्कृति का विषय केन्द्रीय सरकार को सौंप देंगे। कम से कम ग्रुप 'बी' का बनना निश्चित है, और इतना काफी है। कोई यह भी न समझे कि इस ग्रुप-बाज़ी के दाद कांग्रेस ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' (अथवा हिन्दी और उर्दू दोनों) को ग्रुप 'ए' की कामन भाषा और लिपि, और इसलिये शिद्दा का अनिवार्य विषय, घोषित करने की मूर्खता नहीं करेगी। जो कांग्रेस (अर्थात् विभिन्न कांग्रेसी प्रान्तीय सरकारें) सन् १९३८-३९ के अपने अल्प राज्य-काल में यह भली भाँति जानते हुये भी कि मुस्लिम प्रान्त वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों

लिपि' (अथवा हिन्दी उर्दू दोनों) की बात बिल्कुल नहीं पूछेंगे (और न उन्होंने पूछी), युक्त-प्रान्त, विहार और मध्य-प्रान्त ऐसे हिन्दी-भाषी प्रान्तों में, जहाँ मुठ्ठी भर, और वे भी हिन्दी भाषी, मुसलमान रहते हैं, हिन्दी को निकाल कर 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' (अथवा हिन्दी उर्दू दोनों) को सबके सिर पर लादने, और राज-भाषा, शिक्षा के माध्यम, आदि के पद पर प्रतिष्ठित करने से, और दम्बई ऐसे संस्कृत-निष्ठ भाषायें बोलने वाले प्रान्त में राष्ट्र-भाषा के रूप में ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और उर्दू लिपि की अनिवार्य शिक्षा जारी करने से बाज़ न आई, वह ग्रुप 'धी' के (अर्थात् उन्हीं मुस्लिम प्रान्तों के) उर्दू को अपनी भाषा बनाने पर भी केवल १० प्रतिशत (१८७ में २०) मुसलमानों के कारण (जिनमें से अधिकांश हिन्दी और अन्य संस्कृत-निष्ठ भाषायें बोलते और समझते हैं और देवनागरी या उसके किसी रूप में लिखते हैं) ग्रुप 'ए' की (अर्थात् अपने अधीनस्थ हिन्दू प्रान्तों की) कामन भाषा हिन्दी के वजाय 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' (अथवा हिन्दी उर्दू दोनों) फिर घोषित कर सकती है—बस, केवल 'महात्मा' की उपाधि धारण करने वाले गांधी जी, 'तंग-खयाली' से दूर रहने वाले और अन्तरराष्ट्रीयता में विचरने वाले पं० नेहरू, सदा एकरस रहने वाले डा० राजेन्द्रप्रसाद, और मौलाना अबुलकलाम आज़ाद, श्री आम्फअली, डा० नैयदमहमूद और श्री रफीअहमद किदवाई सरीखे कांग्रेसी और मौलाना मदनी जैसे 'नेशनलिस्ट' मुसलमान सलामत रहें । राज्य की बागडोर फिर सँभालने के द महीने के अन्दर अन्दर ही संयुक्त-प्रान्त की कांग्रेसी सरकार का 'हिन्दुस्तानी' को संयुक्त प्रान्त की देशज भाषा ('वर्नाक्युलर') घोषित करना, संयुक्त-प्रान्त और विहार की कांग्रेसी सरकारों का 'हिन्दुस्तानी' को कालेजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये कदम उठाना और संयुक्त-प्रान्त की सरकार का 'हिन्दुस्तानी' के साहित्य की अभिवृद्धि के लिये ५० हजार रुपया स्वीकृत करना, आदि और मद्रास की कांग्रेसी

सरकार का अपने प्रान्त के सब स्कूलों में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा का प्रबन्ध अनिवार्य करार देना हवा का रुख बताने के लिये काफी हैं।

इतिहास साक्षी है कि एक बनावटी समझौते पर आधारित या आश्रित एकता कभी स्थायी नहीं होती। परन्तु "हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि" तो एक ऐसा समझौता भी नहीं है जिसे दोनों विराधी दलों ने मान लिया हो। यह तो एक दल का दूसरे के सामने आत्म-समर्पण है। मद्रास, बम्बई, आदि अहिन्दी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों द्वारा अपने अधीनस्थ स्कूलों में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा के प्रचलित किये जाने का परिणाम यही होना है कि उर्दू और उर्दू लिपि भारत की एकमात्र डी फैक्टो राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि हो जायगी। इसमें सन्देह करने की कोई गुंजाइश नहीं। भाषा की समस्या को कॅबिनेट मिशन की विधान-योजना की रोशनी में देखते हुये क्या कांग्रेस के लिये यह उचित नहीं है कि इसके पूर्व कि वह हिन्दू प्रान्तों पर, जो उसकी मुट्ठी में हैं, अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' (या हिन्दी उर्दू दोनों) लादे और इस प्रकार उनका समय, शक्ति और पैसा बरबाद करे, उनकी भाषा-समस्या को और जटिल बनाये और हिन्दुओं में फूट डाले और संघर्ष उत्पन्न करे—और यह सब उनमें रहनेवाले मुस्लीम (१८७ में २०) मुसलमानों (जिनमें से अधिकांश हिन्दी या अन्य संस्कृत-निष्ठ भाषायें बोलते और समझते हैं) के कारण, कम से कम वह अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' को राष्ट्र-भाषा के रूप में मुसलमान प्रान्तों से भी, कहने के लिये भी और अमल में भी, मनवा ले? अगर वह ऐसा नहीं कर सकती या करने में असमर्थ है, तो न्याय और तर्क का तर्क ज़ा यह है कि भ्रूष 'ए' की कामन भाषा और लिपि हिन्दी और केवल देवनागरी हों और भ्रूष के प्रत्येक निवासी के लिये हिन्दी और देवनागरी का सीखना अनिवार्य हो। केन्द्रीय सरकार हिन्दी और उर्दू दोनों को राष्ट्र-भाषा स्वीकृत करे और दोनों को

समान पद दे। यह कोई नई बात न होगी। कैनाडा में पूर्वी कैनाडा, जहाँ फ्रेंच भाषी जनता का बहुमत है, की राष्ट्र-भाषा फ्रेंच है, और फ्रेंच-ज़ोन की धारा-सभा और सरकार की सारी कार्रवाई फ्रेंच-में होती है, और पश्चिमी कैनाडा, जहाँ अँगरेज़ी भाषी जनता का बहुमत है, की राष्ट्र-भाषा अँगरेज़ी है और अँगरेज़ी-ज़ोन की धारा-सभा और सरकार की सारी कार्रवाई अँगरेज़ी में होती है। कैनाडा की केन्द्रिय सरकार अँगरेज़ी और फ्रेंच दोनों को राष्ट्र-भाषा मानती है और दोनों को समान पद देती है। इसी प्रकार स्वीटज़रलैंड में तीन राष्ट्र-भाषाएँ हैं और तीनों के अलग अलग ज़ोन हैं। भारत में ग्रूप 'ए' को कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा हिन्दी होगी, ग्रूप 'बी' को उर्दू, और केन्द्र दोनों को राष्ट्र-भाषा मानेगा। यह भारत को राष्ट्र-भाषा समस्या का आदर्श नहीं, तो यथेष्ट संतोषजनक और व्यावहारिक हल होगा। हिन्दी और उर्दू तो अँगरेज़ी और फ्रेंच (या जर्मन) की अपेक्षा फिर एक दूसरे के अधिक निकट हैं। ग्रूप 'सी' के बंगाल-प्रान्त की प्रान्त भाषा होगी बँगला और आसाम की असमी। यह ग्रूप बँगला को अपनी कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा बना सकता है (और उस अवस्था में केन्द्र के लिये बँगला को भी राष्ट्र-भाषा स्वीकृत करना आवश्यक होगा), यद्यपि ज़्यादा अच्छा यह होगा कि ये प्रान्त हिन्दी और उर्दू को राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार कर लें या हिन्दी या उर्दू बतौर राष्ट्र-भाषा के सीखना प्रत्येक की इच्छा पर छोड़ दें।

५

कांग्रेस से एक अपील

अन्त में हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि उसके 'हिन्दुस्तानी' के विषय में चाहे जो विचार हों पर हमारी हिन्दी को बख्श दे। वह 'हिन्दुस्तानी' के जोश में आकर हिन्दी का अस्तित्व मिटाने की चेष्टा न करे। कांग्रेस ने बार बार यह घोषणा की है कि वह जनता के प्रत्येक भाग की भाषा और संस्कृति

की रक्षा और आदर करेगी। कांग्रेस अपनी इस घोषणा का पालन करे। कम से कम हिन्दी के अपने निजी प्रदेश में अर्थात् संयुक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त, इन हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का अखण्ड राज्य रहना चाहिये और इनमें सारा काम-काज जैसे राज्य-व्यवहार, शिक्षा का काम और सार्वजनिक व्यवहार परंपरागत शुद्ध हिन्दी में होना चाहिये। कांग्रेस इन हिन्दी प्रान्तों पर अपनी 'हिन्दुस्तानी'—उसकी अन्तिम रूढ़-रेखा कांग्रेस चाहे जो भी निश्चित करे—प्रान्तीय भाषा के तौर पर न लादे। इन प्रान्तों की जनता ने विगत शताब्दियों में हिन्दी को रूप दिया है और उसकी बाणी हिन्दी साहित्य के रूप में प्रसूति हुई है, इनलिये इन प्रान्तों में हिन्दी को छोड़कर प्रादेशिक भाषा के बतौर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य प्रान्तों में परंपरागत प्रान्तीय भाषा को छोड़कर किसी दूसरी भाषा का प्रान्तीय प्रकरण में कोई स्थान नहीं। कांग्रेस की घोषणा का यही अर्थ निकलना है और इसी प्रकार हिन्दी, परंपरागत हिन्दी, के हितों की रक्षा हो सकती है। राष्ट्र का, यदि वह ऐसा करना ही चाहे तो, राष्ट्र-भाषा निर्माण करने का अधिकार हो सकता है परंतु उसे राष्ट्र के किसी भाग या राष्ट्र की जनता के किसी भाग पर उसकी निजी परंपरागत भाषा हटा कर उसके स्थान में राष्ट्र-भाषा लादने का कोई अधिकार नहीं। यदि राष्ट्र-भाषा को ऐसा और वैसा होना चाहिये, ऐसी और वैसी संस्कृति का प्रतीक होना चाहिये, तो खुशी से राष्ट्र उसे इच्छानुसार गढ़े, परन्तु, हमारी निजी भाषा हिन्दी और हमारी निजी संस्कृति के प्रतीक हिन्दी का भी तो अपने प्रदेश में पूर्ण अधिकार रहना चाहिये। हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि वह हिन्दो को अपने घरमें से निकाल कर 'हिन्दुस्तानी' को बसाने का प्रयत्न करना छोड़ दे।

केन्द्र में भी (जैसे आल इन्डिया रेडियो, सरकारी फिल्म, केन्द्रीय सूचना विभाग, आदि) हिन्दी, परंपरागत शुद्ध हिन्दी, को कम से कम वह स्थान दिया जाय जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं को दिया जाय। हम कांग्रेस से, जिसके

हाथ में आज केन्द्रीय सरकार को भी बागडोर है, अपील करते हैं कि वह हिन्दी के साथ कम से कम इतना न्याय करे। यदि उसे हिन्दुस्तानी-वाद में वास्तव में विश्वास है तो इसके पूर्व कि वह ऐसे प्रकरणों में हिन्दी के स्थान में 'हिन्दुस्तानी' धरे जहाँ अन्य प्रान्तीय भाषाओं को स्वतन्त्र स्थान प्राप्त है, जैसे आल इंडिया रेडियो में, और इसलिये जहाँ हिन्दी का भी एक प्रान्तीय भाषा के नाते ही स्वतन्त्र स्थान होना चाहिये, वह पहले अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' को वहाँ प्रतिष्ठित करे जहाँ केवल एक भाषा है और इसलिये जहाँ केवल राष्ट्र-भाषा को ही होना चाहिये, अर्थात् वह पहले, उदाहरण के लिये, सेना और रक्षा-विभाग की रोमन उर्दू और होम-विभाग तथा अन्य विभागों की राजभाषा उर्दू के स्थान में अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' को प्रतिष्ठित करे (यदि सेना में 'दोनों लिपि' की गुंजाइश नहीं तो विदेशी रोमन लिपि के स्थान में दो 'राष्ट्र-लिपियों' में से अधिक प्रचलित लिपि अर्थात् देवनागरी प्रतिष्ठित करे)। जहाँ जहाँ अब तक हिन्दी थी वहाँ वहाँ हिन्दी को निकालकर अपनी 'हिन्दुस्तानी' धरने में कांग्रेस ने देर नहीं की; हमें यह भी तो मालूम हो कि जहाँ जहाँ अब तक उर्दू का अखण्ड राज्य रहा है और है वहाँ वहाँ उर्दू को निकालकर अपनी 'हिन्दुस्तानी' प्रतिष्ठित करने के लिये कांग्रेस कहाँ तक तैयार है, कहाँ तक समर्थ है और उसमें ऐसा करने का कहाँ तक साहस है। यह तो विचित्र प्रकार का न्याय होगा कि केन्द्र में प्रान्तीय भाषाओं का स्थान हो और 'हिन्दुस्तानी' का भी स्थान हो जैसे आल इंडिया रेडियो में, और उर्दू का स्थान भी अक्षुण्ण रहे जैसे सेना और रक्षा-विभाग में (और संयुक्त प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त की अदालतों, पुलिस, दफ्तरों, आदि में भी), परन्तु हिन्दी कहीं दिखाई न दे।

पुनश्च

जिस बात का डर था, अन्त में वह होकर रही। पाकिस्तान बन गया।

जिस कमज़ोर और सीमित केन्द्र की कैबिनेट मिशन ने व्यवस्था की थी, अब वह भी नहीं रहा। कांग्रेस ने शेर की खाल उतार फेंकी और जनता से किये गये अपने वादों को भूल कर, बिना चींचपड़ किये, बिना हाथ-पैर मारे झुपचाप पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। हमारा प्रिय आर्यावर्त्त जिसकी एकता का उच्च घोष वेदों ने किया था और जिम्ने अपनी सांस्कृतिक एकता को अब तक अखंड बनाये रखा था, आज टूक-टूक हो गया। हिन्दुओं के साथ, जिन्होंने भारत-माता की वेड़ियों को काटने के लिये और उसके शरीर को अक्षत रखने के लिये अपना खून और पसीना बहाया था, कांग्रेस ने घोर विश्वासघात किया है। हिन्दुओं की वर्त्तमान दयनीय स्थिति का सबसे करुण पहलू यह है कि हिन्दुओं का ऐसा कोई नेता नहीं है जो मि० जिन्ना से टक्कर ले सके और हिन्दुओं की ऐसी कोई संस्था नहीं जो हिन्दुओं की की ओर से बोल और कर सके। पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया, परन्तु हिन्दुस्तान अब भी हिन्दुओं का नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने जिन्हें पग-पग पर हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने, उनकी ओर से बोलने और सही करने के लिये बुलाया जा रहा है, जन्म भर मनसा, बाचा और कर्मणा यह सिद्ध करने की भरसक चेष्टा की है, और अब भी कर रहे हैं, कि वे हिन्दू नहीं हैं। गांधीजी जिन्होंने हिन्दुओं को मनचाहा नाच नचाया है और जो हिन्दुओं को वर्तमान दशा पर पहुँचाने के लिये सबसे अधिक ज़िम्मेदार हैं, हार गये हैं परन्तु अपनी हार मानने को तैयार नहीं। वे चाहते हैं कि उनके आत्मिक लाभ के लिये अब हिन्दुस्तान के हिन्दू जिन्ना साहब के दो राष्ट्र-बाद (टू नेशन थ्योरी) को अपने कर्म्मों से मलत सिद्ध करें, जिसका अर्थ केवल यह है कि यदि हिन्दुस्तान के मुसलमान हिन्दुस्तान में एक जगह (जो सम्भवतः पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल ही होगी) काफी संख्या में जाकर बस जायँ तो वे फिर उसे अपना घर बताकर हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की सम्पत्ति और साधनों के द्वारा बँटवारे की माँग कर सकें। और कांग्रेसी

नेता जो शुद्ध अहिंसात्मक उपायों से ब्रिटिश सत्ता को भारत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं परन्तु उन्हीं उपायों से मुसलमानों को भारत में रहने पर मजबूर करने में 'हिंसा' समझते हैं, दो-चार आँसू ढरकाकर उस माँग को मान लें ! (हिटलरशाही में दत्त पाकिस्तानी सरकार भी तो उस माँग के पीछे होगी, और फिर 'आत्म-निर्णय' के कांग्रेसी निद्वान्त को कैसे भुलाया जा सकेगा !) दूसरे शब्दों में, गांधी जी चाहते हैं कि हिन्दू अब भी आस्तीन के साँप को दूध पिलाते रहें और हिन्दुस्तान को उनके आध्यात्मिक प्रयोगों के लिये बलिदान का बकरा बने रहने दें । दूसरी ओर पं० नेहरू हैं, जिन्हें अपने नाम के पहले 'पंडित' (जिसका अर्थ है 'विद्वान्') लगने से इसलिये चिढ़ थी और है कि उस शब्द का संबन्ध हिन्दुओं से है, और जो अब चाहते हैं कि भारत का जो भाग हिन्दुओं के हिस्से पड़ा है, उसका भी नाम 'हिन्दुस्तान' (जो अभी कल तक सम्पूर्ण भारत के लिये आता रहा है) न रहे क्योंकि उसमें 'हिन्दू' शब्द वर्तमान है, और उसका नाम 'इन्डिया' रखा जाय । और गांधी जी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं । कांग्रेस नेताओं का शब्द-जाल द्वारा अपनी हाँ, शर्म और भोग को छिपाने का प्रयत्न करना और पुनर्मिलन आदि का सब्ज बाग देखना और दिखाना वास्तव में एक अनोखा दृश्य उपस्थित कर रहा है ।

जो होना था सो हो गया । अब भविष्य का क्या हो ? स्पष्ट है, हिन्दुस्तान एक हिन्दू राष्ट्र हो जिसका राज-धर्म हिन्दू-धर्म हो और जिसमें सब प्रमुख पदों पर हिन्दुओं और अमुस्लिमों की नियुक्ति हो । ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से हिन्दू-धर्म न मानता हो और जो हिन्दू-संस्कृति में डूबा हुआ न हो, हिन्दुस्तान-सरकार का प्रधान नहीं हो सकता । सारा संसार नेहरू-सरकार को हिन्दू-सरकार बताता और समझता है, जब कि वास्तव में अर्थात् अमल में वह हिन्दू-सरकार नहीं है । ऐसी भ्रांति का कारण नहीं रहने या भविष्य में उत्पन्न होने दिया जा सकता । और मुसलमानों को,

जैसा कि मध्य-प्रांत के प्रधान-मंत्री ने कहा है, हिन्दुस्तान राष्ट्र की नागरिकता के अधिकार न दिये जायें। पूरे भारत के मुसलमानों ने अपने आप को एक पृथक राष्ट्र बताते हुये एक पृथक वास-भूमि की माँग की है, और उन्हें अब यह मिल चुकी है और स्पष्टतः भारत का बँटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, अतः इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते। चित और पट दोनों मुसलमानों की नहीं हो सकती। गांधी जी के कहने पर पाकिस्तान जैसे स्थूल सत्य को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता। 'अल्पसंख्यक' के किसी झूठे नाम पर पाकिस्तान के किपथ कालम को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ तक नाम का सम्बन्ध है, 'इन्डिया' पं० नेहरू की, जो मौलाना आज़ाद की साक्ष्यानुसार स्वप्न भी अँगरेज़ी में देखते हैं, स्व-भाषा का शब्द होगा, परन्तु ६६*६ प्रतिशत भारतीयों की मातृ-भाषा का शब्द नहीं है। पं० नेहरू की सनक पूरी करने के लिये इतिहास नहीं बदला जा सकता। नाम में केवल एक परिवर्तन हो सकता है और अवश्य होना चाहिये। वह यह कि फ़ारसी 'स्तान' बदल कर 'स्थान' अर्थात् 'हिन्दुस्तान' अब 'हिन्दुस्थान' कर दिया जाय।

'हिन्दुस्तानी' की टाँय-टाँय फ़िस

इन बातों को छोड़कर अब मूल विषय पर आइये। हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भाषा क्या हो? स्पष्ट है, हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भाषा हिन्दी हो। 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' के मुकाबले में हिन्दी और देवनागरी का पक्ष शाश्वत तर्कों और सिद्धान्तों पर आधारित है और उसका राजनीतिक लौट-पौट से कोई लगाव नहीं रहा है, परन्तु अब तो हिन्दुस्तानी-वाद की कोई जड़ ही नहीं रह गई। जिन प्रदेशों और जिन लोगों को फाँसने के लिये कांग्रेस ने हिन्दुस्तानी-वाद अपनाया था अब वे ही अलग हो गये। कांग्रेस ने ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' का बखेड़ा मुसलमानों को राष्ट्र-

भाषा के मामले पर राज़ करने के लिये खड़ा किया था। अब केवल हिन्दू भारत का सवाल है जो सदा से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा और देवनागरी को राष्ट्र-लिपि मानता आ रहा है क्योंकि उसके लिये यही भाषा और लिपि सबसे अधिक सुलभ, सरल और उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, यह निश्चित है कि पाकिस्तान उर्दू को अपनी राष्ट्र-भाषा बनायगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से हिन्दी और देवनागरी का सर्वथा बहिष्कार कर दिया जायगा। इन दोनों बातों का सिन्ध में श्रीगणेश हो चुका है। सिन्ध की अपनी अलग भाषा है, परन्तु सिन्ध की पाकिस्तानी सरकार ने उर्दू को सिन्ध की राज-भाषा और कचहरियों की भाषा घोषित कर दिया है, और सिन्ध के शिक्षा-मंत्री पीर इलाही वख़्श ने बताया है कि कराची विश्व-विद्यालय की शिक्षा का माध्यम उर्दू होगी, और उर्दू भाषा का विषय सब के लिए प्राइमरी स्टेज से ही अनिवार्य होगा। सिन्ध-सरकार ने हिन्दी और देवनागरी पर भी खुल्लम-खुल्ला प्रहार करना आरंभ कर दिया है, और हिन्दुओं की सब शिक्षा-संस्थाओं की स्वतन्त्रता अपहरण करने या उन्हें विलकुल मिटा डालने का आयोजन किया है। जो भी शिक्षा-संस्था, चाहे वह हिन्दुओं की निजी संस्था ही क्यों न हो, कराची विश्व-विद्यालय की अधीनता स्वीकार नहीं करेगी, उसे नहीं रहने दिया जायगा। प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस अब भी इस कमबख्त 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' का रगड़ा हिन्दुस्थान पर लादेगी ? ताली दोनों हाथों से बजती है। क्या यह बात क्षण भर के लिये भी सहन की जा सकती है कि उर्दू तो पाकिस्तान में राष्ट्र-भाषा, राज-भाषा, शिक्षा का माध्यम, रेडियो की भाषा, आदि के बतौर अखंड राज्य करे परन्तु हिन्दुस्थान में हिन्दी की सुन्नत करके 'हिन्दुस्तानी' को प्रकट किया जाय, और हिन्दी कहीं की न रहे ? जब उर्दू ऐसी ही रही, तो हिन्दी को मिटाने से क्या होगा ? जब 'उर्दू' नाम वर्तमान रहा, तो 'हिन्दी' नाम मिटाने से क्या होगा ? ऊपर कैबिनेट-मिशन की विधान-

योजना की रोशनी में जो कुछ कहा जा चुका है, उसके बाद इसके सिवा कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं कि चूँकि अब हिन्दुस्थान और पाकिस्तान का कामन केन्द्र भी नहीं रहा, अब हिन्दी और उर्दू दोनों को केन्द्र की भाषा स्वीकृत करने का भी प्रश्न नहीं रहा। अब हिन्दी, और केवल हिन्दी, को हिन्दुस्थान की केन्द्रीय भाषा, राष्ट्र-भाषा, शिक्षा का प्रमुख माध्यम और रेडियो की प्रमुख भाषा, आदि होना चाहिये, और हिन्दी भाषा का विषय हिन्दुस्थान भर के शिक्षाक्रम में सबके लिये उसी प्रकार अनिवार्य होना चाहिये जिस प्रकार आज अँगरेजी का है। हिन्दी प्रान्तों में भी अब हिन्दी और केवल और अकेली हिन्दी राज-भाषा, कचहरियों की भाषा और शिक्षा का माध्यम हो सकती है, और हिन्दी भाषा का विषय प्राइमरी स्टेज से सबके लिये अनिवार्य होना चाहिये। इसी प्रकार हिन्दी अपने अपने प्रान्तों में अखंड राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषाओं की भाँति फल-फूल और अबाध रूप से उन्नति कर सकती है और इसी प्रकार हिन्दी प्रान्तों में भाषा के आधार पर निर्मित अन्य प्रान्तों की भाँति भाषा की एकता स्थापित की जा सकती है। उर्दू वैकल्पिक विषय रह सकती है और वह भी तभी जब पाकिस्तान में हिन्दी को वही स्थान दिया जाय। हिन्दुस्थान में उर्दू को उससे ऊँचा पद नहीं दिया जा सकता जो पाकिस्तान में हिन्दी को दिया गया है या भविष्य में दिया जाय। गांधी जी के उदारता-वाद के लिये जो हिन्दुओं और हिन्दी को इस गिरी हुई दशा पर पहुँचाने के लिये जिम्मेदार है, अब विलकुल गुंजाइश नहीं। मुसलमानों की हम बहुत खुशामद-चिरौरी कर चुके। हिन्दुस्थान या हिन्दी प्रान्तों पर दो-दो राज-भाषाओं और राज-लिपियों का फिजूल खर्च और भ्रमेला नहीं लादा जा सकता। हिन्दू बालकों पर एक विदेशियत में रंगी हुई भाषा और एक व्यर्थ लिपि का बोझ नहीं डाला जा सकता। हिन्दुस्थान की विधान-परिपद का कर्तव्य है कि वह विधान में हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि के पद

पर विधिवत् प्रतिष्ठित करे। संभव है, गांधोजी का संकेत पाकर या अपनी जिद रखने के लिये अथवा आत्म-सम्मान की झूठी भावना से प्रेरित होकर कुछ कांग्रेसी नेता अब भी अपनी ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' (पं० नेहरू के संतोषार्थ सब हिन्दूपना निकाल डालने के लिये इसका नाम 'इंडिश' रख कर ?) और 'दोनों लिपि' हिन्दुस्थान के गले मढ़ने का प्रयत्न करें, और 'पुनर्मिलन की संभावना' (यदि सत्य हो भी जाय तो उसका भाषा की समस्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?), 'अल्पसंख्यकों के साथ न्याय' (वे 'अल्पसंख्यक' कौन हैं ?), 'जनता की भाषा' (वह क्या है ?), आदि, आदि जैसे सारहीन और खोखले तर्कों को उपस्थित करें, परंतु विधान-परिषद के हिन्दू सदस्यों को जो वहाँ हिन्दुओं की बोटों से पहुँचे हैं और जिन्होंने अपने आपको 'हिन्दू' समझना नहीं छोड़ दिया है, और अधिक मूर्ख बनने से साफ इन्कार कर देना चाहिये। हिन्दुस्थान की विधान-परिषद संसार को दिखा दे कि भरतवंशी अब भी अपनी जन्म-भूमि और पुण्य भूमि में बसते हैं और अपनी पुरानी, प्रिय भारती को भूले नहीं हैं।

१६ जून, १९४७

रविशंकर शुक्ल

सत्यज्ञान निकेतन

(पश्चिम भारत हिन्दी प्रचार केंद्र)

ज्वालापुर (हरिद्वार)

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की प्रचार पुस्तकमाला :—

- | | |
|---|------|
| १—कचहरी की भाषा और लिपि | III) |
| २—भाषा का प्रश्न | III) |
| ३—बिहार में हिन्दुस्तानी | I) |
| ४—मुल्क की जबान और फाजिल मुसलमान
(उर्दू में) | I=) |
| ५—उर्दू का रहस्य | III) |
| ६—उर्दू का उद्गम | =) |
| ७—मुगल बादशाहों की हिन्दी | II) |
| ८—उर्दू की जबान | -) |
| ९—हकीकत उर्दू की जबान की क्या है ?
(उर्दू में) | -) |
| १०—नेशनल स्क्रिप्ट फार इंडिया (अँगरेजों में) | -) |
| ११—हिन्दी की हिमायत क्यों ? | =) |
| १२—हिन्दुस्तानी का उद्गम | -) |
| १३—'हिन्दुस्तानी' का रहस्य—एक हिन्दी के मुख से | I=) |
| १४—हिन्दी वालो, सावधान ! | III) |